



+++

GENERAL
AWARENESS

कैप्सूल

IBPS PO

मेन्स 2025

अप्रैल-सितंबर 2025

**GA Capsule of IBPS PO Mains 2025**

राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स.....	3
अंतरराष्ट्रीय करेंट अफेयर्स.....	105
नई नियुक्तियाँ: राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय.....	117
समझौता/समझौता ज्ञापन.....	125
बैंकिंग करेंट अफेयर्स	130
अर्थव्यवस्था/व्यापार करेंट अफेयर्स.....	143
रक्षा संबंधी करेंट अफेयर्स.....	159
पुरस्कार और मान्यता.....	167
शिखर सम्मेलन कार्यक्रम त्यौहार (राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय)	172
सूची/सूचकांक (रैंक और रिपोर्ट).....	175
पुस्तक और लेखक.....	181
खेल करेंट अफेयर्स.....	183
साइंस एंड टेक्नोलॉजी.....	195
योजनाएं/ऐप्स/पोर्टल	204
महत्वपूर्ण दिवस.....	210
निधन (राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय).....	216
विविध करेंट अफेयर्स वन-लाइनर्स	221
स्थैतिक टेकअवे करेंट अफेयर्स.....	223





राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स: सितम्बर 2025

महीने की सबसे महत्वपूर्ण खबरें

जीएसटी दर में कटौती 2025: उपभोक्ताओं के लिए क्या सस्ता, क्या महंगा

सरकार ने 2025 में जीएसटी दरों में बड़े बदलावों की घोषणा की है, जिससे रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों से लेकर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और यहां तक कि ऑटोमोबाइल भी अधिक किफ़ायती हो गए हैं। अब उपभोक्ताओं को दैनिक उपयोग के सामान, कृषि उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स पर कम दाम का लाभ मिलेगा। इन कटौतियों से आम जनता की जेब पर बोझ हल्का होगा और बाज़ार में ख़पत को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में इज़ाफ़ा भी किया गया है, जिससे वे पहले से महंगे हो जाएंगे।

दैनिक आवश्यक वस्तुओं पर बड़ी बचत करें

वस्तुएँ	पहले जीएसटी दर	अब जीएसटी दर
बालों का तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप बार, टूथब्रश, शेविंग क्रीम	18%	5%
मक्खन, घी, पनीर एवं डेयरी स्प्रेड्स	12%	5%
पैक किए गए नमकीन, भुजिया और मिक्सचर	12%	5%
बर्तन	12%	5%
बच्चों की फीडिंग बोतलें, नैपकिन व क्लीनिकल डायपर्स	12%	5%
सिलाई मशीनें एवं उनके पुर्जे	12%	5%

किसानों और कृषि का उत्थान

वस्तुएँ	पहले जीएसटी दर	अब जीएसटी दर
ट्रैक्टर टायर एवं पुर्जे	18%	5%
ट्रैक्टर	12%	5%
निर्दिष्ट बायो-पेस्टीसाइड्स, सूक्ष्म पोषक तत्व	12%	5%
ड्रिप सिंचाई प्रणाली एवं स्प्रेंकलर्स	12%	5%
कृषि, बागवानी या वानिकी की मिट्टी की तैयारी, खेती, कटाई एवं मंडाई की मशीनें	12%	5%

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में राहत

वस्तुएँ	पहले जीएसटी दर	अब जीएसटी दर
ट्रैक्टर के टायर एवं पुर्जे	18%	5%
ट्रैक्टर	12%	5%
निर्दिष्ट जैव-कीटनाशक एवं सूक्ष्म पोषक तत्व	12%	5%
ड्रिप सिंचाई प्रणाली एवं स्प्रेंकलर	12%	5%
कृषि, बागवानी या वानिकी हेतु मिट्टी की तैयारी, खेती, कटाई एवं मंडाई की मशीनें	12%	5%

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में राहत

वस्तुएँ	पहले जीएसटी दर	अब जीएसटी दर
व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा	18%	शून्य
थर्मामीटर	18%	5%
चिकित्सीय ग्रेड ऑक्सीजन	12%	5%
सभी डायग्नोस्टिक किट एवं अभिकर्मक	12%	5%
ग्लूकोमीटर एवं टेस्ट स्ट्रिप्स	12%	5%
दृष्टि सुधारक चश्मे	12%	5%

ऑटोमोबाइल को किफायती बनाया गया

वाहनों की श्रेणी	पहले जीएसटी दर	अब जीएसटी दर
पेट्रोल एवं पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कारें (1200 सीसी एवं 4000 मिमी तक)	28%	18%
डीज़ल एवं डीज़ल हाइब्रिड कारें (1500 सीसी एवं 4000 मिमी तक)	28%	18%
तिपहिया वाहन	28%	18%
मोटरसाइकिलें (350 सीसी एवं उससे कम)	28%	18%
माल परिवहन हेतु मोटर वाहन	28%	18%

सस्ती शिक्षा

शैक्षणिक वस्तुएँ	पहले जीएसटी दर	अब जीएसटी दर
मानचित्र, चार्ट एवं ग्लोब	12%	शून्य
पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन एवं पेस्टल	12%	शून्य
अभ्यास पुस्तिकाएँ एवं नोटबुक	12%	शून्य
रबर (इरेज़र)	12%	शून्य

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर बचत करें

इलेक्ट्रॉनिक/घरेलू उपकरण	पहले जीएसटी दर	अब जीएसटी दर
एयर कंडीशनर	28%	18%
टेलीविज़न (32 इंच से ऊपर) (एलईडी एवं एलसीडी टीवी सहित)	28%	18%
मॉनिटर एवं प्रोजेक्टर	28%	18%
बर्तन धोने की मशीनें	28%	18%





प्रक्रिया सुधार

पंजीकरण (Registration)

- आवेदकों को स्वचालित पंजीकरण 3 कार्य दिवसों के भीतर मिलेगा, जिन्हें सिस्टम द्वारा डाटा विश्लेषण के आधार पर चुना जाएगा।
- यह तब लागू होगा जब आवेदक यह निर्धारित करे कि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) ₹2.5 लाख प्रति माह से अधिक नहीं होगा और वह इस योजना का विकल्प चुनता है।

रिफंड (Refund)

- उचित अधिकारी द्वारा सिस्टम-आधारित जोखिम मूल्यांकन के माध्यम से प्रावधिक रिफंड (Provisional Refund) की स्वीकृति दी जाएगी, निम्नलिखित मामलों में:
 - शून्य-कर (Zero Rated) आपूर्ति
 - उल्टे शुल्क संरचना (Inverted Duty Structure) के अंतर्गत आपूर्ति

रैमन मैगसेसे पुरस्कार 2025

31 अगस्त 2025 को एजुकेट गर्ल्स (आधिकारिक नाम: फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली) ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जब यह रैमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय संगठन बना। एशिया के इस प्रतिष्ठित सम्मान से संगठन को उन लड़कियों की शिक्षा के लिए किए गए अथक प्रयासों हेतु सम्मानित किया गया है, जो भारत के सबसे दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों में स्कूल से बाहर हैं।

इस वर्ष के अन्य पुरस्कार विजेताओं में मालदीव की शाहिना अली (पर्यावरण संरक्षण में योगदान) और फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा (फिलीपींस) (हाशिए पर खड़े समुदायों के सहयोग हेतु) शामिल हैं।

एजुकेट गर्ल्स: दृष्टि और उपलब्धियाँ

- स्थापना: 2007, सेफीना हुसैन द्वारा (लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातक)
- उद्देश्य: भारत में लड़कियों की निरक्षरता मिटाना और हर बालिका को स्कूल तक पहुँचाना।
- हुसैन ने सैन फ्रांसिस्को की कॉरपोरेट नौकरी छोड़कर भारत लौटकर इस मिशन की शुरुआत की।

प्रभाव (Impact at Scale)

- राजस्थान के रेगिस्तानी गाँवों से शुरुआत।
- अब तक 20 लाख+ लड़कियों का नामांकन और स्कूल में बनाए रखना।
- 30,000+ गाँवों तक विस्तार।
- 90% से अधिक स्कूल रिटेंशन रेट।

नवाचार: डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड (DIB)

2015 में शिक्षा क्षेत्र का विश्व का पहला DIB मॉडल शुरू किया गया। इसमें निवेशकों की राशि को मापनीय शैक्षिक परिणामों से जोड़ा गया। इस मॉडल ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया और ग्रामीण शिक्षा सुधार की नई राहें खोलीं।

प्रगति कार्यक्रम: युवतियों को सशक्त बनाना

- 15-29 वर्ष की किशोरियों और युवा महिलाओं के लिए खुला स्कूलिंग कार्यक्रम।
- 300 से शुरू होकर आज 31,500+ शिक्षार्थियों को शिक्षा और बेहतर जीवन अवसर उपलब्ध करा रहा है।

पुरस्कार मिलने का कारण

रैमन मैगसेसे अवॉर्ड फाउंडेशन (RMAF) के अनुसार, एजुकेट गर्ल्स को “लड़कियों और युवतियों की शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक रूढ़ियों को तोड़ने, निरक्षरता की बेड़ियों से मुक्त करने और उन्हें कौशल, साहस व स्वायत्तता के साथ उनके पूर्ण मानवीय सामर्थ्य तक पहुँचाने की प्रतिबद्धता” के लिए चुना गया।

रैमन मैगसेसे पुरस्कार: समझ और महत्व

- स्थापना: 1957, रॉकफेलर ब्रदर्स फंड और फिलीपींस सरकार द्वारा।
- उद्देश्य: एशिया में उत्कृष्ट नेतृत्व, सत्यनिष्ठा और लोकसेवा का सम्मान।
- इसे अक्सर “एशियाई नोबेल पुरस्कार” कहा जाता है।
- अब तक 300+ व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया जा चुका है।

भारतीय प्राप्तकर्ता (कुछ प्रमुख):

- अरविंद केजरीवाल (2006)
- रविश कुमार (2019)
- बेजवाड़ा विल्सन (2016)
- सोनम बांगचुक (2018)

पुरस्कार समारोह और विरासत

- हर वर्ष 7 नवंबर को मनीला (फिलीपींस) के मेट्रोपॉलिटन थियेटर में प्रदान किया जाता है।
- यह पुरस्कार रामोन डेल फियरो मैगसेसे (फिलीपींस के राष्ट्रपति, जन्म: 31 अगस्त 1907) की स्मृति में दिया जाता है।
- उनकी पहचान एक द्वितीय विश्वयुद्ध सेनानी, मैकेनिक और ईमानदार, जनता-केन्द्रित नेता के रूप में थी।
- 1957 में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में यह पुरस्कार शुरू हुआ, जो “लोकसेवा में आत्मा की महानता” का प्रतीक है।

सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए

9 सितंबर 2025 को सी.पी. राधाकृष्णन, जो पूर्व तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार बी. सुधर्शन रेड्डी—जो वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं—को पराजित किया। इस चुनाव में 98.3% की उच्च मतदान दर दर्ज हुई, जो सांसदों की एकजुटता और सक्रिय भागीदारी को दर्शाती है।

चुनाव परिणाम और मतदान

- राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता मत मिले, जबकि न्यायमूर्ति रेड्डी को 300 मत प्राप्त हुए।
- 15 मत अमान्य घोषित किए गए।
- 781 योग्य सांसदों में से 767 ने मतदान किया, जो 98.20% मतदान दर रही।
- 13 सांसदों ने मतदान से परहेज किया, जिनमें बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति, शिरोमणि अकाली दल और एक निर्दलीय सांसद शामिल थे।

152 मतों के अंतर से मिली इस जीत ने न केवल एनडीए की संसदीय शक्ति को प्रमाणित किया बल्कि विपक्ष के भीतर संभावित क्रॉस-वोटिंग को भी उजागर किया—जो आंतरिक असहमति या रणनीतिक बदलाव का संकेत है।

रिक्ति की पृष्ठभूमि

उपराष्ट्रपति का पद 21 जुलाई 2025 से रिक्त था, जब जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। समय से पहले हुए इस चुनाव ने संवैधानिक निरंतरता सुनिश्चित की और एनडीए की स्थिर संसदीय भूमिकाओं पर जोर को प्रदर्शित किया।





सी.पी. राधाकृष्णन कौन हैं?

- पूरा नाम: चंद्रापुरम पोनुसामी राधाकृष्णन
- जन्म: 20 अक्टूबर 1957, तिरुप्पुर, तमिलनाडु
- शिक्षा: बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक
- दीर्घकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जुड़े

राजनीतिक करियर

- दो बार लोकसभा सांसद (कोयंबटूर: 1998 और 1999)
- तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष
- विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य
- 2016 से 2020 तक काँयर बोर्ड अध्यक्ष, जिनके कार्यकाल में काँयर निर्यात ने रिकॉर्ड बनाए
- 2020 से 2022 तक भाजपा के केरल प्रभारी
- झारखंड के राज्यपाल, फिर तेलंगाना व पुडुचेरी के अतिरिक्त प्रभार, और जुलाई 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त

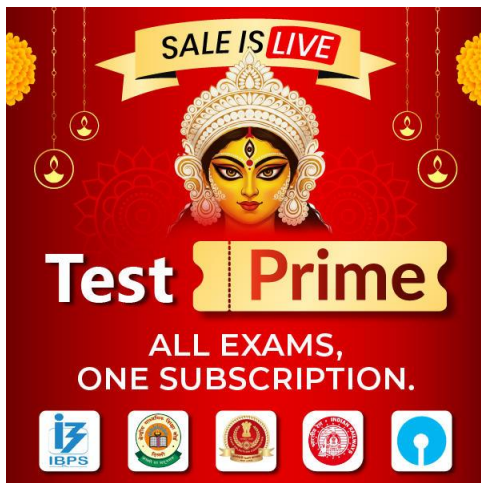
अन्य योगदान राजनीति से परे, वे टेबल टेनिस, क्रिकेट और वॉलीबॉल जैसे खेलों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका में कई अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व भी किया है। उनकी प्रशासनिक दक्षता और राजनीतिक निष्ठा उन्हें राज्यसभा के सभापति जैसे संवैधानिक पद की जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त बनाती है।

चुनाव का महत्व

- एनडीए की रणनीतिक जीत: परिणाम ने संसद में एनडीए की पकड़ को सिद्ध किया और विपक्ष की एकजुटता की कमी उजागर की।
- अनुभव और स्थिरता: राधाकृष्णन का दशकों का अनुभव संसदीय कार्यवाही के संचालन में सहायक होगा।
- राजनीतिक संकेत: अमान्य और अनुपस्थित मतों का पैटर्न विपक्षी गठबंधनों की आंतरिक स्थिति पर प्रश्नचिह्न लगाता है।
- भूमिका की निरंतरता: इस नियुक्ति से भारत के शीर्ष संवैधानिक पदों में स्थिरता बनी रहती है।

मुख्य तथ्य

- चुनाव तिथि: 9 सितंबर 2025
- विजेता: सी.पी. राधाकृष्णन (452 मत)
- प्रतिद्वंद्वी: न्यायमूर्ति बी. सुधर्शन रेड्डी (300 मत)
- अमान्य मत: 15
- कुल मतदान: 767 में से 781 सांसद (98.20%)



Larry Ellison बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, एलन मस्क को छोड़ा पीछे

सॉफ्टवेयर कंपनी Oracle के को-फाउंडर लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। लैरी ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को पीछे छोड़कर पहली बार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होने की उपलब्धि हासिल की है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑरेकल कॉर्प द्वारा उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजों की घोषणा और भविष्य में और भी ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद जताए जाने के बाद, न्यूयॉर्क में बुधवार (10 सितंबर 2025) सुबह 10:10 बजे तक लैरी एलिसन की संपत्ति 101 अरब डॉलर तक बढ़ गई।

सबसे बड़ी बढ़ोतरी

ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार, लैरी एलिसन की संपत्ति में बढ़ोतरी की वजह से उनकी कुल संपत्ति यानी नेट वर्थ 393 अरब डॉलर हो गई। जबकि, एलन मस्क की कुल संपत्ति 385 अरब डॉलर है। ये इंडेक्स द्वारा दर्ज की गई एक दिन में अभी तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। बताते चलें कि एलन मस्क साल 2021 में पहली बार दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बने थे। लेकिन बाद में वे अमेजन के जेफ बेजोस और LVMH के बर्नार्ड अर्नाल्ट के हाथों पीछे हो गए। हालांकि, मस्क ने एक बार फिर वापसी की और पिछले साल एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए और 300 से भी ज्यादा दिनों तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने रहे।

इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के लिए एक आक्रामक दृष्टिकोण

81 साल के लैरी एलिसन, जिन्होंने ऑरेकल की सह-स्थापना की और अब कंपनी के चेयरमैन और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं। ऑरेकल के शेयर, जो इस साल मंगलवार के बंद भाव तक पहले ही 45% बढ़ चुके थे, बुधवार को 41% तक बढ़ गए, जब कंपनी ने बुकिंग में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की और अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के लिए एक आक्रामक दृष्टिकोण दिया। ये कंपनी की अभी तक की सबसे बड़ी एक दिवसीय वृद्धि है।

दुनिया के पहले खरबपति बन सकते हैं एलन मस्क

वहीं दूसरी ओर, टेस्ला के शेयरों का भाव इस साल करीब 13% गिर चुका है। कंपनी के बोर्ड ने मस्क के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर का एक बड़ा वेतन पैकेज प्रस्तावित किया है, अगर वे कई महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने में सफल रहे तो वे दुनिया के पहले ट्रिलेनियर बन सकते हैं।

नेपाल को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री मिलीं

नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की अब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। उन्हें जनरेशन-ज़ी (Gen-Z) विरोध आंदोलन के नेताओं द्वारा अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। यह निर्णय उस युवा-नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद लिया गया जिसने पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर किया और नेपाल की जमी-जमाई राजनीतिक व्यवस्था को हिला कर रख दिया।

73 वर्षीय कार्की ने 12 सितंबर 2025 को शपथ ली, जो राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, नेपाली सेना के नेतृत्व और Gen-Z प्रतिनिधियों के बीच हुई सहमति के बाद संभव हुआ।

जनरेशन-ज़ी विद्रोह

- यह आंदोलन मुख्यतः युवा नेपालियों के नेतृत्व में हुआ, जो भ्रष्टाचार और शासन की विफलताओं से निराश थे।
- सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश ने विरोध को और भड़का दिया।
- हिंसक झड़पों में 30 से अधिक लोगों की मौत और 1,000 से अधिक घायल हुए।





- इस विद्रोह ने पुराने राजनीतिक नेताओं के बड़े पैमाने पर इस्तीफों को मजबूर किया, जिससे नेपाल की राजनीति में पीढ़ीगत बदलाव सामने आया।
- वैकल्पिक नेतृत्व के लिए काठमांडू के मेयर बलेन्द्र शाह (बैलेन) और कुलमान घिसिंग (पूर्व प्रमुख, नेपाल विद्युत प्राधिकरण) के नामों पर भी चर्चा हुई, लेकिन अंततः सुशीला कार्की उनकी साफ छवि और भ्रष्टाचार-विरोधी रुख के कारण सर्वसम्मत विकल्प बनीं।

सुशीला कार्की कौन हैं?

- जन्म: 7 जून 1952, बिराटनगर, नेपाल

शिक्षा

- बी.ए., महेन्द्र मोरंग कैम्पस, नेपाल (1972)
- एम.ए. (राजनीति विज्ञान), बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, भारत (1975)
- एलएलबी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल (1978)

कानूनी करियर

- 1979 से वकालत शुरू की
- 2007 में वरिष्ठ अधिवक्ता बनीं

न्यायपालिका

- 2009 में अस्थायी सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त
- 2010 में स्थायी जज बनीं
- नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश (जुलाई 2016 – जून 2017)
- भ्रष्टाचार के प्रति शून्य-सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध, जिसने उन्हें राजनीतिक अभिजात वर्ग के साथ टकराव में ला दिया।
- 2017 में उन पर महाभियोग लाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कार्यकाल पूरा किया।
- न्यायिक स्वतंत्रता और साहसिक निर्णयों के कारण उन्हें आज का आदर्श अंतरिम नेता माना जा रहा है।

अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में उनकी प्राथमिकताएँ

- अशांति के हफ्तों के बाद नेपाल को स्थिर करना।
- 6-12 महीनों के भीतर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना।
- शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर जनता का विश्वास बहाल करना।

हालाँकि उनके सामने नेपाल की गहरी राजनीतिक विभाजन रेखाएँ, आर्थिक मंदी और नाजुक लोकतांत्रिक संस्थाओं की चुनौतियाँ होंगी।

क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व

- भारत और चीन के बीच स्थित नेपाल का भू-राजनीतिक महत्व अत्यधिक है।
- कार्की का नेतृत्व न केवल पीढ़ीगत बदलाव का संकेत है बल्कि महिला नेतृत्व की ऐतिहासिक उपलब्धि भी है, जो दक्षिण एशिया में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को प्रेरित कर सकती है।
- भारत-नेपाल संबंधों पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि कार्की ने भारत में पढ़ाई की है और उनके अकादमिक रिश्ते सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत कर सकते हैं।

एमी अवार्ड्स 2025: विजेताओं और मुख्य आकर्षणों की पूरी सूची

77वें प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स, जो 14 सितम्बर 2025 को लॉस एंजेलिस के पीकॉक थिएटर में आयोजित हुए, ने 2024-2025 सीज़न की बेहतरीन टेलीविज़न प्रस्तुतियों को प्रदर्शित किया। यह आयोजन CBS पर लाइव प्रसारित हुआ और Paramount+ पर स्ट्रीम किया गया। पूरी रात कहानी कहने की कला, रचनात्मकता और विभिन्न शैलियों में दमदार प्रदर्शन का भव्य उत्सव रहा। रोमांचक ड्रामा से लेकर धारदार कॉमेडी, क्रांतिकारी लिमिटेड सीरीज़ से लेकर प्रभावशाली वैरायटी शो तक, इस आयोजन ने टीवी की दुनिया में वर्ष के सबसे उत्कृष्ट योगदानों को मान्यता दी। समारोह में कई यादगार जीत, भावनात्मक भाषण और विशेष क्षण देखने को मिले। खासतौर पर Severance, Adolescence और The Studio जैसे शो ने विभिन्न श्रेणियों में बाज़ी मारी, जबकि क्रिस्टिन मिलियोटी, सेठ रोगन और ब्रिट लोअर जैसे कलाकारों ने शीर्ष सम्मान अपने नाम किए।

एमी पुरस्कार 2025 विजेताओं की पूरी सूची

मेजर सीरीज़ अवार्ड्स

श्रेणी (Category)	विजेता (Winner)
ड्रामा श्रृंखला	Severance
कॉमेडी श्रृंखला	The Studio
सीमित श्रृंखला	Adolescence
टेलीविज़न फ़िल्म	Bridget Jones: Mad About the Boy
टॉक श्रृंखला	Last Week Tonight With John Oliver
रियलिटी प्रतियोगिता कार्यक्रम	The Traitors
पटकथा आधारित वैरायटी श्रृंखला	Last Week Tonight With John Oliver

अभिनय पुरस्कार

श्रेणी (Category)	विजेता (Winner)
मुख्य अभिनेत्री – ड्रामा	ब्रिट लोअर, Severance
मुख्य अभिनेता – ड्रामा	स्टर्लिंग के. ब्राउन, Paradise
सहायक अभिनेत्री – ड्रामा	कैथरीन ला नासा, The Pitt
सहायक अभिनेता – ड्रामा	ट्रामेल टिलमैन, Severance
मुख्य अभिनेत्री – कॉमेडी	जीन स्मार्ट, Hacks
मुख्य अभिनेता – कॉमेडी	सेथ रोगन, The Studio
सहायक अभिनेत्री – कॉमेडी	हैना आइनबिंडर, Hacks
सहायक अभिनेता – कॉमेडी	जेफ हिलर, Somebody Somewhere
मुख्य अभिनेत्री – सीमित श्रृंखला	क्रिस्टिन मिलियोटी, The Penguin
मुख्य अभिनेता – सीमित श्रृंखला	स्टीफन ग्राहम, Adolescence
सहायक अभिनेत्री – सीमित श्रृंखला	एरिन डोहर्टी, Adolescence
सहायक अभिनेता – सीमित श्रृंखला	ओवेन कूपर, Adolescence





लेखन पुरस्कार

श्रेणी (Category)	विजेता (Winner)
लेखन – ड्रामा श्रृंखला	डैन गिलरॉय, Andor
लेखन – कॉमेडी श्रृंखला	सेथ रोगन और इवान गोल्डबर्ग, The Studio
लेखन – सीमित श्रृंखला	जैक थॉर्न और स्टीफन ग्राहम, Adolescence
लेखन – विविधता श्रृंखला	Last Week Tonight With John Oliver

निर्देशन पुरस्कार

श्रेणी (Category)	विजेता (Winner)
निर्देशन – ड्रामा श्रृंखला	एडम रैंडल, Slow Horses
निर्देशन – कॉमेडी श्रृंखला	सेथ रोगन और इवान गोल्डबर्ग, The Studio
निर्देशन – सीमित श्रृंखला	फिलिप बरांटीनी, Adolescence

विविधता और विशेष

श्रेणी (Category)	विजेता (Winner)
विविधता विशेष (लाइव)	SNL50: द एनिवर्सरी स्पेशल

कैबिनेट की मंजूरी

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) के तहत महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। छह वर्षों (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31) की अवधि वाली यह योजना ई-कचरे, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रेप और जीवन-अंत वाहनों से निकलने वाले उत्प्रेरक कन्वर्टर के पुनर्चक्रण में सहयोग करेगी। यह संयंत्र और मशीनरी पर 20% पूंजीगत व्यय सब्सिडी और वृद्धिशील बिक्री से जुड़ी परिचालन व्यय सब्सिडी प्रदान करती है। लाभ की सीमा बड़ी संस्थाओं के लिए 50 करोड़ रुपये और छोटी इकाइयों के लिए 25 करोड़ रुपये है, जो स्थापित खिलाड़ियों और स्टार्ट-अप दोनों को प्रोत्साहित करती है। इस योजना का उद्देश्य 270 किलो टन वार्षिक पुनर्चक्रण क्षमता बनाना, 40 किलो टन महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन, 8,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना और 70,000 रोजगार सृजित करना है।
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेलवे लाइन खंड (177 किमी) के दोहरीकरण को 3,169 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दे दी है। यह परियोजना रेलवे की गतिशीलता, दक्षता और सेवा विश्वसनीयता को बढ़ाएगी, भीड़भाड़ को कम करेगी और पीएम-गति शक्ति के तहत मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। यह देवघर (बाबा बैद्यनाथ धाम) और तारापीठ (शक्ति पीठ) जैसे महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ेगी, जिससे तीन आकांक्षी जिलों (बांका, गोड्डा, दुमका) सहित 441 गाँवों और 28.72 लाख लोगों को लाभ होगा। इस परियोजना से 15 मिलियन टन प्रति वर्ष अतिरिक्त माल ढुलाई संभव होगी, तेल आयात में 5 करोड़ लीटर की कमी आएगी और 24 करोड़ किलोग्राम CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी, जो 1 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

- सीसीईए ने बिहार में बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के मोकामा-मुंगेर 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड सेक्शन (82.4 किमी) के निर्माण को हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) पर 4,447.38 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दे दी है। यह कॉरिडोर मोकामा, बड़हिया, लखीसराय, जमालपुर, मुंगेर और भागलपुर को जोड़ेगा, जिससे आयुध कारखानों, लोकोमोटिव वर्कशॉप, खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स हब और भागलपुरी रेशमी वस्त्र जैसे क्षेत्रीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। 100 किमी/घंटा की डिज़ाइन गति के साथ, यह परियोजना यात्रा के समय को घटाकर 1.5 घंटे कर देगी, साथ ही सुरक्षा और माल ढुलाई को भी बेहतर बनाएगी। इससे 14.83 लाख मानव-दिवस प्रत्यक्ष रोजगार और 18.46 लाख मानव-दिवस अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है, जिससे पूर्वी बिहार में आर्थिक विकास को और गति मिलेगी।

संसदीय समाचार

अक्टूबर माह की राज्यवार महत्वपूर्ण घटनाएँ

आंध्र प्रदेश

- ज्य ने 3,400 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की: तिरुपति में 400 करोड़ रुपये का स्पेस सिटी और मदकासिरा में 3,000 करोड़ रुपये का रक्षा विनिर्माण केंद्र।

असम

- असम ने 2 सितंबर, 2025 (अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस) पर भारत का पहला गिद्ध पोर्टल - www.thevulturenetwork.org - लॉन्च किया, जिसे गिद्ध संरक्षण के लिए गुवाहाटी विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा विकसित किया गया है।

बिहार

- कैबिनेट ने कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ₹4,447 करोड़ की मोकामा-मुंगेर ग्रीनफील्ड राजमार्ग परियोजना (82.4 किमी) को मंजूरी दी।
- बिहार को कृषि-निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला एपीडा कार्यालय मिला; पहली जीआई-टैग वाली मिथिला मखाना खेप को हरी झंडी दिखाई गई।
- राजगीर में 4 सितंबर, 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री शेरींग तोबगे और केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू द्वारा रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा।

गोवा

- गोवा 23 सितंबर, 2025 को प्रथम विश्व स्तर पर निश्चित तिथि वाले आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा, जिसका विषय होगा "लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद"।

गुजरात

- भारत की पहली मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोलिंग प्रणाली चोर्यासी में शुरू की गई, जिससे बाधा-मुक्त फास्टैग टोलिंग संभव हो गई।

हिमाचल प्रदेश

- शिमला में उल्लास मेला 2025 में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा घोषित राज्य ने राष्ट्रीय औसत को पार करते हुए 99.3% साक्षरता दर हासिल की।
- प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ₹1,500 करोड़ के बाढ़ राहत पैकेज की घोषणा की गई जिसमें घरों का पुनर्निर्माण, राजमार्गों की मरम्मत और अनुग्रह राशि शामिल है।





महाराष्ट्र

- सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने के बाद गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने कर्नाटक और तमिलनाडु के अनुरूप निजी क्षेत्र में 10-12 घंटे की शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने वाले संशोधनों को मंजूरी दी।

मणिपुर

- मणिपुर चिड़ियाघर ने भारत में एशियाई विशालकाय कछुए का पहला कृत्रिम ऊष्मायन किया, जिसमें संरक्षण के लिए 28 बच्चे पैदा हुए।

मध्य प्रदेश

- प्रधानमंत्री मोदी ने कपड़ा, निर्यात और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया।

ओडिशा

- ओडिशा 450 ई-बसों के साथ भारत में 5वें स्थान पर, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश से आगे; सीआरयूटी प्रमुख शहरों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट टिकटिंग और क्यूआर/एनसीएमसी भुगतान के साथ 1,000 से अधिक बसों का बेड़ा बढ़ाएगा।

तमिलनाडु

- केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने तूतीकोरिन बंदरगाह पर 59 करोड़ रुपये की लागत वाली हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र और बंदरगाह अवसंरचना परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

उत्तराखंड

- प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड के लिए ₹1,200 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की, जिसमें अनुग्रह राशि और बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण शामिल हैं।
- भारत और एडीबी ने टिहरी गढ़वाल में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे 87,000 निवासियों को लाभ होगा।

पंजाब

- प्रधानमंत्री मोदी ने गुरदासपुर में हवाई सर्वेक्षण के बाद बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए 1,600 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की, जो पहले दी गई 12,000 करोड़ रुपये की सहायता के अतिरिक्त है।

उत्तर-पूर्व (क्षेत्रीय)

- प्रधानमंत्री मोदी 8,000 करोड़ रुपये की आइजोल रेल लाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जो मिजोरम को पहली बार भारतीय रेलवे से जोड़ेगी।

सितंबर माह के शुभारंभ और उद्घाटन

- भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास सुविधा का उद्घाटन नोएडा (ऑप्टिमस और कॉर्निंग) में किया गया, ₹70 करोड़ का निवेश, 25 मिलियन यूनिट/वर्ष चरण 1 क्षमता।
- बाधा-मुक्त फास्टैग टोलिंग के लिए गुजरात के चोर्यासी में भारत की पहली एमएलएफएफ टोलिंग प्रणाली का शुभारंभ किया गया।
- संताली, भिली, मुंडारी, गोंडी जनजातीय भाषाओं के लिए आदि वाणी एआई अनुवादक का शुभारंभ किया गया।
- एनसीईआरटी ने बाल वाटिका टीवी चैनल, दीक्षा 2.0, प्रशस्त 2.0 के साथ 65वां स्थापना दिवस मनाया।

- भारत ने अंतरिक्ष उपयोग के लिए अपने पहले स्वदेशी रूप से विकसित 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर विक्रम-3201 का अनावरण किया।
- प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने 4.8 मिलियन टीईयू क्षमता वाले भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल, पीएसए मुंबई टर्मिनल चरण-II का उद्घाटन किया।
- स्वच्छता उत्सव 2025: सरकार ने स्वच्छ उत्सव और सफाई मित्र सुरक्षा पर केंद्रित एक पखवाड़े तक चलने वाला स्वच्छता अभियान (17 सितंबर - 2 अक्टूबर) शुरू किया।
- पावर टेस्टिंग लैब: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नासिक में सीपीआरआई की क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया।
- आदि संस्कृति मंच: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 45 से अधिक पाठ्यक्रमों और 5,000 से अधिक सांस्कृतिक संपत्तियों के साथ डिजिटल शिक्षण मंच का शुभारंभ किया।
- विदेश में अटल नवाचार केंद्र: धर्मेन्द्र प्रधान ने आईआईटी दिल्ली-अबू धाबी परिसर में भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया।
- आईआईएम अहमदाबाद वैश्विक परिसर: आईआईएमए ने 35-छात्रों वाले एमबीए कार्यक्रम के साथ दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला।
- SAJEX 2025: सऊदी अरब आभूषण प्रदर्शनी का जेद्दा में शुभारंभ, जिसमें 200 से अधिक प्रदर्शक जीसीसी बाजारों को लक्षित कर रहे हैं।
- ज्ञान भारतम पोर्टल: प्रधानमंत्री मोदी ने पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और वैश्विक अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया।
- एमएनआरई ने 10 गीगावाट क्षमता का दोहन करने के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय नीति का अनावरण किया।
- आईआरडीएआई दिसंबर 2025 में बीमा सुगम (डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म) लॉन्च करेगा।

महत्वपूर्ण त्योहार

विविध राष्ट्रीय समाचार

- भारत-जापान ने अन्वेषण और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- डिजिलॉकर और ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1,938 ई-सरकारी सेवाओं को एकीकृत किया गया।
- ग्रामीण महिलाओं की वित्तीय साक्षरता के लिए IEPFA ने हैदराबाद में निवेशक दीदी चरण II का शुभारंभ किया।
- प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में महिला उद्यमियों के लिए ₹105 करोड़ की राज्य जीविका निधि का शुभारंभ किया।
- MSP कपास खरीद को सुव्यवस्थित करने के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया गया।
- नारियल विकास बोर्ड ने पौध सहायता को ₹4→₹45 से बढ़ाकर ₹40→₹350 कर दिया।
- APEDA ने 100 कृषि-खाद्य स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए BHARATI स्टार्टअप पहल शुरू की, 2030 तक 50 बिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा।
- कैबिनेट ने 2030-31 तक 270 KT क्षमता के लक्ष्य के साथ ₹1,500 करोड़ की महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण योजना को मंजूरी दी।





- UPSC उत्कृष्टता केंद्र को UPSC और राज्य PSCs के लिए ज्ञान केंद्र के रूप में घोषित किया गया।
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए 26 न्यायाधीशों की सिफारिश की।
- भारत ने 1 सितंबर, 2025 से नए बीआईएस मानक के साथ एचयूआईडी-आधारित चांदी हॉलमार्किंग शुरू की।
- केंद्र ने एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) नियमों को अधिसूचित किया, जिससे सेवा अवधि घटकर 20 वर्ष हो गई।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों को 2025 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।
- सरकार ने PMAY-U 2.0 के अंतर्गत अंगीकार 2025 अभियान शुरू किया, जो 5,000 से अधिक शहरों में 31 अक्टूबर तक चलेगा।
- नीति आयोग ने 2047 तक दालों का उत्पादन दोगुना करके 51.57 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है।
- कोयला आयात: मानसून में मंदी और उच्च स्टॉक उपलब्धता के कारण जुलाई 2025 में 16.4% घटकर 21.08 मीट्रिक टन रह गया।
- सड़क अवसंरचना को बढ़ावा: भारत ने 2033 तक एक्सप्रेसवे को 17,000 किलोमीटर तक विस्तारित करने के लिए ₹11 लाख करोड़ की योजना का अनावरण किया।
- रेलवे परियोजना: कैबिनेट ने भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेल लाइन दोहरीकरण के लिए ₹3,169 करोड़ की मंजूरी दी।
- नमो भारत ट्रेन: दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस 160 किमी/घंटा की गति से भारत की सबसे तेज़ ट्रेन बन गई, जिसने एक घंटे से भी कम समय में 55 किमी की दूरी तय की।
- ग्रेट निकोबार परियोजना: रणनीतिक समुद्री और विमानन केंद्र विकसित करने के लिए ₹72,000 करोड़ की योजना।
- पूर्वोत्तर और पूर्वी परियोजनाएँ: प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में ₹71,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया।
- एनएचपीसी प्रमुख: भूपेंद्र गुप्ता एनएचपीसी लिमिटेड के सीएमडी नियुक्त।
- उपराष्ट्रपति: सीपी राधाकृष्णन ने 12 सितंबर, 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।
- साक्षरता दर: भारत की साक्षरता दर 2011 में 74% से बढ़कर 2023-24 में 80.9% हो गई।
- सेना बाढ़ बचाव: ऑपरेशन राहत के तहत 6,000 से अधिक लोगों को निकाला गया और 13,000 से अधिक लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई।
- सेना संभव प्रणाली: ऑपरेशन सिंदूर में एन्क्रिप्शन युक्त स्वदेशी 5G प्रणाली ने व्हाट्सएप की जगह ले ली।
- भारत-मॉरीशस संबंध: विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समुद्र विज्ञान और अंतरिक्ष सहयोग में 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर।
- इमिग्रेशन फ्रास्ट ट्रेक: एफटीआई-टीटीपी का 13 हवाई अड्डों तक विस्तार किया गया, जिससे 30 सेकंड में निकासी संभव हो गई।
- पर्पल फेस्ट 2025: आईएसएलआरटीसी और एमिटी विश्वविद्यालय द्वारा 10-11 सितंबर को दिव्यांगजन समावेशन का जश्न मनाया गया।
- नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धि: भारत ने 250 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता हासिल की; 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य।
- राष्ट्रीय सर्वेक्षण: एनएसओ वित्त और कृषि पर एआईडीआईएस और एसएस सर्वेक्षण (जुलाई 2026-जून 2027) आयोजित करेगा।

राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स: अगस्त 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति वक्तव्य 2025-26: विस्तृत विश्लेषण

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 56वीं बैठक 4-6 अगस्त, 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में डॉ. नागेश कुमार, श्री सौगत भट्टाचार्य, प्रो. राम सिंह, डॉ. पूनम गुप्ता और डॉ. राजीव रंजन भी उपस्थित थे।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) की 56वीं बैठक

दिनांक: 4 से 6 अगस्त, 2025

स्थान: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

अध्यक्षता: गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा द्वारा

अन्य सदस्य:

- डॉ. नागेश कुमार
- श्री सौगाता भट्टाचार्य
- प्रो. राम सिंह
- डॉ. पूनम गुप्ता
- डॉ. राजीव रंजन

मुख्य निर्णय

रेपो दर को 5.50% पर स्थिर रखा गया।

अन्य प्रमुख दरें:

- स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF): 5.25%
- मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) और बैंक रेट: 5.75%

निर्णय का उद्देश्य

यह निर्णय RBI के दोहरे लक्ष्य को संतुलित करता है:

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति को 4% $\pm$ 2% के दायरे में बनाए रखना
- आर्थिक वृद्धि को समर्थन देना

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति (2025-26) का विस्तृत विश्लेषण – वृद्धि और मुद्रास्फीति परिदृश्य

वैश्विक परिदृश्य

- IMF द्वारा वृद्धि अनुमानों में संशोधन के बावजूद वैश्विक आर्थिक वृद्धि धीमी बनी हुई है।
- डिसइंफ्लेशन (मुद्रास्फीति में गिरावट) की रफ्तार कम हो गई है और कुछ विकसित देशों में मुद्रास्फीति में फिर से वृद्धि देखी जा रही है।
- व्यापारिक तनाव, टैरिफ बदलाव, और नीति अनिश्चितताएं चिंता के विषय हैं।

घरेलू अर्थव्यवस्था

- आर्थिक वृद्धि लचीली बनी हुई है।
- निजी खपत (विशेषकर ग्रामीण मांग) और स्थिर पूंजी निवेश में मजबूती दिखाई दे रही है, जिसे सरकार के मजबूत पूंजीगत व्यय से समर्थन मिल रहा है।

कृषि क्षेत्र:

- दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य रहा और खरीफ बुवाई अच्छी रही।





सेवा क्षेत्र:

- निर्माण और व्यापार के नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।

औद्योगिक क्षेत्र:

- वृद्धि असमान है — बिजली और खनन क्षेत्र पीछे हैं।

GDP वृद्धि अनुमान (2025-26): 6.5%

तिमाही	अनुमानित वृद्धि दर
Q1	6.5%
Q2	6.7%
Q3	6.6%
Q4	6.3%
Q1 2026-27	6.6%

मुद्रास्फीति परिदृश्य

वर्तमान स्थिति (जून 2025):

- CPI मुद्रास्फीति: 2.1% (पिछले 77 महीनों में सबसे कम) — लगातार आठवीं बार गिरावट।
- खाद्य मुद्रास्फीति: -0.2% (ऋणात्मक) — फरवरी 2019 के बाद पहली बार।
- कोर मुद्रास्फीति: बढ़कर 4.4% — मुख्यतः सोने की कीमतों में वृद्धि के कारण।

2025-26 के लिए मुद्रास्फीति अनुमान: 3.1%

तिमाही	अनुमानित CPI मुद्रास्फीति
Q2	2.1%
Q3	3.1%
Q4	4.4%
Q1 2026-27	4.9%

प्रमुख जोखिम

- मौसम संबंधित झटके (फसल उत्पादन पर असर)
- वैश्विक अनिश्चितताएं और व्यापार विवाद
- बाद की तिमाहियों में नीतिगत उपायों से उत्पन्न मांग दबाव

रेपो दर को यथावत रखने का कारण

- मुद्रास्फीति नियंत्रण:
 - फिलहाल लक्ष्य से नीचे है, पर वर्ष के अंत तक 4% से ऊपर जाने की संभावना है।
- आर्थिक वृद्धि स्थिर:
 - GDP वृद्धि अनुमान 6.5% पर स्थिर है।
- पिछली कटौतियों का असर:
 - फरवरी 2025 से अब तक 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की जा चुकी है — इनके पूर्ण प्रभाव की प्रतीक्षा की जा रही है।
- वैश्विक अनिश्चितताएं:
 - व्यापार और पूंजी प्रवाह पर टैरिफ तनाव का प्रभाव संभव।
- तटस्थ मौद्रिक रुख (Neutral Stance):
 - MPC आगे के निर्णय डेटा आधारित मूल्यांकन के आधार पर लेगी।

परीक्षा की दृष्टि से प्रमुख बिंदु

- रेपो रेट: 5.50% (बिना बदलाव)
- GDP वृद्धि (2025-26): 6.5%
- CPI मुद्रास्फीति (2025-26): 3.1% (Q4 में 4% से ऊपर जाने की संभावना)
- दर में बदलाव नहीं: पूर्व की कटौतियों का प्रभाव समय के साथ दिखेगा; मुद्रास्फीति में फिर से वृद्धि संभव
- प्रमुख जोखिम: मौसम, वैश्विक व्यापार तनाव, आयात/निर्यात में बाधा
- अगली MPC बैठक: 29 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2025

भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहर 2025: देखें क्या आपका शहर सूची में है

सुरक्षा किसी भी शहर की रहने योग्य होने की क्षमता तय करने वाले सबसे अहम कारकों में से एक है, और 2025 में भारत का शहरी सुरक्षा मानचित्र कुछ दिलचस्प पैटर्न दिखा रहा है। मिड-2025 नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार, भारत वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान पर है, जिसकी सुरक्षा स्कोर 55.8 है। हालांकि राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार की गुंजाइश अभी भी मौजूद है, लेकिन कुछ शहर सुरक्षा और शांति के प्रतीक बनकर उभरे हैं, जो अपने नागरिकों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करते हैं।

ताज़ा रिपोर्ट में मैंगलोर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है, जिसके बाद वडोदरा, अहमदाबाद और सूरत का नाम आता है—जो सुरक्षा रैंकिंग में गुजरात की मज़बूत मौजूदगी को दर्शाता है। दूसरी ओर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के शहर जैसे दिल्ली, नोएडा और गाज़ियाबाद अब भी गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहर 2025

नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स शहरों का मूल्यांकन अपराध दर, कानून प्रवर्तन की दक्षता और सुरक्षा को लेकर जनता की धारणा जैसे कारकों के आधार पर करता है। अधिक सेफ्टी इंडेक्स का मतलब है कम अपराध और बेहतर सार्वजनिक सुरक्षा।

भारत में रैंक	शहर, राज्य	सेफ्टी इंडेक्स	क्राइम इंडेक्स	वैश्विक रैंक
1	मैंगलोर, कर्नाटक	74.2	25.8	49
2	वडोदरा, गुजरात	69.2	30.8	85
3	अहमदाबाद, गुजरात	68.2	31.8	93
4	सूरत, गुजरात	66.6	33.4	106
5	जयपुर, राजस्थान	65.2	34.8	118
6	नवी मुंबई, महाराष्ट्र	63.5	36.8	126
7	तिरुवनंतपुरम, केरल	61.1	38.9	149
8	चेन्नई, तमिलनाडु	60.3	37.9	158
9	पुणे, महाराष्ट्र	58.7	41.3	167
10	चंडीगढ़	57.4	42.6	175





मुख्य बिंदु

मैंगलोर न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सुरक्षा के मामले में 49वें स्थान पर है। गुजरात ने तीन शहरों—वडोदरा, अहमदाबाद और सूरत—के साथ सूची में दबदबा बनाया है। दक्षिणी शहर जैसे तिरुवनंतपुरम, चेन्नई और मैंगलोर ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जो बेहतर शहरी शासन और सामुदायिक अनुशासन को दर्शाता है।

सिक्के का दूसरा पहलू - सबसे असुरक्षित शहर

जहाँ शीर्ष शहर सुरक्षा में चमक रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) अब भी पिछड़ा रहा है। दिल्ली, नोएडा और गाज़ियाबाद भारत के सबसे असुरक्षित शहरों में शामिल हैं, जहाँ ऊँची अपराध दर और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं।

वैश्विक तुलना में भारत

वैश्विक स्तर पर अबू धाबी लगातार नौवें वर्ष दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर का ताज अपने पास बनाए हुए है, जिसकी सुरक्षा रेटिंग 88.8 है। दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में मध्य पूर्व का दबदबा है, जहाँ दोहा, दुबई और शारजाह भी शीर्ष पाँच में शामिल हैं।

दुनिया के टॉप 5 सबसे सुरक्षित शहर (2025)

1. अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात - 88.8
2. दोहा, कतर - 84.3
3. दुबई, संयुक्त अरब अमीरात - 83.9
4. शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात - 83.7
5. ताइपेई, ताइवान - 83.6

सुरक्षा रैंकिंग कैसे तय की गई

नुम्बो सेफ्टी इंडेक्स दैनिक जीवन में, दिन और रात दोनों समय, सुरक्षा को लेकर जनता की धारणा पर आधारित है। प्रतिभागी अपने अनुभवों और चिंताओं के आधार पर अपने शहर को रेट करते हैं, जिनमें शामिल हैं—

- व्यक्तिगत सुरक्षा: लूटपाट, चोरी, कार चोरी, अजनबियों द्वारा शारीरिक हमला, और सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न का जोखिम।
- भेदभाव: त्वचा के रंग, जातीयता, लिंग या धर्म जैसे कारकों के आधार पर।
- संपत्ति संबंधी अपराध: तोड़फोड़, संधमारी और चोरी जैसे अपराध।
- हिंसक अपराध: हमले और हत्या जैसे गंभीर अपराध।

इन सभी इनपुट्स को बाद में सेफ्टी इंडेक्स (उच्च स्कोर का मतलब अधिक सुरक्षित) और क्राइम इंडेक्स (उच्च स्कोर का मतलब कम सुरक्षित) में परिवर्तित किया जाता है।

संशोधित आयकर विधेयक, 2025: करदाताओं और निवेशकों के लिए ज़रूरी जानकारियाँ

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विधेयक, 2025 के पुराने मसौदे को लोकसभा से औपचारिक रूप से वापस लेकर संसद में नया संशोधित मसौदा पेश किया है। यह नया प्रारूप व्यापक समीक्षा और सुझावों का परिणाम है, जिसमें चयन समिति (Select Committee) की लगभग 285 सिफारिशें शामिल की गई हैं। इसका उद्देश्य भारत के प्रत्यक्ष कर ढाँचे को आधुनिक और सरल बनाना है तथा 1961 के आयकर अधिनियम को प्रतिस्थापित करना है।

पुराना विधेयक क्यों वापस लिया गया?

फरवरी 2025 के बजट सत्र में पेश किए गए प्रारंभिक विधेयक को तत्काल समीक्षा हेतु चयन समिति को भेजा गया था। प्रमुख कारण थे:

- मसौदे में असंगतियाँ और तकनीकी त्रुटियाँ
- कानूनी भाषा और शब्दावली में सुधार की आवश्यकता
- हितधारकों और समिति से मिले व्यापक फीडबैक के आधार पर स्पष्ट और एकीकृत विधेयक की ज़रूरत
- कई संस्करणों से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना

नए विधेयक की संरचना और मुख्य विशेषताएँ

- सरल भाषा: विधायी शब्दावली को स्पष्ट किया गया है। विरोधाभासी प्रावधानों को हटाया गया है ताकि विवाद कम हों।
- संगठित प्रावधान: अब 536 धाराएँ और 16 अनुसूचियाँ हैं, जबकि पुराने कानून में 298 धाराएँ थीं।
- “कर वर्ष” (Tax Year) की अवधारणा: “पिछला वर्ष” और “मूल्यांकन वर्ष” की दोहरी व्यवस्था को हटाकर एकल कर-वर्ष प्रणाली लागू की गई है।
- डिजिटल-प्रथम दृष्टिकोण: CBDT को डिजिटल प्रशासन और स्वचालन को बढ़ावा देने के लिए अधिक शक्तियाँ दी गई हैं, जिनमें फेसलेस प्रोसेस भी शामिल है।
- कोई तात्कालिक कर-स्लैब परिवर्तन नहीं: दरें और आय श्रेणियाँ फिलहाल वही रखी गई हैं। ध्यान केवल प्रक्रियाओं और कागजी काम को सरल बनाने पर है।

चयन समिति की प्रमुख सिफारिशें

करदाता लाभ और राहत

- विलंबित रिटर्न पर भी रिफंड का दावा संभव होगा।
- धारा 80M पुनः लागू: अंतर-कार्पोरेट डिविडेंड पर छूट।
- NIL-TDS सुविधा: जिन पर कर देयता नहीं है, उन्हें अग्रिम NIL-TDS प्रमाणपत्र मिल सकेगा।
- खाली मकानों पर अनुमानित किराया कर समाप्त।
- 30% कटौती की स्पष्ट गणना: केवल नगर निगम कर घटाने के बाद।
- गृह ऋण व्याज पर कटौती: किराए पर दी गई संपत्ति (let-out property) पर भी उपलब्ध।

अनुपालन और प्रक्रिया सुधार

- अग्रिम निर्णय (Advance Ruling) शुल्क संरचना सरल।
- दंडात्मक शक्तियों और TDS पर स्पष्ट नियम।
- MSME की परिभाषा सीधे MSME अधिनियम से जोड़ी गई।
- कानूनी भाषा, धारा क्रम और संपत्ति शब्दावली में सुधार।
- पेंशन छूट का विस्तार: अब गैर-कर्मचारियों को भी commuted pension पर छूट मिलेगी।

शीर्ष 10 बदलाव एक नज़र में

1. देर से दाखिल रिटर्न पर भी रिफंड मिलेगा।
2. धारा 80M के तहत अंतर-कार्पोरेट डिविडेंड पर छूट।
3. NIL-TDS प्रमाणपत्र सुविधा।
4. खाली मकान पर अनुमानित किराया कर समाप्त।
5. 30% कटौती केवल नगर निगम कर घटाने के बाद।
6. किराए पर दी गई संपत्ति पर भी गृह ऋण व्याज कटौती।





7. प्रक्रियात्मक नियमों में पारदर्शिता और स्पष्टता।
8. MSME की परिभाषा अधिनियम से संरेखित।
9. कानूनी भाषा और धारा संदर्भ सुधारा।
10. पेंशन कटौती का दायरा गैर-कर्मचारियों तक विस्तारित।

करदाताओं और निवेशकों के लिए इसका क्या अर्थ है?

- सरलता और पारदर्शिता: कर अनुपालन आसान होगा, वित्तीय योजना स्पष्टता से की जा सकेगी।
- विवादों में कमी: अस्पष्ट प्रावधानों को हटाकर मुकदमों की संभावना घटेगी।
- डिजिटल इंडिया को समर्थन: कर दाखिल और रिफंड प्रक्रिया तेज़ होगी, भ्रष्टाचार-रहित माहौल को बढ़ावा मिलेगा।
- निवेशकों का विश्वास: MSME और अचल संपत्ति जैसे क्षेत्रों में स्पष्ट परिभाषाओं से निवेश में अनिश्चितता घटेगी।

ऑपरेशन सिन्दूर: सशस्त्र बलों के वीरों को घोषित हुए वीरता पुरस्कार

स्वतंत्रता दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों को वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की, जिन्होंने ऑपरेशन सिन्दूर में निर्णायक भूमिका निभाई। यह त्रि-सेवा (थलसेना, वायुसेना और नौसेना) अभियान था, जिसका लक्ष्य पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकी ढांचे को ध्वस्त करना था। इन पुरस्कारों के माध्यम से असाधारण साहस, संचालन क्षमता और उत्कृष्ट सेवा का सम्मान किया गया है, जो भारत की सबसे निर्णायक आतंकवाद-रोधी कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है।

पृष्ठभूमि: ऑपरेशन सिन्दूर

- यह ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया था, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) की प्रॉक्सी द रेसिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली थी।
- ऑपरेशन में तीनों सेनाओं का संयुक्त अभियान शामिल था:
 - भारतीय थलसेना ने पाकिस्तान और PoK में स्थित जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 9 आतंकी अड्डों को नष्ट किया।
 - भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के भीतर 4 और PoK में 5 ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए।
 - भारतीय नौसेना ने भारतीय भूमि से परिचालनात्मक समर्थन प्रदान किया।

प्रमुख घोषित पुरस्कार

1. सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक (SYSM) – युद्धकालीन उत्कृष्ट सेवा का सर्वोच्च पुरस्कार
 - 4 अधिकारियों को प्रदान किया गया, जिनमें वायुसेना और नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल:
 - एयर मार्शल नरदेश्वर तिवारी – एयर स्टाफ
 - एयर मार्शल जितेन्द्र मिश्रा – पश्चिमी वायु कमांडर
 - एयर मार्शल अवधेश भारती – महानिदेशक (एयर ऑपरेशन्स)
 - वाइस एडमिरल एस. जे. सिंह – पूर्व पश्चिमी नौसैनिक कमांडर
 - इसके अतिरिक्त थलसेना के दो वरिष्ठ अधिकारियों को भी यह सम्मान मिला।

2. उत्तम युद्ध सेवा पदक (UYSM)

- वाइस एडमिरल तरुण सोबती – उप नौसेनाध्यक्ष

3. युद्ध सेवा पदक (YSM) – युद्धकालीन उत्कृष्ट सेवा हेतु

- 13 वायुसेना अधिकारियों को प्रदान किया गया, जिनमें शामिल हैं:
 - एयर वाइस मार्शल जोसेफ सुवारेस
 - एयर वाइस मार्शल प्रजुअल सिंह
 - एयर कमांडर अशोक राज ठाकुर

4. वायु सेना पदक (VM) – वायु अभियानों में असाधारण साहस हेतु

- 26 अधिकारियों को प्रदान किया गया, जिनमें शामिल हैं:
 - ग्रुप कैप्टन अंकुर हकीम
 - ग्रुप कैप्टन वरुण भोज (फ्लाईंग)
 - विंग कमांडर मयंक पालीवाल (फ्लाईंग)
 - स्क्वाड्रन लीडर कौस्तुभ नलावडे (फ्लाईंग)
 - फ्लाइट लेफ्टिनेंट ए. नवीन चंदर (प्रशासन/फाइटर कंट्रोलर)

5. वीर चक्र – असाधारण बहादुरी के कार्य हेतु

- जिन अधिकारियों को सम्मानित किया गया, उनमें शामिल हैं:
 - ग्रुप कैप्टन रणजीत सिंह सिद्धू
 - ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा
 - स्क्वाड्रन लीडर सार्थक कुमार
 - फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्शवीर सिंह ठाकुर

महत्व

ये पुरस्कार न केवल व्यक्तिगत वीरता और कौशल का सम्मान करते हैं, बल्कि ऑपरेशन सिन्दूर को भारत के आतंकवाद-रोधी अभियानों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर भी सिद्ध करते हैं। इस मिशन ने प्रदर्शित किया:

- त्रि-सेना का उत्कृष्ट समन्वय
- आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी परिचालन क्षमता
- अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ पार किए बिना रणनीतिक सटीक हमले

प्रधानमंत्री मोदी का 79वां स्वतंत्रता दिवस भाषण: मुख्य बिंदु

15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस संबोधन (103 मिनट) दिया। इस भाषण में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, प्रौद्योगिकी नवाचार और जन-सशक्तिकरण पर जोर देते हुए रक्षा, अर्थव्यवस्था, कृषि, ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक सुधारों और प्रमुख पहलों का खाका प्रस्तुत किया। उनका संदेश स्पष्ट था — भारत अब एक आत्मविश्वासी वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है।

प्रमुख घोषणाएँ और नीतिगत मुख्य बिंदु

1. रणनीतिक स्वायत्तता और सुरक्षा

- ऑपरेशन सिन्दूर: पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरी तरह स्वदेशी हथियारों से पाकिस्तान-आधारित आतंकी ढांचे को ध्वस्त किया गया। संदेश स्पष्ट — भारत परमाणु ब्लैकमेल स्वीकार नहीं करेगा।
- सिंधु जल संधि पर रुख: “खून और पानी साथ नहीं बह सकते” — भारत अपने जल संसाधनों को देशहित में सुरक्षित रखेगा।
- मिशन सुदर्शन चक्र: उन्नत हथियार प्रणाली का विकास, ताकि 2035 तक पूरे देश के लिए त्वरित और सटीक रक्षा कवच तैयार हो सके।





2. आत्मनिर्भर भारत और तकनीकी स्वावलंबन

- स्वदेशी सेमीकंडक्टर: वर्ष 2025 में पहला मेड-इन-इंडिया चिप तैयार होगा।
- न्यूक्लियर सेक्टर में निजी भागीदारी: ऊर्जा और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु।
- युवाओं का आह्वान: स्वदेशी जेट इंजन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उर्वरक और अन्य आवश्यक तकनीकों के निर्माण की चुनौती।

3. ऊर्जा और संसाधन आत्मनिर्भरता

- राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन: रक्षा और उद्योग हेतु 1,200 स्थलों की खोज।
- डीपवॉटर एक्सप्लोरेशन मिशन: समुद्री ऊर्जा का दोहन, विदेशी ईंधन निर्भरता घटाने हेतु।
- स्वच्छ ऊर्जा उपलब्धि: भारत ने 2025 में ही 50% स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य हासिल किया (लक्ष्य से पाँच वर्ष पहले)।
- न्यूक्लियर विस्तार: 2047 तक क्षमता में 10 गुना वृद्धि; 10 नए रिएक्टर निर्माणाधीन।

4. आर्थिक और शासन सुधार

- नेक्स्ट-जेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टास्क फोर्स: नियमों और कानूनों में व्यापक सुधार।
- 40,000+ अनुपालनों और 1,500 पुराने कानूनों को हटाया गया।
- GST सुधार (दिवाली 2025 तक): आवश्यक वस्तुओं पर कर घटाकर MSMEs और स्थानीय व्यापारियों को लाभ।

5. रोजगार और जनसांख्यिकीय लाभांश

- पीएम विकसित भारत रोजगार योजना: ₹1 लाख करोड़ की योजना, नए नियोजित युवाओं को ₹15,000 प्रोत्साहन, 3 करोड़ लाभार्थियों का लक्ष्य।
- भारत की जनसंख्या क्षमता को आर्थिक ताकत में बदलने पर फोकस।

6. स्वास्थ्य सेवा और फार्मा नेतृत्व

- दवा आत्मनिर्भरता: भारत अपनी वैक्सीन और जीवनरक्षक दवाएँ स्वयं विकसित करेगा।
- शोधकर्ताओं को फार्मा और मेडिकल डिवाइस में पेटेंट सुरक्षित करने हेतु प्रोत्साहन।

7. कृषि और ग्रामीण समृद्धि

- किसानों को भारत की "समृद्धि की रीढ़" बताया।
- पीएम धान्य-धान्य कृषि योजना: 100 पिछड़े कृषि जिलों के लिए।
- भारत की उपलब्धियाँ:
 - दूध, दलहन, जूट में विश्व #1
 - चावल, गेहूँ, कपास, फल, सब्जियों में विश्व #2
- कृषि निर्यात ₹4 लाख करोड़ पार।

8. अंतरिक्ष और नवाचार नेतृत्व

- भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की तैयारियाँ जारी।

- 300 से अधिक स्पेस स्टार्टअप उपग्रह तकनीक और डीप स्पेस मिशनों पर कार्यरत।

9. राष्ट्रीय एकता और सीमा सुरक्षा

- हाई-पावर्ड डेमोग्राफी मिशन: अवैध घुसपैठ से निपटने और सीमावर्ती आजीविकाओं की सुरक्षा हेतु।

विकसित भारत 2047 का दृष्टिकोण

पीएम मोदी का विज़न स्पष्ट है:

- अहम क्षेत्रों में तकनीकी प्रभुत्व
- पूर्ण ऊर्जा आत्मनिर्भरता
- वैश्विक प्रतिस्पर्धी कृषि
- जन-नेतृत्व वाला नवाचार
- सुरक्षित सीमाएँ और आंतरिक स्थिरता

यह भाषण भारत के लिए एक दीर्घकालिक रोडमैप है, जो स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक "विकसित भारत" की परिकल्पना को मूर्त रूप देने की दिशा दिखाता है।

अंबानी 2025 हरुन इंडिया की सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय सूची में शीर्ष पर

भारत के पारिवारिक व्यवसाय साम्राज्य देश की आर्थिक तस्वीर पर लगातार छाए हुए हैं। अंबानी परिवार लगातार दूसरे वर्ष 2025 बार्कलेज प्राइवेट क्लाइट्स हरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिज़नेस लिस्ट में शीर्ष पर रहा है। ₹28.2 लाख करोड़ के चौकाने वाले मूल्यांकन (जो भारत के जीडीपी का लगभग बारहवाँ हिस्सा है) के साथ अंबानी परिवार पैमाने और प्रभाव दोनों में अपने समकक्षों से बहुत आगे है।

अंबानी परिवार – ₹28.2 लाख करोड़

मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ऊर्जा, दूरसंचार, खुदरा और डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपना दबदबा बनाए हुए है। 1957 में स्थापित यह समूह आज भी भारत की औद्योगिक शक्ति का केंद्र है। अंबानियों की संपत्ति में इस वर्ष 10% की वृद्धि हुई, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी निरंतर विकास को दर्शाती है।

बिरला और जिंदल परिवार – दूसरे और तीसरे स्थान पर

- कुमार मंगलम बिरला परिवार – ₹6.5 लाख करोड़
- चौथी पीढ़ी का आदित्य बिरला समूह इस वर्ष ₹1.1 लाख करोड़ बढ़कर दूसरे स्थान पर पहुँचा। इसकी विरासत 1850 के दशक से जुड़ी है और सीमेंट, दूरसंचार, एल्युमिनियम और वित्तीय सेवाओं तक फैली हुई है।
- जिंदल परिवार – ₹5.7 लाख करोड़
- सज्जन जिंदल के नेतृत्व में जेएसडब्ल्यू स्टील ने जिंदल परिवार को तीसरे स्थान पर पहुँचाया। इस वर्ष 21% वृद्धि दर्ज की गई, जो धातु और खनन क्षेत्र में उछाल को दर्शाती है।

शीर्ष तीन परिवारों (अंबानी, बिरला और जिंदल) का संयुक्त मूल्यांकन ₹40.4 लाख करोड़ है, जो फिलिपींस की जीडीपी के बराबर है।





शीर्ष 10 भारतीय पारिवारिक व्यवसाय 2025

रैंक	परिवार का नाम	कंपनी	मूल्यांकन (₹ करोड़)	नेतृत्वकर्ता	क्षेत्र
1	अंबानी	रिलायंस इंडस्ट्रीज़	28,23,100	मुकेश अंबानी	ऊर्जा
2	बिरला	आदित्य बिरला समूह	6,47,700	कुमार मंगलम बिरला	सीमेंट
3	जिंदल	जेएसडब्ल्यू स्टील	5,70,900	सज्जन जिंदल	धातु
4	बजाज	बजाज समूह	5,64,200	संजीव बजाज	वित्तीय सेवाएँ
5	महिंद्रा	महिंद्रा एंड महिंद्रा	5,43,800	आनंद महिंद्रा	ऑटोमोबाइल
6	नादर	एचसीएल टेक्नोलॉजीज़	4,68,900	रोशनी नादर मल्होत्रा	आईटी सेवाएँ
7	मुरुगप्पा	चोलामंडलम फ़ाइनेंस	2,92,400	वेल्लायन मुन्बैया	वित्त
8	प्रेमजी	विप्रो	2,78,600	ऋषद प्रेमजी	आईटी सेवाएँ
9	अनिल अग्रवाल	हिंदुस्तान जिंक	2,55,000	अनिल अग्रवाल	धातु
10	दानी-चोकसी-वकील	एशियन पेंट्स	2,20,900	आर. शेषसायी	रसायन

RBI का फ्री-एआई फ्रेमवर्क: भारतीय वित्तीय क्षेत्र में नैतिक एआई को आकार देना

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वित्तीय सेवाओं को नए सिरे से गढ़ रही है—धोखाधड़ी की पहचान से लेकर ऋण मूल्यांकन तक। लेकिन यदि इसके लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश न हों, तो यह जोखिमों को और बढ़ा सकती है। इस बदलाव को सही दिशा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने दिसंबर 2024 में एक समिति गठित की, ताकि वित्तीय क्षेत्र के लिए फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ़ एआई (FREE-AI) तैयार किया जा सके। इसका उद्देश्य सरल किंतु महत्वाकांक्षी है: नवाचार को बढ़ावा देना और साथ ही विश्वास, निष्पक्षता एवं स्थिरता की रक्षा करना।

समिति, कार्यदिश और कार्यप्रणाली

यह समिति आईआईटी बॉम्बे के डॉ. पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता में बनी, जिसमें नीति, उद्योग और शिक्षाविद् जगत के विशेषज्ञ शामिल थे। समिति को निम्न कार्य सौंपे गए:

- एआई अपनाने की स्थिति का आकलन करना
- वैश्विक दृष्टिकोणों की समीक्षा करना
- जोखिमों की पहचान करना
- भारत के लिए उपयुक्त शासन-ढाँचा सुझाना

समिति ने चार-आयामी कार्यप्रणाली अपनाई:

1. विभिन्न हितधारकों से व्यापक परामर्श
2. बैंकों/एनबीएफसी/फिनटेक कंपनियों पर दो राष्ट्रीय सर्वेक्षण (DoS और FTD)
3. वैश्विक मानकों और कानूनों का अध्ययन
4. RBI के मौजूदा दिशा-निर्देशों (आईटी, साइबर सुरक्षा, आउटसोर्सिंग, डिजिटल लेंडिंग और उपभोक्ता संरक्षण) की खामियों का विश्लेषण

अवसर: जहाँ एआई मूल्य जोड़ता है

एआई उत्पादकता बढ़ाने का वादा करता है—प्रक्रियाओं के स्वचालन, व्यक्तिगत ग्राहक अनुभव (बहुभाषी चैट/वॉयस), जोखिम विश्लेषण में सुधार, और वैकल्पिक डाटा के ज़रिए वित्तीय समावेशन द्वारा। भारत की विविधता बहुभाषी और क्षेत्र-अनुकूल मॉडल (कुशल SLMs और LTD “त्रिमूर्ति” मॉडल सहित) की माँग करती है, साथ ही सुरक्षित प्रयोगों को तेज़ करने के लिए जेनएआई (GenAI) नवाचार सैंडबॉक्स की ज़रूरत है।

जोखिम परिदृश्य: क्या गलत हो सकता है

रिपोर्ट मॉडल और परिचालन जोखिमों को रेखांकित करती है—पक्षपात, अपारदर्शिता, भ्रमित परिणाम (hallucinations), मॉडल का अस्थिर होना (drift), डाटा में गड़बड़ी (poisoning), प्रतिकूल प्रॉम्प्ट्स, और थर्ड-पार्टी पर अत्यधिक निर्भरता। इसमें प्रणालीगत चिंताएँ (भीड़-चाल, procyclicality) और साइबर सुरक्षा खतरों (स्वचालित फ़िशिंग, डीपफेक्स) का भी उल्लेख है। गैर-निश्चित (non-deterministic) प्रणालियों में दायित्व जटिल होता है और उपभोक्ता संरक्षण के लिए स्पष्ट खुलासा और एआई-आधारित निर्णयों को चुनौती देने की व्यवस्था आवश्यक है।

वैश्विक नीति परिप्रेक्ष्य और भारत की स्थिति

दृष्टिकोण अलग-अलग हैं:

- यूरोपीय संघ (EU AI Act): क्षेत्रीय, जोखिम-आधारित नियम
- सिंगापुर: टूलकिट (FEAT/Veritas) और मार्गदर्शन का मिश्रण
- यूके/यूएस: सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण
- चीन: एआई प्रकार के अनुसार विनियमन

भारत का रुख नवाचार समर्थक लेकिन सुरक्षा-संतुलित है, जिसे IndiaAI मिशन (₹10,372 करोड़) और AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट (AISII) का समर्थन प्राप्त है, जो मॉडलों का मूल्यांकन करेगा और सुरक्षित व भरोसेमंद एआई को बढ़ावा देगा।

सात सूत्र (मूल सिद्धांत) और छह रणनीतिक स्तंभ

समिति ने अपनाने के लिए सात सूत्र स्पष्ट किए:

1. विश्वास (Trust)
2. लोग पहले (People First)
3. संयम से अधिक नवाचार (Innovation over Restraint)
4. निष्पक्षता और समानता (Fairness & Equity)
5. उत्तरदायित्व (Accountability)
6. समझने योग्य डिज़ाइन (Understandable by Design)
7. सुरक्षा, लचीलापन और स्थिरता (Safety, Resilience & Sustainability)

इनको छह स्तंभों से लागू किया गया है:

- अवसंरचना (Infrastructure): साझा डेटा/कंप्यूट, एआई इनोवेशन सैंडबॉक्स, सेक्टर मॉडल
- नीति (Policy): आनुपातिक, जोखिम-आधारित मार्गदर्शन; आउटसोर्सिंग व विक्रेता एआई पर स्पष्टता





- क्षमता (Capacity): बोर्ड से लेकर स्टाफ तक एआई साक्षरता, उत्कृष्टता केंद्र, साझा प्लेबुकस
- शासन (Governance): बोर्ड-स्वीकृत एआई नीति, जीवनचक्र नियंत्रण, प्रलेखन
- संरक्षण (Protection): उपभोक्ता खुलासा, निष्पक्षता परीक्षण, मानव हस्तक्षेप (human-in-the-loop)
- आश्वासन (Assurance): साइबर सुरक्षा में वृद्धि, घटना रिपोर्टिंग, स्वतंत्र ऑडिट

छब्बीस सिफारिशें: RBI क्या चाहता है

रिपोर्ट में मुख्य कदम सुझाए गए हैं:

- साझा कंप्यूट/डेटा ढाँचा बनाना
- GenAI सैंडबॉक्स शुरू करना
- देशी वित्तीय-ग्रेड मॉडल को बढ़ावा देना
- बोर्ड-स्वीकृत एआई नीतियाँ अनिवार्य करना
- उत्पाद अनुमोदन व ऑडिट दायरे में एआई को शामिल करना
- एआई-विशिष्ट साइबर सुरक्षा और घटना रिपोर्टिंग को मजबूत करना
- ग्राहकों को स्पष्ट बताना कि वे एआई से संवाद कर रहे हैं
- सेक्टर की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना
- कम-जोखिम वाले उपयोगों के लिए अनुपालन सरल बनाना

सर्वेक्षण निष्कर्ष: वर्तमान अपनाना और अंतराल

एआई अपनाना अभी उथला है: केवल 20.8% (127/612) विनियमित संस्थाएँ एआई का उपयोग कर रही हैं या विकसित कर रही हैं।

- टियर-1 शहरी सहकारी बैंक (UCBs): 0%
- टियर-2/3 UCBs: <10%
- एनबीएफसी: 27%
- एआरसी: 0%

सामान्य उपयोग:

- ग्राहक सहायता (15.6%)
- ऋण मूल्यांकन (13.7%)
- बिक्री/विपणन (11.8%)
- साइबर सुरक्षा (10.6%)

35% ने स्केलेबिलिटी के लिए पब्लिक क्लाउड को प्राथमिकता दी।

शासन क्षमता कमज़ोर है:

- ~1/3 के पास बोर्ड-स्तरीय निगरानी
- ~1/4 के पास औपचारिक घटना-प्रबंधन तंत्र

नियंत्रण और टूलिंग उपयोग:

- SHAP/LIME (15%)
- ऑडिट लॉग (18%)
- पक्षपात मान्यता (bias validation) 35% (मुख्यतः पूर्व-परिनियोजन)
- आवधिक पुनःप्रशिक्षण (37%)
- मॉडल ड्रिफ्ट निगरानी (21%)
- रीयल-टाइम निगरानी (14%)

मुख्य बाधाएँ: प्रतिभा की कमी, लागत/कंप्यूट सीमाएँ, डेटा गुणवत्ता और कानूनी अस्पष्टता।

इन ऑकड़ों का अर्थ

भारत में एआई अर्थव्यवस्था दो गति वाली बन सकती है—जहाँ बड़े बैंक आगे बढ़ेंगे और छोटे UCBs/NBFCs पीछे छूट जाएँगे। यही कारण है कि साझा अवसंरचना, स्पष्ट दिशा-निर्देश और क्षमता निर्माण FREE-AI का केंद्रीय तत्व है।

मौजूदा RBI नियमों से मेल

रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि FREE-AI कैसे मेल खाता है:

- आउटसोर्सिंग: विक्रेता एआई पर भी RE की ज़िम्मेदारी बनी रहेगी, एआई-विशिष्ट धाराएँ शामिल होंगी
- आईटी/साइबर सुरक्षा: मॉडल, डेटा पाइपलाइन, एक्सेस/ऑडिट ट्रेल्स पर भी नियंत्रण बढ़ेगा
- डिजिटल लेंडिंग: ऑडिट योग्य, समझने योग्य ऋण मॉडल; डेटा न्यूनतमकरण और सहमति
- उपभोक्ता संरक्षण: खुलासा और एआई परिणामों पर शिकायत निवारण साथ ही, मॉडल रजिस्टर, वंशावली (lineage) और ट्रेसबिलिटी का सुझाव है ताकि पर्यवेक्षण में आसानी हो।

आगे की राह (परीक्षा-उपयोगी बिंदु)

- एआई सैंडबॉक्स को कार्यान्वित करना
- बोर्ड नीति टेम्पलेट और घटना रिपोर्टिंग प्रारूप जारी करना
- बहुभाषी समावेशन मॉडल को बढ़ावा देना
- बोर्ड, जोखिम, ऑडिट और तकनीकी स्तर पर प्रशिक्षण बढ़ाना
- पारदर्शी, ऑडिट योग्य एआई सुनिश्चित करना—पक्षपात जाँच और मानव अपील विकल्प के साथ

कम-जोखिम उपयोगों (जैसे FAQ चैट) के लिए आनुपातिक अनुपालन मार्ग तेजी से अपनाने को बढ़ा सकता है, बिना सुरक्षा को कम किए।

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 पारित: ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा, रियल मनी गेमिंग पर प्रतिबंध

लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पारित कर भारत के डिजिटल मनोरंजन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स और सामाजिक ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देता है, वहीं हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर सख्त प्रतिबंध लगाता है, जिन्हें नशे, आर्थिक बर्बादी और आत्महत्याओं से जोड़ा गया है। यह कानून एक केंद्रीय नियामक ढांचा तैयार करता है जो क्षेत्र के विकास का मार्गदर्शन करेगा और युवाओं सहित संवेदनशील वर्गों की रक्षा करेगा।

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

तीन प्रमुख श्रेणियाँ

1. ई-स्पोर्ट्स (E-sports): कौशल आधारित, प्रतिस्पर्धी डिजिटल खेल, जिन्हें पेशेवर स्तर पर खेला जाता है।
2. सामाजिक ऑनलाइन खेल (Online Social Games): मनोरंजन के लिए खेले जाने वाले खेल, जिनमें कोई मौद्रिक इनाम नहीं होता।
3. ऑनलाइन मनी गेम्स (Online Money Games): ऐसे खेल जिनमें दांव या जमा राशि के बदले आर्थिक लाभ का वादा किया जाता है।





प्रोत्साहन और विनियमन

- ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा – विधेयक में ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण (Online Gaming Authority) के गठन का प्रावधान।
- यह प्राधिकरण नीतिगत समन्वय, नियामकीय निगरानी, गेम डेवलपर्स को सहयोग और अवसरचना विकास का कार्य करेगा।

ऑनलाइन मनी गेम्स पर सख्त प्रतिबंध

- वास्तविक पैसे वाले खेलों जैसे रमी, पोकर और अन्य जुए आधारित ऐप्स को चलाने, पेश करने या प्रोत्साहित करने पर पूरी तरह से रोक।
- ऐसे प्लेटफॉर्म अक्सर आसान कमाई का लालच देकर उपयोगकर्ताओं को फंसाते हैं और आत्महत्या, आर्थिक संकट एवं धोखाधड़ी की घटनाओं में वृद्धि से जुड़े पाए गए हैं।

दंड और प्रवर्तन तंत्र

- आपराधिक दायित्व:
 - उल्लंघन पर अधिकतम 3 वर्ष की कैद, ₹1 करोड़ का जुर्माना या दोनों।
 - बार-बार अपराध करने पर 3-5 वर्ष की कैद और ₹2 करोड़ तक का जुर्माना।
- राष्ट्रीय स्तर का ढांचा:
 - यह विधेयक पूरे देश में एक समान कानूनी ढांचा तैयार करता है, जिससे पहले मौजूद कानूनी अस्पष्टता समाप्त होगी।
 - केंद्र सरकार को ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक और सार्वजनिक हित व राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप नियंत्रण का अधिकार मिलेगा।

विधेयक की आवश्यकता क्यों थी?

- बिना नियंत्रण के तेज़ी से वृद्धि:
- पिछले दशक में डिजिटल विस्तार के दौरान कई वास्तविक पैसों पर आधारित गेमिंग प्लेटफॉर्म सामने आए, जो "कौशल आधारित" खेलों का दिखावा कर रहे थे।
- सामाजिक दुष्परिणाम:
 - बीते 31 महीनों में 32 आत्महत्याएँ सीधे-सीधे ऑनलाइन मनी गेम्स से जुड़े नुकसान के कारण।
 - देशभर में परिवारों ने दिवालियापन, कर्ज़ और मानसिक स्वास्थ्य संकट की शिकायतें दर्ज कराईं।
- आर्थिक और सुरक्षा खतरे:
- जाँच में सामने आया कि इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण में भी हुआ।

सरकार का दृष्टिकोण और समर्थन

- केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक सुरक्षित, नवाचारी और ज़िम्मेदार डिजिटल इंडिया के विज़न के अनुरूप है।
- उन्होंने जोर दिया कि स्टार्टअप्स को मज़बूत नियामकीय वातावरण में सहयोग मिलेगा ताकि रचनात्मकता और उद्यमिता को बढ़ावा मिले लेकिन जनहित से समझौता न हो।
- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस कानून की तात्कालिक आवश्यकता को रेखांकित किया और सभी दलों से सहयोग की अपील की।

प्रधानमंत्री मोदी की 2025 की जापान यात्रा के परिणामों की सूची

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा (29-30 अगस्त 2025) भारत-जापान द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव साबित हुई। 15वें वार्षिक भारत-जापान शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के नेताओं ने अगले दशक के सहयोग को गति देने वाले कई रणनीतिक समझौते किए। रक्षा और डिजिटल तकनीक से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण और स्वच्छ ऊर्जा तक, इस यात्रा ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षा, समृद्धि और स्थिरता की नींव रखी।

रणनीतिक दृष्टि: अगले दशक का खाका

भारत और जापान ने अगले दशक के लिए संयुक्त दृष्टि (India-Japan Joint Vision for the Next Decade) प्रस्तुत की, जिसमें सहयोग के आठ प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं:

- अर्थव्यवस्था
- आर्थिक सुरक्षा
- हरित विकास (Green Growth)
- प्रौद्योगिकी और नवाचार
- स्वास्थ्य
- गतिशीलता (Mobility)
- जन-से-जन संबंध
- राज्य-प्रिफेक्चर सहयोग

यह दृष्टि 2035 तक एक रोडमैप की तरह काम करेगी और रणनीतिक, आर्थिक व सामाजिक विकास को दिशा देगी।

रक्षा और सुरक्षा को सुदृढ़ करना

- संयुक्त सुरक्षा सहयोग घोषणा (Joint Declaration on Security Cooperation) पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे रक्षा संबंध और उन्नत हुए।
- इंडिया-जापान ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज प्लान के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 5 लाख कर्मियों के आदान-प्रदान का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें 50,000 कुशल भारतीय कार्यकर्ता शामिल होंगे।

तकनीकी सहयोग और डिजिटल भविष्य

- India-Japan Digital Partnership 2.0 की शुरुआत हुई, जिसमें समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत सहयोग होगा:
 - एआई, सेमीकंडक्टर, IoT और डिजिटल सार्वजनिक ढाँचे में
 - प्रतिभा विकास और स्टार्टअप इनक्यूबेशन में
 - संयुक्त अनुसंधान और नवाचार कार्यक्रमों में
- India-Japan AI Initiative भी लॉन्च किया गया, जिसके तहत बड़े भाषा मॉडल (LLMs) और विश्वसनीय एआई इकोसिस्टम के विकास में सहयोग होगा।

अंतरिक्ष और विज्ञान: चाँद की ओर

- चंद्रयान-5 लूनर पोलर मिशन के लिए कार्यान्वयन व्यवस्था (Implementing Arrangement) को अंतिम रूप दिया गया, जिससे इसरो (ISRO) और जैक्सा (JAXA) का सहयोग गहरा होगा।
- अतिरिक्त वैज्ञानिक कार्यक्रमों में शामिल:
 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर संयुक्त वक्तव्य
 - LOTUS कार्यक्रम और सकुरा साइंस के तहत आदान-प्रदान
 - क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायोटेक और जियोस्पैटियल साइंस में संयुक्त स्टार्टअप और शोध सहयोग





आर्थिक सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals)

- इंडिया-जापान इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव शुरू हुआ, जो केंद्रित है:
 - आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) की मजबूती
 - स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, दूरसंचार और महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग
 - संयुक्त भंडारण और प्रसंस्करण तकनीकों का विकास
- अगले दशक में ₹10 ट्रिलियन (जापानी येन) के निजी निवेश का लक्ष्य तय किया गया है।

स्वच्छ ऊर्जा और स्थिरता

दोनों देशों ने हरित सहयोग को बढ़ाने हेतु समझौते किए:

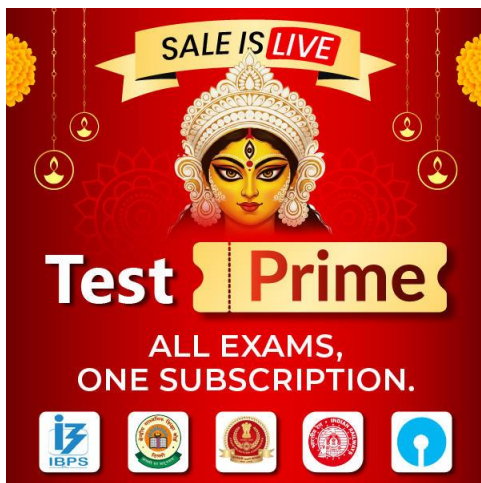
- क्लीन हाइड्रोजन और अमोनिया पर संयुक्त घोषणा
- जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज़्म (JCM) पर समझौता ज्ञापन
- सस्टेनेबल फ्यूल इनिशिएटिव, जिसमें बायोगैस और बायोफ्यूल शामिल हैं
- घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण पर MoU

कनेक्टिविटी और गतिशीलता

- नेक्स्ट-जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप लॉन्च हुई, जिसमें रेलवे, विमानन, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स शामिल हैं, और यह मेक इन इंडिया के तहत होगी।
- राज्य-प्रिफेक्चर सहयोग को बढ़ावा देने हेतु कंसाई और क्यूशू क्षेत्रों में उच्चस्तरीय आदान-प्रदान और व्यापार मंच आयोजित होंगे।

सांस्कृतिक और जन-केंद्रित कूटनीति

- सांस्कृतिक आदान-प्रदान MoU पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें शामिल हैं:
 - कला प्रदर्शनियाँ
 - संग्रहालय साझेदारी
 - संरक्षण प्रथाएँ
- शिक्षा और विदेशी सेवा सहयोग के लिए भारत के सुषमा स्वराज संस्थान और जापान के विदेश मंत्रालय के बीच MoU पर भी हस्ताक्षर हुए।



15वाँ भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का संयुक्त वक्तव्य

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत और जापान ने अपनी गहरी मित्रता को दोहराते हुए एक सुरक्षित, नवोन्मेषी और समृद्ध भविष्य के लिए साहसिक दृष्टि प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 29-30 अगस्त 2025 की जापान यात्रा के दौरान (15वाँ भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन), दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और जन-जन सहयोग में कई समझौतों के साथ अपने विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मज़बूत किया। इस सम्मेलन की मेज़बानी जापानी प्रधानमंत्री इशिबा शिगेरु ने की।

एक दशक की रणनीतिक प्रगति

दोनों नेताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों, सांस्कृतिक संबंधों और साझा रणनीतिक दृष्टिकोण पर आधारित भारत-जापान संबंधों के पिछले दशक के विस्तार पर विचार किया। 70 से अधिक संवाद तंत्रों के साथ यह रिश्ता एशिया की सबसे गतिशील साझेदारियों में से एक बन गया है, जिसमें समुद्री सुरक्षा से लेकर स्वच्छ प्रौद्योगिकी तक शामिल है।

सहयोग के तीन स्तंभ: रक्षा, अर्थव्यवस्था और आदान-प्रदान

1. रक्षा और सुरक्षा सहयोग

- संयुक्त सुरक्षा घोषणा-पत्र को अपनाया गया।
- वीर गार्जियन, तरंग शक्ति और मिलन जैसे अभ्यासों से सैन्य सहयोग और इंटरऑपरेबिलिटी में बढ़ोतरी।
- रक्षा प्रौद्योगिकी विकास और समुद्री सुरक्षा में संयुक्त प्रतिबद्धता।

2. आर्थिक और तकनीकी साझेदारी

- भारत-जापान आर्थिक सुरक्षा पहल का शुभारंभ → सेमीकंडक्टर, दूरसंचार, फार्मा और सप्लाइ-चेन लचीलापन पर फोकस।
- महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौता ज्ञापन (MoU)।
- भारत में जापानी निजी निवेश का लक्ष्य: ₹10 ट्रिलियन (पिछले लक्ष्य का दोगुना)।
- CEPA समझौते का उन्नयन, जिससे व्यापारिक रिश्ते और मज़बूत होंगे।

3. जन-जन और प्रतिभा आदान-प्रदान

- मानव संसाधन आदान-प्रदान कार्ययोजना – पाँच साल में 5 लाख लोगों का आदान-प्रदान, जिनमें 50,000 भारतीय पेशेवर जापान भेजे जाएंगे।
- जापानी भाषा और मैन्युफैक्चरिंग कौशल शिक्षा का विस्तार।
- फुकुओका में भारत का नया वाणिज्य दूतावास।

डिजिटल और एआई नवाचार – नई दिशा

- भारत-जापान डिजिटल साझेदारी 2.0 का शुभारंभ।
- एआई सहयोग पहल: AI और LLMs में संयुक्त अनुसंधान।
- संयुक्त R&D, स्टार्टअप इनक्यूबेशन, भारत में डेटा सेंटर।
- डिजिटल टैलेंट एक्सचेंज और उद्योग-शिक्षा मंच।

स्वच्छ ऊर्जा और अवसंरचना सहयोग

- स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी और हाइड्रोजन व अमोनिया पर संयुक्त घोषणा।
- मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल में शिकानसेन E10 ट्रेन और सिग्नलिंग सिस्टम।
- संयुक्त ऋण व्यवस्था (जेसीएम) के तहत सतत विकास सहयोग।

वैश्विक और क्षेत्रीय सहयोग

- Indo-Pacific साझेदारी → ASEAN केंद्रीयता, FOIP दृष्टि और QUAD सहयोग का समर्थन।
- एकट ईस्ट फोरम और अफ्रीका विकास पहल में सहयोग।





वैश्विक मुद्दों पर रुख

- यूक्रेन और गाज़ा में शांति का आह्वान, कूटनीति और मानवीय सहायता का समर्थन।
- उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण और अप्रैल 2025 पहलगाम आतंकी हमले की निंदा।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार की तात्कालिकता दोहराई, एक-दूसरे की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी का समर्थन।

उपलब्धियों का उत्सव और आगे की राह

- 2027 में भारत-जापान राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ विशेष आयोजनों के साथ मनाई जाएगी।
- 2025 को भारत-जापान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार आदान-प्रदान वर्ष घोषित किया गया, जो S&T सहयोग की 40वीं वर्षगांठ भी है।
- LUPEX चंद्र मिशन और उन्नत शैक्षणिक कार्यक्रम इस सहयोग का हिस्सा हैं।

एजुकेट गर्ल्स को 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलेगा

31 अगस्त 2025 को एजुकेट गर्ल्स (Foundation to Educate Girls Globally) ने इतिहास रचते हुए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन बनकर एशिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में जगह बनाई। यह पुरस्कार भारत के सबसे दूरदराज़ क्षेत्रों में स्कूल से बाहर रहने वाली लड़कियों के लिए शिक्षा की दिशा बदलने के इसके अथक प्रयासों की मान्यता है।

अन्य पुरस्कार विजेता 2025

- शाहिना अली (मालदीव) – पर्यावरण संरक्षण में योगदान
- फ्लावियानो एंटोनियो एल. विलानुएवा (फिलीपींस) – हाशिए पर खड़े समुदायों के समर्थन हेतु कार्य

एजुकेट गर्ल्स: दृष्टि और उपलब्धियाँ

- स्थापना: 2007, संस्थापक सफीना हुसैन (लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातक)
- प्रेरणा: सैन फ्रांसिस्को की कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ भारत लौटकर हर लड़की को स्कूल पहुँचाने का संकल्प
- शुरुआत: राजस्थान के रेगिस्तानी गाँवों से

बड़े पैमाने पर प्रभाव

- 20 लाख से अधिक लड़कियों का नामांकन और स्कूल में बनाए रखना
- भारत के 30,000+ गाँवों तक विस्तार
- 90% से अधिक स्कूल रिटेंशन रेट

नवाचार: डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड (DIB)

2015 में एजुकेट गर्ल्स ने शिक्षा में विश्व का पहला डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया। इसमें निवेशक के धन को मापनीय शैक्षिक परिणामों से जोड़ा गया। इस मॉडल को वैश्विक पहचान मिली और ग्रामीण भारत में शिक्षा सुधार के लिए नई राह बनी।

‘प्रगति’ कार्यक्रम: युवतियों को सशक्त बनाना

- उद्देश्य: 15-29 वर्ष की किशोरियों और युवा महिलाओं के लिए ओपन-स्कूलिंग प्रोग्राम
- शुरुआत: 300 प्रतिभागियों से
- वर्तमान में: 31,500 से अधिक शिक्षार्थियों को शिक्षा और बेहतर अवसर उपलब्ध कराना

क्यों मिला पुरस्कार?

रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन (RMAF) के अनुसार, एजुकेट गर्ल्स को यह सम्मान मिला—

"लड़कियों और युवतियों की शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों को चुनौती देने, निरक्षरता की बेड़ियों से उन्हें मुक्त करने और उन्हें कौशल, साहस तथा आत्मनिर्भरता के साथ अपने पूर्ण मानवीय सामर्थ्य को पाने में सक्षम बनाने की प्रतिबद्धता" के लिए।

यह सम्मान जमीनी आंदोलनों और अभिनव शिक्षा वित्तपोषण (innovative financing) की शक्ति को दर्शाता है, जो लंबे समय तक सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं।

रेमन मैग्सेसे पुरस्कार: परिचय और महत्व

स्थापना और प्रतिष्ठा

- स्थापना: 1957, रॉकफेलर ब्रदर्स फंड और फिलीपींस सरकार द्वारा
- उपाधि: इसे अक्सर “एशिया का नोबेल पुरस्कार” कहा जाता है
- लक्ष्य: नेतृत्व, ईमानदारी और सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्टता को सम्मानित करना

भारतीय विजेता (कुछ प्रमुख नाम)

- अरविंद केजरीवाल (2006)
- बेजवाड़ा विल्सन (2016)
- सोनम बांगचुक (2018)
- रविश कुमार (2019)

समारोह और विरासत

- पुरस्कार हर वर्ष 7 नवंबर को मनीला, फिलीपींस के मेट्रोपॉलिटन थिएटर में प्रदान किया जाता है।
- यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन डेल फिएरो मैग्सेसे (जन्म: 31 अगस्त 1907) की स्मृति में दिया जाता है।
- मैग्सेसे द्वितीय विश्वयुद्ध के गुरिल्ला नेता, मैकेनिक और जन-केन्द्रित शासन के प्रतीक माने जाते हैं।
- उनकी राष्ट्रपति पद की अवधि ईमानदार प्रशासन और भ्रष्टाचार विरोधी सुधारों के लिए जानी जाती है।
- 1957 में विमान दुर्घटना में उनकी असामयिक मृत्यु के बाद इस पुरस्कार की शुरुआत हुई, जो सार्वजनिक सेवा में “आत्मा की महानता” (Greatness of Spirit) का उत्सव मनाता है।

कैबिनेट की मंजूरी

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम और त्रिपुरा के लिए ₹4,250 करोड़ के परिव्यय के साथ विशेष विकास पैकेज (एसडीपी) की केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत चार नए घटकों को मंजूरी दी, जो आदिवासी गांवों (₹500 करोड़), डिमासा क्षेत्रों (₹500 करोड़), असम में उल्फा समूहों (₹3,000 करोड़) और त्रिपुरा में आदिवासी विकास (₹250 करोड़) पर केंद्रित हैं, जिसका उद्देश्य शांति, बुनियादी ढांचा, रोजगार और सामाजिक-आर्थिक उत्थान है।
- मंत्रिमंडल ने ₹4,200 करोड़ (2025-30) के परिव्यय के साथ मेरिट योजना (तकनीकी शिक्षा में बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार) को मंजूरी दी, जिसे ₹2,100 करोड़ के विश्व बैंक ऋण से समर्थन प्राप्त है, जिसका उद्देश्य 275 संस्थानों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और शासन में सुधार करना है।





- कैबिनेट ने वैश्विक स्तर पर एलपीजी की ऊँची कीमतों (2024-25) के कारण घरेलू एलपीजी अंडर-रिकवरी के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल) को 30,000 करोड़ रुपये का मुआवजा मंजूर किया है। इससे किफायती एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित होगी, तेल विपणन कंपनियों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं को निरंतर समर्थन मिलेगा।
- कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के उपभोक्ताओं के लिए 12,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर (प्रति वर्ष 9 रिफिल तक) पर 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी को मंजूरी दी है। इससे 10.33 करोड़ परिवारों को लाभ होगा और गरीब परिवारों में एलपीजी के उपयोग में सुधार होगा।
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 2,157 करोड़ रुपये की लागत से हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) पर 4-लेन मरक्कनम-पुदुचेरी (एनएच-332ए) खंड (46 किमी) के निर्माण को मंजूरी दी, जिससे चेन्नई, पुदुचेरी और नागपट्टिनम के बीच संपर्क बढ़ेगा, पर्यटन, व्यापार और रोजगार (18 लाख मानव दिवस) को बढ़ावा मिलेगा।
- कैबिनेट ने ₹5,801 करोड़ के परिव्यय के साथ लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना चरण-1बी (11.165 किमी, 12 स्टेशन) को मंजूरी दी, जिससे पुराने लखनऊ में कनेक्टिविटी में सुधार होगा, वाणिज्यिक केंद्रों, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और विरासत स्थलों को जोड़ा जाएगा, यातायात की भीड़ कम होगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और आर्थिक विकास व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- कैबिनेट ने ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में ₹4,600 करोड़ मूल्य की सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें भारत का पहला वाणिज्यिक कंपाउंड फैब (SiCSem, ओडिशा), 3D उन्नत पैकेजिंग इकाई (ओडिशा), ASIP सुविधा (आंध्र प्रदेश) और CDIL विस्तार (पंजाब) शामिल हैं। इनसे 2,034 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने और इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
- सीसीईए ने अरुणाचल प्रदेश के शि योमी में 700 मेगावाट की तातो-II जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी, जिसका परिव्यय ₹8,146.21 करोड़ है और इसे 72 महीने में पूरा किया जाएगा। इससे सालाना 2,738 एमयू बिजली का उत्पादन होगा, जिससे राज्य को 12% मुफ्त बिजली, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, बुनियादी ढांचे का उन्नयन और रोजगार सृजन जैसे लाभ होंगे।
- सीसीईए ने एचएएम मोड के तहत ₹8,307.74 करोड़ की लागत से 6-लेन कैपिटल रीजन रिंग रोड (भुवनेश्वर बाईपास, 110.875 किमी, ओडिशा) के निर्माण को मंजूरी दी, जो खोरधा, भुवनेश्वर, कटक को जोड़ेगा, एनएच-55, एनएच-57, एनएच-655 के साथ एकीकृत होगा और 1.67 करोड़ से अधिक मानव-दिवस रोजगार पैदा करेगा, जिससे माल ढुलाई दक्षता और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- कैबिनेट ने कोटा-बूंदी (राजस्थान) में ₹1,507 करोड़ की लागत से एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है, जिसमें 20,000 वर्ग मीटर का टर्मिनल (2 एमपीपीए क्षमता), 3,200 मीटर का रनवे और 7 विमान बे जैसी सुविधाएँ शामिल होंगी। यह राजस्थान के कोचिंग हब

- और औद्योगिक राजधानी कोटा में बढ़ते यातायात को संबोधित करेगा, क्योंकि मौजूदा हवाई अड्डा अपर्याप्त है।
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह भी घोषणा की है कि कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा ए-321 विमानों के संचालन में सहायता करेगा, जिससे शिक्षा और औद्योगिक केंद्र के लिए बेहतर हवाई संपर्क सुनिश्चित होगा। राजस्थान 440.06 हेक्टेयर भूमि प्रदान करेगा, जिससे यह क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा परियोजना बन जाएगी।
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ₹8,307.74 करोड़ की लागत से 6-लेन भुवनेश्वर बाईपास (110.875 किमी, ओडिशा) को मंजूरी देने की पुष्टि की, जिसमें खोरधा, भुवनेश्वर और कटक में भीड़भाड़ कम करने, रसद लागत को कम करने, आर्थिक और सामाजिक नोड्स को जोड़ने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया।
- कैबिनेट ने कोटा-बूंदी (राजस्थान) में ₹1,507 करोड़ की लागत से एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है, जिसमें 20,000 वर्ग मीटर का टर्मिनल (2 एमपीपीए क्षमता), 3,200 मीटर का रनवे और 7 विमान बे जैसी सुविधाएँ शामिल होंगी। यह राजस्थान के कोचिंग हब और औद्योगिक राजधानी कोटा में बढ़ते यातायात को संबोधित करेगा, क्योंकि मौजूदा हवाई अड्डा अपर्याप्त है।
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह भी घोषणा की है कि कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा ए-321 विमानों के संचालन में सहायता करेगा, जिससे शिक्षा और औद्योगिक केंद्र के लिए बेहतर हवाई संपर्क सुनिश्चित होगा। राजस्थान 440.06 हेक्टेयर भूमि प्रदान करेगा, जिससे यह क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा परियोजना बन जाएगी।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ₹8,307.74 करोड़ की लागत से 6-लेन भुवनेश्वर बाईपास (110.875 किमी, ओडिशा) को मंजूरी देने की पुष्टि की, जिसमें खोरधा, भुवनेश्वर और कटक में भीड़भाड़ कम करने, रसद लागत कम करने, आर्थिक और सामाजिक केंद्रों को जोड़ने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद में 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों (CWG) की मेजबानी के लिए भारत की बोली को मंजूरी दे दी, अगर बोली स्वीकार कर ली जाती है तो गुजरात सरकार को अनुदान सहायता प्राप्त होगी। शहर में विश्व स्तरीय स्टेडियम हैं, जिनमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी शामिल है, जिसने 2023 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप फाइनल की मेजबानी की थी।
- कैबिनेट ने ₹7,332 करोड़ के परिव्यय के साथ पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के पुनर्गठन और विस्तार को 31 मार्च, 2030 तक मंजूरी दे दी है। इससे 50 लाख नए विक्रेताओं सहित 1.15 करोड़ विक्रेताओं को लाभ होगा। यह योजना अब उच्च ऋण राशि (₹15,000, ₹25,000 और ₹50,000) प्रदान करती है, UPI-लिंकड RuPay क्रेडिट कार्ड शुरू करती है, और ₹1,600 तक का डिजिटल कैशबैक प्रदान करती है। साथ ही, इसका विस्तार जनगणना और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। 2020 से 68 लाख विक्रेताओं को ₹13,797 करोड़ के ऋण वितरित करने और डिजिटल, वित्तीय और उद्यमशीलता सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की इसकी सफलता जारी है।





- कैबिनेट ने ₹12,328 करोड़ की चार रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें गुजरात के कच्छ में कच्छ के रण, धोलावीरा, कोटेश्वर और नारायण सरोवर को जोड़ने वाली 145 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के साथ-साथ मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाएँ शामिल हैं: सिकंदराबाद-वाडी (₹5,012 करोड़), भागलपुर-जमालपुर (₹1,156 करोड़), और फुरकाटिंग-न्यू तिनसुकिया (₹3,634 करोड़)। इन परियोजनाओं से कुल मिलाकर 565 किलोमीटर नई पटरियाँ जुड़ेंगी, लगभग 47 लाख लोगों को लाभ होगा, 2.5 करोड़ रोजगार दिवस सृजित होंगे, माल ढुलाई में 68 मिलियन टन प्रति वर्ष की वृद्धि होगी और CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे पीएम गति शक्ति योजना को बल मिलेगा और लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी।

संसद समाचार

राज्यवार अक्टूबर माह की महत्वपूर्ण घटनाएँ

आंध्र प्रदेश

- आंध्र प्रदेश सरकार ने नियमित नगरपालिका कर्मचारियों के लिए ₹1 करोड़ और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ₹20 लाख के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है, साथ ही स्थायी विकलांगता की स्थिति में भी इतनी ही राशि का आश्वासन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उनके बच्चों के लिए ₹8 लाख तक की शिक्षा सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने काकीनाडा जिले के पेड्डापुरम में स्वर्ण आंध्र-स्वच्छ आंध्र अभियान रैली के दौरान यह घोषणा की और श्रमिकों के कल्याण और स्वच्छता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया।
- आंध्र प्रदेश के राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड (एसआईपीबी) ने 53,922 करोड़ रुपये की 30 निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 83,437 नौकरियाँ पैदा करने की क्षमता है; प्रमुख स्वीकृतियों में एचएफसीएल, अपोलो टायर्स और धीरूभाई अंबानी ग्रीन टेक पार्क शामिल हैं, क्योंकि सीएम चंद्रबाबू नायडू व्यक्तिगत रूप से परियोजना निष्पादन की निगरानी करने और राज्य में व्यापार करने में आसानी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

असम

- लोकसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित कर दिया है, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र, गुवाहाटी, असम में एक नया आईआईएम स्थापित करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इस संस्थान के लिए ₹550 करोड़ के वित्तीय अनुदान की घोषणा की, जिससे एक लंबे समय से चली आ रही क्षेत्रीय मांग पूरी हुई। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में भारत में 21 आईआईएम संचालित हैं और अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कर रहे हैं, और अगले महीने आईआईएम दुबई परिसर का शुभारंभ होने वाला है। एसआईआर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण विधेयक बिना चर्चा के पारित हो गया।

बिहार

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को बिहार के गया में ₹12,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जो कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, शहरी विकास और पर्यटन पर केंद्रित हैं। इन परियोजनाओं में औंटा-सिमरिया पुल और बख्तियारपुर-मोकामा राजमार्ग का उन्नयन, ₹6,880 करोड़ का बक्सर थर्मल पावर प्लांट, मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल, नमामि गंगे परियोजनाएँ, और नई अमृत भारत एक्सप्रेस और बौद्ध सर्किट ट्रेनें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 16,000 से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थियों को आवास प्रदान किए गए।

छत्तीसगढ़

- भारत के महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक विकास के तहत, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के भालुकोना-जमनीडीह ब्लॉक में निकल-कॉपर-प्लैटिनम समूह तत्व (Ni-Cu-PGE) सल्फाइड खनिजीकरण का संभावित भंडार खोजा गया है। इस खोज को भारत के औद्योगिक और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए अत्यावश्यक रणनीतिक खनिज संसाधनों को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

गुजरात

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में रेलवे, सड़क, बिजली, आवास और शहरी बुनियादी ढाँचे से जुड़ी ₹5,400 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण किया। प्रमुख रेलवे परियोजनाओं में कनेक्टिविटी और माल ढुलाई में सुधार के लिए महत्वपूर्ण रेल लाइनों का दोहरीकरण और आमान परिवर्तन शामिल हैं। मोदी ने स्थानीय पहुँच और औद्योगिक रसद को बढ़ावा देने के लिए नई यात्री और मालगाड़ी सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। छह-लेन अंडरपास और ओवरब्रिज जैसी सड़क परियोजनाओं का उद्देश्य भीड़भाड़ कम करना और व्यापार को बढ़ावा देना है। यूजीवीसीएल के तहत बिजली पहल विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए बिजली वितरण के आधुनिकीकरण पर केंद्रित है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में हरित गतिशीलता पहल का उद्घाटन किया और सुजुकी के पहले भारत निर्मित वैश्विक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (ई विटारा) को लॉन्च किया, जिसका निर्यात जापान और यूरोप सहित 100 देशों में किया जाएगा। उन्होंने तोशिबा, डेंसो और सुजुकी के संयुक्त उद्यम, टीडीएसजी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड निर्माण की शुरुआत की भी घोषणा की, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम है।

केरल

- केरल के ओणम उत्सव की शुरुआत त्रिपुनिथुरा में जीवंत अथचमयम जुलूस के साथ हुई, जिसने धूप भरे आसमान के नीचे हज़ारों दर्शकों को आकर्षित किया। इस परेड में थेय्यम, कथकली और पुलिकली जैसी 59 पारंपरिक कलाओं के साथ-साथ सामाजिक विषयों पर आधारित झांकियाँ, फिल्मी पात्रों की नकलें और 1,500 किलो फूलों से बना एक शानदार 60 फुट का अथपुक्कलम भी शामिल था। कड़ी सुरक्षा, जीवंत प्रस्तुतियों और कलाकारों, छात्रों और पर्यटकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ, इस कार्यक्रम ने धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव को उजागर किया।





महाराष्ट्र

- मुंबई में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर अब तक के सबसे बड़े 18वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन हो रहा है। होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र द्वारा आयोजित 10-दिवसीय कार्यक्रम में 64 देशों के लगभग 300 छात्र भाग ले रहे हैं, जिनमें 12 पहली बार भाग ले रहे प्रतिभागी भी शामिल हैं। यह ओलंपियाड खगोल विज्ञान में वैश्विक मैत्री और शिक्षा को बढ़ावा देता है, जिसमें परीक्षाएँ, टीम चुनौतियाँ और आकाश अवलोकन शामिल हैं। साथ ही, युद्ध प्रभावित देशों का स्वागत करते हुए, इसमें रिकॉर्ड संख्या में महिला प्रतिभागी भी शामिल हो रही हैं।
- महाराष्ट्र ने बौद्धिक दिव्यांग छात्रों को एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 'दिशा अभियान' को सफलतापूर्वक लागू करके समावेशी शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जय वकील फाउंडेशन द्वारा विकसित और राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईडीपीआईडी) द्वारा अनुमोदित, यह अभिनव पाठ्यक्रम वर्तमान में राज्य भर के 453 विशेष विद्यालयों में लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बात पर ज़ोर दिया कि महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है जिसने शिक्षा के माध्यम से दिव्यांगजनों की ज़रूरतों को प्राथमिकता दी है।

पंजाब

- पंजाब किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और पाँक्सो अधिनियम, 2012 के तहत सांकेतिक भाषा दुभाषियों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों को औपचारिक रूप से सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है। यह पहल संचार संबंधी कमियों को दूर करेगी और प्रशिक्षित पेशेवरों के साथ अदालती कार्यवाही में सहयोग प्रदान करके बच्चों के लिए न्याय और अधिकारों तक पहुँच को मज़बूत करेगी। इन विशेषज्ञों को ज़िलेवार तैनात किया जाएगा और कानूनी प्रावधानों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाएगा, जिससे निष्पक्ष और पारदर्शी परिणाम सुनिश्चित होंगे। राज्य पहले ही पंजाब विधानसभा की कार्यवाही को सांकेतिक भाषा में प्रसारित करने में अग्रणी रहा है।

राजस्थान

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कोटा-बूंदी (राजस्थान) में ₹1507 करोड़ की अनुमानित लागत से एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दे दी है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एआई) राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई 440.06 हेक्टेयर भूमि पर इस हवाई अड्डे का विकास करेगा, जिसमें ए-321 विमानों के लिए सुविधाएँ, 20,000 वर्ग मीटर का टर्मिनल और प्रति वर्ष 20 लाख यात्रियों की क्षमता (एमपीपीए) होगी।

सिक्किम

- सिक्किम ने सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनकर इतिहास रच दिया है। इस योजना के तहत, वरिष्ठता और सेवा निरंतरता सुनिश्चित करते हुए, 50% मूल वेतन के साथ 365 से 1,080 दिनों की छुट्टी प्रदान की जाती है। यह योजना नियमित और अस्थायी दोनों तरह के कर्मचारियों को कवर करती है और अब इसमें निर्णयों में तेज़ी लाने के लिए एक विकेन्द्रीकृत अनुमोदन प्रणाली भी शामिल है, जो प्रगतिशील शासन और कर्मचारी सशक्तिकरण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने रोंगपो में पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर 'नारी अदालत' का शुभारंभ किया। यह समुदाय-आधारित मंच महिलाओं द्वारा चलाया जाता है ताकि पारिवारिक मतभेदों, घरेलू हिंसा और वैवाहिक समस्याओं जैसे छोटे-मोटे विवादों के लिए सुलभ, अनौपचारिक न्याय प्रदान किया जा सके, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को एक सहायक, भयमुक्त वातावरण प्रदान करके सशक्त बनाना है जो औपचारिक अदालती प्रक्रियाओं की आवश्यकता के बिना स्थानीय स्तर पर विवादों का समाधान करता है।

तमिलनाडु

- तमिलनाडु ने केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के सीधे जवाब में अपनी राज्य शिक्षा नीति (एसईपी) जारी की है। इसमें द्वि-भाषा प्रणाली को बरकरार रखा गया है, कक्षा 3, 5 और 8 में सार्वजनिक परीक्षाओं को अस्वीकार किया गया है और स्नातक स्तर पर दाखिले के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षाओं का विरोध किया गया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा जारी की गई एसईपी विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और अंग्रेजी को बढ़ावा देती है, शिक्षा को राज्य सूची में वापस लाने का आग्रह करती है और सार्वजनिक संस्थानों में निवेश पर ज़ोर देती है।

उत्तर प्रदेश

- केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को मंजूरी दे दी है, जिसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने की थी। स्थानीय लोग पुराने नाम को "गुलामी" ("गुलामी") का प्रतीक मानते थे और सनातन परंपराओं को प्रतिबिंबित करने वाले इस बदलाव का स्वागत करते थे। इस नाम परिवर्तन को ऐतिहासिक उत्पीड़न से जुड़े नामों को बदलने के व्यापक सरकारी प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है। इस बदलाव की आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना जल्द ही जारी होने की उम्मीद है।

जम्मू और कश्मीर

- चिनाब नदी पर स्थित 2,185 मेगावाट क्षमता वाली रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना, सावलकोट जलविद्युत परियोजना का पुनरुद्धार एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी द्वारा ₹22,704 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना के रूप में, इसका लक्ष्य सालाना 7,000 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन करना है, जिससे क्षेत्र में बिजली अधिशेष बढ़ेगा और बाढ़ नियंत्रण में भी योगदान मिलेगा। इसका पुनरुद्धार भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करने के निर्णय के बाद हुआ है, जो क्षेत्रीय जल और ऊर्जा नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।

दिल्ली

- दिल्ली विधानसभा, 500 किलोवाट के रूफटॉप सोलर प्लांट के चालू होने के बाद, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है, जिससे बिजली की लागत में सालाना लगभग 1.75 करोड़ रुपये की कमी आई है। इसके साथ ही, इसने केंद्र की "एक राष्ट्र, एक एप्लीकेशन" पहल के तहत राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) का शुभारंभ किया, जो कागज़ रहित, डिजिटल विधायी कार्यप्रणाली की ओर एक बदलाव का प्रतीक है। ये कदम स्थायी शासन और डिजिटल परिवर्तन की ओर दिल्ली के बढ़ते कदम को दर्शाते हैं, जिसमें अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता और उन्नत स्मार्ट विधायी उपकरण आगामी मानसून सत्र से पूरी तरह से चालू हो जाएंगे।

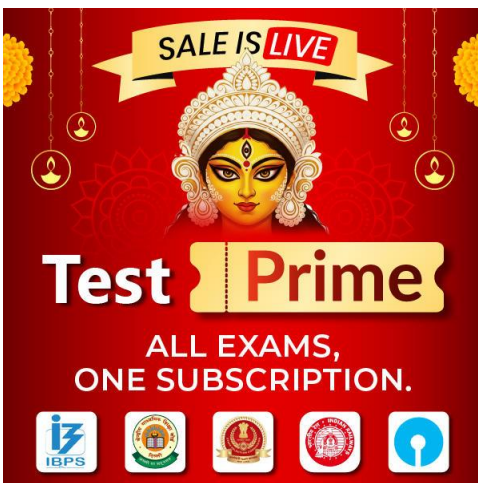




- पिछले एक दशक में दिल्ली की अर्थव्यवस्था ने मज़बूत विकास दिखाया है, जिसकी वार्षिक जीएसडीपी वृद्धि दर 5.8% और प्रति व्यक्ति आय में 7% की वृद्धि हुई है। हालाँकि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली का योगदान 2011-12 के 3.94% से थोड़ा कम होकर 2024-25 में 3.79% रह गया है, लेकिन समग्र आर्थिक गतिविधि महामारी-पूर्व स्तर से ऊपर उठ गई है। 2024-25 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 4,93,024 रुपये है, जो राष्ट्रीय औसत से 2.4 गुना अधिक है, जो मज़बूत आर्थिक प्रदर्शन और सुधार को दर्शाता है।
- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कॉलेज के छात्रों के लिए 'यू-स्पेशल' बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वर्षों की निष्क्रियता के बाद इस सेवा को फिर से शुरू किया गया है। घरों और दिल्ली विश्वविद्यालय के बीच संपर्क बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस पहल में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरों और पैनिक बटन से लैस इलेक्ट्रिक, वातानुकूलित बसें शामिल हैं। गुप्ता ने विश्वविद्यालय की जीवंतता बढ़ाने और दिल्ली के परिवहन में स्वच्छ हवा को बढ़ावा देने में इस योजना की भूमिका पर प्रकाश डाला।

अगस्त माह के शुभारंभ और उद्घाटन:

- दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण (डीपीए) ने कांडला में भारत का पहला स्वदेशी 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया; इसे 10 मेगावाट तक विस्तारित करने की योजना है।
- पश्चिम रेलवे ने मध्य प्रदेश में पातालपानी-कालाकुंड लाइन पर हेरिटेज ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू किया।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ट्रक चालकों के लिए स्वच्छ विश्राम स्थलों के साथ 'अपना घर' पहल शुरू की।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत पहले कॉमन सेंट्रल सेक्रेटारिएट (सीसीएस) भवन, कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने एमपीलैड योजना के डिजिटल एकीकरण के लिए ई-साक्षी पोर्टल लॉन्च किया।
- आठ प्रमुख सहकारी समितियों ने सहकारी-संचालित राइड-हेलिंग सेवा 'भारत' टैक्सी शुरू की।
- भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी 'रुद्र' (4.5 किमी) का ट्रायल रन किया।



- केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन 'भारत स्टील' का लोगो, ब्रोशर और वेबसाइट लॉन्च की।
- भारत ने पीएलआई योजना से प्रेरित होकर एएलएमएम के तहत 100 गीगावाट सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता हासिल की।
- ओडीओपी पहल के तहत सऊदी अरब में कारगिल खुबानी का अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू हुआ।
- एनएचआई ने देश भर के 1,150 टोल प्लाजा पर फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया।
- नागपुर-पुणे कॉरिडोर पर भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ हुआ।
- भारत ने जयपुर के रामगढ़ बांध पर अपना पहला ड्रोन-एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग शुरू किया।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में प्लुमेरिया गार्डन, बनयान ग्रीव और बबलिंग ब्रुक का उद्घाटन किया।
- स्वतंत्रता दिवस पर सिएटल के स्पेस नीडल में पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया गया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ₹11,000 करोड़ की लागत से निर्मित शहरी विस्तार मार्ग-II (UER-II) और द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड का उद्घाटन किया।
- भारत की सिनेमाई विविधता को प्रदर्शित करने के लिए श्रीलंका के ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में छह दिवसीय भारतीय सिनेमा महोत्सव का उद्घाटन किया गया।
- दिल्ली-एनसीआर में भीड़भाड़ कम करने और NH-44, NH-09 और द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए शहरी विस्तार मार्ग-II (UER-II) परियोजना का उद्घाटन किया गया।
- प्रयोगशाला मान्यता में सुधार के लिए NABL ने ISO 15189:2022 के अंतर्गत एक मेडिकल एप्लिकेशन पोर्टल लॉन्च किया।
- केंद्र ने 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अन्न-चक्र आपूर्ति शृंखला अनुकूलन उपकरण लॉन्च किया, जिससे सालाना ₹250 करोड़ की बचत होगी।
- जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने दुनिया के सबसे बड़े जनजातीय जमीनी स्तर के नेतृत्व कार्यक्रम, आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ किया।
- प्रेस महापंजीयक ने समाचार पत्रों के सरल पंजीकरण के लिए प्रेस सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया।
- भारत ने लिथियम और दुर्लभ मृदा खनिजों के खनन को उदार बनाने हेतु खान एवं खनिज (संशोधन) विधेयक 2025 पारित किया।
- भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने ECINET, 100% वेबकास्टिंग और मतदाता सूची शुद्धिकरण सहित 28 पहलों का शुभारंभ किया।
- भारतीय रेलवे ने भारत का पहला हटाने योग्य सौर पैनेल सिस्टम और 2x25 kV विद्युत कर्षण प्रणाली का शुभारंभ किया।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ई-स्पोर्ट्स को विनियमित करने और ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने हेतु ऑनलाइन गेमिंग विधेयक को मंजूरी दी।





- 30+ दिनों से हिरासत में लिए गए प्रधानमंत्रियों/मुख्यमंत्रियों/मंत्रियों को हटाने के लिए 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया।
- भारतीय डाक ने डिजिपिन, क्यूआर-भुगतान, ओटीपी डिलीवरी के साथ आईटी 2.0 - उन्नत डाक प्रौद्योगिकी (APT) का शुभारंभ किया।
- एनसीईआरटी ने साहस, देशभक्ति और सुरक्षा पर प्रकाश डालने के लिए स्कूलों के लिए ऑपरेशन सिंदूर शैक्षिक मॉड्यूल लॉन्च किया।
- सरकार ने सभासार लॉन्च किया, जो भाषिणी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राम सभा मिनट्स तैयार करने के लिए एक एआई-संचालित टूल है।
- केंद्र ने विकसित भारत 2047 और नियामक सुधारों के लिए दो उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया।
- केरल को भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया, जिसने डिजी केरल के तहत 21.87 लाख नागरिकों को प्रशिक्षण दिया।
- उज्जैन 27 अगस्त 2025 को पीएचडीसीसीआई के दूसरे वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन "रूहमानटिक" की मेजबानी करेगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे; मुख्य भाषण गौरांग दास प्रभु देंगे।
- एनएचएआई ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के साथ 'प्रोजेक्ट आरोहण' लॉन्च किया, जिसमें छात्रवृत्ति और मेंटरशिप (₹1 करोड़ का फंड) की पेशकश की गई।
- सीजी पावर ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत गुजरात के साणंद में ओएसएटी पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया; ₹7,600 करोड़ का निवेश, 5,000 से अधिक नौकरियां मिलने की उम्मीद।

महत्वपूर्ण त्यौहार

विविध राष्ट्रीय समाचार

- केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने घोषणा की कि भारत मछली उत्पादन में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सौंदर्य प्रसाधन नियम, 2020 में संशोधन किया है, जो 29 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगा।
- परीक्षा पे चर्चा (पीपीसी) 2025 ने 3.53 करोड़ पंजीकरणों के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।
- कपड़ा मंत्रालय हथकरघा और हस्तशिल्प के जीआई पंजीकरण को बढ़ावा दे रहा है।
- एसईसीआई ने ग्रीन अमोनिया खरीद के लिए अपनी पहली नीलामी आयोजित की, जिसमें रिकॉर्ड-कम कीमत ₹55.75/किग्रा पाई गई।
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिबंधों के प्रवर्तन का हवाला देते हुए भारतीय आयातों पर शुल्क दोगुना करके 50% कर दिया।
- संसद ने 1925 के अधिनियम के स्थान पर समुद्री माल ढुलाई विधेयक, 2025 पारित किया।
- अरुणाचल के पर्वतारोही कबक यानो ने सेवन समिट अभियान के हिस्से के रूप में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की।
- प्रधानमंत्री मोदी के 'मन की बात' से 2014 से अब तक ₹34.13 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।

- 2025 की पहली छमाही में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 29,000 से ज्यादा मौतें होंगी; सरकार का लक्ष्य 2030 तक इन मौतों को आधा करना है।
- भारतीय रेलवे ने त्योहारों के दौरान वापसी टिकटों पर 20% छूट के साथ राउंड ट्रिप पैकेज शुरू किया है।
- मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में 700 मेगावाट की टाटो-II जलविद्युत परियोजना के लिए ₹8146.21 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामक प्रणालियों के मानकीकरण हेतु SHRESTH सूचकांक लॉन्च किया।
- यूपीएससी शताब्दी वर्ष (1925-2026) को सुधारों और कार्यक्रमों के साथ मनाएगा।
- लोकसभा ने 1908 के अधिनियम का आधुनिकीकरण करते हुए भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 पारित किया।
- संसद ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया।
- भारत ने एकट ईस्ट नीति के तहत मानवीय सहायता के रूप में फिजी को 5 टन लोबिया के बीज भेजे।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत की विकास यात्रा पर प्रकाश डालते हुए अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया।
- भारत वैश्विक डेटा मानक स्थापित करेगा, MoSPI सेवा उत्पादन सूचकांक लॉन्च करेगा।
- प्रधानमंत्री मोदी ने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगातार 12वां स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया।
- प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण (103 मिनट) दिया।
- सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा लंबित रहने तक दिल्ली-एनसीआर में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध पर रोक लगा दी।
- एनसीईई आरटीओ ने साहसिक, देश और सुरक्षा पर प्रकाश डाला, खोज के लिए ऑपरेशन सिन्दूरस्टार्ट लॉन्च किया गया।
- सरकार ने सभासार का शुभारंभ किया, जो भाषिणी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राम सभा मिनटों की तैयारी के लिए एक प्रयोगशाला-संचालन उपकरण है।
- केंद्र ने दो उच्च स्तरीय उद्यमों के लिए भारत 2047 और अनुमोदित सुधारों का विकास किया।
- केरल को भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया, जिसने केरल के तहत 21.87 लाख नागरिकों को प्रशिक्षण दिया।
- 27 अगस्त 2025 को ड्रैगनसी सीसीआई के दूसरे वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन "रूहमानटिक" का आगमन होगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे; मुख्य भाषण गौरांग दास प्रभु जायेंगे।
- एनएच मिशेल ने टोल प्लाजा एंज्लॉयज के बच्चों की शिक्षा के समर्थन के लिए वर्टिस ट्रस्ट ट्रस्ट के साथ 'प्रोजेक्ट आरोहण' लॉन्च किया, जिसमें स्कॉलरशिप और मेंटरशिप (₹1 करोड़ का फंड) शामिल है।
- सीजी पावर ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत गुजरात के सांड में टमाटर की पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया; ₹7,600 करोड़ का निवेश, 5,000 से ज्यादा की बोली मिलने की उम्मीद।





राष्ट्रीय करंट अफेयर्स: जुलाई 2025

सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेख

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025: शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश

संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2015 में अपनाए गए सतत विकास लक्ष्य (SDGs) का उद्देश्य 2030 तक एक अधिक न्यायसंगत, हरित और समावेशी विश्व का निर्माण करना था। लेकिन हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क (SDSN) द्वारा प्रकाशित 2025 सतत विकास रिपोर्ट (SDR) की तस्वीर चिंताजनक है। रिपोर्ट के अनुसार, 17 में से कोई भी सतत विकास लक्ष्य 2030 तक पूरी तरह हासिल होने की राह पर नहीं है, और केवल 17% लक्ष्य ही अपेक्षा के अनुरूप प्रगति कर रहे हैं। हालाँकि बुनियादी सेवाओं, आधारभूत संरचना और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में कुछ हद तक प्रगति हुई है, लेकिन मीडिया स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार की धारणा, पोषण और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर गिरावट दर्ज की गई है।

वैश्विक रैंकिंग: दो दुनियाओं की कहानी

SDG इंडेक्स 2025 में शीर्ष 10 देश

यूरोप, विशेषकर नॉर्डिक देश, सतत विकास की दिशा में वैश्विक प्रयासों में लगातार अग्रणी बने हुए हैं। फिनलैंड ने एक बार फिर शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जिसके बाद स्वीडन और डेनमार्क क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

रैंक	देश	स्कोर (2025)
1	फिनलैंड	87.0
2	स्वीडन	85.7
3	डेनमार्क	85.3
4	जर्मनी	83.7
5	फ्रांस	83.1
6	ऑस्ट्रिया	83.0
7	नॉर्वे	82.7
8	क्रोएशिया	82.4
9	पोलैंड	82.1
10	चेकिया (चेक गणराज्य)	81.9



Test Prime

ALL EXAMS,
ONE SUBSCRIPTION.







ये देश गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, जलवायु कार्रवाई, और शांति एवं न्याय जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर, SDG इंडेक्स 2025 में निचले पायदान पर वे देश हैं जो सशस्त्र संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता, और आर्थिक संकट जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन स्थितियों के चलते सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में उनकी प्रगति अत्यंत धीमी रही है।

रैंक	देश	स्कोर (2025)
167	दक्षिण सूडान	41.6
166	मध्य अफ्रीकी गणराज्य	45.2
165	चाड	46.0
164	सोमालिया	46.1
163	यमन गणराज्य	47.7
162	कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य	48.2
161	सूडान	49.1
160	अफ़ग़ानिस्तान	49.1
159	नाइजर	50.3
158	मेडागास्कर	51.0

ये देश अक्सर सीमित राजकोषीय संसाधनों, प्राकृतिक आपदाओं, हिंसा और बुनियादी सेवाओं की कमी जैसी समस्याओं से जूझते हैं, जो सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की दिशा में उनकी प्रगति को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं।

भारत की SDG रैंकिंग में ऐतिहासिक प्रगति

भारत पहली बार टॉप 100 में शामिल

2025 के SDG इंडेक्स में भारत ने 99वाँ स्थान हासिल किया है, जिसका स्कोर 67.0 रहा। यह अब तक की भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इससे पहले भारत की स्थिति इस प्रकार रही थी:

- **2024:** 109वाँ स्थान
- **2023:** 112वाँ स्थान
- **2022:** 121वाँ स्थान
- **2021:** 120वाँ स्थान

भारत की यह लगातार सुधार होती रैंकिंग यह दर्शाती है कि देश ने सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में साफ-सफाई, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल सार्वजनिक ढाँचे और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है।

क्षेत्रीय तुलना में भारत की स्थिति

हालाँकि भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 100 देशों में प्रवेश कर चुका है, फिर भी दक्षिण एशिया के कई पड़ोसी देशों की तुलना में यह अभी भी पीछे है। यह दर्शाता है कि भारत ने प्रगति तो की है, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

देश	रैंक (2025)	स्कोर
मालदीव	53	उपलब्ध नहीं
भूटान	74	70.5
नेपाल	85	68.6
भारत	99	67.0
श्रीलंका	93	उपलब्ध नहीं
बांग्लादेश	114	उपलब्ध नहीं
पाकिस्तान	140	उपलब्ध नहीं





भारत ने भले ही बांग्लादेश और पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन यह अब भी भूटान, नेपाल और श्रीलंका से पीछे है, जो यह संकेत देता है कि क्षेत्रीय सहयोग और साझा सीखने की पर्याप्त गुंजाइश अब भी मौजूद है।

एशिया और ग्लोबल साउथ से मुख्य झलकियाँ

दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में उल्लेखनीय प्रगति

2015 के बाद से एशिया के कई देशों ने स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं:

देश	स्कोर में सुधार
नेपाल	+11.1 अंक
कंबोडिया	+10.0 अंक
फिलीपींस	+8.6 अंक

इन देशों की प्रगति यह दर्शाती है कि यदि नीतियाँ लक्षित हों और उन्हें अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त हो, तो कम आय वाले देश भी सतत विकास लक्ष्यों में तेज़ी से सुधार कर सकते हैं।

चीन और अमेरिका: मिला-जुला प्रदर्शन

देश	रैंक (2025)	स्कोर
चीन	49	74.4
संयुक्त राज्य अमेरिका	44	75.2

दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ होने के बावजूद, ये दोनों देश शीर्ष 40 में नहीं आ सके।

इनकी रैंकिंग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं:

- असमानता (Inequality)
- पर्यावरणीय टिकाऊपन की कमी
- स्वास्थ्य परिणामों में असंतुलन

2025 में वैश्विक चुनौतियाँ

हालाँकि कुछ क्षेत्रों में प्रगति हुई है, फिर भी वैश्विक स्तर पर SDGs की दिशा में प्रगति पटरी से उतरी हुई है।

2025 सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार:

- केवल 17% लक्ष्य ही समय पर प्रगति कर रहे हैं
- मोटापा (Obesity), भ्रष्टाचार और मीडिया पर अंकुश में वृद्धि हो रही है
- पर्यावरणीय क्षरण (विशेषकर नाइट्रोजन प्रबंधन) तेज़ी से बिगड़ रहा है
- लैंगिक असमानता और आय विषमता विकसित और विकासशील देशों दोनों में जारी है

समाधान की दिशा में सुझाव:

रिपोर्ट इस बात पर बल देती है कि 2030 तक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है:

- वैश्विक सहयोग में वृद्धि
- वित्तीय निवेश को बढ़ावा
- डेटा-आधारित नीति निर्माण
- स्थानीय और वैश्विक रणनीति में तालमेल

PM मोदी को घाना में मिला 'ऑर्डर ऑफ द स्टार' सम्मान

एक ऐतिहासिक कूटनीतिक दिशा में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, "ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना" से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा द्वारा दिया गया यह सम्मान पीएम मोदी की वैश्विक राजनेता, दक्षिण-दक्षिण सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता और भारत-घाना द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में उनकी भूमिका को मान्यता देता है। भारतीय प्रधानमंत्री ने यह पुरस्कार भारत के युवाओं, इसकी विविध सांस्कृतिक विरासत और दोनों देशों के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित किया।

खबरों में क्यों?

पीएम मोदी को घाना का शीर्ष नागरिक सम्मान 3 जुलाई, 2025 को घाना की अपनी पहली राजकीय यात्रा के दौरान मिला। यह सम्मान उनके नेतृत्व का जश्न मनाता है और भारत और घाना के बीच कूटनीतिक जुड़ाव को मजबूत करता है, खासकर व्यापार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में।

सम्मान के बारे में

- पुरस्कार का नाम: घाना के स्टार ऑफिसर का सम्मान
- द्वारा प्रदान किया गया: राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा
- कारण: पीएम मोदी के विशिष्ट वैश्विक नेतृत्व, कूटनीतिक पहुंच और दक्षिण-दक्षिण सहयोग बनाने के प्रयासों के सम्मान में।

प्रमुख समझौते और घोषणाएँ

अकरा में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए कई रणनीतिक पहलों का अनावरण किया।

शिक्षा और युवा विकास

- घाना के छात्रों के लिए ITEC और ICCR छात्रवृत्ति को दोगुना करना
- युवाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए घाना में एक कौशल विकास केंद्र की स्थापना

कृषि और खाद्य सुरक्षा

- भारत ने घाना के 'फ़ीड घाना' कार्यक्रम को समर्थन देने का वादा किया, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञता और संसाधन साझा किए

स्वास्थ्य सेवा

- घाना में जन औषधि केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव, सस्ती जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराना
- टीका उत्पादन सहयोग पर चर्चा

डिजिटल और वित्तीय एकीकरण

- भारत घाना को अपना भारत यूपीआई डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा, जिससे वित्तीय समावेशन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में वृद्धि होगी

व्यापार संबंध

- नए व्यापार और निवेश के अवसरों के माध्यम से अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा को दोगुना करने के लिए समझौता

यात्रा का महत्व

- 30 से अधिक वर्षों में घाना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री।
- अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण के लिए भारत की रणनीतिक पहुंच को मजबूत करता है।





- जवाहरलाल नेहरू और नेहरू द्वारा शुरू किए गए ऐतिहासिक संबंधों को आगे बढ़ाता है क्वामे नक्रमा।
- साझा लोकतांत्रिक आदर्शों और आपसी विकास लक्ष्यों के आधार पर सहयोग को गहरा करता है।

पीएम मोदी को मिला त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 जुलाई 2025 को त्रिनिदाद और टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें उनकी वैश्विक नेतृत्व क्षमता, भारतीय प्रवासी समुदाय से गहरे जुड़ाव और कोविड-19 महामारी के दौरान मानवीय प्रयासों के लिए दिया गया। बता दें कि पीएम मोदी फिलहाल पांच देशों के दौर पर हैं और त्रिनिदाद और टोबैगो की यह दो दिन की यात्रा उनका दूसरा पड़ाव है। वहीं सम्मान मिलने के बाद उन्होंने कहा, 'त्रिनिदाद एंड टोबैगो के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होकर मैं गौरवान्वित हूँ। मैं यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों की ओर से स्वीकार करता हूँ।'

ऐतिहासिक पहली यात्रा

यह प्रधानमंत्री मोदी की त्रिनिदाद और टोबैगो की पहली आधिकारिक यात्रा है। साथ ही, यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 1999 के बाद पहली त्रिनिदाद यात्रा भी है। यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की पाँच देशों की यात्रा का हिस्सा है, जो भारत और द्वीपीय राष्ट्र के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को नई ऊँचाई पर ले जाने का संकेत देती है।

सम्मान मिलने का कारण

"ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो" प्रधानमंत्री मोदी को उनके वैश्विक नेतृत्व, प्रवासी भारतीय समुदाय के लिए कार्य, और कोविड-19 महामारी के दौरान सहायता के लिए प्रदान किया गया। त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर ने यह सम्मान देने की घोषणा की और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा दोनों देशों के बीच गर्व और जुड़ाव का प्रतीक है।

पीएम मोदी की प्रतिक्रिया और सांस्कृतिक भेंट

सम्मान प्राप्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह यह पुरस्कार 140 करोड़ भारतीयों की ओर से स्वीकार कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने त्रिनिदाद की प्रधानमंत्री को महाकुंभ का पवित्र जल और राम मंदिर की एक प्रतिकृति भेंट की। यह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक माना गया।

इससे पहले घाना का दौरा

त्रिनिदाद यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने घाना का दौरा किया था, जहाँ उन्हें देश के एक और प्रतिष्ठित सम्मान "ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना" से नवाज़ा गया। भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, यह सम्मान उन्हें वैश्विक सहयोग में योगदान और मजबूत नेतृत्व के लिए दिया गया।

भारत और त्रिनिदाद एवं टोबैगो ने संबंधों को बढ़ावा देने के लिए छह नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए

भारत और त्रिनिदाद एवं टोबैगो ने 4 जुलाई 2025 को पोर्ट ऑफ स्पेन में छह महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के बीच साझेदारी को कई क्षेत्रों में मजबूती मिलेगी। इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, चिकित्सा, संस्कृति और खेल शामिल हैं। ये समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की त्रिनिदाद एवं टोबैगो यात्रा के दौरान हुए, जो दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

25 वर्षों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा

यह 1999 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की त्रिनिदाद एवं टोबैगो की पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर से मुलाकात की और सहयोग को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बातचीत की। दोनों नेताओं ने कृषि, शिक्षा, डिजिटल भुगतान और स्वास्थ्य सेवाओं में भविष्य की साझेदारी पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए।

इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने आपसी गर्मजोशी और सम्मान का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री बिसेसर ने इसे एक "ऐतिहासिक क्षण" बताया जो दोनों देशों की मित्रता को नई ऊर्जा देगा।

छह समझौतों पर हस्ताक्षर

भारत और त्रिनिदाद एवं टोबैगो के बीच छह समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देंगे:

- औषधि मानकों में सहयोग
- त्वरित विकास परियोजनाएं
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान
- खेलों का प्रचार-प्रसार
- राजनयिक प्रशिक्षण
- आधिकारिक दस्तावेजों और शोध साझा करना

इन समझौतों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना, सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना और जन-जन के बीच संबंधों को मजबूत करना है।

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी घोषणा की कि अब त्रिनिदाद एवं टोबैगो में रहने वाले भारतीय मूल के लोग, भले ही वे छठी पीढ़ी के हों, भारत के ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह निर्णय प्रवासी भारतीयों को भारत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात

प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद एवं टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कांगालू से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति कांगालू को हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोनों नेताओं की बैठक सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक रही। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति की जनसेवा और नेतृत्व की प्रशंसा की।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत और त्रिनिदाद एवं टोबैगो "ग्लोबल साउथ" यानी वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मिलकर कार्य करेंगे, जिनमें जलवायु संकट और निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रमुख हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को समर्थन देने के लिए त्रिनिदाद एवं टोबैगो का आभार भी व्यक्त किया और कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं।

प्रधानमंत्री मोदी को मिला नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 09 जुलाई 2025 को नामिबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एन्शिअंट वेल्विशिया मिराबिलिस' से नवाजा गया। यह सम्मान उन्हें नामीबिया की राष्ट्रपति नेतुम्बो नंदी-डैतवाह ने एक खास समारोह में दिया। ये भारत और नामीबिया के रिश्तों की नई इबारत लिखने की शुरुआत है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय नेता को यह सम्मान हासिल हुआ है। बतौर PM, मोदी का यह 27वां इंटरनेशनल अवॉर्ड है। प्रधानमंत्री ने नामीबिया की संसद को भी संबोधित किया।





नामीबिया में मोदी को मिला सर्वोच्च नागरिक सम्मान

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया की राजधानी में आयोजित एक भव्य समारोह में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एन्सिफ्ट वेल्विथिया मिराबिलिस' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान नामीबिया की राष्ट्रपति नेतुम्बो नंदी-डैतवाह ने प्रदान किया। यह पुरस्कार एक दुर्लभ रेगिस्तानी पौधे वेल्विथिया मिराबिलिस के नाम पर रखा गया है, जो केवल नामीबिया में पाया जाता है और संघर्ष, दीर्घायु और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है।

प्रधानमंत्री मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बने। अपने स्वीकृति भाषण में उन्होंने कहा, "मैं इस सम्मान को गहरे आभार के साथ स्वीकार करता हूँ और इसे 140 करोड़ भारतीयों और भारत-नामीबिया की मजबूत मित्रता को समर्पित करता हूँ।"

वेल्विथिया मिराबिलिस सम्मान की शुरुआत

वेल्विथिया मिराबिलिस सम्मान की शुरुआत 1995 में की गई थी। यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो श्रेष्ठ नेतृत्व का प्रदर्शन करते हैं और देशों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए उल्लेखनीय योगदान देते हैं। यह पुरस्कार जिस पौधे के नाम पर है — वेल्विथिया मिराबिलिस — वह रेगिस्तान में वर्षों तक जीवित रह सकता है। इसलिए इसे सहनशीलता और एकता का प्रतीक माना जाता है।

यह प्रधानमंत्री मोदी का 27वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है, और उनके वर्तमान पांच देशों के दौरे के दौरान मिला चौथा पुरस्कार है। खास बात यह है कि यह उन्हें 24 घंटे के भीतर मिला दूसरा सम्मान है, जो इस यात्रा में उन्हें मिल रही वैश्विक सराहना को दर्शाता है।

भारत-नामीबिया संबंधों में एक नया अध्याय

यह सम्मान भारत और नामीबिया के बीच संबंधों में एक नए मील के पत्थर को दर्शाता है। दोनों देशों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम किया है। यह पुरस्कार नामीबिया द्वारा भारत के समर्थन के प्रति आदर और कृतज्ञता का प्रतीक है, और भविष्य में संबंधों को और मजबूत बनाने की रुचि को भी दर्शाता है।

इस सम्मान के साथ, आने वाले महीनों में भारत और नामीबिया के बीच व्यापार, हरित ऊर्जा, और डिजिटल नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग और भी गहरा होने की उम्मीद है।

PM मोदी ब्राज़ील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 08 जुलाई 2025 को ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वे ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस' से सम्मानित किया। यह पुरस्कार पीएम मोदी को भारत-ब्राज़ील के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और ग्लोबल मंचों पर सहयोग बढ़ाने के लिए दिया गया। मई 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से पीएम मोदी को किसी विदेशी सरकार की तरफ से दिया गया यह 26वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है।

ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार

'ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस' ब्राज़ील का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार आम तौर पर राष्ट्रपति और सरकार प्रमुखों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने ब्राज़ील और अन्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में विशेष योगदान दिया हो।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान प्रदान करके ब्राज़ील ने भारत-ब्राज़ील रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में उनके प्रयासों की सराहना की है। साथ ही, उन्होंने BRICS, G20 और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग को बढ़ावा देने में जो भूमिका निभाई है, उसे भी इस सम्मान के माध्यम से वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया गया है।

भारत-ब्राज़ील संबंधों की मजबूती का प्रतीक

यह सम्मान भारत और ब्राज़ील, दो लोकतांत्रिक देशों, के बीच गहराते संबंधों का प्रतीक है। दोनों देशों के बीच साझा मूल्य हैं—जैसे संप्रभुता का सम्मान, सतत विकास, और बहुधुवीय वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देना। बीते वर्षों में भारत और ब्राज़ील ने कई क्षेत्रों में मिलकर कार्य किया है, जैसे:

- व्यापार और निवेश
- नवीकरणीय ऊर्जा
- कृषि तकनीक
- अंतरिक्ष अनुसंधान
- वैश्विक शासन और सहयोग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन दोनों देशों के बीच रिश्ते और भी मजबूत हुए हैं, खासकर बहुपक्षीय मंचों और क्षेत्रीय संवादों के ज़रिए। यह सम्मान इस साझेदारी की बढ़ती शक्ति और गहराई का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतीक बन गया है।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का गर्व

यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मई 2014 में कार्यभार संभालने के बाद किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा प्रदान किया गया 26वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। ये सम्मान भारत की कूटनीतिक शक्ति, बढ़ती आर्थिक ताकत, और वैश्विक नेतृत्व में उस पर हो रहे विश्वास को दर्शाते हैं।

ब्राज़ील द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित करना न केवल उनकी वैश्विक भूमिका की सराहना है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारत अब वैश्विक दक्षिण (Global South) में नीतियों के निर्माण में एक अहम भागीदार बन चुका है।

भारतीय नेताओं की ओर से सराहना

इस सम्मान की घोषणा के बाद पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। देशभर के नेताओं ने इसे गर्व का क्षण बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। कई नेताओं ने कहा कि यह सम्मान सिर्फ मोदी की कूटनीतिक सफलता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भारत की वैश्विक साख और अंतरराष्ट्रीय मामलों में बढ़ते प्रभाव को भी दर्शाता है।

'मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स' यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल

भारत के 'मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स' को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। इस प्रस्ताव का मूल्यांकन 6 से 16 जुलाई के बीच पेरिस में चल रहे यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति (डब्ल्यूएचसी) के 47वें सत्र में किया गया। इस सत्र में दुनिया भर से कुल 32 नए स्थलों के नामांकन पर चर्चा की गई, जिनमें भारत का यह ऐतिहासिक सैन्य तंत्र भी शामिल है। भारत की ओर से यह नामांकन 2024-25 चक्र के लिए प्रस्तुत किया गया।

क्या है 'मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स'?

'मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स' में 12 किले और किलेबंद क्षेत्र शामिल हैं जो 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच विकसित किए गए थे। यह किले मराठा साम्राज्य की सैन्य शक्ति, रणनीति और निर्माण कला का अद्भुत उदाहरण माने जाते हैं। ये किले न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि रणनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण थे।

महाराष्ट्र और तमिलनाडु के ये किले शामिल

इन 12 स्थानों में महाराष्ट्र का साल्हेर किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़, खांदेरी किला, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला किला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और तमिलनाडु का जिन्जी किला शामिल है। इन किलों को देश के कई भौगोलिक और प्राकृतिक क्षेत्रों में इस तरह से बनाया गया था कि वे मराठा शासन की सैन्य ताकत को दर्शाते हैं। इनमें पहाड़ी क्षेत्रों, समुद्र के किनारे और अंदरूनी मैदानों पर बने किलों का अनोखा संगम देखने को मिलता है।





कैसे चली मूल्यांकन प्रक्रिया?

विश्व धरोहर समिति की बैठक में 11 से 13 जुलाई के बीच 32 स्थलों की समीक्षा की गई। भारत के इस नामांकन के साथ-साथ कैमरून का डीआईवाई-जीआईडी-बीआईवाई (Diy-Gid-Biy) सांस्कृतिक क्षेत्र, मलावी का माउंट मुलंजे सांस्कृतिक परिदृश्य, और यूएई का फाया पैलियोलैंडस्केप जैसे स्थलों पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा दो पहले से ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सीमाओं में संभावित बदलाव के प्रस्तावों पर भी विचार किया गया।

एक देश से एक नामांकन नियम

यूनेस्को के 'ऑपरेशनल गाइडलाइंस 2023' के अनुसार, हर देश एक बार में केवल एक ही नामांकन जमा कर सकता है। भारत ने इस चक्र के लिए 'मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स' को चुना।

क्यों महत्वपूर्ण है नामांकन?

अगर इस नामांकन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में स्थान मिलता है, तो यह भारत के लिए गर्व का विषय होगा। इससे इन ऐतिहासिक स्थलों की वैश्विक मान्यता बढ़ेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और इनके संरक्षण के प्रयासों को और गति मिलेगी।

यूनेस्को की मान्यता और समिति की बैठक

पेरिस में आयोजित यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 47वीं बैठक में इन किलों को विश्व धरोहर सूची (World Heritage List) में शामिल किया गया। यह नामांकन भारत द्वारा 2024-25 विश्व धरोहर चक्र के तहत किया गया था। भारतीय अधिकारियों और इतिहासकारों ने इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को वैश्विक मंच पर प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया।

भारत का गौरव और ऐतिहासिक महत्व

ये किले केवल स्थापत्य संरचनाएं नहीं थे, बल्कि रणनीतिक सोच, आत्मरक्षा और एकता के प्रतीक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे मराठा शासकों ने इनका उपयोग साम्राज्य की नींव और रक्षा के लिए किया। विशेष रूप से रायगढ़ और प्रतापगढ़ जैसे किले भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उदाहरण के लिए, महाबलेश्वर से 22 किमी दूर स्थित प्रतापगढ़ किला कई प्रसिद्ध युद्धों का गवाह रहा है।

ब्यूनस आयर्स में पीएम मोदी को 'की टू द सिटी' सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान 'की टू द सिटी' (शहर की चाबी) सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान भारत और अर्जेंटीना के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। यह सम्मान विश्व के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ही दिया जाता है जो किसी शहर के साथ विशेष संबंध बनाते हैं या उस शहर में सांस्कृतिक, राजनीतिक या आर्थिक जुड़ाव बढ़ाते हैं। यह यात्रा ऐतिहासिक रही, क्योंकि 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली अर्जेंटीना यात्रा थी।

प्रधानमंत्री मोदी को प्रतीकात्मक सम्मान

ब्यूनस आयर्स शहर सरकार के प्रमुख जॉर्ज मैकरी ने पीएम मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। यह सम्मान परंपरागत रूप से किसी सम्मानित अतिथि को मैत्री और विश्वास का प्रतीक मानते हुए दिया जाता है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि यह सम्मान पीएम मोदी की भारत-अर्जेंटीना संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाने की भूमिका को दर्शाता है। पीएम मोदी ने इस गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए धन्यवाद व्यक्त किया और अपने आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर तस्वीरें और संदेश साझा किए।

सांस्कृतिक श्रद्धांजलि और साझा विरासत

अपनी यात्रा के दौरान, पीएम मोदी ने महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि गांधीजी का शांति और अहिंसा का संदेश आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। उन्होंने जनरल जोसे दे सैन मार्टिन को भी श्रद्धांजलि दी, जिन्हें अर्जेंटीना का राष्ट्रीय नायक माना जाता है। पीएम मोदी ने उनके दक्षिण अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व की सराहना की। इस यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य सांस्कृतिक सम्मान और साझा मूल्यों को उजागर करना था।

भारत-अर्जेंटीना संबंधों को नया विस्तार

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति जेवियर मिलेई से मुलाकात की और उच्च स्तरीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत-अर्जेंटीना के 75 वर्ष के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाया और रक्षा, ऊर्जा, कृषि, खनन और व्यापार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।

- अर्जेंटीना ने भारत को लिथियम और शेल गैस आपूर्ति करने पर सहमति दी, जो भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए अहम है।
- पीएम मोदी ने भारतीय दवाओं के आयात में सुविधा की भी मांग की।
- खेल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा हुई।
- पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मिलेई को भारत आने का आमंत्रण भी दिया।

प्रवासी भारतीयों से भावुक मुलाकात

ब्यूनस आयर्स में पीएम मोदी का प्रवासी भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से स्वागत किया। लोग उनके होटल के बाहर भारतीय झंडे लहराते, गीत गाते और नृत्य करते नजर आए। पीएम मोदी ने उनसे आत्मीयता से बातचीत की और कहा, "दूरी कभी भी सांस्कृतिक रिश्तों को तोड़ नहीं सकती।" उन्होंने प्रवासी भारतीयों के स्नेह को सराहा और कहा कि उनकी उपस्थिति ने इस यात्रा को और भी खास बना दिया।

केंद्र सरकार ने 18 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के स्थानांतरण और प्रत्यावर्तन को अधिसूचित किया

भारत में न्यायपालिका की निष्पक्षता, दक्षता और संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 14 जुलाई 2025 को 18 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण और प्रत्यावर्तन से संबंधित आदेश अधिसूचित किए। यह निर्णय 26 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के आधार पर लिया गया। इन रणनीतिक नियुक्तियों का उद्देश्य न्यायिक कार्यप्रणाली को मजबूत करना, मामलों के निपटान में समानता लाना और राज्यों के बीच न्यायिक स्टाफ में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है।

पृष्ठभूमि

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत, राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की सलाह से एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, इन स्थानांतरणों की अनुशंसा करता है। वर्तमान स्थानांतरण इसी प्रक्रिया का हिस्सा है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता व निष्पक्षता को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जाते हैं।





स्थानांतरणों का महत्व

इन न्यायिक फेरबदल का प्रशासनिक ही नहीं, बल्कि व्यापक प्रभाव होता है:

- निष्पक्षता: न्यायाधीशों को उनके मूल राज्य से बाहर नियुक्त कर क्षेत्रीय पक्षपात या स्थानीय दबाव को कम किया जाता है।
- दक्षता: जिन उच्च न्यायालयों पर कार्यभार अधिक है, वहां अन्य न्यायालयों से अनुभवी न्यायाधीशों की नियुक्ति से राहत मिलती है।
- विशेषज्ञता का आदान-प्रदान: स्थानांतरित न्यायाधीश अपने पिछले अनुभव और दृष्टिकोण के साथ नई न्यायिक इकाई को सशक्त बनाते हैं।
- राष्ट्रीय एकता: ये स्थानांतरण पूरे देश में न्यायिक दृष्टिकोण की एकरूपता को बढ़ावा देते हैं।

स्थानांतरित न्यायाधीशों की सूची

- न्यायमूर्ति तडकमल्ला विनोद कुमार: तेलंगाना से मद्रास हाईकोर्ट
- न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी: इलाहाबाद से कर्नाटक हाईकोर्ट
- न्यायमूर्ति अरुण मोंगा: राजस्थान से दिल्ली हाईकोर्ट
- न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल: पंजाब एवं हरियाणा से दिल्ली हाईकोर्ट
- न्यायमूर्ति सुधीर सिंह: पंजाब एवं हरियाणा से पटना हाईकोर्ट
- न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर: राजस्थान से बॉम्बे हाईकोर्ट
- न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला: इलाहाबाद से दिल्ली हाईकोर्ट
- न्यायमूर्ति बट्टू देवनंद: मद्रास से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (प्रत्यावर्तित)
- न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह: मद्रास से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
- न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह: केरल से कर्नाटक हाईकोर्ट
- न्यायमूर्ति विवेक चौधरी: इलाहाबाद से दिल्ली हाईकोर्ट
- न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा: पंजाब एवं हरियाणा से राजस्थान हाईकोर्ट
- न्यायमूर्ति सुमन श्याम: गुवाहाटी से बॉम्बे हाईकोर्ट
- न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा: इलाहाबाद से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
- न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव सांब्रे: बॉम्बे से दिल्ली हाईकोर्ट
- न्यायमूर्ति मनश रंजन पाठक: गुवाहाटी से ओडिशा हाईकोर्ट
- न्यायमूर्ति लानुसुंगकुम जामिर: गुवाहाटी से कलकत्ता हाईकोर्ट
- न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव: कर्नाटक से दिल्ली हाईकोर्ट

उद्देश्य

इन स्थानांतरणों के प्रमुख उद्देश्य हैं:

- राष्ट्रीय न्यायिक एकरूपता को बढ़ावा देना
 - अत्यधिक बोझ वाले न्यायालयों का कार्यभार संतुलित करना
 - पारदर्शिता व निष्पक्षता सुनिश्चित करना
 - हर उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना
 - स्थानीय हस्तक्षेप से मुक्त निष्पक्ष न्यायिक माहौल प्रदान करना
- यह कदम न्यायिक सुधारों को गति देने और नागरिकों का न्यायपालिका में विश्वास बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25: देश के स्वच्छ शहरों में अहमदाबाद अव्वल

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत भारत के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण में अहमदाबाद को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। यह सर्वेक्षण आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष 4,589 शहरों ने भाग लिया। सर्वेक्षण के परिणामों ने शहरी भारत में सतत स्वच्छता और नागरिक सहभागिता आधारित पहलों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाया।

स्वच्छ सर्वेक्षण की पृष्ठभूमि

स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत 2016 में 73 शहरों के साथ हुई थी। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर प्रतिस्पर्धात्मक भावना उत्पन्न करना है। यह एक वार्षिक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकन पर आधारित सर्वेक्षण है, जिसमें नागरिक फीडबैक, कचरा प्रबंधन, और सेवा स्तर प्रगति जैसे मानकों को ध्यान में रखा जाता है।

2024-25 सर्वेक्षण की प्रमुख झलकियाँ

- अहमदाबाद ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान प्राप्त किया।
- इंदौर, सूरत और नवी मुंबई को "सुपर स्वच्छ लीग शहरों" की नई श्रेणी में शामिल किया गया, जो पिछले तीन वर्षों में लगातार टॉप परफॉर्मर रहे हैं।
- सर्वेक्षण अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच आयोजित किया गया।
- पहली बार शहरों को 5 जनसंख्या-आधारित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया।
- ध्यान केंद्रित क्षेत्रों में गंगा नगरों, छावनी परिषदों, सफाई मित्र सुरक्षा, महाकुंभ, और राज्य स्तरीय पुरस्कार शामिल रहे।

सुपर स्वच्छ लीग का महत्व

2024-25 में शुरू की गई यह श्रेणी उन शहरों को सम्मानित करती है जो लगातार तीन वर्षों से अपने वर्ग में शीर्ष तीन में रहे हैं। यह एक माँडल शहरों की लीग के निर्माण की पहल है, जो केवल एक बार की सफलता नहीं बल्कि दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को मान्यता देती है।

सर्वेक्षण के उद्देश्य

- शहरों के बीच स्वच्छता को लेकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।
- नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- कचरे की छंटाई, वैज्ञानिक निपटान, और व्यवहार परिवर्तन को मापना।
- सफाई मित्र सुरक्षा जैसी श्रेणियों के माध्यम से नवाचार को प्रेरित करना।

विशेष पहलें

- 15 अगस्त 2024 से एक वर्षीय अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य पुराने कचरा स्थलों की सफाई (legacy landfill remediation) है।
- जनसंख्या आधारित श्रेणियों के आधार पर शहरों का वर्गीकरण कर मूल्यांकन को और अधिक न्यायसंगत और तुलनीय बनाया गया।
- गंगा नगरों और धार्मिक स्थलों को शामिल कर सततता और समावेशन पर बल दिया गया है।

यह सर्वेक्षण भारत में स्वच्छता संस्कृति को मजबूती देने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है।





A. सुपर स्वच्छ लीग शहर विजेता

क्रम संख्या	जनसंख्या श्रेणी	राज्य	शहर
1	10 लाख से अधिक	मध्य प्रदेश	इंदौर
2	10 लाख से अधिक	गुजरात	सूरत
3	10 लाख से अधिक	महाराष्ट्र	नवी मुंबई
4	10 लाख से अधिक	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
5	3-10 लाख	उत्तर प्रदेश	नोएडा
6	3-10 लाख	चंडीगढ़	चंडीगढ़
7	3-10 लाख	कर्नाटक	मैसूरु
8	3-10 लाख	मध्य प्रदेश	उज्जैन
9	3-10 लाख	गुजरात	गांधीनगर
10	3-10 लाख	आंध्र प्रदेश	गुंटूर
11	50,000-3 लाख	दिल्ली (एनडीएमसी)	नई दिल्ली
12	50,000-3 लाख	आंध्र प्रदेश	तिरुपति
13	50,000-3 लाख	छत्तीसगढ़	अंबिकापुर
14	50,000-3 लाख	महाराष्ट्र	लोनावाला
15	20,000-50,000	महाराष्ट्र	विटा
16	20,000-50,000	महाराष्ट्र	सासवड
17	20,000-50,000	महाराष्ट्र	देवलाई प्रवरा
18	20,000-50,000	राजस्थान	डूंगरपुर
19	20,000 से कम	महाराष्ट्र	पंचगनी
20	20,000 से कम	छत्तीसगढ़	पाटन
21	20,000 से कम	महाराष्ट्र	पन्हाला
22	20,000 से कम	छत्तीसगढ़	विश्रामपुर
23	20,000 से कम	मध्य प्रदेश	बुधनी

B. राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता: जनसंख्या श्रेणी के अनुसार स्वच्छ शहर

क्रम संख्या	जनसंख्या श्रेणी	राज्य	शहर
1	10 लाख से अधिक	गुजरात	अहमदाबाद
2	10 लाख से अधिक	मध्य प्रदेश	भोपाल
3	10 लाख से अधिक	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
4	3-10 लाख	महाराष्ट्र	मीरा-भायंदर
5	3-10 लाख	छत्तीसगढ़	बिलासपुर
6	3-10 लाख	झारखंड	जमशेदपुर
7	50,000-3 लाख	मध्य प्रदेश	देवास
8	50,000-3 लाख	महाराष्ट्र	कराड
9	50,000-3 लाख	हरियाणा	करनाल

क्रम संख्या	जनसंख्या श्रेणी	राज्य	शहर
10	20,000-50,000	गोवा	पणजी
11	20,000-50,000	ओडिशा	अस्का
12	20,000-50,000	छत्तीसगढ़	कुम्हारी
13	20,000 से कम	छत्तीसगढ़	बिल्हा
14	20,000 से कम	ओडिशा	चिकीटी
15	20,000 से कम	मध्य प्रदेश	शाहगंज

C. मंत्रिस्तरीय पुरस्कार विजेता: विशेष श्रेणी

क्रम संख्या	विशेष पहल की मान्यता	राज्य	शहर
1	स्वच्छ महाकुंभ 2025 मान्यता	—	—
2	गंगा नगर	आंध्र प्रदेश	जीवीएमसी विशाखापट्टनम
3	गंगा नगर	मध्य प्रदेश	जबलपुर
4	गंगा नगर	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर
5	छावनी परिषद	तेलंगाना	सिकंदराबाद छावनी
6	गंगा नगर	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज

D. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वच्छ शहर का वादा

क्रम संख्या	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	शहर
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	श्री विजयपुरम
2	आंध्र प्रदेश	राजमुंद्री
3	अरुणाचल प्रदेश	जयरामपुर
4	असम	नॉर्थ लखीमपुर
5	असम	गुवाहाटी
6	बिहार	पटना
7	छत्तीसगढ़	रायपुर
8	दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव	दीव-दमन
9	गोवा	सांकेलिम
10	गुजरात	वडोदरा
11	हरियाणा	सोनीपत
12	हिमाचल प्रदेश	ठियोग
13	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
14	झारखंड	बुंड़ू
15	कर्नाटक	दावणगेरे
16	केरल	मत्तनूर
17	लद्दाख	कारगिल
18	मध्य प्रदेश	ग्वालियर
19	महाराष्ट्र	पिंपरी चिंचवड
20	मणिपुर	जीरीबाम





क्रम संख्या	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	शहर
21	मेघालय	शिलांग
22	मिज़ोरम	लुंगलई
23	नागालैंड	जलुकी
24	ओडिशा	भुवनेश्वर
25	पुडुचेरी	औल्यारेट-ओझुकारई
26	पंजाब	बठिंडा
27	राजस्थान	जयपुर ग्रेटर
28	सिक्किम	मंगन
29	तमिलनाडु	नमक्कल
30	तेलंगाना	ग्रेटर हैदराबाद
31	त्रिपुरा	खोवाई
32	उत्तर प्रदेश	आगरा
33	उत्तराखंड	लालकुआँ
34	पश्चिम बंगाल	बैद्यबटी

ऐतिहासिक दिन! भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 24 जुलाई 2025 को एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए। तीन वर्षों से अधिक समय तक चली व्यापक वार्ताओं के बाद यह समझौता संपन्न हुआ है, जो द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन देने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और रणनीतिक सहयोग को कई क्षेत्रों में गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह भारत का अब तक का सबसे व्यापक एफटीए है और ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार समझौता माना जा रहा है, जो दोनों देशों के संबंधों में एक नए युग की शुरुआत करता है।

पृष्ठभूमि

भारत-यूके FTA वार्ताएं जनवरी 2022 में यूके-इंडिया एन्हांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप की घोषणा के बाद शुरू हुई थीं। 14 दौर की बातचीत और ब्रिटेन में राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन के बाद, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह समझौता साकार हुआ। यह समझौता महामारी के बाद वैश्विक पुनर्निर्माण, भू-राजनीतिक बदलावों और विश्वसनीय व्यापार साझेदारों की खोज की पृष्ठभूमि में आया है।

महत्व

- भारत के लिए: ब्रिटेन के उच्च प्रौद्योगिकी उत्पाद जैसे चिकित्सा उपकरण और एयरोस्पेस कंपोनेंट अब अधिक सुलभ और सस्ते होंगे।
- ब्रिटेन के लिए: भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार तक नई पहुंच खुलेगी।
- यह एक नियम-आधारित, लोकतांत्रिक साझेदारी को दर्शाता है जो भविष्य की वैश्विक भागीदारी के लिए एक आदर्श स्थापित कर सकती है।

उद्देश्य

- वस्तुओं और सेवाओं पर शुल्क को समाप्त करना या कम करना।
- निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना।
- सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, रक्षा और शिक्षा में सहयोग को सुदृढ़ करना।
- 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 120 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य।

मुख्य विशेषताएं

- भारत में ब्रिटेन से आयातित उत्पादों पर औसत टैरिफ 15% से घटकर 3% हो जाएगा।
- भारत में लाभान्वित होने वाले प्रमुख क्षेत्र: वस्त्र, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, रत्न एवं आभूषण, ऑटो पार्ट्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स।
- ब्रिटिश चिकित्सा उपकरण और एयरोस्पेस पार्ट्स भारतीय बाजार में अधिक किफायती होंगे।

नई रणनीतिक साझेदारी – इंडिया-यूके विज़न 2035

व्यापार से आगे बढ़कर सहयोग को विस्तारित करने के लिए निम्नलिखित पहल की गई:

- डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप
- टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव
- क्लाइमेट चेंज एकशन
- शैक्षिक सहयोग

आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव

- द्विपक्षीय व्यापार में हर साल £25.5 बिलियन की वृद्धि।
- दोनों देशों में हज़ारों नए रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना।
- एयरबस और रोल्स-रॉयस जैसी ब्रिटिश कंपनियां भारतीय एयरलाइनों को विमान आपूर्ति शुरू करेंगी।
- अपराध, धोखाधड़ी और प्रवासन जैसे मुद्दों पर इंटेलिजेंस साझाकरण और सहयोग में वृद्धि।
- दोनों देशों ने आतंकवाद और कट्टरवाद की निंदा करते हुए सुरक्षा और लोकतंत्र के साझा मूल्यों की पुष्टि की।

यूके-भारत मुक्त व्यापार समझौता: किसे लाभ, क्या हुआ सस्ता, और आप पर क्या असर पड़ेगा!

हाल ही में 24 जुलाई 2025 को हस्ताक्षरित भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में एक परिवर्तनकारी क्षण को दर्शाता है। इस समझौते के तहत कई उत्पादों पर शुल्क कम या समाप्त कर दिए जाएंगे, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं के लिए कई आयातित वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, वहीं भारतीय निर्यात को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा। प्रमुख वस्तुओं जैसे स्कांच व्हिस्की, ब्रिटिश लग्जरी कारें, चॉकलेट और कॉस्मेटिक्स की कीमतों में समय के साथ उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिलेगी। यह समझौता दोनों देशों के उपभोक्ताओं, उद्योगों और रोजगार के क्षेत्र के लिए लाभकारी साबित होने की उम्मीद है।

एफटीए (मुक्त व्यापार समझौते) को लेकर वार्ताएं जनवरी 2022 में शुरू हुई थीं, और तीन वर्षों से अधिक चली चर्चाओं और कई दौर की कूटनीतिक बैठकों के बाद इसे जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूके यात्रा के दौरान आधिकारिक रूप से हस्ताक्षरित किया गया। इस एफटीए को भारत का अब तक का सबसे व्यापक व्यापार समझौता और ब्रेक्सिट के बाद यूके का सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समझौता माना जा रहा है।

समझौते का महत्व

यह समझौता यूके को होने वाले 99% भारतीय निर्यातों पर शुल्क समाप्त कर देता है।

भारतीय उपभोक्ताओं के लिए स्कांच व्हिस्की, लग्जरी कारें, चॉकलेट और मेडिकल उपकरण जैसी उच्च श्रेणी की आयातित वस्तुएं अधिक सुलभ हो जाएंगी।

अनुमान के अनुसार, यह समझौता यूके की जीडीपी में सालाना £4.8 बिलियन (\$6.5 बिलियन) का इजाफा करेगा।





इसका उद्देश्य 2030 तक भारत से यूके को होने वाले निर्यात को दोगुना करना है।

उद्देश्य

इस समझौते के प्रमुख उद्देश्य हैं:

- वस्तुओं और सेवाओं तक सुलभ और किफायती पहुंच को बढ़ावा देना।
- निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित करना।
- दोनों देशों के एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) और निर्यातकों को समर्थन देना।
- कुशल पेशेवरों की अस्थायी आवाजाही को सुगम बनाना।
- गैर-शुल्क बाधाओं को कम करना और बाजार तक पहुंच में सुधार करना।

भारतीयों के लिए क्या होगा सस्ता?

1. स्कॉच व्हिस्की और जिन
 - o स्कॉच व्हिस्की और जिन पर वर्तमान 150% आयात शुल्क को घटाकर पहले चरण में 75% किया जाएगा और अगले 10 वर्षों में इसे 40% तक लाया जाएगा।
 - o इससे डियाजियो जैसे प्रीमियम ब्रांड्स को बड़ा लाभ मिलेगा।
2. ब्रिटिश लग्जरी कारें
 - o यूके में बनी कारों पर वर्तमान में 100% से अधिक आयात शुल्क है, जिसे कोटा आधारित प्रणाली के तहत घटाकर 10% किया जाएगा।
 - o जगुआर लैंड रोवर और एस्टन मार्टिन जैसे निर्माताओं को सीधा लाभ होगा।
3. चॉकलेट, बिस्किट और सैल्मन मछली
 - o ब्रिटिश निर्मित चॉकलेट, बिस्किट और सैल्मन पर शुल्क में कमी से ये उत्पाद भारतीय सुपरमार्केट्स में सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगे।
4. कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर उत्पाद
 - o ब्रिटिश ब्रांड्स से आने वाले सौंदर्य प्रसाधन और स्किनकेयर उत्पादों पर शुल्क में कटौती की जाएगी, जिससे इनकी कीमतें घटेंगी।
5. चिकित्सा उपकरण
 - o यूके में निर्मित चिकित्सा उपकरणों और डायग्नोस्टिक उपकरणों तक सस्ता और आसान पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

भारत में किसे मिलेगा लाभ?

1. वस्त्र एवं चमड़ा निर्यातक
 - o परिधान, होम टेक्स्टाइल और चमड़े के सामानों पर यूके द्वारा लगाए गए शुल्क (जो कि 12% तक थे) हटाए जाने से भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे।
2. रत्न एवं आभूषण क्षेत्र
 - o सोना, हीरे और आभूषणों पर शून्य शुल्क से भारतीय निर्यातकों को लाभ मिलेगा और भारतीय कारीगरी को वैश्विक मंच पर बढ़ावा मिलेगा।
3. कृषि, फार्मा एवं प्रोसेस्ड फूड
 - o चावल, मसाले, झींगा, चाय और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों पर शुल्क में कटौती से इन क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा।
 - o भारतीय फार्मा कंपनियों को यूके बाजार में प्रवेश और आसान होगा।

4. इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन
 - o ईवी और हाइब्रिड वाहन निर्माताओं को कोटा आधारित प्रणाली के तहत प्राथमिकता मिलेगी।
 - o टाटा मोटर्स, महिंद्रा इलेक्ट्रिक और भारत फोर्ज जैसी कंपनियों को इससे सीधा लाभ होगा।
5. पेशेवर एवं कुशल कार्यकर्ता
 - o भारतीय पेशेवरों (जैसे शेफ, योग प्रशिक्षक, संगीतकार आदि) के लिए वीज़ा और वर्क परमिट प्रक्रियाएं सरल होंगी।
 - o यूके में काम करने वाले भारतीयों को तीन साल तक सोशल सिक्योरिटी से छूट मिलेगी, जिससे हर साल लगभग ₹4,000 करोड़ की बचत होगी।

Cabinet Approvals

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति (एनएसपी) 2025 को मंजूरी दे दी है। यह नीति 2001 की नीति का स्थान लेगी जिसका उद्देश्य भारत को 2036 के ओलंपिक खेलों के दृष्टिकोण के साथ एक वैश्विक खेल महाशक्ति बनाना है। यह नीति पाँच स्तंभों पर आधारित है - वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास के लिए खेल, सामाजिक विकास के लिए खेल, जन आंदोलन के रूप में खेल और शिक्षा के साथ एकीकरण (एनईपी 2020) - और यह जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, खेल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल पर्यटन, स्वदेशी खेल, जन भागीदारी और स्कूल स्तर पर खेल एकीकरण पर केंद्रित है। केपीआई, पीपीपी मॉडल और एक राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली वाला एक रणनीतिक ढाँचा कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करेगा और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करेगा।
- कैबिनेट ने उभरते और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए ₹1 लाख करोड़ की निधि वाली अनुसंधान विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना को मंजूरी दे दी है। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) द्वारा प्रबंधित, यह योजना अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और नवाचारों के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक रियायती ऋण, इक्विटी सहायता और एक डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स प्रदान करती है। इसका उद्देश्य वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता, आत्मनिर्भरता और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाना बढ़ाना है, जिसका संचालन प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले एएनआरएफ बोर्ड द्वारा किया जाएगा और कार्यान्वयन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा।
- कैबिनेट ने विनिर्माण क्षेत्र और पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, दो वर्षों (अगस्त 2025 - जुलाई 2027) में 3.5 करोड़ से ज़्यादा रोजगार सृजित करने के लिए ₹99,446 करोड़ के परिव्यय वाली रोजगार-आधारित प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दे दी है। भाग ए के तहत, पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को दो किश्तों में ₹15,000 तक का एक महीने का वेतन मिलेगा, जबकि भाग बी के तहत, नियोजितों को कम से कम छह महीने (विनिर्माण क्षेत्र के लिए चार साल तक बढ़ाया गया) तक नियुक्त प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ₹1,000-₹3,000 प्रति माह मिलेंगे। सभी भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से होंगे, जिसका उद्देश्य कार्यबल को औपचारिक बनाना, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और सामाजिक सुरक्षा कवरेज को मजबूत करना है।





- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) के तहत ₹1,853 करोड़ की लागत से तमिलनाडु में NH-87 के परमकुडी-रामनाथपुरम खंड के 4-लेन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। 46.7 किलोमीटर लंबी यह परियोजना मौजूदा 2-लेन राजमार्ग पर भीड़भाड़ कम करेगी, यातायात सुरक्षा में सुधार करेगी और NH-38, NH-85, NH-36, NH-536, NH-32 और SH-47, SH-29, SH-34 जैसे प्रमुख मार्गों को जोड़ेगी। यह मदुरै हवाई अड्डे, रामेश्वरम और पंबन बंदरगाहों और परमकुडी, रामनाथपुरम, रामेश्वरम जैसे प्रमुख शहरों के लिए मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। इस परियोजना से क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने, रामेश्वरम और धनुषकोडी में पर्यटन को बढ़ावा मिलने और लगभग 8.4 लाख व्यक्ति-दिवस प्रत्यक्ष और 10.45 लाख व्यक्ति-दिवस अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 100 जिलों को लक्षित करते हुए छह साल (2025-31) के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित यह योजना फसल विविधीकरण, टिकाऊ खेती, बेहतर सिंचाई, कटाई के बाद भंडारण में वृद्धि और बेहतर ऋण पहुंच पर केंद्रित है। इसे राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में 11 विभागों में 36 योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से लागू किया जाएगा। जिलों का चयन कम उत्पादकता, कम फसल तीव्रता और कम ऋण वितरण के आधार पर किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक राज्य में न्यूनतम एक जिला होगा। डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से 117 प्रदर्शन संकेतकों का उपयोग करके निगरानी की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, स्थानीय आजीविका का सृजन करना, जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर भारत में योगदान देना है।
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) को नवरत्न सीपीएसई पर लागू निवेश सीमाओं से एक विशेष छूट प्रदान की है, जिससे उसे अपनी सहायक कंपनी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (एनआईआरएल) में बिना पूर्व अनुमोदन के नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 7,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की अनुमति मिल गई है। यह एनएलसीआईएल के 2030 तक 10.11 गीगावाट और 2047 तक 32 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लक्ष्य का समर्थन करता है, जो 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने के लिए भारत की सीओपी26 प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। यह कदम भारत के स्वच्छ ऊर्जा में बदलाव को तेज करेगा, कोयले के आयात को कम करेगा, 24x7 बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और एक हरित ऊर्जा नेता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करेगा। वर्तमान में, एनएलसीआईएल 2 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता का संचालन करता है।
- मंत्रिमंडल ने नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के लिए एनटीपीसी को शक्तियों के बड़े हुए प्रतिनिधिमंडल को मंजूरी दी - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने एनटीपीसी लिमिटेड को अपनी सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) के लिए एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआईएल) और अन्य संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में निवेश करने के लिए 7,500 करोड़ रुपये की पिछली सीमा से 20,000 करोड़ रुपये तक निवेश शक्तियों के एक विस्तारित प्रतिनिधिमंडल को मंजूरी दी है। यह 2032 तक एनटीपीसी के 60 गीगावाट आरई क्षमता के लक्ष्य की ओर नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता वृद्धि में तेजी लाएगा, जिससे भारत को 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य और 2070 तक नेट जीरो की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी एनजीईएल के

पास वर्तमान में लगभग 32 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का पोर्टफोलियो है, जिसमें 6 गीगावाट परिचालन, 17 गीगावाट अनुबंधित/प्रदान की गई और 9 गीगावाट पाइपलाइन परियोजनाएं शामिल हैं।

- कैबिनेट ने 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' को मंजूरी दी - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश्य 11 केंद्रीय विभागों, राज्य सरकारों और अन्य भागीदारों की योजनाओं को मिलाकर कम उपज वाले जिलों में कृषि उत्पादकता में सुधार करना है। लगभग 100 जिलों की पहचान की जाएगी, प्रत्येक राज्य से कम से कम एक जिला, कम उत्पादकता वाले या कृषि क्रेडिट कार्ड (एसीसी) के सीमित उपयोग वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी होगा, और नीति आयोग एक डैशबोर्ड के माध्यम से प्रगति को ट्रैक करेगा। अभियान रबी सीजन (अक्टूबर 2025) में शुरू होगा और इसमें ग्राम पंचायतों/जिला कलेक्टरों के नेतृत्व वाली जिला-स्तरीय समितियां शामिल होंगी, जिसमें राज्य और केंद्र स्तर की टीमों प्रभावी योजना अभिसरण सुनिश्चित करेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय या शीर्ष-स्तरीय बेंचमार्क तक उत्पादकता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ फसलों, फलों की खेती, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन और कृषि वानिकी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

संसदीय समाचार

जुलाई माह की राज्यवार महत्वपूर्ण घटनाएँ

आंध्र प्रदेश

- आंध्र प्रदेश का ऐतिहासिक बंदरगाह नगर मछलीपट्टनम अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। मंगीनापुडी में एक नया ग्रीनफील्ड पोर्ट तेजी से निर्माणाधीन है, जिसका 48% काम पहले ही पूरा हो चुका है। यह बंदरगाह 2026 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है और इससे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना—दोनों राज्यों को आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
- आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम ग्रीनफील्ड बंदरगाह का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिसका 48% काम पूरा हो चुका है और 2026 के अंत तक परिचालन शुरू करने की योजना है। MEIL द्वारा निर्मित यह बंदरगाह क्षेत्र में निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देगा। ₹5,155 करोड़ की इस परियोजना में 2007 से देरी हो रही थी, लेकिन अब मछलीपट्टनम बंदरगाह विकास निगम लिमिटेड के तहत यह फिर से पटरी पर आ गई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही संबंधित बुनियादी ढाँचे, जैसे शुष्क बंदरगाह और माल ढुलाई गलियारों में निवेश कर रहे हैं। स्थानीय लोग ज़मीन की बेहतर कीमतों और रोजगार को लेकर आशान्वित हैं। इस बंदरगाह से हर साल 36 मिलियन टन माल की ढुलाई और बड़े जहाजों को सहारा मिलने की उम्मीद है, जिससे यह पूर्वी तट पर एक प्रमुख व्यापार केंद्र बन जाएगा।

असम

- असम सरकार ने 2025-26 के बजट लक्ष्यों के तहत ग्रामीण जीवन, शिक्षा और पारंपरिक उद्योगों में सुधार के लिए कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। इन निर्णयों में गांव प्रधानों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि, मानव-हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गजा मित्र योजना, छात्रों और कारीगरों के लिए वित्तीय सहायता, और एक विश्वविद्यालय का नाम बदलना शामिल है।





बिहार

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में ₹7,200 करोड़ की आधारभूत परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य राज्य को विकास और अवसरों के केंद्र के रूप में बदलना है। ये परियोजनाएं 'विकसित भारत मिशन' का हिस्सा हैं, जो संतुलित क्षेत्रीय विकास और पूर्वी भारत को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाने की परिकल्पना करती हैं।
- महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन करते हुए, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय 8 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। इस फैसले का उद्देश्य महिलाओं की सरकारी सेवाओं में भागीदारी बढ़ाना और उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाना है।
- आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और इससे राज्य के लगभग 1.67 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। यह निर्णय कल्याणकारी नीति और अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों के सम्मिलन का प्रतीक है, जो "सभी के लिए ऊर्जा" के व्यापक विज़न के अंतर्गत लिया गया है।

गुजरात

- गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जिसने "आदिवासी जीनोम अनुक्रमण परियोजना" (Tribal Genome Sequencing Project) की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य है—आदिवासी समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना, अनुवांशिक अनुसंधान के माध्यम से रोगों की प्रारंभिक पहचान करना, और व्यक्तिगत चिकित्सा समाधान विकसित करना।
- एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात एक करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। इन राज्यों में कुल मिलाकर भारत के निवेशक आधार का 36% हिस्सा है, जो बढ़ती वित्तीय भागीदारी को दर्शाता है। मई 2025 तक, भारत में लगभग 11.5 करोड़ निवेशक होंगे, जिनमें से 11 लाख नए निवेशक अकेले मई में जुड़े हैं, जो मंदी के बाद नई वृद्धि को दर्शाता है। उत्तर भारत 4.2 करोड़ निवेशकों के साथ क्षेत्रीय स्तर पर सबसे आगे है, उसके बाद पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी भारत का स्थान है।
- गुजरात, 30 सितंबर, 2024 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा शुरू किए गए कूज भारत मिशन से आधिकारिक रूप से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस मिशन का लक्ष्य 2029 तक कूज पर्यटन को दस गुना बढ़ाना है। गुजरात दीव, पोरबंदर, द्वारका और पडाला द्वीप जैसे स्थलों को जोड़ते हुए कई तटीय कूज सर्किट बनाने की योजना बना रहा है। यह कदम न केवल भारत के पर्यटन लक्ष्यों का समर्थन करता है, बल्कि गुजरात की समुद्री अर्थव्यवस्था को भी विकसित करने में मदद करता है।

गोवा

- गोवा ने मंडोवी नदी पर भारत की पहली रो-रो फेरी सेवा शुरू की है, जिसमें दो उच्च तकनीक वाली फेरी, गंगोत्री और द्वारका, शामिल हैं। विजय मरीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित ये जहाज, चोराओ और रिबंदर के बीच यात्रा के समय को केवल 12-13 मिनट तक कम कर देते हैं और यात्रियों और वाहनों को ले जा सकते हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा शुरू की गई यह परियोजना सरकार के लिए निःशुल्क है और जल परिवहन में सुधार, पर्यटन और स्थानीय यात्रा को बढ़ावा देने का वादा करती है। इन फेरी में एसी केबिन, वाहन लेन और आपातकालीन किट जैसी आधुनिक सुविधाएँ हैं, जो सभी के लिए सुरक्षित और तेज़ यात्रा प्रदान करती हैं।

हिमाचल प्रदेश

- हिमाचल प्रदेश ने जुलाई 2025 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन वितरण के लिए भारत की पहली आधार-आधारित चेहरा प्रमाणीकरण (फेसअथ) प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली ओटीपी या उंगलियों के निशान के बजाय व्यक्ति के चेहरे की पुष्टि के लिए स्मार्टफोन के कैमरे का उपयोग करती है। डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग (डीडीटीजी) द्वारा संचालित और गोकुल बटेल द्वारा समर्थित इस नई पद्धति का उद्देश्य पिछली समस्याओं को दूर करना और सुचारू एवं तेज़ सेवा सुनिश्चित करना है। हिमाचल प्रदेश की यह पहल डिजिटल और समावेशी शासन की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में, भूमि पंजीकरण को डिजिटल बनाने और कागज़-रहित, उपस्थिति-रहित और नकदी-रहित शासन को बढ़ावा देने के लिए 'माई डीड' एनजीडीआरएस (राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली) पायलट परियोजना शुरू की है। यह प्रणाली नागरिकों को भूमि पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा देती है, जिसके लिए उन्हें तहसील कार्यालय में केवल एक बार जाना पड़ता है। शुरुआत में 10 जिलों की 10 तहसीलों में शुरू की गई इस परियोजना को पूरक डिजिटल राजस्व सुधारों का समर्थन प्राप्त है, जिसमें हिंदी में एक नया जमाबंदी प्रारूप, ई-रोज़नामचा वक्तव्य (डिजिटल डायरी), और कारगुजारी (ऑनलाइन उपस्थिति) शामिल हैं।

झारखंड

- झारखंड जल्द ही सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के सहयोग और झारखंड पर्यटन विकास निगम (जेटीडीसी) की देखरेख में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू करेगा। पायलट चरण में दो मार्गों—रजरप्पा और पतरातू—से होते हुए उत्तरी उरीमारी (बिरसा) कोयला खदान का भ्रमण शामिल है, जिसमें खदानों, मंदिरों और घाटियों का भ्रमण शामिल है। इस पहल का उद्देश्य वैकल्पिक पर्यटन को बढ़ावा देना, रोज़गार सृजन और औद्योगिक विरासत का संरक्षण करना है, साथ ही इको-माइनिंग सर्किट और एक धार्मिक सर्किट की भी योजना है।

कर्नाटक

- कर्नाटक मंत्रिमंडल ने शहर के बुनियादी ढाँचे के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नाम पर रखने का फैसला किया है। बेंगलुरु मेट्रो और एलिवेटेड हाईवे की नींव रखने से लेकर केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन तक, शहर के विकास में सिंह का योगदान गहराई से समायोजित हुआ है।





- केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक के शिवमोग्गा में शरवती बैकवाटर पर ₹470 करोड़ से अधिक की लागत से बने 2.44 किलोमीटर लंबे सिंगदूर पुल का उद्घाटन किया। देवी चौदेश्वरी देवी के नाम पर बना यह पुल सागर और मारकुटिका को जोड़ता है, जिससे लिंगनमक्की बांध के कारण टूटे संपर्क बहाल हो गए हैं। गडकरी ने यह भी बताया कि कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और ₹5 लाख करोड़ की प्रमुख सड़क परियोजनाएँ जल्द ही शुरू होने वाली हैं।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में, बेंगलुरु दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 36वें स्थान पर पहुँच गया, जो पिछले वर्ष के 125वें स्थान से बेहतर है, लेकिन शौचालय स्वच्छता और लैंडफिल उपचार में पिछड़ गया। इस बीच, मैसूर ने सुपर स्वच्छ लीग में शामिल होकर सुर्खियाँ बटोरीं, जहाँ उन्होंने अपनी दीर्घकालिक स्वच्छता, सामुदायिक भागीदारी और स्वच्छता उत्कृष्टता को उजागर किया। ये परिणाम प्रभावी शहरी अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक स्वच्छता और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के व्यापक लक्ष्यों को लागू करने में कर्नाटक की प्रगति और कमियों को दर्शाते हैं।

केरल

- केरल का पहला स्किन बैंक 15 जुलाई, 2025 को तिरुवनंतपुरम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में खुल रहा है। के-सोट्रो द्वारा अनुमोदित और 6.75 करोड़ रुपये की लागत वाली यह सुविधा, जले हुए पीड़ितों के इलाज के लिए दान की गई त्वचा एकत्र करेगी। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कोट्टायम में भी इसी तरह का एक बैंक खोलने की भविष्य की योजना की घोषणा की। अलप्पुझा, कोल्लम और कन्नूर में बर्न सेंटर और प्लास्टिक सर्जरी इकाइयाँ पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। इस नए कदम से जले हुए रोगियों की देखभाल सेवाओं में सुधार होगा और पूरे केरल में रोगियों को राहत मिलेगी।
- केरल के अलप्पुझा स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से IS/ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है। यह पुरस्कार अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था, जन प्रतिक्रिया और शिकायत निवारण में स्टेशन की उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया गया है। यह प्रमाणन ASP हरीश जैन के नेतृत्व में आधुनिक चेरथला पुलिस कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पुलिसिंग मानकों को उन्नत करना है। राज्य पुलिस प्रमुख रावदा आज़ाद चंद्रशेखर सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और जन सुरक्षा में गुणवत्ता मानकों के महत्व पर प्रकाश डाला।
- एम्ब्रोसिया बीटल (यूप्लेटिपस पैरेलेलस), जिसकी भारत में पहली बार 2012 में रिपोर्ट हुई थी, अब केरल के खबर बागानों के लिए खतरा बन रहा है। यह फ्यूजेरियम कवक का वाहक है, जो लकड़ी को खराब करता है और लेटेक्स की उपज को कम करता है। इसके लक्षणों में पत्तियाँ गिरना, तने का सूखना और लेटेक्स का क्षय शामिल हैं। जाल और एंटीफंगल जैसी वर्तमान नियंत्रण विधियाँ सीमित रूप से सफल रही हैं। यह कीट काजू, सागौन और नारियल जैसी अन्य चौड़ी पत्ती वाली फसलों के लिए भी खतरा है। विशेषज्ञ स्थायी प्रबंधन के लिए स्थानीय रणनीतियों, विरोधी कवकों के उपयोग और नीति-स्तरीय हस्तक्षेप की सलाह देते हैं।

महाराष्ट्र

- मुंबई का कार्नेक ब्रिज, जो मूल रूप से 1868 में बना था, का पुनर्निर्माण किया गया है और इसका नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। यह ऑपरेशन सिंदूर, जो पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर एक सैन्य हमले का हिस्सा था, के सम्मान में किया गया है। यह नया नाम गवर्नर कार्नेक की औपनिवेशिक विरासत को मिटाने के प्रयास को भी दर्शाता है, जिनका संबंध भारतीयों पर अत्याचारों से था। 328 मीटर लंबे इस नए पुल का उद्घाटन 10 जुलाई, 2025 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे और इससे दक्षिण मुंबई में यातायात में सुधार होगा।
- महाराष्ट्र पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, जिससे 3.7 करोड़ से ज्यादा किसानों को रियायती बिजली, कृषि ऋण, कर राहत और सौर उपकरणों पर सब्सिडी प्राप्त होगी। इस निर्णय से मुर्गी पालन, डेयरी, मत्स्य पालन और छोटे जुगाली करने वाले पशु क्षेत्रों को लाभ होगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सालाना ₹7,000 करोड़ से ज्यादा की वृद्धि होने की संभावना है, साथ ही यह वैज्ञानिक पशुधन विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप भी होगा।
- महाराष्ट्र ने गढ़चिरोली में एलएमईएल द्वारा विदर्भ के पहले एकीकृत इस्पात संयंत्र का अनावरण किया है, जिसमें 4.5 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाली इस्पात सुविधा, 5 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाला लौह अयस्क पीसने का संयंत्र और राज्य की पहली 10 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाली स्लरी पाइपलाइन शामिल है। यह पहल औद्योगिक विकास, हरित रसद और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण प्रगति का वादा करती है और विदर्भ को भारत में एक उभरते हुए विनिर्माण और बुनियादी ढाँचे के केंद्र के रूप में स्थापित करती है।
- केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा मुंबई में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (IICT) का उद्घाटन भारत की रचनात्मक तकनीकी अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव का संकेत है। यह संस्थान Google, Meta, Microsoft और Apple जैसे वैश्विक दिग्गजों के साथ साझेदारी में VFX, XR, एनीमेशन और गेमिंग में उद्योग-उन्मुख शिक्षा प्रदान करेगा। कुशल पेशेवरों को तैयार करने के उद्देश्य से, IICT से AVGC-XR क्षेत्र में विकास को गति देने और भारत को एक वैश्विक डिजिटल कंटेंट केंद्र के रूप में स्थापित करने की उम्मीद है।

SALE IS LIVE

Test Prime

ALL EXAMS,
ONE SUBSCRIPTION.

Logos: IBPS, IAS, UPSC, SSC, Banking, and others.





मध्य प्रदेश

- केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि BIND योजना के तहत मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक नया आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह निर्णय 8 जुलाई, 2025 को केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन और मुख्यमंत्री मोहन यादव के बीच हुई बैठक में लिया गया। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय प्रसारण को बेहतर बनाना, अधिक लोगों तक विश्वसनीय जानकारी पहुँचाना और राज्य में मीडिया के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना है। आकाशवाणी उज्जैन, समाचार, शिक्षा, संस्कृति और सरकारी संदेशों को जनता तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुँचाने में मदद करेगा।
- मध्य प्रदेश सरकार ने पंजीकृत उद्योगों में इंटरनशिप के लिए बेरोजगार महिलाओं को ₹6,000 और पुरुषों को ₹5,000 मासिक वजीफा देने की एक नई योजना शुरू की है। यह योजना लाडली बहना योजना पर आधारित है, जिसका उद्देश्य कौशल विकास को बढ़ावा देना और अचारपुरा जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक विस्तार के माध्यम से स्थानीय रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। शुरुआत में 1,600 से ज्यादा नौकरियों के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। यह पहल सामाजिक कल्याण को औद्योगिक विकास के साथ जोड़ती है, जिसका उद्देश्य लैंगिक समावेशन, आर्थिक आत्मनिर्भरता और युवा सशक्तिकरण पर केंद्रित है।

ओडिशा

- पुरी ओडिशा का छठा नगर निगम बन जाएगा, जैसा कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 5 जुलाई, 2025 को बहुदा यात्रा से पहले घोषणा की थी। इस निर्णय का उद्देश्य शहर में बेहतर सेवाएँ प्रदान करना है, जहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। पुरी शहर के आसपास के क्षेत्रों को निगम में जोड़ा जाएगा, और सरकार ने उड़िया संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक जगन्नाथ संग्रहालय, पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र बनाने की भी योजना बनाई है। यह कदम 2036 तक पुरी को एक प्रमुख पर्यटन और आध्यात्मिक केंद्र बनाने के राज्य के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

तमिलनाडु

- तमिलनाडु में परमकुडी-रामनाथपुरम सड़क के उन्नयन हेतु ₹1,853 करोड़ की परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी, बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) के तहत विकसित, यह परियोजना NH-87 के 46.7 किलोमीटर लंबे हिस्से को चार-लेन कॉरिडोर में परिवर्तित करेगी, जिससे प्रमुख शहरों और रामेश्वरम जैसे धार्मिक स्थलों के बीच संपर्क बेहतर होगा। इस पहल से यातायात की भीड़ कम होने, पर्यटन को बढ़ावा मिलने, सड़क सुरक्षा में सुधार होने और 18 लाख से अधिक व्यक्ति-दिन रोजगार सृजित होने की उम्मीद है, जिससे यह राज्य में क्षेत्रीय विकास और आर्थिक एकीकरण की आधारशिला बन जाएगी।
- तमिलनाडु के विरुधुनगर में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, भारत की कपड़ा विकास रणनीति के तहत एक ऐतिहासिक पहल है। केंद्र सरकार के ₹1,900 करोड़ के निवेश के साथ, 1,052 एकड़ में फैला यह पार्क उन्नत बुनियादी ढाँचा प्रदान करेगा, जिसमें ZLD अपशिष्ट उपचार, श्रमिक छात्रावास और औद्योगिक कार्यस्थल शामिल हैं। 2026 तक ₹10,000 करोड़ के निजी निवेश और एक लाख से ज्यादा रोजगार सृजित होने की उम्मीद के साथ, यह पार्क इस क्षेत्र में निर्यातनुमुखी और टिकाऊ कपड़ा निर्माण को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा देगा।

- तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित जिंजी किले को मराठा सैन्य परिदृश्य के हिस्से के रूप में 11 जुलाई, 2025 को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह निर्णय पेरिस में विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान लिया गया। "पूर्व का ट्रॉय" कहे जाने वाले इस किले की अपनी अनूठी वास्तुकला, मज़बूत सैन्य डिज़ाइन और गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं। इस मान्यता से भारत के प्रतिष्ठित धरोहर स्थलों में से एक को वैश्विक ध्यान, अपेक्षित पर्यटन वृद्धि और संरक्षण समर्थन प्राप्त होगा।
- तमिलनाडु सरकार ने लुप्तप्राय प्रजाति संरक्षण कोष से ₹1 करोड़ की धनराशि के साथ अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र को मंजूरी दी है। यह परियोजना चार हॉर्नबिल प्रजातियों को लक्षित करती है और इसमें जनसंख्या निगरानी, आवास पुनर्स्थापन, समुदाय-आधारित घोंसलों को अपनाना और सहयोगात्मक अनुसंधान शामिल हैं। यह संरक्षण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए नागरिक विज्ञान उपकरण और शैक्षिक सहायता भी प्रदान करती है। यह पहल पश्चिमी घाट में आवास हानि, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता में गिरावट जैसे प्रमुख मुद्दों को संबोधित करती है।

उत्तराखंड

- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में फर्जी संतों और धार्मिक ढोंगियों को पकड़ने के लिए पुलिस अभियान 'ऑपरेशन कालनेमि' शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान का नाम हिंदू पौराणिक कथाओं के एक राक्षस कालनेमि के नाम पर रखा गया है, जिसने दूसरों को गुमराह करने के लिए साधु का वेश धारण किया था। धामी ने कहा कि ये लोग लोगों, खासकर महिलाओं को धोखा देते हैं और सनातन धर्म की छवि को नुकसान पहुँचाते हैं।

उत्तर प्रदेश

- भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का दौरा किया। उन्होंने एक नए सभागार, शैक्षणिक ब्लॉक और पंचकर्म केंद्र का उद्घाटन किया और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बालिका छात्रावास की आधारशिला रखी। आधुनिक एलोपैथी और पारंपरिक आयुर्वेद को एकीकृत करने के विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए, उन्होंने समग्र चिकित्सा शिक्षा में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला।
- 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र (पीएमडीके) का उद्घाटन 15 जुलाई, 2025 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में केंद्रीय मंत्री श्री बी.एल. वर्मा द्वारा किया जाएगा। यह केंद्र दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को एडीआईपी योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरबीवाई) के तहत व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल और श्रवण यंत्र जैसे निःशुल्क उपकरण प्रदान करके उनकी सहायता करेगा। इस नए केंद्र के साथ, अब पूरे भारत में 75 पीएमडीके कार्यरत हैं, जो अब तक 1.40 लाख से अधिक लोगों को सहायता प्रदान कर चुके हैं। यह कदम समावेशी विकास और अंतिम छोर तक सेवा प्रदान करने पर सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।





केंद्र शासित प्रदेश

- भारत सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के दूसरे चरण के तहत प्रस्तावित ₹100 करोड़ के एकीकृत जल पार्क के साथ जम्मू-कश्मीर के मत्स्य पालन और पशुधन क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने जम्मू में 50,000 लीटर क्षमता वाले यूएचटी दूध संयंत्र का भी उद्घाटन किया, जो ग्रामीण आय सृजन, शीत जल जलीय कृषि और डेयरी उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करने को रेखांकित करता है। इस क्षेत्र में ट्राउट उत्पादन में 800% की वृद्धि और दुग्ध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसे रणनीतिक निवेश और डेनमार्क से बीज आयात से सहायता मिली है।
- दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) जल्द ही अपनी गुलाबी टिकट प्रणाली को मुफ्त बस यात्रा के लिए एक नए 'सहेली स्मार्ट कार्ड' से बदल देगा। केवल दिल्ली में रहने वाली महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति ही आधार और पते के प्रमाण के आधार पर यह कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। इस कार्ड का उद्देश्य दुरुपयोग को रोकना, यह सुनिश्चित करना है कि लाभ सही लोगों तक पहुँचे, और एक आधुनिक, कैशलेस और कनेक्टेड परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देना है। सहेली कार्ड, ज़ीरो केवाईसी और फुल केवाईसी कार्ड के साथ, एक व्यापक डिजिटल योजना का हिस्सा है जिसमें क्यूआर-आधारित टिकट, एनसीएमसी एकीकरण और दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में सुगम यात्रा के लिए मोबाइल ऐप शामिल हैं।
- दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कागज़ रहित शासन को बढ़ावा देने के लिए नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। नेवा परियोजना का पहला चरण पूरा हो गया है, जिसमें विधायकों को डिजिटल उपकरण, प्रशिक्षण और स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह पहल डिजिटल इंडिया का समर्थन करती है, पारदर्शिता का लक्ष्य रखती है और तकनीक-संचालित समाधानों के माध्यम से विधायी दक्षता को बढ़ाती है।
- पुडुचेरी की एकमुश्त नियमितीकरण योजना 2025 का उद्देश्य 1 मई, 1987 से 16 जुलाई, 2025 के बीच किए गए अनधिकृत निर्माणों को वैध बनाना है। आवेदन ओबीपीएस के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं, जिनमें निश्चित शुल्क और जाँच शुल्क शामिल हैं। सरकारी भवनों को छूट दी गई है, जबकि सहायता प्राप्त स्कूलों को 50% शुल्क में छूट दी गई है। अतिक्रमण और बिना कानूनी स्वामित्व वाले भूखंडों को इससे बाहर रखा गया है। इस कदम से शहरी नियोजन अनुपालन में सुधार होगा और मौजूदा संपत्ति मालिकों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी।
- दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार राशि में वृद्धि की है। इसके तहत स्वर्ण पदक के लिए ₹7 करोड़, रजत पदक के लिए ₹5 करोड़ और कांस्य पदक के लिए ₹3 करोड़ की राशि दी जाएगी। साथ ही, शीर्ष ओलंपिक विजेताओं को ग्रेड ए की नौकरी भी दी जाएगी। इस योजना में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर ₹3 करोड़ की राशि भी शामिल है। इसके अलावा, 1,200 मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने और सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब को उन्नत करने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना भी शुरू की गई है।

जुलाई माह के शुभारंभ और उद्घाटन

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जून, 2025 को तेलंगाना के निज़ामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया। यह कदम हल्दी किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है और 2030 तक हल्दी निर्यात को 1 अरब डॉलर तक पहुँचाने के केंद्र के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप है। बोर्ड अनुसंधान, ब्रांडिंग, विपणन और किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ₹200 करोड़ के वित्तपोषण से समर्थित, यह कृषि, निर्यात और ग्रामीण आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है।
- भारत सरकार ने कृषि वानिकी को बढ़ावा देने, वृक्षारोपण की अनुमतियों को सुव्यवस्थित करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कृषि भूमि पर वृक्षों की कटाई के लिए आदर्श नियम लागू किए हैं। आगामी राष्ट्रीय इमारती लकड़ी प्रबंधन प्रणाली (एनटीएमएस) पोर्टल, भू-टैग किए गए डेटा का उपयोग करके वृक्षारोपण के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार को आसान बनाएगा। राज्य स्तरीय समितियों द्वारा निर्देशित और प्रभागीय वन अधिकारियों द्वारा निगरानी की जाने वाली यह पहल, लकड़ी उत्पादन को बढ़ाएगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाएगी।
- केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल द्वारा शुरू की गई सी-फ्लड एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली, एक वेब-आधारित प्लेटफॉर्म है जो ग्राम स्तर तक उन्नत बाढ़ पूर्वानुमान प्रदान करता है। सी-डैक, सीडब्ल्यूसी और एनआरएससी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित, यह प्रणाली राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (एनएसएम) के तहत हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग, एचपीसी सिमुलेशन और उपग्रह डेटा को एकीकृत करती है। यह वर्तमान में तीन प्रमुख नदी घाटियों - महानदी, गोदावरी और तापी - को कवर करती है और इसे व्यापक रूप से लागू करने की योजना है। यह पहल आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाती है, समय पर निकासी को सक्षम बनाती है और वैज्ञानिक पूर्वानुमान और अंतर-एजेंसी समन्वय के माध्यम से बाढ़ आपदाओं के जोखिम को कम करती है।
- कोयला मंत्रालय भारत में समावेशी और टिकाऊ खदान बंद करने को बढ़ावा देने के लिए रिक्लेम फ्रेमवर्क (RECLAIM) शुरू करेगा। क्षेत्र-परीक्षित उपकरणों और कार्यप्रणालियों के साथ तैयार किया गया यह फ्रेमवर्क सामुदायिक सहभागिता, लैंगिक समानता और कमज़ोर समूहों के प्रतिनिधित्व पर जोर देता है। यह स्थानीय प्रासंगिकता सुनिश्चित करने, दीर्घकालिक आजीविका सुरक्षा और खनन भूमि के पुनर्प्रयोजन को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के साथ तालमेल बिठाता है। इसके साथ ही, भारत खनन क्षेत्र में न्यायसंगत बदलाव की दिशा में एक प्रगतिशील कदम उठा रहा है।
- केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने एसवीपीयूएटी, मेरठ में उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप एवं टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन किया, जो कृषि को डिजिटल रूप से बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह पहल किसानों, स्टार्टअप्स, प्रौद्योगिकीविदों और शिक्षाविदों को स्थायी, क्षेत्र-विशिष्ट समाधान विकसित करने के लिए जोड़ती है। IoT-सक्षम सेंसर, स्मार्ट सिंचाई, ऑटोमेशन टूल्स और रीयल-टाइम एनालिटिक्स से लैस, यह एग्रीटेक हब सटीक खेती और जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देता है।





- भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन शिवा 2025 शुरू किया है। यह अभियान 12 जुलाई, 2025 को शुरू हुआ और इसमें 8,500 से अधिक सैनिकों की तैनाती, ड्रोन-रोधी प्रणालियाँ, चिकित्सा सुविधाएँ और इंजीनियरिंग सहायता शामिल है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और नागरिक प्रशासन के समन्वय से, यह अभियान पाकिस्तान समर्थित समूहों से सुरक्षा खतरों का समाधान करता है। सेना के प्रयासों में निगरानी, आपदा तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया शामिल हैं, जो इस पवित्र यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के प्रति उसके समर्पण को दर्शाता है।
- जुलाई 2025 में श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा उद्घाटन किया गया महिला आरोग्यम कक्ष, विधि कार्य विभाग द्वारा महिलाओं के लिए विशेष रूप से शुरू किया गया एक स्वास्थ्य केंद्र है। शास्त्री भवन में स्थित, इसमें एक जिम और स्तनपान कक्ष भी शामिल है, जो फिट इंडिया मूवमेंट और विकसित भारत विजन के तहत फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और समावेशी कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देता है।

महत्वपूर्ण त्योहार

- लद्दाख ने हाल ही में लेह में अपना पहला खगोल पर्यटन महोत्सव संपन्न किया, जिसका आयोजन पर्यटन विभाग ने भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के सहयोग से किया था। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में रात्रि आकाश अवलोकन, विशेषज्ञों द्वारा संचालित सत्र और शैक्षिक आउटरीच कार्यक्रम शामिल थे, जिसका उद्देश्य लद्दाख को खगोल पर्यटन का केंद्र बनाना था। साफ आसमान, ऊँचाई और कम प्रकाश प्रदूषण जैसी आदर्श परिस्थितियों के साथ, यह पहल न केवल वैज्ञानिक जागरूकता को बढ़ावा देती है, बल्कि सतत पर्यटन विकास के साथ भी जुड़ी हुई है।
- महाराष्ट्र सरकार ने 10 जुलाई, 2025 को सार्वजनिक गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया, जैसा कि सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने विधानसभा में घोषणा की। लोकमान्य तिलक द्वारा 1893 में शुरू किया गया यह उत्सव महाराष्ट्र की एकता, संस्कृति और गौरव का प्रतीक है। सरकार अब राज्य भर में इस भव्य उत्सव के लिए धन और प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगी। इस कदम का उद्देश्य पारंपरिक सामुदायिक भावना को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और इस आनंदमय अवसर में अधिक लोगों को शामिल करना है।
- जुलाई 2025 में मेघालय के जोवाई में बेहदेनखलम उत्सव पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया गया। यह उत्सव जयंतिया समुदाय की एक उप-जनजाति, पनार के लिए महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य एवं अच्छी फसल की प्रार्थना के रूप में मनाया जाता है। इस उत्सव के अनुष्ठानों में सिम्बुद खनोंग धारण करना, नृत्य करना, महिलाओं द्वारा भोजन अर्पित करना और अनोखा खेल दाद-लावाकोर खेलना शामिल है। यह नशामुक्त जीवन, जलवायु जागरूकता और परंपरा संरक्षण के संदेश भी फैलाता है। यह उत्सव नियामत्रे धर्म को जीवित रखने और समुदाय को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- तमिलनाडु के कुट्टालम में आयोजित सारल विज्ञा 2025 एक जीवंत मानसून उत्सव है जो संस्कृति, परंपरा और सामुदायिक कल्याण का उत्सव मनाता है। राजस्व मंत्री के.के.एस.एस.आर. रामचंद्रन द्वारा उद्घाटन किए गए इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, पुष्प प्रदर्शनी और सार्वजनिक प्रतियोगिताएँ शामिल थीं, जिनमें प्रकृति और विरासत

का सम्मिश्रण था। सशक्त सरकारी सहयोग, स्थानीय अधिकारियों की भागीदारी और पारंपरिक कलाओं एवं युवा कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़ाव के साथ, यह उत्सव समावेशी सांस्कृतिक विकास पर तमिलनाडु के ध्यान को रेखांकित करता है।

- गंगईकोंडा चोलपुरम में आदि तिरुवथिरई महोत्सव (23-27 जुलाई 2025) राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो उनके समुद्री अभियान और मंदिर निर्माण के 1,000 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। इस आयोजन में भरतनाट्यम, देवराम गायन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की प्रदर्शनियाँ और इलैयाराजा द्वारा एक प्रस्तुति शामिल है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि होंगे। यह महोत्सव शैव सिद्धांत, तमिल भक्ति परंपरा और चोल विरासत को बढ़ावा देता है, और शासक के दूरदर्शी सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव को उजागर करता है।
- उत्तराखंड 16 जुलाई, 2025 को गढ़वाल और कुमाऊँ क्षेत्र में 5 लाख से ज़्यादा पौधे लगाकर हरेला उत्सव मनाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में आयोजित यह कार्यक्रम "एक पेड़ माँ के नाम" और "हरेला का त्यौहार मनाओ, धरती माँ का रिन चुकाओ" थीम पर केंद्रित होगा। इस वृक्षारोपण अभियान में छात्र, ग्रामीण और सरकारी निकाय शामिल होंगे। इस हरित पहल का उद्देश्य पिछले रिकॉर्ड को तोड़ना और पर्यावरण संरक्षण एवं सामुदायिक भागीदारी के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को उजागर करना है।

विविध राष्ट्रीय समाचार

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक नया नियम पेश किया है जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुछ विशेष हिस्सों जैसे सुरंगों (टनल), पुलों, फ्लाईओवर और एलिवेटेड सड़कों पर टोल शुल्क 50% तक कम हो जाएगा। इस कदम का उद्देश्य यात्रा को सस्ता बनाना और लोगों को राजमार्गों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है।
- भारत यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्मार्ट योजना पर काम कर रहा है कि देश कभी भी तेल की कमी से न जूझे, चाहे किसी भी आपात स्थिति का सामना क्यों न करना पड़े। सरकार तीन नए रणनीतिक तेल भंडार बनाने की योजना बना रही है। ये ऐसे बड़े भंडारण क्षेत्र होंगे, जहां देश भविष्य की जरूरतों के लिए कच्चा तेल सुरक्षित रख सकेगा।
- हालांकि, लंबे समय तक जीने का मतलब हमेशा स्वस्थ रहना नहीं होता। पार्किंसंस और डिमेंशिया जैसी उम्र से जुड़ी बीमारियों के बढ़ते मामलों के साथ, यह समझने की जरूरत बढ़ रही है कि भारतीय कैसे बूढ़े होते हैं – सिर्फ सालों के हिसाब से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के हिसाब से भी।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में एक ऑडिटोरियम, शैक्षणिक ब्लॉक और पंचकर्म केंद्र सहित प्रमुख सुविधाओं का उद्घाटन किया और एक नए बालिका छात्रावास की आधारशिला रखी – जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
- स्थायी खनन और सामुदायिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कोयला मंत्रालय रिक्लेम फ्रेमवर्क लॉन्च करने जा रहा है – समावेशी खदान बंद करने और पुनः उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक संरचित मार्गदर्शिका। यह पहल सामुदायिक भागीदारी, लैंगिक समावेशिता और कमजोर समूहों की भागीदारी पर ज़ोर देती है, जिसका उद्देश्य खनन के बाद के बदलाव को न्यायसंगत, पारदर्शी और स्थानीय रूप से संरेखित बनाना है।





- भारत की अग्रणी समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले को सम्मानित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (National Institute of Public Cooperation and Child Development) का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान (Savitribai Phule National Institute of Women and Child Development) कर दिया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा घोषित यह नाम परिवर्तन देश भर में महिलाओं और बाल कल्याण के लिए समावेशी, क्षेत्र-विशिष्ट और मिशन-संचालित समर्थन के लिए सरकार की नई प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- सी-डैक, सीडब्ल्यूसी और एनआरएससी द्वारा सहयोग से विकसित यह वेब-आधारित प्लेटफॉर्म गांव स्तर पर दो दिन का अग्रिम बाढ़ पूर्वानुमान प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्रों में तैयारी को बढ़ाना और बाढ़ के जोखिम को कम करना है। यह परियोजना राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (एनएसएम) का हिस्सा है, जो जलवायु चुनौतियों से निपटने में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तालमेल को प्रदर्शित करती है।
- रेलवे सेवाओं में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 जुलाई, 2025 को 'रेलवन' मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया। एक व्यापक, वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित, ऐप यात्रियों को टिकट बुकिंग, पीएनआर पृष्ठताछ, यात्रा योजना, भोजन बुकिंग और माल ढुलाई पृष्ठताछ जैसी सेवाओं तक एकीकृत पहुंच प्रदान करता है, जिससे लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा और डिजिटल अनुभव बढ़ जाता है।
- भारत के पंजाब राज्य के फाजिल्का जिले में स्थित भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा — श्री नानक निवास — श्रद्धा और सेवा (सेवा भाव) का एक अनुपम उदाहरण बनकर उभरा है। यह गुरुद्वारा फिनलैंड से आयातित देवदार लकड़ी से पूरी तरह से निर्मित है और इसे पुलिस लाइन परिसर के अंदर स्थापित किया गया है। यह धार्मिक स्थल न केवल आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि स्थायी वास्तुकला और सार्वजनिक सेवा के समन्वय का भी प्रेरणादायक उदाहरण है। इस अनूठे गुरुद्वारे की परिकल्पना एसएसपी भूपिंदर सिंह सिद्धू ने की थी, जिनकी व्यक्तिगत श्रद्धा ने इसे 2023 में साकार किया।
- भारतीय रेलवे ने यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और आरक्षण प्रणाली को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक सुधार योजना की घोषणा की है। इन सुधारों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे टिकट बुकिंग से लेकर यात्रा तक की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बन सके।
- भारत के चुनाव आयोग ने 345 गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों (RUPPs) को अपनी लिस्ट से हटाने का फैसला किया है। ये वे दल हैं जो पिछले 6 सालों में एक भी चुनाव नहीं लड़े और इनके पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं मिला। चुनाव आयोग ने बताया कि देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले इन 345 दलों ने रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बने रहने की अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं किया। आयोग के पास वर्तमान में 2800 से ज्यादा RUPPs रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इनमें से कई दल न तो चुनाव लड़ रहे हैं और न ही अपनी मौजूदगी साबित कर पा रहे हैं।
- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 29 जून 2025 को "कृषि भूमि में पेड़ों की कटाई के लिए मॉडल नियम" जारी किए। यह पहल सतत कृषि, आजीविका संवर्धन, और आगोफरेस्ट्री (Agroforestry) को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही मंत्रालय ने आगामी नेशनल टिंबर मैनेजमेंट सिस्टम (NTMS) पोर्टल की भी घोषणा की, जो वृक्ष कटाई की मंजूरी प्रक्रिया को डिजिटली सरल बनाएगा।
- भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए "ऑपरेशन शिवा 2025" की शुरुआत की है। इस अभियान की घोषणा शुक्रवार को की गई, जिसमें बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती, आधुनिक निगरानी उपकरणों और आपदा प्रतिक्रिया उपायों को शामिल किया गया है। इस वर्ष पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूहों से बढ़ते खतरे के कारण यह सुरक्षा अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है।
- भारत के 'मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स' को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। इस प्रस्ताव का मूल्यांकन 6 से 16 जुलाई के बीच पेरिस में चल रहे यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति (डब्ल्यूएचसी) के 47वें सत्र में किया गया। इस सत्र में दुनिया भर से कुल 32 नए स्थलों के नामांकन पर चर्चा की गई, जिनमें भारत का यह ऐतिहासिक सैन्य तंत्र भी शामिल है। भारत की ओर से यह नामांकन 2024-25 चक्र के लिए प्रस्तुत किया गया। [Click here to read article](#)
- केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में 4,000% की वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह (IESW) में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि देश 227 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तक पहुँच गया है और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। यह भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए एक बड़ा कदम है।
- राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (नेस्ट्स) और यूनिसेफ इंडिया ने आदिवासी छात्रों की शिक्षा और व्यक्तिगत विकास में सहयोग के लिए एक नया कार्यक्रम, "तलाश" शुरू किया है। यह पहल 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में पढ़ने वाले छात्रों की मदद करेगी। इसका उद्देश्य आत्मविश्वास और जीवन कौशल का विकास करना और छात्रों को सही करियर चुनने में मार्गदर्शन प्रदान करना है।
- डाक विभाग ने दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देशभक्तिपूर्ण वाद्य यंत्रों के प्रदर्शन सहित जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रम और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन, विरासत और योगदान पर आधारित एक प्रदर्शनी का प्रदर्शन किया गया।
- ब्राज़ील की राजकीय यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ब्राज़ील के बीच द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक 20 अरब डॉलर तक पहुँचाने का एक साहसिक लक्ष्य निर्धारित किया, जो वर्तमान में 12.2 अरब डॉलर है। ब्रासीलिया में ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिलवा के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों वैश्विक दक्षिण देशों के बीच आर्थिक सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया।





- नवाचार और डिजिटल तकनीक के माध्यम से कृषि में क्रांति लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान और शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी ने 9 जुलाई 2025 को मेरठ स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (SVPUAT) में उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब तथा एग्रीटेक स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन किया।
- भारत के प्रमुख ताप विद्युत स्टेशनों में से एक, एनटीपीसी सिम्हाद्री ने मंगलवार, 8 जुलाई को आंध्र प्रदेश के अनकपल्ली जिले के परावाड़ा स्थित अपने प्रशासनिक परिसर में 28वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया। यह अवसर लगभग तीन दशकों की सेवा, नवाचार और समुदाय-केन्द्रित विकास को समर्पित रहा, जिसने देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम योगदान दिया है।
- महिला स्वास्थ्य और कल्याण को सरकारी कार्यस्थलों पर बढ़ावा देने की दिशा में एक अग्रणी कदम उठाते हुए, विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन विधिक कार्य विभाग ने नई दिल्ली स्थित शास्त्री भवन में “महिला आरोग्यम कक्ष” का उद्घाटन किया है। यह अपने तरह का पहला फिटनेस और वेलनेस स्पेस है, जिसे विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया है। इस पहल के तहत पुराने गैराज को रूपांतरित कर एक समर्पित स्वास्थ्य सुविधा के रूप में विकसित किया गया है, जो महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करता है।
- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) इंटरनेशनल 17 जुलाई 2025 से UPI-PayNow लिंकज सेवा का विस्तार करने जा रहा है, जिससे भारत और सिंगापुर के बीच सीमापार धन प्रेषण सेवाओं को और अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और किफायती बनाया जा सकेगा। इस सेवा में अब 13 नए भारतीय बैंकों को जोड़ा गया है, जिससे कुल 19 बैंक अब इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन गए हैं। यह पहल भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और सिंगापुर की मौद्रिक प्राधिकरण (MAS) द्वारा समर्थित एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य तेज़, विश्वसनीय और कम लागत पर अंतरराष्ट्रीय भुगतान को बढ़ावा देना है।
- भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोकप्रिय भारतीय स्नैक्स में मौजूद पोषण संबंधी तथ्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक नई अभियान की शुरुआत की है। इस पहल की शुरुआत AIIMS नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई है। इसका उद्देश्य है कि खाने में छिपी हुई चीनी, वसा और तेल के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को कम किया जाए और लोगों को बेहतर खान-पान के विकल्प चुनने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सके।
- गुजरात अब भारत का प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया है, विशेष रूप से फ्रेंच फ्राइज़ और वेफर्स बनाने वाले आलू के क्षेत्र में। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, यह उपलब्धि किसानों और खाद्य कंपनियों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हुई है और निर्यात को बढ़ावा मिला है। इस सफलता के पीछे आधुनिक खेती, सरकारी सहयोग और फूड चेन व वैश्विक बाजारों से बढ़ती माँग प्रमुख कारण हैं।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह पर चार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा (संसद के उच्च सदन) में नामित किया है। यह कदम कानून, शिक्षा, कूटनीति और

- सामाजिक सेवा जैसे विविध क्षेत्रों से विशेषज्ञता को संसद में प्रतिनिधित्व देने की दिशा में उठाया गया है।
- जुलाई 2025 में अर्जुन राम मेघवाल द्वारा उद्घाटन किया गया महिला आरोग्यम कक्ष, विधि कार्य विभाग द्वारा महिलाओं के लिए विशेष रूप से शुरू किया गया एक स्वास्थ्य केंद्र है। शास्त्री भवन में स्थित, इसमें एक जिम और स्तनपान कक्ष भी शामिल है, जो फिट इंडिया मूवमेंट और विकसित भारत विजन के तहत फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और समावेशी कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देता है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड किंगडम की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान सैंड्रिघम हाउस में किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने किंग चार्ल्स तृतीय को शरद ऋतु में लगाए जाने वाले एक पेड़ का उपहार दिया। ये पौधा “एक पेड़ मां के नाम” पर्यावरण पहल के तहत भेंट किया गया है। इसका उद्देश्य माताओं के सम्मान में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है।
- भारत और मालदीव ने 25 जुलाई 2025 को अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकटों का विमोचन कर एक ऐतिहासिक क्षण को चिह्नित किया। इन टिकटों का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज़ु द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। डाक टिकटों में दोनों देशों की साझा समुद्री विरासत की सुंदर झलक देखने को मिलती है। यह प्रतीकात्मक पहल न केवल एक महत्वपूर्ण राजनयिक पड़ाव का स्मरण है, बल्कि भारत और मालदीव के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और समुद्री सहयोग की गहराई को भी दर्शाती है।
- भारत ने 25 जुलाई 2025 को चेन्नई स्थित इंटेग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) में अपने पहले हाइड्रोजन-चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कर हरित परिवहन के एक नए युग में प्रवेश किया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय रेल में सतत और स्वच्छ गतिशीलता की दिशा में एक बड़ा कदम है और भारत को उन कुछ चुनिंदा देशों की सूची में शामिल करती है जो हाइड्रोजन आधारित रेल प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं। यह पहल भारत के नेट-ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने और रेलवे बुनियादी ढांचे को स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों के साथ आधुनिक बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए लगातार प्रधानमंत्री पद पर सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे नेता बन गए हैं। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इस दिन मोदी ने लगातार 4,078 दिन देश की बागडोर संभालते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 4,077 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा की थी। हालाँकि, उन्होंने 1980 से 1984 तक एक और कार्यकाल भी पूरा किया था, लेकिन वह दो कार्यकालों के बीच में एक अंतराल था।
- भारत ने अपनी ऊर्जा संक्रमण यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 2025 में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है—जो कि मूल रूप से 2030 तक निर्धारित किया गया था। यह महत्वपूर्ण घोषणा केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा की गई और इसे भारत की ईंधन रणनीति में एक परिवर्तनकारी मोड़ माना जा रहा है। यह उपलब्धि ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करती है, स्थिरता को बढ़ावा देती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त बनाती है।





- केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहयोग नीति – 2025 का अनावरण किया। यह ऐतिहासिक नीति भारत के सहकारी आंदोलन को पुनर्परिभाषित और पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसका उद्देश्य “सहकार से समृद्धि” के संकल्प को साकार करना है। समावेशिता और जमीनी सशक्तिकरण की भावना से प्रेरित यह नीति दूरदर्शी होने के साथ-साथ व्यावहारिक भी है। इसका लक्ष्य 2047 तक सहकारिता क्षेत्र को राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास का एक प्रमुख इंजन बनाना है।
- लंदन में 24 जुलाई 2025 को एक उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और यूनाइटेड किंगडम ने भारत-यूके विज़न 2035 का अनावरण किया। यह रूपरेखा द्विपक्षीय सहयोग को व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु कार्यवाई जैसे क्षेत्रों में गहराई और विविधता प्रदान करने के लिए एक परिवर्तनकारी एजेंडा प्रस्तुत करती है। यह दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है और बदलती वैश्विक चुनौतियों के बीच एक सुरक्षित, सतत और समृद्ध विश्व के निर्माण के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- हाल ही में 24 जुलाई 2025 को हस्ताक्षरित भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में एक परिवर्तनकारी क्षण को दर्शाता है। इस समझौते के तहत कई उत्पादों पर शुल्क कम या समाप्त कर दिए जाएंगे, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं के लिए कई आयातित वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, वहीं भारतीय निर्यात को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा। प्रमुख वस्तुओं जैसे स्कॉच व्हिस्की, ब्रिटिश लग्जरी कारें, चॉकलेट और कॉस्मेटिक्स की कीमतों में समय के साथ उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिलेगी। यह समझौता दोनों देशों के उपभोक्ताओं, उद्योगों और रोजगार के क्षेत्र के लिए लाभकारी साबित होने की उम्मीद है।
- भारत ने ग्रामीण कृषि अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत की है, जिसमें सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना (Grain Storage Plan) की शुरुआत की गई है। इस पहल के तहत, सरकार का उद्देश्य प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) के माध्यम से स्थानीय स्तर पर भंडारण क्षमता को बढ़ाना है, जिससे अनाज की बर्बादी, कटाई के बाद नुकसान, और किसानों के लिए बाजार तक पहुंच जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सके।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67(a) भारत के उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। यह प्रावधान उस समय विशेष रूप से चर्चा में आया जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे होने के बाद 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया। यह प्रावधान देश के उच्चतम संवैधानिक पदों में से एक से त्यागपत्र देने की स्पष्ट प्रक्रिया सुनिश्चित करता है, जिससे संस्थागत निरंतरता और स्थायित्व बनाए रखने में सहायता मिलती है।
- पिछले पाँच वर्षों में भारत में बौद्धिक संपदा (IP) पंजीकरण में 44% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका श्रेय सरकार की नीतिगत सुधारों, शुल्क में रियायतों और IP सेवाओं के डिजिटलीकरण को जाता है। यह वृद्धि देश में बढ़ती जागरूकता, जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और भौगोलिक संकेतक (GI), पेटेंट तथा ट्रेडमार्क के माध्यम से स्वदेशी उत्पादों की रक्षा के प्रयासों को दर्शाती है।
- भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल एक हलफनामे में स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने की पात्रता स्थापित करने के लिए आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को स्वतंत्र दस्तावेज़ नहीं माना जा सकता। यह स्पष्टीकरण बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और इस प्रक्रिया की चल रही न्यायिक जाँच के बीच आया है।
- मानसून सत्र के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 21 जुलाई 2025 की शाम अचानक पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए पत्र में धनखड़ ने इस्तीफे के लिए खराब स्वास्थ्य को कारण बताया है। राज्यसभा के पदेन सभापति होने के नाते, उप-राष्ट्रपति की भूमिका संसद के संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उनके इस्तीफे से न केवल संवैधानिक रूप से नया उप-राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया शुरू हुई है, बल्कि राज्यसभा की कार्यप्रणाली में भी अस्थायी बदलाव आया है। यह घटनाक्रम प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई संवैधानिक अनुच्छेद, चुनावी प्रक्रिया और संसदीय नियमों का प्रत्यक्ष उल्लेख है।
- ‘फ़िट इंडिया साइकिल सेंड’ पहल अब केवल एक फिटनेस कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय जन आंदोलन बन चुकी है, जिसका उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवाओं में नशामुक्ति और सशक्तिकरण जैसे सामाजिक संदेशों को भी मज़बूती से फैलाना है। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संचालित इस पहल का 32वां संस्करण वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया समेत 3,000 से अधिक साइकिल चालकों ने भाग लिया। इस अभियान ने शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय निकायों के सहयोग से यह संदेश फैलाया कि “स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क बनता है”, जो विकसित भारत की दिशा में सहायक है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई 2025 तक ब्रिटेन और मालदीव के द्विदेशीय दौरे पर जाने वाले हैं। यह यात्रा भारत की सक्रिय और गतिशील विदेश नीति का प्रतीक है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के साथ रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है, जिससे भारत की वैश्विक प्रभावशीलता बढ़े और क्षेत्रीय एवं वैश्विक सहयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता सुदृढ़ हो।
- भारत ने अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक उत्कृष्टता की दिशा में अपनी प्रगति जारी रखते हुए ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड (IMO) 2025 में सातवां स्थान हासिल किया। 110 देशों की प्रतिस्पर्धा के बीच भारत की छह सदस्यीय टीम ने तीन स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक जीता तथा 252 में से 193 अंक प्राप्त कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। यह उपलब्धि भारत की गणितीय शिक्षा, प्रतिभा विकास, और ओलंपियाड प्रशिक्षण व्यवस्था की प्रभावशीलता को उजागर करती है।





राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स: जून 2025

जून माह के महत्वपूर्ण समसामयिकी

भारत 2027 की जनगणना दो चरणों में जाति गणना के साथ करेगा

16 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसे दो चरणों में जातीय गणना के साथ आयोजित किया जाएगा। अधिकांश क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि (00:00 बजे) होगी, जबकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए यह 1 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। यह निर्णय कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित 2021 जनगणना के बाद भारत में दशकीय जनगणना प्रक्रिया को पुनः शुरू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

समाचार में क्यों?

गृह मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी और इसमें जातीय गणना भी की जाएगी। इससे सरकार की मंशा स्पष्ट होती है कि वह शासन, योजना और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए आधुनिक और अद्यतन जनसांख्यिकीय डेटा जुटाना चाहती है। जनगणना की अधिसूचना 16 जून 2025 को जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 के तहत राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

भारत में जनगणना का पृष्ठभूमि

- जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 द्वारा शासित।
- अंतिम पूर्ण जनगणना 2011 में हुई थी, जिसमें 1.2 अरब से अधिक लोग गिने गए थे।
- 2021 की जनगणना कोविड-19 के कारण स्थगित कर दी गई थी, हालांकि सभी तैयारी पूर्ण हो चुकी थी।

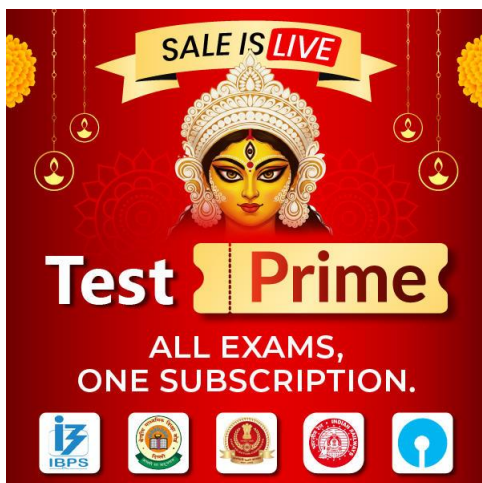
जनगणना 2027 की प्रमुख विशेषताएँ

दो चरणों में आयोजित

- चरण I: गृह-सूचीकरण (House Listing)
- चरण II: जनसंख्या गणना (Population Enumeration)

संदर्भ तिथि

- भारत के अधिकांश क्षेत्रों के लिए: 1 मार्च 2027
- लद्दाख व बर्फबारी वाले क्षेत्रों के लिए: 1 अक्टूबर 2026



जातीय गणना का समावेश

- कई दशकों बाद पहली बार जाति आधारित आंकड़ों को जनगणना के साथ आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा।
- उद्देश्य: नीतियों के निर्धारण और सामाजिक न्याय कार्यक्रमों के लिए विस्तृत सामाजिक-आर्थिक डेटा इकट्ठा करना।

उद्देश्य और महत्त्व

- जनसंख्या के आँकड़ों को अद्यतन कर वर्तमान जनसांख्यिकी रूझानों को दर्शाना।
- लोक अवसंरचना, कल्याणकारी योजनाओं और निर्वाचन प्रबंधन की योजना बनाने में सहायता।
- जातीय डेटा से आरक्षण नीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और वंचित वर्गों की पहचान में मदद।

स्थैतिक और विधिक तथ्य

- कानूनी आधार: जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3
- अधिसूचना तिथि: 16 जून 2025

पिछली जनगणना के चरण

- 2011: गृह-सूचीकरण (अप्रैल-सितंबर 2010), जनगणना (फरवरी 2011)
- 2021: योजना बनाई गई थी अप्रैल 2020 और फरवरी 2021 के लिए, लेकिन स्थगित कर दी गई

PM मोदी ने जम्मू-कश्मीर में चिनाब पुल का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को जम्मू-कश्मीर में विश्व के सबसे ऊँचे रेलवे आर्च पुल — चेनाब रेल पुल — का उद्घाटन किया। यह ऐतिहासिक अवसर उधमपुर-थ्रीनगर-बारामुला रेल लिंक (USBRL) परियोजना की पूर्णता को चिह्नित करता है, जो 42 वर्षों से निर्माणाधीन थी और जिसका उद्देश्य कश्मीर घाटी को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ना था। यह पुल एक पूरी तरह से विद्युतीकृत 272 किलोमीटर लंबे रेल गलियारे का हिस्सा है और हिमालय की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को पार करते हुए इस क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और आर्थिक विकास के नए रास्ते खोलता है।

समाचार में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को चेनाब रेल पुल का उद्घाटन किया, जिससे USBRL परियोजना पूरी हुई। यह पुल अब दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे आर्च पुल बन गया है, जिसकी ऊँचाई एफिल टॉवर से भी अधिक है। यह परियोजना चार दशक पहले कश्मीर को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और यह पहली बार कश्मीर घाटी को हर मौसम में विद्युतीकृत रेल संपर्क प्रदान करती है।

उद्देश्य एवं लक्ष्य

- कश्मीर क्षेत्र को हर मौसम में निर्बाध रेलवे संपर्क प्रदान करना।
- दूरस्थ क्षेत्रों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़कर बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना।
- जम्मू-कश्मीर में व्यापार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देना।
- भारत की इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करना।





परियोजना का समयरेखा और पूरा होना

USBRL कुल लंबाई: 272 किमी (उधमपुर से बारामुला)

प्रमुख पड़ाव:

- काजीगुंड-बारामुला (118 किमी): अक्टूबर 2009 में चालू
- काजीगुंड-बनिहाल (18 किमी): जून 2013 में चालू
- उधमपुर-कटरा (25 किमी): जुलाई 2014 में चालू
- बनिहाल-संगलदान (48.1 किमी): फरवरी 2024 में चालू
- चेनाब पुल का उद्घाटन: जून 2025

चेनाब रेल पुल की प्रमुख विशेषताएँ

- ऊँचाई: 359 मीटर (एफिल टॉवर से ऊँचा)
- स्पैन (आर्च की लंबाई): 467 मीटर
- डिज़ाइन: स्टील और कंक्रीट आर्च

अन्य विशेषताएँ

- उच्च भूकंपीय गतिविधियों और तेज हवाओं को सहन करने के लिए डिज़ाइन किया गया
- 36 सुरंगों और 943 पुलों के साथ चुनौतीपूर्ण हिमालयी भूभाग में बनाया गया
- पर्यावरण अनुकूल परिवहन के लिए विद्युतीकृत रेलमार्ग
- चेनाब नदी (सिंधु की प्रमुख सहायक) पर निर्मित

राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व

- जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय एकता और विकास का प्रतीक
- यात्रा समय में कमी, माल परिवहन में सुधार और सुरक्षा लॉजिस्टिक्स में सहायता
- कश्मीर घाटी में सतत पर्यटन को प्रोत्साहन
- आपदा प्रबंधन क्षमता में सुधार और वर्ष भर पहुंच की सुविधा

प्रमुख अवसंरचना परियोजनाएँ

1. चेनाब रेल पुल

- ऊँचाई: 359 मीटर (चेनाब नदी के ऊपर)
- लंबाई: 1,315 मीटर
- संरचना: स्टील आर्च, भूकंप और तेज हवाओं के प्रतिरोधक
- महत्व: जम्मू-कश्मीर के बीच निर्बाध रेल संपर्क, सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार

2. अंजी पुल

- भारत का पहला केबल-स्टे रेल पुल
- दुर्गम हिमालयी इलाके में निर्मित
- कटरा और कश्मीर घाटी को जोड़ता है

3. USBRL (उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक)

- कुल लंबाई: 272 किमी
- उद्देश्य: कश्मीर घाटी को हर मौसम में रेल संपर्क प्रदान करना
- रणनीतिक महत्व: आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक

4. वंदे भारत ट्रेन सेवाएँ

- कटरा और श्रीनगर के बीच नई सेवाएँ
- यात्रा समय लगभग 3 घंटे (2-3 घंटे की बचत)
- पर्यटन, व्यापार और धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा

स्वास्थ्य सेवा में प्रगति

श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस

- निवेश: ₹350 करोड़
- स्थान: कटरा (रेसी ज़िला)
- क्षेत्र का पहला मेडिकल कॉलेज; गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाता है

RBI ने 55वीं मौद्रिक नीति समिति की बैठक की घोषणा की (जून 2025)

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 4 से 6 जून, 2025 तक अपनी 55वीं मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने की। यह बैठक बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और घरेलू परिस्थितियों के बीच हुई, और इसके प्रमुख फैसले विकास समर्थन और मूल्य स्थिरता के बीच संतुलन बनाने की दिशा में इंगित करते हैं।

प्रमुख निर्णय

1. नीतिगत दरों में कटौती

- रेपो दर: 6.00% से घटाकर 5.50% की गई (50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती)।
- कारण: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति लक्ष्य से नीचे है, जिससे विकास को समर्थन देना संभव हुआ।
- 2025 में दूसरी कटौती: फरवरी से अब तक कुल 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती।

2. नीतिगत कॉरिडोर में समायोजन

- Standing Deposit Facility (SDF):** 5.25% (रेपो दर से 25 bps कम)।
- Marginal Standing Facility (MSF)** और बैंक दर: 5.75% (रेपो दर से 25 bps अधिक)।

3. नीति रुख में बदलाव

- "समायोजी" (Accommodative) से "तटस्थ" (Neutral) में बदला।
- अब RBI डेटा आधारित दृष्टिकोण अपनाएगा, जिससे आगे और बड़ी कटौती की संभावना कम हो गई है।

आगामी MPC बैठकें

- 5-7 अगस्त, 2025
- 29-30 सितंबर और 1 अक्टूबर, 2025
- 3-5 दिसंबर, 2025
- 4-6 फरवरी, 2026

GDP पूर्वानुमान (FY26)

कोई परिवर्तन नहीं - 6.5% पर स्थिर:

अवधि	वर्तमान पूर्वानुमान	पूर्व पूर्वानुमान
FY26	6.5%	6.5%
Q1	6.5%	6.5%
Q2	6.7%	6.7%
Q3	6.6%	6.6%
Q4	6.3%	6.3%





CPI मुद्रास्फीति पूर्वानुमान (FY26)

3.7% (पहले 4.0%):

अवधि	वर्तमान अनुमान	पहले का अनुमान
FY26	3.7%	4.0%
Q1	2.9%	3.6%
Q2	3.4%	3.9%
Q3	3.9%	3.8%
Q4	4.4%	4.4%

मौद्रिक नीति समिति (MPC) के सदस्य

RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत, 6 सदस्यीय MPC का गठन किया गया है। 1 अक्टूबर 2024 की अधिसूचना के अनुसार वर्तमान सदस्य:

1. भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर – अध्यक्ष (पदेन)
2. मौद्रिक नीति के प्रभारी डिप्टी गवर्नर – सदस्य (पदेन)
3. RBI के केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी – सदस्य (पदेन)
4. डॉ. नागेश कुमार, निदेशक, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान – सदस्य
5. श्री सौगात भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री – सदस्य
6. प्रो. राम सिंह, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स – सदस्य
 - बाहरी सदस्य (क्रम 4 से 6) चार वर्ष के लिए या अगले आदेश तक नियुक्त हैं।
 - समिति में प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। टाई होने पर गवर्नर का निर्णायक वोट होता है।
 - हर सदस्य को अपने निर्णय का कारण स्पष्ट करना होता है।

RBI के मौद्रिक नीति उपकरण

रेपो दर

वह दर जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है (सरकारी प्रतिभूतियों के बदले)।

- दर में वृद्धि → उधारी महंगी → मुद्रास्फीति नियंत्रण
- दर में कमी → उधारी सस्ती → निवेश/विकास को प्रोत्साहन

स्थायी जमा सुविधा (SDF)

- बिना प्रतिभूति के RBI में बैंक अपनी अतिरिक्त नकदी जमा कर सकते हैं।
- अप्रैल 2022 में शुरू।
- रेपो दर से 25 bps कम।

सीमांत स्थायी सुविधा (MSF)

- बैंक अपनी SLR में कटौती कर RBI से आपातकालीन उधारी ले सकते हैं।
- रेपो दर से 25 bps अधिक।

तरलता समायोजन सुविधा (LAF)

- RBI द्वारा नकदी को प्रबंधित करने के लिए रेपो/रिवर्स रेपो ऑपरेशन।
- अन्य उपकरण: OMOs, MSS, फॉरेक्स स्वैप।

LAF कॉरिडोर

- रेंज जिसमें शॉर्ट टर्म ब्याज दरें बदलती हैं।
 - o ऊपरी सीमा: MSF दर
 - o निचली सीमा: SDF दर
 - o मध्य: रेपो दर

मुख्य नकदी प्रबंधन उपकरण

- 14-दिन की वेरिएबल रेट टर्म रेपो – मुख्य उपकरण जो CRR साइकिल के अनुरूप चलता है।

फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशन

- अप्रत्याशित नकदी बदलाव के लिए अल्पकालिक उपाय:
 - o ओवरनाइट/लंबी अवधि की नीलामी
 - o 14 दिन से अधिक की नीलामी भी संभव

रिवर्स रेपो दर

- RBI बैंकों से नकदी को सरकारी प्रतिभूतियों के बदले लेता है।
- अब SDF के बाद इसका उपयोग कम हुआ है।

बैंक दर

- RBI जिस दर पर वाणिज्यिक बिलों को रिडिस्काउंट करता है।
- CRR/SLR न बनाए रखने पर दंड स्वरूप शुल्क भी यही दर है।
- यह दर अब MSF दर के समान है।

नकद आरक्षित अनुपात (CRR)

- बैंक को अपनी जमा राशि का एक न्यूनतम हिस्सा RBI के पास रखना होता है।
- इससे नकदी की आपूर्ति नियंत्रित होती है।

वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)

- बैंकों को अपनी जमा राशि का एक हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी, या सोने में रखना होता है।
- बैंकिंग क्षेत्र की तरलता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

खुला बाजार परिचालन (OMOs)

- RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद।
- बिक्री → नकदी बाहर खींचना
- खरीद → नकदी बाजार में डालना

डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष: सबसे गरीब लोगों को सशक्त बनाने वाली तकनीकी क्रांति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार ने बीते 11 वर्षों में टेक्नोलॉजी की ताकत का इस्तेमाल कर आम लोगों के जीवन में अनगिनत लाभ पहुंचाए हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत युवाओं की ऊर्जा से टेक्नोलॉजी और नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2015 में शुरू की गई यह पहल भारत को एक डिजिटली सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने का लक्ष्य लेकर आई थी। बीते एक दशक में यह पहल जनकल्याण योजनाओं की रीढ़ बन गई है, जिससे विकास के लाभ देश के दूरदराज क्षेत्रों तक पहुंच सके हैं।





समाचार में क्यों?

जून 2025 में डिजिटल इंडिया मिशन को 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके गरीबों को सशक्त बनाने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में हुए प्रभाव को रेखांकित किया। अब यह पहल नीतिनिर्धारण और सेवा वितरण में गहराई से समाहित हो चुकी है।

डिजिटल इंडिया की प्रमुख उपलब्धियाँ

1. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT): गति और पारदर्शिता

- 322+ योजनाएँ, 56 मंत्रालयों से जुड़ी
- ₹44 लाख करोड़ सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित
- ₹3.48 लाख करोड़ की बचत बिचौलियों और गड़बड़ियों को खत्म करके
- पिछले दशक में DBT लेनदेन में 90 गुना वृद्धि

2. आधार: विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली

- 140 करोड़ से अधिक नागरिकों को 12-अंकीय आधार संख्या
- 150 अरब से अधिक आधार प्रमाणीकरण लेनदेन
- DBT, डिजिटल सिग्नेचर, बैंकिंग KYC जैसे कार्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण

3. डिजीलॉकर: कागज़ रहित शासन की ओर

- 52+ करोड़ उपयोगकर्ता
- 852+ करोड़ दस्तावेज़ जारी
- पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षिक प्रमाणपत्र आदि को सुरक्षित रूप से एक्सेस करने की सुविधा

4. जीवन प्रमाण: पेंशनभोगियों के लिए राहत

- डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र से बैंकों में जाने की आवश्यकता नहीं
- 10 करोड़ से अधिक पेंशनभोगी पंजीकृत
- नवंबर 2024 से अब तक 143 लाख प्रमाणपत्र जमा किए गए

5. उमंग ऐप: एक राष्ट्र, एक डिजिटल गेटवे

- 2,000+ सेवाएँ एक ही प्लेटफॉर्म पर
- 8.21 करोड़ उपयोगकर्ता, 597+ करोड़ लेनदेन

6. ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण

- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA):
 - o 6 करोड़ ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल साक्षर बनाना लक्ष्य
 - o डिजिटल खाई को पाटने और जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान: 9 वर्ष

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य पहल है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को उनकी गर्भावस्था के दूसरे और तीसरे तिमाही में निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण और सुनिश्चित प्रसवपूर्व देखभाल (ANC) सेवाएं प्रदान करना है। यह अभियान हर महीने की 9 तारीख को पूरे देश में आयोजित किया जाता है।

अब तक की उपलब्धियाँ (जून 2025 तक)

- 6.19 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं की जांच की जा चुकी है
- पंजीकृत स्वयंसेवी डॉक्टर: 6,813
- सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य केंद्र: 20,752

मुख्य उद्देश्य: मातृ और नवजात मृत्यु दर में कमी लाना

इस योजना का मूल उद्देश्य है हाई-रिस्क गर्भधारण की समय पर पहचान और प्रबंधन के माध्यम से मातृ मृत्यु दर (MMR) और नवजात मृत्यु दर को कम करना। समय रहते परीक्षण, परामर्श और रेफरल सुनिश्चित कर यह योजना सुरक्षित प्रसव में सहायक सिद्ध हो रही है।

निजी क्षेत्र के साथ सहभागिता: सार्वजनिक-निजी साझेदारी मॉडल यह योजना निजी डॉक्टरों के स्वैच्छिक योगदान को प्रोत्साहित करती है। वे:

- सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में ANC जांच करते हैं
- जागरूकता अभियान में भाग लेते हैं
- PMSMA दिवस पर स्वास्थ्य प्रणाली को सहयोग करते हैं

मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय सुधार

- 2014-16: 130 प्रति 1 लाख जीवित जन्म
- 2021-23: 80 प्रति 1 लाख जीवित जन्म
- 50 अंकों की गिरावट, जो सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की सफलता को दर्शाती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के RMNCAH+N लक्ष्यों के अनुरूप

यह योजना प्रजनन, मातृत्व, नवजात, शिशु, किशोर स्वास्थ्य और पोषण (RMNCAH+N) रणनीति का अहम हिस्सा है। इसके तहत:

- प्रत्येक गर्भवती महिला को दूसरी या तीसरी तिमाही में कम-से-कम एक विशेषज्ञ जांच मिलती है
- हाई-रिस्क गर्भधारण की पहचान और देखभाल पर जोर
- प्रसव की तैयारी और जटिलताओं से निपटने की योजना
- किशोर गर्भावस्था और कुपोषण पर ध्यान

PMSMA की प्रमुख विशेषताएं

- निश्चित ANC दिवस: हर महीने की 9 तारीख
- विशेषज्ञ डॉक्टरों की स्वैच्छिक सेवा
- निःशुल्क जांच, परामर्श और पोषण संबंधी सहायता
- हाई-रिस्क गर्भवती की समय पर पहचान
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की साझेदारी

विस्तारित PMSMA (E-PMSMA): हाई-रिस्क मामलों की निगरानी

जनवरी 2022 से शुरू हुआ E-PMSMA योजना का विस्तृत रूप है, जो हाई-रिस्क गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल तक ट्रेकिंग सुनिश्चित करता है। इसमें गर्भवती महिला और ASHA कार्यकर्ता दोनों को प्रोत्साहन दिया जाता है।

◆ मुख्य आँकड़े (31 दिसंबर 2024 तक)

- पहचानी गई हाई-रिस्क गर्भधारण: 78.27 लाख+

◆ प्रमुख विशेषताएं:

- नाम के अनुसार HRP's की सूची
- हर महीने 4 तक सत्रों की सुविधा
- प्रसव के 45वें दिन तक व्यक्तिगत ट्रेकिंग
- SMS अलर्ट द्वारा नियमित फॉलो-अप





PMSMA के अंतर्गत सेवाएं

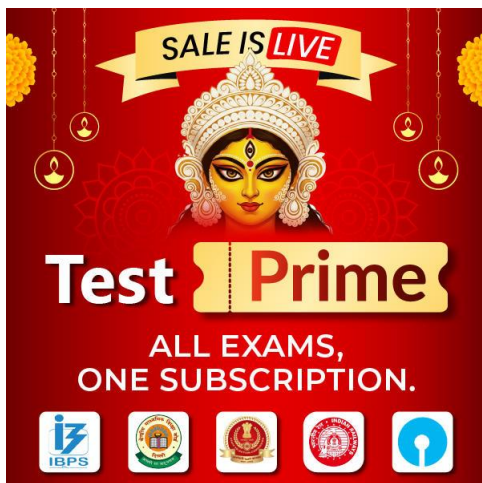
- संपूर्ण प्रसवपूर्व जांच (ANC)
- रक्त, मूत्र, रक्तचाप जांच
- पोषण परामर्श और सप्लीमेंट
- टिटनेस टीकाकरण
- जटिलताओं के लिए विशेषज्ञ रेफरल
- प्रसव की योजना बनाना

अन्य मातृ और शिशु स्वास्थ्य योजनाओं के साथ समन्वय

योजना	उद्देश्य	उपलब्धियां (मार्च 2025 तक)
जननी सुरक्षा योजना (JSY)	संस्थागत प्रसव के लिए नकद प्रोत्साहन	11.07 करोड़ लाभार्थी
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)	निःशुल्क प्रसव और नवजात देखभाल	16.60 करोड़ लाभार्थी
लक्ष्य (LaQshya)	प्रसव कक्ष और मातृ ICU की गुणवत्ता सुधार	जारी
सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (SUMAN)	गरिमायु मातृत्व देखभाल की गारंटी	90,015 सक्रिय सुविधाएं
पोषण अभियान	कुपोषण की रोकथाम	6.97 करोड़ पोषण पखवाड़े
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)	₹5,000 नकद सहायता	मातृ और शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा

बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा

भारत की प्रमुख साहित्यिक संस्था और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन साहित्य अकादमी ने देश में बाल साहित्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। श्री माधव कौशिक की अध्यक्षता में कार्यकारी बोर्ड ने हाल ही में अपनी बैठक में प्रतिष्ठित बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के विजेताओं को अंतिम रूप देने के लिए बैठक की।



बाल साहित्य पुरस्कार 2025 विजेताओं की पूरी सूची

भाषा-वार पुरस्कार प्राप्तकर्ता

निम्न तालिका में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के 24 प्रतिष्ठित विजेताओं की पूरी सूची प्रस्तुत की गई है, जिन्हें भाषा के अनुसार उनके संबंधित कार्यों और लेखकों के साथ व्यवस्थित किया गया है:

क्रमांक	भाषा	कृति का नाम (विधा)
1	असमिया	महाभारतर पद्य (कविता)
2	बंगाली	एछारा गए कथा दाए (कहानी संग्रह)
3	बोडो	खांथि बोरोन्न अंग अभु दुहुई (कहानी संग्रह)
4	डोगरी	नाचि तोर (कविता)
5	अंग्रेज़ी	दिवाकर सिन्हा: इंडियन माइथ्स एंड फेबल्स (कथाएँ)
6	गुजराती	त्रिवक (कविता)
7	हिंदी	एक काले बारा (लघुकथाएँ)
8	कन्नड़	नोटबुक (लघुकथाएँ)
9	कश्मीरी	शूरे ता तोतुरु ग्याश (लघुकथाएँ)
10	कोंकणी	बेटेकड्डो शंकर आनी हार काऱ्यो (कथाएँ)
11	मैथिली	औदिक (लघुकथाएँ)
12	मलयालम	रंगमंडलाचे यद्रावादी (उपन्यास)
13	मणिपुरी	अंगांगांगीनगे शमहुंगसीदा (नाटक)
14	मराठी	आठमंगा (कविता)
15	नेपाली	शांति वन (उपन्यास)
16	उड़िया	केते फुला फुताची (कविता)
17	पंजाबी	जादू पटका (उपन्यास)
18	राजस्थानी	पनाहरावंश नी पीड़ा (नाटक)
19	संस्कृत	बालवियम् (कविता)
20	संथाली	सोना मौ-अग संदेश (कविता)
21	सिंधी	आसमान हरी (कविता)
22	तमिल	ओत्रै सिरागो ओरवा (उपन्यास)
23	तेलुगु	काकुरला देवता (कहानी)
24	उर्दू	कौमी सितारे (निबंध/लेख)

साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 विजेता

साहित्य अकादमी, जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है और भारतीय साहित्य की सर्वोच्च संस्था मानी जाती है, ने युवा लेखकों के अद्वितीय योगदान को मान्यता देने हेतु एक ऐतिहासिक घोषणा की है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक के नेतृत्व में कार्यकारी मंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें युवा पुरस्कार 2025 के विजेताओं के नामों को अंतिम रूप दिया गया। यह पुरस्कार भारत के युवा साहित्यकारों की रचनात्मक प्रतिभा, भाषा के प्रति समर्पण और समसामयिक विषयों पर उनकी सशक्त लेखनी को सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है।





युवा पुरस्कार 2025 प्राप्तकर्ताओं की पूरी सूची

विजेताओं की विस्तृत तालिका

निम्न तालिका में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के 23 प्रतिष्ठित विजेताओं की पूरी सूची प्रस्तुत की गई है, जिन्हें भाषा के अनुसार उनके संबंधित कार्यों और लेखकों के साथ व्यवस्थित किया गया है:

क्रमांक	भाषा	पुस्तक का नाम (विधा)	लेखक का नाम
1	असमिया	कुशियारामा (लघु कहानियाँ)	सुप्रक्षम भुयान
2	बांग्ला	एकदा चिनिष तोलियामी (कविता)	सुदेशना मोइत्रा
3	बोडो	अंग ऐसू (कविता)	अमर खुंगुर बोरो
4	अंग्रेज़ी	सिद्धार्थ - द बॉय हू बिकेम द बुद्धा (उपन्यास)	अद्वैत कोलारकर
5	गुजराती	नारंच टेकारी (निबंध)	मयूर खराडी
6	हिंदी	फिर उगना (कविता)	प्रवेश यादव
7	कन्नड	पञ्चेया जगत (आलोचना)	आर. दीपकुमार
8	कश्मीरी	हरफ़स हरफ़स ज़ागी (आलोचना)	साइबा सहर
9	कोंकणी	गावगास्थास (लघु कहानियाँ)	ग्लिनिस डायस
10	मैथिली	बनारस आ हम (कविता)	नेहा झा मैनी
11	मलयालम	राम ओरु आनंदी (उपन्यास)	अखिल धर्मजन पी.
12	मणिपुरी	खोयुम नोंगदान चोई (महाकाव्य)	ए. के. जीतन
13	मराठी	खेल खेल दुःखाना देले (उपन्यास)	प्रदीप कोकणे
14	नेपाली	जुनको आँसु (कविता)	सुभाष ठकुरी
15	उड़िया	कडेमसाबना (लघु कहानियाँ)	सुब्रत कुमार सेनापति
16	पंजाबी	गिरका हॉस्टल (कविता)	मंदीप औलख
17	राजस्थानी	आंखस नी संगमत (कविता)	पूनम चंद गोदारा
18	संस्कृत	पंचभौतिकशहोल-स्वावास्यम् (वेदान्तदर्शनसारविशेषता) (आलोचना)	धिरेशना कुमार पांडेय
19	संथाली	आरा साजो ते (कविता)	फागुई बास्के
20	सिंधी	पांधियादो (कविता)	मंझम बचानी
21	तमिल	कुट्टार कुत्तुवि (लघु कहानियाँ)	लटरहिन्हार
22	तेलुगु	मरलावाथा (उपन्यास)	प्रसाद सूरी
23	उर्दू	मौरल्लड हकीकत, तहरीक-ए-आज़ादी, और हिंदी जिहाद का फर्मानसुत्ति करदा क़साइद (उपन्यास)	नीतू रुबाबी

विविध साहित्यिक विधाएँ और रचनात्मक समृद्धि

विस्तृत साहित्यिक प्रतिनिधित्व

युवा पुरस्कार 2025 के विजेताओं की सूची समकालीन भारतीय लेखन की विविधता और गहराई को दर्शाती है। यह विविधता उभरते हुए लेखकों की रुचियों और क्षमताओं की विविधता के साथ-साथ आधुनिक भारतीय साहित्य की जीवंत प्रकृति को भी प्रतिबिंबित करती है।

कविता संग्रह:

सबसे बड़ी श्रेणी रही कविता, जिसमें 8 भाषाओं—बांग्ला, बोडो, हिंदी, मैथिली, नेपाली, पंजाबी, राजस्थानी, संथाली और सिंधी—में उत्कृष्ट रचनाएँ शामिल हैं। यह युवा लेखकों के बीच काव्यात्मक अभिव्यक्ति की निरंतर प्रासंगिकता को दर्शाता है।

लघु कथाएँ:

4 भाषाओं—असमिया, कोंकणी, उड़िया और तमिल—में लघु कहानी संग्रह प्रस्तुत किए गए हैं। यह दर्शाता है कि समकालीन कहानियाँ कहने का यह माध्यम अभी भी अत्यधिक लोकप्रिय है।

उपन्यास:

5 भाषाओं—अंग्रेज़ी, मलयालम, मराठी, तेलुगु और उर्दू—में प्रमुख उपन्यास प्रकाशित हुए हैं, जो युवा उपन्यासकारों की साहित्यिक उपलब्धियों को रेखांकित करते हैं।

आलोचना और निबंध:

4 भाषाओं—गुजराती, कन्नड, कश्मीरी और संस्कृत—में आलोचनात्मक लेखन प्रस्तुत किया गया है। यह दिखाता है कि युवा लेखक केवल रचनात्मक ही नहीं, बल्कि दार्शनिक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से भी साहित्य में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं।

महाकाव्य साहित्य:

मणिपुरी भाषा में एक अद्वितीय महाकाव्य रचना को मान्यता दी गई है, जो पारंपरिक साहित्यिक शैलियों की समकालीन लेखन में निरंतरता को दर्शाती है।

यह विविधता भारतीय भाषाओं की समृद्ध परंपरा और उनमें पनप रही नई आवाज़ों की गूंज का प्रमाण है।

सांस्कृतिक और भाषाई महत्त्व

हर चयनित रचना न केवल व्यक्तिगत साहित्यिक उपलब्धि का प्रतीक है, बल्कि अपनी-अपनी भाषा की साहित्यिक परंपरा के संरक्षण और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न विधाओं की यह विविधता यह सुनिश्चित करती है कि मानव अनुभव और कलात्मक अभिव्यक्ति के अनेक पहलू इस वर्ष के पुरस्कारों में सम्मिलित हों।

पुरस्कार संरचना और मान्यता पैकेज

समग्र मान्यता ढाँचा

युवा पुरस्कार 2025 के विजेताओं को एक ऐसा समग्र मान-सम्मान प्राप्त होगा, जो उनके साहित्यिक योगदान की प्रतीकात्मक और व्यावहारिक दोनों ही दृष्टियों से सराहना करता है। यह पुरस्कार संरचना उभरते हुए लेखकों को उनके साहित्यिक करियर के निर्णायक चरणों में सशक्त समर्थन देने के उद्देश्य से बनाई गई है।





प्रतीकात्मक सम्मान:

हर विजेता को एक सुंदर संदूक (कास्केट) प्रदान किया जाएगा जिसमें उनका नाम खुदा हुआ एक तांबे का पट्ट (कॉप्पर प्लेट) होगा। यह उनकी साहित्यिक उपलब्धि का स्थायी प्रतीक होगा और उन्हें साहित्य अकादमी की प्रतिष्ठित परंपरा से जोड़ता है।

आर्थिक सहायता:

प्रतीकात्मक सम्मान के साथ-साथ प्रत्येक पुरस्कार विजेता को ₹50,000 की पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहयोग युवा लेखकों को साहित्य-साधना में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों से उबरने में मदद करेगा और उनके रचनात्मक प्रयासों को आगे बढ़ाने में सहायक होगा।

विशेष पुरस्कार समारोह

साहित्य अकादमी ने घोषणा की है कि युवा पुरस्कार 2025 के औपचारिक वितरण के लिए एक विशेष समारोह का आयोजन भविष्य में किसी उपयुक्त तिथि पर किया जाएगा। यह आयोजन इन युवा साहित्यकारों की उपलब्धियों का उत्सव मनाने और समकालीन भारतीय साहित्य में उनके योगदान को रेखांकित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा।

यह समारोह कई उद्देश्यों की पूर्ति करेगा:

- विजेताओं को सार्वजनिक स्तर पर पहचान और सम्मान प्रदान करना
- साहित्यिक समुदाय के भीतर संवाद और नेटवर्किंग के अवसर उपलब्ध कराना
- उभरती हुई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने में साहित्य अकादमी की प्रतिबद्धता को दर्शाना

जूरी की सिफारिशें और विशेषज्ञ मान्यता

विशेषज्ञ समिति की संरचना

युवा पुरस्कार 2025 की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को उन जूरी सदस्यों की विशेषज्ञता और प्रतिष्ठा से बल मिला है, जिनकी सिफारिशों के आधार पर अंतिम चयन किए गए।

आधिकारिक दस्तावेज के परिशिष्ट 'बी' में इन जूरी सदस्यों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इनका सामूहिक अनुभव और विद्वता भारतीय भाषाओं और साहित्यिक परंपराओं के पूरे परिदृश्य को समेटे हुए है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि चयन निष्पक्ष, सुसंगत और साहित्यिक मूल्यों पर आधारित है।

लोकतांत्रिक निर्णय-निर्माण प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता, जिसमें विशेषज्ञ जूरी द्वारा बहुमत अथवा सर्वसम्मति से मतदान पर बल दिया गया है, यह सुनिश्चित करती है कि युवा पुरस्कार अपनी उत्कृष्टता की प्रतिष्ठा बनाए रखे। यह लोकतांत्रिक तरीका पक्षपात को रोकता है और इस बात की गारंटी देता है कि चयन केवल साहित्यिक योग्यता के आधार पर होता है।

समकालीन भारतीय साहित्य पर प्रभाव

युवा आवाज़ों को प्रोत्साहन

युवा पुरस्कार 2025 भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में युवाओं को साहित्यिक करियर अपनाने के लिए प्रेरित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। करियर की शुरुआती अवस्था में ही मान्यता और आर्थिक सहयोग देकर यह पुरस्कार उनके लिए एक स्थायी साहित्यिक योगदान की नींव रखता है।

भाषा संरक्षण एवं नवाचार

बहुभाषी दृष्टिकोण के माध्यम से यह पुरस्कार भारत की विविध भाषाओं के संरक्षण और विकास में अहम योगदान देता है। युवा लेखक पारंपरिक भाषाओं में नई दृष्टि और रचनात्मकता लाते हैं, जिससे भाषाएं अपने सांस्कृतिक सार को बनाए रखते हुए विकसित होती हैं।

साहित्यिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण

यह पुरस्कार एक मज़बूत साहित्यिक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में मदद करता है, जिसमें युवा लेखकों, वरिष्ठ साहित्यकारों, प्रकाशकों और पाठकों के बीच सम्बंधों और संवाद का निर्माण होता है। इस नेटवर्किंग प्रभाव के माध्यम से व्यक्तिगत पहचान सामूहिक साहित्यिक विकास में परिवर्तित हो जाती है।

क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2026: शीर्ष 10 और सर्वश्रेष्ठ भारतीय विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 का प्रकाशन QS (क्वैकक्वारेली सायमंड्स) द्वारा आधिकारिक रूप से कर दिया गया है। यह रैंकिंग दुनिया की 1,500 से अधिक विश्वविद्यालयों को शामिल करती है, जो 100 से अधिक देशों से हैं, और यह वैश्विक उच्च शिक्षा परिदृश्य में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और विकास को दर्शाती है।

MIT लगातार 14वें वर्ष शीर्ष पर

- मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) ने लगातार 14वें वर्ष वैश्विक स्तर पर #1 स्थान प्राप्त किया है।
- यह संस्थान शैक्षणिक प्रतिष्ठा, फैकल्टी-स्टूडेंट अनुपात, और नियोजित प्रतिष्ठा जैसे मानकों पर शीर्ष प्रदर्शन कर रहा है।
- MIT की यह स्थिति इसके शोध कौशल, नवाचार नेतृत्व, और शैक्षणिक कठोरता को दर्शाती है।

मुख्य रूढ़ान और सुधार

- QS की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस वर्ष लगभग 500 विश्वविद्यालयों ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है।
- सुधार के प्रमुख कारणों में शामिल हैं:
 - o प्रति फैकल्टी उद्धरण (Citations per Faculty)
 - o अंतरराष्ट्रीय छात्र अनुपात
 - o सतत विकास (Sustainability) प्रयास

एशिया से चमका मलेशिया का सनवे विश्वविद्यालय

- सनवे यूनिवर्सिटी (Sunway University), मलेशिया ने अपनी रैंकिंग में 120 से अधिक स्थानों की छलांग लगाई है।
- यह उभरता प्रदर्शन एशिया की वैश्विक शिक्षा में बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है, जो निम्नलिखित के चलते संभव हुआ है:
 - o शोध अवसंरचना में निवेश
 - o अंतरराष्ट्रीय सहयोग
 - o विविध और समावेशी अकादमिक वातावरण

2026 QS रैंकिंग की वैश्विक पहुंच

- यह संस्करण 100 से अधिक क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों को कवर करता है, जिनमें शामिल हैं:
 - o उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका
- यह रैंकिंग छात्रों, शोधकर्ताओं और नीति-निर्माताओं के लिए एक मूल्यवान मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है।





क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष 10 विश्वविद्यालय नवीनतम रैंकिंग के अनुसार, शीर्ष 10 वैश्विक संस्थान इस प्रकार हैं:

क्रमांक	संस्थान का नाम (अंग्रेजी में)	2026 में रैंक	2025 में रैंक
1	मैसाचुसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT)	1	1
2	इम्पीरियल कॉलेज लंदन	2	2
3	स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी	3	6
4	यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड	4	3
5	हार्वर्ड यूनिवर्सिटी	5	4
6	यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज	6	5
7	ईटीएच ज्यूरिख (स्विस फेडरल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी)	7	7
8	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (NUS)	8	8
9	यूसीएल (यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन)	9	9
10	कैलिफोर्निया इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (कैलटेक)	10	10

वैश्विक सूची में शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय

क्रमांक	संस्थान का नाम	2026 में रैंक	2025 में रैंक
1	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IIT Delhi)	123	150
2	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (IIT Bombay)	129	118
3	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT Madras)	180	227
4	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खडगपुर (IIT Kharagpur)	215	222
5	भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु (IISc Bangalore)	219	211
6	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर (IIT Kanpur)	222	263
7	दिल्ली विश्वविद्यालय (University of Delhi)	328	328
8	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी (IIT Guwahati)	334	344
9	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की (IIT Roorkee)	339	335
10	अन्ना विश्वविद्यालय (Anna University)	465	383

PM मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 16 जून, 2025 को साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौल्लिडिस द्वारा 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III' से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार साइप्रस के पहले राष्ट्रपति आर्कबिशप मकारियोस III के नाम पर रखा गया है और यह उन वैश्विक नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के लिए आरक्षित है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंधों और शांति में उत्कृष्ट योगदान दिया है।

समाचार में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 16 जून 2025 को साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौल्लिडिस द्वारा 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III' से सम्मानित किया गया। यह साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो वैश्विक नेताओं को अंतरराष्ट्रीय संबंधों और शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान पीएम मोदी को भारत-साइप्रस संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया। यह यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि नरेंद्र मोदी साइप्रस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने।

सम्मान के बारे में

- नाम: ऑर्डर ऑफ मकारियोस III
- देश: साइप्रस गणराज्य
- नामकरण: आर्कबिशप मकारियोस III (साइप्रस के पहले राष्ट्रपति) के नाम पर
- उद्देश्य: राष्ट्र सेवा और अंतरराष्ट्रीय राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया जाता है

सम्मान की श्रेणियाँ

- ग्रैंड कॉलर
- ग्रैंड क्रॉस (पीएम मोदी को दिया गया)
- ग्रैंड कमांडर
- कमांडर
- ऑफिसर
- नाइट

प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया

“साइप्रस के ‘Grand Cross of the Order of Makarios III’ सम्मान को पाकर अभिभूत हूँ। मैं इसे भारत और साइप्रस की मित्रता को समर्पित करता हूँ।” (यह संदेश पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर साझा किया।)

द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति क्रिस्टोडौल्लिडिस के बीच उच्च स्तरीय वार्ताएं हुईं। प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा:

- नवाचार (Innovation)
- ऊर्जा सहयोग
- प्रौद्योगिकी में साझेदारी
- व्यापार और रणनीतिक संबंध

CEO राउंडटेबल

- पीएम मोदी ने भारतीय और साइप्रियट व्यवसायियों के साथ बातचीत की
- भारत में आर्थिक सुधारों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जानकारी साझा की

साझा उद्देश्य

- रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को और विस्तार देना
- सतत विकास, नवाचार और डिजिटल परिवर्तन पर साझेदारी करना





ऐतिहासिक यात्रा की मुख्य झलकियाँ

- पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस की यात्रा पर पहुंचे
- लारनाका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति द्वारा स्वयं स्वागत किया गया
- लिमासोल में प्रवासी भारतीय समुदाय द्वारा गर्मजोशी से अभिनंदन
- साइप्रस राष्ट्रपति ने कहा:
“आज हम और अधिक पुल बना रहे हैं... विश्वास, साझा मूल्य, नवाचार और हमारे समृद्ध ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित एक नई रणनीतिक साझेदारी का युग आरंभ हो रहा है।”

भारत 2026 में पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करेगा

भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने घोषणा की है कि वह 2026 में पहला ऑल-इंडिया हाउसहोल्ड इनकम सर्वेक्षण (All-India Household Income Survey) आयोजित करेगा। यह ऐतिहासिक पहल देश में आय वितरण, प्रौद्योगिकी के प्रभाव और आर्थिक असमानताओं को बेहतर ढंग से समझने में सहायक होगी।

समाचार में क्यों?

यह सर्वेक्षण देश के इतिहास में पहली बार घरेलू आय पर केंद्रित होगा, जिसका उद्देश्य है

- वेतन और आजीविका में तकनीकी प्रगति का प्रभाव समझना,
 - और कल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी और लक्षित बनाना।
- इस सर्वेक्षण की निगरानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के पूर्व कार्यकारी निदेशक सुरजीत भल्ला की अध्यक्षता में गठित तकनीकी विशेषज्ञ समूह (TEG) करेगा।

प्रमुख उद्देश्य

- देशभर के परिवारों में आय वितरण का पैटर्न समझना।
- यह देखना कि तकनीक का प्रभाव वेतन व आय पर क्या पड़ रहा है।
- कल्याणकारी योजनाओं की बेहतर पहचान और टारगेटिंग के लिए ठोस आय-आधारित डेटा प्रदान करना।
- अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप डेटा संग्रह।

तकनीकी पर्यवेक्षण

- TEG सर्वे की रूपरेखा, परिभाषाओं, सैम्पलिंग डिज़ाइन और अनुमान विधियों पर सलाह देगा।
- सर्वेक्षण की प्रक्रिया में वैश्विक मानकों को अपनाया जाएगा।

क्रियान्वयन और रणनीति

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा।
- इसमें विभिन्न आय स्रोतों को शामिल किया जाएगा जैसे:
 - वेतन
 - स्वरोजगार
 - रेमिटेंस (विदेश से भेजी गई राशि)
 - डिजिटल आय
- पहले के प्रयासों की तुलना में डेटा विश्वसनीयता और क्षेत्रीय विश्लेषण को मजबूत किया जाएगा।

महत्व और संभावित प्रभाव

- भारत में पहली बार आय-केन्द्रित सर्वेक्षण।
- अब तक के आर्थिक सर्वेक्षण मुख्यतः खपत या रोजगार पर आधारित रहे हैं।
- इससे आर्थिक विषमता को समझने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में सुधार लाने में मदद मिलेगी।
- योजनाएं जैसे पीएम-किसान, सब्सिडी लक्षित प्रणाली और DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) को और सटीक बनाया जा सकेगा।

वैश्विक शांति सूचकांक 2025: वैश्विक स्थिरता और बढ़ते तनाव पर गहन नजर

वैश्विक शांति सूचकांक (Global Peace Index - GPI) 2025, जो अब अपने 19वें संस्करण में है, दुनिया में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति का सबसे प्रमुख मापक बना हुआ है। इंस्टिट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा विकसित यह सूचकांक 163 देशों की शांति स्थिति का मूल्यांकन करता है, जो विश्व की 99.7% आबादी को कवर करता है। ऐसे समय में जब वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है, GPI संघर्ष, सुरक्षा और सैन्यकरण की वर्तमान वैश्विक प्रवृत्तियों का एक महत्वपूर्ण संकेतक बन गया है।

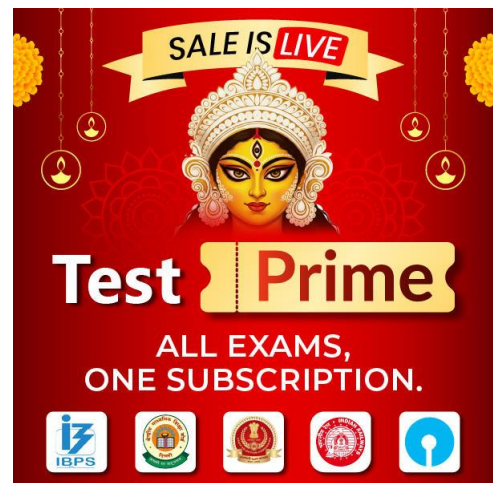
क्या है 'वैश्विक शांति सूचकांक'?

- ग्लोबल पीस इंडेक्स (GPI) एक वार्षिक मात्रात्मक विश्लेषण है, जो शांति को तीन प्रमुख क्षेत्रों में 23 संकेतकों के आधार पर मापता है:
 1. सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा
 2. चल रहे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संघर्ष
 3. सैन्यकरण की स्थिति

कौन करता है प्रकाशन?

इस सूचकांक को इंस्टिट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) में स्थित एक स्वतंत्र, गैर-पक्षपाती थिंक टैंक है।

IEP का उद्देश्य स्थायी शांति और सुरक्षा सुधारों के लिए सरकारों, शोधकर्ताओं और वैश्विक संस्थानों को विश्वसनीय आंकड़ों और विश्लेषणों के माध्यम से मार्गदर्शन देना है।





वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के प्रमुख मापदंड

मापदंड	विवरण
GPI क्या है?	23 संकेतकों पर आधारित 3 क्षेत्रों में शांति को मापने वाला समग्र सूचकांक
प्रकाशक संस्था	इंस्टिट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस (IEP)
संस्करण	19वाँ संस्करण (वर्ष 2025)
शामिल देश	कुल 163 देश
शीर्ष स्थान प्राप्त देश	आइसलैंड (रैंक 1, स्कोर: 1.095)
भारत की रैंकिंग (2025)	115वाँ स्थान (स्कोर: 2.229)
वैश्विक शांति प्रवृत्ति	2024 की तुलना में 0.36% की गिरावट
शांति में सुधार वाले देश	74 देश
स्थिति बिगड़ने वाले देश	87 देश
निचला स्थान प्राप्त देश	रूस (रैंक 163, स्कोर: 3.441)
सबसे खराब क्षेत्र	दक्षिण एशिया
हिंसा की आर्थिक लागत	\$19.97 ट्रिलियन (वैश्विक GDP का 11.6%)
सबसे अधिक बिगड़ा संकेतक	लड़े गए बाहरी संघर्ष (External Conflicts Fought)
सबसे बेहतर सुधार संकेतक	आपराधिकता की धारणा (Perceptions of Criminality)

वैश्विक शांति सूचकांक (GPI) स्कोर कैसे गणना किया जाता है

GPI स्कोर 23 संकेतकों पर आधारित एक वेटेड (भारांकित) प्रणाली के माध्यम से तैयार किया जाता है, जो गुणात्मक मूल्यांकन (जैसे कि राजनीतिक स्थिरता, आपराधिकता की धारणा) और मात्रात्मक आँकड़ों (जैसे कि हत्या की दर, आंतरिक संघर्षों की संख्या) को शामिल करता है।

यह स्कोर 1 (सबसे शांतिपूर्ण) से 5 (सबसे अशांत) के बीच होता है। कम GPI स्कोर का अर्थ है कि कोई देश अधिक शांतिपूर्ण और स्थिर है।

गणना में शामिल प्रमुख कारक:

- आंतरिक और बाहरी संघर्ष की अवधि
- आतंकवाद का प्रभाव और हत्या की दर
- राजनीतिक अस्थिरता और दमन
- सैन्य व्यय और हथियारों का आयात
- पड़ोसी देशों के साथ संबंध

वैश्विक शांति सूचकांक 2025: प्रमुख प्रवृत्तियाँ और मुख्य बातें

वैश्विक शांति में गिरावट

2025 वैश्विक शांति में पिछले 17 वर्षों में 13वीं गिरावट का वर्ष है। औसतन वैश्विक शांति में 0.36% की कमी दर्ज की गई।

- 87 देशों में स्थिति खराब हुई
- 74 देशों में सुधार हुआ

संघर्षों में वृद्धि

वर्तमान में 59 सक्रिय राज्य-आधारित संघर्ष चल रहे हैं — यह संख्या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे अधिक है।

- केवल 2024 में 1.52 लाख से अधिक मौतें हुईं।

सैन्यीकरण में इज़ाफ़ा

84 देशों में सैन्य व्यय (GDP के प्रतिशत के रूप में) बढ़ा है, जो वैश्विक असुरक्षा और तनाव का संकेत है।

यह प्रवृत्तियाँ बताती हैं कि वैश्विक स्तर पर तनाव, संघर्ष और सैन्यीकरण बढ़ रहा है, जिससे शांति बनाए रखना अधिक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है।

2025 में विश्व के शीर्ष 10 सबसे शांतिपूर्ण देश (Global Peace Index के अनुसार)

वैश्विक अशांति के बावजूद, कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अत्यधिक शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखी है:

रैंक	देश	GPI स्कोर	क्षेत्र
1	आइसलैंड (Iceland)	1.095	यूरोप
2	आयरलैंड (Ireland)	1.260	यूरोप
3	न्यूज़ीलैंड (New Zealand)	1.282	ओशिनिया
4	ऑस्ट्रिया (Austria)	1.294	यूरोप
5	स्विट्ज़रलैंड (Switzerland)	1.294	यूरोप
6	सिंगापुर (Singapore)	1.357	एशिया
7	पुर्तगाल (Portugal)	1.371	यूरोप
8	डेनमार्क (Denmark)	1.393	यूरोप
9	स्लोवेनिया (Slovenia)	1.409	यूरोप
10	फिनलैंड (Finland)	1.420	यूरोप

सबसे शांतिपूर्ण देश: आइसलैंड (Iceland)

आइसलैंड वर्ष 2008 से लगातार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है।

इसकी प्रमुख वजहें हैं:

- अत्यंत कम अपराध दर
- स्थिर और पारदर्शी राजनीतिक व्यवस्था
- स्थायी सैन्य बलों की अनुपस्थिति

2025 में सबसे कम शांतिपूर्ण देश (Global Peace Index के अनुसार)

GPI रैंकिंग के निचले पायदान पर वे देश हैं जो गंभीर संघर्ष, युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं:

रैंक	देश	GPI स्कोर	क्षेत्र
163	रूस (Russia)	3.441	यूरेशिया
162	यूक्रेन (Ukraine)	3.434	यूरोप
161	सूडान (Sudan)	3.323	अफ्रीका
160	कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC)	3.292	अफ्रीका
159	यमन (Yemen)	3.262	मध्य पूर्व

सबसे कम शांतिपूर्ण देश: रूस

यूक्रेन युद्ध के लंबा खिंचने, पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और आंतरिक राजनीतिक दमन के कारण रूस को 2025 के वैश्विक शांति सूचकांक (GPI) में सबसे निचला स्थान (रैंक 163) प्राप्त हुआ है। इसके ठीक बाद यूक्रेन का स्थान है।





भारत का प्रदर्शन - वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में

भारत ने 163 देशों में 115वां स्थान प्राप्त किया है, और इसका GPI स्कोर 2.229 है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 0.58% सुधार को दर्शाता है।

भारत की GPI रैंकिंग का वर्षवार विश्लेषण:

वर्ष	रैंक
2025	115
2024	116
2023	126
2020	139
2019	141

सुधार के प्रमुख क्षेत्र:

- अपराध की धारणा में सुधार
- राजनीतिक स्थिरता में वृद्धि
- आतंकवाद से प्रभाव में कमी

हालाँकि, भारत अब भी आंतरिक अशांति, सीमा-पार तनाव, और सैन्यकरण जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है।

दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति

दक्षिण एशिया अब भी दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र माना गया है, लेकिन भारत ने अपने कई पड़ोसी देशों से बेहतर प्रदर्शन किया है:

देश	GPI रैंक
भारत	115
बांग्लादेश	123
पाकिस्तान	144
अफगानिस्तान	158

क्षेत्रीय शांति विश्लेषण

पश्चिमी और मध्य यूरोप

यह अब भी दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है, लेकिन आतंकवाद की आशंकाओं, राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों, और आर्थिक दबावों के कारण धीरे-धीरे गिरावट देखी जा रही है।

मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका

लगातार दसवें वर्ष यह क्षेत्र सबसे कम शांतिपूर्ण रहा है। गृह युद्धों और राजनीतिक अस्थिरता ने इस क्षेत्र की स्थिति को गंभीर बना दिया है।

दक्षिण एशिया

2025 में सबसे बड़ी गिरावट दक्षिण एशिया में देखी गई, विशेष रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की स्थितियों के कारण।

एशिया-प्रशांत

मिश्रित परिणाम देखने को मिले:

- न्यूजीलैंड और सिंगापुर ने अपनी शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखी।
- लेकिन अन्य देशों ने भूराजनीतिक तनावों के चलते गिरावट दर्ज की।

उप-सहारा अफ्रीका

लंबे समय से चल रहे संघर्ष, विशेष रूप से सूडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में, अब भी क्षेत्र की शांति को बाधित कर रहे हैं।

दक्षिण अमेरिका

2025 में सुधार दिखाने वाला एकमात्र क्षेत्र।

- लोकतांत्रिक बदलाव और नीतिगत सुधार, विशेषकर पेरू जैसे देशों में, इस सुधार का कारण रहे।

उत्तर अमेरिका

- कुछ सुरक्षा संकेतकों में सुधार देखा गया,
- लेकिन गन वायलेंस (हथियारों से होने वाली हिंसा) और राजनीतिक ध्रुवीकरण अभी भी बड़ी चिंताएं बनी हुई हैं।

2024 में हिंसा की आर्थिक लागत

कुल लागत: \$19.97 ट्रिलियन

वैश्विक GDP का हिस्सा: 11.6%

इन मदों में शामिल:

- युद्ध और सशस्त्र संघर्ष
- आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था
- पुलिसिंग और कानून व्यवस्था
- सैन्य खर्च

शुभांशु शुक्ला ने स्पेसएक्स फाल्कन 9 से एक्सिओम-4 को आईएसएस तक पहुंचाया

25 जून 2025 को दोपहर 12:01 बजे (भारतीय समयानुसार), भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की ओर उड़ान भरी। यह भारत के अंतरिक्ष इतिहास में दूसरा मानव मिशन है और पहली बार कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री ISS पर रहकर काम कर रहा है।

कौन हैं शुभांशु शुक्ला? - एक फाइटर पायलट से अंतरिक्ष यात्री तक का सफर

- जन्म: 10 अक्टूबर 1985, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
- शिक्षा: 2005 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) से स्नातक
- भारतीय वायुसेना में कमीशन: जून 2006 को फाइटर पायलट के रूप में
- उड़ान अनुभव: 2000 घंटे से अधिक, लड़ाकू विमान - Su-30MKI, मिग-21/29, जैगुआर, हॉक
- ISRO से जुड़ाव: 2019 में गगनयान मिशन के लिए चयन
- प्रशिक्षण: रूस और बेंगलुरु में
- मिशन नाम: Axiom-4 (Ax-4)
- नामांकन: जनवरी 2024 में अंतरराष्ट्रीय चालक दल में चयन

फाल्कन 9 ब्लॉक 5 और क्यू ड्रैगन कैप्सूल

- फाल्कन 9 ब्लॉक 5: स्पेसएक्स का मानव मिशनों के लिए प्रमाणित पुनः प्रयोज्य रॉकेट
- 2020 में NASA से प्रमाणन प्राप्त
- 100% मानव मिशन सफलता दर
- क्यू ड्रैगन कैप्सूल: स्वचालित रूप से नियंत्रित, चार अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्रियों को ISS तक पहुंचाने के लिए प्रयोग किया गया





Ax-4 मिशन: एक वैश्विक सहयोग

- कमांडर: पैगी व्हिटसन (पूर्व NASA अंतरिक्ष यात्री)
- मिशन विशेषज्ञ: पोलैंड और हंगरी से
- पायलट: शुभांशु शुक्ला (भारत)
- अवधि: लगभग 14 दिन
- प्रयोग: कुल 60 वैज्ञानिक प्रयोग, जिनमें 7 भारत में विकसित हैं (माइक्रोग्रैविटी, जैविक अध्ययन, पदार्थ विज्ञान आदि)

भारत के लिए क्या है महत्व?

- 1984 में राकेश शर्मा के बाद भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान
- पहली बार सरकारी समर्थन प्राप्त कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री ISS पर पहुँचा
- गगनयान मिशन के दृष्टिकोण से मील का पत्थर
- भारत को विश्व के अग्रणी अंतरिक्ष राष्ट्रों की पंक्ति में मजबूत करता है

तकनीकी देरी और अंतिम प्रक्षेपण

- शुरुआत में मौसम, तकनीकी समस्याओं और सुरक्षा कारणों से कई बार प्रक्षेपण में देरी हुई
- जून की शुरुआत में लिक्विड ऑक्सीजन लीकेज जैसी दिक्कतें सामने आईं
- समस्याओं के समाधान के बाद 25 जून को अंतिम प्रक्षेपण खिड़की खोली गई और सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ

अमृत के 10 वर्ष: शहरी भारत में बदलाव

25 जून 2025 को भारत सरकार ने 'अमृत मिशन' (AMRUT: Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) की 10वीं वर्षगांठ मनाई। 2015 में शुरू की गई यह प्रमुख योजना शहरी जीवन स्तर सुधारने के लिए पानी की आपूर्ति, सीवरेज नेटवर्क, हरित क्षेत्रों, और शहरी गतिशीलता को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। अमृत मिशन ने अब तक 2 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन, 1.5 करोड़ से ज्यादा सीवरेज कनेक्शन और ₹2.73 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

समाचार में क्यों?

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने 25 जून 2025 को अमृत और अमृत 2.0 की 10वीं वर्षगांठ पर अब तक की प्रमुख उपलब्धियां और शहरी क्षेत्रों में जल, स्वच्छता, जल निकासी और गतिशीलता में हुए बदलावों को प्रदर्शित किया।

अमृत मिशन के उद्देश्य

- हर शहरी घर तक नल जल आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन सुनिश्चित करना।
- हरित क्षेत्र और पार्क बनाना जिससे जीवन स्तर में सुधार हो।
- गैर-मोटर चालित परिवहन (साइकिल, पैदल पथ) को बढ़ावा देना और प्रदूषण कम करना।
- शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को सशक्त बनाना व क्षमता निर्माण।

2015-2025 की प्रमुख उपलब्धियां

जल आपूर्ति

- 2.03 करोड़ नल कनेक्शन दिए गए।
- ₹1.14 लाख करोड़ की लागत से 3,568 परियोजनाएं स्वीकृत (AMRUT 2.0)।
- 10,647 MLD जल शोधन संयंत्र क्षमता मंजूर।
- SCADA तकनीक द्वारा 1,487 परियोजनाओं में रीयल-टाइम निगरानी।

सीवरेज व सेप्टेज प्रबंधन

- 1.50 करोड़ सीवरेज कनेक्शन जोड़े गए।
- ₹67,607 करोड़ की लागत से 592 परियोजनाएं मंजूर (AMRUT 2.0)।
- 6,739 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STP) की क्षमता मंजूर।
- फीकल स्लज प्रबंधन (FSM) और विकेन्द्रीकृत नेटवर्क को बढ़ावा।

ऊर्जा दक्षता

- 99 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित।
- वार्षिक बचत: 666 करोड़ यूनिट बिजली व 46 लाख टन CO₂ उत्सर्जन में कमी।

हरित क्षेत्र और जल स्रोत

- बच्चों और बुजुर्गों के अनुकूल पार्क विकसित किए गए।
- 544 जलाशयों का पुनरुद्धार (9,511 एकड़ क्षेत्र)।
- 3,032 जलाशयों की स्वीकृति (AMRUT 2.0)।

शहरी गतिशीलता

- पैदल पथ, साइकिल ट्रैक, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (BRTS) की सुविधा।
- फेरी सेवा, फुटओवर ब्रिज और बहु-स्तरीय पार्किंग पर विशेष ध्यान।

वित्तपोषण और नवाचार

- 13 ULBs ने ₹4,984 करोड़ नगर निगम बॉन्ड्स के माध्यम से जुटाए।
- 90,000 से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया (प्लंबर, संयंत्र ऑपरेटर, अधिकारी)।
- "टेक्नोलॉजी सब-मिशन" के अंतर्गत 120 स्टार्टअप्स को सहायता।

अमृत 2.0 की विशेषताएं (लॉन्च: 1 अक्टूबर 2021)

- सभी शहरी स्थानीय निकायों को कवर करता है।
- हर घर जल और सीवरेज लक्ष्य।
- कुल राशि: ₹2.99 लाख करोड़ (₹76,760 करोड़ केंद्रांश)।
- जल पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, और "जल ही अमृत" जैसी स्थायी पहल।

केरल साहित्य अकादमी ने 2024 के साहित्य पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की

केरल साहित्य अकादमी, राज्य की प्रमुख साहित्यिक संस्था, ने 2024 के अपने साहित्यिक पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की है, जो मलयालम साहित्य में उभरती प्रतिभाओं और अनुभवी लेखकों दोनों को सम्मानित करते हैं। ये पुरस्कार उपन्यास और कविता से लेकर नाटक, जीवनी और अनुवाद तक की विधाओं में उत्कृष्टता का सम्मान करते हैं, जो केरल में साहित्यिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अकादमी की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं।

चर्चा में क्यों?

2024 केरल साहित्य अकादमी पुरस्कारों की आधिकारिक घोषणा 26 जून, 2025 को त्रिशूर में की गई, जिसमें मलयालम साहित्य के विभिन्न योगदानों को मान्यता दी गई। इन पुरस्कारों का सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है और इन्हें मलयालम लेखकों के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है।





प्रमुख साहित्यिक पुरस्कार:

- सर्वश्रेष्ठ उपन्यास:
- जी. आर. इंदुगोपन — "आणो"
- कविता:
- अनिता थंपी — "मुर्रिगा वाझा करिवेप्पु"
- लघु कहानी:
- वी. शिनिलाल — "गारीसप्पा अरुवि अथवा ओरु जलयात्रा"
- निबंध (सिबी कुमार स्मृति पुरस्कार):
- एम. स्वराज — "पूक्कलुडे पुस्तकम्"

फेलोशिप एवं आजीवन योगदान सम्मान:

- अकादमी फेलोशिप:
- के. वी. रामकृष्णन
- आजीवन साहित्यिक योगदान सम्मान:
- एल्लेचरी रामचंद्रन

अतिरिक्त छह लेखक जिन्हें आजीवन योगदान पुरस्कार मिला:

1. पी. के. एन. पणिक्कर
2. पय्यनूर कुन्हिरामन
3. एम. एम. नारायणन
4. टी. के. गंगाधरन
5. के. ई. एन.
6. मल्लिका यूनस

अन्य श्रेणियों में विजेता लेखक और कृतियाँ:

- नाटक:
- सशीधरन नाडुविल
- साहित्य समालोचना:
- जी. दिलीप
- वैज्ञानिक साहित्य:
- दीपक वी.
- जीवनी / आत्मकथा:
- डॉ. के. राजशेखरन नायर
- यात्रा-वृत्तांत:
- के. आर. अजयन्
- अनुवाद:
- चिंथु प्रकाश
- बाल साहित्य:
- ई. एन. शीजा
- हास्य लेखन:
- निरंजन

पुरस्कार विवरण:

- नियमित श्रेणियों के पुरस्कार:
- ₹25,000 की नकद राशि, शील्ड (plaque), और प्रमाणपत्र
- फेलोशिप और प्रमुख आजीवन योगदान पुरस्कार:
- ₹50,000 नकद, दो तोला स्वर्ण पदक, शॉल, प्रशस्ति पत्र और शील्ड
- अन्य आजीवन योगदान पुरस्कार:
- ₹30,000 नकद, शील्ड, शॉल और प्रमाणपत्र

विशेष सूचना:

इस वर्ष विलासिनी पुरस्कार (Vilasini Award) के लिए किसी भी लेखक का चयन नहीं किया गया।

एससीओ 2025 में भारत की सामरिक स्वायत्तता का प्रदर्शन

जून 2025 में चीन के क्रिंगदाओ में आयोजित SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में, भारत के रक्षा मंत्री ने उस संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया जिसमें पाहलगाम आतंकी हमले का कोई जिक्र नहीं था, जबकि पाकिस्तान में हुई जाफ़र एक्सप्रेस हाईजैकिंग की चर्चा की गई थी। यह भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति और रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाता है।

भारत की रणनीति और रुख

- आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं: भारत ने साफ संदेश दिया कि शांति और आतंक एक साथ नहीं चल सकते।
- चीन द्वारा तैयार मसौदे में केवल पाकिस्तान की घटना को महत्व दिया गया, भारत की संवेदनशीलता की अनदेखी की गई।
- LAC गतिरोध (2020) के बाद चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा थी—भारत ने दबाव के बावजूद सैद्धांतिक रुख अपनाया।
- चीन के SCO अध्यक्ष पद के चलते मसौदे से जानबूझकर भारत की चिंताओं को हटाया गया।

SCO: कुछ स्थायी तथ्य

- स्थापना: 2001 (शुरुआत: शंघाई फाइव, 1996)
- मुख्यालय: बीजिंग (RATS: ताशकंद)
- 2025 के सदस्य देश: भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, कज़ाख़स्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान
- मुख्य उद्देश्य:
 - o आतंकवाद के खिलाफ सहयोग
 - o क्षेत्रीय सुरक्षा
 - o आर्थिक एकीकरण

RATS (क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी ढांचा)

- 2011-2015 में 20 आतंकी हमलों को रोक
- आतंकवादी तत्वों की गिरफ्तारी में मदद
- लेकिन भारत के अनुसार, "चयनात्मक आतंकवाद विरोध" से इसकी विश्वसनीयता पर सवाल

चीन की भूमिका और भारत की प्रतिक्रिया

- चीन ने SCO अध्यक्ष के रूप में मसौदे से भारत के आतंकवाद संबंधित मुद्दे (पाहलगाम हमला) को हटाया।
- अधिकांश सदस्य चीन के Belt and Road Initiative (BRI) का समर्थन करते हैं—भारत इसका विरोधी रहा है।
- भारत ने SCO 2023 में BRI और BRICS मुद्रा टोकरी प्रस्ताव का भी विरोध किया था।

भारत की रणनीतिक स्वायत्तता

- भारत कोई स्थायी गठबंधन नहीं बनाता, लेकिन Quad, SCO, BRICS, G20 जैसी संस्थाओं में भाग लेता है।
- भारत की विदेश नीति का मूलमंत्र:
- 🏠 अधिकतम सहभागिता, न्यूनतम उलझाव





- SCO भारत के लिए ज़रूरी है:
 - o मध्य एशिया तक बाज़ार और ऊर्जा की पहुँच
 - o आतंकवाद विरोधी रणनीतिक सहयोग

भविष्य की रणनीति

भारत आगे भी:

- चयनात्मक भागीदारी अपनाएगा (RATS जैसे कार्यशील क्षेत्र)
- सिद्धांत आधारित नीति पर डटा रहेगा
- दो-तरफा विवादों के चलते बहुपक्षीय मंचों पर सतर्क रहेगा
- आतंकवाद पर स्पष्ट परिभाषा और निष्पक्ष रुख की मांग करता रहेगा

कैबिनेट की मंजूरी

- कैबिनेट ने दो रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी: कैबिनेट ने ₹6,405 करोड़ की लागत वाली दो मल्टीट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है- झारखंड में कोडरमा-बरकाकाना (133 किमी) और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी-चिकजाजुर (185 किमी)- जो रेल नेटवर्क में 318 किमी की वृद्धि करेंगी। इससे यात्रा आसान होगी, लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी, CO₂ उत्सर्जन (264 करोड़ किलोग्राम) और तेल आयात (52 करोड़ लीटर) में कमी आएगी। ये परियोजनाएं 7 जिलों को कवर करती हैं, 1,408 गांवों (जनसंख्या ~28.19 लाख) को लाभ पहुंचाती हैं और 108 लाख मानव-दिवस रोजगार पैदा करती हैं। ये रणनीतिक परियोजनाएं पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के साथ संरेखित हैं।
- कैबिनेट ने आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर श्रद्धांजलि दी: आपातकाल (1975-77) के 50 वर्ष पूरे होने पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो मिनट का मौन रखकर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का विरोध करने वालों को श्रद्धांजलि दी। प्रस्ताव में संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक लचीलेपन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई, तथा संविधान और संघीय भावना की रक्षा के लिए नए सिरे से प्रयास करने का आह्वान किया गया।
- कैबिनेट ने आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र को मंजूरी दी: खाद्य सुरक्षा, किसानों की आय और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (सीआईपी) का एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह उच्च उपज देने वाली, जलवायु-अनुकूल आलू और शकरकंद की किस्मों का विकास करेगा और भारत और दक्षिण एशिया में कटाई के बाद और मूल्य श्रृंखला प्रणालियों में सुधार करेगा।
- पुणे मेट्रो रेल फेज-2 को मंजूरी: कैबिनेट ने पुणे मेट्रो फेज-2 कॉरिडोर 2ए (वनाज-चांदनी चौक) और 2बी (रामवाडी-वाघोली) को मंजूरी दे दी है, जो 12.75 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और 13 स्टेशन बनाएगा, जिसकी लागत ₹3,626.24 करोड़ होगी। ये विस्तार प्रमुख आईटी हब और उपनगरों को जोड़ेंगे, प्रमुख सड़कों पर यातायात को आसान बनाएंगे, अन्य मेट्रो लाइनों के साथ एकीकृत करेंगे और 2057 तक प्रतिदिन 3.49 लाख यात्रियों को बढ़ाएंगे।
- संशोधित झरिया मास्टर प्लान को मंजूरी: झरिया कोलफील्ड में आग, भूस्खलन और पुनर्वास से निपटने के लिए ₹5,940.47 करोड़ की संशोधित योजना को मंजूरी दी गई है। इसमें संवेदनशील स्थलों से पुनर्वास, ₹1 लाख का आजीविका अनुदान, ₹3 लाख तक का ऋण और सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और अस्पतालों का विकास शामिल है। एक समर्पित कोष और कौशल प्रशिक्षण से प्रभावित परिवारों के लिए स्थायी आजीविका सुनिश्चित होगी।

संसद समाचार

राज्यवार अक्टूबर माह की महत्वपूर्ण घटनाएँ

आंध्र प्रदेश

- गूगल ने 18 जून, 2025 को हैदराबाद में अपने पहले एशिया-प्रशांत सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र (GSEC) का उद्घाटन किया, जिससे वैश्विक साइबर सुरक्षा और जिम्मेदार AI विकास में भारत की भूमिका मजबूत हुई। सीएम ए रेवंत रेड्डी द्वारा उद्घाटन किया गया यह केंद्र ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटेगा, बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और वास्तविक समय में घोटाले की चेतावनी और सिंथआईडी वॉटरमार्किंग जैसे AI-संचालित सुरक्षा समाधान विकसित करेगा। 2007 से हैदराबाद में अपने संचालन के साथ, गूगल ने उपयोगकर्ता सुरक्षा, रोजगार सृजन और कौशल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। यह लॉन्च भारत की AI परिवर्तन रणनीति और 2035 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के तेलंगाना के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

असम

- असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने लैंगिक समावेशन और जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण के उद्देश्य से दो ऐतिहासिक सुधारों की घोषणा की है। ट्रांसजेंडर समुदाय को अब अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा, जिससे उन्हें शिक्षा, नौकरी और कल्याणकारी लाभों तक पहुँच प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण और बाल देखभाल में उनके योगदान को मान्यता देते हुए एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) के भीतर पर्यवेक्षक स्तर के पदों पर 50% आरक्षण मिलेगा। गुवाहाटी में एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान अनावरण की गई ये पहल असम की कल्याण और भर्ती नीति में एक प्रगतिशील बदलाव को दर्शाती हैं।

बिहार

- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले की बिक्रम लॉक नहर के किनारे 2 मेगावाट की नहर-बैंक सौर परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना बिहार सरकार की जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत हरित और सतत ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। खास बात यह है कि यह परियोजना राज्य सरकार पर किसी वित्तीय बोझ के बिना, निजी भागीदारी से विकसित की गई है। आगामी 25 वर्षों तक यह संयंत्र ₹3.10 प्रति यूनिट की दर से बिजली आपूर्ति करेगा। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण को बल मिलेगा और राज्य में इस प्रकार की अन्य परियोजनाओं के लिए एक प्रेरणास्रोत बनेगा।
- बिहार राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की है, जिससे बिहार ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह नई प्रणाली 28 जून को होने वाले नगर निकाय चुनावों में लागू की जाएगी, जिसकी पुष्टि राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने की है।





- बिहार सरकार ने सीतामढ़ी जिले में देवी सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर के निर्माण और पुनर्विकास के लिए बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय न्यास का गठन किया। राज्य सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (आईपीआरडी) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर पुनौरा धाम में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। यह पहल उस क्षेत्र को एक प्रमुख आध्यात्मिक और पर्यटन स्थल में बदलने के उद्देश्य से की गई है, जिसे पारंपरिक रूप से सीता माता का जन्मस्थान माना जाता है। यह परियोजना अयोध्या में बने श्रीराम मंदिर की तर्ज पर तैयार की जा रही है।
- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार, 22 जून 2025 को वृद्धजन, विधवाओं और दिव्यांग लाभार्थियों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को ₹400 से बढ़ाकर ₹1,100 प्रति माह करने की घोषणा की। यह बड़ोदरी अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले की गई है और इसे मतदाताओं का समर्थन सुनिश्चित करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। यह 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार इतनी बड़ी पेंशन वृद्धि है।

गुजरात

- कर्नाटक उच्च न्यायालय से स्थानांतरित होने के बाद न्यायमूर्ति नेरनहल्ली श्रीनिवासन संजय गौड़ा ने 9 जून, 2025 को गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में आधिकारिक रूप से कार्यभार संभाला। वडोदरा में एक समारोह के दौरान मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल ने उन्हें शपथ दिलाई। 58 वर्षीय न्यायमूर्ति गौड़ा का 1989 से एक प्रतिष्ठित कानूनी करियर रहा है और उन्हें 2021 में कर्नाटक में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उनका स्थानांतरण विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनुभवी न्यायाधीशों को पुनर्वितरित करके विविधता और न्यायिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की पहल का हिस्सा है।

हिमाचल प्रदेश

- केंद्र सरकार ने हिमाचल को 2,006.40 करोड़ रुपये एक साथ मंजूर कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में आपदा के बाद की स्थिति से निपटने के प्रयासों में सहायता करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्र सरकार ने 2023 के मानसून के दौरान विनाशकारी बाढ़, भूस्खलन और बाढ़ फटने की घटनाओं के मद्देनजर पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए ₹2,006.40 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने हिमाचल की पुनर्वास व पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। जुलाई 2023 में बाढ़, भूस्खलन एवं बाढ़ फटने की घटनाओं से हिमाचल को जानमाल का भारी नुकसान हुआ था।

कर्नाटक

- कर्नाटक ने COTPA (कर्नाटक संशोधन) अधिनियम, 2024 को लागू करके अपने तंबाकू नियमों को कड़ा कर दिया है, जिसके तहत तंबाकू खरीदने की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है, पूरे राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है और सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करने पर जुर्माना बढ़ाकर ₹1,000 कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 47

का हवाला देते हुए प्रतिबंध को बरकरार रखा। इन सुधारों का उद्देश्य तंबाकू की लत को कम करना और पूरे राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों में सुधार करना है।

- कर्नाटक मंत्रिमंडल ने राज्य आवास योजनाओं के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए 15% आवास आरक्षण को मंजूरी दे दी है, जो पहले 10% था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीसीएम डीके शिवकुमार ने इस कदम का बचाव करते हुए इसे अल्पसंख्यकों के लिए आवास की कमी को दूर करने और खाली घरों की संख्या को कम करने के उद्देश्य से एक सामाजिक कल्याण उपाय बताया। हालांकि, भाजपा ने इस फैसले की आलोचना वोट बैंक की राजनीति के रूप में की और इसे असंवैधानिक करार दिया। मंत्रिमंडल ने आम किसानों को मुआवजा देने, नंदी हिल्स में कैबिनेट बैठक का आयोजन करने और अप्सराकोंडा-मुगली को एक नया समुद्री वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के बारे में भी निर्णय लिए।

केरल

- केरल को राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों (Protected Areas - PAs) के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (Management Effectiveness Evaluation - MEE) 2020-2025 चक्र में भारत का सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। यह मूल्यांकन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया। केरल को 76.22% स्कोर मिला और यह एकमात्र राज्य है जिसे "बहुत अच्छा" (Very Good) रेटिंग प्राप्त हुई है।
- जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केरल अब भारत के पहले तितली अभयारण्य का घर बन गया है। कन्नूर जिले में स्थित अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अब "अरलम तितली अभयारण्य" रख दिया गया है। यह देश में अपनी तरह की पहली पहल है, जो पश्चिमी घाट की हरियाली में फैले 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यहां 266 से अधिक तितली प्रजातियों को संरक्षित किया गया है, जिनमें कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियाँ भी शामिल हैं।

महाराष्ट्र

- पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सभी अवसंरचना विकास परियोजनाओं को एक भू-टैग युक्त 13-अंकीय अल्फान्यूमेरिक यूनिफाइड आईडी (Infra ID) से चिन्हित करना अनिवार्य कर दिया है। यह आईडी प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद परियोजना की प्राथमिक पहचान के रूप में कार्य करेगी। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल एकरूपता लाना, दोहराव को रोकना और विभिन्न विभागों में परियोजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी को सक्षम बनाना है। Infra ID पोर्टल के माध्यम से यह प्रणाली संचालित होगी, और लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक पिछले पांच वर्षों में स्वीकृत सभी परियोजनाएं इस पोर्टल पर पंजीकृत हो जाएं।
- महाराष्ट्र सरकार ने एक नया सरकारी आदेश जारी करते हुए कहा है कि राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को "आम तौर पर" तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। यह आदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप राज्य पाठ्यचर्या ढाँचा (State Curriculum Framework for School Education) 2024 के तहत लागू किया गया है।





मिजोरम

- स्काइन लीडर मनीषा पाधी भारतीय इतिहास में राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला एड-डी-कैप (ADC) बन गई हैं, जो भारतीय सशस्त्र बलों में एक महत्वपूर्ण क्षण है। मिजोरम के राज्यपाल के पद पर नियुक्त, यह ऐतिहासिक पदस्थापना सैन्य औपचारिक भूमिकाओं में लैंगिक समावेशिता के प्रति भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कई वायु सेना स्टेशनों में पिछले अनुभव के साथ, पाधी की उपलब्धि उच्च रैंकिंग, प्रतिष्ठित पदों पर सेवा करने की इच्छुक महिला अधिकारियों के लिए एक नई मिसाल कायम करती है।
- शैक्षिक समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, त्रिपुरा को उल्लास - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है, जो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में 95% से अधिक साक्षरता प्राप्त करने में मिजोरम और गोवा के साथ शामिल हो गया है। इस सफलता का श्रेय मजबूत सामुदायिक भागीदारी, घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करने और उल्लास ऐप जैसे डिजिटल उपकरणों को जाता है। 2022 में शुरू की गई उल्लास योजना एनईपी 2020 के साथ संरेखित है और युवाओं और वयस्कों को बुनियादी कौशल और आजीवन सीखने के अवसरों के साथ सशक्त बनाकर विकसित भारत @2047 का समर्थन करती है।

मेघालय

- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (IICA) पीएम-डेविन योजना के तहत वित्त पोषण के साथ मेघालय के शिलांग में अपना पहला क्षेत्रीय परिसर स्थापित कर रहा है। ₹100.95 करोड़ के निवेश का उद्देश्य इस क्षेत्र को नीति और प्रशिक्षण केंद्र में बदलना है, जिससे कॉर्पोरेट प्रशासन, उद्यमिता और क्षमता निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। नॉलेज सिटी क्लस्टर के भीतर स्थित, नया परिसर पूर्वोत्तर क्षेत्र में समावेशी और विकेंद्रीकृत विकास के सरकार के दृष्टिकोण को पूरा करते हुए, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत @2047 जैसे राष्ट्रीय मिशनों का समर्थन करेगा।

मध्य प्रदेश

- स्कूल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक बड़े कदम के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई 2025 से सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों के लिए डिजिटल रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया है। यह 'हमारे शिक्षक' प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा, जो राज्य के शिक्षा 3.0 पोर्टल के साथ एकीकृत एक ई-गवर्नेंस टूल है।

ओडिशा

- 20 जून, 2025 को, प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में ₹2,750 करोड़ की लागत वाली कई रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जो क्षेत्रीय संपर्क और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सोनपुर-पुरुनकटक रेल लाइन के उद्घाटन ने बौध जिले को पहली बार भारत के रेल नेटवर्क से जोड़ा। अन्य मुख्य आकर्षणों में माल दुलाई सुविधाएँ, सड़क ओवर ब्रिज और नई साप्ताहिक ट्रेन सेवाएँ शामिल हैं।

पंजाब

- फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए, पंजाब में वर्ष 2025 में कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2024 में जहाँ कपास की खेती 2.49 लाख एकड़ भूमि पर

की गई थी, वहीं 2025 में यह बढ़कर 2.98 लाख एकड़ तक पहुँच गई है — यानी करीब 49,000 एकड़ की बढ़ोतरी हुई है। फाजिल्का, मानसा, बठिंडा और श्री मुक्तसर साहिब जैसे जिले इस वृद्धि में अग्रणी हैं। राज्य सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी और डिजिटल पंजीकरण अभियान चला रही है।

तमिलनाडु

- विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून 2025) के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी (रामनाथपुरम जिला) को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया। यह अभयारण्य 524.7 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यह निर्णय मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन के साथ लिया गया। यह कदम दक्षिण भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण और जैव विविधता की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- तमिलनाडु सरकार ने मध्य एशियाई फ्लाईवे के साथ प्रवासी पक्षियों, विशेष रूप से ग्रेटर और लेसर फ्लेमिंगो की रक्षा के लिए धनुषकोडी को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया। 524.7 हेक्टेयर में फैले इस अभयारण्य में मैंग्रोव, मडफ्लैट और दलदल शामिल हैं, जो मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी के भीतर एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। 128 प्रजातियों के 10,700 से अधिक पक्षियों के साथ, यह अभयारण्य आर्द्रभूमि संरक्षण, इकोटूरिज्म और जलवायु लचीलेपन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कदम का उद्घाटन मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के दौरान किया।
- प्रयोग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च ने एसबीआई फाउंडेशन और एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के साथ मिलकर 17 जून, 2025 को रायचूर जिले के 12 सरकारी स्कूलों में क्रिया कार्यक्रम शुरू किया। एनईपी 2020 के साथ मिलकर, इस पहल का उद्देश्य कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों को अनुभववात्मक विज्ञान शिक्षा प्रदान करना है, जिससे आलोचनात्मक सोच और खोज-आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिले। कर्नाटक में पहले से ही 11,000 से अधिक छात्रों को प्रभावित करने वाला यह कार्यक्रम, मापनीय, शोध-समर्थित तरीकों के माध्यम से ग्रामीण STEM शिक्षा को बदलने के प्रयोग के मिशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

उत्तर प्रदेश

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जून 2025 को आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जो उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह 91.35 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे ₹7,283 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार हुआ है और राज्य सरकार के उस विज्ञान का हिस्सा है, जिसमें उत्तर प्रदेश को 'एक्सप्रेसवे स्टेट' के रूप में स्थापित करने और क्षेत्रीय संपर्क, निवेश और औद्योगिक विकास को गति देने का लक्ष्य है।
- उत्तर प्रदेश ने डिजिटल सार्वजनिक खरीद में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जिसने वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 2025 के बीच सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर कुल ₹65,227.68 करोड़ मूल्य के ऑर्डर दर्ज किए हैं। अकेले वित्त वर्ष 2024-25 में, राज्य ने ₹5.43 लाख करोड़ मूल्य के 72 लाख ऑर्डर संसाधित किए, जो ई-गवर्नेंस, पारदर्शिता और कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नवंबर 2024 के सुधारों ने, GFR 2017 के साथ संरेखित करते हुए, 100% GeM को अपनाने में सक्षम बनाया, जो डिजिटल इंडिया पहल के तहत अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण स्थापित करता है।





- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जून 2025 को आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जो उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह 91.35 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे ₹7,283 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार हुआ है और राज्य सरकार के उस विज्ञान का हिस्सा है, जिसमें उत्तर प्रदेश को 'एक्सप्रेसवे स्टेट' के रूप में स्थापित करने और क्षेत्रीय संपर्क, निवेश और औद्योगिक विकास को गति देने का लक्ष्य है।
- उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है, जिसमें इसके 1.4 अरब साल पुराने स्ट्रोमेटोलाइट और शैवाल जीवाश्मों को मान्यता दी गई है - जो पृथ्वी पर जीवन के सबसे पुराने ज्ञात साक्ष्यों में से कुछ हैं। पार्क के नामांकन को बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेज द्वारा किए गए वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा समर्थित किया गया था और इसे सीएम योगी आदित्यनाथ के तहत यूपी इको-टूरिज्म बोर्ड द्वारा समर्थित किया गया है। इस कदम से राज्य की इको-टूरिज्म क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने, अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलने और वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान मिलने की उम्मीद है।

पश्चिम बंगाल

- कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक 15 वर्षीय लड़के को अपने सौतेले पिता का उपनाम अपनाने की अनुमति दी है, जो संरक्षक माता-पिता के अधिकारों को बरकरार रखता है और आधुनिक पारिवारिक गतिशीलता को मान्यता देता है। हालाँकि कोलकाता नगर निगम (केएमसी) ने इस बदलाव का विरोध किया, लेकिन अदालत ने फैसला सुनाया कि उपनाम कोलकाता नगर निगम अधिनियम की धारा 454 के दायरे में आता है, जो नाम में बदलाव की अनुमति देता है। हालाँकि, अदालत ने कानूनी गोद लेने के आदेश की कमी के कारण जैविक पिता का नाम बदलने की याचिका को अस्वीकार कर दिया। न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने इस बात पर जोर दिया कि परिस्थितियों के अनुसार वैधानिक समय सीमा की लचीले ढंग से व्याख्या की जा सकती है।
- कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में केंद्र को पश्चिम बंगाल में 1 अगस्त, 2025 से मनरेगा के संचालन को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। कथित अनियमितताओं के कारण तीन साल तक इसे स्थगित रखा गया था। न्यायालय ने 25 मिलियन से अधिक ग्रामीण श्रमिकों को काम के अवसर बहाल करते हुए, आजीविका के भविष्य के अधिकार से अतीत के कदाचार को अलग करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस योजना के पुनरुद्धार को नागरिक अधिकारों की जीत के रूप में देखा जा रहा है, अधिवक्ताओं ने इसे भारत के प्रमुख सामाजिक कल्याण कार्यक्रम में ग्रामीण रोजगार, आर्थिक न्याय और सार्वजनिक जवाबदेही के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में सराहा है।

केंद्र शासित प्रदेश

- केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन प्रमुख विनियमों को 3 जून 2025 को अधिसूचित किया है। ये विनियम स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण, भाषा की मान्यता, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। यह कदम लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने, स्थानीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और समावेशी शासन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी पहल है।

- 9 जून, 2025 को पुडुचेरी भारत में 19वीं विधानसभा बन गई, जिसने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) को अपनाया, जो कागज रहित विधायी कामकाज के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने किया। यह पहल डिजिटल इंडिया विजन का समर्थन करती है, जो 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ वास्तविक समय की विधायी पारदर्शिता, लाइवस्ट्रीमिंग और कागज की बचत को सक्षम बनाती है। नेवा "एक राष्ट्र, एक एप्लीकेशन" की ओर एक कदम है, जो पर्यावरण के अनुकूल शासन, नागरिक पहुंच और संस्थागत दक्षता को आगे बढ़ाता है।
- दिल्ली सरकार जून 2025 के अंत तक क्लाउड-सीडिंग परीक्षण शुरू करने जा रही है, जो प्रदूषण और पानी की कमी से निपटने के लिए मौसम संशोधन तकनीक में एक महत्वपूर्ण कदम है। 3.21 करोड़ रुपये की पायलट परियोजना, जिसमें सिल्वर आयोडाइड और लवण जैसे सीडिंग एजेंटों के साथ पाँच हवाई परीक्षण शामिल हैं, आईआईटी कानपुर, आईएमडी और कई राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से संचालित की जा रही है। परीक्षण शहर में प्रतिबंधित वायु क्षेत्रों से बचते हुए वर्षा प्रेरण दक्षता और पर्यावरण सुरक्षा का आकलन करेंगे।

जून माह के शुभारंभ और उद्घाटन:

- भारत सरकार ने आयात शुल्क में छूट देकर और स्थानीय विनिर्माण को समर्थन देकर घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के विकास में तेजी लाने के लिए SPMEPCI योजना शुरू की है। ब्राउनफील्ड निवेश की अनुमति देकर और रोलओवर प्रावधानों के साथ आयात को सीमित करके, सरकार का लक्ष्य प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों को आकर्षित करना और भारत के स्वच्छ गतिशीलता एजेंडे को बढ़ावा देना है। हालांकि, केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने पुष्टि की कि टेस्ला भारत में कारों का निर्माण करने की योजना नहीं बना रही है, जिससे ईवी क्षेत्र में विदेशी निवेश हासिल करने की चुनौती को रेखांकित किया जा सके।
- भारत के डाक विभाग द्वारा शुरू की गई ध्रुवा नीति, एक राष्ट्रव्यापी, जियो-कोडेड डिजिटल एड्रेस सिस्टम पेश करती है, जिसे एड्रेस डेटा के उपयोग, भंडारण और साझा करने के तरीके को आधुनिक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पते की जानकारी को मूलभूत सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में मान्यता देते हुए, ध्रुवा सुरक्षित, मानकीकृत और सहमति-आधारित पता प्रबंधन सुनिश्चित करता है। यह शासन से लेकर रसद तक के क्षेत्रों को लाभ पहुँचाने के लिए एड्रेस-एज़-ए-सर्विस (AaaS) मॉडल का लाभ उठाता है। इस डिजिटल दृष्टिकोण को एकीकृत करके, भारत समावेशी विकास, उपयोगकर्ता गोपनीयता और सेवा नवाचार का समर्थन करने के लिए अपने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करता है।
- अमित शाह ने 6 जून, 2025 को प्रशासनिक और शासन प्रक्रियाओं में भारतीय भाषाओं को एकीकृत करने के लिए भारतीय भाषा अनुभाग (बीबीए) का उद्घाटन किया, जिससे अंग्रेजी का प्रभुत्व कम हो सके। ₹56 करोड़ के वित्तपोषण और सी-डैक द्वारा समर्थित यह प्लेटफॉर्म वास्तविक समय में अनुवाद सुनिश्चित करेगा और मातृभाषाओं में संचार की अनुमति देगा, खासकर क्षेत्र सी राज्यों के साथ। यह पहल एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप है और भाषाई समावेशिता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है।





- भारत के चुनाव आयोग ने इंडेक्स कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट के निर्माण को स्वचालित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणाली शुरू की है, जो पहले के मैनुअल तरीकों की जगह लेगी। सीईसी ज्ञानेश कुमार के मार्गदर्शन में यह बदलाव, चुनाव के बाद डेटा प्रसार में काफी तेजी लाएगा, जिससे चुनावी जनसांख्यिकी, मतदान पैटर्न और पार्टी के प्रदर्शन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई यह पहल भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ पारदर्शिता, डेटा की सुलभता और अकादमिक जुड़ाव को मजबूत करती है।
- विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 'एक पेड़ माँ के नाम 2.0' अभियान की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य 30 सितंबर तक पूरे भारत में 10 करोड़ पेड़ लगाना है। यह पहल, पर्यावरण चेतना को सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जोड़ती है, व्यक्तियों को अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री ने स्वच्छ शहरी परिवहन को बढ़ावा देने और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राजधानी में 200 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। ये कार्य सतत विकास, जलवायु कार्रवाई और हरित गतिशीलता के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
- दिल्ली सरकार ने उत्तरी दिल्ली के होलंबी कला में भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (ई-कचरा) इको पार्क की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य एक परिपत्र अर्थव्यवस्था और टिकाऊ शहरी जीवन को बढ़ावा देना है, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने उन्नत हरित प्रौद्योगिकी साझेदारी के लिए वैश्विक निविदा जारी करने की योजना की पुष्टि की है।
- भारत सरकार ने आयुष निवेश सारथी पोर्टल लॉन्च किया है, जो आयुष मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य आयुष क्षेत्र में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करना और उनकी सहायता करना है - जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी शामिल हैं। यह पोर्टल निवेश नीतियाँ, परियोजना लिस्टिंग, लाभ और वास्तविक समय सहायता प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य एफडीआई को बढ़ावा देना, स्टार्टअप का समर्थन करना और 2014 और 2020 के बीच इस क्षेत्र की 17% वार्षिक वृद्धि का लाभ उठाना है।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण और रखरखाव परियोजनाओं पर काम करने वाली कंसल्टेंसी फर्मों के लिए प्रति इंजीनियर 10 परियोजनाओं की सीमा तय की है। इस कदम का उद्देश्य पर्यवेक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना, इंजीनियरों पर अत्यधिक बोझ को रोकना और HAM और EPC जैसे परियोजना मोड के तहत अनुबंध अनुपालन सुनिश्चित करना है। 60 दिनों के बाद प्रभावी होने वाले इस नियम के तहत मासिक साइट विज़िट और प्रगति रिपोर्ट में इनपुट देना अनिवार्य है, जिससे भारत के राजमार्ग बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
- जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया धरती आवा जनभागीदारी अभियान भारत का सबसे बड़ा आदिवासी सशक्तिकरण अभियान है, जो 549 से अधिक आदिवासी जिलों, 2,900+ ब्लॉकों और 1 लाख गांवों को कवर करता है। यह अभियान आधार नामांकन, आयुष्मान भारत कार्ड, पीएम-किसान पंजीकरण, जन धन खाते, पेंशन और कौशल विकास जैसी प्रमुख सेवाओं को आदिवासी परिवारों के दरवाजे पर पहुंचाकर लाभ संतुष्टि सुनिश्चित करता है। जनजातीय गौरव वर्ष के हिस्से के रूप में कार्यान्वित और पीएम-जनमन और डीएजेजीयूए जैसे कार्यक्रमों द्वारा समर्थित यह पहल समावेशी शासन और अंतिम-मिल वितरण में एक बड़ा कदम है।
- मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने मानेसर प्लांट में भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इन-प्लांट रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया है, जो ग्रीन लॉजिस्टिक्स की दिशा में एक बड़ा कदम है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के अनुरूप, ₹452 करोड़ की यह सुविधा 126 किलोमीटर लंबे हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का हिस्सा है। यह सालाना 4.5 लाख वाहनों को डिस्पैच करेगा, 1.75 लाख टन CO₂ उत्सर्जन में कटौती करेगा और हर साल 60 मिलियन लीटर ईंधन की बचत करेगा। इसके साथ, MSIL का लक्ष्य वित्त वर्ष 2030-31 तक रेल-आधारित डिस्पैच को 35% तक बढ़ाना है, जो 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन अर्थव्यवस्था के भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।
- भारत सरकार ने 15 अगस्त, 2025 से कार, जीप और वैन जैसे निजी वाहनों के लिए ₹3,000 का फास्टैग वार्षिक पास शुरू किया है। एक वर्ष या 200 ट्रिप के लिए वैध, इस पहल का उद्देश्य टोल से संबंधित विवादों को कम करना है, खासकर जहाँ प्लाजा एक-दूसरे से बहुत कम दूरी पर हैं, और डिजिटल-फर्स्ट टोलिंग सिस्टम को प्रोत्साहित करना है। इस पास को राजमार्ग यात्रा ऐप या आधिकारिक NHAI/MoRTH प्लेटफॉर्म के माध्यम से सक्रिय किया जा सकता है, जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक किफायती, परेशानी मुक्त यात्रा अनुभव प्रदान करता है।
- भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने 18 जून, 2025 को, मतदाता सूची अपडेट के 15 दिनों के भीतर मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) वितरित करने के लिए एक नया SOP पेश किया। ECINet प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित और डाक विभाग के साथ एकीकृत, यह प्रणाली मतदाताओं को वास्तविक समय की ट्रैकिंग और SMS सूचनाएँ प्रदान करती है। इस तकनीक-संचालित कदम का उद्देश्य मतदाता सुविधा में सुधार करना, समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना और भारत की चुनावी सेवाओं में डिजिटल पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।
- विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर, एम्स मंगलगिरी ने 19 जून, 2025 को स्वास्थ्य और आदिवासी कल्याण विभागों के सहयोग से एक जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में छात्रों, आदिवासी सदस्यों और चिकित्सा पेशेवरों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना था, जो एक वंशानुगत रक्त विकार है जो भारत में आदिवासी आबादी को असमान रूप से प्रभावित करता है।
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने "प्रतिभा सेतु" नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो नियोक्ताओं को उन गैर-अनुशंसित उम्मीदवारों के विवरण तक पहुँचने की अनुमति देता है, जिन्होंने UPSC परीक्षा के सभी चरणों को पास कर लिया है, लेकिन अंतिम मेरिट सूची में नहीं थे। यह कदम शीर्ष स्तर के उम्मीदवारों को करियर के विकल्प प्रदान करता है और सरकार द्वारा चयनित प्रतिभा और निजी क्षेत्र की मांग के बीच इंटरफेस को मजबूत करता है। सत्यापित भर्तीकर्ताओं के लिए सुरक्षित लॉगिन एक्सेस और उम्मीदवारों की ऑफ्ट-इन भागीदारी के साथ, प्रतिभा सेतु एक दूरदर्शी रोजगार सुधार पहल का प्रतिनिधित्व करता है।
- भुवनेश्वर की अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून, 2025 को ₹18,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, नई रेल और बस सेवाओं को हरी झंडी दिखाई और 2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखते हुए ओडिशा विज्ञान डॉक्यूमेंट लॉन्च किया। सांस्कृतिक पुनरुत्थान, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास पर ज़ोर देते हुए, पीएम ने बारापुत्र ऐतिहास्य ग्राम योजना की भी शुरुआत की और SHG पहल के तहत लखपति दीदियों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम ने ओडिशा में समग्र, समावेशी प्रगति के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत दिया।





- अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 20 जून, 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय परामर्श के दौरान जेंडर बजटिंग नॉलेज हब लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म जेंडर बजटिंग संसाधनों के लिए एक डिजिटल रिपोजिटरी के रूप में कार्य करेगा, जिससे मंत्रालयों, राज्यों और नीति निर्माताओं को योजना और बजट में लैंगिक समानता को एकीकृत करने में सहायता मिलेगी। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र का आवंटन ₹4.49 लाख करोड़ है, जो 2014-15 से 4.5 गुना अधिक है। परामर्श में भारत में 20 वर्षों के जेंडर बजटिंग की समीक्षा की गई और समावेशी राजकोषीय शासन को और मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण मैनुअल और क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियों का प्रस्ताव दिया गया।
- आयुष मंत्रालय की पहल योग संगम 2025, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) के परिवर्तनकारी उत्सव को चिह्नित करता है, जिसका विषय है "श्वास के माध्यम से एकता"। यह राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम स्कूलों, कार्यालयों, गांवों और महानगरों सहित एक लाख से अधिक स्थानों पर भागीदारी को संगठित करेगा, जो स्वास्थ्य और सद्भाव के लिए एक सामूहिक आंदोलन का प्रतीक है। समन्वित श्वास और सामुदायिक जुड़ाव पर जोर देते हुए, यह योग को एक कल्याणकारी अभ्यास और राष्ट्रीय एकीकरणकर्ता दोनों के रूप में पुनर्परिभाषित करता है।
- शैक्षणिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, आईआईटी-दिल्ली ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों के लिए एक विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है। यह पहल, जो 30 जून, 2025 तक चलेगी, डॉक्टरेट स्तर पर आरक्षित सीटों की लगातार कमी को संबोधित करती है, जैसा कि एक संसदीय समिति को पता चला है। पात्रता मानदंडों में ढील के बावजूद, संस्थान को कम आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिससे अतिरिक्त प्रवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग-व्यापी बदलाव किए गए हैं।
- भारत के इतिहास में सबसे बड़ा आदिवासी सशक्तिकरण अभियान, जिसका लक्ष्य 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 5.5 करोड़ से अधिक आदिवासी नागरिकों तक पहुंचना है। बिरसा मुंडा के नाम पर शुरू की गई यह पहल आदिवासी विरासत का सम्मान करते हुए पीएम मोदी के समावेशी शासन के दृष्टिकोण को पूरा करती है। केवल नौ दिनों में, DAJA ने 1.68 लाख आयुष्मान कार्ड, 1.38 लाख आधार नामांकन और 22,000+ उज्ज्वला योजना कनेक्शन सक्षम किए।

Important Festival

- बोनालु उत्सव 2025 हैदराबाद के गोलकुंडा किले में बड़े उत्साह और परंपरा के साथ शुरू हुआ, जहाँ भक्त श्री जगदम्बा महाकाली मंदिर में बोनाम चढ़ाने और सदियों पुराने अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए एकत्र हुए। तेलंगाना सरकार ने 2,783 मंदिरों के लिए ₹20 करोड़ के फंड के साथ इस आयोजन का सक्रिय रूप से समर्थन किया, जबकि प्रमुख राजनीतिक नेताओं और हजारों भक्तों ने क्षेत्र की लोक विरासत का जश्न मनाया। यह उत्सव आने वाले हफ्तों में सिकंदराबाद और पुराने शहर में जारी रहेगा, जो तेलंगाना के गहरे सांस्कृतिक गौरव को दर्शाता है।
- असम के कामाख्या मंदिर में आयोजित अंबुबाची मेला 2025, 22 जून से 25 जून तक देवी कामाख्या के मासिक धर्म चक्र का स्मरण करता है, 26 जून को मंदिर के दरवाजे फिर से खुलते हैं भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति और सरकारी समर्थन के साथ, यह आयोजन आध्यात्मिक भक्ति और स्त्री शक्ति और गरिमा के बारे में सामाजिक संदेश दोनों को मजबूत करता है।

- जम्मू और कश्मीर के भद्रवाह में तीसरे लैवेंडर महोत्सव ने सीएसआईआर-अरोमा मिशन की बढ़ती सफलता को प्रदर्शित किया। 1-2 जून, 2025 तक आयोजित और 1,200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, इस कार्यक्रम में फील्ड विजिट, लाइव आसवन प्रदर्शन और किसानों और स्टार्टअप की सफलता की कहानियां शामिल थीं। लैवेंडर आधारित उत्पादों से ₹10.5 करोड़ से अधिक के कारोबार और 9,000 से अधिक प्रशिक्षित व्यक्तियों के साथ, महोत्सव ने लैवेंडर की खेती से प्रेरित सामाजिक-आर्थिक उत्थान, महिला उद्यमिता और औद्योगिक विकास को रेखांकित किया।
- श्रीलंका श्रद्धेय पोसन पोया त्योहार मना रहा है, राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने राष्ट्रीय एकता और नैतिक पुनरुत्थान पर जोर दिया, जबकि भारतीय उच्चायोग ने बौद्ध विरासत पर एक प्रदर्शनी के साथ इस अवसर पर भाग लिया। पवित्र सप्ताह के दौरान तीर्थयात्रियों की आवाजाही में निःशुल्क और विशेष रेल सेवाएं भी सहायता कर रही हैं। (लेख पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें)
- श्रीलंका में कटारगामा एसाला महोत्सव 2025 की शुरुआत ध्वजारोहण समारोह के साथ हुई, जिसमें विभिन्न धर्मों और क्षेत्रों के भक्तों का स्वागत किया गया। भगवान स्कंद को समर्पित महा देवला मंदिर के आसपास मनाया जाने वाला यह उत्सव अंतरधार्मिक परंपराओं का सम्मान करता है, जिसमें हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम सभी शामिल होते हैं। इस उत्सव का एक मुख्य पहलू पद यात्रा है, जो पैदल 500 किलोमीटर की तीर्थयात्रा है। प्रमुख कार्यक्रमों में 7 जुलाई को अग्नि-चलन समारोह और 10 जुलाई को भव्य महा परहेरा जुलूस शामिल हैं, जो उत्सव की आध्यात्मिक तीव्रता और सांस्कृतिक समृद्धि को उजागर करते हैं। (लेख पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें)

विविध राष्ट्रीय समाचार

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 जून, 2025 को नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग (बीबीए) का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य भारत के प्रशासनिक कामकाज में विदेशी भाषाओं, खासकर अंग्रेजी के प्रभुत्व को कम करना और निर्णय लेने और आधिकारिक संचार में मातृभाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। यह कदम भाषाई समावेशन के दृष्टिकोण के अनुरूप है और भारत की भाषाई विविधता के माध्यम से एकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 5 जून 2025 को घोषणा की कि मई 2025 में 211 करोड़ से अधिक आधार प्रमाणीकरण लेनदेन किए गए, जो पिछले महीने (अप्रैल 2025) और मई 2024 (201.76 करोड़) की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। इस वृद्धि से यह स्पष्ट होता है कि आधार डिजिटल गवर्नेंस और कल्याणकारी योजनाओं में एक मजबूत आधार बना हुआ है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को जम्मू-कश्मीर में विश्व के सबसे ऊँचे रेलवे आर्च पुल — चेनाब रेल पुल — का उद्घाटन किया। यह ऐतिहासिक अवसर उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक (USBRL) परियोजना की पूर्णता को चिह्नित करता है, जो 42 वर्षों से निर्माणाधीन थी और जिसका उद्देश्य कश्मीर घाटी को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ना था। यह पुल एक पूरी तरह से विद्युतीकृत 272 किलोमीटर लंबे रेल गलियारे का हिस्सा है और हिमालय की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को पार करते हुए इस क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और आर्थिक विकास के नए रास्ते खोलता है।





- चुनावी डेटा प्रसार में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने चुनाव के बाद इंडेक्स कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणाली लागू की है। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में, डॉ. सुखवीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ, ईसीआई की उन्नत प्रणाली समय लेने वाली मैन्युअल प्रक्रियाओं को स्वचालित डेटा एकीकरण उपकरणों से बदल देती है। इस सुधार से शोधकर्ताओं, पत्रकारों, नीति निर्माताओं और आम जनता के लिए चुनाव संबंधी जानकारी की गति, सटीकता और पहुँच में वृद्धि होने की उम्मीद है।
- भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने स्वच्छता पखवाड़ा 2025 को 1 मई से 15 मई 2025 तक सक्रिय रूप से मनाया। इस दौरान DBT मुख्यालय (नई दिल्ली), इसके स्वायत्त संस्थानों (AIs) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में कुल 188 गतिविधियाँ आयोजित की गईं। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छता, जन स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्थिरता और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना था।
- अर्बन अड्डा 2025 के दूसरे दिन (4 जून 2025) भारत के शहरी विकास संवाद के इस राष्ट्रीय मंच पर महिलाओं ने लैंगिक समावेशी शहरी डिज़ाइन की पुरज़ोर माँग उठाई। इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में नीति-निर्माताओं, कार्यकर्ताओं, उद्यमियों और शहरी विकास विशेषज्ञों ने भाग लिया और बताया कि किस प्रकार भारतीय शहरों में महिलाएं रोजाना असुरक्षित यात्रा, खराब लास्ट-माइल कनेक्टिविटी और भेदभावपूर्ण परिवहन नीतियों का सामना कर रही हैं।
- 16 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जो दो चरणों में की जाएगी और इसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। अधिकतर क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि (00:00 बजे) होगी, जबकि लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए यह तिथि 1 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। यह निर्णय COVID-19 महामारी के कारण 2021 में स्थगित की गई जनगणना प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- भारत के पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए, राजस्थान के दो आर्द्रभूमियों—खीचन (फालोदी) और मेणार (उदयपुर)—को अंतरराष्ट्रीय महत्व की रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया है। इस घोषणा के साथ भारत की कुल रामसर साइटों की संख्या बढ़कर 91 हो गई है। यह घोषणा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की पूर्व संध्या (4 जून 2025) को की गई, जो भारत की महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है।
- सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम के रूप में, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी ने कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) के एक नए वेब पोर्टल, C केयर्स वर्जन 2.0 को लॉन्च किया। एसबीआई के साथ साझेदारी में सी-डैक द्वारा विकसित इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य रियल-टाइम ट्रैकिंग, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और मोबाइल-आधारित पहुंच की शुरुआत करके कोयला श्रमिकों के लिए भविष्य निधि और पेंशन सेवाओं को सरल बनाना है। इस लॉन्च से कोयला क्षेत्र में

- पारदर्शिता, श्रमिक कल्याण और डिजिटल परिवर्तन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है।
- भारत सरकार ने घोषणा की है कि 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले कम से कम 10 साल की अर्हक सेवा के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत अतिरिक्त लाभ का दावा कर सकते हैं। इन बड़े हुए लाभों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2025 है। यह एनपीएस सेवानिवृत्त लोगों और उनके जीवनसाथी को पेंशन लाभों में वित्तीय सुरक्षा और समानता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप है।
- केंद्र सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (SPMEPCI) के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं। इस योजना का उद्देश्य रियायती सीमा शुल्क और ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड विनिर्माण निवेश दोनों के लिए समर्थन देकर वैश्विक EV निर्माताओं को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करना है। यह कदम उसी दिन उठाया गया है जब केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने खुलासा किया कि टेस्ला फिलहाल भारत में कारों के विनिर्माण में दिलचस्पी नहीं रखती है, बल्कि केवल शोरूम खोलने में दिलचस्पी रखती है।
- भारत सरकार ने अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी IREL (India Rare Earths Limited) को जापान के साथ 13 साल पुराने दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (Rare Earths) के निर्यात समझौते को निलंबित करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब चीन द्वारा इन तत्वों के निर्यात पर पाबंदी लगाने के बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अस्थिरता बढ़ गई है। भारत अब अपने संसाधनों की रक्षा करने, आयात पर निर्भरता (विशेष रूप से चीन पर) कम करने, और घरेलू मूल्यवर्धित रियर अर्थ उद्योग को विकसित करने की दिशा में कदम उठा रहा है।
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 जून 2025 को दक्षिण ब्लॉक, नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) के 10 युवा कैडेट्स (5 लड़कियाँ और 5 लड़के) को सम्मानित किया, जिन्होंने विश्व की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। इन कैडेट्स की औसत आयु 19 वर्ष थी। इस अवसर पर उनके साहस, अनुशासन, और अदम्य उत्साह की सराहना की गई।
- राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता निगरानी को मजबूत करने और कार्यान्वयन मानकों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने परामर्श इंजीनियरों द्वारा एक साथ देखे जाने वाले प्रोजेक्ट्स की संख्या को अधिकतम 10 तक सीमित कर दिया है। यह सीमा स्वतंत्र इंजीनियरों (Independent Engineers), प्राधिकरण इंजीनियरों (Authority Engineers), और सुपरविजन कंसल्टेंट्स पर लागू होगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि परियोजनाओं में तकनीकी और संविदात्मक अनुपालन बेहतर हो।
- नई दिल्ली स्थित राज घाट पर आयोजित एक उल्लासपूर्ण समारोह में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने 'लोक संवर्धन पर्व' का उद्घाटन किया। यह बहु-दिवसीय आयोजन भारत की अल्पसंख्यक समुदायों की प्रतिभा, परंपराओं और आर्थिक संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित है। यह पर्व सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांत "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास" के तहत समावेशी विकास के प्रति साझा संकल्प को दर्शाता है।





- केंद्र सरकार ने झारखंड और कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के दो रेलखंडों (Rail Sections) के दोहरीकरण (Doubling) का फैसला किया है। सरकार ने झारखंड के कोडरमा-बरकाकाना सेक्शन और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाले बल्लारी-चिकजाजपुर सिंगल लाइन सेक्शन को डबल लाइन में बदलने का निर्णय लिया है। इन दोनों प्रोजेक्ट में करीब 6400 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
- रेल मंत्रालय ने Tatkal टिकट बुकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और दुरुपयोग रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 15 जुलाई 2025 से IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर Tatkal टिकट बुकिंग के लिए आधार-आधारित OTP प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था से एजेंटों की भूमिका सीमित की गई है और वास्तविक यात्रियों को अधिक अवसर देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
- बेंगलुरु अब आधिकारिक रूप से 'भारत की तेंदुआ राजधानी' बन गया है, जिससे यह मेट्रो शहरों के किनारों पर रहने वाले स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले जंगली तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या वाला शहर बन गया है। होलेमट्टी नेचर फाउंडेशन (HNF) द्वारा किए गए एक साल लंबे सर्वेक्षण और संरक्षणवादी डॉ. संजय गुब्बी के नेतृत्व में किए गए अध्ययन के अनुसार, बेंगलुरु के आसपास के जंगलों और झाड़ियों में वर्तमान में लगभग 80-85 तेंदुए रहते हैं। यह इसे एक दुर्लभ शहरी क्षेत्र बनाता है, जो आज भी बड़े शिकारी और अन्य बड़े स्तनधारियों से समृद्ध है — और यह इसके पारिस्थितिक महत्व और स्थायी संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता को दर्शाता है।
- भारत एक बड़े जलवायु संकट के कगार पर खड़ा है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि 2030 तक मुंबई, दिल्ली, चेन्नई सहित आठ प्रमुख शहरों में हीटवेव (लू) वाले दिनों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। यह अध्ययन IPE Global और Esri India द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है और "Weathering the Storm: Managing Monsoons in a Warming Climate" शीर्षक से 10 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित International Global-South Climate Risk Symposium में जारी किया गया।
- संयुक्त राष्ट्र की एक नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जनसंख्या 2025 में 1.46 अरब पहुंचने का अनुमान है, जोकि दुनिया में सर्वाधिक होगी। देश की 68 प्रतिशत आबादी कामकाजी है। इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला 1.9 जन्म रह गई है, जोकि प्रतिस्थापन दर 2.1 से कम है। 'वास्तविक प्रजनन संकट' शीर्षक वाली यूएनएफपीए की 'विश्व जनसंख्या स्थिति (एसओडब्ल्यूपी) रिपोर्ट 2025' घटती प्रजनन क्षमता से घबराने के बजाय अपूर्ण प्रजनन लक्ष्यों पर ध्यान देने का आह्वान करती है। इसमें कहा गया है कि लाखों लोग अपने वास्तविक प्रजनन लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम नहीं हैं।
- सतत विकास और स्वच्छ शहरी जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, दिल्ली सरकार ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-वेस्ट) ईको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। यह अत्याधुनिक सुविधा उत्तर दिल्ली के होलम्बी कलां क्षेत्र में बनाई जाएगी और इसे सर्कुलर इकोनॉमी (परिप्रचलन अर्थव्यवस्था) की दिशा में एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा।
- भारतीय निर्माण क्षेत्र और वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून 2025 को बिहार के माहौरा रेल फैक्ट्री से भारत में निर्मित पहले स्वदेशी लोकोमोटिव के निर्यात को गिनी गणराज्य के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। यह कदम रेलवे निर्माण क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है और भारत-अफ्रीका आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम मील का पत्थर है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून 2025 को क्रोएशिया की ऐतिहासिक यात्रा की, जिससे वह वहां जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। यह यात्रा भारत की केंद्रीय और पूर्वी यूरोप (CEE) के प्रति रणनीतिक रुचि को दर्शाती है और भारत-क्रोएशिया संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ती है। यूरोप और भूमध्यसागर के संगम पर स्थित क्रोएशिया भारत के लिए आर्थिक, संपर्क और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है, विशेष रूप से India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) परियोजना के संदर्भ में।
- मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) की तेजी से डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने एक नई मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) शुरू की है, जिससे मतदाता सूची में किसी भी अद्यतन के 15 दिनों के भीतर ईपीआईसी की डिलीवरी संभव हो सकेगी, जिसमें किसी मतदाता का नया नामांकन या मौजूदा मतदाता के किसी भी विवरण में बदलाव शामिल है। यह पहल मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री जानेश कुमार द्वारा निर्वाचन आयुक्तों डॉ. सुखवीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मिलकर मतदाताओं की सुविधा के लिए ईसीआई द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों के अनुरूप है।
- मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) ने प्रोफेसर अनंता चंद्रकासन को अपना अगला प्रोवोस्ट नियुक्त किया है, जिससे वे इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाले पहले भारतीय मूल के शिक्षाविद बन गए हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में अग्रणी माने जाने वाले चंद्रकासन 1 जुलाई 2025 से यह कार्यभार ग्रहण करेंगे। वे सिंथिया बार्नहार्ट का स्थान लेंगे और इस भूमिका में MIT के शैक्षणिक मामलों, वित्तीय योजना और रणनीतिक पहलों का नेतृत्व करेंगे।
- ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने 'ऑपरेशन सिंधु' शुरू किया है, जिसका उद्देश्य संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने तेहरान (ईरान) और येरेवान (आर्मेनिया) स्थित भारतीय दूतावासों के माध्यम से समन्वित प्रयास शुरू किए हैं। पहले चरण में 110 भारतीय छात्रों को सफलतापूर्वक ईरान से सड़क मार्ग द्वारा आर्मेनिया लाया गया, जहां से 18 जून 2025 को एक विशेष उड़ान के जरिए उन्हें नई दिल्ली लाया गया।
- टोल भुगतान को आसान बनाने और राजमार्ग यात्रा सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने ₹3,000 का फास्टैग-आधारित वार्षिक पास लॉन्च किया है, जो विशेष रूप से कार, जीप और वैन जैसे निजी वाहनों के लिए है। 15 अगस्त, 2025 से शुरू होने वाली यह योजना 200 ट्रिप या एक साल की यात्रा की अनुमति देती है, जो भी पहले हो, और इसे लागत कम करने, टोल बूथों पर विवादों को खत्म करने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध, डिजिटल-फर्स्ट टोल संग्रह को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।





- हरित परिवहन और टिकाऊ लॉजिस्टिक्स की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने हरियाणा के मानेसर प्लांट में देश की सबसे बड़ी इन-प्लांट ऑटोमोबाइल रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया है। ₹452 करोड़ की लागत से विकसित यह परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप है और रेल आधारित वाहन डिस्पैच को बढ़ाकर ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी।
- समावेशी शासन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, जनजातीय मामलों के मंत्रालय (MoTA) ने धरती आवा जनभागीदारी अभियान शुरू किया है, जो भारत में अब तक का सबसे बड़ा आदिवासी सशक्तिकरण अभियान है। इस पहल का उद्देश्य 549 आदिवासी जिलों, 2,900 से अधिक ब्लॉकों और 207 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) बहुल जिलों में सरकारी लाभों को पहुंचाना है, जिसमें लगभग 1 लाख गाँव और बस्तियाँ शामिल हैं। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री जुएल ओराम ने इसे अंत्योदय और विकसित भारत के सपने को साकार करने में एक प्रमुख मील का पत्थर बताया।
- नई दिल्ली में 14 जून, 2025 को आयोजित संस्थागत मध्यस्थता पर एक ऐतिहासिक सम्मेलन में, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने घोषणा की कि भारत मध्यस्थता का एक वैश्विक केंद्र बनने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य निवेशकों का विश्वास बढ़ाना और गति, दक्षता और कॉर्पोरेट लचीलेपन का पक्ष लेने वाली प्रणाली के माध्यम से भारतीय अदालतों पर बढ़ते बोझ को कम करना है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जून, 2025 को साइप्रस पहुंचे, जो 20 से अधिक वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इस द्वीप राष्ट्र की पहली यात्रा है। यह यात्रा, जो कनाडा और क्रोएशिया सहित तीन देशों की यात्रा का हिस्सा है, तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संबंधों के बीच प्रमुख भू-राजनीतिक महत्व रखती है। मोदी की इस यात्रा को यूरोप और भूमध्य सागर में भारत की भागीदारी को गहरा करने, तुर्की की क्षेत्रीय मुखरता का प्रतिकार करने और एक विश्वसनीय सहयोगी के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
- भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) की 10वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारियों के बीच, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम को वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम के 11वें संस्करण के लिए राष्ट्रीय मेज़बान के रूप में चुना गया है। आयुष मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने तैयारियों का आकलन करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समीक्षा और क्षेत्र का दौरा किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग को जमीनी स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस प्राचीन भारतीय परंपरा का लाभ हर नागरिक तक पहुँचे।
- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 29 जून 2025 को "कृषि भूमि में पेड़ों की कटाई के लिए मॉडल नियम" जारी किए। यह पहल सतत कृषि, आजीविका संवर्धन, और आगोफॉरेस्ट्री (Agroforestry) को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही मंत्रालय ने आगामी नेशनल टिंबर मैनेजमेंट सिस्टम (NTMS) पोर्टल की भी घोषणा की, जो वृक्ष कटाई

की मंजूरी प्रक्रिया को डिजिटली सरल बनाएगा।

- सांख्यिकी दिवस 2025 के अवसर पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने अपनी इकाई राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय (NSO) के माध्यम से GoStats मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया। यह नवाचारपूर्ण ऐप नागरिकों को कहीं भी, कभी भी वास्तविक समय में आधिकारिक सरकारी आंकड़ों तक आसान पहुंच प्रदान करता है। यह पहल डेटा पारदर्शिता, नागरिक सशक्तिकरण और डिजिटल समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। GoStats ऐप इंटरएक्टिव डैशबोर्ड, विजुअल स्टोरीटेलिंग और यूज़र-फ्रेंडली डिज़ाइन को एकीकृत करके, सरकारी आंकड़ों के साथ लोगों की सहभागिता को अधिक आसान, समझने योग्य और भागीदारीपूर्ण बनाता है।
- डाक विभाग ने घोषणा की है कि अगस्त 2025 तक भारत के सभी डाकघरों में काउंटर पर डिजिटल भुगतान स्वीकार किए जाएंगे। यह परिवर्तन आईटी 2.0 (IT 2.0) नामक एक सशक्त तकनीकी उन्नयन के माध्यम से संभव हो रहा है, जो UPI से जुड़े डायनामिक क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान को अधिक सुरक्षित और उपभोक्ता-अनुकूल बनाएगा।
- गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जून 2025 को तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया। यह पहल हल्दी उत्पादन, ब्रांडिंग, अनुसंधान और वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। केंद्र सरकार ने इसके लिए ₹200 करोड़ का समर्थन दिया है और 2030 तक हल्दी निर्यात को \$1 बिलियन तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। यह बोर्ड भारत की मसाला अर्थव्यवस्था को नया स्वरूप देने में सहायक साबित हो सकता है।
- आदिवासी विकास को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने "आदि कर्मयोगी" कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसका उद्देश्य फील्ड-स्तर के अधिकारियों को प्रेरित और प्रशिक्षित कर जनजातीय कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूत बनाना है। इस कार्यक्रम की घोषणा नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में आयोजित "आदि अन्वेषण" राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन अवसर पर की गई।
- कृषि अनुसंधान और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्र सरकार ने आगरा जिले के सिंगना में इंटरनेशनल पोटेटो सेंटर (CIP) के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (CSARC) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र पेरू स्थित इंटरनेशनल पोटेटो सेंटर (CIP) का क्षेत्रीय अंग होगा, जो विश्व स्तर पर आलू और शकरकंद अनुसंधान में अग्रणी है। भारत, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक और उपभोक्ता देश है, इस केंद्र की स्थापना से बीज गुणवत्ता, उत्पादकता, प्रोसेसिंग और निर्यात में क्रांतिकारी सुधार की उम्मीद कर रहा है।
- भारत में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) ने गवर्नेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 2-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। आईआईटी दिल्ली के प्रबंधन अध्ययन विभाग (डीएमएस) में आयोजित इस पहल का उद्देश्य केंद्रीय और राज्य विभागों के सरकारी अधिकारियों को आवश्यक एआई ज्ञान और शासन, सार्वजनिक सेवा वितरण और नीति कार्यान्वयन में इसके व्यावहारिक अनुप्रयोगों से लैस करना है।





- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में देहरादून में अपनी 21वीं संचालन समिति की बैठक के दौरान प्रोजेक्ट एलीफेंट की व्यापक समीक्षा की। समीक्षा में पूर्वोत्तर राज्यों में समन्वित हाथी जनसंख्या आकलन के चरण-1 के पूरा होने, हाथी-ट्रेन टकराव के लिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए 3,400 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण और प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में सुस्त भालू और घड़ियाल को शामिल करने सहित महत्वपूर्ण विकास का खुलासा किया गया। ये प्रयास भारत भर में बेहतर वन्यजीव संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष के शमन की दिशा में एक व्यापक प्रयास का संकेत देते हैं।
- भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक रथ यात्रा 2025 के दौरान यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, ईस्ट कोस्ट रेलवे (ECoR) ने 'ECoR Yatra' मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह रियल-टाइम डिजिटल समाधान अब Google Play Store पर उपलब्ध है और तीर्थयात्रियों को रेलवे सेवाओं, आवास और यात्री सुविधाओं की संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।
- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और अधोसंरचनात्मक पहल करते हुए गंगा नदी पर बने छह लेन वाले पुल का उद्घाटन किया, जो राज्य की राजधानी पटना को उनके कट्टर प्रतिद्वंद्वी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद के राजनीतिक गढ़ राघोपुर से जोड़ता है। यह रणनीतिक परियोजना केवल एक संरचना नहीं, बल्कि एक गहरे राजनीतिक संदेश का प्रतीक है—सत्ता के केंद्र को विपक्षी नेता के क्षेत्र से जोड़ना।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IIT-दिल्ली) ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। संस्थान ने पहली बार अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) उम्मीदवारों के लिए विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है। यह पहल प्रतिष्ठित संस्थान में इन समुदायों की पीएचडी कार्यक्रमों में निरंतर कम भागीदारी को देखते हुए की गई है, और हाल ही में एक संसदीय समिति द्वारा संवैधानिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा के बाद इसे गति मिली है।
- त्रिपुरा मिजोरम और गोवा के बाद तीसरा भारतीय राज्य बन गया है, जिसने 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच 95% साक्षरता के राष्ट्रीय मानक के अनुसार पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। इसकी घोषणा 23 जून, 2025 को अगरतला के रवींद्र सतबर्षिकी भवन में एक भव्य समारोह के दौरान की गई, जिसमें मुख्यमंत्री प्रो. (डॉ.) माणिक साहा और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
- मानव और वन्यजीवों के बीच सतत सह-अस्तित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence - CoE) की स्थापना की घोषणा की है। यह केंद्र WII-SACON में स्थापित किया जाएगा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर संघर्ष की घटनाओं को कम करने के लिए जन-जागरूकता और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को बढ़ावा देगा।

राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स: मई 2025

कैबिनेट मंजूरी

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) उन्नयन योजना" और पांच "राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों" की स्थापना को एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी है। यह योजना केंद्रीय बजट 2024-25 और 2025-26 के तहत घोषित की गई है, जिसकी कुल लागत ₹60,000 करोड़ है। इसमें केंद्र, राज्य सरकारों, उद्योग जगत के योगदान के साथ-साथ एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक का सह-वित्त पोषण भी शामिल है। योजना के तहत देशभर के 1,000 सरकारी आईटीआई संस्थानों को "हब और स्पोक" मॉडल के तहत उन्नत किया जाएगा और भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित पांच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTIs) को सशक्त बनाया जाएगा। इन NSTIs में ही पांच "राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र" भी स्थापित किए जाएंगे, और 50,000 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह पांच वर्षीय पहल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगी। योजना में आवश्यकता-आधारित निवेश मॉडल और परिणाम-उन्मुख कार्यान्वयन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) संरचना शामिल है। इसका उद्देश्य आईटीआई को आकर्षक बनाना और "विकसित भारत 2047" के विजन को साकार करना है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के पांच नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) — आंध्र प्रदेश (IIT तिरुपति), केरल (IIT पलक्कड़), छत्तीसगढ़ (IIT भिलाई), जम्मू-कश्मीर (IIT जम्मू) और कर्नाटक (IIT धारवाड़) — के लिए शैक्षणिक और बुनियादी ढांचे की क्षमता विस्तार (फेज-बी निर्माण) को मंजूरी दी है। वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक की अवधि में यह विस्तार ₹11,828.79 करोड़ के निवेश से किया जाएगा। इस परियोजना के तहत 130 नए संकाय पद सृजित किए जाएंगे और पांच अनुसंधान पार्क विकसित किए जाएंगे। छात्र क्षमता में 6,500 की वृद्धि होगी, जिससे कुल क्षमता 7,111 से बढ़कर 13,687 हो जाएगी। यह पहल उच्च शिक्षा तक पहुंच, रोजगार सृजन और स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ पूरे भारत के छात्रों को पैन-इंडिया प्रवेश प्रणाली के माध्यम से लाभ पहुंचाएगी। बजट 2025-26 के अनुसार, पिछले दस वर्षों में सभी 23 IITs की कुल छात्र क्षमता 65,000 से बढ़कर 1.35 लाख हो गई है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने संशोधित SHAKTI नीति के तहत थर्मल पावर प्लांट्स (TPPs) को नई कोयला लिंकिंग की मंजूरी दी है। इस नीति के अंतर्गत दो नई विंडो शुरू की गई हैं: विंडो-I के तहत केंद्र और राज्य सरकार के प्लांटों को अधिसूचित मूल्य पर कोयला मिलेगा, जबकि विंडो-II के अंतर्गत 25 वर्षों तक की अवधि के लिए बिना पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) की आवश्यकता के, प्रीमियम मूल्य पर कोयला नीलामी के माध्यम से उपलब्ध होगा। यह नीति कोयला खरीद में लचीलापन बढ़ाती है, नई बिजली उत्पादन क्षमता को प्रोत्साहित करती है और घरेलू कोयले के उपयोग को बढ़ावा देती है। इसे कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसके लाभों में प्रक्रियाओं का सरलीकरण, खदान के समीप स्थित संयंत्रों को बढ़ावा, कोयला स्रोतों का युक्तिकरण और बाजार भागीदारी में वृद्धि शामिल हैं। नीति के क्रियान्वयन की निगरानी एक सशक्त समिति द्वारा की जाएगी। यह योजना कोयला कंपनियों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं डालती और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' तथा ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्यों को भी सशक्त करती है।





- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत छठी सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह संयंत्र HCL और Foxconn के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में जेवर एयरपोर्ट के पास YEIDA क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इसमें मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल और अन्य उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण किया जाएगा। इस संयंत्र की क्षमता प्रति माह 20,000 वेफर्स और 36 मिलियन यूनिट्स का आउटपुट होगी। इसके लिए ₹3,700 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इससे पहले देश में पाँच अन्य सेमीकंडक्टर यूनिट्स का निर्माण कार्य पहले से जारी है। भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है, जिसमें Applied Materials और Lam Research जैसी वैश्विक कंपनियाँ अब भारत में संचालन कर रही हैं। Merck, Linde, Air Liquide और Inox जैसे प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी इस उद्योग को समर्थन देने की तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान में देश की 270 शैक्षणिक संस्थाएँ और 70 स्टार्टअप चिप डिज़ाइन पर कार्य कर रहे हैं, और SCL मोहाली द्वारा अब तक 20 उत्पाद टेप आउट किए जा चुके हैं। यह पहल आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को सशक्त बनाती है और भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में सेमीकंडक्टर की मांग को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के तकनीकी और कृषि क्षेत्रों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से दो प्रमुख पहलों को मंजूरी दी है। पहली पहल के तहत, भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत HCL और Foxconn के संयुक्त उपक्रम के रूप में छठी सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई की स्थापना की जाएगी। यह संयंत्र उत्तर प्रदेश के YEIDA क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट के पास स्थापित होगा। ₹3,700 करोड़ की लागत से बनने वाला यह संयंत्र मोबाइल फोन, लैपटॉप और वाहनों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण करेगा, जिसकी डिज़ाइन क्षमता प्रति माह 36 मिलियन यूनिट होगी। यह पहल भारत को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसे शैक्षणिक संस्थानों, स्टार्टअप्स और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला साझेदारों के नवाचार से समर्थन मिल रहा है।
- इसके साथ ही, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना (Modified Interest Subvention Scheme - MISS) के तहत ब्याज सहायता (Interest Subvention - IS) घटक को जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से कम ब्याज दरों पर अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराना है। इसमें ₹3 लाख तक के ऋण पर 7% ब्याज दर निर्धारित की गई है, जिसमें बैंकों को 1.5% की सहायता दी जाती है, और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त 3% की प्रॉम्प्ट रिपेमेंट प्रोत्साहन (Prompt Repayment Incentive) मिलता है, जिससे प्रभावी ब्याज दर घटकर सिर्फ 4% रह जाती है। यह योजना 7.75 करोड़ से अधिक किसानों को कवर करती है और समावेशी कृषि विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ ही किसान ऋण पोर्टल (Kisan Rin Portal) जैसी डिजिटल पहलों के माध्यम से पारदर्शिता और कार्यक्षमता को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय रेलवे की क्षमता और गति बढ़ाने के लिए दो प्रमुख मल्टिट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है — रतलाम-नागदा तीसरी और चौथी लाइन तथा वर्धा-बल्लारशाह चौथी लाइन। इन परियोजनाओं में कुल लगभग ₹3,399 करोड़ का निवेश किया जाएगा और यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगभग 176 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेंगी। इससे 784 गांवों के लगभग 19.74 लाख लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत स्वीकृत ये परियोजनाएं 18.40 मिलियन टन प्रतिवर्ष (MTPA) तक माल ढुलाई की क्षमता बढ़ाएंगी, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाएंगी, और 20 करोड़ लीटर तेल आयात को घटाकर 99 करोड़ किलोग्राम CO₂ उत्सर्जन से बचाव करेंगी, जो कि लगभग 4 करोड़ पेड़ों के लगाने के बराबर है। इन परियोजनाओं के निर्माण चरण में लगभग 74 लाख मानव-दिवस का रोजगार उत्पन्न होगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बल मिलेगा और क्षेत्रीय विकास, स्व-रोजगार और रेलवे नेटवर्क की संचालन क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार होगा।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश में 108.134 किमी लंबा, चार लेन वाला बदवेल-नेल्लोर राजमार्ग विकसित करने की मंजूरी दी है। यह परियोजना ₹3,653.10 करोड़ की लागत से DBFOT मॉडल के तहत विकसित की जाएगी। यह रणनीतिक कॉरिडोर कोम्पार्थी (VCIC), ओरवकल (HBIC) और कृष्णापट्टनम (CBIC) जैसे प्रमुख औद्योगिक केंद्रों को आपस में जोड़ेगा, और कृष्णापट्टनम पोर्ट तक पहुंच और लॉजिस्टिक्स में सुधार करेगा। इस राजमार्ग के निर्माण से यात्रा दूरी में 33.9 किमी की कमी आएगी, यात्रा समय एक घंटे तक कम होगा, और ईंधन की खपत व वाहन संचालन लागत में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। यह परियोजना लगभग 43 लाख मानव-दिवस का रोजगार उत्पन्न करेगी, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल सरकार की बुनियादी ढांचा विकास नीति और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

संसद समाचार

इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण खबरें

ऑपरेशन सिंदूर: भारत ने पाकिस्तान और पीओके में जवाबी हमला किया

भारतीय सशस्त्र बलों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में स्थित आतंकी शिविरों पर सटीक हमले किए। यह कार्रवाई पाहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की गई, जिसमें 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की जान गई थी। इस निर्मम हमले के बाद पूरे देश में गहरा आक्रोश और निर्णायक जवाब की मांग उठी थी।

नौ आतंकी ठिकाने निशाने पर: सटीकता और संयम पर जोर

प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इन हमलों में कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनके बारे में माना जाता है कि वे भारत के खिलाफ हमलों की योजना और क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। इन ठिकानों में शामिल हैं:





- मुजफ्फराबाद (PoK) के पास स्थित लश्कर-ए-तैयबा का पूर्व बेस
 - बाहावलपुर (पंजाब प्रांत, पाकिस्तान) में स्थित जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा एक मदरसा
 - कोटली (PoK) में स्थित एक प्रमुख घुसपैठ केंद्र
- सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया और यह कार्रवाई पूरी तरह से संयमित, केंद्रित और गैर-उकसावे वाली थी।

उद्देश्य: आतंकी ढांचे को नष्ट करना और प्रतिरोध को पुनः स्थापित करना

बालाकोट के बाद फिर से रणनीतिक संतुलन बनाना

भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े सूत्रों ने बताया कि 'ऑपरेशन सिंदूर' का उद्देश्य 2019 के बालाकोट हवाई हमले के बाद धीरे-धीरे कमजोर हो रहे रणनीतिक प्रतिरोध को फिर से मजबूती देना है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, हाल की गतिविधियों से यह स्पष्ट हुआ कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों ने यह मान लिया था कि भारत अब सीमित प्रतिक्रिया देगा।

पाहलगाम का बर्बर हमला, जिसे लश्कर-ए-तैयबा के प्रांक्सी समूह 'द रेजिस्टेंस फोर्स' (TRF) द्वारा अंजाम दिया गया माना जा रहा है, इस नीति परिवर्तन का मुख्य कारण बना। इस हमले में तीर्थयात्रियों और स्थानीय नागरिकों सहित कुल 26 लोगों की जान चली गई, जिससे जनता और नेतृत्व दोनों की ओर से तत्काल कार्रवाई की मांग उठी।

शीर्ष स्तर पर सैन्य समन्वय और रणनीतिक योजना

प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा प्रमुखों के साथ की अहम बैठकें

ऑपरेशन सिंदूर को शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, और भारतीय सशस्त्र बलों के शीर्ष अधिकारियों के बीच कई दिनों तक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठकें हुईं। इन बैठकों में शामिल थे:

- नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी
- वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह
- रक्षा सचिव आर. के. सिंह

इन बैठकों का उद्देश्य था:

- जवाबी विकल्पों की समीक्षा
- सैन्य तैयारियों का मूल्यांकन
- खुफिया जानकारी का विश्लेषण

भारतीय सेना ने संभावित पाकिस्तानी प्रतिक्रिया को देखते हुए पहले ही नियंत्रण रेखा (LoC) पर अग्रिम चौकियों को मजबूत कर दिया था।

जमीनी स्तर पर कार्रवाई और रणनीतिक संदेश

कोई उकसावे का प्रयास नहीं—केवल जवाबदेही

सेना अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई बड़ा सैन्य टकराव उत्पन्न करना नहीं था, बल्कि यह आतंकवादी नेटवर्क और उनके संरक्षकों को स्पष्ट और कड़ा संदेश देना था।

हवा और ज़मीन से समन्वित हमला

रॉयटर्स और न्यूयॉर्क टाइम्स की अपुष्ट रिपोर्टों के अनुसार:

- भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (PoK) के ऊपर देखे गए
 - मुजफ्फराबाद और कोटली के पास कई विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं
- ये इलाके लंबे समय से आतंकवाद के गढ़ माने जाते हैं और पाकिस्तान की "रणनीतिक गहराई" की नीति के तहत संरक्षित रहे हैं।

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया: बदला लेने की चेतावनी

पाकिस्तानी सेना ने ARY न्यूज के माध्यम से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया दी, जिसमें पुष्टि की गई कि:

- भारत ने तीन स्थानों पर मिसाइल हमले किए हैं
 - पाकिस्तान अपने चुने हुए समय और स्थान पर जवाब देगा
- हालांकि, इस्लामाबाद की ओर से अभी तक किसी जान-माल के नुकसान की पुष्टि नहीं की गई है।

भारत में जन प्रतिक्रिया और राजनीतिक प्रतिक्रिया

यह हमले भारत में व्यापक रूप से सराहे जा रहे हैं, खासकर:

- पाहलगाम पीड़ितों के परिवारों द्वारा
- सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा, जो लंबे समय से राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक नीति की वकालत कर रहे हैं

सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस ऑपरेशन के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सेना की प्रशंसा की है।

सोशल मीडिया पर जबरदस्त समर्थन देखा गया है, विशेषकर इन हैशटैग्स के माध्यम से:

#OperationSindoor,

#JusticeForPahalgam,

#IndiaStrikesBack

आगे क्या? रणनीतिक निर्णय जारी रहेंगे

आज देर शाम तक 'ऑपरेशन सिंदूर' पर एक विस्तृत ब्रीफिंग की उम्मीद है, जिसमें:

- रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय
- संचालन के परिणाम,
- क्षेत्रीय प्रभाव,
- और कूटनीतिक संदेश साझा करेंगे।

सतर्कता बनाए रखना अनिवार्य

भारतीय सेना पश्चिमी सीमा पर पूरी तरह सतर्क है, और:

- निगरानी अभियानों में वृद्धि की गई है
- सीमा पार खुफिया गतिविधियाँ तेज़ की गई हैं

विश्लेषकों का मानना है कि भले ही यह ऑपरेशन रणनीतिक रूप से सफल रहा है, लेकिन इसके कारण क्षेत्र में अल्पकालिक तनाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

भारत 2025 में बनेगा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की अप्रैल 2025 आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। IMF का अनुमान है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) \$4.187 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, जो जापान के \$4.186 ट्रिलियन से थोड़ा अधिक होगा। इससे भारत केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी से पीछे रहेगा। यह अनुमान भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक प्रगति और उपभोग तथा निवेश से प्रेरित मजबूत विकास गति को दर्शाता है।

समाचार में क्यों?

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की अप्रैल 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत को वैश्विक मंच पर केंद्र में लाया गया है, क्योंकि रिपोर्ट में भारत के नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के मामले में जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान लगाया गया है। यह उपलब्धि भारत के 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।





IMF द्वारा 2025 के प्रमुख अनुमान:

- भारत का GDP (2025): \$4,187.02 अरब
- जापान का GDP (2025): \$4,186.43 अरब
- भारत की रैंक: चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
- विकास दर (2025): 6.2%
- विकास दर (2026): 6.3%
- अनुमानित GDP (2027): \$5 ट्रिलियन
- अनुमानित GDP (2030): \$6.8 ट्रिलियन

IMF का परिचय (स्थिर पृष्ठभूमि):

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) एक वैश्विक वित्तीय संस्था है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में है। इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना।

2025 में अनुमानित शीर्ष अर्थव्यवस्थाएँ (नाममात्र GDP के अनुसार):

1. संयुक्त राज्य अमेरिका: \$30.5 ट्रिलियन
2. चीन: \$19.2 ट्रिलियन
3. जर्मनी: \$4.74 ट्रिलियन
4. भारत: \$4.19 ट्रिलियन (अनुमानित)
5. जापान: \$4.18 ट्रिलियन (अनुमानित)

मुख्य विशेषताएँ और महत्व:

- मजबूत आर्थिक आधार: ग्रामीण खपत, निजी निवेश और सेवाक्षेत्र की मजबूती भारत की वृद्धि को समर्थन दे रहे हैं।
- विकास दर की तुलना (2025):
 - o भारत: 6.2% (सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़)
 - o चीन: 4%
 - o अमेरिका: 1.8%
 - o जापान: 0.6%
 - o यूनाइटेड किंगडम: 1.1%

पुलित्जर पुरस्कार 2025: पत्रकारिता विजेताओं की पूरी सूची

पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक, पुलित्जर पुरस्कार 2025 की घोषणा इस सप्ताह पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा की गई। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करते हैं और दुनिया भर में सार्वजनिक विमर्श को आकार देने वाली सबसे प्रभावशाली कहानियों को उजागर करते हैं।

इस वर्ष, द न्यूयॉर्क टाइम्स शीर्ष विजेता के रूप में उभरा, जिसने चार प्रमुख पुरस्कार हासिल किए, जबकि द वाशिंगटन पोस्ट, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, रॉयटर्स और द न्यू यॉर्कर ने भी अपनी खोजी गहराई, ब्रेकिंग न्यूज कवरेज और कथात्मक कहानी कहने के लिए उल्लेखनीय प्रशंसा अर्जित की।

पुलित्जर पुरस्कार 2025: पत्रकारिता विजेताओं की पूरी सूची

- सार्वजनिक सेवा : कविता सुराना, लिज़ी प्रेसर, कैसंड्रा जारामिलो और स्टेसी क्रैनिट्ज़
- ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग : द वाशिंगटन पोस्ट स्टाफ
- खोजी रिपोर्टिंग : रॉयटर्स स्टाफ – “फ्रेंटेनाइल एक्सप्रेस”
- व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग : आजम अहमद, क्रिस्टीना गोल्डबाम और मैथ्यू ऐकिंस (NYT)
- स्थानीय रिपोर्टिंग : एलिसा झू, निक थिएम और जेसिका गैलाघर (बाल्टीमोर बैनर और NYT)

- राष्ट्रीय रिपोर्टिंग : द वॉल स्ट्रीट जर्नल स्टाफ - एलन मस्क जांच
- अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग : डेक्लान वाल्श और NYT स्टाफ – सूडान संघर्ष
- फीचर लेखन : मार्क वॉरेन (एस्कायर)
- टिप्पणी : मोसाब अबू तोहा (द न्यू यॉर्कर)
- आलोचना : एलेक्जेंड्रा लांगे (ब्लूमबर्ग सिटीलैब)
- संपादकीय लेखन : राज मांकड़ एवं टीम (ह्यूस्टन क्रॉनिकल)
- सचित्र रिपोर्टिंग : एन टेलनेस (वाशिंगटन पोस्ट)
- ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी : डग मिल्स (NYT) - ट्रम्प की हत्या का प्रयास
- फीचर फोटोग्राफी : मोइसेस समन (द न्यू यॉर्कर) – सीरिया जेल
- ऑडियो रिपोर्टिंग : द न्यू यॉर्कर स्टाफ – “इन द डार्क” पांडकास्ट

न्यूयॉर्क टाइम्स ने चार पुलित्जर पुरस्कार जीते

न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) ने 2025 में चार पुलित्जर पुरस्कार जीतकर इस क्षेत्र में अग्रणी स्थान प्राप्त किया। इनमें से एक प्रमुख पुरस्कार ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी के लिए मिला, जिसका श्रेय अनुभवी फोटो पत्रकार डग मिल्स को दिया गया।

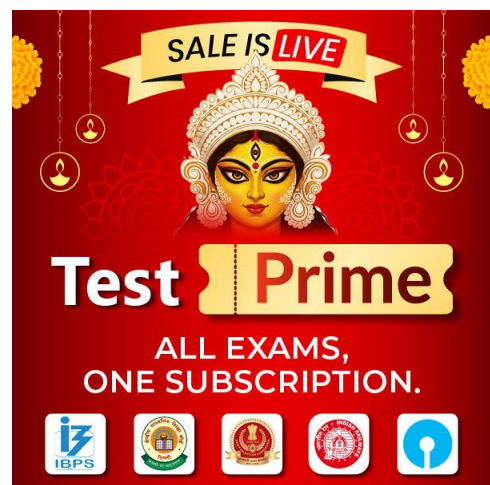
डॉग मिल्स ने एक निर्णायक क्षण को कैद किया

डग मिल्स ने 13 जुलाई, 2024 को बटलर, पेनसिल्वेनिया में एक अभियान कार्यक्रम के दौरान डोनाल्ड ट्रम्प पर हत्या के प्रयास को कैद करने वाली अपनी नाटकीय छवि के लिए यह पुरस्कार जीता। तस्वीर में दिखाया गया था कि पोडियम पर खड़े ट्रम्प को गोली कुछ इंच की दूरी से छूती हुई निकल गई, एक ऐसी तस्वीर जिसने दुनिया को चौंका दिया।

इसके अलावा, NYT को गाजा संघर्ष पर अपनी व्यापक रिपोर्टिंग सहित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कवरेज के लिए सम्मानित किया गया। शेष तीन पुरस्कारों का विवरण प्रारंभिक घोषणा में पूरी तरह से प्रकट नहीं किया गया था, लेकिन यह अखबार की व्यापक संपादकीय ताकत को दर्शाता है।

वाशिंगटन पोस्ट को ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए मान्यता मिली

वाशिंगटन पोस्ट के कर्मचारियों को ट्रम्प की हत्या के प्रयास की व्यापक और त्वरित कवरेज के लिए ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला। न्यायाधीशों ने ऑडियो और विज्ञापन फॉरेंसिक के उपयोग के लिए काम की प्रशंसा की, जिसमें उच्च-दांव की स्थिति में सटीकता और स्पष्टता के साथ गति का संयोजन किया गया।





एलन मस्क की जांच के लिए बॉल स्ट्रीट जर्नल को जीत मिली नेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में, बॉल स्ट्रीट जर्नल ने एलन मस्क के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में गहनता से जानकारी दी। रिपोर्टिंग में शामिल हैं:

- मस्क का व्यावसायिक संचालन
- उनका कथित नशीली दवाओं का उपयोग
- राजनीतिक पुनर्संरक्षण, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प के साथ उनके घनिष्ठ संबंध भी शामिल हैं

यह कवरेज आधुनिक तकनीकी दुनिया के सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद व्यक्तियों में से एक पर प्रकाश डालता है।

रॉयटर्स को फेंटेनाइल संकट की जांच के लिए पुरस्कृत किया गया

रॉयटर्स को अपनी विस्फोटक श्रृंखला "फेंटेनल एक्सप्रेस" के लिए खोजी रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला। सात भागों वाली इस जांच ने यह उजागर किया कि:

- फेंटेनाइल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले प्रीकर्सर रसायनों को कानूनी तौर पर मात्र 3,600 डॉलर में खरीदा जा सकता है
- इस राशि से 3 मिलियन डॉलर मूल्य की दवाइयां बनाई जा सकती हैं
- कमज़ोर अंतर्राष्ट्रीय नियमन अमेरिका में ओपिओइड संकट को बढ़ावा दे रहे हैं

द न्यू यॉर्कर ने विभिन्न श्रेणियों में तीन पुरस्कार जीते

द न्यू यॉर्कर ने एक बार फिर कथात्मक पत्रकारिता में अपनी प्रतिष्ठा मजबूत की, तथा तीन पुलित्जर पुरस्कार जीते :

- टिप्पणी : गाजा युद्ध में हुई मानवीय क्षति पर निबंध के लिए मोसाब अबू तोहा को यह पुरस्कार दिया गया।
- फीचर फोटोग्राफी : सीरिया की सेडनया जेल के अंदर से काले और सफेद चित्रों के लिए मोइसेस समन को दिया गया
- ऑडियो रिपोर्टिंग : पॉडकास्ट "इन द डार्क" के लिए, सैन्य गोपनीयता और संस्थागत विफलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए

पत्रकारिता में अन्य प्रमुख विजेता

- सार्वजनिक सेवा : कविता सुराना, लिजी प्रेसर, कैसांद्रा जारामिलो और स्टेसी क्रैनिट्ज़ को अस्पष्ट गर्भपात कानूनों से जुड़ी मातृ मृत्यु पर उनकी रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार मिला।
- व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग : NYT के पत्रकार आजम अहमद, क्रिस्टीना गोल्डबाम और मैथ्यू ऐकिंस को इस बात पर काम करने के लिए सम्मानित किया गया कि किस प्रकार मिलिशिया को अमेरिकी समर्थन ने अफगानिस्तान में प्रयासों को नुकसान पहुंचाया।
- स्थानीय रिपोर्टिंग : बाल्टीमोर बैनर और NYT के पत्रकारों ने बाल्टीमोर में वृद्ध अश्वेत पुरुषों के बीच फेंटेनाइल महामारी पर प्रकाश डाला।
- अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग : डेक्कन वाल्थ और NYT स्टाफ को सूडान के संघर्ष में विदेशी हस्तक्षेप को उजागर करने के लिए सम्मानित किया गया।
- फीचर लेखन : एस्क्वायर के मार्क वारेन ने एक पादरी-मेयर की ऑनलाइन एक्सपोज़र के बाद आत्महत्या की एक मार्मिक कहानी लिखी।
- आलोचना : ब्लूमबर्ग सिटीलैब की एलेक्जेंड्रा लांगे को परिवारों के लिए डिजाइन किए गए शहरी स्थानों पर लेखन के लिए यह पुरस्कार मिला।
- संपादकीय लेखन : ह्यूस्टन क्रॉनिकल की संपादकीय टीम को घातक ट्रेन क्रॉसिंग पर एक श्रृंखला के लिए पुरस्कार मिला।

- सचित्र रिपोर्टिंग और टिप्पणी : वाशिंगटन पोस्ट की पूर्व कार्टूनिस्ट एन टेलनेस को शक्तिशाली व्यक्तियों और संस्थाओं पर निशाना साधते हुए उनके साहसिक चित्रों के लिए यह पुरस्कार दिया गया।

लक्कुंडी स्मारक समूह को यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव

भारत की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में, कर्नाटक के लक्कुंडी और उसके आसपास स्थित प्राचीन मंदिरों एवं स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची (Tentative List) में शामिल किए जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ये मंदिर कल्याण चालुक्य काल (10वीं-12वीं शताब्दी ईस्वी) के दौरान निर्मित किए गए थे और स्थापत्य कला की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध माने जाते हैं।

क्यों है यह ख़बर में?

कर्नाटक सरकार ने इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) की सहायता से लक्कुंडी स्मारकों और चालुक्य कालीन मंदिरों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया है। ये स्मारक यूनेस्को के सांस्कृतिक मानकों को पूर्ण करते हैं।

स्थान और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- स्थिति: गडग ज़िला, कर्नाटक
- निर्माण काल: 10वीं से 12वीं शताब्दी, कल्याण चालुक्य वंश के शासन में
- महत्व: चालुक्य युग की स्थापत्य तकनीकों और सांस्कृतिक उत्कर्ष के अद्वितीय उदाहरण

यूनेस्को मानदंड जिनको पूरा किया गया है

- सांस्कृतिक आदान-प्रदान: नागर, द्रविड़ और भूमिजा शैलियों के सम्मिलन से बनी वेसर शैली का उत्कर्ष
- ऐतिहासिक महत्व: मंदिर वास्तुकला और तकनीकी उन्नति का प्रतीक — जैसे कि बावड़ियाँ (स्टेपवेल्स)

प्रस्ताव में शामिल प्रमुख संरचनाएँ

लक्कुंडी में:

- काशी विश्वेश्वर मंदिर
- मणिकेश्वर मंदिर
- नन्नेश्वर मंदिर
- ब्रह्मा जिनालय (1007 ई.)
- मुसुकिना बावि

आसपास के मंदिर:

- डोडुबासप्पा मंदिर (डांबळ)
- जापडा बावि
- त्रिकुटेश्वर मंदिर (गडग)
- महादेव मंदिर (इटागी)
- श्री मल्लिकार्जुन मंदिर (कुरुवट्टी)
- सोमेश्वर मंदिर (लक्ष्मेश्वर)
- तारकेश्वर मंदिर (हंगल)

स्थापत्य महत्व

- वेसर शैली का अनूठा समन्वय
- मंदिर परिसरों में शामिल बावड़ियाँ, कई बार मंदिरों से भी बड़ी और अधिक सजावटी
- वास्तुकला, जल संरचना, और सामाजिक उपयोगिता का अद्भुत समावेश





प्रक्रिया और आगे के कदम

- प्रस्ताव की समीक्षा INTACH और पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञ कर रहे हैं
- अस्थायी सूची में शामिल होने के 1 वर्ष बाद पूर्ण नामांकन डोज़ियर (dossier) प्रस्तुत किया जाएगा
- कर्नाटक के अन्य अस्थायी सूची वाले स्थल:
 - o बादामी
 - o ऐहोले
 - o श्रीरंगपट्टन
 - o हीरे बेनकल

राष्ट्रपति मुर्मू ने राज्यपालों की विधेयक स्वीकृति शक्तियों पर अनुच्छेद 143 का प्रयोग किया

एक दुर्लभ संवैधानिक कदम के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143 का हवाला देते हुए अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्य विधान के संबंध में राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों और आचरण से संबंधित कई कानूनी सवालों पर सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार राय मांगी है। राष्ट्रपति का यह संदर्भ सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक फैसले से उपजा है जिसमें राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा की गई देरी की आलोचना की गई है।

समाचार में क्यों?

13 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है। यह सलाह राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका से जुड़े 14 संवैधानिक प्रश्नों पर आधारित है। यह कदम तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर निर्णय में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 8 अप्रैल 2025 के फैसले के बाद उठाया गया।

राष्ट्रपति संदर्भ के तहत उठाए गए प्रमुख प्रश्न

1. जब कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष अनुच्छेद 200 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है, तो उनके पास कौन-कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं?
2. क्या राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य होना चाहिए?
3. क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा किए गए विवेकाधीन निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं?
4. क्या अनुच्छेद 361 (राष्ट्रपति/राज्यपाल को कार्यकाल के दौरान कानूनी कार्यवाही से छूट) न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः रोक प्रदान करता है?
5. यदि संविधान राज्यपाल के विवेकाधीन निर्णय की समय-सीमा या प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता, तो क्या न्यायालय समय-सीमा और प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है?
6. क्या राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 201 के तहत लिए गए निर्णय न्यायिक जांच के अधीन हैं?
7. क्या न्यायिक आदेश राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे और कब करना है, यह निर्देशित कर सकते हैं?
8. जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना आवश्यक होता है?
9. क्या विधेयक के कानून बनने से पहले ही उसके विषय-वस्तु पर न्यायिक हस्तक्षेप किया जा सकता है?
10. क्या न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति/राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों को प्रतिस्थापित कर सकता है?

11. क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक, राज्यपाल की स्वीकृति के बिना भी "प्रचलित कानून" माना जा सकता है?
12. क्या सुप्रीम कोर्ट की पीठ को संविधान की व्याख्या संबंधी मामलों को कम से कम पाँच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष भेजना अनिवार्य है (अनुच्छेद 145(3))?
13. क्या अनुच्छेद 142 केवल प्रक्रिया संबंधी कानूनों तक सीमित है या यह मौलिक संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध निर्देश देने की शक्ति भी देता है?
14. क्या केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निपटारा केवल अनुच्छेद 131 के अंतर्गत मूल वाद द्वारा ही हो सकता है?

पृष्ठभूमि और कारण

- तमिलनाडु सरकार ने एक याचिका दायर कर राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा 10 दोबारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई में देरी को चुनौती दी थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए राज्यपाल की निष्क्रियता को असंवैधानिक करार दिया और माना कि विधेयकों को मौन स्वीकृति मिल गई है।
- इस निर्णय ने न्यायिक सक्रियता और कार्यपालिका की सीमा को लेकर संवैधानिक बहस छेड़ दी, जिससे राष्ट्रपति को यह मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजना पड़ा।

सांविधानिक प्रावधान

अनुच्छेद	विषय
अनुच्छेद 200	राज्यपाल के पास राज्य विधेयकों पर स्वीकृति, अस्वीकृति या राष्ट्रपति के पास भेजने के विकल्प
अनुच्छेद 201	राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति की भूमिका
अनुच्छेद 143	राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार
अनुच्छेद 142	सुप्रीम कोर्ट को "पूर्ण न्याय" करने की शक्ति
अनुच्छेद 145(3)	संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को कम-से-कम पाँच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनने की व्यवस्था
अनुच्छेद 361	राष्ट्रपति और राज्यपाल को कार्यकाल के दौरान कानूनी कार्यवाही से छूट

इस संदर्भ का महत्व

- राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधायी प्रक्रिया में भूमिका स्पष्ट करने में मदद करेगा।
- विधेयकों की स्वीकृति को लेकर समयबद्धता तय हो सकती है, जिससे विधायी जड़ता रोकी जा सके।
- कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन पर निर्णय तय करेगा।
- यह फैसला संघीय ढांचे और केंद्र-राज्य संबंधों को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है।





अश्विनी वैष्णव ने नोएडा और बेंगलुरु में पहले 3 एनएम सेमीकंडक्टर डिज़ाइन हब का उद्घाटन किया

केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर (nm) चिप डिज़ाइन केंद्रों का नोएडा और बेंगलुरु में उद्घाटन किया। ये अत्याधुनिक केंद्र रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया (Renesas Electronics India) द्वारा स्थापित किए गए हैं और यह भारत की सेमीकंडक्टर डिज़ाइन क्षमताओं में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक हैं। यह आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत भारत को एक वैश्विक सेमीकंडक्टर महाशक्ति बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

समाचार में क्यों?

भारत ने सेमीकंडक्टर डिज़ाइन के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की है। पहली बार देश में 3nm टेक्नोलॉजी पर आधारित चिप डिज़ाइन केंद्र स्थापित किए गए हैं। यह भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत संकेत है।

मुख्य उद्देश्य और प्रमुख बिंदु

- 3nm चिप डिज़ाइन केंद्रों का शुभारंभ: नोएडा और बेंगलुरु में उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया।
- भारत में अपनी तरह के पहले केंद्र: ये केंद्र देश में पहली बार 3nm तकनीक पर चिप डिज़ाइन कर रहे हैं, जो 5nm और 7nm डिज़ाइनों से एक बड़ा तकनीकी सुधार है।
- रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया द्वारा स्थापित: यह एक वैश्विक अग्रणी एम्बेडेड सेमीकंडक्टर समाधान प्रदाता है।

सरकार की सेमीकंडक्टर रणनीति

- समग्र रणनीति: डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, एटीएमपी (असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग) और सप्लाय चेन विकास को एकीकृत रूप में बढ़ावा।
- वैश्विक समर्थन: Applied Materials और Lam Research जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का समर्थन।
- शैक्षणिक संस्थानों का योगदान: 270+ से अधिक संस्थानों को EDA सॉफ्टवेयर टूल्स दिए गए हैं; अब उन्हें सेमीकंडक्टर लर्निंग किट भी दी जाएगी।
- कौशल विकास: उद्योग-तैयार इंजीनियरों के निर्माण हेतु नई सेमीकंडक्टर लर्निंग किट का शुभारंभ।

रणनीतिक महत्व

- भू-राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण: यह केंद्र भारत की रणनीतिक जरूरतों और भारत-जापान सहयोग को भी मजबूती प्रदान करते हैं।
- सतत विकास: यह पहल स्मार्टफोन, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल, रक्षा आदि क्षेत्रों के लिए आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद करेगी।

रेनेसास की भूमिका और दृष्टिकोण

- वैश्विक विशेषज्ञता: रेनेसास एम्बेडेड सिस्टम्स और सिस्टम-स्तरीय नवाचार में विशेषज्ञ है।
- भारत के लिए रणनीति: डिज़ाइन से लेकर परीक्षण तक की क्षमताओं को भारत में विस्तारित करने की योजना।
- शिक्षा और स्टार्टअप के साथ साझेदारी: Design Linked Incentive (DLI) और Chips to Startup (C2S) जैसी सरकारी योजनाओं के माध्यम से सहयोग।

ऑपरेशन ओलिविया: भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण में सहायता की

समुद्री संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, भारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने अपने वार्षिक अभियान ऑपरेशन ओलिविया के तहत फरवरी 2025 में ओडिशा के रुपिकुल्या नदी मुहाने पर लगभग 6.98 लाख ऑलिव रिडले कछुओं की सफलतापूर्वक रक्षा की। यह अभियान इस प्रजाति के वार्षिक प्रजनन काल के दौरान उनके सुरक्षित अंडे देने के स्थलों को सुनिश्चित कर समुद्री जैव विविधता की रक्षा के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऑलिव रिडले कछुए विश्व स्तर पर एक संवेदनशील प्रजाति माने जाते हैं और उनके संरक्षण हेतु यह पहल वैश्विक स्तर पर सराहनीय कदम है।

समाचार में क्यों?

भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard - ICG) ने 19 मई 2025 को घोषणा की कि उसके वार्षिक मिशन ऑपरेशन ओलिविया (Operation Olivia) के तहत फरवरी 2025 में ओडिशा के रुपिकुल्या नदी मुहाने पर लगभग 6.98 लाख ऑलिव रिडले कछुओं की सफलतापूर्वक रक्षा की गई। यह उपलब्धि समुद्री जैव विविधता संरक्षण में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उद्देश्य और लक्ष्य

- मुख्य उद्देश्य: ऑलिव रिडले कछुओं के सुरक्षित अंडे देने (नेस्टिंग) को सुनिश्चित करना।
- खतरों की रोकथाम: अवैध मछली पकड़ने और आवास नष्ट होने जैसे जोखिमों को कम करना।
- सामुदायिक भागीदारी: स्थानीय मछुआरों, NGOs और टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेज़ (TEDs) जैसी टिकाऊ मछली पकड़ने की तकनीकों को बढ़ावा देना।

पृष्ठभूमि और क्रियान्वयन

- प्रारंभ: 1980 के दशक की शुरुआत में लॉन्च किया गया।
- समय अवधि: हर साल नवंबर से मई तक संचालित।
- मुख्य क्षेत्र: ओडिशा के गहिरमाथा, रुपिकुल्या नदी मुहाना, और अन्य तटीय इलाकों में कछुओं के अंडे देने के समय गश्त और निगरानी।

2025 के प्रमुख उपलब्धियाँ

- 6.98 लाख कछुओं की सुरक्षा फरवरी 2025 में रुपिकुल्या में सुनिश्चित की गई।
- अब तक 5,387 सतही गश्त अभियान और 1,768 हवाई निगरानी मिशन संचालित किए गए।
- 366 अवैध मछली पकड़ने वाली नौकाएं जब्त की गईं।
- कई NGOs के साथ MoU साइन किए गए ताकि संरक्षण और शिक्षा कार्यक्रम चलाए जा सकें।

सामुदायिक और तकनीकी पहल

- मछुआरों के बीच TEDs के उपयोग को प्रोत्साहन।
- स्थानीय समुदायों के साथ जागरूकता कार्यक्रम, सतत जीवनशैली को समर्थन।
- कर्नाटक जैसे राज्यों के सहयोग से कछुओं की जियो-टैगिंग शुरू—उनकी आवाजाही पर निगरानी रखने हेतु।





मिज़ोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना

भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तहत मिज़ोरम को आधिकारिक रूप से देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। यह घोषणा 20 मई 2025 को मिज़ोरम के मुख्यमंत्री श्री लालदूहोमा द्वारा आइज़ोल में आयोजित एक विशेष समारोह में की गई। इस अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। यह उपलब्धि ULLAS - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (New India Literacy Programme) की सफलता और समावेशी शिक्षा के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

क्यों है यह खबरों में?

मिज़ोरम को हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (NILP) के अंतर्गत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। यह मान्यता व्यापक सर्वेक्षण, शिक्षण प्रयासों और समुदाय की भागीदारी के माध्यम से शेष अशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षित करने के बाद प्राप्त हुई है। यह घोषणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सर्वजन साक्षरता के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पृष्ठभूमि और स्थैतिक जानकारी

- राज्य का दर्जा: 20 फरवरी 1987
- क्षेत्रफल: 21,081 वर्ग किमी
- 2011 की जनगणना में साक्षरता दर: 91.33% (भारत में तीसरा स्थान)

प्रमुख बिंदु

- घोषणा की तिथि: 20 मई 2025
- घोषणा करने वाले: मुख्यमंत्री श्री लालदूहोमा
- स्थान: मिज़ोरम विश्वविद्यालय का ऑडिटोरियम, आइज़ोल
- उपस्थित गणमान्य व्यक्ति:
 - श्री जयंतीलाल चौधरी (केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री)
 - डॉ. वानललथलाना (मिज़ोरम के शिक्षा मंत्री)
 - मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारीगण

ULLAS - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम

- शुभारंभ: 2022
- अवधि: 2022-2027
- लक्ष्य समूह: 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के अशिक्षित वयस्क
- दृष्टिकोण: जन जन साक्षर - Literacy for All
- क्रियान्वयन मॉडल: स्वयंसेवी आधारित (कर्तव्य बोध)

ULLAS योजना के प्रमुख घटक

- आधारभूत साक्षरता एवं गणना
- महत्वपूर्ण जीवन कौशल
- प्रारंभिक शिक्षा
- व्यावसायिक प्रशिक्षण
- निरंतर शिक्षा

प्रभाव और आँकड़े

- पहचान किए गए अशिक्षित व्यक्ति (2023 सर्वे): 3,026
- शिक्षा में संलग्न शिक्षार्थी: 1,692
- प्राप्त साक्षरता दर: 98.20% (PFLS 2023-24 के अनुसार)
- स्वयंसेवी शिक्षक: 292 (विद्यार्थी, शिक्षक, क्लस्टर समन्वयक)

- राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत:
 - 2.37 करोड़ से अधिक शिक्षार्थी
 - 40.84 लाख से अधिक स्वयंसेवक (ULLAS मोबाइल ऐप के माध्यम से)

महत्व

- वयस्क कार्यात्मक साक्षरता में राष्ट्रीय मानक स्थापित किया।
- समुदाय आधारित शिक्षा मॉडल को प्रोत्साहन मिला।
- स्वयंसेवकता और जनभागीदारी की शक्ति को दर्शाया।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य-4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) की ओर एक प्रभावशाली कदम।

WHO ने पहली बार वैश्विक महामारी संधि अपनाई

एक ऐतिहासिक पहल के तहत, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 20 मई 2025 को जिनेवा में आयोजित अपनी वार्षिक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के दौरान विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि (Global Pandemic Treaty) को अपनाया। यह संधि 124 देशों के समर्थन, 11 देशों की अनुपस्थिति और किसी भी विरोध के बिना पारित हुई। इसका उद्देश्य भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए समानता आधारित और समन्वित वैश्विक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करना है। हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका — जो 2025 की शुरुआत में WHO से हट चुका है — की अनुपस्थिति इस संधि के कार्यान्वयन और वित्तपोषण को लेकर चिंता पैदा करती है।

क्यों है यह खबरों में?

20 मई 2025 को WHO के सदस्य देशों ने विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि को अपनाया। यह संधि COVID-19 के गंभीर प्रभाव के बाद शुरू हुई तीन वर्षों की बातचीत का परिणाम है। अमेरिका की गैर-भागीदारी के बावजूद, यह वैश्विक स्वास्थ्य शासन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

उद्देश्य और लक्ष्य

- निदान, टीके और उपचार तक समान पहुंच सुनिश्चित करना
- अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य समन्वय और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना
- वन हेल्थ दृष्टिकोण को बढ़ावा देना (मानव, पशु और पौधों के स्वास्थ्य की आपसी कड़ी को पहचानना)
- रोगजनकों की पहुंच और लाभ-साझाकरण प्रणाली स्थापित करना
- स्थानीय उत्पादन और विविध R&D को प्रोत्साहित करना
- प्रौद्योगिकी और ज्ञान हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाना

मुख्य बिंदु

- वोटिंग परिणाम: 124 देशों ने समर्थन किया, 11 देशों ने मतदान से परहेज़ किया, कोई विरोध नहीं
- राष्ट्रीय संप्रभुता बनी रहेगी: WHO इस संधि के माध्यम से किसी देश में लॉकडाउन या वैक्सीनेशन नियम अनिवार्य नहीं बना सकता
- वित्तीय तंत्र: वैश्विक महामारी तैयारी के लिए एक नया फंड स्थापित किया जाएगा
- समानता पर बल: यह संधि उन असमानताओं का समाधान करती है जो कोविड के दौरान देखी गईं, जब अमीर देशों ने चिकित्सा संसाधनों को अधिक मात्रा में संग्रहित कर लिया था





विवादास्पद मुद्दे जिनका समाधान हुआ

- बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights)
- रोगजनक साझा करने की प्रणाली (Pathogen Sharing)
- राष्ट्रीय संप्रभुता बनाम वैश्विक समन्वय

पृष्ठभूमि

- यह विचार दिसंबर 2021 में विशेष विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान सामने आया था, जब कोविड की दूसरी लहर का प्रभाव स्पष्ट था
- Intergovernmental Negotiation Body (INB) ने 13 दौर की बैठकों के बाद ड्राफ्ट तैयार किया
- अंतिम मसौदा अप्रैल 2025 में पूर्ण हुआ

महत्व और प्रभाव

- भविष्य की महामारियों के लिए दुनिया को बेहतर तैयार करता है
- वैश्विक संकटों में बहुपक्षीय सहयोग की शक्ति को दर्शाता है
- प्रतिक्रियाशील से सक्रिय नीति की ओर वैश्विक स्वास्थ्य दृष्टिकोण में परिवर्तन
- यह संधि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य की विजय है, जो वैश्विक स्वास्थ्य असमानता को संबोधित करती है

पीएम मोदी ने 1,100 करोड़ रुपये की योजना के तहत 18 राज्यों में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 18 राज्यों के 86 जिलों में स्थित 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। यह भारत की रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। ₹1,100 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित इन आधुनिक स्टेशनों का उद्देश्य यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाना है — जिसमें आराम, कनेक्टिविटी और सुविधा को बढ़ावा देना प्रमुख है। साथ ही, यह पहल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत का भी उत्सव मनाती है। यह परियोजना 1,300 से अधिक स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी योजना का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य देश की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं के अनुरूप रेलवे अवसंरचना को आधुनिक और सशक्त बनाना है।

यह समाचार में क्यों है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 18 राज्यों के 86 जिलों में स्थित 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। यह परियोजना ₹1,100 करोड़ से अधिक की लागत से पूरी हुई है, और यह भारत के रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसका उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधा, संपर्क और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करना है।

मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य

- रेलवे स्टेशनों का विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचे के साथ आधुनिकीकरण।
- यात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार, विशेष रूप से दिव्यांगजन-हितैषी डिज़ाइन पर बल।
- क्षेत्रीय स्थापत्य शैलियों और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और प्रदर्शित करना।
- सतत विकास और ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करना।
- यात्रा की सुरक्षा, सुविधा और कनेक्टिविटी को बढ़ाना।

घटनाक्रम के मुख्य बिंदु

- पीएम मोदी ने राजस्थान के बीकानेर जिले में देशनोक स्टेशन का उद्घाटन किया।
- बीकानेर-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।
- रेल, सड़क और राज्य स्तरीय परियोजनाओं की ₹26,000 करोड़ से अधिक लागत वाली आधारशिलाएं रखीं।

अमृत भारत स्टेशन योजना - पृष्ठभूमि

- भारतीय रेल द्वारा शुरू की गई योजना, जिसके तहत 1,300+ स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा।
- आधुनिक सुविधाओं के साथ प्रत्येक स्टेशन की सांस्कृतिक पहचान को संजोने पर जोर।
- यात्री यातायात की भविष्य की वृद्धि और संचालन क्षमता सुधार के अनुसार डिज़ाइन किया गया।

प्रमुख आधारभूत परियोजनाएं

रेलवे विद्युतीकरण (कुल ~999 किमी):

- चूरू-सादुलपुर (58 किमी) - शिलान्यासा।
- सूरतगढ़-फलोदी (336 किमी)
- फुलेरा-डीडवाना (109 किमी)
- उदयपुर-हिम्मतनगर (210 किमी)
- फलोदी-जैसलमेर (157 किमी)
- समदड़ी-बाड़मेर (129 किमी)

सड़क अवसंरचना परियोजनाएं

- तीन वाहन अंडरपास और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण।
- राजस्थान में सात सड़क परियोजनाएं - लागत: ₹4,850 करोड़।
- सड़कें भारत-पाक सीमा तक फैलीं, जिससे रक्षा ढांचे और लॉजिस्टिक मूवमेंट को बल मिलेगा।

राज्य विकास योजनाएं - राजस्थान

- राजस्थान में 25 प्रमुख राज्य परियोजनाओं का उद्घाटन/शिलान्यासा।
- प्रमुख क्षेत्र: स्वास्थ्य, जल, संपर्क, बिजली और बुनियादी ढांचा।

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए तीन साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य की

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 20 मई 2025 को एक ऐतिहासिक निर्णय में यह अनिवार्य कर दिया कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पद के लिए आवेदन करने हेतु कम से कम तीन वर्षों का विधिक अभ्यास (legal practice) अनिवार्य होगा। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा दिया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायिक पदों पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों को मुकदमों की व्यावहारिक जानकारी और अनुभव हो, जिससे न्यायपालिका की गुणवत्ता और कार्यकुशलता बेहतर हो सके।

क्यों चर्चा में है?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 20 मई 2025 को एक ऐतिहासिक निर्णय में यह अनिवार्य कर दिया कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पद के लिए आवेदन करने हेतु कम से कम तीन वर्ष का अधिवक्ता अनुभव आवश्यक होगा। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया, जिसका उद्देश्य न्यायपालिका की गुणवत्ता में सुधार करना और न्यायिक पदों के लिए व्यावहारिक अनुभव को प्राथमिकता देना है।





पृष्ठभूमि:

- कई उच्च न्यायालयों ने प्रत्यक्ष रूप से कानून स्रोतों को न्यायिक सेवा में नियुक्ति की अनुमति दी थी, भले ही उनके पास कोई व्यावहारिक अनुभव न हो।
- सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों से प्राप्त हलफनामों की समीक्षा की, जिनमें अनुभवहीन उम्मीदवारों की नियुक्तियों के नकारात्मक प्रभावों की जानकारी दी गई थी।

प्रमुख निर्देश और निर्णय:

- सभी उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को अपनी सेवा नियमावली में संशोधन करना होगा।
- कम से कम तीन वर्ष का अधिवक्ता के रूप में अनुभव अनिवार्य किया गया है।
- अनुभव की गणना बार काउंसिल में अनंतिम नामांकन की तिथि से की जाएगी।

प्रमाणन आवश्यकताएँ:

- उम्मीदवार को अपने अधिवक्ता अनुभव का प्रमाण देना होगा, जो निम्न में से किसी द्वारा प्रमाणित हो:
- संबंधित न्यायालय के प्रधान न्यायिक अधिकारी, या
- कम से कम 10 वर्षों के अनुभव वाले अधिवक्ता, जिनका प्रमाणन किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो।

अतिरिक्त बिंदु:

- न्यायिक अधिकारी या न्यायाधीश के लॉ क्लर्क के रूप में कार्य किया गया अनुभव भी इन तीन वर्षों में गिना जाएगा।
- यह नियम केवल भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं पर लागू होगा, वर्तमान में चल रही भर्तियों पर नहीं।

उद्देश्य और महत्त्व:

- यह सुनिश्चित करता है कि नव नियुक्त न्यायिक अधिकारी न्यायिक कार्यवाही की व्यावहारिक समझ रखते हों।
- न्यायिक प्रणाली को ऐसे अधिकारियों से सशक्त बनाता है जो विधिक प्रक्रिया की जमीनी हकीकत समझते हैं।
- अनुभव की कमी से उत्पन्न त्रुटियों और अक्षमताओं को कम करने का प्रयास है।

7,516 किमी से 11,099 किमी तक: भारत की नई तटीय लंबाई की व्याख्या

भारत सरकार ने अपने भौगोलिक मापदंडों में एक ऐतिहासिक संशोधन करते हुए देश की समुद्र तट रेखा की लंबाई को 7,516.6 किमी से बढ़ाकर 11,098.8 किमी कर दिया है — यानी लगभग 50% की वृद्धि, बिना किसी नई भूमि को जोड़े। यह जानकारी गृह मंत्रालय की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट में सामने आई। यह संशोधन नक्शे की उन्नत तकनीकों के माध्यम से हुआ है, जिससे अब तटीय विशेषताओं की कहीं अधिक सटीक माप संभव हो सकी है। यह भारत की भू-स्थानिक समझ में एक बड़ा बदलाव है और तटीय सुरक्षा, जलवायु योजना और आर्थिक क्षेत्र नियमन के लिए दूरगामी प्रभाव डालता है।

क्यों है यह खबरों में?

दिसंबर 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत की आधिकारिक समुद्री तटरेखा की लंबाई में संशोधन की घोषणा की। इस बदलाव के तहत भारत की तटरेखा की पुरानी लंबाई 7,516.6 किलोमीटर थी, जिसे अब बढ़ाकर 11,098.8 किलोमीटर कर दिया गया है। यह बड़ोतरी किसी नई भूमि के जुड़ने के कारण नहीं हुई है, बल्कि उन्नत मापन तकनीकों जैसे जियोस्पेशियल मैपिंग, सैटेलाइट इमेजिंग, और ड्रोन सर्वेक्षण के प्रयोग से अधिक सटीक गणना की गई है। अब इस आंकड़े की हर 10 वर्षों में समीक्षा की जाएगी। यह संशोधन भारत की तटीय सुरक्षा, जलवायु नीति, आपदा प्रबंधन और भूगोल शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुख्य विशेषताएँ

- घोषणा द्वारा: गृह मंत्रालय (MoHA) ने 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट में की।
- मापन किया: सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस (NHO) द्वारा।
- नई मापन पद्धति: अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया गया, जिनमें शामिल हैं:
 - जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स (GIS)
 - सैटेलाइट अल्टीमीट्री
 - LiDAR-GPS तकनीक
 - ड्रोन-आधारित इमेजिंग
- बेस स्केल: नया स्केल 1:2,50,000 रखा गया, जबकि पहले 1:45,00,000 था।
- संदर्भ रेखा: हाई वॉटर लाइन (HWL), जो 2011 की इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन चार्ट्स पर आधारित है।

कोस्टलाइन पैराडॉक्स की समझ

- यह अवधारणा सबसे पहले लुईस फ्राय रिचर्डसन ने पहचानी थी और बाद में बेनोआ मंडेलब्रोत ने इसे विस्तार दिया।
- किसी समुद्री तट की लंबाई मापन की सटीकता पर निर्भर करती है — जितना सूक्ष्म पैमाना, उतनी अधिक लंबाई।
- समुद्री तट फ्रैक्टल जैसा व्यवहार करते हैं — हर स्तर पर अत्यधिक जटिलता और विस्तार दिखाते हैं।
- उदाहरण: ब्रिटेन की तटरेखा मापने के पैमाने के अनुसार 2,400 किमी से लेकर 3,400 किमी तक भिन्न हो सकती है।

महत्त्व क्यों है?

- समुद्री सुरक्षा (Maritime Security): अब समुद्र तट की लंबाई अधिक होने से रक्षा के लिए क्षेत्र भी बड़ा हो गया है।
- विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ): नई सीमाओं के आधार पर भारत अपने समुद्री आर्थिक क्षेत्र का विस्तार कर सकता है।
- आपदा प्रबंधन (Disaster Management): चक्रवात, बाढ़ और समुद्र स्तर में वृद्धि जैसी आपदाओं से निपटने की योजना अब अधिक सटीक और प्रभावी बन सकेगी।
- जलवायु मॉडलिंग (Climate Modelling): अधिक सटीक तटीय डेटा के आधार पर जलवायु प्रभावों का पूर्वानुमान बेहतर होगा।
- पाठ्यपुस्तक में बदलाव (Textbook Changes): विद्यालयों की भूगोल की पुस्तकों में भारत की नई तटीय लंबाई को शामिल करने की आवश्यकता होगी।





स्थैतिक सामान्य ज्ञान तथ्य

- भारत के पास 11 तटीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश (अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप) हैं।
- भारत से जुड़ने वाला अंतिम तटीय राज्य: गोवा (1961)

एलआईसी ने बीमा बिक्री में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा

एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तहत, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को एक ही दिन में सबसे अधिक जीवन बीमा पॉलिसियां बेचने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। 20 जनवरी 2025 को, LIC ने देशभर में अपनी विशाल एजेंट नेटवर्क के माध्यम से 5,88,107 जीवन बीमा पॉलिसियां बेचीं, जो किसी भी जीवन बीमा कंपनी द्वारा 24 घंटे में हासिल की गई वैश्विक सर्वोच्च बिक्री है।

समाचार में क्यों?

25 मई 2025 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा इस रिकॉर्ड को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई। यह उपलब्धि भारत के बीमा क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर है और LIC की मजबूत पहुंच और व्यापक उपस्थिति को सिद्ध करती है।

पृष्ठभूमि

- LIC एक राज्य स्वामित्व वाली जीवन बीमा कंपनी है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी।
- यह देशभर में करोड़ों लोगों को वित्तीय सुरक्षा और बीमा सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाती है।
- LIC ने हमेशा भारत के जीवन बीमा बाजार में सबसे बड़ा बाजार हिस्सा, उच्चतम पॉलिसीधारक संख्या और जनविश्वास बनाए रखा है।

रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन - 20 जनवरी 2025

- LIC एजेंट्स ने सिर्फ 24 घंटों में 5,88,107 पॉलिसियां बेचीं।
- इस राष्ट्रीय प्रयास में 4,52,839 एजेंट्स ने भाग लिया।
- यह उपलब्धि LIC द्वारा शुरू किए गए "मैड मिलियन डे" अभियान के तहत हासिल की गई।

नेतृत्व पहल

- LIC के CEO और MD सिद्धार्थ मोहंती ने "मैड मिलियन डे" की अवधारणा को जन्म दिया।
- उन्होंने हर एजेंट से उस दिन कम से कम एक पॉलिसी बेचने की अपील की थी।
- इस संगठित प्रयास ने इस विशाल सामूहिक उपलब्धि को संभव बनाया।

उपलब्धि का महत्व

- यह घटना LIC की एजेंट उत्पादकता, संगठनात्मक क्षमता, और कार्यकुशलता को दर्शाती है।
- यह भारतीय जनता के बीच LIC की विश्वसनीयता और सेवाओं पर विश्वास को भी दर्शाती है।
- यह रिकॉर्ड LIC के मिशन — हर नागरिक तक वित्तीय सुरक्षा और बीमा पहुंचाने — का प्रतीक है।

LIC की प्रतिक्रिया

- निगम ने इस मान्यता को लेकर गौरव और आभार प्रकट किया।
- LIC ने इस अद्वितीय सफलता को संभव बनाने में अपने एजेंटों, कर्मचारियों और ग्राहकों के समर्पण और समर्थन को धन्यवाद दिया।

पीएम मोदी ने 10वीं नीति आयोग बैठक की अध्यक्षता की: विकसित भारत @2047 के लिए रोडमैप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 मई 2025 को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक का आयोजन भारत मंडपम, नई दिल्ली में हुआ। इस महत्वपूर्ण बैठक में 24 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री व उपराज्यपाल शामिल हुए। बैठक का विषय था "विकसित राज्य से विकसित भारत @2047", जिसमें भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को लेकर राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय व सहयोग को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया।

समाचार में क्यों?

- नीति आयोग की स्थापना (2015) के 10 वर्ष पूरे होने पर 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक आयोजित।
- भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की रणनीति पर चर्चा (Viksit Bharat @2047)।
- कई नई योजनाओं और पहलों की शुरुआत:
 - ₹60,000 करोड़ की कौशल विकास योजना
 - ₹1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष (Urban Challenge Fund)
 - राज्य स्तरीय निवेश चार्टर, नदी जोड़ परियोजनाएं, और वैश्विक स्तर के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा।

भारत की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश:

- भारत शीर्ष 5 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल।
- 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठाए गए।
- ऑपरेशन सिंदूर और Aspirational Districts Programme की सफलता।

मुख्य बिंदु:

- **विषय:** विकसित राज्य से विकसित भारत @2047
- **स्थान:** भारत मंडपम, नई दिल्ली
- **उपस्थित गण:** 24 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश
- **विशेष श्रद्धांजलि:** पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए मौन

प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य संदेश:

- 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य: हर राज्य, ज़िला, गांव इस दिशा में योगदान दे।
- आर्थिक विकास: भारत अब शीर्ष 5 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में है, परिवर्तन की गति और तेज करनी होगी।
- निर्माण मिशन: घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल।
- निवेश को प्रोत्साहन: नीति आयोग निवेश के अनुकूल चार्टर तैयार करेगा; राज्यों से UAE, UK, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ व्यापार समझौतों का लाभ उठाने का आग्रह।





कौशल विकास और युवाओं को सशक्त बनाना:

- ₹60,000 करोड़ की कौशल विकास योजना को मंजूरी।
- AI, 3D प्रिंटिंग, सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक क्षेत्रों पर ध्यान।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण हब की स्थापना।

शहरी विकास:

- ₹1 लाख करोड़ का Urban Challenge Fund।
- द्वितीय व तृतीय श्रेणी के शहरों में नियोजित विकास।
- शहरों में सतत विकास को प्राथमिकता।

पर्यटन:

- प्रत्येक राज्य को 1 वैश्विक मानक पर्यटन स्थल विकसित करने का निर्देश।
- G20 की मेज़बानी से मिले वैश्विक ध्यान का लाभ उठाने का सुझाव।

जल प्रबंधन:

- बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए नदी ग्रीड की अवधारणा।
- कोसी-मोची नदी जोड़ परियोजना (बिहार) को आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया।

नारी शक्ति (महिला सशक्तिकरण):

- कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु कानूनी और प्रणालीगत सुधार।
- सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में कार्य स्थितियों में सुधार पर ज़ोर।

सिविल सुरक्षा और रक्षा:

- ऑपरेशन सिंदूर की सटीक आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की सराहना।
- दीर्घकालिक सिविल डिफेंस तैयारी को संस्थागत रूप देने का सुझाव।

कृषि:

- विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत।
- 2,500 वैज्ञानिक देशभर में रासायन मुक्त खेती और फसल विविधता को बढ़ावा देंगे।

स्वास्थ्य:

- ई-संजीवनी के ज़रिए टेलीमेडिसिन पर बल।
- कोविड जैसी आपात स्थितियों के लिए ऑक्सीजन संयंत्रों की तैयारियों की समीक्षा।

भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया

भारत ने एक ऐतिहासिक आर्थिक उपलब्धि हासिल करते हुए जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव प्राप्त किया है। 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के साथ, भारत अब केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी से पीछे है। यह उपलब्धि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की निरंतर आर्थिक गति और लचीलापन को दर्शाती है, साथ ही वर्ष 2047 तक "विकसित भारत" (Viksit Bharat) बनने की महत्वाकांक्षा को भी बल देती है।

समाचार में क्यों?

भारत के चौथे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बनने की पुष्टि नीति आयोग के CEO बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के दौरान की, जिसका विषय था - "विकसित राज्य से विकसित भारत 2047"। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गया है।

भारत की आर्थिक छलांग: प्रमुख बिंदु

1. IMF की पुष्टि और वैश्विक रैंकिंग

- IMF की अप्रैल 2025 की World Economic Outlook रिपोर्ट के अनुसार,
- भारत की नाममात्र GDP 4,187.017 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है (वित्त वर्ष 2026 में)।
- वहीं, जापान की GDP 4,186.431 अरब डॉलर रहने की उम्मीद है।
- यह बदलाव भारत की वैश्विक रैंकिंग में पांचवें से चौथे स्थान पर आधिकारिक तौर पर उन्नति को दर्शाता है।

2. विकास दर और आर्थिक मजबूती

- IMF का अनुमान है कि भारत अगले दो वर्षों तक सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा।
- भारत की GDP वृद्धि दर 2025 में 6.2% और 2026 में 6.3% रहने का अनुमान है, जबकि वैश्विक औसत 2025 में 2.8% और 2026 में 3.0% है।
- यह प्रक्षेपण भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का एक प्रमुख इंजन बनाता है।

3. तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में

- बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने भरोसा जताया कि यदि वर्तमान विकास नीतियां और सुधार जारी रहे तो भारत अगले 2 से 3 वर्षों में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।
- इससे भारत केवल अमेरिका और चीन से पीछे रहेगा।

4. विज़न 2047: विकसित भारत

- यह आर्थिक छलांग भारत की दीर्घकालिक विकास योजना "विकसित भारत @2047" के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक एक विकसित देश बनाना है।
- नीति आयोग की बैठक में राज्यों की भूमिका को प्रमुखता दी गई, जिसमें सुधारों, नवाचार, बुनियादी ढांचे और समावेशी विकास पर जोर दिया गया।

भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन उत्तर प्रदेश में शुरू की गई

भारत में वन्यजीव पर्यटन और पर्यावरणीय यात्रा को एक साथ जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने देश की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है। यह ट्रेन दुधवा टाइगर रिज़र्व और कतरनियाघाट वन्यजीव अभयारण्य को जोड़ती है और यात्रियों को पारदर्शी छतों और कांच की खिड़कियों से जंगल का 360-डिग्री नज़ारा देखने का अनोखा अनुभव देती है। यह पहल सतत पर्यटन और जैव विविधता जागरूकता को बढ़ावा देती है।

क्यों है यह ख़बरों में?

26 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च की। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देना और यात्रियों को ट्रेन से ही वन्यजीवों का अनोखा अनुभव प्रदान करना है।





उद्देश्य और योजना

- उद्देश्य: इको-टूरिज्म, वन्यजीव संरक्षण शिक्षा और रेल यात्रा का समावेश
- योजना: "वन गंतव्य, तीन जंगल" (One Destination, Three Forests) के तहत यूपी इको-टूरिज्म बोर्ड की पहल
- लक्ष्य: इको-लकज़री यात्रा, जैव विविधता के प्रति जागरूकता और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना

ट्रेन मार्ग और विवरण

- ट्रेन नंबर 52259: बिछिया (बहराइच) → मेलानी (खीरी)
- समय: 11:45 पूर्वाह्न → 4:10 अपराह्न
- ट्रेन नंबर 52260: मेलानी → बिछिया
- समय: 6:05 पूर्वाह्न → 10:30 पूर्वाह्न
- मार्ग की लंबाई: 107 किमी
- टिकट मूल्य: ₹275 प्रति व्यक्ति
- कुल स्टेशन: 9 (दुधवा, टिकुनिया, पलिया कलां आदि)

जंगल और अभयारण्य कवर किए गए

- दुधवा राष्ट्रीय उद्यान
- कतरनियाघाट वन्यजीव अभयारण्य
- किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य

विस्टाडोम कोच की विशेषताएं

- घुमने वाली आरामदायक सीटें
- बड़ी कांच की खिड़कियाँ और पारदर्शी छत
- हरे-भरे जंगलों का लुभावना दृश्य
- आरामदायक और लकज़री सफारी अनुभव

संरक्षण और शिक्षा पहलें

- यूथ टूरिज्म क्लब: स्कूल छात्रों के लिए साप्ताहिक प्रकृति टूर
- FAM ट्रिप्स: ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए विशेष दौरे
- स्थानीय रोजगार: होमस्टे, रिसॉर्ट्स और नेचर गाइड को बढ़ावा
- यातायात संपर्क: लखनऊ से विशेष लिंक और सब्सिडी योजनाएं

महत्वपूर्ण प्रभाव

- भारत की पहली ट्रेन आधारित जंगल सफारी
- संरक्षण, शिक्षा और पर्यटन का एकीकरण
- कम प्रसिद्ध वन क्षेत्रों को राष्ट्रीय पहचान
- पूरे वर्ष आकर्षण - मानसून में हरियाली, सर्दियों में शांति, हर मौसम में सौंदर्य

भारत ने अपना सबसे शक्तिशाली सिंगल-यूनिट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पेश किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में भारतीय रेलवे के पहले 9000 हॉर्सपावर (HP) वाले इलेक्ट्रिक इंजन का उद्घाटन किया। "मेक इन इंडिया" पहल के तहत सिएमएस इंडिया के सहयोग से विकसित यह शक्तिशाली एकल यूनिट लोकोमोटिव माल परिवहन को क्रांतिकारी रूप से बदलने जा रहा है — इससे भीड़भाड़, टर्नअराउंड समय और संचालन लागत में कमी आएगी।

क्यों है यह समाचारों में?

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाया गया यह 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भारतीय रेलवे के लिए अब तक का सबसे शक्तिशाली एकल यूनिट इंजन है। यह उच्च घनत्व वाले माल गलियारों में लॉजिस्टिक्स की जटिल समस्याओं को हल करने में सहायक होगा और रेलवे अवसंरचना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ी छलांग है।

मुख्य विशेषताएँ और झलकियाँ

- भारतीय रेलवे का पहला एकल यूनिट 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव
- गुजरात के दाहोद में नए निर्माण संयंत्र में तैयार किया गया
- वैश्विक निविदा के माध्यम से सिएमएस इंडिया के साथ साझेदारी में विकसित
- लंबी और भारी मालगाड़ियों को कुशलता से खींचने के लिए डिज़ाइन किया गया
- 'कवच' प्रणाली से लैस — भारत की स्वदेशी ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली

उद्देश्य और लक्ष्य

- व्यस्त माल ढुलाई मार्गों पर भीड़भाड़ कम करना
- टर्नअराउंड समय को घटाना और लॉजिस्टिक कुशलता बढ़ाना
- उद्योगों के लिए परिवहन लागत को कम करना
- मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड विजन को बढ़ावा देना
- स्थानीय रोजगार सृजन और स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन देना

स्थैतिक और पृष्ठभूमि तथ्य

- पारंपरिक मालगाड़ी इंजन आमतौर पर 4500 या 6000 HP के होते हैं
- 12,000 HP इंजन दो 6000 HP यूनिट को जोड़कर बनाए जाते हैं
- दाहोद संयंत्र में 1,200 इलेक्ट्रिक माल लोकोमोटिव बनाए जाएंगे
- 89% पुर्जे भारत में निर्मित, जिससे निर्यात के लिए तैयार
- संयंत्र हरित ऊर्जा द्वारा संचालित, ग्रीन मैनुफैक्चरिंग यूनिट प्रमाणित

महत्व और प्रभाव

- अनेक इंजनों की आवश्यकता को समाप्त करता है — इससे मैनपावर और ऊर्जा की बचत
- तेज़, किफायती और कुशल माल ढुलाई सुनिश्चित करता है
- सतत विकास को बढ़ावा देता है और भारत की निर्यात क्षमता को मजबूत करता है
- आधुनिक चालक केबिन और कम शोर संचालन के कारण सुरक्षा और सुविधा बढ़ाता है
- 85% स्थानीय रोजगार, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनते हैं

भारत के राष्ट्रपति ने अनुकरणीय नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 प्रदान किए

राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भावपूर्ण समारोह में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से देशभर की 15 उत्कृष्ट नर्सिंग पेशेवरों को सम्मानित किया। यह पुरस्कार नर्सों की अटूट समर्पण भावना, करुणा और सेवा भाव को मान्यता देते हैं और भारत में नर्सिंग व मिडवाइफरी पेशे के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों में से एक हैं।





भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ को सम्मान

राष्ट्रीय फ्लोरेस नाइटिंगेल पुरस्कार के बारे में

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित, यह पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स दाइयों (ANM), और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (LHV) को दिया जाता है, जो सार्वजनिक और स्वैच्छिक दोनों क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इसका उद्देश्य रोगी देखभाल, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं और सामुदायिक कल्याण में असाधारण प्रतिबद्धता दिखाने वाले पेशेवरों को सम्मानित करना है।

प्रत्येक पुरस्कार में शामिल हैं:

- एक मेरिट प्रमाण पत्र
- ₹1,00,000 की नकद राशि
- एक पदक, जो नर्सिंग समुदाय की निस्वार्थ सेवा के लिए राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है

वर्ष 2025 के पुरस्कार विजेता

इस वर्ष देश के विभिन्न राज्यों और स्वास्थ्य सेवाओं से 15 नर्सों को सम्मानित किया गया। इनका विविध भौगोलिक और कार्य क्षेत्र भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में नर्सिंग सेवाओं की व्यापकता और विविधता को दर्शाता है।

श्रेणी	नाम	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
ANM	श्रीमती रेबा रानी सरकार	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
ANM	श्रीमती वलिवेटी सुभावती	आंध्र प्रदेश
ANM	श्रीमती सरोज फकीरभाई पटेल	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव
ANM	श्रीमती रज़िया बेगम पी बी	लक्षद्वीप
ANM	श्रीमती सुजाता अशोक बागुल	महाराष्ट्र
LHV	श्रीमती बीना पानी डेका	असम
नर्स	श्रीमती कीजुम सोरा कारगा	अरुणाचल प्रदेश
नर्स	मिस डिंपल अरोड़ा	दिल्ली
नर्स	मेजर जनरल शीना पी डी	दिल्ली
नर्स	डॉ. बनू एम आर	कर्नाटक
नर्स	श्रीमती लैमपोकपम रंजिता देवी	मणिपुर
नर्स	श्रीमती वी लाल्हमंगैही	मिजोरम
नर्स	श्रीमती एल एस मणिमोझी	पुदुच्चेरी
नर्स	श्रीमती अलमेलु मंगयर्करसी के	तमिलनाडु
नर्स	श्रीमती डोली बिस्वास	पश्चिम बंगाल

राज्यवार मई माह की महत्वपूर्ण घटनाएँ

आंध्र प्रदेश

- आंध्र प्रदेश ने अमरावती में भारत के पहले ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर क्रिएटर लैंड का अनावरण किया है, जिसका लक्ष्य डिजिटल नवाचार और रचनात्मक उद्योगों के लिए एक वैश्विक केंद्र बनना है। सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू द्वारा WAVES शिखर सम्मेलन में घोषित, ₹10,000 करोड़ की इस परियोजना से फिल्म निर्माण, गेमिंग, वर्चुअल प्रोडक्शन और AI-संचालित सामग्री जैसे क्षेत्रों में 25,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। इसमें युवा कौशल विकास को बढ़ावा देने और FDI को आकर्षित करने के लिए क्रिएटरलैंड अकादमी भी शामिल होगी, जो भारत के मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी क्षण को चिह्नित करेगी।
- आईबीएम, टीसीएस और आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती में क्वांटम वैली टेक पार्क स्थापित करने के लिए साझेदारी की है, जो भारत की क्वांटम यात्रा में एक ऐतिहासिक कदम है। भारत के सबसे बड़े 156-क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर द्वारा संचालित इस पहल का उद्देश्य अनुप्रयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देना, प्रतिभाओं को आकर्षित करना और औद्योगिक नवाचार को बढ़ावा देना है। यह राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के साथ संरेखित है और आंध्र प्रदेश को वैश्विक क्वांटम क्रांति में अग्रणी के रूप में स्थापित करता है।
- पवन कल्याण के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत क्षेत्रों में सक्रिय रक्षा कर्मियों के स्वामित्व वाले घरों के लिए संपत्ति कर माफ़ी की घोषणा की है। सैनिक कल्याण विभाग द्वारा समर्थित यह कदम मौजूदा लाभों का विस्तार करता है और जम्मू-कश्मीर में शहीद हुए अग्निवीर मुरली नाइक जैसे वीरों को श्रद्धांजलि देता है। यह नीति जीवनसाथी के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली संपत्तियों पर लागू होती है और इसमें सेना, नौसेना, वायु सेना, सीआरपीएफ और अन्य अर्धसैनिक बलों के कर्मी शामिल हैं, जो राष्ट्रीय रक्षा और ग्रामीण कल्याण के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अरुणाचल प्रदेश

- सीईएसएचएस ने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा समर्थित, यह पहल अक्षय ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम है, विशेष रूप से हिमालयी भूभाग में अंतरिक्ष हीटिंग और कृषि-आधारित प्रसंस्करण के लिए। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राज्य सरकार के समर्थन से, यह सफलता दिरांग को भारत का पहला भूतापीय-संचालित शहर बना सकती है, जो स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में क्षेत्र की क्षमता को उजागर करती है।

असम

- पूर्वोत्तर असम के विश्वनाथ जिले में स्थित नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर का दर्जा दिया गया है। यह सम्मान 23 मई, 2025 को विश्व कछुआ दिवस पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान दिया गया। इस कार्यक्रम में कछुओं के संरक्षण में मंदिर के महत्वपूर्ण कार्य का जश्न मनाया गया, जिनका असम की संस्कृति में गहरा सम्मान है।





गुजरात

- प्रधानमंत्री का दाहोद दौरा 24,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई उच्च-प्रभावी विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शुभारंभ के कारण चर्चा में है। मुख्य आकर्षणों में दाहोद से भारत के पहले 9,000-हॉर्सपावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का सफल रोलआउट, गुजरात के रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण और आदिवासी कल्याण से संबंधित घोषणाएँ शामिल हैं, जिनमें 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' और पीएम जनमन योजना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पीएम मोदी ने जम्मू और कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के मजबूत मूल्यों और सैन्य ताकत के प्रतिबिंब के रूप में "ऑपरेशन सिंदूर" की सराहना की।
- गुजरात भारत का 24वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है, जो 2030 तक ग्रीन मोबिलिटी और नेट-जीरो उत्सर्जन के लिए भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित यह मील का पत्थर दाहोद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री के उद्घाटन के साथ जुड़ा हुआ है, जो भारत के पहले 9000 एचपी इलेक्ट्रिक फ्रेट इंजन का उत्पादन करेगा। 16 किमी/दिन की औसत विद्युतीकरण गति के साथ, भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है, केवल स्विट्जरलैंड से पीछे है, और इसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 तक पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण करना है।
- 21 मई, 2025 को गुजरात वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की, जिसमें 2020 से आबादी में 32% की वृद्धि पर प्रकाश डाला गया। यह अपडेट संरक्षण की सफलता और उभरती चुनौतियों, विशेष रूप से मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व दोनों को रेखांकित करता है। यह मार्च 2025 में पीएम मोदी द्वारा शेरों के आवासों को बेहतर बनाने के लिए ₹2,900 करोड़ के परिव्यय के साथ प्रोजेक्ट लायन को मंजूरी देने के बाद आया है।

गोवा

- 30 मई, 2025 को गोवा राज्य गर्व से अपना 39वां राज्य दिवस मनाएगा, जो भारत गणराज्य में एक पूर्ण राज्य के रूप में इसके औपचारिक समावेश के लगभग चार दशक पूरे होने का प्रतीक है। अपने प्राचीन समुद्र तटों, औपनिवेशिक वास्तुकला और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाने वाला गोवा भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में एक अद्वितीय स्थान रखता है।
- 30 मई, 2025 को मनाए जाने वाले गोवा के 39वें राज्य दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने आधिकारिक तौर पर उल्लास - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम) के तहत गोवा को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। यह ऐतिहासिक उपलब्धि गोवा को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित 95% साक्षरता बेंचमार्क को पार करने वाला भारत का दूसरा राज्य बनाती है, जो भारत की शैक्षिक प्रगति में अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि करता है।

महाराष्ट्र

- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वेब्स समिट 2025 में विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी में नवी मुंबई में भारत के पहले एडु सिटी की घोषणा करके एक दूरदर्शी पहल का अनावरण किया। यॉर्क विश्वविद्यालय और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय ने अपतटीय परिसरों की स्थापना के लिए कुल 3,000 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त, प्राइम फोकस और गोदरेज द्वारा एआई-संचालित फिल्म सिटी के लिए मेगा निवेश सुरक्षित किया गया, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार का वादा किया गया और नवी मुंबई को वैश्विक ज्ञान और मनोरंजन केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। यह पहल एनईपी 2020 के अनुरूप है और महाराष्ट्र की आगामी एआई नीति के लिए मंच तैयार करती है।
- महाराष्ट्र सरकार द्वारा अहिल्याबाई होल्कर पर बायोपिक बनाने की घोषणा 2025 में उनकी 300वीं जयंती पर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक श्रद्धांजलि के रूप में की गई है। अपने दूरदर्शी नेतृत्व, धार्मिक योगदान और प्रशासनिक उत्कृष्टता के लिए पहचानी जाने वाली रानी की विरासत को इस फिल्म प्रोजेक्ट के माध्यम से दर्शाया जाएगा। इसे मराठी और अन्य भारतीय भाषाओं में निर्मित किया जाएगा और दूरदर्शन और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जाएगा, जिसका उद्देश्य व्यापक दर्शकों तक पहुंचना और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करना है। यह कदम भारत की ऐतिहासिक महिला नेताओं को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के प्रयासों को भी रेखांकित करता है।
- महाराष्ट्र ने कुपोषण, घरेलू हिंसा, बाल विवाह जैसे प्रमुख सामाजिक मुद्दों से निपटने और शासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 10.50 करोड़ रुपये के बजट के साथ एक व्यापक महिला-केंद्रित कल्याण अभियान आदिशक्ति अभियान शुरू किया है। कई स्तरों पर समितियां इस योजना को लागू करेंगी और वार्षिक पुरस्कार प्रभावी कार्यवाई को प्रोत्साहित करेंगे। यह पहल अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती पर शुरू की गई थी, जो समावेशी और सशक्त समुदायों के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- महाराष्ट्र सरकार ने सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी निर्माण परियोजनाओं के लिए कृत्रिम रेत (एम-सैंड) के उपयोग को अनिवार्य करने वाली एक ऐतिहासिक नीति को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य अवैध नदी रेत खनन को रोकना और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। प्रमुख विशेषताओं में अनिवार्य एम-सैंड का उपयोग, राज्य भर में 1,500 क्रशर की स्थापना, उत्पादकों के लिए एमएसएमई का दर्जा, कम रॉयल्टी (₹200/पीतल) और मौजूदा स्टोन क्रशर के लिए 3 साल का संक्रमण शामिल है। यह कदम एनजीटी के निर्देशों के अनुरूप है, चट्टानी इलाकों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है और गड्ढों को तालाबों में परिवर्तित करके जल संरक्षण का समर्थन करता है।

मिजोरम

- पूर्वोत्तर भारत में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए, मिजोरम की राजधानी आइजोल को बैराबी-सैरांग नई लाइन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है। यह विकास देश के सबसे भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में से एक में क्षेत्रीय एकीकरण और परिवहन संपर्क बढ़ाने के भारत के प्रयासों में एक प्रमुख मील का पत्थर है।





- भारत में शिक्षा के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर, मिजोरम को आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से साक्षर राज्य घोषित किया गया है, यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह घोषणा 20 मई 2025 को मुख्यमंत्री श्री लालदुहोमा द्वारा आइजोल में एक विशेष समारोह के दौरान प्रमुख केंद्रीय और राज्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में की गई थी। यह उपलब्धि समावेशी शिक्षा के लिए राज्य के समर्पण को उजागर करती है और राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा पहल, उल्लास - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की सफलता को चिह्नित करती है।

ओडिशा

- शहरी परिवर्तन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, ओडिशा सरकार ने अंकुर- ज्ञान, शहरीकरण और सुधार के लिए अटल नेटवर्क नामक एक दूरदर्शी पहल शुरू की है। आवास और शहरी विकास (एचएंडयूडी) विभाग की अगुवाई में, अंकुर को शहरी नवाचार को बढ़ावा देने, सहयोगी भागीदारी को बढ़ावा देने और स्मार्ट, टिकाऊ और नागरिक-केंद्रित शहरों का निर्माण करने के लिए एक रणनीतिक मंच के रूप में देखा गया है।

राजस्थान

- कोटा में ओम बिरला द्वारा उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र (पीएमडीके) दिव्यांग नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग है। ALIMCO और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में, यह केंद्र आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए सहायक उपकरण, गतिशीलता सहायता और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है। 100 केंद्रों तक विस्तार करने की दृष्टि से, यह पहल सुलभता, समानता और सामाजिक न्याय के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है।

तेलंगाना

- मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता तेलंगाना में आयोजित की जा रही है, जिसमें इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, यूनेस्को स्थल और इको-टूरिज्म क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा। 120 देशों के प्रतिभागियों और 150 से अधिक देशों में प्रसारण के साथ, इस आयोजन से विदेशी पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा मिलने, वैश्विक निवेश आकर्षित करने और तेलंगाना को बहुआयामी पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने की उम्मीद है। सरकारी प्रयासों में सुरक्षा व्यवस्था, विरासत पर्यटन और प्रचार अभियान शामिल हैं, जो इसे राज्य की वैश्विक ब्रांडिंग के लिए एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में चिह्नित करते हैं।

त्रिपुरा

- पीएमएमएसवाई के तहत त्रिपुरा में ₹42.4 करोड़ की लागत से बनने वाले एकीकृत एक्वापार्क की आधारशिला रखना पूर्वोत्तर क्षेत्र में मत्स्य पालन क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय स्तर पर मत्स्य पालन में 9.08% की प्रभावशाली दर से वृद्धि के साथ, इस पहल का लक्ष्य त्रिपुरा के मछली उत्पादन को 2 लाख टन तक बढ़ाना है, जो इसकी वर्तमान मांग को पार कर जाएगा। यह परियोजना प्रौद्योगिकी-संचालित टिकाऊ खेती, क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देती है, जिसका उद्देश्य त्रिपुरा को मछली अधिशेष राज्य और निर्यातक बनाना है। लॉन्च कार्यक्रम, जिसमें एक मछली महोत्सव भी शामिल था, ने मत्स्य पालन को एक जीवंत, अभिनव और आर्थिक रूप से प्रभावशाली क्षेत्र में बदलने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर किया।

- त्रिपुरा ने 29 मई से 12 जून, 2025 तक चलने वाले अखिल भारतीय कृषि अभियान, विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की घोषणा की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, कृषि लागत को कम करना और ICAR तथा KVK विशेषज्ञों की मदद से गांव-स्तर पर लोगों तक पहुँच बनाकर सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह कदम 2047 तक विकसित भारत (विकसित भारत) के सपने को पूरा करता है।
- रेल मंत्रालय ने अगरतला और गुवाहाटी के बीच एक नई ट्रेन सेवा को मंजूरी दे दी है, जो पूर्वोत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की जरूरत को पूरा करेगी। त्रिपुरा पश्चिम के सांसद बिप्लव कुमार देब द्वारा घोषित, यह विकास त्रिपुरा के पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की शुरुआत के तुरंत बाद हुआ है। यह कदम भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप है, हरित परिवहन को बढ़ावा देता है, और अंतरराज्यीय रेल संपर्क को बढ़ाता है।

तमिलनाडु

- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने घोषणा की कि 5 मई को व्यापारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिससे व्यापारिक समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई। कई सुधार पेश किए गए, जैसे कि वित्तीय सहायता में वृद्धि, सरलीकृत विनियामक प्रक्रियाएँ और शिकायत निवारण पैनल का गठन। व्यापारियों को तमिल साइनेज का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। इन कदमों का उद्देश्य छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाना, सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना और द्रविड़ शासन मॉडल के तहत व्यापार करने में आसानी को मजबूत करना है।
- तमिलनाडु लुप्तप्राय प्रजाति संरक्षण कोष, जिसे 2024 में ₹50 करोड़ की राशि के साथ शुरू किया गया था, को राज्य वन विकास एजेंसी (SFDA) की निष्क्रिय स्थिति के कारण प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। देरी से बचने के लिए, अब इस कोष को उन्नत वन्यजीव संरक्षण संस्थान (AIWC), बंडालूर में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो अपने शोध और वन्यजीव पहलों के लिए जाना जाता है। इस कोष का उद्देश्य मानचित्रण, शोध अनुदान और साझेदारी के माध्यम से मालाबार सिवेट और सलीम अली के फ्रूट बैट जैसी प्रजातियों की रक्षा करना है। यह कदम जैव विविधता संरक्षण के प्रति तमिलनाडु की प्रतिबद्धता को पुनर्जीवित करता है।
- तमिलनाडु सरकार ने राज्य को अंतरिक्ष अनुसंधान, विनिर्माण और नवाचार के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक समर्पित अंतरिक्ष औद्योगिक नीति शुरू की है। 10,000 करोड़ रुपये के निवेश और 10,000 नई नौकरियों के लक्ष्य के साथ, नीति में अनुसंधान और विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स और हरित प्रौद्योगिकी में कंपनियों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन शामिल हैं। मौजूदा ISRO बुनियादी ढांचे और संस्थागत समर्थन का लाभ उठाकर, तमिलनाडु का लक्ष्य भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान देना है।





उत्तराखंड

- पुष्कर कुंभ 2025 उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा गांव में स्थित केशव प्रयाग में 12 साल के अंतराल के बाद शुरू हुआ, जो बृहस्पति के मिथुन राशि में प्रवेश के साथ ही शुरू हुआ। यह आयोजन अलकनंदा और सरस्वती नदियों के संगम पर, विशेष रूप से दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों के लिए एक प्रमुख आध्यात्मिक समागम है। डीएम संदीप तिवारी के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को समायोजित करने के लिए बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार और प्रबंधन प्रावधान किए हैं। यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ाता है बल्कि भारत के विविध सांस्कृतिक ताने-बाने को भी मजबूत करता है।

उत्तर प्रदेश

- 11 मई, 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन सुविधा का वर्चुअल उद्घाटन किया। ₹300 करोड़ के निवेश से निर्मित इस सुविधा का लक्ष्य सालाना 80-100 ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन करना है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच रक्षा विनिर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 नए उत्पाद जोड़कर अपनी एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना का विस्तार किया है, जिससे 75 जिलों में कुल 74 उत्पाद हो गए हैं। 2018 में शुरू की गई ODOP योजना का उद्देश्य स्वदेशी शिल्प को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना और निर्यात को बढ़ाना है। यह योजना वित्तीय सहायता, विपणन और जीआई टैगिंग के माध्यम से कारीगरों का समर्थन करती है, जिसका दीर्घकालिक लक्ष्य 2029 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। यह नवीनतम समावेश स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करता है, आत्मनिर्भर भारत के साथ संरेखित करता है और मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करता है।

केंद्र शासित प्रदेश

- दिल्ली पुलिस ने 'नई दिशा- सीखने की राह पर वापसी' नामक सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है, जिसे स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली में वापस लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। गैर सरकारी संगठनों, स्कूलों और परामर्शदाताओं की मदद से, यह पहल प्रवेश सहायता, भावनात्मक मार्गदर्शन और शैक्षणिक सहायता प्रदान करती है। यह पुलिसिंग में पारंपरिक प्रवर्तन से सामाजिक सशक्तिकरण की ओर एक आदर्श बदलाव को उजागर करता है। यह परियोजना पहले से ही परिणाम दे रही है और इसे पूरे शहर में विस्तारित करने की तैयारी है।
- जम्मू और कश्मीर में स्थायी परिवहन और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने चिनाब (एनडब्ल्यू-26), झेलम (एनडब्ल्यू-49) और रावी (एनडब्ल्यू-84) के साथ अंतर्देशीय नौवहन अवसंरचना विकसित करने के लिए श्रीनगर में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत इस पहल का उद्देश्य नदी-आधारित संपर्क को बढ़ाना, रसद लागत को कम करना और केंद्र शासित प्रदेश में रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

मई माह के शुभारंभ और उद्घाटन

- भारत सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025 शुरू की है, जिसके तहत दुर्घटना के बाद 7 दिनों तक सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ₹1.5 लाख की कैशलेस आपातकालीन देखभाल की पेशकश की जाती है। 6 मई, 2025 को अधिसूचित इस योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा लागू किया जाता है और इसमें पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ समन्वय शामिल है। यह पहल एक महत्वपूर्ण सड़क सुरक्षा उपाय है, जिसका उद्देश्य मृत्यु दर को कम करना और देश भर में आघात देखभाल को सस्ती और सुलभ बनाना है।
- भारत सरकार ने अपने सर्कुलर इकोनॉमी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित गैर-लौह धातु रीसाइक्लिंग पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी की अगुवाई में शुरू की गई यह पहल हितधारकों को वास्तविक समय में डेटा साझा करने, पंजीकरण और प्रदर्शन निगरानी में शामिल होने के लिए वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। इससे पारदर्शिता बढ़ाने, नीति को सूचित करने और औद्योगिक भागीदारी में सुधार करके भारत के स्थायी धातु रीसाइक्लिंग प्रयासों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- 10 मई, 2025 को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेड सेंटर (आईएचसी) में भारत बोध केंद्र का उद्घाटन किया। हैबिटेड लाइब्रेरी और रिसोर्स सेंटर के हिस्से के रूप में विकसित इस केंद्र का उद्देश्य कला, दर्शन, आध्यात्मिकता और इतिहास पर संसाधनों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत को बढ़ावा देना है। मंत्री ने आईएचसी की हरित पहल की प्रशंसा की और इसकी स्थायी प्रथाओं को व्यापक रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उम्मीद है कि यह केंद्र सांस्कृतिक शोध, विरासत शिक्षा और सार्वजनिक शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा।
- भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने और आतंकवाद विरोधी समन्वय को मजबूत करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत एक महत्वपूर्ण रूप से संशोधित मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) शुरू किया है। अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया गया नया MAC देश भर की 28 प्रमुख एजेंसियों को जोड़ता है और AI, ML और GIS क्षमताओं को एकीकृत करता है। यह आतंकवाद, नक्सलवाद, संगठित अपराध और साइबर युद्ध सहित जटिल खतरों से निपटने के लिए निर्बाध डेटा साझाकरण, उन्नत खतरे की भविष्यवाणी और एकीकृत प्रतिक्रिया तंत्र का वादा करता है। इस रणनीतिक उन्नयन को भारत के आंतरिक सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है।
- फ्यूचर शिफ्ट लैब्स के सहयोग से NCW द्वारा शुरू किया गया यथोदा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का एक अग्रणी प्रयास है। यह कार्यक्रम ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को लक्षित करता है, उन्हें भारत के डिजिटल भविष्य में आगे बढ़ने और नेतृत्व करने के लिए महत्वपूर्ण कौशल प्रदान करता है। AI-संचालित अपराधों और डिजिटल





गोपनीयता जैसे प्रमुख मुद्दों को संबोधित करके, यशोदा AI एक समुदाय-संचालित दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है जहाँ महिलाएँ प्रौद्योगिकी में अग्रणी और नवप्रवर्तक के रूप में उभरती हैं, जिससे एक सुरक्षित, समावेशी और तकनीकी रूप से उन्नत भारत बनाने में मदद मिलती है।

- पंचायती राज मंत्रालय ने 26-27 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की राइटशॉप के दौरान PAI 2.0 लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य ग्राम पंचायत स्तर पर बेहतर डेटा-संचालित शासन सुनिश्चित करना है। उन्नत सूचकांक निगरानी संकेतकों को काफी सरल बनाता है, पोर्टल की उपयोगिता में सुधार करता है, और इसमें निर्णय सहायता प्रणाली और ऑटो-डेटा एकीकरण जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण भी दिया गया और कार्यान्वयन के अनुभव साझा किए गए, जिससे राज्यों में प्रभावी रूप से इसे अपनाया जाना सुनिश्चित हुआ। PAI 2.0 स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों (LSDG) के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है और इससे ग्रामीण नियोजन और शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- भारत सरकार ने डाक विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 के तहत भू-स्थानिक शासन और पता अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 'अपना डिजिपिन जानें' और 'अपना पिन कोड जानें' पोर्टल लॉन्च किए हैं। जहाँ डिजिपिन आईआईटी हैदराबाद और इसरो के सहयोग से एक सटीक, डिजिटल, जियो-कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम प्रदान करता है, वहीं उन्नत पिन कोड सिस्टम डाक भूगोल को परिष्कृत करने के लिए जीएनएसएस का लाभ उठाता है। ये प्लेटफॉर्म अंतिम-मील डिलीवरी, आपातकालीन प्रतिक्रिया और डिजिटल सेवा समावेशन को बढ़ाने के लिए तैयार हैं, जो भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) का एक मुख्य हिस्सा है।
- भारत सरकार ने डाक विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 के तहत भू-स्थानिक शासन और पता अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 'अपना डिजिपिन जानें' और 'अपना पिन कोड जानें' पोर्टल लॉन्च किए हैं। जहाँ डिजिपिन आईआईटी हैदराबाद और इसरो के सहयोग से एक सटीक, डिजिटल, जियो-कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम प्रदान करता है, वहीं उन्नत पिन कोड सिस्टम डाक भूगोल को परिष्कृत करने के लिए जीएनएसएस का लाभ उठाता है। ये प्लेटफॉर्म अंतिम-मील डिलीवरी, आपातकालीन प्रतिक्रिया और डिजिटल सेवा समावेशन को बढ़ाने के लिए तैयार हैं, जो भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) का एक मुख्य हिस्सा है।

महत्वपूर्ण त्यौहार

- 78वें फेस्टिवल डे कान्स की शुरुआत सिनेमा के समृद्ध उत्सव के साथ हुई, जिसमें रॉबर्ट डी नीरो जैसे कलाकारों को सम्मानित किया गया और फातिमा हसौना जैसी आवाजों को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में कला, स्वतंत्रता और लोकतंत्र की शक्ति पर जोर दिया गया, जिसमें जूलियट बिनोचे, लियोनार्डो डि कैप्रियो और डी नीरो के प्रेरक भाषण शामिल थे। क्वेंटिन टारनटिनो जैसी सांस्कृतिक हस्तियों के साथ, यह उत्सव समावेशिता, प्रतिनिधित्व और सिनेमा को प्रतिरोध और आशा के माध्यम के रूप में बढ़ावा देता है।

विविध राष्ट्रीय समाचार

- जनरेटिव एआई (GenAI) क्षेत्रों में महिलाओं की कम भागीदारी को दूर करने के उद्देश्य से फेसबुक इंडिया (अब मेटा) की पहली कर्मचारी और पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर किर्तिगा रेड्डी ने एक महिला-केंद्रित एआई प्लेटफॉर्म AI किरण की घोषणा की है। यह पहल भारतीय महिलाओं को एआई के क्षेत्र में जोड़ने, मार्गदर्शन देने, आर्थिक सहायता प्रदान करने और प्रमाणित करने का कार्य करेगी। इसका विशेष फोकस स्वास्थ्य, शिक्षा और सततता जैसे प्रभावशाली क्षेत्रों पर रहेगा। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारतीय महिलाओं को वैश्विक एआई क्रांति के केंद्र में स्थापित करना है।
- नेशनल सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) भारत की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग (HPC) के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। इस मिशन की शुरुआत 2015 में की गई थी और इसका मकसद भारत की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना है। इसके तहत देशभर के शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में सुपरकंप्यूटर स्थापित किए जा रहे हैं। ये सुपरकंप्यूटर नेशनल नॉलेज नेटवर्क (NKN) के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान, विकास और नवाचार के लिए व्यापक स्तर पर पहुँच और सहयोग सुनिश्चित होता है।
- सतत शहरी नदी प्रबंधन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने रिवर सिटीज़ एलायंस (RCA) के तहत एक्शन प्लान 2025 को मंजूरी दी है। यह योजना क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और सहयोगात्मक शहरी शासन के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रस्तुत करती है, जिसका उद्देश्य शहर नियोजन में नदी-संवेदनशील प्रथाओं को शामिल करना है। जल शक्ति मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त पहल RCA में अब 145 शहर शामिल हो चुके हैं, जो समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से नदियों के पुनर्जीवन के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- पारदर्शिता को बढ़ावा देने के प्रयास में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले अपने 21 सेवार्त न्यायाधीशों की संपत्ति का खुलासा किया है। यह कदम महत्वपूर्ण न्यायिक सूचनाओं तक जनता की पहुँच बढ़ाने के न्यायालय के चल रहे प्रयासों के अनुरूप है।
- मई 2025 में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए देश के जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) क्षेत्र में कई चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण रोगाणुनाशकों (एंटीमाइक्रोबियल्स) के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। यह कदम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) को लेकर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर उठाया गया है, जो खाद्य उत्पादन, विशेष रूप से मछली पालन में एंटीबायोटिक के दुरुपयोग से उत्पन्न होती है। इस प्रतिबंध में कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स और एंटीप्रोटोजोआल्स शामिल हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और भारत के समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।
- एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, वियतनाम ने अपने वैश्विक स्वरूप को एक अल्पकालिक पर्यटन स्थल से एक सतत व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र में बदलने की दिशा में पहल की है। इसके तहत वियतनाम ने एक 10 वर्षीय गोल्डन वीजा पेश किया है, जिसका उद्देश्य विदेशी निवेशकों, पेशेवरों और दीर्घकालिक पर्यटकों, विशेष रूप से भारत से आने वालों को आकर्षित करना है। यह वीजा नीति वियतनाम की नवाचार, आर्थिक





साझेदारी और दक्षिण-पूर्व एशिया में अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता को बढ़ावा देने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

- “ऑपरेशन सिंदूर” के तहत की गई जवाबी सैन्य कार्रवाई के बाद, भारत ने 7 मई 2025 को अस्थायी रूप से करतारपुर कॉरिडोर को बंद कर दिया। यह कॉरिडोर भारतीय तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान स्थित दरबार साहिब गुरुद्वारे तक वीजा-मुक्त पहुँच प्रदान करता है। भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में स्थित आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले करने के बाद, सुरक्षा कारणों से इसे एक दिन के लिए निलंबित किया गया।
- कोझिकोड को WHO के वैश्विक वृद्ध-अनुकूल शहरों और समुदायों के नेटवर्क (GNAFCC) में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। यह मान्यता शहर के वृद्धजन समुदाय के लिए समावेशी, सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण संकेत है, जो शहरी वृद्ध देखभाल और सुलभता के वैश्विक मानकों के अनुरूप है।
- भारत ने 7 मई 2025 की रात एक साहसिक और सटीक सैन्य अभियान के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर गहरे हवाई हमले किए। इस अभियान को “ऑपरेशन सिंदूर” नाम दिया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं पर्यवेक्षण किया और इसका प्रतीकात्मक नाम भी उन्होंने ही दिया। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की जवाबी कार्रवाई थी, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी, जिनमें आम नागरिकों के साथ एक भारतीय नौसेना अधिकारी भी शामिल थे। यह हवाई हमला 1971 के युद्ध के बाद पहली बार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के भीतर गहराई तक किया गया सैन्य कदम था, जो भारत के आतंकवाद के प्रति “ज़ीरो टॉलरेंस” रुख को दर्शाता है।
- भारत ने आधिकारिक रूप से चिप-आधारित ई-पासपोर्ट की शुरुआत कर दी है, जो यात्रा दस्तावेजों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये नए पासपोर्ट, जो RFID चिप और बायोमेट्रिक डेटा से लैस हैं, अंतरराष्ट्रीय यात्रा को अधिक सुरक्षित, कुशल और सुविधाजनक बनाने का उद्देश्य रखते हैं। इस कदम के साथ भारत अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे उन देशों की कतार में शामिल हो गया है, जो पहले ही उन्नत ई-पासपोर्ट तकनीक अपना चुके हैं।
- संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-निरोधक कार्यालय (UNOCT) ने 28 अप्रैल 2025 को **Victims of Terrorism Advocacy Network (VoTAN)** की औपचारिक शुरुआत की। यह एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य आतंकवादी घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों के लिए एक सहायक, सुरक्षित और सशक्त मंच प्रदान करना है।
- पूर्वोत्तर भारत में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज़ (CESHS) ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में पहला जियोथर्मल उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक ड्रिल किया है। यह उपलब्धि ऊँचाई वाले क्षेत्रों में भू-तापीय ऊर्जा की संभावनाओं के दोहन में एक बड़ी सफलता है और क्षेत्र में पर्यावरण-अनुकूल हीटिंग एवं कृषि प्रसंस्करण तकनीकों को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त करती है।

- भारत में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने 7 मई 2025 को नॉन-फेरस मेटल रीसाइक्लिंग वेबसाइट और स्टेकहोल्डर्स पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल राष्ट्रीय नॉन-फेरस मेटल स्कैप रीसाइक्लिंग फ्रेमवर्क के तहत विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य एल्यूमिनियम, तांबा (कॉपर), सीसा (लेड), जस्ता (जिंक) तथा अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक पारदर्शी, संगठित और एकीकृत रीसाइक्लिंग पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है।
- रूस ने महान भारतीय नेता और विमान चालक बिजू पटनायक को सम्मानित करते हुए नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया। यह सम्मान उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के स्टालिनग्राद युद्ध के दौरान उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया है। इस अवसर पर ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव उपस्थित थे। हालाँकि बिजू पटनायक को अक्सर उनके राजनीतिक योगदान के लिए जाना जाता है, लेकिन युद्धकालीन पायलट के रूप में उन्होंने घिरे हुए रेड आर्मी के लिए आपूर्ति पहुँचाने का जो साहसिक कार्य किया था, उसने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और ऐतिहासिक पहचान दिलाई है।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) की 62वीं कार्यकारी समिति (EC) की बैठक में गंगा नदी बेसिन के पुनर्जीवन और सतत प्रबंधन को लेकर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। राजीव कुमार मित्तल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली से जुड़ी पहलों को अपनाने पर जोर दिया गया, जिनमें वेटलैंड संरक्षण (आर्द्रभूमि) और गंदे पानी के पुनः उपयोग जैसे उपाय शामिल हैं। यह निर्णय नमामि गंगे मिशन के प्रमुख उद्देश्यों के अनुरूप है और एक स्वच्छ और टिकाऊ गंगा पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में अहम कदम है, जिससे पर्यावरण और जल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार होगा।
- भारत में व्यापार शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT), नई दिल्ली के एक ऑफ-कैंपस केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह नया केंद्र गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT City), गांधीनगर में स्थित होगा। यह रणनीतिक निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के उद्देश्यों का समर्थन करता है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में बहु-विषयक शिक्षा और क्षमताविकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है।
- भारत सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए ₹1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए एक प्रमुख राष्ट्रव्यापी योजना शुरू की है। 5 मई, 2025 से शुरू होने वाली यह नीति दुर्घटना के बाद पहले सात दिनों के भीतर तत्काल आघात देखभाल तक पहुँच को सक्षम बनाती है, जिसका उद्देश्य जीवित रहने की दर में सुधार करना है।
- पारदर्शिता को बढ़ावा देने के प्रयास में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले अपने 21 सेवार्त न्यायाधीशों की संपत्ति का खुलासा किया है। यह कदम महत्वपूर्ण न्यायिक सूचनाओं तक जनता की पहुँच बढ़ाने के न्यायालय के चल रहे प्रयासों के अनुरूप है।





- मई 2025 में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए देश के जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) क्षेत्र में कई चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण रोगाणुनाशकों (एंटीमाइक्रोबियल्स) के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। यह कदम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) को लेकर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर उठाया गया है, जो खाद्य उत्पादन, विशेष रूप से मछली पालन में एंटीबायोटिक के दुरुपयोग से उत्पन्न होती है। इस प्रतिबंध में कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोरल्ल्स और एंटीप्रोटोजोआल्स शामिल हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और भारत के समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।
- एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, वियतनाम ने अपने वैश्विक स्वरूप को एक अल्पकालिक पर्यटन स्थल से एक सतत व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र में बदलने की दिशा में पहल की है। इसके तहत वियतनाम ने एक 10 वर्षीय गोल्डन वीजा पेश किया है, जिसका उद्देश्य विदेशी निवेशकों, पेशेवरों और दीर्घकालिक पर्यटकों, विशेष रूप से भारत से आने वालों को आकर्षित करना है। यह वीजा नीति वियतनाम की नवाचार, आर्थिक साझेदारी और दक्षिण-पूर्व एशिया में अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता को बढ़ावा देने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
- “ऑपरेशन सिंदूर” के तहत की गई जवाबी सैन्य कार्रवाई के बाद, भारत ने 7 मई 2025 को अस्थायी रूप से करतारपुर कॉरिडोर को बंद कर दिया। यह कॉरिडोर भारतीय तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान स्थित दरबार साहिब गुरुद्वारे तक वीजा-मुक्त पहुँच प्रदान करता है। भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में स्थित आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले करने के बाद, सुरक्षा कारणों से इसे एक दिन के लिए निलंबित किया गया।
- कोझिकोड को WHO के वैश्विक वृद्ध-अनुकूल शहरों और समुदायों के नेटवर्क (GNAFCC) में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। यह मान्यता शहर के वृद्धजन समुदाय के लिए समावेशी, सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण संकेत है, जो शहरी वृद्ध देखभाल और सुलभता के वैश्विक मानकों के अनुरूप है।
- भारत ने 7 मई 2025 की रात एक साहसिक और सटीक सैन्य अभियान के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर गहरे हवाई हमले किए। इस अभियान को “ऑपरेशन सिंदूर” नाम दिया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं पर्यवेक्षण किया और इसका प्रतीकात्मक नाम भी उन्होंने ही दिया। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की जवाबी कार्रवाई थी, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी, जिनमें आम नागरिकों के साथ एक भारतीय नौसेना अधिकारी भी शामिल थे। यह हवाई हमला 1971 के युद्ध के बाद पहली बार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के भीतर गहराई तक किया गया सैन्य कदम था, जो भारत के आतंकवाद के प्रति “ज़ीरो टॉलरेंस” रुख को दर्शाता है।
- भारत ने आधिकारिक रूप से चिप-आधारित ई-पासपोर्ट की शुरुआत कर दी है, जो यात्रा दस्तावेजों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये नए पासपोर्ट, जो RFID चिप और बायोमेट्रिक डेटा से लैस हैं, अंतरराष्ट्रीय यात्रा को अधिक सुरक्षित, कुशल और सुविधाजनक बनाने का उद्देश्य रखते हैं। इस कदम के साथ भारत अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे उन देशों की कतार में शामिल हो गया है, जो पहले ही उन्नत ई-पासपोर्ट तकनीक अपना चुके हैं।
- संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-निरोधक कार्यालय (UNOCT) ने 28 अप्रैल 2025 को Victims of Terrorism Advocacy Network (VoTAN) की औपचारिक शुरुआत की। यह एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य आतंकवादी घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों के लिए एक सहायक, सुरक्षित और सशक्त मंच प्रदान करना है।
- पूर्वोत्तर भारत में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज़ (CESHS) ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में पहला जियोथर्मल उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक ड्रिल किया है। यह उपलब्धि ऊँचाई वाले क्षेत्रों में भू-तापीय ऊर्जा की संभावनाओं के दोहन में एक बड़ी सफलता है और क्षेत्र में पर्यावरण-अनुकूल हीटिंग एवं कृषि प्रसंस्करण तकनीकों को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त करती है।
- भारत में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने 7 मई 2025 को नॉन-फेरस मेटल रीसाइक्लिंग वेबसाइट और स्टेकहोल्डर्स पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल राष्ट्रीय नॉन-फेरस मेटल स्कैप रीसाइक्लिंग फ्रेमवर्क के तहत विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य एल्युमिनियम, तांबा (कॉपर), सीसा (लेड), जस्ता (जिंक) तथा अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक पारदर्शी, संगठित और एकीकृत रीसाइक्लिंग पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है।
- रूस ने महान भारतीय नेता और विमान चालक बिजू पटनायक को सम्मानित करते हुए नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया। यह सम्मान उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के स्टालिनग्राद युद्ध के दौरान उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया है। इस अवसर पर ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव उपस्थित थे। हालाँकि बिजू पटनायक को अक्सर उनके राजनीतिक योगदान के लिए जाना जाता है, लेकिन युद्धकालीन पायलट के रूप में उन्होंने घिरे हुए रेड आर्मी के लिए आपूर्ति पहुँचाने का जो साहसिक कार्य किया था, उसने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और ऐतिहासिक पहचान दिलाई है।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) की 62वीं कार्यकारी समिति (EC) की बैठक में गंगा नदी बेसिन के पुनर्जीवन और सतत प्रबंधन को लेकर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। राजीव कुमार मित्तल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली से जुड़ी पहलों को अपनाने पर जोर दिया गया, जिनमें बेटलैंड संरक्षण (आर्द्रभूमि) और गंदे पानी के पुनः उपयोग जैसे उपाय शामिल हैं। यह निर्णय नमामि गंगे मिशन के प्रमुख उद्देश्यों के अनुरूप है और एक स्वच्छ और टिकाऊ गंगा पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में अहम कदम है, जिससे पर्यावरण और जल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार होगा।
- भारत में व्यापार शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय विदेश व्यापार





संस्थान (HIFT), नई दिल्ली के एक ऑफ-कैंपस केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह नया केंद्र गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT City), गांधीनगर में स्थित होगा। यह रणनीतिक निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के उद्देश्यों का समर्थन करता है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में बहु-विषयक शिक्षा और क्षमताविकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है।

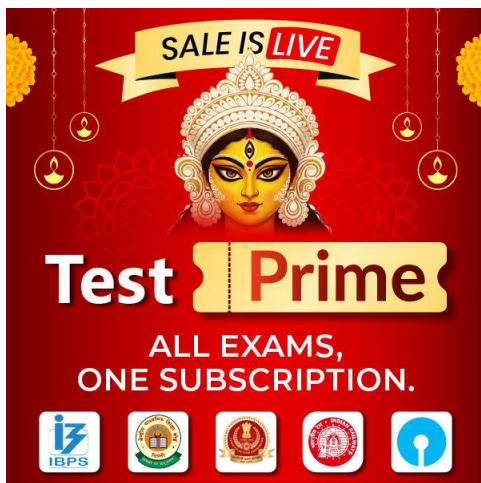
- भारत सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए ₹1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए एक प्रमुख राष्ट्रव्यापी योजना शुरू की है। 5 मई, 2025 से शुरू होने वाली यह नीति दुर्घटना के बाद पहले सात दिनों के भीतर तत्काल आघात देखभाल तक पहुँच को सक्षम बनाती है, जिसका उद्देश्य जीवित रहने की दर में सुधार करना है।
- पारदर्शिता को बढ़ावा देने के प्रयास में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले अपने 21 सेवारत न्यायाधीशों की संपत्ति का खुलासा किया है। यह कदम महत्वपूर्ण न्यायिक सूचनाओं तक जनता की पहुँच बढ़ाने के न्यायालय के चल रहे प्रयासों के अनुरूप है।
- मई 2025 में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए देश के जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) क्षेत्र में कई चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण रोगाणुनाशकों (एंटीमाइक्रोबियल्स) के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। यह कदम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) को लेकर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर उठाया गया है, जो खाद्य उत्पादन, विशेष रूप से मछली पालन में एंटीबायोटिक के दुरुपयोग से उत्पन्न होती है। इस प्रतिबंध में कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स और एंटीप्रोटोजोआल्स शामिल हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और भारत के समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।
- एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, वियतनाम ने अपने वैश्विक स्वरूप को एक अल्पकालिक पर्यटन स्थल से एक सतत व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र में बदलने की दिशा में पहल की है। इसके तहत वियतनाम ने एक 10 वर्षीय गोल्डन वीजा पेश किया है, जिसका उद्देश्य विदेशी निवेशकों, पेशेवरों और दीर्घकालिक पर्यटकों, विशेष रूप से भारत से आने वालों को आकर्षित करना है। यह वीजा नीति वियतनाम की नवाचार, आर्थिक साझेदारी और दक्षिण-पूर्व एशिया में अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता को बढ़ावा देने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
- “ऑपरेशन सिंदूर” के तहत की गई जवाबी सैन्य कार्रवाई के बाद, भारत ने 7 मई 2025 को अस्थायी रूप से करतारपुर कॉरिडोर को बंद कर दिया। यह कॉरिडोर भारतीय तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान स्थित दरबार साहिब गुरुद्वारे तक वीजा-मुक्त पहुँच प्रदान करता है। भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में स्थित आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले करने के बाद, सुरक्षा कारणों से इसे एक दिन के लिए निलंबित किया गया।

- कोझिकोड को WHO के वैश्विक वृद्ध-अनुकूल शहरों और समुदायों के नेटवर्क (GNAFCC) में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। यह मान्यता शहर के वृद्धजन समुदाय के लिए समावेशी, सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण संकेत है, जो शहरी वृद्ध देखभाल और सुलभता के वैश्विक मानकों के अनुरूप है।
- भारत ने 7 मई 2025 की रात एक साहसिक और सटीक सैन्य अभियान के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर गहरे हवाई हमले किए। इस अभियान को “ऑपरेशन सिंदूर” नाम दिया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं पर्यवेक्षण किया और इसका प्रतीकात्मक नाम भी उन्होंने ही दिया। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की जवाबी कार्रवाई थी, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी, जिनमें आम नागरिकों के साथ एक भारतीय नौसेना अधिकारी भी शामिल थे। यह हवाई हमला 1971 के युद्ध के बाद पहली बार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के भीतर गहराई तक किया गया सैन्य कदम था, जो भारत के आतंकवाद के प्रति “ज़ीरो टॉलरेंस” रख को दर्शाता है।
- भारत ने आधिकारिक रूप से चिप-आधारित ई-पासपोर्ट की शुरुआत कर दी है, जो यात्रा दस्तावेजों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये नए पासपोर्ट, जो RFID चिप और बायोमेट्रिक डेटा से लैस हैं, अंतरराष्ट्रीय यात्रा को अधिक सुरक्षित, कुशल और सुविधाजनक बनाने का उद्देश्य रखते हैं। इस कदम के साथ भारत अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे उन देशों की कतार में शामिल हो गया है, जो पहले ही उन्नत ई-पासपोर्ट तकनीक अपना चुके हैं।
- संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-निरोधक कार्यालय (UNOCT) ने 28 अप्रैल 2025 को Victims of Terrorism Advocacy Network (VoTAN) की औपचारिक शुरुआत की। यह एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य आतंकवादी घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों के लिए एक सहायक, सुरक्षित और सशक्त मंच प्रदान करना है।
- पूर्वोत्तर भारत में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज़ (CESHS) ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में पहला जियोथर्मल उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक ड्रिल किया है। यह उपलब्धि ऊँचाई वाले क्षेत्रों में भू-तापीय ऊर्जा की संभावनाओं के दोहन में एक बड़ी सफलता है और क्षेत्र में पर्यावरण-अनुकूल हीटिंग एवं कृषि प्रसंस्करण तकनीकों को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त करती है।
- भारत में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने 7 मई 2025 को नॉन-फेरस मेटल रीसाइक्लिंग वेबसाइट और स्टेकहोल्डर्स पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल राष्ट्रीय नॉन-फेरस मेटल स्कैप रीसाइक्लिंग फ्रेमवर्क के तहत विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य एल्यूमिनियम, तांबा (कॉपर), सीसा (लेड), जस्ता (ज़िंक) तथा अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक पारदर्शी, संगठित और एकीकृत रीसाइक्लिंग पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है।





- रूस ने महान भारतीय नेता और विमान चालक बिजू पटनायक को सम्मानित करते हुए नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया। यह सम्मान उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के स्टालिनग्राद युद्ध के दौरान उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया है। इस अवसर पर ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव उपस्थित थे। हालाँकि बिजू पटनायक को अक्सर उनके राजनीतिक योगदान के लिए जाना जाता है, लेकिन युद्धकालीन पायलट के रूप में उन्होंने घिरे हुए रेड आर्मी के लिए आपूर्ति पहुँचाने का जो साहसिक कार्य किया था, उसने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और ऐतिहासिक पहचान दिलाई है।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) की 62वीं कार्यकारी समिति (EC) की बैठक में गंगा नदी बेसिन के पुनर्जीवन और सतत प्रबंधन को लेकर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। राजीव कुमार मित्तल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली से जुड़ी पहलों को अपनाने पर जोर दिया गया, जिनमें वेटलैंड संरक्षण (आर्द्रभूमि) और गंदे पानी के पुनः उपयोग जैसे उपाय शामिल हैं। यह निर्णय नमामि गंगे मिशन के प्रमुख उद्देश्यों के अनुरूप है और एक स्वच्छ और टिकाऊ गंगा पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में अहम कदम है, जिससे पर्यावरण और जल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार होगा।
- भारत में व्यापार शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT), नई दिल्ली के एक ऑफ-कैंपस केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह नया केंद्र गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT City), गांधीनगर में स्थित होगा। यह रणनीतिक निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के उद्देश्यों का समर्थन करता है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में बहु-विषयक शिक्षा और क्षमताविकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है।
- भारत सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए ₹1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए एक प्रमुख राष्ट्रव्यापी योजना शुरू की है। 5 मई, 2025 से शुरू होने वाली यह नीति दुर्घटना के बाद पहले सात दिनों के भीतर तत्काल आघात देखभाल तक पहुँच को सक्षम बनाती है, जिसका उद्देश्य जीवित रहने की दर में सुधार करना है।



राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स: अप्रैल 2025

माह की महत्वपूर्ण खबरें

संसद ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया

संसद ने 26 मार्च 2025 को बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया, जिससे भारत के बैंकिंग क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए। यह विधेयक दिसंबर 2024 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और अब इसे राज्यसभा में ध्वनि मत से मंजूरी मिली। इस संशोधन के तहत, बैंक खाता धारक अब चार नामांकित व्यक्ति (नोमिनी) जोड़ सकते हैं, जिससे वित्तीय योजना में अधिक लचीलापन आएगा। इसके अलावा, 'महत्वपूर्ण हित' (Substantial Interest) की परिभाषा को संशोधित कर इसकी सीमा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹2 करोड़ कर दी गई, जो लगभग छह दशकों के बाद हुआ बड़ा बदलाव है। विधेयक में सहकारी बैंकों के निदेशकों के कार्यकाल, वैधानिक लेखा परीक्षक (Auditor) के पारिश्रमिक, तथा नियामक अनुपालन रिपोर्टिंग तिथियों को भी संशोधित किया गया है।

मुख्य प्रावधान

1. चार नामांकित व्यक्ति (Nominee) जोड़ने की सुविधा

- अब बैंक खाता धारक चार नामांकित व्यक्ति जोड़ सकते हैं, जबकि पहले केवल एक ही नोमिनी की अनुमति थी।
- यह नियम कैश और फिक्स्ड डिपॉजिट दोनों पर लागू होगा।
- लॉकर खातों के लिए सिर्फ संयुक्त नामांकन (Simultaneous Nomination) की अनुमति दी गई है।

2. 'महत्वपूर्ण हित' की नई परिभाषा

- बैंक में 'Substantial Interest' की सीमा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹2 करोड़ कर दी गई है।
- यह बदलाव 60 वर्षों के बाद किया गया, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में बड़े निवेशकों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

3. सहकारी बैंकों में सुधार

- निदेशकों का कार्यकाल (चेयरमैन और पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़कर) 8 साल से बढ़ाकर 10 साल किया गया।
- अब राज्य सहकारी बैंकों के बोर्ड में केंद्रीय सहकारी बैंकों के निदेशक भी शामिल हो सकते हैं।

4. बैंकिंग क्षेत्र में निगरानी और अनुपालन सुधार

- बैंकों को लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक (Auditor Remuneration) तय करने में अधिक लचीलापन दिया गया।
- नियामक रिपोर्टिंग की तिथियां अब हर महीने की 15वीं और अंतिम तिथि होंगी, पहले यह दूसरे और चौथे शुक्रवार को होती थी।

5. जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों (Wilful Defaulters) पर कड़ी कार्रवाई

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीए (Non-Performing Assets) को कम करने और जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता दोहराई।





- पिछले 5 वर्षों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा 112 बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच की गई।

6. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले वित्त वर्ष में ₹1.41 लाख करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा अर्जित किया।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 में और अधिक लाभ वृद्धि की उम्मीद है।

7. व्यापक बैंकिंग सुधार

- यह संशोधन पांच अलग-अलग बैंकिंग कानूनों को प्रभावित करता है, जिससे यह बैंकिंग इतिहास में एक ऐतिहासिक सुधार माना जा रहा है। यह विधेयक भारत के बैंकिंग क्षेत्र को अधिक पारदर्शी, लचीला और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उत्तराखंड में सरकार ने बदले 15 स्थानों के नाम

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिलों में 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की। यह निर्णय जनभावनाओं और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप लिया गया है। सरकार का उद्देश्य महान ऐतिहासिक व्यक्तियों को सम्मान देना और राज्य के लोगों में प्रेरणा जगाना है।

संस्कृति और जनभावना से जुड़ा निर्णय

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इन स्थानों के नए नाम उन महापुरुषों के सम्मान में रखे गए हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा और उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राज्य सरकार के अनुसार, यह बदलाव जनसामान्य की मांग और ऐतिहासिक महत्व के आधार पर किया गया है।

उत्तराखंड में बदले गए स्थानों की सूची

चार जिलों—हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में स्थानों के नाम बदले गए हैं।

हरिद्वार जिले में बदले गए नाम:

- औरंगजेबपुर → शिवाजी नगर
- गाजीवाली → आर्य नगर
- चांदपुर → ज्योतिबा फुले नगर
- मोहम्मदपुर जाट → मोहनपुर जाट
- खानपुर कुर्सीली → अंबेडकर नगर
- इंद्रिशपुर → नंदपुर
- खानपुर → श्रीकृष्णपुर
- अकबरपुर फजलपुर → विजय नगर

देहरादून जिले में बदले गए नाम:

- मियांवाला → रामजी वाला
- पीरवाला → केशरी नगर
- चांदपुर खुर्द → पृथ्वीराज नगर
- अब्दुल्ला नगर → दक्ष नगर

नैनीताल जिले में बदले गए नाम:

- नवाबी रोड → अटल मार्ग
- पंचक्री से आईटीआई रोड → गुरु गोलवलकर मार्ग

ऊधम सिंह नगर जिले में बदला गया नाम:

- सुल्तानपुर पट्टी नगर पालिका → कौशल्या पुरी

नाम परिवर्तन के पीछे के प्रमुख कारण:

- ऐतिहासिक व्यक्तियों को सम्मान – शिवाजी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों के नाम से स्थानों का नामकरण, उनके योगदान का सम्मान करने के लिए किया गया।
- सांस्कृतिक पहचान की पुनर्स्थापना – मुगलकालीन और औपनिवेशिक युग के नामों को हटाकर भारतीय संस्कृति के अनुरूप नाम दिए गए।
- जनभावनाओं का सम्मान – लंबे समय से स्थानीय लोगों द्वारा नाम परिवर्तन की मांग की जा रही थी, जिसे सरकार ने पूरा किया।
- राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव – इस कदम को संस्कृति संरक्षण का प्रयास माना जा रहा है, हालांकि कुछ आलोचकों का कहना है कि केवल नाम बदलने से बुनियादी विकास से जुड़े मुद्दे हल नहीं होंगे।

नाम परिवर्तन का प्रभाव:

- संस्कृति का पुनरुत्थान – लोगों को अपनी ऐतिहासिक जड़ों से जोड़ने में मदद मिलेगी।
- शैक्षिक महत्व – नई पीढ़ी को ऐतिहासिक महापुरुषों के बारे में जानने का अवसर मिलेगा।
- राजनीतिक प्रभाव – सरकार को संस्कृति संरक्षक के रूप में प्रस्तुत करने में सहायक होगा।
- स्थानीय भावना का उत्थान – क्षेत्रीय गौरव और ऐतिहासिक चेतना को बल मिलेगा।

संसद ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया

राज्यसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को 12 घंटे की विस्तृत चर्चा के बाद मंजूरी दे दी, जिसमें पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। यह मंजूरी लोकसभा द्वारा 288-232 मतों से विधेयक पारित किए जाने के एक दिन बाद मिली।

भारतीय संसद ने हाल ही में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार और उनकी निगरानी को मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण विधायी उपाय पारित किए हैं। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 पर संसद के दोनों सदनों में बहस हुई और उन्हें मंजूरी दी गई। 12 घंटे की मैराथन बहस के बाद शुक्रवार तड़के इसे राज्यसभा ने पारित कर दिया। पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोटों के साथ, विधेयक को उच्च सदन से मंजूरी मिली, गुरुवार को लोकसभा में 288-232 वोटों से इसे मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, राज्यसभा ने मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 को भी 17 घंटे की बैठक के बाद पारित कर दिया, जिसे सुबह 4 बजे स्थगित कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु

विधेयक का उद्देश्य

- वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के कामकाज को सुव्यवस्थित करना तथा पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करना है।
- इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की देखरेख करने वाले प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करना तथा उनके कानूनी ढांचे को बढाना है।





लोकसभा/राज्यसभा में पारित

- वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास (यूएमईईडी) विधेयक रखा गया।
- मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक 2024 को मंजूरी दी गई, जो मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को निरस्त करेगा।

संसदीय प्रक्रिया

- यह विधेयक 12 घंटे की बहस के बाद राज्यसभा में 128-95 मतों से पारित हुआ, जबकि लोकसभा में इसे 288-232 मतों से मंजूरी मिली थी।
- इस बहस में सांसदों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिसमें वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग तथा विवादों के समाधान में न्यायाधिकरणों की भूमिका पर चर्चा हुई।

मंत्रिस्तरीय वक्तव्य

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने संसदीय बहस के दौरान विधेयक और इसके प्रावधानों का बचाव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक 2024

पृष्ठभूमि

दो विधेयक प्रस्तुत किये गये,

- वक्फ (संशोधन) विधेयक
- मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक

उद्देश्य

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025

- वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में चुनौतियों के समाधान के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन किया जाएगा।
- वक्फ बोर्डों के प्रशासन और दक्षता में सुधार करना।

मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024

- मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को निरस्त किया जाए, जो एक पुराना औपनिवेशिक युग का कानून है।
- वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत वक्फ संपत्ति प्रबंधन में एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- पुराने कानून द्वारा उत्पन्न विसंगतियों और अस्पष्टताओं को दूर करना।

'वक्फ' का अर्थ

- इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियां।
- संपत्ति की बिक्री या अन्य उपयोग निषिद्ध है।
- स्वामित्व अल्लाह को हस्तांतरित हो जाता है, जिससे यह अपरिवर्तनीय हो जाता है।
- वाकिफ (निर्माता) की ओर से मुतवल्ली द्वारा प्रबंधित।

'वक्फ' की अवधारणा की उत्पत्ति

- इसका इतिहास दिल्ली सल्तनत काल से जुड़ा है, जब सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद को कई गांव समर्पित किए थे।
- भारत में इस्लामी राजवंशों के उदय के साथ वक्फ संपत्तियों में भी वृद्धि हुई।

- मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम, 1913 ने भारत में वक्फ को संरक्षण प्रदान किया।

संवैधानिक ढांचा और शासन

- धर्मार्थ और धार्मिक संस्थाएं संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं।
- संसद और राज्य विधानमंडल दोनों इस पर कानून बना सकते हैं।
- वक्फ शासन: वक्फ अधिनियम, 1995 द्वारा शासित, जो 1913, 1923 और 1954 के पूर्ववर्ती कानूनों का स्थान लेता है।

वक्फ का निर्माण

द्वारा निर्मित,

- घोषणा (मौखिक या लिखित विलेख)।
- धार्मिक या धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए भूमि का दीर्घकालिक उपयोग।
- उत्तराधिकार की एक पंक्ति के अंत के बाद दान।

सर्वाधिक वक्फ संपत्ति वाले राज्य

- उत्तर प्रदेश (27%)
- पश्चिम बंगाल (9%)
- पंजाब (9%)

वक्फ कानूनों का विकास

- 1913 अधिनियम: वक्फ विलेखों को वैध बनाया गया।
- 1923 अधिनियम: वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य बनाया गया।
- 1954 अधिनियम: केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई।
- 1995 अधिनियम: निर्वाचित सदस्यों और इस्लामी विद्वानों के साथ विवाद समाधान के लिए न्यायाधिकरण की शुरुआत की गई।

नये विधेयक में प्रमुख संशोधन

केंद्रीय वक्फ परिषद संरचना

- वक्फ के प्रभारी केंद्रीय मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं।

सदस्यों में शामिल हैं

- संसद सदस्य (एमपी)
- राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति
- सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश
- मुस्लिम कानून के प्रख्यात विद्वान
- नया प्रावधान: गैर-मुस्लिम सदस्य आवश्यक (दो)

वक्फ बोर्डों की संरचना

- राज्य सरकारों को प्रत्येक समूह से एक व्यक्ति को नामित करने का अधिकार देना।
- गैर-मुस्लिम सदस्य आवश्यक (दो)।
- इसमें शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्ग से एक-एक सदस्य शामिल हैं।
- दो मुस्लिम महिला सदस्यों की आवश्यकता है।

न्यायाधिकरणों की संरचना

- मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ को हटा दिया गया।
- जिला न्यायालय के न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया गया।
- संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी।





न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील

- पूर्ववर्ती अधिनियम : कोई अपील की अनुमति नहीं थी।
- नया विधेयक: न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की अनुमति देता है।

संपत्तियों का सर्वेक्षण

- वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण की देखरेख के लिए सर्वेक्षण आयुक्त के स्थान पर जिला कलेक्टर या वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

वक्फ के रूप में सरकारी संपत्ति

- वक्फ के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रहेगी।
- कलेक्टर द्वारा राजस्व अभिलेख अद्यतन किये गये।

ऑडिट

- एक लाख रुपये से अधिक आय वाली वक्फ संस्थाओं का राज्य प्रायोजित लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया जाएगा।

केंद्रीकृत पोर्टल

- बेहतर कार्यकुशलता और पारदर्शिता के लिए केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से स्वचालित वक्फ संपत्ति प्रबंधन।

संपत्ति समर्पण

- धार्मिक आस्था रखने वाले मुसलमान (कम से कम पांच वर्ष) अपनी संपत्ति वक्फ को समर्पित कर सकते हैं, जिससे 2013 से पहले के नियम बहाल हो जाएंगे।

महिलाओं की विरासत

- महिलाओं को वक्फ घोषणा से पहले उत्तराधिकार प्राप्त करना होगा।
- विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए विशेष प्रावधान।

विधेयक की आवश्यकता

- मुकदमेबाजी को कम करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वक्फ संपत्तियों की एकीकृत डिजिटल सूची।
- वक्फ बोर्डों में महिलाओं को अनिवार्य रूप से शामिल करके लैंगिक न्याय सुनिश्चित किया गया है।

चिंताएं

वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्य

- राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य किया गया।
- चिंता यह है कि इन निकायों में मुख्य रूप से गैर-मुस्लिम लोग शामिल हो सकते हैं, जबकि हिंदू और सिख बंदोबस्ती बोर्डों में ऐसे ही बोर्ड हैं।

वक्फ न्यायाधिकरणों पर प्रभाव

- वक्फ न्यायाधिकरणों से मुस्लिम कानून के विशेषज्ञों को हटाने से विवाद समाधान प्रभावित हो सकता है।

वक्फ का निर्माण

- वक्फ निर्माण को कम से कम पांच वर्षों तक इस्लाम का पालन करने वाले मुसलमानों तक सीमित करना।
- इस पांच-वर्षीय मानदंड के पीछे तर्क के बारे में अस्पष्टता।

निष्कर्ष

- यह विधेयक भारत में वक्फ संपत्ति प्रबंधन में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- प्रस्तावित सुधार बेहतर प्रशासन, जवाबदेही और अधिक समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित करेंगे, जिससे सभी संबंधित समुदायों को लाभ होगा।

बिम्सटेक: पूर्ण स्वरूप, सदस्य देश, उद्देश्य और क्षेत्रीय सहयोग का महत्व

छठा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल, 2025 को बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान, बिम्सटेक सदस्य देशों के नेताओं ने क्षेत्रीय विकास और एकीकरण के उद्देश्य से छह प्रमुख परिणामों को मंजूरी दी, साथ ही 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साझा दृष्टिकोण भी अपनाया।

बिम्सटेक (BIMSTEC) क्या है?

बिम्सटेक का पूर्ण रूप है बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation)। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों को एक साथ लाकर आर्थिक विकास, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

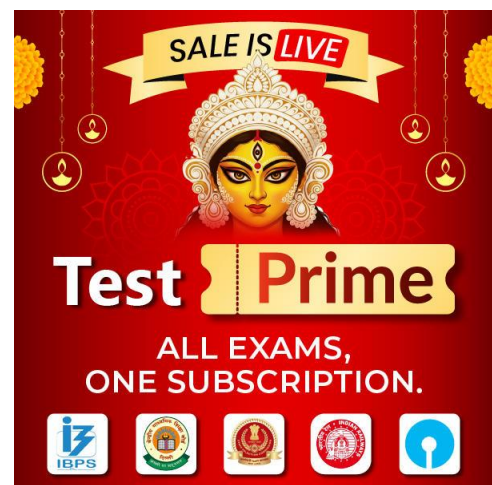
स्थापना की तिथि: 6 जून 1997

मूल नाम: BIST-EC (Bangladesh, India, Sri Lanka, and Thailand Economic Cooperation)

वर्तमान नाम: BIMSTEC (जुलाई 2004 में पहले शिखर सम्मेलन के दौरान बदला गया)

संस्थापक सदस्य देश (1997)

1. बांग्लादेश
2. भारत
3. श्रीलंका
4. थाईलैंड





बैंकोंक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रमुख प्रतिनिधि:

- अबुल हसन चौधरी (बांग्लादेश)
- सलीम इकबाल शेर्वानी (भारत)
- डी. पी. विक्रमसिंघे (श्रीलंका)
- पिटक इन्द्रावित्यानुन्त (थाईलैंड)

सदस्यता का विस्तार

म्यांमार:

- 22 दिसंबर 1997 को शामिल हुआ
- इसके बाद नाम बदला गया – BIMST-EC

नेपाल और भूटान:

- दोनों फरवरी 2004 में शामिल हुए
- जुलाई 2004 में पहले शिखर सम्मेलन में नाम BIMSTEC रख दिया गया

वर्तमान सदस्य देश (7 देश)

1. बांग्लादेश
2. भूटान
3. भारत
4. म्यांमार
5. नेपाल
6. श्रीलंका
7. थाईलैंड

ये सभी देश बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित हैं और सामरिक व आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

बिस्मटेक के मुख्य उद्देश्य

बिस्मटेक का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना और सदस्य देशों के बीच आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है।

विस्तृत उद्देश्य:

- आर्थिक विकास: व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, परिवहन, पर्यटन, ऊर्जा और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर तेज़ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- सामाजिक प्रगति: सतत और समावेशी विकास के माध्यम से क्षेत्रीय जनता के जीवन स्तर को सुधारना।
- तकनीकी सहयोग: विज्ञान और तकनीक में नवाचार को बढ़ावा देना और डिजिटल विकास के लिए सहयोग करना।
- कनेक्टिविटी: भौतिक, डिजिटल और जनसंपर्क आधारित कनेक्टिविटी को मजबूत करना ताकि क्षेत्रीय एकीकरण को गति मिले।
- ऊर्जा सहयोग: ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पारस्परिक ऊर्जा खोज, व्यापार और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास में सहयोग।
- आपदा प्रबंधन व जलवायु परिवर्तन: प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु संकटों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ावा देना।
- सुरक्षा व आतंकवाद विरोध: क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराधों से मिलकर मुकाबला करना।

बिस्मटेक का महत्व

- रणनीतिक स्थान: बंगाल की खाड़ी दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ती है, जिससे बिस्मटेक इन दोनों क्षेत्रों के बीच एक सेतु की भूमिका निभाता है।
- SAARC का विकल्प: SAARC में लंबे समय से गतिरोध के चलते बिस्मटेक एक अधिक सक्रिय और प्रभावी मंच बनकर उभरा है।
- विकास पर केंद्रित: यह संगठन न केवल आर्थिक विकास पर बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय सततता पर भी समान रूप से ध्यान देता है, जो इसे अन्य क्षेत्रीय संगठनों से अलग बनाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान - मिश्रा विभूषण से सम्मानित किया गया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और श्रीलंका के बीच दीर्घकालिक ऐतिहासिक संबंधों और मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, मिश्रा विभूषण से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया।

5 अप्रैल, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, मिश्रा विभूषण से सम्मानित किया गया। कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में आयोजित एक समारोह के दौरान राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। यह प्रतिष्ठित सम्मान दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती और सहयोग का प्रतिबिंब है।

प्रमुख बिंदु

पुरस्कार विवरण

- मिश्रा विभूषण श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसे पहली बार 2008 में शुरू किया गया था।
- इससे पहले यह सम्मान मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम और फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात को दिया जा चुका है।
- पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और नौ प्रकार के श्रीलंकाई रत्नों से सुसज्जित एक रजत पदक शामिल है।
- पदक के डिजाइन में कमल, ग्लोब, सूर्य, चंद्रमा और चावल के ढेर जैसे प्रतीक अंकित हैं, जो भारत और श्रीलंका की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं।

ऐतिहासिक महत्व

- पदक पर अंकित धर्म चक्र साझी बौद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करता है जिसने दोनों देशों की सांस्कृतिक परंपराओं को आकार दिया है।
- चावल के ढेरों से युक्त पुन कलश या औपचारिक बर्तन समृद्धि और नवीनीकरण का प्रतीक है।
- नवरत्न (नौ बहुमूल्य रत्न) को कमल की पंखुड़ियों से घिरे एक ग्लोब के अंदर दर्शाया गया है।





मोदी की टिप्पणी

- मोदी ने कहा कि यह पुरस्कार भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का प्रतिबिंब है।
- उन्होंने कहा कि मिश्रा विभूषण प्राप्त करना न केवल उनके लिए बल्कि 1.4 अरब भारतीयों के लिए भी सम्मान की बात है।

मोदी की अंतर्राष्ट्रीय पहचान

मोदी को 15 से अधिक देशों द्वारा राजकीय सम्मान प्रदान किया गया है, जिनमें शामिल हैं,

- सऊदी अरब के राजा अब्दुल अजीज का आदेश
- फिलिस्तीन राज्य का आदेश
- संयुक्त अरब अमीरात का ऑर्डर ऑफ जायद
- ऑर्डर ऑफ फिजी
- मिस्र का नील नदी का आदेश

मार्च 2025 में, मॉरीशस ने देश की यात्रा के दौरान मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया।

समारोह विवरण

- यह समारोह कोलंबो स्थित राष्ट्रपति सचिवालय में हुआ।
- राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया।

भारत-श्रीलंका ने भविष्य के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारत और श्रीलंका ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के बीच इस तरह का पहला समझौता है। यह पहल लगभग 40 वर्षों बाद आई है, जब भारतीय शांति सेना (IPKF) को श्रीलंका में गृहयुद्ध के दौरान तैनात किया गया था। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलंबो यात्रा और श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ हुई चर्चाओं के दौरान संपन्न हुआ। यह दोनों देशों के बीच साझा रणनीतिक दृष्टिकोण और सुरक्षा व विकास के मामलों में बढ़ती परस्पर निर्भरता को दर्शाता है। यह समझौता रक्षा, ऊर्जा, डिजिटल सहयोग और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में केंद्रित दस प्रमुख समझौतों के व्यापक ढांचे का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच साझेदारी को और गहरा करना है।

भारत-श्रीलंका रक्षा समझौता और अन्य समझौतों के प्रमुख बिंदु:

रक्षा सहयोग

- यह रक्षा सहयोग पर पहला फ्रेमवर्क समझौता जापान (MoU) है।
- इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रम और उच्च स्तरीय वार्तालाप शामिल हैं।
- यह इस विचार को सुदृढ़ करता है कि दोनों देशों की सुरक्षा एक-दूसरे से जुड़ी हुई है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका द्वारा भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता को रेखांकित किया।
- राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने आश्वासन दिया कि श्रीलंकाई भूमि का उपयोग भारत के विरुद्ध नहीं होने दिया जाएगा।

ऊर्जा और अवसंरचना

संपूर पावर प्रोजेक्ट

- इस परियोजना की शिलान्यास समारोह वर्चुअली आयोजित की गई।
- यह परियोजना श्रीलंका की ऊर्जा सुरक्षा को सशक्त बनाएगी।
- मल्टी-प्रोडक्ट ऊर्जा पाइपलाइन परियोजना
- भारत, श्रीलंका और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समझौता जापान (MoU) पर हस्ताक्षर।
- त्रिकोमाली को ऊर्जा हब के रूप में विकसित करने की योजना।
- ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी समझौता
- भारत और श्रीलंका की बिजली ग्रिड को जोड़ने का प्रस्ताव।
- इससे बिजली व्यापार और विद्युत निर्यात की संभावनाएं बढ़ेंगी।

डिजिटल परिवर्तन

- भारत और श्रीलंका के बीच डिजिटल गवर्नेंस समाधानों को साझा करने के लिए समझौता जापान (MoU) पर हस्ताक्षर।
- श्रीलंका के डिजिटल परिवर्तन को तेज करने का उद्देश्य।

नवीकरणीय ऊर्जा पहल

सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट

- 5,000 धार्मिक स्थलों पर रूफटॉप सोलर पैनलों की स्थापना की जाएगी।
- भारत द्वारा 17 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता से वित्तपोषित।
- 25 मेगावॉट हरित ऊर्जा उत्पन्न होगी।
- इसमें हिंदू, बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम धार्मिक स्थलों को शामिल किया गया है।

स्वास्थ्य और औषधि

MoU के तहत साझेदारी

- भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और
- श्रीलंका के स्वास्थ्य और मास मीडिया मंत्रालय के बीच।
- उद्देश्य: स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग।

अलग समझौता जापान

- इंडियन फार्माकोपिया कमीशन और
- श्रीलंका की नेशनल मेडिसिन्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के बीच।
- औषधीय मानकों और प्रथाओं में सहयोग सुनिश्चित करने के लिए।

क्षेत्रीय समर्थन और विकास

- भारत ने 2.4 अरब श्रीलंकाई रुपये की सहायता योजना की घोषणा की।
- श्रीलंका के पूर्वी प्रांतों के सामाजिक और आर्थिक विकास पर केंद्रित।

प्रधानमंत्री मोदी ने नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु में नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया, जो भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। यह देश का पहला वर्टिकल-लिफ्ट समुद्री पुल है, जो सौ साल पुराने पंबन ब्रिज का स्थान लेता है और आधुनिक इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। यह पुल रामेश्वरम द्वीप को मांडपम (मुख्य भूमि) से जोड़ता है और इसे टिकाऊपन व तकनीकी उत्कृष्टता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इसका उद्घाटन राम नवमी के पावन दिन और श्रीलंका से प्रधानमंत्री मोदी की वापसी के साथ हुआ, जहां उन्होंने राम सेतु का हवाई दर्शन भी किया। यह दिन आध्यात्मिक और संरचनात्मक दोनों दृष्टियों से भारत के लिए विशेष बन गया।





नए पंबन ब्रिज की प्रमुख विशेषताएं:

नया पंबन ब्रिज

- उद्घाटन तिथि: 6 अप्रैल 2025 (राम नवमी)
- उद्घाटनकर्ता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
- स्थान: रामनाथपुरम जिला, तमिलनाडु
- उद्देश्य: रामेश्वरम द्वीप को मांडपम (मुख्य भूमि) से जोड़ना

ब्रिज की तकनीकी विशेषताएं

- कुल लंबाई: 2.07 किमी
- निर्माण लागत: ₹700 करोड़ से अधिक
- कार्यकारी एजेंसी: रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL), एक नवरत्न PSU
- डिज़ाइन प्रकार: वर्टिकल-लिफ्ट ब्रिज
- लिफ्ट स्पैन: 72.5 मीटर (17 मीटर तक ऊँचा किया जा सकता है, ताकि जहाज़ निकल सकें)
- ट्रैक क्षमता: दो रेलवे ट्रैकों के लिए डिज़ाइन, फिलहाल एक चालू
- ट्रेन गति क्षमता: 80 किमी/घंटा तक
- आयु: 100 वर्षों तक टिकाऊ

उन्नत निर्माण तकनीक

- स्टेनलेस स्टील रिइंफोर्समेंट
- पूरी तरह वेल्डेड जोड़
- समुद्री जंग से सुरक्षा के लिए हाई-ग्रेड पेंट व पॉलिसिलॉक्सेन कोटिंग
- न्यूनतम रख-रखाव वाला डिज़ाइन

वैश्विक तुलना व महत्व

- गोल्डन गेट ब्रिज (USA),
- टॉवर ब्रिज (UK),
- ओरेसुंड ब्रिज (डेनमार्क-स्वीडन) जैसी प्रतिष्ठित संरचनाओं से तुलना
- आधुनिक भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक

प्रधानमंत्री मोदी के अन्य कार्यक्रम

- एक नए तटरक्षक जहाज़ को रवाना किया (जो ब्रिज के नीचे से गुज़रा)
- रामेश्वरम-तांबरम (चेन्नई) ट्रेन को हरी झंडी
- ₹8,300 करोड़ के रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला
- रामेश्वरम के रामनाथस्वामी मंदिर में पूजा अर्चना

आध्यात्मिक पहलू: राम सेतु दर्शन

- श्रीलंका से लौटते समय प्रधानमंत्री मोदी ने राम सेतु (एडम्स ब्रिज) का हवाई दर्शन किया
- यह दृश्य उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर साझा किया
- यह घटना अयोध्या के सूर्य तिलक समारोह के साथ हुई — “दैवीय संयोग” बताया गया
- राम सेतु को धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रमुखता दी गई

राम सेतु (एडम्स ब्रिज) के बारे में

- स्थान: रामेश्वरम (भारत) से मन्नार द्वीप (श्रीलंका) तक का समुद्री प्राकृतिक शृंखला
- लंबाई: लगभग 48 किमी
- उत्तर में: पाल्क जलडमरूमध्य (बंगाल की खाड़ी से जुड़ाव)
- दक्षिण में: मन्नार की खाड़ी (हिंद महासागर से जुड़ाव)

यह पुल न केवल भारत की इंजीनियरिंग उपलब्धि का प्रतीक है, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

RBI Monetary Policy 2025: Bi-Monthly Highlights द्विमासिक आरबीआई मौद्रिक नीति 2025: RBI ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नए वित्तीय वर्ष की पहली नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दरों में कटौती की घोषणा की है। 7 से 9 अप्रैल 2025 के बीच हुई 54वीं बैठक में समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 6% करने का निर्णय लिया, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। इसके साथ ही स्टैंडिंग डिपॉज़िट फैसिलिटी (SDF) दर को 5.75% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) व बैंक दर को 6.25% कर दिया गया है।

बैठक की अध्यक्षता RBI गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने की, और इसमें डॉ. नागेश कुमार, श्री सौगता भट्टाचार्य, प्रो. राम सिंह, डॉ. राजीव रंजन और श्री एम. राजेश्वर राव शामिल हुए। वर्ष 2025 के लिए अगली MPC बैठकें जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर और फरवरी में निर्धारित हैं।

वर्तमान नीतिगत दरें:

नीति	दर
रेपो दर	6.00%
SDF दर	5.75%
MSF दर	6.25%
बैंक दर	6.25%
फिक्स्ड रिवर्स रेपो दर	3.35%

RBI द्वारा घोषित 6 अतिरिक्त उपाय:

1. संकटग्रस्त परिसंपत्तियों (stressed assets) की सेक्यूरिटाइजेशन की सुविधा प्रस्तावित।
2. सह-उधारी (co-lending) दिशानिर्देश सभी नियामक संस्थाओं व सभी प्रकार के ऋणों पर लागू होंगे।
3. सोने के विरुद्ध ऋण (loan against gold) के लिए नए नियामक प्रावधान।
4. आंशिक क्रेडिट एन्हांसमेंट (Partial Credit Enhancement) पर व्यापक दिशा-निर्देश।
5. NPCI को बैंकों और हितधारकों की सलाह से UPI के व्यक्ति-से-व्यापारी लेनदेन की सीमा ₹2 लाख से अधिक बढ़ाने की स्वतंत्रता।
6. रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को विषय-तटस्थ (theme-neutral) और ऑन-टैप रूप में लागू किया जाएगा।

GDP वृद्धि अनुमान (RBI द्वारा):

अवधि	पूर्व अनुमान	नया अनुमान
FY26	6.7%	6.5%
Q1 FY26	6.7%	6.5%
Q2 FY26	7.0%	6.7%
Q3 FY26	6.5%	6.6%
Q4 FY26	6.5%	6.3%





CPI मुद्रास्फीति अनुमान (RBI द्वारा):

अवधि	पूर्व अनुमान	नया अनुमान
FY26	4.2%	4.0%
Q1 FY26	4.5%	3.6%
Q2 FY26	4.0%	3.9%
Q3 FY26	3.8%	3.8%
Q4 FY26	4.2%	4.4%

यह मौद्रिक नीति समीक्षा RBI के विकास व स्थिरता के संतुलन की ओर बढ़ते दृष्टिकोण को दर्शाती है, जहां व्याज दरों में कटौती के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है, जबकि मुद्रास्फीति को भी नियंत्रण में रखा गया है।

भारत-यूआई रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए सहमत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम ने 8 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में उच्च स्तरीय वार्ता की, जिसका उद्देश्य भारत-यूआई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना था। उनकी बातचीत रक्षा, तटरक्षक बल संचालन, व्यापार, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और जनसंपर्क संबंधों में सहयोग को सशक्त बनाने पर केंद्रित रही। भारत में क्राउन प्रिंस के रूप में शेख हमदान की यह पहली आधिकारिक यात्रा थी, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। यह यात्रा दोनों देशों की साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं और पारस्परिक आर्थिक हितों को रेखांकित करती है।

प्रमुख बिंदु

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

- भारत और यूआई ने रक्षा एवं तटरक्षक बल सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई।
- तटरक्षक बल सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
- शेख हमदान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच हुई बातचीत में व्यापारिक संबंधों की तरह रक्षा संबंधों को भी ऊंचे स्तर तक ले जाने पर बल दिया गया।

प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान:

- संयुक्त प्रशिक्षण और आदान-प्रदान कार्यक्रम
- सह-उत्पादन और सह-विकास परियोजनाएं
- रक्षा निर्माण में सहयोग
- दोनों पक्षों ने इंडिया-यूआई डिफेंस पार्टनरशिप फोरम का स्वागत किया।
- मेक-इन-इंडिया और मेक-इन-एमिरेट्स पहलों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

उच्च स्तरीय राजनयिक संवाद

- प्रधानमंत्री मोदी ने शेख हमदान की यात्रा को "गहरी मित्रता की पुष्टि" बताया।
- विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी शेख हमदान से मुलाकात की और मजबूत संबंधों के लिए आभार जताया।
- शेख हमदान ने भारत-यूआई संबंधों को "विश्वास पर आधारित, इतिहास द्वारा आकारित" बताया।

व्यापार और आर्थिक सहयोग

- दुबई चैंबर ने मुंबई में दुबई-इंडिया बिज़नेस फोरम का आयोजन किया, जिसमें 200 भारतीय व्यापारिक नेताओं ने भाग लिया।

महत्वपूर्ण व्यापारिक आँकड़े:

- भारत-यूआई गैर-तेल व्यापार (2023): \$54.2 बिलियन
- दुबई-भारत द्विपक्षीय व्यापार: \$45.4 बिलियन
- भारत में दुबई का निवेश: \$4.68 बिलियन

2024 में:

- 16,623 भारतीय कंपनियाँ दुबई चैंबर ऑफ कॉमर्स में शामिल हुईं।
- अब दुबई में 70,000 से अधिक भारतीय कंपनियाँ कार्यरत हैं।

संपर्क और जन-सामान्य संबंध

- 2024 में दुबई ने 3.14 मिलियन दक्षिण एशियाई पर्यटकों का स्वागत किया, जिनमें सबसे अधिक संख्या भारत से थी।
- नेताओं ने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और संपर्क के माध्यमों की भूमिका को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण बताया।

तेलंगाना अनुसूचित जाति उप-वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बना

तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जातियों (SC) के उप-श्रेणीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद, 14 अप्रैल 2025 को—जो कि डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है—राज्य सरकार ने तेलंगाना अनुसूचित जातियाँ (आरक्षण का युक्तिकरण) अधिनियम, 2025 को लागू करते हुए एक सरकारी आदेश (GO) जारी किया। इस पहल का उद्देश्य मौजूदा 15% SC आरक्षण को 59 उप-जातियों के बीच तीन समूहों में बाँटकर उनकी आपसी सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर अधिक न्यायसंगत तरीके से लाभ वितरित करना है। यह निर्णय ऐतिहासिक प्रयासों जैसे कि लोकुर समिति (1965) और हाल की जस्टिस रामचंद्र राजू व उषा मेहरा आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है, जो लक्षित सकारात्मक कार्यवाई की दिशा में एक ठोस बदलाव को दर्शाता है।

तेलंगाना में अनुसूचित जाति (SC) उप-श्रेणीकरण के मुख्य बिंदु (मुख्य विशेषताएँ)

विधायी और कानूनी ढांचा

- तेलंगाना विधानसभा ने यह अधिनियम 18 मार्च 2025 को पारित किया।
- राज्यपाल की स्वीकृति 8 अप्रैल 2025 को प्राप्त हुई।
- 14 अप्रैल (अंबेडकर जयंती) को सरकारी आदेश (GO) जारी किया गया।
- यह सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के फैसले पर आधारित है, जिसमें SC उप-श्रेणीकरण की अनुमति दी गई थी।
- न्यायमूर्ति शमीम अख्तर की अध्यक्षता में अक्टूबर 2024 में एक सदस्यीय आयोग गठित किया गया था।





SC उप-श्रेणीकरण की संरचना

- कुल SC आरक्षण: 15% (2011 की जनगणना के आधार पर)
- SC उप-श्रेणियाँ: सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर तीन समूहों में विभाजित।

समूह	समुदायों की संख्या	जनसंख्या भागीदारी	आरक्षण आवंटन
समूह 1	15 (सबसे पिछड़े)	3.288% (~1.71 लाख)	1%
समूह 2	18 (मध्यम रूप से पिछड़े)	62.74% (~34 लाख)	9%
समूह 3	26 (तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति वाले)	33.963% (~17 लाख)	5%

वर्गीकरण का आधार

- जनसंख्या का आकार, साक्षरता दर, रोजगार, शिक्षा की उपलब्धता, वित्तीय सहायता, राजनीतिक भागीदारी।
- शमीम अख्तर आयोग को 8,600 से अधिक प्रस्तुतियाँ प्राप्त हुईं।
- विस्तृत परामर्श के बाद अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

प्रमुख वक्तव्य और औचित्य

- स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजा नरसिंह
 - कहा, यह अंतिम समाधान नहीं, बल्कि उत्थान का एक साधन है।
 - शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, औद्योगिक सहायता और वित्तीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।
 - बुडिगा जांगा जाति को असमान रूप से वंचित जाति का उदाहरण बताया।
- नागरिक आपूर्ति मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी
 - 13 अप्रैल 2025 को अंतिम बैठक की अध्यक्षता की।
 - SC समुदायों में क्रीमी लेयर की अवधारणा को खारिज किया।
 - स्पष्ट किया कि मौजूदा लाभों में कोई कटौती नहीं होगी।
 - बताया कि तेलंगाना की SC जनसंख्या अब 17.5% है, 2026 की जनगणना के बाद आरक्षण बढ़ सकता है।

राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएँ

- CPI विधायक कुनमनेनी संबाशिवा रेड्डी
 - रेल्ला समुदाय को समूह 3 में डाले जाने पर सवाल उठाया।
- AIMIM विधायक माजिद हुसैन
 - SC आरक्षण को 18% तक बढ़ाने और 3 के बजाय 4 उप-श्रेणियाँ बनाने का सुझाव दिया।
- सरकार का पक्ष
 - 3 समूहों को संतुलित और व्यावहारिक बताया—2 से असंतुलन होता, 4 अत्यधिक होते।

यह पहल सामाजिक न्याय की दिशा में एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है, जिससे सबसे कमजोर वर्गों तक वास्तविक लाभ पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति को 3 महीने की समय सीमा दी

तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल (2023) के एक ऐतिहासिक निर्णय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विधायी प्रक्रिया में मौजूद एक महत्वपूर्ण शून्य को संबोधित किया—राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास भेजे गए राज्य विधेयकों पर निर्णय में देरी। पहली बार, न्यायालय ने राष्ट्रपति के निर्णय के लिए 3 महीने की समयसीमा तय की, जिससे उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो और संघवाद तथा लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांतों की रक्षा हो सके। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने यह सलाह भी दी कि यदि कोई विधेयक संभावित असंवैधानिकता के आधार पर राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा गया हो, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना चाहिए। यह निर्णय सहकारी संघवाद की भावना की रक्षा करने और कार्यपालिका के मनमाने रवैये पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य विशेषताएँ

मामला: तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल, 2023

संविधानिक अनुच्छेद संबंधित

- अनुच्छेद 201 – राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे गए राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की शक्तियाँ।
- अनुच्छेद 143 – राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति।

अनुच्छेद 201 की न्यायालयीय व्याख्या

- यदि राज्यपाल कोई विधेयक राष्ट्रपति को भेजते हैं, तो राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर निर्णय लेना अनिवार्य होगा।
- पहले इस प्रक्रिया में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं थी, जिससे विधायी ठहराव और अनिश्चितता पैदा होती थी।
- कोर्ट ने कहा कि अनिश्चितकालीन देरी असंवैधानिक है और यह "गैर-मनमानेपन" के सिद्धांत का उल्लंघन करती है।

समयबद्ध निर्णय

- अब राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर सहमति या अस्वीकृति देने के लिए 3 महीने की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
- यह निर्णय कारण सहित राज्य सरकार को सूचित किया जाना आवश्यक है।

कोई "पूर्ण वीटो" नहीं

- राष्ट्रपति अनिश्चितकाल तक विधेयक को रोके नहीं रख सकते—यह असंवैधानिक "एब्सोल्यूट वीटो" के समान होगा।
- यदि राष्ट्रपति सहमति नहीं देते हैं, तो कानूनी आधार पर स्पष्ट और तर्कसंगत कारण प्रस्तुत करना अनिवार्य है—राजनीतिक कारण मान्य नहीं होंगे।

न्यायिक उपाय

- यदि राष्ट्रपति द्वारा कोई निर्णय लंबे समय तक नहीं लिया जाता है, तो संबंधित राज्य न्यायालय का सहारा ले सकते हैं।
- राज्य सरकारें "मैंडमस" याचिका दायर कर राष्ट्रपति को निर्णय लेने हेतु बाध्य कर सकती हैं।





अनुच्छेद 143: सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श

- यदि राज्यपाल विधेयक को असंवैधानिक मानते हुए राष्ट्रपति को भेजते हैं, तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए।
- यह सलाह बाध्यकारी नहीं होती, परंतु इसकी प्रभावशीलता और मान्यता उच्च होती है।
- इससे स्पष्ट रूप से असंवैधानिक कानूनों के निर्माण को रोका जा सकता है, जिससे जन संसाधनों की बचत होती है।

राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच अंतर

- यदि राज्यपाल कोई विधेयक वापस भेजते हैं और वह दोबारा पारित होता है, तो उन्हें अनिवार्य रूप से उस पर सहमति देनी होती है।
- राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 201 के अंतर्गत ऐसा कोई बंधन नहीं होता।

नीति बनाम संविधान

- सुप्रीम कोर्ट केवल तभी परामर्श देगा जब मामला शुद्ध रूप से विधिक या संवैधानिक प्रश्न से जुड़ा हो।
- यदि मामला नीति, सामाजिक-आर्थिक या राजनीतिक प्रकृति का है, तो न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा।

सहायक सिफारिशें

- सरकारिया आयोग (1988) और पुंड्री आयोग (2010) की सिफारिशें:
 - o राष्ट्रपति को समय-सीमित निर्णय लेना चाहिए।
 - o असंवैधानिकता की आशंका होने पर अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना चाहिए।
- गृह मंत्रालय की कार्यालय ज्ञापन (2016) ने भी 3 महीने की समय-सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की थी।

न्यायमूर्ति बीआर गवई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे

भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने 16 अप्रैल 2025 को सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. आर. गवई को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। यह घोषणा केंद्रीय विधि मंत्रालय को भेजे गए एक पत्र के माध्यम से की गई। सरकार की औपचारिक मंजूरी के बाद न्यायमूर्ति गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। न्यायमूर्ति गवई को वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था। वे वर्तमान CJI संजीव खन्ना के 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होने के बाद पदभार संभालेंगे। न्यायमूर्ति गवई का कानूनी सफर दशकों तक फैला हुआ है, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से संविधानिक और प्रशासनिक कानून के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका नियुक्त होना न्यायपालिका में विविधता और अनुभव की निरंतरता को दर्शाता है।

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई का करियर विवरण (हिंदी में)

प्रारंभिक पृष्ठभूमि और प्रारंभिक करियर

- जन्म: अमरावती, महाराष्ट्र।
- कानूनी करियर की शुरुआत: 1985 में वकालत शुरू की।
- प्रारंभिक प्रशिक्षण: बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता और न्यायाधीश राजा एस. भोंसले के अधीन 1987 तक कार्य किया।
- प्रमुख अभ्यास क्षेत्र: नागपुर खंडपीठ, विशेष रूप से संवैधानिक और प्रशासनिक कानून में विशेषज्ञता।

सरकारी भूमिकाएँ

- 1992-93: नागपुर पीठ में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त।
- 2000 से आगे: सरकारी वकील और लोक अभियोजक के पद पर पदोन्नति।

न्यायिक करियर

- नवंबर 2003: बॉम्बे हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त।
- नवंबर 2005: स्थायी न्यायाधीश बने।
- मई 2019: भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त।

न्यायमूर्ति गवई के प्रमुख न्यायिक योगदान

1 नोटबंदी पर फैसला (जनवरी 2023)

- 2016 में ₹500 और ₹1,000 के नोटों को अमान्य घोषित करने के केंद्र सरकार के फैसले को बहुमत के साथ सही ठहराया।
- न्यायमूर्ति गवई इस बहुमत निर्णय का हिस्सा थे।

2 अनुसूचित जातियों/जनजातियों का उप-वर्गीकरण (अगस्त 2024)

- ऐतिहासिक फैसले में SC/ST वर्गों में 'क्रीमी लेयर' लागू करने की वकालत की।
- इससे यह सुनिश्चित किया गया कि वास्तविक रूप से वंचित लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिले।

3 अनुच्छेद 370 की समाप्ति (2019)

- पाँच-न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा रहे, जिसने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को वैध ठहराया।

4 बुलडोज़र से तोड़फोड़ पर आलोचना (नवंबर 2024)

- दो-न्यायाधीशों की पीठ में रहते हुए अपराध के आरोपियों की संपत्तियों को बिना विधिक प्रक्रिया के ध्वस्त करने की कार्रवाई की आलोचना की।
- इसे कानून के शासन का उल्लंघन बताया।

भगवद् गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया

भारत ने अपनी प्राचीन सभ्यता की विरासत में एक और गौरवपूर्ण अध्याय जोड़ते हुए भगवद् गीता की पांडुलिपियों और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को यूनेस्को की 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर' में शामिल करवा लिया है। यह निर्णय वैश्विक स्तर पर भारत की समृद्ध बौद्धिक और सांस्कृतिक धरोहर को मान्यता देने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने इस उपलब्धि को भारत के लिए एक महत्वपूर्ण और गर्व का क्षण बताया है। इन दो नई प्रविष्टियों के साथ अब भारत की कुल 14 दस्तावेज़ी धरोहरें इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हो चुकी हैं, जो हमारी संस्कृति की गहराई और विश्व योगदान का प्रतीक हैं।





मुख्य विशेषताएँ

- मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर क्या है?
 - वर्ष 1992 में स्थापित, यूनेस्को का "मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड (MoW) प्रोग्राम" वैश्विक महत्व की दस्तावेज़ी धरोहरों को संरक्षित करने और उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
 - यह पांडुलिपियों, अभिलेखों, मौखिक परंपराओं, ऑडियो-विजुअल सामग्री और पुस्तकालय संग्रहों की सुरक्षा करता है।
- भारत की 2025 में शामिलियाँ
 - 17 अप्रैल 2025 को भगवद गीता की पांडुलिपियाँ और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र इस रजिस्टर में शामिल किए गए।
 - अब भारत की कुल 14 दस्तावेज़ी धरोहरें इस सूची में दर्ज हैं।
- भगवद गीता का महत्व
 - हिंदू धर्म का एक प्रमुख आध्यात्मिक ग्रंथ, जो महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है।
 - इसे दर्शन, धर्म (कर्तव्य) और आध्यात्मिकता का सार्वभौमिक मार्गदर्शक माना जाता है।
 - यह लगभग 80 भाषाओं में अनूदित हो चुकी है।
- नाट्यशास्त्र का महत्व
 - भरत मुनि द्वारा रचित यह प्राचीन ग्रंथ नाट्य, रंगमंच और प्रदर्शन कलाओं पर आधारित है।
 - इसमें अभिनय, मंच सज्जा, संगीत, नृत्य और सौंदर्यशास्त्र (रस सिद्धांत) सहित कई विषयों का वर्णन है।
 - यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य और नाट्य परंपराओं की आधारशिला माना जाता है।
- आधिकारिक प्रतिक्रियाएँ
 - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोषणा को "हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण" बताया और गीता व नाट्यशास्त्र को भारतीय सभ्यता और चेतना को पोषित करने वाले ग्रंथ कहा।
 - संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सभ्यतागत विरासत के लिए "ऐतिहासिक क्षण" बताया।
- वैश्विक परिप्रेक्ष्य
 - वर्ष 2025 में कुल 74 नई कलेक्शन इस सूची में जोड़ी गईं, जिससे कुल वैश्विक संख्या 570 हो गई।
 - इनमें से 14 वैज्ञानिक दस्तावेज़ी धरोहरों से संबंधित हैं, जिनमें महिलाओं और बहुपक्षीय संस्थाओं का योगदान भी शामिल है।
- यूनेस्को का वक्तव्य
 - यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्री अज़ूले ने कहा कि दस्तावेज़ी धरोहरें नाजुक होती हैं, लेकिन वे मानव स्मृति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
 - यह रजिस्टर संरक्षण प्रयासों, ज्ञान साझा करने और वैश्विक अभिलेख के रूप में कार्य करता है।
- यूनेस्को का व्यापक कार्यक्रम
 - यूनेस्को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने को भी समर्थन देता है।
 - अब 100 से अधिक देशों में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड समितियाँ कार्यरत हैं।
 - यह कार्यक्रम धरोहर दस्तावेज़ों तक सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देता है।

महाराष्ट्र के राज्यपाल ने यशराज भारती सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किए

महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने स्वास्थ्य, सतत विकास हेतु शिक्षा और सुशासन के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले तीन प्रमुख जमीनी स्तर के संगठनों को 'यशराज भारती सम्मान' के तीसरे संस्करण से सम्मानित किया। मुंबई में आयोजित इस पुरस्कार समारोह में जन स्वास्थ्य सहयोग (छत्तीसगढ़), प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित सर्विसेज प्लस प्लेटफॉर्म के प्रभाव को मान्यता दी गई। इस अवसर पर महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप वलसे पाटिल और भारत के G-20 शेरपा अमिताभ कांत जैसी विशिष्ट हस्तियों की उपस्थिति रही। राज्यपाल राधाकृष्णन ने अपने संबोधन में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और नैतिक शासन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि समाज में वास्तविक परिवर्तन लाया जा सके।

यशराज भारती सम्मान 2025 के मुख्य बिंदु

सम्मान का अवलोकन

- यशराज भारती सम्मान उन व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रदान किया जाता है जो जमीनी स्तर पर उल्लेखनीय योगदान देते हैं।
- यह पुरस्कार का तीसरा संस्करण है।

पुरस्कार विजेता और उनके योगदान

जन स्वास्थ्य सहयोग (छत्तीसगढ़)

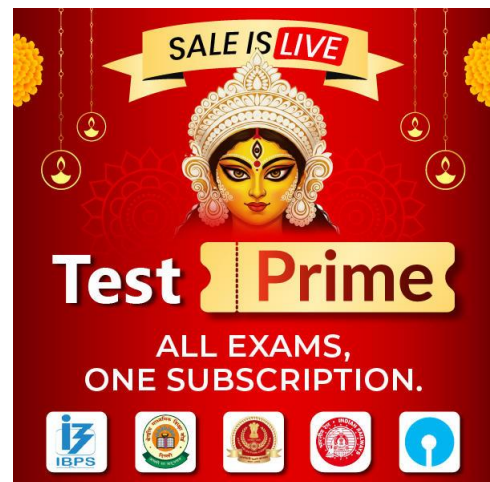
- दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ-निर्देशित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सम्मानित।
- स्वास्थ्य सेवाओं में समानता और सस्ती चिकित्सा तक पहुंच पर केंद्रित।

प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन

- शिक्षा के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित।
- पूरे भारत में सीखने के परिणामों की निगरानी और सुधार के लिए ASER (Annual Status of Education Report) जैसे नवाचारों के लिए प्रसिद्ध।

सर्विसेज प्लस प्लेटफॉर्म (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र - NIC)

- नागरिक-केंद्रित ई-सेवाएं कुशलतापूर्वक और पारदर्शी ढंग से प्रदान कर अच्छी शासन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म।





कार्यक्रम की झलकियां

- यह आयोजन मुंबई में राज भवन द्वारा आयोजित किया गया।

मुख्य अतिथियों की उपस्थिति

- दिलीप बलसे पाटिल, पूर्व महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष।
- अमिताभ कांत, भारत के G-20 शेरपा।

राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन का संबोधन

शिक्षा:

- महाराष्ट्र में स्कूलों की संख्या अधिक होने के बावजूद गिरते शिक्षा स्तर पर चिंता जताई।

स्वास्थ्य सेवा:

- जनजातीय क्षेत्रों में जीवन गुणवत्ता सुधारने हेतु विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाओं की आवश्यकता पर बल दिया।

शासन व्यवस्था:

- भ्रष्टाचार के खिलाफ जन-जागरूकता की आवश्यकता और नैतिक शासन को सामाजिक परिवर्तन की नींव बताया।

लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025: विजेताओं की पूरी सूची देखें

2025 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स ने मैड्रिड में एक भव्य समारोह के साथ अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाई, जिसमें पिछले वर्ष के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और टीमों को सम्मानित किया गया। "खेलों के ऑस्कर" कहे जाने वाले इन अवार्ड्स में व्यक्तिगत प्रतिभा के साथ-साथ सामूहिक उपलब्धियों को भी सराहा गया। इस आयोजन में दुनिया भर के खेलों से जुड़े दिग्गज, उभरते सितारे और बदलाव लाने वाले खिलाड़ी एकत्रित हुए। मैड्रिड की जीवंतता के बीच आयोजित यह समारोह विश्व खेल जगत की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों का उत्सव बन गया।

विजेताओं की शानदार सूची

मोंडो डुप्लांटिस: द वॉल्टिंग लीजेंड

25 वर्षीय स्वीडिश-अमेरिकन पोल वॉल्टर मोंडो डुप्लांटिस को **Laureus** वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब मिला। लगातार तीन वर्षों तक नामांकित होने के बाद उन्होंने पहली बार यह प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम किया।

डुप्लांटिस को अब तक का सबसे महान पोल वॉल्टर माना जाता है। उन्होंने इन दिग्गजों को पीछे छोड़ा:

- कार्लोस अल्कराज (टेनिस – स्पेन)
- लियोन मार्चा (स्विमिंग – फ्रांस)
- तदेइ पोगाचार (साइक्लिंग – स्लोवेनिया)
- मैक्स वेरस्टैपेन (फॉर्मूला 1 – नीदरलैंड)

2024 में डुप्लांटिस ने:

- दूसरा वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप गोल्ड जीता
- नौवीं बार अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा
- पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता

इस पुरस्कार को और खास बना दिया यूसेन बोल्ट की विशेष श्रद्धांजलि ने, जो ट्रैक एंड फील्ड के एकमात्र अन्य खिलाड़ी हैं जिन्हें यह सम्मान मिल चुका है।
सिमोन बाइल्स: द क्वीन रिटर्न्स

प्रतिस्पर्धा से कुछ समय दूर रहने के बाद सिमोन बाइल्स ने पेरिस ओलंपिक में शानदार वापसी की और जीते:

- तीन स्वर्ण पदक
- एक रजत पदक

उन्हें चौथी बार Laureus वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला, जिससे उन्होंने सेरेना विलियम्स के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।

यह जीत उन्हें इतिहास की सबसे सज्जित (decorated) जिमनास्टों में से एक के रूप में स्थापित करती है।

गौरतलब है कि बाइल्स और डुप्लांटिस दोनों ही पहले Comeback of the Year अवॉर्ड भी जीत चुके हैं — जो उनके जज़्बे और हौसले का प्रमाण है।

विजेताओं की पूरी सूची

श्रेणी	विजेता
वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर	मोंडो डुप्लांटिस
वर्ल्ड स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर	सिमोन बाइल्स
वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर	रियल मैड्रिड
ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर	लामिन यमाल
कमबैक ऑफ द ईयर	रेबेका आंद्राडे
स्पोर्ट्सपर्सन विद अ डिसएबिलिटी	जियांग यूयान
एक्शन स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ द ईयर	टॉम पिडकॉक
स्पोर्ट फॉर गुड अवॉर्ड	किक4लाइफ
स्पोर्टिंग आइकन अवॉर्ड	राफेल नडाल
लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड	केली स्लेटर

IISc टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर

टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की घोषणा 23 अप्रैल को की गई, जिसमें एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों को प्रस्तुत किया गया। इस वर्ष की रैंकिंग में 35 देशों और क्षेत्रों के कुल 853 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं, जो शोध, शिक्षण और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत की ओर से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc), बेंगलुरु ने एक बार फिर श्रेष्ठता कायम रखते हुए देश की सर्वोच्च रैंक प्राप्त की है, जिसे एशिया में कुल मिलाकर 38वां स्थान मिला है। हालांकि, कई भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट देखी गई, जो एशियाई उच्च शिक्षा क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता मानकों में बदलाव को दर्शाता है।

एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की प्रमुख झलकियां

भारतीय संस्थानों की रैंकिंग

- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) को 38वां स्थान मिला है, हालांकि यह 2024 की 32वीं रैंक से थोड़ा नीचे खिसका है।
- अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां और आईआईटी इंदौर को 131वां स्थान मिला है।
- महात्मा गांधी विश्वविद्यालय ने 140वीं रैंक हासिल की है, जो पिछले वर्ष की 134वीं रैंक से थोड़ी कम है।
- अन्य प्रमुख भारतीय संस्थान जैसे शूलिनी यूनिवर्सिटी, सवीथा इंस्टीट्यूट, और जामिया मिलिया इस्लामिया भी सूची में शामिल हैं।





भारतीय विश्वविद्यालयों की विस्तृत रैंकिंग

- 38वां – इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc)
- 111वां – अन्ना विश्वविद्यालय
- 131वां – इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) इंदौर
- 140वां – महात्मा गांधी विश्वविद्यालय
- 146वां – शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज
- 149वां – सवीथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज
- 161वां – जामिया मिलिया इस्लामिया
- 184वां – IIT गुवाहाटी
- 184वां – KIIT यूनिवर्सिटी
- 188वां – अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
- 188वां – UPES
- 191वां – IIT पटना
- 191वां – NIT राउरकेला
- 200वां – इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रूझान

- चीन ने एक बार फिर वर्चस्व कायम रखा है: लिंगहुआ यूनिवर्सिटी और पेकिंग यूनिवर्सिटी पहले और दूसरे स्थान पर हैं।
- सिंगापुर की स्थिति मजबूत हुई है: नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तीसरे और नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी चौथे स्थान पर है।
- जापान और हॉन्गकॉन्ग की प्रमुख यूनिवर्सिटियाँ भी शीर्ष 10 में बनी हुई हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो और यूनिवर्सिटी ऑफ हॉन्गकॉन्ग।
- इस वर्ष पहली बार उज़्बेकिस्तान, बहरीन, मंगोलिया और सीरिया की यूनिवर्सिटियाँ भी रैंकिंग में शामिल हुई हैं।

न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

भारतीय विधिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दिनेश माहेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में अप्रैल 2025 में नियुक्त किया गया है। यह घोषणा सरकार की उस निरंतर पहल का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत भारतीय कानून व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जा रही है और सुधारों की सिफारिशों की जा रही हैं। इस नियुक्ति को विशेष रूप से समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) जैसे लंबे समय से चर्चा में रहे संवेदनशील विषयों की पृष्ठभूमि में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। न्यायमूर्ति माहेश्वरी के नेतृत्व में विधि आयोग से यह अपेक्षा की जा रही है कि वह विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और संवैधानिक पहलुओं पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए व्यापक कानूनी सुधारों की सिफारिश करेगा।

भारत के 23वें विधि आयोग का कार्यकाल और संरचना

23वां विधि आयोग 1 सितंबर 2024 को औपचारिक रूप से गठित किया गया था, जिसका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। यह आयोग कुल 7 सदस्यों से मिलकर बना है, जिनमें शामिल हैं:

- एक अध्यक्ष: न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दिनेश माहेश्वरी
- चार पूर्णकालिक सदस्य: जिनमें वकील हितेश जैन और शैक्षणिक विशेषज्ञ पी. वर्मा (जो 22वें आयोग का भी हिस्सा थे) शामिल हैं

- दो पदेन सदस्य: जो विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग से नामित किए गए हैं

इसके अतिरिक्त, सरकार 5 अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकती है। यदि वर्तमान में सेवारत न्यायाधीशों को आयोग में शामिल किया जाता है, तो वे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में सेवानिवृत्ति या आयोग के कार्यकाल के अंत तक कार्य करेंगे।

समान नागरिक संहिता (UCC) पर विशेष ध्यान

इस आयोग का मुख्य कार्य समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) की व्यवहार्यता की जांच करना है—जो भारत में एक अत्यधिक राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील विषय रहा है। UCC का उद्देश्य विभिन्न धर्मों और समुदायों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक साझा नागरिक कानून लागू करना है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो।

UCC पर पूर्व परामर्श की पृष्ठभूमि:

- 22वें विधि आयोग ने 2023 में UCC पर देशव्यापी परामर्श शुरू किए थे, जिनमें 70 से अधिक परामर्श सत्रों में जनता की राय ली गई थी।
- इसने एक 749-पृष्ठों का प्रारंभिक मसौदा रिपोर्ट तैयार किया था, लेकिन इसकी प्रक्रिया पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी के लोकपाल नियुक्त हो जाने के बाद अधूरी रह गई।
- 21वें आयोग ने 2018 की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि "वर्तमान समय में UCC न तो आवश्यक है, न ही वांछनीय", जिससे नीति निर्माण में मतभेद उत्पन्न हुआ।
- अब 23वें आयोग से उम्मीद की जा रही है कि वह इस मुद्दे पर अंतिम सिफारिशें देगा, जो भारत के बदलते सामाजिक और कानूनी परिवेश को ध्यान में रखेगी।

UCC का राजनीतिक महत्व

UCC लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वैचारिक एजेंडे का हिस्सा रहा है, जिसमें शामिल हैं:

- अनुच्छेद 370 की समाप्ति (जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला प्रावधान)
- अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण
- इन दोनों वादों को BJP ने अपने दूसरे कार्यकाल (2019–2024) में पूरा कर दिया है। अब UCC को पार्टी के आखिरी वैचारिक स्तंभ के रूप में देखा जा रहा है।

राज्यों में हो रहे विकास:

- उत्तराखंड UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
- गुजरात ने भी यूसीसी ड्राफ्टिंग समिति का गठन किया है।
- 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों का अस्तित्व "राष्ट्र की एकता के लिए अपमानजनक" है, जिससे UCC पर सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।

वित्तीय और संचालन संरचना

23वें विधि आयोग के कार्य संचालन हेतु एक सुव्यवस्थित वित्तीय एवं प्रशासनिक ढांचा निर्धारित किया गया है:

- अध्यक्ष (सेवानिवृत्त) को ₹2.5 लाख मासिक मानधन मिलेगा, जिसमें





पेंशन शामिल है।

- पूर्णकालिक सेवानिवृत्त सदस्यों को ₹2.25 लाख प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा।

यह आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, लेकिन साथ ही विधि एवं न्याय मंत्रालय, अन्य विधिक निकायों और नागरिक समाज संगठनों के साथ समन्वय में कार्य कर समावेशी और व्यावहारिक विधि सुधारों की सिफारिश करेगा।

कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025: पांच साल बाद फिर से शुरू

कैलाश मानसरोवर यात्रा (केएमवाई) एक महत्वपूर्ण वार्षिक तीर्थयात्रा है, जो भारत और चीन के बीच गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक मानी जाती है। यह यात्रा हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। माना जाता है कि माउंट कैलाश की परिक्रमा करने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह तीर्थयात्रा 2020 में COVID-19 महामारी और सीमा तनावों के कारण स्थगित कर दी गई थी। पांच वर्षों के बाद इसका पुनः आरंभ होना धार्मिक पर्यटन और द्विपक्षीय सहयोग में एक सकारात्मक विकास का संकेत है।

समाचार में क्यों?

26 अप्रैल 2025 को विदेश मंत्रालय (MEA) ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के पुनः आरंभ की घोषणा की। यह यात्रा जून से अगस्त 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। कुल 750 तीर्थयात्रियों को अनुमति दी जाएगी, जो लिपुलेख दर्रा (उत्तराखंड) और नाथू ला दर्रा (सिक्किम) मार्गों से जल्यों में जाएंगे।

कैलाश मानसरोवर यात्रा क्या है?

कैलाश मानसरोवर यात्रा भारतीय नागरिकों के लिए आयोजित एक वार्षिक सरकारी तीर्थयात्रा है, जिसमें वे तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (चीन) स्थित माउंट कैलाश और मानसरोवर झील के दर्शन करते हैं। इसका गहरा धार्मिक महत्व है:

- हिंदू माउंट कैलाश को भगवान शिव का निवास मानते हैं।
- बौद्ध इसे बुद्ध देमचोक का निवास मानते हैं।
- जैन मानते हैं कि उनके प्रथम तीर्थंकर ने यहीं मोक्ष प्राप्त किया था।
- बोन धर्म के अनुयायी भी इसे पवित्र पर्वत मानते हैं।

यात्रा का मुख्य उद्देश्य धार्मिक तीर्थारण और भारत-चीन सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।

मुख्य विवरण / विशेषताएँ

यात्रा के दो आधिकारिक मार्ग हैं:

- लिपुलेख दर्रा (उत्तराखंड): पारंपरिक मार्ग, 1981 से चालू।
- नाथू ला दर्रा (सिक्किम): मोटेरेबल मार्ग, 2015 से चालू।

तीर्थयात्रियों का विवरण:

- लिपुलेख मार्ग से 5 जल्ये, प्रत्येक में 50 तीर्थयात्री।
- नाथू ला मार्ग से 10 जल्ये, प्रत्येक में 50 तीर्थयात्री।

पंजीकरण पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड है (<https://kmy.gov.in>) के माध्यम से, जिसमें निष्पक्ष, यादृच्छिक और लैंगिक संतुलन सुनिश्चित किया गया है। यात्रा का समन्वय MEA, गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), उत्तराखंड, सिक्किम और दिल्ली की राज्य सरकारों और कुमाऊँ मंडल विकास निगम (KMVN) द्वारा किया जाता है।

प्रभाव / महत्व

यात्रा के पुनः आरंभ होने के कई प्रमुख निहितार्थ हैं:

- धार्मिक और सांस्कृतिक: आस्था और परंपराओं को सुदृढ़ करता है।
- कूटनीतिक संबंध: भारत-चीन संबंधों में जन संपर्क के माध्यम से सुधार का प्रतीक है।
- आर्थिक लाभ: उत्तराखंड और सिक्किम में पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय रोजगार सृजन।
- रणनीतिक मूल्य: सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना और संपर्क में सुधार कर राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है।

चुनौतियाँ / चिंताएँ

हालांकि यात्रा का आरंभ सकारात्मक है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं:

- सुरक्षा: वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर तनाव।
- लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा: कठिन भूभाग, ऊँचाई और मौसम संबंधी जोखिम।
- कूटनीतिक संवेदनशीलता: चीन के साथ नाजुक संबंध।
- पर्यावरणीय चिंता: हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर तीर्थयात्रियों के बढ़ते दबाव से खतरा।

आगे का रास्ता / समाधान

यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है:

- सुरक्षा उपाय बढ़ाना: चिकित्सीय जाँच, आपातकालीन सुविधाओं और बचाव प्रबंधों को मजबूत करना।
- कूटनीतिक संवाद बनाए रखना: चीन के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना।
- सतत आधारभूत संरचना विकास: न्यूनतम पारिस्थितिक क्षति के साथ सड़कों, संचार और आश्रय सुविधाओं में सुधार।
- पर्यावरण संरक्षण: कचरा प्रबंधन लागू करना और हरित पर्यटन को बढ़ावा देना।
- तीर्थयात्रियों का प्रशिक्षण: उच्च ऊँचाई के अनुरूप बनाने और पर्यावरणीय जागरूकता के लिए प्रशिक्षण देना।

कैबिनेट की मंजूरी

कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए “जीवंत गांव कार्यक्रम-II (वीवीपी-II)” को मंजूरी दी

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II (VVP-II) को केंद्रीय क्षेत्र योजना (100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित) के रूप में मंजूरी दी, जो ‘सुरक्षित, संरक्षित और जीवंत भूमि सीमाओं’ के लिए विकसित भारत@2047 की परिकल्पना के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।
- यह कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमाओं (ILBs) से सटे ब्लॉकों में स्थित गांवों के समग्र विकास में सहायता करेगा, उत्तर सीमा को छोड़कर, जिसे पहले ही VVP-I के तहत शामिल किया जा चुका है।
- इस योजना के तहत कुल ₹6,839 करोड़ की लागत से इसे वित्त वर्ष 2028-29 तक अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर (केंद्रशासित प्रदेश), लद्दाख (केंद्रशासित प्रदेश), मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के चुनिंदा रणनीतिक गांवों में लागू किया जाएगा।





- इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेहतर जीवन स्थितियाँ और पर्याप्त आजीविका के अवसर प्रदान करना है ताकि सीमाएं समृद्ध और सुरक्षित बनें, सीमा पार अपराधों पर नियंत्रण हो सके, और सीमावर्ती आबादी को राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके तथा उन्हें सीमा सुरक्षा बलों की आंख और कान के रूप में तैयार किया जा सके, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- यह कार्यक्रम गांव या गांवों के समूह के भीतर बुनियादी ढांचा विकास, मूल्य श्रृंखला विकास (सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों आदि के माध्यम से), सीमा-विशिष्ट जनसंपर्क गतिविधियाँ, शैक्षणिक अवसरचना जैसे स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना, पर्यटन सर्किटों का विकास, और सीमा क्षेत्रों में विविध और सतत आजीविका के अवसरों के लिए परियोजनाएं प्रदान करने हेतु धन उपलब्ध कराएगा।
- हस्तक्षेप सीमा-विशिष्ट, राज्य एवं गांव-विशिष्ट होंगे और इन्हें सहभागी दृष्टिकोण के तहत तैयार की गई ग्राम कार्य योजनाओं के आधार पर लागू किया जाएगा। इन गांवों के लिए हर मौसम में सड़क संपर्क की व्यवस्था कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत पहले से स्वीकृत पीएमजीएसवाई-IV के तहत की जाएगी। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति सीमा क्षेत्रों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु योजनागत दिशानिर्देशों में उचित ढील देने पर विचार करेगी।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य, पहचाने गए गांवों में व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर की मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को योजना मानदंडों के अनुसार पूर्ण रूप से लागू (सैचुरेशन) करना है। साथ ही, इन ब्लॉकों के सभी गांवों में चार प्रमुख विषयों — हर मौसम में सड़क संपर्क, दूरसंचार संपर्क, टेलीविजन संपर्क, और विद्युतीकरण — में योजनाओं के समेकन के माध्यम से सैचुरेशन प्राप्त करने का लक्ष्य है।
- कार्यक्रम का जोर इन गांवों में जीवंतता को बढ़ाने पर है, जिसके तहत मेलों और उत्सवों का आयोजन, जागरूकता शिविर, राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, केंद्रीय एवं राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के नियमित दौर एवं रात्रि प्रवास शामिल हैं। इससे पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी और इन गांवों की स्थानीय संस्कृति एवं विरासत को बढ़ावा मिलेगा।
- तकनीक का लाभ उठाया जाएगा और PM गति शक्ति जैसे सूचना डेटाबेस का उपयोग इस परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किया जाएगा।
- VVP-II, VVP-I के साथ मिलकर, सीमावर्ती गांवों को आत्मनिर्भर और जीवंत बनाने की एक परिवर्तनकारी पहल है।

कैबिनेट ने भारतीय रेलवे में चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की, ने रेलवे मंत्रालय की चार परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत लगभग ₹18,658 करोड़ है। ये चारों परियोजनाएं तीन राज्यों — महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ — के 15 जिलों में फैली हुई हैं और इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 1247 किलोमीटर की वृद्धि होगी।

इन परियोजनाओं में शामिल हैं:

- संबलपुर – जरापड़ा तीसरी और चौथी लाइन
- झारसुगुड़ा – सासोन तीसरी और चौथी लाइन
- खरसिया – नया रायपुर – परमलकसा पांचवीं और छठी लाइन
- गोंदिया – बल्हारशाह दोहरीकरण

लाइन क्षमता में वृद्धि से गतिशीलता में सुधार होगा, जिससे सेवा की दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। ये मल्टी-ट्रैकिंग योजनाएं रेलवे की सबसे व्यस्त मार्गों पर संचालन को सुगम बनाएंगी और भीड़भाड़ को कम करेंगी। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के "नए भारत" के विजन के अनुरूप हैं, जो क्षेत्रीय विकास के माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगी और रोजगार / स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगी।

ये परियोजनाएं पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए तैयार की गई हैं, जो समन्वित योजना के जरिए संभव हुई हैं और लोगों, सामान और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करेंगी।

इन परियोजनाओं के तहत 19 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे दो आकांक्षी जिलों (गडचिरोली और राजनांदगांव) को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाएं लगभग 3350 गांवों और 47.25 लाख की जनसंख्या को जोड़ेंगी।

खरसिया – नया रायपुर – परमलकसा परियोजना से बलौदा बाजार जैसे नए क्षेत्रों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे नए औद्योगिक इकाइयों, जैसे कि सीमेंट कारखानों की स्थापना की संभावनाएं बनेंगी।

ये मार्ग कृषि उत्पादों, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, स्टील, सीमेंट, चूना पत्थर आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इन परियोजनाओं से रेलवे की मालवाहन क्षमता में 88.77 मिलियन टन प्रतिवर्ष (MTPA) की वृद्धि होगी। रेलवे एक पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन माध्यम होने के कारण देश के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा, साथ ही लॉजिस्टिक्स लागत में कमी, 95 करोड़ लीटर तेल आयात में बचत, और 477 करोड़ किलोग्राम CO₂ उत्सर्जन में कमी लाएगा, जो 19 करोड़ पेड़ों के वृक्षारोपण के बराबर है।

SALE IS LIVE



Test Prime

**ALL EXAMS,
ONE SUBSCRIPTION.**











संसद समाचार

अप्रैल महीने की राज्यवार महत्वपूर्ण घटनाएँ

आंध्र प्रदेश

- समान आरक्षण लाभों के न्यायसंगत वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में अनुसूचित जातियों (SCs) की उप-श्रेणीकरण (sub-categorisation) को लागू करने के लिए एक मसौदा अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय "आरक्षण के भीतर आरक्षण" की अवधारणा पर आधारित है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों की विभिन्न उप-जातियों के बीच उनकी सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति के आधार पर कोटा लाभों का संतुलित वितरण सुनिश्चित करना है।
- आंध्र प्रदेश की नियोजित राजधानी अमरावती, सौर, पवन और जल विद्युत पर ध्यान केंद्रित करते हुए, पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला शहर बनने जा रही है। कृष्णा नदी के किनारे 217 वर्ग किलोमीटर में फैली इस परियोजना की लागत ₹65,000 करोड़ है, जिसका लक्ष्य 2050 तक 2,700 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करना है, जिसमें कम से कम 30% सौर और पवन ऊर्जा से होगी।

अरुणाचल प्रदेश

- पूर्वोत्तर भारत में जलविद्युत क्षमता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई एसजेवीएन लिमिटेड (SJVN Ltd) ने अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में 3,097 मेगावाट की एतालिन जलविद्युत परियोजना के लिए ₹269.97 करोड़ की भूमि मुआवजा राशि जारी की है। यह भुगतान 26 मार्च 2025 को दिबांग घाटी के उपायुक्त (DC) और जिला भूमि राजस्व एवं निपटान अधिकारी (DLRSO) के संयुक्त खाते में किया गया। यह पहल न केवल नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की योजना को गति प्रदान करती है, बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के अधोसंरचनात्मक विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है।

असम

- महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए असम सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है, जो इसकी सबसे व्यापक उद्यमिता सहायता योजना है। बिश्ननाथ जिले में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य 30 लाख महिलाओं को सशक्त बनाना है।

बिहार

- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने "महिला संवाद" अभियान की शुरुआत की, जो ग्रामीण महिलाओं को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर और नीतिगत चर्चाओं में उनकी आवाज़ को बुलंद करके उन्हें सशक्त बनाने पर केंद्रित एक राज्यव्यापी पहल है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में शिक्षित करना, सार्वजनिक संसाधनों (स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आजीविका) के उनके सक्रिय उपयोग को प्रोत्साहित करना और सरकारी अधिकारियों के साथ दो-तरफा संचार चैनल स्थापित करना है।

गुजरात

- गुजरात पुलिस द्वारा शुरू किया गया GP-DRASTI (ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलांस टैक्टिकल इंटरवेंशन्स) कार्यक्रम राज्य में कानून व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल के तहत क्वाड्रॉप्टर ड्रोन का उपयोग अपराध की निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और अपराध स्थलों के दस्तावेजीकरण को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा जैसे शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही गैंग गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए तैयार किया गया है।

हरियाणा

- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे राज्य ऐसा प्रावधान करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह निर्णय सेवा के बाद अग्निवीरों के भविष्य की सुरक्षा के लिए एक व्यापक योजना के हिस्से के रूप में लिया गया है।
- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की, जिसमें हरियाणा पुलिस की नौकरियों में 20% आरक्षण शामिल है, जिससे यह भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने ऐसी गारंटी दी है। इसके अतिरिक्त, स्व-रोजगार के लिए क्वायिटी ऋण और निजी सुरक्षा भूमिकाओं के लिए बंदूक लाइसेंस में प्राथमिकता के प्रावधान पेश किए गए, जिसका उद्देश्य सेवा के बाद अग्निवीरों के भविष्य के कल्याण को सुनिश्चित करना है। ये कदम अग्निवीरों की आजीविका को सुरक्षित करने के लिए हरियाणा की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
- हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित दो हड़प्पा सभ्यता स्थलों - मिताथल और तिघराना - को आधिकारिक तौर पर संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है। 4,400 साल से भी पुराने ये स्थल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत मूल्यवान हैं, जो हड़प्पा और हड़प्पा के बाद के काल में प्रारंभिक कृषि समाजों, नगर नियोजन, शिल्प उद्योगों और व्यापार के विकास पर प्रकाश डालते हैं। हरियाणा प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1964 के तहत हरियाणा विरासत और पर्यटन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से अब इन स्थलों को कानूनी संरक्षण में लाया गया है। इस कदम का उद्देश्य इन प्राचीन बस्तियों को अतिक्रमण और क्षति से बचाना है, साथ ही बाड़ लगाने और सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी।

महाराष्ट्र

- मुगल काल से पहले की विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 8 अप्रैल, 2025 को खुल्ताबाद का नाम बदलकर उसके मूल नाम रत्नापुर करने की घोषणा की है। यह घोषणा सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने की। छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित खुल्ताबाद में औरंगजेब का मकबरा है, साथ ही आजम शाह और आसफ जाह प्रथम की कब्रें भी हैं। मुगल काल के दौरान इसका नाम बदल दिया गया था।
- रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई की उपनगरीय रेल सेवाओं को 30% तक बढ़ाने के लिए अगली पीढ़ी की स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली कवच 5.0 की घोषणा की। दिसंबर 2025 तक विकसित होने





वाला कवच 5.0 सुरक्षा को बढ़ाता है, ऑटो-ब्रेकिंग के साथ लोको पायलटों का समर्थन करता है और प्रतिकूल मौसम में भी सुचारु संचालन सुनिश्चित करता है।

मध्य प्रदेश

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के तहत चीता परियोजना संचालन समिति ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान से चीतों को लगभग 300 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है, जो एक जुड़े हुए परिदृश्य में 60-70 चीतों की मेटा-आबादी स्थापित करने की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है। प्रोजेक्ट चीता (2022 में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के चीतों के साथ लॉन्च) के तहत यह कदम, जगह, शिकार की उपलब्धता पर चिंताओं को संबोधित करता है।

ओडिशा

- सिमिलीपाल, ओडिशा का एक अनोखा और पारिस्थितिक रूप से समृद्ध क्षेत्र, अब आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। ओडिशा सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना के साथ यह फैसला लिया गया, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। इस महत्वपूर्ण कदम के साथ सिमिलीपाल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है और ओडिशा में भितरकनिका के बाद दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। यह निर्णय राज्य के संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है और "विकसित ओडिशा" की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

पंजाब

- पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, राज्य में पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल कर रही है। नंगल को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए प्रारंभिक बजट ₹10 करोड़ निर्धारित किया गया है। वहीं, श्री आनंदपुर साहिब स्थित झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य को पंजाब के पहले तेंदुआ सफारी गंतव्य के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। ये योजनाएँ 'बदलदा पंजाब' बजट 2025-26 का हिस्सा हैं, जिसे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रस्तुत किया। इस बजट में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ के लिए भी विशेष आवंटन किया गया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, जैव विविधता का संरक्षण करना, रोजगार सृजन करना और पंजाब की सांस्कृतिक धरोहर को सशक्त बनाना है।

तेलंगाना

- तेलंगाना सरकार ने भूमि शासन में ऐतिहासिक सुधार की शुरुआत की है - इसके तहत तेलंगाना भू भारती (अधिकार अभिलेख) अधिनियम, 2025 को लागू किया गया है। यह अधिनियम पूर्ववर्ती धरनी पोर्टल प्रणाली में आई खामियों और नागरिकों की व्यापक शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य से लाया गया है। भू भारती अधिनियम का मूल उद्देश्य भूमि प्रशासन को अधिक पारदर्शी, कुशल और समावेशी बनाना है। यह अधिनियम विकेंद्रीकरण और नागरिक भागीदारी को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है, जिससे भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली को जनोन्मुखी और भरोसेमंद बनाया जा सके।

तमिलनाडु

- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विधानसभा में केंद्र-राज्य संबंधों, संवैधानिक प्रावधानों और नीतियों की समीक्षा हेतु एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। इस समिति का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए सुझाव देना है। यह कदम भारतीय संविधान की संघीय भावना के अनुरूप उठाया गया है, खासकर उस पृष्ठभूमि में जब राज्यों की शक्तियों में कटौती को लेकर चिंता बढ़ रही है। तीन सदस्यीय यह समिति जनवरी 2026 तक अपनी अंतरिम रिपोर्ट और दो वर्षों के भीतर अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।
- तमिलनाडु ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है। राज्य ने 9.69% की दर से विकास किया, जो देश में सबसे अच्छा है और पिछले 10 वर्षों में तमिलनाडु के लिए भी सबसे अधिक है। यह वृद्धि दर्शाती है कि तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था साल दर साल मजबूत होती जा रही है।

त्रिपुरा

- त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने 21 अप्रैल, 2025 को स्वामी विवेकानंद मैदान, अगरतला में 'गरिया और बोरशो बोरोन उत्सव 2025' का उद्घाटन किया। दो दिवसीय उत्सव में गरिया पूजा मनाई जाती है, जो त्रिपुरी और रियांग समुदायों के लिए एक प्रमुख धार्मिक आयोजन है, जो शांति और समृद्धि के लिए भगवान शिव को समर्पित है। इस उत्सव में पारंपरिक नृत्य, लोकगीत, रवींद्र संगीत और जादू के शो के साथ-साथ क्षेत्रीय व्यंजनों को प्रदर्शित करने वाले स्थानीय खाद्य स्टॉल भी शामिल हैं।

उत्तराखंड

- नैनीताल के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत, नैनी झील, जल स्तर में गंभीर गिरावट का सामना कर रही है, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे कम 4.7 फीट पर पहुंच गई है, जिससे संभावित पेयजल की कमी की चिंता बढ़ गई है। झील शहर की 76% पानी की मांग को पूरा करती है, लेकिन कम बारिश, कम बर्फबारी, अनियोजित विकास और प्रदूषण जैसे कारकों ने स्थिति को और खराब कर दिया है। विशेषज्ञ चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्राकृतिक कार्याकल्प और सतत विकास प्रथाओं सहित समग्र संरक्षण दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देते हैं।
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण अभियान 2025 (जल संरक्षण अभियान) के तहत भागीरथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप नागरिकों को नौलों, धाराओं और वर्षा आधारित नदियों जैसे खतरे में पड़े जल स्रोतों की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है, जिससे उनके संरक्षण के लिए सरकार को तुरंत कार्रवाई करने में मदद मिलती है। अभियान की थीम, "धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा" जल संसाधनों के संरक्षण के लिए सामूहिक कार्रवाई पर जोर देती है।

पश्चिम बंगाल

- पश्चिम बंगाल में 30 अप्रैल, 2025 को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दीघा में जगन्नाथ धाम मंदिर के उद्घाटन के साथ एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम की मेजबानी करने की तैयारी है। इस हाई-प्रोफाइल समारोह में लगभग 12,000-14,000 लोग शामिल होंगे, जिनमें मुख्यमंत्री, राजनीतिक नेता, मशहूर हस्तियां और उद्योगपति जैसे वीआईपी अतिथि शामिल होंगे।





केंद्र शासित प्रदेश

- जम्मू-कश्मीर सरकार ने महिलाओं के लिए एक निःशुल्क बस सेवा शुरू की है, जिसका उद्देश्य लैंगिक-समावेशी गतिशीलता को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुरू की गई इस सेवा के तहत महिलाएं पूरे केंद्र शासित प्रदेश में स्मार्ट सिटी ई-बसों और जेकेआरटीसी बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं। इस पहल में शहरी क्षेत्रों में 200 ई-बसें और कश्मीर और जम्मू क्षेत्रों में 235 जेकेआरटीसी बसें शामिल हैं।

शुभारंभ और उद्घाटन:

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मार्च, 2025 को MY-Bharat पहल के तहत ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर लॉन्च किया, जिसमें बच्चों को नए शौक और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अपने मन की बात संबोधन में उन्होंने तकनीकी शिविर, पर्यावरण पाठ्यक्रम और नेतृत्व कार्यक्रम जैसे अवसरों पर प्रकाश डाला। कैलेंडर में जन औषधि केंद्रों के अध्ययन दौरे, सीमावर्ती गांवों का दौरा (वाइब्रेंट विलेज कैपेन) और सांस्कृतिक और खेल गतिविधियाँ शामिल हैं।
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर बिहार में 800 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर शहरी विकास, सहकारी क्षेत्र, कानून व्यवस्था के बुनियादी ढांचे और परिवहन परियोजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की घोषणा की गई।
- नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 अप्रैल 2025 को "नीति एनसीएईआर स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम" पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल को नीति आयोग और नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) के सहयोग से विकसित किया गया है। यह पोर्टल राज्यों की वित्तीय, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों से संबंधित व्यापक डेटा प्रदान करता है, जिससे राज्यों को बेहतर वित्तीय प्रबंधन और नीतिगत निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

महत्वपूर्ण त्यौहार

- छोटानागपुर क्षेत्र, खास तौर पर झारखंड में आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला सरहुल उत्सव, वसंत ऋतु के आगमन और नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। 1 अप्रैल, 2025 को आयोजित होने वाला यह उत्सव साल के पेड़ का सम्मान करता है, जिसे गांव की देवी सरना मां का निवास माना जाता है। यह त्यौहार सूर्य और पृथ्वी के मिलन का प्रतीक है, जो जीवन के लिए आवश्यक है, और विशेष रूप से आदिवासी पहचान और अधिकारों को मुखर करने के लिए गहरा सांस्कृतिक, पारिस्थितिक और राजनीतिक महत्व रखता है।
- पांडिचेरी हेरिटेज फेस्टिवल के 11वें संस्करण की शुरुआत पुडुचेरी के तमिल क्वार्टर में जीवंत 'बीधी विलायट्टू' (स्ट्रीट गेम्स) के साथ हुई, जिसमें 250 से ज्यादा बच्चे और कई निवासी शामिल हुए। ईश्वरन कोइल और अन्ना सलाई के बीच आयोजित इस फेस्टिवल में शहर की संस्कृति और इतिहास का जश्न मनाया गया, जिसमें पल्लंगुडी, पम्बरम, धयम और पाचा कुथिराई जैसे पारंपरिक खेल शामिल थे। पीपल फॉर पांडिचेरी हेरिटेज और पॉडीकैन द्वारा सह-आयोजित इस कार्यक्रम ने समुदाय को सफलतापूर्वक जोड़ा, जिसमें पारंपरिक गतिविधियों, भोजन और मौज-मस्ती के साथ सड़कें जीवंत हो उठीं।

- माधवपुर मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने 6 अप्रैल, 2025 को रामनवमी के दौरान भगवान कृष्ण और रुक्मणीजी के दिव्य मिलन के उपलक्ष्य में किया था। पोरबंदर के माधवपुर में आयोजित यह सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एकता और सांस्कृतिक सद्भाव का प्रतीक है। 2018 में इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम का दर्जा दिए जाने के बाद से, इस मेले का महत्व बढ़ गया है और केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया जैसे गणमान्य व्यक्ति इसमें शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री पटेल ने धार्मिक पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करते हुए रुक्मणी मंदिर में नई तीर्थ सुविधाओं का भी शुभारंभ किया।

विविध राष्ट्रीय समाचार

- व्यापक वित्तीय समावेशन को समर्थन देने के लिए, इंडिया पोस्ट ने निष्पांन इंडिया म्यूचुअल फंड के साथ साझेदारी की है, ताकि घर-घर जाकर केवाईसी सत्यापन सेवाएं प्रदान की जा सकें, जिससे सभी के लिए, विशेष रूप से दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए निवेश प्रक्रिया सरल हो सके।
- ब्रासीलिया में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत ने ब्रिक्स देशों के बीच एकजुट जलवायु नेतृत्व की जोरदार वकालत की। सतत विकास और 2030 जलवायु एजेंडा पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत ने 1.3 ट्रिलियन डॉलर हासिल करने की रणनीति के रूप में "बाकू से बेलेम रोडमैप" का प्रस्ताव रखा।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अप्रैल, 2025 को छोटे बिस्मटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। इस यात्रा का उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना है, जिसमें व्यापार, संपर्क और आर्थिक सहयोग पर विशेष जोर दिया जाएगा।
- कारगिल विजय दिवस 2025 समारोह के हिस्से के रूप में भारतीय सेना द्वारा जुबर स्टेडियम में बटालिक क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना, खेलों को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं को जोड़ना था। यह स्थानीय शिल्प कौशल को बढ़ावा देने का भी एक प्रयास था।
- केंद्र सरकार ने देश भर में 440 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) स्थापित करने की एक बड़ी पहल की है। इन विद्यालयों का उद्देश्य आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, खासकर उन ब्लॉकों में जहाँ 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति (एसटी) की आबादी है।
- राज्यसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को 12 घंटे की विस्तृत चर्चा के बाद मंजूरी दे दी, जिसमें पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। यह मंजूरी लोकसभा द्वारा 288-232 मतों से विधेयक पारित किए जाने के एक दिन बाद मिली।
- नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय रेलवे ने फरवरी 2025 तक 2,249 स्टेशनों और सेवा भवनों में 209 मेगावाट सौर ऊर्जा सफलतापूर्वक स्थापित की है। यह एक असाधारण वृद्धि दर को दर्शाता है, पिछले 5 वर्षों में 1,489 नए सौर प्रतिष्ठान स्थापित किए गए हैं।
- 27 मार्च, 2025 तक केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के तहत केंद्र के हिस्से से कोई धनराशि नहीं मिली है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवंटन स्वीकृत हो चुके हैं। शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राज्यसभा में CPI(M) MP जॉन ब्रिटास द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में यह खुलासा किया।





- भारत सरकार ने बिहार में दो परिवर्तनकारी बुनियादी ढांचे की पहलों को हरी झंडी दे दी है – पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर और कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना। इन परियोजनाओं को पीएम के नेतृत्व में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने मंजूरी दे दी है।
- नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 अप्रैल 2025 को “नीति एनसीआईआर स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम” पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल को नीति आयोग और नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) के सहयोग से विकसित किया गया है। यह पोर्टल राज्यों की वित्तीय, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों से संबंधित व्यापक डेटा प्रदान करता है, जिससे राज्यों को बेहतर वित्तीय प्रबंधन और नीतिगत निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।
- मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली को एक बड़ी तकनीकी मजबूती देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ‘कवच 5.0’ नामक अगली पीढ़ी की स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (ATP) प्रणाली के कार्यान्वयन की घोषणा की है। यह उन्नत प्रणाली ट्रेन की आवृत्ति में 30% तक की वृद्धि करने में सहायक होगी, जिससे लगभग 80 लाख दैनिक यात्रियों को राहत मिलेगी। ‘कवच’ न केवल खराब मौसम के दौरान ट्रेन की सुरक्षा को बढ़ाता है, बल्कि यदि लोको पायलट समय पर प्रतिक्रिया नहीं करता है तो यह अपने आप ब्रेक लगाकर संभावित दुर्घटना को रोकने में सक्षम है। यह कदम रेलवे संचालन को और अधिक सुरक्षित, सुगम और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।
- भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) ने अपने 75वें वर्षगांठ का भव्य आयोजन किया, जिसे ढाका में भारत के हाई कमिशन के अंतर्गत भारतीय सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित किया गया। इस समारोह में 1950 में स्थापना के बाद से ICCR की विरासत, सांस्कृतिक कूटनीति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका, और भारत-बांग्लादेश सांस्कृतिक संबंधों में इसके गहरे योगदान को उजागर किया गया। कार्यक्रम में पारंपरिक प्रस्तुतियाँ शामिल थीं और इसमें दोनों देशों के बीच कलात्मक एवं शैक्षिक पहलों के जीवंत आदान-प्रदान को भी प्रदर्शित किया गया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में ₹3,880 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, शिक्षा, कानून व्यवस्था, जनकल्याण और सांस्कृतिक विरासत जैसे क्षेत्रों में फैली हुई हैं। इनका उद्देश्य वाराणसी को एक आधुनिक शहर में परिवर्तित करना है, साथ ही इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना भी है। इसके अंतर्गत कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, और कारीगरों, छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों तथा छोटे व्यवसायों के कल्याण को सुनिश्चित करना शामिल है।
- भारत की हरित ऊर्जा महत्वाकांक्षाएं काफी हद तक उन महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं, जो सौर पैनल, पवन टर्बाइन, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और बैटरी भंडारण जैसी तकनीकों के लिए अनिवार्य हैं। इन आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (National Critical Mineral Mission – NCMM) की शुरुआत की है।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्लोवाकिया और पुर्तगाल की चार दिवसीय राजकीय यात्रा के अंतिम दिन स्लोवाकिया के नित्रा शहर स्थित कॉन्टेंटाइन द फिलॉसॉफर यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें उनके उल्लेखनीय सार्वजनिक सेवा कार्य, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता, तथा शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के समर्थन के लिए प्रदान किया गया। यह सम्मान भारत की वैश्विक नेतृत्व में बढ़ती प्रतिष्ठा और लोकतांत्रिक मूल्यों एवं समावेशी शासन के प्रतिनिधित्व में राष्ट्रपति मुर्मू की अद्वितीय भूमिका को दर्शाता है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा ने हाल ही में भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन को रूपांतरित करने के सरकार के निरंतर प्रयासों के तहत इंटर-एम्स रेफरल पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली द्वारा देश में ही विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य मरीजों के रेफरल सिस्टम को बेहतर बनाना और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति को सुव्यवस्थित करना है।
- भारत की हरित ऊर्जा महत्वाकांक्षाएं काफी हद तक उन महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं, जो सौर पैनल, पवन टर्बाइन, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और बैटरी भंडारण जैसी तकनीकों के लिए अनिवार्य हैं। इन आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (National Critical Mineral Mission – NCMM) की शुरुआत की है।
- वैश्विक विस्तार की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) अहमदाबाद दुबई में अपना पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने जा रहा है। यह निर्णय IIM-अहमदाबाद और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) सरकार के बीच हुए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर के बाद लिया गया है। यह पहल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की उच्च शिक्षा की पहुंच को मजबूत बनाएगी। दुबई कैंपस में शुरुआत में वैश्विक पेशेवरों और उद्यमियों के लिए एक वर्षीय पूर्णकालिक MBA प्रोग्राम शुरू किया जाएगा।





- भारत द्वारा अफ्रीकी चीता को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क (KNP) में फिर से जंगल में बसाए जाने के दो साल बाद, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 20 अप्रैल 2025 को हासिल होगी, जब दो वयस्क चीतों को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य (GWSW) में स्थानांतरित किया जाएगा। यह कदम चीता पुनर्वास परियोजना के विस्तार का प्रतीक है और मंदसौर जिले में स्थित GWSW को चीतों के लिए दूसरा घर बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। यह निर्णय चीता परियोजना की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में लिया गया और यह केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच संरक्षण, अनुसंधान और ईको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हो रहे साझा प्रयास को दर्शाता है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास स्थित विजिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे। यह भारत के समुद्री अवसंरचना क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी, क्योंकि यह देश का पहला सेमी-ऑटोमेटेड और वास्तविक डीप-वॉटर अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांशशिपमेंट पोर्ट होगा। यह परियोजना केरल सरकार, केंद्र सरकार और अडानी पोर्ट्स के बीच एक सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) के तहत विकसित की गई है। अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों के निकट स्थित इस बंदरगाह से भारत की व्यापारिक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है और यह केरल को एक प्रमुख समुद्री केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।
- कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि 1 मई 2025 से मौजूदा फास्टैग आधारित टोल संग्रह प्रणाली को हटाकर उपग्रह आधारित टोल प्रणाली शुरू की जाएगी। इन दावों को खारिज करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार ने इसके विपरीत, कुछ चयनित टोल प्लाज़ाओं पर एक उन्नत एएनपीआर-फास्टैग आधारित बिना बाधा वाली टोलिंग प्रणाली (Barrier-Less Tolling System) के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की घोषणा की है।
- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से आग्रह किया है कि कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) की अब तक की पहली थर्ड-पार्टी मूल्यांकन प्रक्रिया वर्ष 2025 के अंत तक पूरी कर ली जाए। समिति ने यह भी जोर दिया कि नवंबर 1995 में शुरू हुई इस योजना के तहत दी जा रही न्यूनतम पेंशन राशि ₹1,000 को अब महंगाई में आई तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए।
- केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली स्थित नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी (NDTL) में एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट (APMU) का उद्घाटन किया। यह पहल भारत के एंटी-डोपिंग प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत देती है, जिससे देश अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होता है और निष्पक्ष, स्वच्छ और नैतिक खेलों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
- भारतीय विमानन क्षेत्र 2026 तक दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला बड़ा विमानन बाजार बनने की ओर अग्रसर है, ऐसा एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) का कहना है। हालांकि कुल विमानन बाजार के आकार में चीन अभी भी काफी आगे है, लेकिन भारत की तेज़ी से होती वृद्धि का कारण है देश की विशाल आबादी में बढ़ती हवाई यात्रा की मांग, जहाँ प्रति व्यक्ति हवाई यात्रा अभी भी बहुत कम है। बढ़ते बुनियादी ढांचे का विकास, नीतिगत सुधार और मध्यम वर्ग की बढ़ती आकांक्षाएं इस वृद्धि को और गति दे रही हैं। अगले तीन दशकों में, भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़े विमानन बाजार के रूप में बना रहेगा, लेकिन विकास दर के मामले में यह शीर्ष पर रहेगा।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल 2025 को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में माता-पिता को सख्त चेतावनी दी है, जिससे बच्चों की तस्करी के बढ़ते खतरे के प्रति अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि तस्करी के गिरोह बच्चों को यौन शोषण, बंधुआ मजदूरी, बाल विवाह और अवैध गोद लेने जैसे अपराधों के लिए शिकार बना रहे हैं। अदालत ने विशेष रूप से यह चिंता व्यक्त की कि अब ये आपराधिक नेटवर्क तकनीक का दुरुपयोग करके अपने जाल फैला रहे हैं, जबकि सरकारी और संस्थागत उपाय अभी भी इन चुनौतियों से निपटने में अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।
- पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण को सरल बनाने और पर्यावरणीय सेवाओं में अहम भूमिका निभाने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने उद्योगों के लिए एक नया वर्गीकरण लागू किया है। इस संशोधित श्रेणीकरण में “आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं” (Essential Environmental Services – EES) के लिए एक नई ‘ब्लू श्रेणी’ बनाई गई है। इस ब्लू श्रेणी में वे उद्योग शामिल हैं जो पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में सीधे योगदान करते हैं, जैसे वेस्ट-टू-एनर्जी संयंत्र, बायोमाइनिंग इकाइयाँ, और कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र। इन उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण की मंजूरी (consent) की अवधि लंबी दी जाएगी, जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा।
- भारत अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विदेशी कंपनियों को 49% तक हिस्सेदारी लेने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है, जो कि देश के सबसे संरक्षित क्षेत्रों में से एक के लिए एक महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन है। यह पहल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने, कोयले पर निर्भरता को कम करने और महत्वाकांक्षी कार्बन उत्सर्जन कमी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
- कैलाश मानसरोवर यात्रा (केएमवाई) एक महत्वपूर्ण वार्षिक तीर्थयात्रा है, जो भारत और चीन के बीच गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक मानी जाती है। यह यात्रा हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। माना जाता है कि माउंट कैलाश की परिक्रमा करने से आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होता है, जबकि मानसरोवर झील में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह तीर्थयात्रा 2020 में COVID-19 महामारी और सीमा तनावों के कारण स्थगित कर दी गई थी। पांच वर्षों के बाद इसका पुनः आरंभ होना धार्मिक पर्यटन और द्विपक्षीय सहयोग में एक सकारात्मक विकास का संकेत है।
- भारतीय उच्च शिक्षा और कला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत, पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से “डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी” का दर्जा प्रदान किया गया है। यह कदम संस्थान की यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होता है और सिनेमा व टेलीविज़न अध्ययन के क्षेत्र में शैक्षणिक स्वायत्तता, पाठ्यक्रम में लचीलापन और शोध नवाचार के लिए नए द्वार खोलता है।





- राजनयिक और सैन्य तनावों के बीच एक बड़े घटनाक्रम में, पाकिस्तान ने 1972 की शिमला समझौता को निलंबित कर दिया है। साथ ही, वाघा बॉर्डर को बंद, भारत के साथ सभी व्यापारिक गतिविधियाँ रोक दी गई हैं, और भारतीय एयरलाइनों के लिए अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने और राजनयिक संबंधों को घटाने के जवाब में लिया गया है। इन कदमों की पृष्ठभूमि में पहलगाम आतंकी हमले की त्रासदी है, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी। जैसे-जैसे दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, सभी मौजूदा द्विपक्षीय समझौते और संवाद तंत्र ठप हो चुके हैं।
- जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें एक विदेशी नागरिक सहित 26 लोगों की जान गई, के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े जवाबी कदम उठाए हैं। भारत ने इस हमले में सीमा पार आतंकवाद की स्पष्ट संलिप्तता के प्रमाणों का हवाला देते हुए त्वरित कार्रवाई की है। यह निर्णय भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा इकाई—कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS)—की आपात बैठक में लिए गए। इस बैठक में एक पाँच-सूत्रीय रणनीतिक कार्ययोजना को

मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करना और भारत में उसकी किसी भी प्रकार की गतिविधि और प्रभाव को सीमित करना है।

- भारत और पाकिस्तान, जो कि पड़ोसी होने के बावजूद अक्सर कूटनीतिक रूप से तनावपूर्ण संबंधों में रहते हैं, के बीच व्यापार हमेशा सीमित रहा है, फिर भी यह महत्वपूर्ण रहा है। ऐतिहासिक रूप से, राजनीतिक तनावों के कारण दोनों देशों के वैश्विक व्यापार में एक-दूसरे के साथ व्यापार की हिस्सेदारी बेहद कम रही है, लेकिन कुछ खास वस्तुएं ऐसी रही हैं जो पाकिस्तान से भारत को लगातार निर्यात होती रही हैं।
- एक नाटकीय बदलाव के तहत, भारत ने 1960 में लागू हुई सिंधु जल संधि (इंडस वॉटर ट्रीटी) को पहली बार निलंबित कर दिया है, जिसके दूरगामी भू-राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। यह कदम जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के एक दिन बाद उठाया गया, जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की जान ले ली। यह हमला मुंबई 26/11 के बाद सबसे भीषण नागरिक हमला माना जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स

अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स: सितम्बर 2025

- चीन ने एससीओ शिखर सम्मेलन में 2 बिलियन डॉलर देने का वादा किया: 2025 एससीओ शिखर सम्मेलन में, चीन ने 2 बिलियन डॉलर के अनुदान और ऋण, 100 स्थानीय परियोजनाओं, विस्तारित छात्रवृत्ति और जिम्मेदार एआई विकास पर तियानजिन घोषणा की घोषणा की।
- प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया: तियानजिन में 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन में, प्रधानमंत्री मोदी ने सभ्यतागत संवाद मंच का प्रस्ताव रखते हुए और वैश्विक शासन सुधारों का समर्थन करते हुए तीन स्तंभों - सुरक्षा, संपर्क और अवसर - पर जोर दिया।
- एससीओ घोषणापत्र में पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा: तियानजिन घोषणापत्र में 22 अप्रैल, 2025 को हुए पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई, आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट रुख की पुष्टि की गई और खुफिया जानकारी साझा करने का आह्वान किया गया।
- अफ़ग़ान छात्र छात्रवृत्तियाँ: भारत ने नौ भारतीय विश्वविद्यालयों को कवर करने वाले आईसीसीआर के ई-विद्याभारती पोर्टल के माध्यम से शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए 18-35 आयु वर्ग के अफ़ग़ान छात्रों के लिए 1,000 ई-छात्रवृत्ति की घोषणा की।
- डब्ल्यूएचओ आत्महत्या चेतावनी: विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में 7.27 लाख मामलों के साथ, वैश्विक स्तर पर आत्महत्या से होने वाली 100 मौतों में से 1 मौत होती है, और युवाओं की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया गया है।

- भारत-सिंगापुर रक्षा सहयोग: सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान, दोनों देश राजनयिक संबंधों के 60 वर्षों का जश्न मनाते हुए प्रौद्योगिकी सह-विकास पर केंद्रित रक्षा सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए।
- नेपाल सोशल मीडिया प्रतिबंध: नेपाल ने औपचारिक पंजीकरण अनिवार्य करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और वाइबर सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया।
- सिंगापुर ने एक्ट ईस्ट नीति के तहत समुद्री सुरक्षा को मजबूत करते हुए मलक्का जलडमरूमध्य में गश्त करने की भारत की योजना का समर्थन किया।
- राजनीतिक अशांति के बीच, अनुतिन चार्नविराकुल ने 63% मतों के साथ थाईलैंड के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता और सत्तारूढ़ दल को हराया।
- पेरिस में कीव मित्र राष्ट्र शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन सहित 26 देशों ने यूक्रेन को युद्धोत्तर सुरक्षा का वचन दिया।
- एंजेलो रेनर के इस्तीफे के बाद, डेविड लैमी एक बड़े कैबिनेट फेरबदल में ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री, न्याय सचिव और लॉर्ड चांसलर बने।
- 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा ने माउंट फूजी पर विजय प्राप्त की: कोकिची अकुजावा जापान के सबसे ऊंचे पर्वत 3,776 मीटर पर चढ़ने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए, जिसकी पुष्टि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने की।
- चुनावी हार के बाद जापानी प्रधानमंत्री का इस्तीफा: एलडीपी की ऐतिहासिक हार के बाद, शिगेरु इशिबा ने 7 सितंबर, 2025 को पद छोड़ दिया, जिससे नेतृत्व विवाद शुरू हो गया।





- भारत-इजराइल ने द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बेजेल स्मोट्रिच ने नई दिल्ली में निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 800 मिलियन डॉलर के मौजूदा द्विपक्षीय निवेश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- नेपाल ने घातक विरोध प्रदर्शनों के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटाया: सरकार ने जनरल जेड के नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद देशव्यापी सोशल मीडिया प्रतिबंध को वापस ले लिया, जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख शहरों में 19 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए।
- फ्रांकोइस बायरू को फ्रांसीसी प्रधानमंत्री पद से हटाया गया: प्रधानमंत्री ने 8 सितंबर, 2025 को 364-194 के अंतर से विश्वास मत खो दिया, जो मैक्रों की अल्पमत सरकार के तहत एक साल से भी कम समय में प्रधानमंत्री का दूसरा इस्तीफा है।
- नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा: सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ जनरेशन ज़ी के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के बाद, प्रधानमंत्री ने 9 सितंबर, 2025 को पद छोड़ दिया। इस विरोध प्रदर्शन में 20 लोगों की मौत हो गई और 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए। संसद में आग लगा दी गई।
- HIRE अधिनियम 2025 भारत के आईटी निर्यात के लिए खतरा: प्रस्तावित अमेरिकी सीनेट विधेयक विदेशी प्रदाताओं को आउटसोर्सिंग भुगतान पर 25% उत्पाद शुल्क लगाने की मांग करता है, जिससे भारत के 100 अरब डॉलर के आईटी निर्यात क्षेत्र पर अनुपालन बोझ पड़ सकता है।
- इरफ़ान अली ने गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता: 1 सितंबर को हुए चुनाव में पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी ने नेशनल असेंबली की 65 में से 36 सीटें हासिल कीं, जिससे तेल-संचालित आर्थिक विकास के बीच एक मज़बूत जनादेश मिला।
- मैक्रों ने लेकोर्नु को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया: 39 वर्षीय वफादार और पूर्व रक्षा मंत्री ने फ्रांस्वा बायरू की जगह ली, जो संसदीय चुनौतियों के बावजूद व्यापार-समर्थक एजेंडे को जारी रखने का संकेत है।
- नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने दूसरा कार्यकाल हासिल किया: बढ़ती लागत संबंधी चिंताओं के बीच प्रोग्रेस पार्टी द्वारा रिकॉर्ड 48 सीटें हासिल करने के बावजूद, जोनास गहर स्टोएरे की लेबर पार्टी ने 87 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया।
- लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर बने: एआई तकनीक के विकास से प्रेरित ओरेकल के शेयरों में 41% की वृद्धि के बाद, ओरेकल के सह-संस्थापक ने \$395.7 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ एलोन मस्क को पीछे छोड़ दिया।
- फिच ने भारत के विकास पूर्वानुमान को उन्नत किया: रेटिंग एजेंसी ने मजबूत घरेलू मांग और उपभोक्ता खर्च का हवाला देते हुए भारत के वित्त वर्ष 2025 के आर्थिक विकास अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया।

- भारत-मॉरीशस 680 मिलियन डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज: मॉरीशस के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान, भारत ने अनुदान-आधारित परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ऋण सहायता सहित व्यापक आर्थिक पैकेज की घोषणा की।
- भारत ने इजरायल-फिलिस्तीन के लिए दो-राज्य समाधान के संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव का समर्थन किया; अमेरिका ने इस कदम का विरोध किया।
- अल्बानिया ने AI कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति की: सार्वजनिक खरीद और डिजिटल सेवाओं की देखरेख करने वाले AI-संचालित आभासी मंत्री "डिएला" का अनावरण करने वाला यह देश दुनिया का पहला देश बन गया।
- अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की, जिससे ढील चक्र की शुरुआत का संकेत मिला।
- पश्चिम एशिया में तनाव के बीच सऊदी अरब और पाकिस्तान ने आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- ऑस्ट्रेलिया ने 2035 तक उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य बढ़ाकर 62% कर दिया।
- उत्तर कोरिया के प्रतिरोध के बावजूद, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप के तीन-चरणिय परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्धता जताई।
- भारत-नॉर्वे समुद्री सुरक्षा वार्ता: ओस्लो में पहली बार समुद्री सुरक्षा, निरस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार वार्ता आयोजित की गई, जिसका ध्यान सुरक्षित समुद्री पर्यावरण और आर्थिक विकास पर केंद्रित था।
- भारत और कनाडा व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने और रक्षा, ऊर्जा तथा महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए।

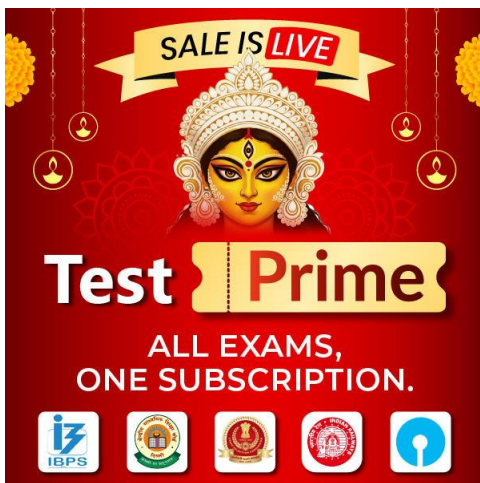
अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स: अगस्त 2025

- शंघाई में आयोजित वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस (WAIC) 2025 के दौरान चीन के प्रधानमंत्री ली क्वांग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के विकास और उससे जुड़ी सुरक्षा जोखिमों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए वैश्विक सहमति की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उनका यह बयान उस समय आया है जब अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा तेज़ होती जा रही है, और दोनों देश वैश्विक AI नेतृत्व के लिए प्रयासरत हैं। ली क्वांग ने कहा कि AI का विकास मानवता के लिए अपार संभावनाएं रखता है, लेकिन इसके साथ जुड़े खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए सभी देशों को मिलकर एक जिम्मेदार और सुरक्षित ढांचा तैयार करना होगा।
- तुर्की ने इस्तांबुल में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले (IDEF) 2025 में अपना सबसे शक्तिशाली गैर-परमाणु बम 'गज़ैप' (तुर्की भाषा में अर्थ: 'क्रोध') का अनावरण किया है। यह बम 970 किलोग्राम वजन का है और इसे तुर्की की रक्षा तकनीक में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। गज़ैप को अब तक के सबसे घातक पारंपरिक हथियारों में से एक बताया गया है, जो तुर्की की सैन्य क्षमता को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है।





- संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) ने महीनों की तनावपूर्ण वार्ताओं के बाद एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर सहमति बना ली है, जिससे दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच लंबे समय से जारी शुल्क विवाद का अंत हो गया है। यह समझौता स्कॉटलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के बीच हुई उच्च स्तरीय बातचीत के बाद घोषित किया गया। इस समझौते के तहत अब अमेरिका में यूरोपीय संघ के निर्यात पर 15% शुल्क लगाया जाएगा, जो कि पहले ट्रंप द्वारा प्रस्तावित 30% की दर का आधा है। इस सौदे को इतिहास का सबसे बड़ा व्यापार समझौता माना जा रहा है।
- काकेशस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक सफलता में, अज़रबैजान और आर्मेनिया के नेताओं ने शुकुवार को व्हाइट हाउस में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे विवादित नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र को लेकर दशकों से चली आ रही दुश्मनी का औपचारिक अंत हो गया। यह बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेज़बानी में हुई। इस समझौते का उद्देश्य लड़ाई को "हमेशा के लिए" समाप्त करना और दोनों देशों के बीच स्वतंत्र यात्रा, व्यापार तथा कूटनीतिक संबंधों का मार्ग प्रशस्त करना है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने हेपेटाइटिस के एक रूप हेपेटाइटिस-डी को कैंसरकारक घोषित कर दिया है। हेपेटाइटिस लिवर में इन्फ्लेमेशन की स्थिति है। हेपेटाइटिस-ए, बी हो या सी इन सभी को लिवर के लिए गंभीर समस्याओं का कारण माना जाता रहा है। अब हेपेटाइटिस-डी को लेकर काफी चर्चा की जा रही है। हेपेटाइटिस डी लिवर का एक गंभीर रोग है जो हेपेटाइटिस डी वायरस (एचडीवी) के कारण होता है। यह अनोखा है क्योंकि यह केवल हेपेटाइटिस बी वायरस (एचबीवी) से संक्रमित व्यक्तियों को ही संक्रमित करता है।
- अमेरिका ने कई प्रमुख भारतीय वस्तुओं पर 50% का भारी शुल्क लगाकर भारतीय निर्यातकों को बड़ा झटका दिया है। यह कदम रूस के साथ नई दिल्ली के निरंतर तेल व्यापार के बाद उठाया गया है, जिस पर वाशिंगटन की तीखी प्रतिक्रिया हुई है। इस अचानक और एकतरफा फैसले ने कपड़ा, रत्न एवं आभूषण, रसायन और समुद्री खाद्य जैसे प्रमुख भारतीय निर्यात क्षेत्रों को झकझोर दिया है। उद्योग जगत के नेताओं को डर है कि इससे अमेरिका को होने वाले निर्यात में लगभग आधी कमी आ सकती है, जिससे राजस्व और दीर्घकालिक व्यापार संबंध दोनों प्रभावित होंगे।
- अपनी रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत और रूस ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मज़बूत करने के लिए एक औपचारिक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजधानी स्थित वाणिज्य भवन में आयोजित आधुनिकीकरण और औद्योगिक सहयोग पर भारत-रूस कार्य समूह के 11वें सत्र के दौरान यह समझौता हुआ।
- द्विपक्षीय व्यापार को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, फिलीपींस के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने चावल, भैंस के मांस, सब्जियों, फलों और मूंगफली सहित प्रमुख भारतीय खाद्य उत्पादों का आयात बढ़ाने पर सहमति जताई है। यह समझौता कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडी) और भारतीय चावल निर्यातक संघ (आईआरईएफ) के साथ हुई चर्चा के बाद हुआ है।
- विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कहा कि मोल्दोवा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का 107वां सदस्य बन गया है। एक्स पर एक पोस्ट में विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में भारत में मोल्दोवा की राजदूत एना तबान के साथ बैठक के दौरान अनुसमर्थन पत्र सौंपा गया। यह घोषणा भारत के विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा नई दिल्ली में औपचारिक अनुसमर्थन के बाद की गई।
- रूस के कामचटका प्रायद्वीप में स्थित क्राशेनिनिकोव ज्वालामुखी ने आज लगभग 600 वर्षों के बाद विस्फोट किया, जो एक दुर्लभ और नाटकीय प्राकृतिक घटना है। यह विस्फोट स्थानीय समयानुसार सुबह 2:50 बजे शुरू हुआ, जिसमें राख के विशाल बादल लगभग 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक आकाश में फैल गए। यह ज्वालामुखी 15वीं शताब्दी के बाद पहली बार फटा है।
- भारत की ऊर्जा सोर्सिंग रणनीति अगस्त 2025 में और अधिक रूसी कच्चे तेल की ओर झुकी रही। आयात बढ़कर 20 लाख बैरल प्रतिदिन (bpd) हो गया, जो जुलाई के 16 लाख बैरल प्रतिदिन से अधिक है। वैश्विक एनालिटिक्स फर्म Kpler के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त के पहले पखवाड़े में भारत के कुल कच्चे तेल आयात का 38% हिस्सा रूस से आया। यह दर्शाता है कि कच्चे तेल की खरीद में भारत की प्राथमिकता आर्थिक हितों को दी जा रही है, भले ही भू-राजनीतिक दबाव मौजूद हो।
- भारत और सिंगापुर ने नई दिल्ली में आयोजित तीसरे भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन (ISMIR) के दौरान अपने लंबे समय से चले आ रहे निरंतर विकसित होते द्विपक्षीय संबंधों की पुनः पुष्टि की। इस बैठक में दोनों देशों के शीर्ष मंत्रियों ने भाग लिया और व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) के तहत स्थापित मजबूत आधारों को और सुदृढ़ करने के लिए प्रमुख सहयोग क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया। यह मंच दोनों देशों की क्षेत्रीय विकास, नवाचार और इंडो-पैसिफिक में रणनीतिक तालमेल की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- विदेश नीति में एक बड़े बदलाव के तहत, ऑस्ट्रेलिया सितंबर 2025 में होने वाले 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) सत्र में औपचारिक रूप से फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देगा। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने 11 अगस्त 2025 को इस निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य दो-राष्ट्र समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन बढ़ाना, गाज़ा में युद्धविराम को प्रोत्साहित करना और बंधकों की रिहाई को आगे बढ़ाना है।





- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने कड़ी चेतावनी जारी की है कि अत्यधिक गर्मी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है, बढ़ते तापमान, लंबे समय तक चलने वाली लू और बिगड़ती वायु गुणवत्ता के कारण गंभीर जन स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो रहे हैं। संगठन देशों से इस बढ़ते जलवायु खतरे के प्रभावों को कम करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ और ताप-स्वास्थ्य कार्य योजनाएँ लागू करने का आग्रह कर रहा है।
थाईलैंड और कंबोडिया ने संघर्षविराम व्यवस्था पर सहमति बना ली है, जिसके तहत दोनों देशों ने सभी प्रकार की सशस्त्र झड़पों को रोकने और अपनी साझा सीमा पर मौजूदा सैनिक तैनाती को बनाए रखने का संकल्प लिया है। यह समझौता मलेशिया के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक विशेष जनरल बॉर्डर कमेटी (जीबीसी) बैठक के दौरान औपचारिक रूप से किया गया। इस बैठक में दोनों देशों के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने भाग लिया, जबकि अमेरिका, चीन और मलेशिया ने तीसरे पक्ष के पर्यवेक्षक के रूप में भागीदारी की।
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लंबे समय से सहयोगी रहे सर्जियो गोर को भारत में अगला अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत नामित किया है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत-अमेरिका संबंध ऊँचे टैरिफ और भू-राजनीतिक मतभेदों के चलते तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिससे यह भूमिका और भी संवेदनशील और अहम हो जाती है। गोर की नियुक्ति ट्रंप के इस इरादे को रेखांकित करती है कि वे अपने भरोसेमंद सहयोगियों को वैश्विक स्तर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर नियुक्त करना चाहते हैं।
- फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका 24-26 अगस्त तक भारत की यात्रा पर रहेंगे, जहाँ वे प्रधानमंत्री मोदी से वार्ता करेंगे, राष्ट्रपति मुर्मू से मिलेंगे तथा भारतीय विश्व मामलों की परिषद में व्याख्यान देंगे। एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जुड़ाव में, फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामामादा राबुका 24 से 26 अगस्त, 2025 तक भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा घोषित इस यात्रा से शासन, विकास और सांस्कृतिक आदान-प्रदान सहित कई क्षेत्रों में भारत-फिजी द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की उम्मीद है।
- ईरान ने संघर्ष के बाद क्षेत्रीय तनाव के बीच ओमान की खाड़ी में कूज मिसाइलों, युद्धपोतों और वायु इकाइयों के साथ “सस्टेनेबल पावर 1404” मिसाइल अभ्यास शुरू किया। अपनी रणनीतिक ताकत का प्रदर्शन करते हुए, ईरान ने उत्तरी हिंद महासागर और ओमान की खाड़ी में “सस्टेनेबल पावर 1404” नामक एक बड़े पैमाने पर मिसाइल अभ्यास किया। गुरुवार को शुरू हुआ यह दो दिवसीय अभ्यास, 12 जून को हुए संघर्ष के बाद ईरान का पहला बड़ा सैन्य अभ्यास है, जो बढ़ते क्षेत्रीय तनाव और हालिया सैन्य असफलताओं के बाद तेहरान द्वारा समुद्री प्रतिरोध स्थापित करने के प्रयासों को दर्शाता है।
- भारत और सऊदी अरब ने रणनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए शिपिंग और लॉजिस्टिक्स पर संयुक्त कार्यदल (Joint Working Group – JWG) गठित करने का निर्णय लिया है। यह समझौता 20 अगस्त 2025 को आयोजित एक उच्चस्तरीय वर्चुअल बैठक में हुआ, जिसमें भारत के केंद्रीय मंत्री सरवानंद सोनोवाल और सऊदी अरब के परिवहन एवं लॉजिस्टिक सेवाओं के मंत्री सालेह बिन नासिर अल-जासर शामिल हुए।

- दुबई ने अपने वैश्विक व्यवसाय केंद्र की स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए “वन फ्रीज़ोन पासपोर्ट” की शुरुआत की है। यह एकीकृत लाइसेंसिंग प्रणाली कंपनियों को एक ही लाइसेंस के तहत अमीरात के सभी फ्रीज़ोन में काम करने की अनुमति देती है। दुबई फ्रीज़ोन काउंसिल द्वारा लॉन्च किया गया यह सुधार लागत को कम करने, नौकरशाही को घटाने और व्यापार विस्तार को तेज़ करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
- दुनिया के सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मशहूर दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (DXB) ने हवाई यात्रा को भविष्य की दिशा देने वाला ऐतिहासिक कदम उठाया है। “ट्रैवल विडआउट बॉर्डर्स” पहल के तहत दुबई ने एआई-संचालित पैसेंजर कॉरिडोर लॉन्च किया है, जिसमें यात्रियों को अब इमिग्रेशन के लिए किसी भी तरह के दस्तावेज़ दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। यात्री महज़ 14 सेकंड में इमिग्रेशन क्लियर कर सकेंगे।
- बीजिंग में आयोजित वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स ने भविष्य की रोबोटिक्स की झलक पेश की, जहाँ 16 देशों के 500 से अधिक ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने हिस्सा लिया। चार दिन तक चले इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन ने खेल, नृत्य और वास्तविक कार्यों में रोबोट्स की क्षमता को परखते हुए तकनीकी कौशल, शक्ति और सीमाओं का मिश्रण प्रस्तुत किया।
- वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत और जापान ने अपनी गहरी मित्रता को दोहराते हुए एक सुरक्षित, नवोन्मेषी और समृद्ध भविष्य के लिए साहसिक दृष्टि प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 29-30 अगस्त 2025 की जापान यात्रा के दौरान (15वाँ भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन), दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और जन-जन सहयोग में कई समझौतों के साथ अपने विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत किया। इस सम्मेलन की मेज़बानी जापानी प्रधानमंत्री इशिबा शिगेरु ने की।
- केंद्रीय मंत्री किरति वर्धन सिंह ने घोषणा की कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत-अफ्रीका व्यापार 100 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है, जो 2019-20 के 56 अरब डॉलर की तुलना में लगभग दोगुना है। यह मजबूत वृद्धि न केवल भारत की स्थिति को अफ्रीका में शीर्ष पाँच निवेशकों में मजबूत करती है, बल्कि गहरे सहयोग और साझा विकास की दिशा में एक रणनीतिक कदम भी है।
- छात्रों में बढ़ती सोशल मीडिया की लत से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया ने एक नया क़ानून पारित किया है, जिसके तहत स्कूल की कक्षाओं में मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरणों का उपयोग प्रतिबंधित होगा। संसद में इस विधेयक को सर्वदलीय समर्थन मिला और यह मार्च 2026 से लागू होगा। इस तरह दक्षिण कोरिया उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो शैक्षणिक वातावरण में स्मार्टफोन उपयोग पर रोक लगा रहे हैं।
- इंगा रुगिनिएने, जो एक सोशल डेमोक्रेट और पूर्व मजदूर नेता रही हैं, को लिथुआनिया की संसद ने आधिकारिक रूप से देश की नई प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दे दी है। उनका यह चयन लिथुआनिया के राजनीतिक नेतृत्व में एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि वे सामाजिक सुरक्षा और श्रम मंत्री की भूमिका से देश के सर्वोच्च कार्यकारी पद पर पहुंच रही हैं।





- भारत और जापान ने ऊर्जा क्षेत्र में अपनी बढ़ती साझेदारी को और मज़बूत किया है। इसके तहत 25 अगस्त 2025 को आयोजित भारत-जापान ऊर्जा संवाद (Ministerial-level India-Japan Energy Dialogue) में दोनों देशों ने भाग लिया, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुआ। इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के विद्युत एवं आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल तथा जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री श्री मुतो योजी ने की। यह संवाद दोनों देशों के बीच जापान-भारत स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी (Clean Energy Partnership) के रणनीतिक महत्व को दर्शाता है।
- भारत के डाक विभाग ने घोषणा की है कि 25 अगस्त 2025 से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएँ अस्थायी रूप से निलंबित कर दी जाएँगी। यह कदम अमेरिकी सरकार द्वारा हाल ही में लागू कार्यकारी आदेश 14324 के जवाब में उठाया गया है, जिसके तहत अमेरिका 29 अगस्त 2025 से USD 800 तक के आयात पर लागू शुल्क-मुक्त "डी मिनिमिस छूट" को समाप्त कर रहा है। इस बदलाव के चलते अब हर प्रकार के आयातित सामान पर सीमा शुल्क लगेगा, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो।

अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स: जुलाई 2025

- यूरोपीय संघ (EU) ने 2 जुलाई 2025 को अपने लंबे समय से प्रतीक्षित जलवायु योजना की घोषणा की, जिसके तहत 2040 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर की तुलना में 90% तक घटाने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की ईयू की व्यापक प्रतिबद्धता का हिस्सा है। हालांकि, सभी सदस्य देशों का समर्थन सुनिश्चित करने के लिए इस योजना में कुछ लचीलापन जोड़ा गया है, जिससे विभिन्न देशों में बहस छिड़ गई है।
- रूस ने अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है, और 2021 के बाद ऐसा करने वाला वह पहला देश बन गया है। यह ऐतिहासिक कदम अफ़गानिस्तान के साथ वैश्विक राजनयिक संबंधों को नया आकार दे सकता है और व्यापक अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव के द्वार खोल सकता है।
- पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का अध्यक्ष बन गया है और वो इस पूरे महीने ही अध्यक्ष रहेगा। हालांकि उसे किसी वोटिंग के जरिए ये अध्यक्षता नहीं मिली, बल्कि रोटेशन नंबर आने से ये मौका मिला है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद पूरे महीने परिषद का नेतृत्व करेंगे। पाकिस्तान इसी साल जनवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया था। परिषद की अध्यक्षता इसके 15 सदस्य देशों के बीच बदलती रहती है। इस परिषद में 5 स्थायी सदस्य के अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं।
- औद्योगिक सहयोग बढ़ाने और संधारणीय विनिर्माण को आगे बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में, भारत और संयुक्त अरब अमीरात

(यूएई) ने हरित इस्पात और उच्च श्रेणी के एल्युमीनियम के उत्पादन में सहयोग करने के लिए चर्चा शुरू की है। केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने स्वच्छ ऊर्जा-संचालित धातु विज्ञान, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और दीर्घकालिक संसाधन सुरक्षा में तालमेल का पता लगाने के लिए भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) ढांचे के तहत यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री महामहिम अब्दुल्ला बिन तौक अल मारी से मुलाकात की।

- एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव में, ग्रुप ऑफ सेवन (G7) देशों ने अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वैश्विक न्यूनतम कर ढांचे से छूट देने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे उन्हें एक विशेष "साइड-बाय-साइड" कराधान समाधान की पेशकश की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन द्वारा आगे बढ़ाई गई यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करेगी कि अमेरिकी निगमों पर घरेलू और विदेशी दोनों तरह के मुनाफे पर केवल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कर लगाया जाए, जो संभवतः 2021 से OECD ढांचे के तहत बातचीत की गई वैश्विक कर संरचना को नया रूप दे सकता है।
- भारत ने बांग्लादेश से भूमि मार्ग से कुछ जूट उत्पादों और बुने हुए कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि इसकी अनुमति केवल न्हावा शेवा बंदरगाह के माध्यम से दी गई है। 17 मई को भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों जैसी कुछ वस्तुओं के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगा दिया था। इन प्रतिबंधों के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में जूट उत्पाद, एकल सन यार्न, जूट का एकल यार्न, बुने हुए कपड़े या फ्लेक्स तथा जूट के बिना साफ किए बुने हुए कपड़े शामिल हैं।
- यूरोपीय संघ (ईयू) ने 2 जुलाई, 2025 को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 90% की कटौती करने के लिए 2040 के अपने जलवायु लक्ष्य को साझा किया, जिसका लक्ष्य 2050 तक कार्बन तटस्थता हासिल करना है। व्यापक समर्थन प्राप्त करने के लिए, योजना 2036 से 3% तक अंतराष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट का उपयोग करने की अनुमति देती है। इसने जलवायु समूहों के बीच इस प्रयास के कमजोर होने की चिंता जताई है। वोपके होकेस्ट्रा और उर्सुला वॉन डेर लेयेन जैसे प्रमुख यूरोपीय संघ के नेताओं ने इस योजना का महत्वाकांक्षी लेकिन लचीला बताते हुए बचाव किया। अंतिम निर्णय जुलाई में चर्चा और सितंबर में मतदान के बाद आएगा, उम्मीद है कि इसे ब्राजील में COP30 से पहले पारित कर दिया जाएगा।
- यूनेस्को ने 11 जुलाई 2025 को कंबोडिया के तीन ऐतिहासिक स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया, जो खमेर रूज शासन की क्रूरता से जुड़े हैं। यह निर्णय पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान लिया गया, जो इस तानाशाही शासन के उदय की 50वीं वर्षगांठ पर हुआ। इस कदम का उद्देश्य इन स्थलों को त्रासदी की याद के रूप में संरक्षित करना और शांति व शिक्षा को बढ़ावा देना है।





- विश्व धरोहर समिति ने तीन अफ्रीकी धरोहर स्थलों – मेडागास्कर, मिस्र और लीबिया – को संकटग्रस्त स्थलों की यूनेस्को की सूची से हटा दिया है तथा इन स्थलों पर खतरों को कम करने और उनकी सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिक अखंडता को बहाल करने के सफल प्रयासों की सराहना की है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने एक बयान में कहा कि यह निर्णय पेरिस में जारी विश्व धरोहर समिति (डब्ल्यूएचसी) के 47वें सत्र के दौरान नौ जुलाई को लिया गया।
- यूएई गोल्डन वीज़ा एक दीर्घकालिक निवास कार्यक्रम है जो दुनिया भर के निवेशकों, कुशल पेशेवरों, छात्रों और अन्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करता है। हाल ही में, एक नई वीज़ा योजना पर काफ़ी ध्यान आकर्षित हुआ है, जिसकी कथित लागत 23 लाख रुपये है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं।
- यूरोपीय संघ (EU) के वित्त मंत्रियों ने 8 जुलाई 2025 को बुल्गारिया को यूरो अपनाने की अंतिम मंजूरी दे दी। अब बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाएगा। इस ऐतिहासिक कदम के साथ बुल्गारिया यूरोज़ोन का 21वां सदस्य बन जाएगा। यह निर्णय यूरोपीय एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति मानी जा रही है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को स्थिरता, निवेश और व्यापार के नए अवसर मिलेंगे।
- त्रिनिदाद और टोबैगो दुनिया का आठवां देश और कैरेबियाई क्षेत्र का पहला देश बन गया है जहाँ भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) सेवाएं शुरू की गई हैं। इस पहल के तहत अब भारतीय पर्यटक अपने मोबाइल यूपीआई ऐप्स का उपयोग करके सीधे भारतीय रुपये में भुगतान कर सकेंगे। इस सेवा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा के दौरान की गई, जो भारत और इस द्वीपीय राष्ट्र के बीच डिजिटल सहयोग और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की सदस्यता ग्रहण की है। इस कदम से एनडीबी के कुल सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। यह घोषणा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 10वीं बैठक के बाद की गई, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं में विकास को गति देने के उद्देश्य से हुई थी।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफगानिस्तान के तालिबान शासकों से महिलाओं और लड़कियों पर अत्याचार खत्म करने और देश में सक्रिय आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। यह प्रस्ताव 116 देशों के समर्थन से पारित हुआ, जबकि अमेरिका और इज़रायल ने इसके खिलाफ मतदान किया। भारत, चीन, रूस और ईरान सहित 12 देशों ने मतदान से परहेज (abstain) किया।
- दुनिया के मशहूर अरबपति और टेक्नोलॉजी उद्यमी एलन मस्क ने “अमेरिका पार्टी” नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू करने की घोषणा की है। यह घोषणा उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर की। उनका कहना है कि यह पार्टी अमेरिका की दू-पार्टी सिस्टम (दो दलों वाली व्यवस्था) का एक वैकल्पिक रास्ता बनेगी। यह कदम ऐसे समय में आया है जब मस्क का अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सार्वजनिक विवाद हुआ है।
- हवाई के माउना लोआ ज्वालामुखी की चोटी पर स्थित एक छोटा वेधशाला केंद्र पिछले 65 वर्षों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) की मात्रा माप रहा है। इस स्टेशन ने जलवायु परिवर्तन के सबसे ठोस और दीर्घकालिक प्रमाण दिए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि मानव गतिविधियां पृथ्वी को गर्म कर रही हैं। लेकिन अब अमेरिकी सरकार इसे फंड देना बंद करने की योजना बना रही है, जिससे यह ऐतिहासिक स्टेशन बंद हो सकता है।
- सुरिनाम की संसद ने 6 जुलाई 2025 को जेनिफर गेरलिंग्स-साइमन्स को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना। यह ऐतिहासिक निर्णय ऐसे समय पर आया है जब दक्षिण अमेरिकी देश सुरिनाम आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उनकी नियुक्ति को सुरिनाम के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है और लोगों को उम्मीद है कि वे देश की वित्तीय स्थिति सुधारने में मदद करेंगी।
- रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच यूक्रेन की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पूर्व आर्थिक मंत्री और अमेरिका के साथ यूक्रेन के खनिज समझौते की प्रमुख वार्ताकार यूलिया स्विरीडेंको को यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने डेनिस शमहल का स्थान लिया है, जो अब देश के रक्षा मंत्री की भूमिका संभालेंगे। वहीं निवर्तमान रक्षा मंत्री रुस्तेम उमेरोव को अमेरिका में यूक्रेन का नया राजदूत बनाया जा सकता है। स्विरीडेंको इससे पहले यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री पद पर तैनात थीं। यह नियुक्ति 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन की पहली नेतृत्वगत बदलाव है और राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की की युद्धकालीन शासन में नई ऊर्जा भरने की कोशिश को दर्शाती है।
- यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण एशिया ने वर्ष 2024 में बच्चों के टीकाकरण में अब तक का सर्वोच्च स्तर प्राप्त कर लिया है। यह उपलब्धि डिप्थीरिया, खसरा और रूबेला जैसी घातक लेकिन रोकी जा सकने वाली बीमारियों से लाखों बच्चों को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस सफलता के पीछे सरकारों की निरंतर प्रतिबद्धता, नवाचारपूर्ण सेवा वितरण मॉडल, और हर बच्चे तक—यहाँ तक कि दूर-दराज़ के क्षेत्रों में रहने वालों तक—पहुँचने के लिए किए गए व्यापक प्रयास शामिल हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग (DoD) ने OpenAI, Google, Anthropic और एलन मस्क की कंपनी xAI को 200-200 मिलियन डॉलर के अनुबंध (contracts) दिए हैं। इन अनुबंधों का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके राष्ट्रीय रक्षा प्रणाली को अधिक स्मार्ट और तेज़ बनाना है, ताकि अमेरिका वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों में आगे बना रहे।
- भारत पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL) शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे आधुनिक डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके भारत की समृद्ध पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों का संरक्षण और संवर्धन करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे वैश्विक स्वास्थ्य सेवा नवाचार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया है।
- फ्रांस और उसके प्रशांत क्षेत्र न्यू कैलेडोनिया के बीच एक नए समझौते की घोषणा की गई है, जिसके तहत न्यू कैलेडोनिया को अधिक अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन वह अब भी फ्रांस का हिस्सा बना रहेगा। यह समझौता 2024 में हुई हिंसक झड़पों के बाद आया है और इसे स्वतंत्रता के समर्थकों और विरोधियों के बीच तनाव को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।





- भारत ने प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा के दौरान नए समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत मालदीव को 4,850 करोड़ की लोन सहायता प्रदान किया है। इस यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) और द्विपक्षीय निवेश संधि पर वार्ता की भी शुरुआत हुई, जो पड़ोसी पहले और महासागर (MAHASAGAR) दृष्टिकोण के तहत संबंधों को नई ऊर्जा देने की दिशा में एक निर्णायक पहल है। यह कदम राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ु के कार्यकाल में भारत-मालदीव संबंधों में आई खटास को कम करने का संकेत भी देता है, जिन्होंने अपने चुनाव अभियान में “इंडिया आउट” की नीति को प्रमुखता दी थी।
- भारत ने आधिकारिक रूप से पाँच वर्षों के अंतराल के बाद चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू कर दिया है, जो भारत-चीन संबंधों में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और जन-जन के बीच जुड़ाव का संकेत है। यह कदम दोनों देशों के बीच पर्यटन, सॉफ्ट डिप्लोमेसी और क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्र में एक सतर्क लेकिन सकारात्मक पुनर्संतुलन को दर्शाता है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब भारत इनबाउंड टूरिज्म को पुनर्जीवित करने के व्यापक प्रयास कर रहा है और हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी दोबारा शुरू किया गया है—जो एक आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा है और जिसे चीनी मूल के अनुयायियों के बीच विशेष मान्यता प्राप्त है।
- फ्रांस ने सितंबर 2025 में आधिकारिक रूप से फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। यह फैसला फ्रांस को ऐसा करने वाला पहला G7 देश बना देगा। यह ऐलान राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने किया, जो इज़राइल-फ़िलिस्तीन संघर्ष पर यूरोप के रुख में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब गाज़ा में हिंसा लगातार जारी है, और क्षेत्रीय शांति को लेकर चिंताएं गहराती जा रही हैं।
- चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में यारलुंग त्सांगपो नदी पर दुनिया के सबसे बड़े जलविद्युत बांध के निर्माण की शुरुआत कर दी है। यह परियोजना पर्यावरणीय और भू-राजनीतिक चिंताओं को जन्म दे रही है, विशेष रूप से भारत और बांग्लादेश में, जो इस नदी के डाउनस्ट्रीम (नदी के बहाव की दिशा में नीचे) क्षेत्रों में स्थित हैं। बांध के कारण जल प्रवाह, पारिस्थितिकी तंत्र और पड़ोसी देशों की जल सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक और शैक्षिक एजेंसी यूनेस्को (UNESCO) से हटने का फैसला किया है, यह निर्णय पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के तहत लिया गया है। यह कदम ट्रंप के पहले कार्यकाल में 2017 में लिए गए ऐसे ही निर्णय की पुनरावृत्ति है, जिसे राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2023 में पलट दिया था। व्हाइट हाउस ने इस कदम के पीछे वैचारिक मतभेदों का हवाला दिया है, यह आरोप लगाते हुए कि यूनेस्को “वोक” और “विभाजनकारी” एजेंडों को बढ़ावा देता है, जो अमेरिकी हितों के अनुकूल नहीं हैं।
- हाल ही में रूस के कामचाटका प्रायद्वीप में एक के बाद एक शक्तिशाली भूकंपों की श्रृंखला दर्ज की गई, जिनमें सबसे तीव्र झटका 7.4 तीव्रता का था। इसका केंद्र स्थल समुद्र के अंदर, पेरोपावलोव्स्क-कामचात्स्की से 144 किलोमीटर पूर्व और 20 किलोमीटर की उथली गहराई पर स्थित था। प्रारंभ में सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन बाद में प्रशांत महासागर सुनामी चेतावनी केंद्र ने इसे वापस ले लिया, जिससे क्षेत्र में कुछ राहत की भावना देखी गई।
- श्रीलंका के कालुतारा ज़िले स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वास्काडुवा श्री सुभूति विहाराय में 21 जुलाई 2025 को अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया। यह पहल भारत और श्रीलंका के बीच आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक कूटनीति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जो सम्राट अशोक के श्रीलंकाई बौद्ध धर्म में योगदान को मान्यता देती है। यह विकास क्षेत्र में बौद्ध विरासत और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के निरंतर प्रयासों को भी दर्शाता है।
- भारत सरकार के मंत्रिमंडल ने यूनाइटेड किंगडम (यूके) के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को मंजूरी दे दी है, जिसे आधिकारिक रूप से समग्र आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) कहा जाता है। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 जुलाई 2025 को लंदन यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित किया जाएगा। इस समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहित करना है, जिसमें शुल्कों में कटौती, बाज़ार तक बेहतर पहुंच, सेवाओं, नवाचार और बौद्धिक संपदा के क्षेत्रों में सहयोग को सशक्त बनाना शामिल है। [Click here to read article](#)
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि वो दोबारा हावर्ड विश्वविद्यालय लौटना चाहती हैं। आईएमएफ की नंबर-2 की कुर्सी संभालने वाली गीता पहली महिला हैं। गीता गोपीनाथ पहली महिला हैं, जो आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट बनीं। उनका यह निर्णय IMF में एक महत्वपूर्ण युग का समापन है, जहाँ उन्होंने COVID-19 महामारी और रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसी वैश्विक आपदाओं के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोपीनाथ के कार्यकाल के दौरान IMF के शोध, विश्लेषण और वैश्विक आर्थिक समन्वय को नई ऊंचाइयाँ मिलीं, जिसे वैश्विक स्तर पर सराहा गया है।
- संयुक्त राष्ट्र (UN) में भारत की मतदान प्रवृत्ति में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। विशेष रूप से 2025 में मतदान से दूरी ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो भारत की विदेश नीति में एक नए चरण की शुरुआत को दर्शाता है। यह बदलाव एक ध्रुवीकृत वैश्विक व्यवस्था के प्रति भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया है, जिसमें वह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए एक अधिक मुखर और संतुलित वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने का प्रयास कर रहा है।

अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स: जून 2025

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून 2025 को बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC), लातविया, और लाइबेरिया को UNSC के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना। इनका कार्यकाल जनवरी 2026 से दिसंबर 2027 तक रहेगा। विशेष रूप से, लातविया पहली बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है, जो उसके लिए एक बड़ा कूटनीतिक उपलब्धि है।
- भारत की वैश्विक प्रशासनिक नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, भारत को अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (IIAS) का अध्यक्ष चुना गया है। यह अध्यक्षता 2025-2028 कार्यकाल के लिए होगी। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के सचिव वी. श्रीनिवास इस ब्रुसेल्स (बेल्जियम) स्थित अंतरराष्ट्रीय संस्था का नेतृत्व करेंगे। यह भारत के सार्वजनिक प्रशासन में सुधार और आधुनिकीकरण के प्रति प्रतिबद्धता का वैश्विक स्तर पर मान्यता है।



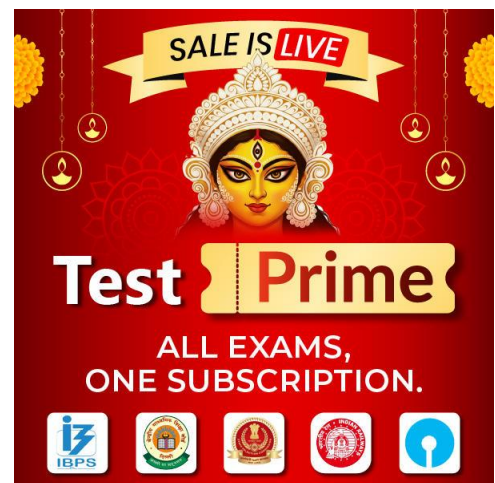


- बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसके प्रमुख मोहम्मद यूनुस हैं, ने हाल ही में नई श्रृंखला के बैंकनोट्स जारी किए हैं जिनमें अब देश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान का चित्र नहीं होगा। इन नए डिज़ाइन में प्राकृतिक दृश्यों, पुरातात्विक स्थलों और हिंदू व बौद्ध मंदिरों को दर्शाया गया है। यह कदम देश में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता के बीच राष्ट्रीय प्रतीकों को राजनीतिक रंग से मुक्त करने की दिशा में एक प्रतीकात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।
- निकारागुआ ने 2 जून 2025 को विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मत्स्य पालन सप्तिह समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिससे वह इस ऐतिहासिक संधि को अपनाने वाला 101वां सदस्य देश बन गया। यह कदम विश्व स्तर पर हानिकारक मछली पकड़ने की प्रथाओं को रोकने और समुद्री जैव विविधता बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। WTO के महानिदेशक एनगोर्ज़ी ओकोंजो-इवेला को निकारागुआ की राजदूत रोज़ालिया बोहोरकेज़ पालासियस द्वारा इस स्वीकृति का दस्तावेज सौंपा गया।
- महीनों की राजनीतिक अशांति के बाद ऐतिहासिक चुनावी बदलाव में, दक्षिण कोरिया की डेमोक्रेटिक पार्टी के उदार विपक्षी नेता ली जे-म्युंग को दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। उनकी जीत रूढ़िवादी नेता यूं सुक येओल के निष्कासन के बाद एक महत्वपूर्ण क्षण है, जिन्हें विवादास्पद मार्शल लॉ लागू होने के बाद हटा दिया गया था। विनम्र शुरुआत और आर्थिक पुनरुद्धार और व्यावहारिक कूटनीति के वादे वाली पृष्ठभूमि के साथ, ली ने उत्तर कोरिया, अमेरिकी व्यापार तनाव और ध्रुवीकृत घरेलू परिदृश्य पर बढ़ती चिंताओं के बीच नेतृत्व संभाला।
- वैश्विक वित्तीय मंच पर एक बड़े बदलाव में, जर्मनी ने 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है, जिससे जापान का 34 साल का वर्चस्व खत्म हो गया है। चालू खाता अधिशेष, विनिमय दर की गतिशीलता और संरचनात्मक आर्थिक रुझानों से प्रेरित यह परिवर्तन वैश्विक व्यापार और निवेश पैटर्न में व्यापक परिवर्तनों को दर्शाता है।
- विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी (वाडा) फाउंडेशन बोर्ड ने स्वतंत्र अध्यक्ष विटोल्ड बांका और उपाध्यक्ष यांग यांग को तीसरे और अंतिम तीन साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना है, जो 1 जनवरी, 2026 से 2028 के अंत तक प्रभावी रहेगा। बांका को 36 वोट मिले, जबकि दो वोटों ने मतदान में भाग नहीं लिया, जबकि यांग को सर्वसम्मति से फिर से चुना गया। दोनों नेताओं ने बोर्ड के विश्वास के लिए आभार व्यक्त किया और शिक्षा, एथलीट जुड़ाव और वैज्ञानिक अनुपालन को मजबूत करके दुनिया भर में स्वच्छ खेल की सुरक्षा के वादा के मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।
- लुईस मोंटेनेग्रो को हाल ही में हुए आम चुनावों के बाद एक बार फिर पुर्तगाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। केंद्र-दक्षिणपंथी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (PSD) और डेमोक्रेटिक अलायंस (AD) के नेता मोंटेनेग्रो की वापसी उस समय हुई है जब देश में राजनीतिक संतुलन नया रूप ले रहा है। इस बार संसद में दूर-दक्षिणपंथी चेगा (Chega) पार्टी दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। हालांकि चेगा की मांगों के बावजूद मोंटेनेग्रो ने फिलहाल किसी भी तरह के संवैधानिक सुधार से इनकार किया है। उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है।
- इज़राइल ने 13 जून को घोषणा की कि उसने ईरान भर में "दर्जनों परमाणु और सैन्य स्थलों" को निशाना बनाकर हमलों की एक श्रृंखला शुरू की है। यह कदम तेहरान और वाशिंगटन के बीच संवेदनशील कूटनीतिक जुड़ाव के बीच उठाया गया है, जहाँ दोनों पक्ष प्रतिबंधों में राहत के बदले ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर संभावित सीमाओं पर चर्चा कर रहे थे।
- क्षेत्रीय संघर्ष में बड़ी वृद्धि के तहत, इज़राइल ने अपने चल रहे सैन्य अभियान 'ऑपरेशन राइजिंग लायन' (Operation Rising Lion) के तहत दूसरे दौर के हमले शुरू कर दिए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है कि नतानज़ (Natanz) यूरेनियम संवर्धन केंद्र पर एक बड़ा विस्फोट हुआ है। इज़राइल ने ईरान की सैन्य और परमाणु अवसंरचना को निशाना बनाने की घोषणा की है, इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए "अस्तित्वगत खतरा" बताते हुए।
- ईरान ने घोषणा की है कि रूस उसके क्षेत्र में आठ नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगा, जो पहले से हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौते का हिस्सा हैं। यह घोषणा ईरान की परमाणु ऊर्जा संगठन (AEOI) के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लामी ने तब की, जब संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के सदस्य AEOI मुख्यालय, तेहरान के दौरे पर थे। यह कदम ईरान की नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षमता को तीन गुना बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है और रूस की रोसएटोम कंपनी इसमें प्रमुख साझेदार है।
- एक उच्च-दांव वाले समुद्री ऑपरेशन में, भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने सिंगापुर के कंटेनर जहाज एमवी वान हार्ड 503 पर लगी भीषण आग को बुझाने के लिए अग्निशमन और बचाव कार्य तेज कर दिया है, जो 9 जून 2025 से केरल तट से खतरनाक तरीके से भटक रहा है। 2,100 मीट्रिक टन से अधिक ईंधन और खतरनाक माल से लदा यह जहाज गंभीर पर्यावरणीय और नौवहन जोखिम पैदा करता है, क्योंकि यह भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में है।
- भारत और ईरान के बीच व्यापारिक संबंध ऐतिहासिक और रणनीतिक हितों से लंबे समय से प्रभावित रहे हैं, विशेष रूप से ऊर्जा, कृषि और खाद्य क्षेत्रों में। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद, गैर-प्रतिबंधित वस्तुएं—विशेष रूप से खाद्य और उपभोक्ता उत्पाद—भारतीय बाजार में लगातार पहुंच बना रही हैं। यह लेख भारत में उपलब्ध ईरानी उत्पादों की नवीनतम सूची, उनके वर्गीकरण और उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने वाले कारोबारी तंत्रों की पड़ताल करता है।
- पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और वैश्विक ऋणदाताओं का विश्वास फिर से प्राप्त करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा समर्थित 1 अरब अमेरिकी डॉलर की सिंडिकेटेड फाइनेंसिंग सुविधा पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पांच वर्षीय सुविधा को इस्लामिक और पारंपरिक दोनों प्रारूपों में संरचित किया गया है और यह पाकिस्तान की वित्तीय सुधारों तथा मैक्रोइकोनॉमिक रिकवरी में फिर से जागृत विश्वास को दर्शाती है। यह सौदा पाकिस्तान की दो वर्षों के बाद मध्य-पूर्वी वित्तीय बाजार में वापसी को भी चिह्नित करता है।





- भारत और यूक्रेन के बीच 18 जून 2025 को कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group – JWG) बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। यह बैठक दोनों देशों के कृषि और संबंधित क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारत से श्री अजीत कुमार साहू (संयुक्त सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग) और यूक्रेन से सुश्री ऑक्साना ओस्माचको (उप मंत्री, कृषि नीति एवं खाद्य मंत्रालय) ने की।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को 'अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष' घोषित किया है, जो वैश्विक कृषि में महिलाओं की अहम भूमिका को पहचानने और उसे मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस पहल का उद्देश्य विकासशील देशों में भूमि अधिकार, तकनीक, बाज़ार पहुंच और कृषि नीतियों में मौजूद लैंगिक असमानताओं को उजागर करना और उन्हें दूर करने के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित करना है।
- ईरान-इज़राइल संघर्ष में एक महत्वपूर्ण वृद्धि के रूप में, ईरान ने "ऑपरेशन डू प्रॉमिस 3" शुरू किया है, जो लगातार तीसरे दिन इज़राइली बुनियादी ढांचे पर मिसाइल हमलों की श्रृंखला है। यह अभियान, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) द्वारा संचालित है, और ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इज़राइली हमलों की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। इसमें AI आधारित मिसाइल प्रणाली और डिफेंस सैचुरेशन (भ्रम फैलाने की तकनीक) जैसे नए रणनीतिक हथियारों का प्रयोग किया गया है।
- OpenAI, जो ChatGPT का निर्माता है, को अमेरिकी रक्षा विभाग (U.S. Department of Defense) द्वारा \$200 मिलियन (लगभग ₹1,670 करोड़) का अनुबंध प्रदान किया गया है। यह अनुबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य अभियानों के लिए उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) उपकरणों के विकास के उद्देश्य से किया गया है। 16 जून 2025 को पेंटागन द्वारा इस सौदे की घोषणा की गई, जो जुलाई 2026 तक चलेगा और मुख्य रूप से वॉशिंगटन डी.सी. के आस-पास संचालित होगा।
- ब्लेज़ मेट्रेवेली को 1909 में अपनी स्थापना के बाद से यूनाइटेड किंगडम की विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। 15 जून, 2025 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर द्वारा घोषित, यह ऐतिहासिक निर्णय पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान जासूसी की दुनिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। सुश्री मेट्रेवेली, जो वर्तमान में MI6 में प्रौद्योगिकी और नवाचार की निदेशक हैं, साइबर सुरक्षा और डिजिटल खुफिया में अनुभव और विशेषज्ञता का खजाना लेकर आई हैं, जो आज के उभरते वैश्विक खतरों से निपटने के लिए आवश्यक है।
- एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव में, ग्रुप ऑफ सेवन (G7) देशों ने अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वैश्विक न्यूनतम कर ढांचे से छूट देने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे उन्हें एक विशेष "साइड-बाय-साइड" कराधान समाधान की पेशकश की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन द्वारा आगे बढ़ाई गई यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करेगी कि अमेरिकी निगमों पर घरेलू और विदेशी दोनों तरह के मुनाफे पर केवल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कर लगाया जाए, जो संभवतः 2021 से OECD ढांचे के तहत बातचीत की गई वैश्विक कर संरचना को नया रूप दे सकता है।
- भारत ने बांग्लादेश से भूमि मार्ग से कुछ जूट उत्पादों और बुने हुए कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि इसकी अनुमति केवल न्हावा शेवा बंदरगाह के माध्यम से दी गई है। 17 मई को भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों जैसी कुछ वस्तुओं के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगा दिया था। इन प्रतिबंधों के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में जूट उत्पाद, एकल सन यार्न, जूट का एकल यार्न, बुने हुए कपड़े या फ्लेक्स तथा जूट के बिना साफ किए बुने हुए कपड़े शामिल हैं।
- इजरायल के साथ 12 दिनों तक चले संघर्ष के बाद ईरान की संसद (मजलिस) ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ सहयोग को निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया है। यह कदम अमेरिका द्वारा ईरान के तीन परमाणु स्थलों पर हवाई हमलों के बाद उठाया गया है – जबकि ईरान IAEA और परमाणु अप्रसार संधि (NPT) दोनों का सदस्य है। इसके समानांतर, भारत में ईरान के दूतावास ने हाल की शत्रुता के दौरान भारत के लोगों की एकजुटता के लिए उनके प्रति गहरा आभार व्यक्त किया, जो कूटनीतिक आख्यानो और परमाणु निगरानी गतिशीलता में बदलाव को दर्शाता है।
- दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली ने हाल ही में अपने मंत्रिमंडल की घोषणा की है, जो देश के लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता का विश्वास बहाल करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यह घटनाक्रम पूर्व राष्ट्रपति यूं सुक-योल द्वारा दिसंबर 2024 में घोषित मार्शल लॉ और उसके कारण अप्रैल 2025 में उनके पद से हटाए जाने के बाद आया है।
- सोने ने अब आधिकारिक रूप से वैश्विक भंडार संपत्तियों में दूसरा सबसे बड़ा स्थान हासिल कर लिया है, यूरो को पीछे छोड़ते हुए। यह खुलासा यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) की जून 2025 रिपोर्ट में हुआ है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने भू-राजनीतिक तनाव, महंगाई की चिंता, और प्रमुख मुद्राओं (विशेष रूप से रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिकी प्रतिबंधों) की विश्वसनीयता को लेकर संदेह के चलते अपनी स्वर्ण होल्डिंग्स में तेज़ी से वृद्धि की। हालांकि, अब संकेत मिल रहे हैं कि यह खरीदारी की होड़ धीरे-धीरे थम सकती है, जो वैश्विक आरक्षित रणनीतियों में बदलाव को दर्शाता है।





अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स: मई 2025

- रोमन कैथोलिक चर्च के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण आया जब अमेरिकी कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट को 8 मई 2025 को चर्च का 267वां पोप चुना गया। उन्होंने पोप लियो चौदहवें (Leo XIV) नाम धारण किया और इस प्रकार वे संयुक्त राज्य अमेरिका से चुने जाने वाले पहले पोप बन गए। उन्होंने पोप फ्रांसिस का स्थान लिया, जिनका निधन 21 अप्रैल 2025 को हुआ था। इस घोषणा के साथ ही जब सेंट पीटर्स स्क्वायर में सफेद धुआं उठा और नई पोप की पहली झलक वेटिकन की बालकनी से मिली, तो हजारों की भीड़ उल्लास और आशा से झूम उठी।
- यमन के नेतृत्व में 5 मई, 2025 को एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला, जब देश की राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद ने वित्त मंत्री सलीम सालेह बिन ब्रिक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यह बदलाव अहमद अवद बिन मुबारक के इस्तीफे के बाद हुआ, जिन्होंने गंभीर संवैधानिक सीमाओं का हवाला देते हुए पद छोड़ दिया था।
- भारत और अंगोला के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेन्सो ने मई 2025 में भारत की राजकीय यात्रा पूरी की। इस यात्रा के दौरान आयुर्वेद, कृषि और संस्कृति के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए, साथ ही भारत ने अंगोला के रक्षा क्षेत्र के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता (Line of Credit) को मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त, अंगोला ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की सदस्यता लेकर इस क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को मजबूती दी और ISA का 123वां सदस्य बना।
- सिंगापुर की सत्तारूढ़ पार्टी पीपल्स एक्शन पार्टी (PAP) ने 3 मई 2025 को हुए ऐतिहासिक आम चुनाव में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के नेतृत्व में जोरदार जीत दर्ज की, जिसमें उसने 97 में से 87 संसदीय सीटें हासिल कीं। यह चुनाव प्रधानमंत्री वोंग की बतौर राष्ट्र प्रमुख पहली चुनावी परीक्षा थी, जो ली सिएन लूंग से नेतृत्व संभालने के बाद हुई। 65.57% की लोकप्रिय वोट हिस्सेदारी के साथ, सिंगापुर की जनता ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और क्षेत्रीय भू-राजनीतिक बदलावों के बीच PAP पर अपना विश्वास फिर से जताया।
- ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ ने लेबर पार्टी को आश्चर्यजनक रूप से प्रचंड जीत दिलाई है और लगातार दूसरा कार्यकाल सुरक्षित किया है। यह जीत, स्वास्थ्य सेवा, आवास की उपलब्धता और वैश्विक स्तर पर फैली सत्ता-विरोधी लहर के बीच आई है, और इसे पीटर डटन के नेतृत्व वाले रूढ़िवादी लिबरल-नेशनल गठबंधन के स्पष्ट अस्वीकार के रूप में देखा जा रहा है। एल्बनीज़ की यह जीत पिछले दो दशकों में किसी भी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की पहली लगातार दूसरी जीत है।
- नेपाल के लांगटांग में स्थित याला ग्लेशियर, जो कभी हिंदू कुश हिमालय (HKH) क्षेत्र में ग्लेशियोलॉजिकल प्रशिक्षण और क्रायोस्फीयर अनुसंधान का एक अहम केंद्र था, को अब आधिकारिक रूप से "मृत" घोषित कर दिया गया है। यह घोषणा 12 मई 2025 को की गई, जब वैज्ञानिकों, स्थानीय समुदायों और भिक्षुओं ने मिलकर एक भावुक स्मृति

समारोह आयोजित किया। यह घटना ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालयी ग्लेशियरों पर पड़ रहे गंभीर प्रभावों को उजागर करती है, जिनका दक्षिण एशिया की जल सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

डेनमार्क के कैस्सो (Kasso) में 3 मई 2025 को दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मेथनॉल उत्पादन संयंत्र उद्घाटित किया गया। यह परियोजना European Energy और जापान की Mitsui द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। संयंत्र प्रति वर्ष 42,000 मीट्रिक टन ई-मेथनॉल का उत्पादन करेगा, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा और बायोगैस संयंत्रों व अपशिष्ट जलाने से प्राप्त CO₂ का उपयोग होगा।

- पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रियाद, सऊदी अरब की यात्रा के दौरान सीरिया पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। यह निर्णय अमेरिका की सीरिया नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है, जिसका उद्देश्य वर्षों के संघर्ष, गृहयुद्ध और अंतरराष्ट्रीय अलगाव के बाद सीरिया के संक्रमणकालीन सरकार को समर्थन देना और स्थायित्व व शांति की राह को प्रशस्त करना है।
- अमेरिका और सऊदी अरब ने 142 बिलियन डॉलर (12.1 लाख करोड़ रुपए) का रक्षा समझौता किया, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मई 2025 की रियाद यात्रा के दौरान संपन्न हुआ। व्हाइट हाउस ने इसे अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा करार दिया है, जो दोनों देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक सहयोग को और गहरा करता है।
- वैश्विक आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन ने अपने लंबे समय से चले आ रहे व्यापार युद्ध में 90-दिवसीय संघर्ष विराम के तहत पारस्परिक टैरिफ में 115% की कटौती करने पर सहमति व्यक्त की है। जिनेवा में अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और चीनी उप प्रधानमंत्री हे लाइफेंग के बीच उच्च स्तरीय वार्ता के बाद अंतिम रूप दिया गया यह सौदा दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- भूटान की रॉयल सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में डिजिटल नवाचार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मई 2025 में Binance Pay और DK Bank के साथ साझेदारी में एक क्रिप्टोकॉरेसी-आधारित भुगतान प्रणाली शुरू की है। इस पहल के साथ भूटान पहला संप्रभु देश बन गया है जिसने आधिकारिक रूप से अपनी राष्ट्रीय पर्यटन नीति में क्रिप्टो भुगतान को शामिल किया है। यह प्रणाली वैश्विक पर्यटकों को एक सहज, नकद-मुक्त अनुभव प्रदान करती है और ग्रामीण भूटान में वित्तीय समावेशन को भी प्रोत्साहित करती है।
- भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए बातचीत फिर से शुरू कर दी है, जिसका 11वां दौर 12 मई 2025 से ब्रसेल्स में शुरू हुआ है। यह दौर समझौते के अंतरिम चरण को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो दो-चरणीय समझौता ढांचे का हिस्सा है और वर्षों के अंत तक समझौते को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा गया है। यह पहल भारत की व्यापारिक कूटनीति में हालिया प्रगति के बाद आई है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम के साथ FTA लगभग अंतिम चरण में पहुंच गया है।





- सऊदी अरब ने 22 मई 2025 को आधिकारिक रूप से TOURISE नामक एक वैश्विक मंच (ग्लोबल प्लेटफॉर्म) लॉन्च किया, जिसे पर्यटन, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्थिरता क्षेत्रों के वैश्विक नेताओं को जोड़ने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस मंच की घोषणा पर्यटन मंत्री अहमद अल-खतीब ने की, जिसका उद्देश्य पर्यटन उद्योग में निवेश के नए अवसर खोलना, प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना, और सहयोग व नवाचार के माध्यम से भविष्य की यात्रा नीतियों को आकार देना है। TOURISE का शुभारंभ सऊदी अरब की वैश्विक पर्यटन नेतृत्व की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, जो रणनीतिक अवसरचताना निवेश और नीतिगत सुधारों पर आधारित है।
- भारत ने एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन (APO) की 2025-26 कार्यकाल के लिए अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। यह जिम्मेदारी जकार्ता, इंडोनेशिया में 20-22 मई 2025 के बीच आयोजित 67वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग (GBM) के दौरान सौंपी गई। इस अवसर पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री अमरदीप सिंह भाटिया, सचिव, DPIIT और भारत के APO निदेशक ने किया। यह भारत की क्षेत्रीय उत्पादकता और नवाचार एजेंडों में बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।
- अल्जीरिया ने 19 मई 2025 को औपचारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की सदस्यता ग्रहण कर ली है — यह संस्था BRICS देशों द्वारा स्थापित की गई थी। यह कदम न केवल सतत विकास के प्रति अल्जीरिया की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि यह NDB की संस्थापक सदस्यों से परे उसके वैश्विक विस्तार को भी रेखांकित करता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 20 मई 2025 को जिनेवा में आयोजित अपनी वार्षिक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के दौरान दुनिया की पहली वैश्विक महामारी संधि (Global Pandemic Treaty) को अपनाया। इस संधि के पक्ष में 124 देशों ने वोट दिया, 11 देशों ने मतदान से परहेज किया, और किसी ने भी विरोध नहीं किया। इसका उद्देश्य भविष्य में महामारी की स्थिति में समानता आधारित और समन्वित वैश्विक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करना है। हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो 2025 की शुरुआत में WHO से बाहर हो चुका है, की अनुपस्थिति से क्रियान्वयन और वित्तीय सहायता को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।
- लाल सागर सुरक्षा संकट के चलते समुद्री यातायात और राजस्व पर पड़े भारी प्रभाव को देखते हुए, स्वेज नहर प्राधिकरण (Suez Canal Authority - SCA) ने बड़े मालवाहक जहाजों के लिए ट्रांजिट शुल्क में 15% की छूट देने की घोषणा की है। यह कदम अमेरिका और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बीच हुए संघर्षविराम समझौते के तुरंत बाद उठाया गया है। हूती विद्रोही 2023 के अंत से लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे थे। यह छूट 15 मई 2025 से लागू होगी और इसका उद्देश्य वैश्विक शिपिंग कंपनियों—विशेष रूप से कंटेनर जहाजों—को स्वेज नहर मार्ग पर लौटने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्वेज नहर, जो विश्व व्यापार की एक महत्वपूर्ण धुरी है, हाल के महीनों में इसके उपयोग और आय में भारी गिरावट देखी गई है।
- चीन और कंबोडिया ने मई 2025 के मध्य में “गोल्डन ड्रैगन-2025” संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है, जो दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के क्षेत्र में आकार, दायरे और तकनीकी परिष्कार के लिहाज से एक बड़ा विस्तार दर्शाता है। इस बार के अभ्यास में अत्याधुनिक मानव रहित युद्ध प्रणालियाँ शामिल हैं और यह ज़मीनी, समुद्री और हवाई अभियानों को कवर करता है। इसका उद्देश्य सामरिक समन्वय, मानवीय सहायता और आतंकवाद-रोधी क्षमताओं को सुदृढ़ करना है।

- सूडान की सेना प्रमुख जनरल अब्देल-फताह अल-बुरहान ने 19 मई 2025 को कामिल अल-ताएब इदरीस को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो अप्रैल 2023 में शुरू हुए गृहयुद्ध के बाद पहली बार यह पद भरा गया है। यह कदम राजनीतिक स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, खासकर खार्तूम पर सैन्य नियंत्रण की पुनः स्थापना के बाद।
- एक महत्वपूर्ण राजनयिक घटनाक्रम में रूस और यूक्रेन ने 16 मई 2025 को इस्तांबुल में तीन वर्षों में पहली बार सीधे वार्ता की। तुर्किये की मध्यस्थता में हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में, व्यापक संघर्षविराम पर सहमति नहीं बनी, लेकिन प्रत्येक देश से 1,000 युद्धबंदियों की अदला-बदली पर समझौता हुआ। वार्ता ने आगे बातचीत की संभावना का संकेत दिया, हालांकि क्षेत्रीय नियंत्रण और राजनीतिक मांगों को लेकर गहरी असहमति बनी रही।

अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स: अप्रैल 2025

- 4 अप्रैल, 2025 को बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर अगले दो वर्षों के लिए BIMSTEC का नया अध्यक्ष बन गया। इसे पिछले अध्यक्ष थाईलैंड से नेतृत्व प्राप्त हुआ। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनस ने अध्यक्षता स्वीकार की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश BIMSTEC को अधिक समावेशी (सभी को शामिल करना) और कार्रवाई-उन्मुख (वास्तविक परिणामों पर केंद्रित) बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- अग्रणी प्रौद्योगिकियों को अपनाने में भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जैसा कि UNCTAD के वैश्विक ‘अग्रणी प्रौद्योगिकियों के लिए तत्परता’ सूचकांक में 36वें स्थान पर पहुंचने से पता चलता है। यह 2022 में 48वें स्थान से एक बड़ी छलांग है, जो अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में प्रगति से प्रेरित है।
- पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रस्तावित “रेसीप्रोकल टैरिफ” नीति एक बार फिर सुर्खियों में है। इस प्रस्तावित टैरिफ ढांचे के तहत, संयुक्त राज्य अमेरिका को भारतीय निर्यात पर 27% समायोजित पारस्परिक टैरिफ लगाया जाएगा, जिससे अमेरिकी मार्क में भारतीय वस्तुओं की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रस्तावित “रेसीप्रोकल टैरिफ” नीति एक बार फिर सुर्खियों में है।
- ब्राजील ने वैश्विक जलवायु कार्रवाई परिषद बनाने का प्रस्ताव यूएनएफसीसीसी ढांचे के भीतर पेश किया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक जलवायु पहलों को गति देना है। यह प्रस्ताव नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलेम में आयोजित होने वाले COP30 से पहले आया है। परिषद को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- तेल-समृद्ध मध्य अफ्रीकी देश गैबॉन 12 अप्रैल 2025 को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयार है, जिसमें तख्तापलट के प्रमुख ब्राइस ओलिगुई नगुएमा को प्रमुख उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। यह चुनाव अगस्त 2023 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद देश के सैन्य शासन से नागरिक शासन की ओर परिवर्तन की दिशा में एक निर्णायक क्षण है, जिसने बॉन्गो परिवार के पाँच दशकों से अधिक समय के शासन का अंत किया था।





- वैश्विक व्यापार नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अधिकांश देशों के लिए हाल ही में लगाए गए उच्च टैरिफ पर 90 दिनों की रोक लगाने की घोषणा की है। इस फैसले से अमेरिका के कई व्यापारिक साझेदारों को कुछ राहत मिली है। हालांकि, यह रोक चीन पर लागू नहीं होती।
- अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध ने गंभीर रूप धारण कर लिया है, क्योंकि चीन ने जवाबी टैरिफ में भारी वृद्धि की घोषणा की है। ट्रंप प्रशासन द्वारा चीनी आयात पर 104% शुल्क लगाए जाने के जवाब में, चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाकर 84% तक कर दिए हैं। यह निर्णय दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को एक नए स्तर पर ले गया है। इस बढ़ती टकराव की स्थिति में, चीन ने कई कड़े कदम उठाए हैं, जिनमें निर्यात नियंत्रण लागू करना, अमेरिकी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट में शामिल करना, और विश्व व्यापार संगठन (WTO) में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराना शामिल है। यह व्यापार युद्ध न केवल द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि वैश्विक व्यापार प्रणाली पर भी गहरा असर डाल सकता है।
- एक उल्लेखनीय इंजीनियरिंग उपलब्धि के तहत, वेस्ट जापान रेलवे कंपनी (JR वेस्ट) ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है, जिसे वाकायामा प्रीफेक्चर के अरिदा सिटी में मात्र छह घंटे से भी कम समय में स्थापित किया गया। इस स्टेशन का नाम हात्सुशिमा स्टेशन है और यह 1948 से सेवा दे रहे एक पुराने लकड़ी के स्टेशन की जगह लेता है। यह परियोजना सार्वजनिक अवसंरचना में 3D प्रिंटिंग की क्रांतिकारी संभावनाओं को दर्शाती है।
- भारत ने सिएरा लियोन में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक परियोजना हेतु 9.90 लाख अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इस पहल का नाम है "सिएरा लियोन में विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता सक्षम करना", जिसे भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष के तहत समर्थन प्राप्त है और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से लागू किया जा रहा है। यह परियोजना सिएरा लियोन की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है और समावेशी विकास, सततता तथा दक्षिण-दक्षिण सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- मॉरीशस ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किया है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस (ISA) के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क (CPF) पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश और विश्व स्तर पर चौथा देश बन गया है। इस रणनीतिक समझौते का उद्देश्य ISA और मॉरीशस के बीच स्वच्छ ऊर्जा पहलों पर, विशेष रूप से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है, जो राष्ट्र के सतत विकास और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों के अनुरूप है। CPF दीर्घकालिक सौर ऊर्जा सहयोग के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करेगा, जिसमें नवोन्मेषी और पैमाने योग्य तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- न्यूयॉर्क सिटी में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मेयर एरिक एडम्स ने 14 अप्रैल 2025 को आधिकारिक रूप से "डॉ. भीमराव अंबेडकर दिवस" घोषित किया। यह घोषणा भारत के संविधान निर्माता और महान समाज सुधारक डॉ. अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर की गई, जो उनके मानवाधिकार, न्याय और समानता के लिए किए गए योगदान को वैश्विक मान्यता प्रदान करती है।
- वन्यजीव संरक्षण में भारत की वैश्विक नेतृत्व भूमिका को सशक्त करते हुए, भारत सरकार ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत IBCA का मुख्यालय और सचिवालय भारत में स्थापित किया जाएगा। यह समझौता दुनिया की सात प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों — बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा — के संरक्षण के प्रति भारत की गहन प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्वर्ण जयंती के अवसर पर शुरू किया गया IBCA, इन संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण, अनुसंधान और उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करेगा।
- चीन ने सात दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (Rare Earth Elements – REEs) के निर्यात पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे पहले से ही अस्थिर वैश्विक व्यापार माहौल में तनाव और बढ़ गया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब अमेरिका ने अपने प्रमुख व्यापारिक भागीदारों पर नए शुल्क लगाए हैं। चीन लंबे समय से दुर्लभ पृथ्वी खनन और परिशोधन में वैश्विक स्तर पर अग्रणी रहा है, और ये तत्व इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों और सैन्य तकनीकों के निर्माण में बेहद आवश्यक हैं। इन प्रतिबंधों के चलते वैश्विक उद्योगों पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दुनिया के विभिन्न देशों को अब अपने आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और चीनी निर्यात पर निर्भरता कम करने की दिशा में तेजी से काम करने की जरूरत है।
- जनरल ब्राइस ओलिगी नगुएमा ने गैबॉन के राष्ट्रपति चुनाव में 90% से अधिक मतों के साथ जीत दर्ज की है, जिससे मध्य अफ्रीकी देश पर उनकी पकड़ और मजबूत हुई है। यह विजय 2023 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद आई है, जिसमें नगुएमा ने दशकों से सत्ता में रही बोंगो वंश को सत्ता से हटा दिया था। तख्तापलट के समय उन्होंने सत्ता छोड़ने का वादा किया था, लेकिन नए चुनावी नियमों के तहत उन्होंने चुनाव लड़ा, जो सैन्य अधिकारियों को चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। गैबॉन, जो तेल और खनिज संसाधनों से समृद्ध है, अब भी असमानता और भ्रष्टाचार जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, जिन्हें नगुएमा को अपने सात साल के कार्यकाल में सुलझाना होगा।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने महामारी संधि (Pandemic Treaty) के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है, जो वैश्विक स्तर पर महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक समझौता है। यह प्रस्ताव अंतर-सरकारी वार्ताकार निकाय (Intergovernmental Negotiating Body – INB) द्वारा तैयार किया गया है और इसे 19 मई 2025 को 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) में प्रस्तुत किया जाएगा। यह समझौता व्यापक बातचीत के बाद सामने आया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है, साथ ही राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए भविष्य के स्वास्थ्य संकटों के प्रति समान और त्वरित प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करना है।
- इक्वाडोर के दक्षिणपंथी मौजूदा राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने दूसरे दौर के राष्ट्रपति रन-ऑफ चुनाव में जीत हासिल कर ली है। इस जीत के साथ उन्हें पूर्ण चार वर्षीय कार्यकाल मिला है। नोबोआ ने अपनी वामपंथी प्रतिद्वंद्वी लुइसा गोंजालेज़ को बड़े अंतर से हराया, जो देश में बढ़ती नशीली तस्करी से जुड़ी हिंसा और आर्थिक अस्थिरता के बीच जनता की चिंताओं को दर्शाता है। राष्ट्रीय चुनाव परिषद ने परिणामों की घोषणा की, हालांकि लुइसा गोंजालेज़ ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए पुनर्मतगणना की मांग की है।





- अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच, बीजिंग ने अपने प्रमुख एयरलाइनों को बोइंग विमान की खरीद और डिलीवरी रोकने का निर्देश दिया है। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीनी वस्तुओं पर 145% शुल्क लगाने की घोषणा के बाद उठाया गया है। यह निर्णय न केवल व्यापारिक टकराव को और गहराता है, बल्कि वैश्विक विमानन उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक संरचना को भी बदलता है। इससे एयरबस और चीन की अपनी विमान निर्माता कंपनी COMAC जैसे बोइंग के प्रतिद्वंद्वियों के लिए नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।
- ट्रंप प्रशासन ने अप्रैल 2025 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय को मिलने वाली लगभग 2.3 अरब डॉलर की संपत्तीय निधि को रोक दिया, क्योंकि संस्थान ने उन मांगों को मानने से इनकार कर दिया जो उसकी आंतरिक नीतियों में बड़े बदलाव लाने के लिए रखी गई थीं। इन मांगों में विविधता, समानता और समावेशन (DEI) कार्यक्रमों को बंद करना और योग्यता आधारित सुधारों को लागू करना शामिल था। इस टकराव ने देशभर में अकादमिक स्वतंत्रता, सरकारी हस्तक्षेप, यहूदी विरोध (Antisemitism), और निजी संस्थानों पर कार्यकारी अधिकार की कानूनी सीमाओं को लेकर एक व्यापक बहस छेड़ दी है। हार्वर्ड सहित अन्य आइवी लीग विश्वविद्यालयों ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है और इन मांगों को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी है।
- चीन ने हाल ही में एक क्रांतिकारी प्रकार के हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है, जो पारंपरिक विखंडनीय पदार्थों जैसे युरेनियम या प्लूटोनियम के बिना कार्य करता है। इसके बजाय, यह मैग्नीशियम हाइड्राइड-आधारित फ्यूजन जैसी उन्नत संलयन तकनीकों का उपयोग करता है। इस विकास ने हथियार नियंत्रण, अंतरराष्ट्रीय कानून और वैश्विक सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं। यह प्रगति आधुनिक युद्ध में परमाणु हथियारों की धारणा और उनके नियमन को पूरी तरह से पुनर्परिभाषित कर सकती है।
- यूनेस्को ने 17 अप्रैल 2025 को 16 नए वैश्विक जियोपार्क्स (Global Geoparks) को मान्यता दी, जिससे अब विश्वभर में ऐसे जियोपार्क्स

- की कुल संख्या 50 देशों में 229 हो गई है। यह नेटवर्क अब लगभग 8,55,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है, जो नामीबिया देश के आकार के बराबर है। नए घोषित जियोपार्क्स एशिया, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में फैले हैं और इन्हें उनकी अद्वितीय भूवैज्ञानिक धरोहर के लिए मान्यता दी गई है, जिसमें ज्वालामुखीय श्रृंखलाएं, प्राचीन चट्टानी संरचनाएं, पर्वतीय क्षेत्र, जीवाश्म स्थल और रेगिस्तानी परिदृश्य शामिल हैं। ये स्थल न केवल भूवैज्ञानिक चमत्कारों के संरक्षण को बढ़ावा देते हैं, बल्कि पर्यावरणीय शिक्षा, स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने 21 अप्रैल 2025 को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की शुरुआत की। नई दिल्ली स्थित पालम एयरपोर्ट पर उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके साथ सेकंड लेडी उषा वांस और उनके बच्चे भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। चार दिवसीय इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, रक्षा और आर्थिक साझेदारी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को गहराना है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक भी निर्धारित है, जो भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ती गति को दर्शाती है।
 - सतत शहरी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, आंध्र प्रदेश की नियोजित राजधानी अमरावती दुनिया का पहला ऐसा शहर बनने की ओर अग्रसर है, जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू द्वारा परिकल्पित यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारत की स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण-संवेदनशील शहरीकरण की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच स्थित अमरावती को एक आधुनिक, पर्यावरण-मित्र "जनता की राजधानी" के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो सतत शहर नियोजन में वैश्विक मानक स्थापित करने की दिशा में एक प्रेरणास्रोत बनेगा।

नई नियुक्तियाँ: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय

नई नियुक्तियाँ: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सितम्बर 2025

व्यक्ति का नाम	नियुक्ति / पद	संस्था / स्थान	मुख्य विवरण
डॉ. दीपक मित्तल (1998 बैच IFS)	राजदूत	भारत के राजदूत, संयुक्त अरब अमीरात (UAE)	सुंजय सुधीर के उत्तराधिकारी; महत्वपूर्ण मिशनों में अनुभवशाली राजनयिक।
श्री रजित पुणहानी (1991 बैच IAS, बिहार कैडर)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)	1 सितम्बर 2025 से कार्यभार ग्रहण; देशभर में खाद्य सुरक्षा नियमन व मानकों की देखरेख।
पियूष गोयल (1994 बैच IAS, नागालैंड कैडर)	सचिव	खान मंत्रालय	पूर्व NATGRID CEO; 4 सितम्बर 2025 को कार्यभार ग्रहण किया; वी.एल. कंथा राव के उत्तराधिकारी।
न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर	मुख्य न्यायाधीश	बॉम्बे उच्च न्यायालय	शपथ ग्रहण की; न्यायमूर्ति आलोक अराधे के स्थान पर नियुक्त।
मोहम्मद सिराज	ब्रांड अंबेसडर	स्केचर्स इंडिया	क्रिकेट फुटबियर लाइन का प्रचार; भारतीय क्रिकेट बाज़ार में ब्रांड की उपस्थिति मजबूत।
आलिया भट्ट	वैश्विक ब्रांड अंबेसडर	लीवाइस (Levi's)	स्टाइल-प्रेमी नई पीढ़ी के उपभोक्ताओं से जुड़ाव का लक्ष्य।
डॉ. गीता वाणी रयसम	निदेशक	CSIR-NIScPR	चुस्त STI नीतियों, भविष्य-उन्मुख विज्ञान संचार और AI व डिजिटल चुनौतियों में वैश्विक सहयोग पर केंद्रित।
श्रीनिवास इंजेटी	चेयरपर्सन	NSE गवर्निंग बोर्ड	40+ वर्षों का अनुभव; दिवालिपन व कॉरपोरेट गवर्नेंस सुधारों के विशेषज्ञ; SEBI द्वारा स्वीकृत।





व्यक्ति का नाम	नियुक्ति / पद	संस्था / स्थान	मुख्य विवरण
रवि रंजन	(अनुशंसित) प्रबंध निदेशक (MD)	भारतीय स्टेट बैंक (SBI)	FSIB द्वारा अनुशंसित; अंतिम स्वीकृति नियुक्ति समिति के पास लंबित।
न्यायमूर्ति एम. सुन्दर	10वें मुख्य न्यायाधीश	मणिपुर उच्च न्यायालय	15 सितम्बर 2025 को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला द्वारा शपथ ग्रहण
आचार्य देवव्रत	राज्यपाल (अतिरिक्त प्रभार)	महाराष्ट्र	पूर्व गुजरात राज्यपाल; सी.पी. राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने के बाद नियुक्त
अमित खरे	सचिव	उपराष्ट्रपति कार्यालय	सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एवं पूर्व पीएम सलाहकार; उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन के तहत 3-वर्षीय अनुबंध
कार्लोस फेलिप जरामिल्लो	उपाध्यक्ष	विश्व बैंक - पूर्व एशिया एवं प्रशांत (EAP)	सिंगापुर हब से US\$32 अरब पोर्टफोलियो का प्रबंधन
डॉ. सीमा बहौस	कार्यकारी निदेशक (द्वितीय कार्यकाल)	यूएन विमेन	नए कार्यकाल की शुरुआत; लैंगिक समानता एवं 2026-2029 रणनीतिक योजना पर केंद्रित
शशांक स्रोथी	मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO)	पी एंड जी हेल्थ	1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी; 14 वर्षों का वैश्विक वित्त अनुभव
डेनियल कैटज़ (प्रस्तावित)	प्रथम उप-प्रबंध निदेशक	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)	IMF प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा द्वारा प्रस्तावित; अमेरिकी ट्रेजरी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध

नई नियुक्तियाँ: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अगस्त 2025

नाम	नियुक्ति पद	संस्था / स्थान	प्रमुख बिंदु
पी. बी. बालाजी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) (17 नवम्बर 2025 से प्रभावी)	जगुआर लैंड रोवर (JLR)	एड्रियन मार्टेल के उत्तराधिकारी; वर्तमान में टाटा मोटर्स के समूह सीएफओ; लग्जरी व स्थिरता हेतु Reimagine रणनीति का नेतृत्व करेंगे
राजीव आनंद	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (25 अगस्त 2025 - 24 अगस्त 2028, स्वीकृति लंबित)	इंडसइंड बैंक	पूर्व उप-प्रबंध निदेशक, एक्सिस बैंक; खुदरा और थोक बैंकिंग में व्यापक अनुभव
एस. राधा चौहान	अध्यक्ष	क्षमता निर्माण आयोग, नई दिल्ली	सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी; पूर्व सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग; मिशन कर्मयोगी को आगे बढ़ाएंगी
युर्गेन वेस्टरमेयर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (भारत व दक्षिण एशिया) (1 सितम्बर 2025 से)	एयरबस	बिक्री और संचालन का नेतृत्व; एयरबस-टाटा उपक्रमों की निगरानी; मेक इन इंडिया सहयोग को मजबूत करेंगे
राजीव प्रताप रूडी	महासचिव (प्रशासन)	संविधान क्लब ऑफ इंडिया	25 वर्षों से पद पर बरकरार; संजीव कुमार बलियान को हराया; सर्वदलीय समर्थन मिला
रवि नारायणन	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)	एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट (SMFG India Credit)	एसएमएफजी अधिग्रहण के बाद पहली नेतृत्व नियुक्ति; NBFC के लिए नई रणनीतिक दिशा का संकेत
शाहरुख खान	ब्रांड एंबेसडर	ज़ोमैटो	"फ्यूल योर हसल" अभियान का नेतृत्व; हसल कल्चर को उजागर किया; विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर नज़र आएंगे
अजय कुमार भल्ला	अतिरिक्त प्रभार, राज्यपाल	नागालैंड	मणिपुर के राज्यपाल; ला. गणेशन (80) के निधन के बाद अतिरिक्त प्रभार





नाम	नियुक्ति पद	संस्था / स्थान	प्रमुख बिंदु
नोएल एन टाटा	निदेशक	टाटा सन्स	रतन टाटा के निधन के बाद नियुक्त; एजीएम में स्वीकृति; शापूरजी पलोनजी समूह का समर्थन
सतीश गोलचा (IPS, 1992, AGMUT)	पुलिस आयुक्त	दिल्ली	शशि भूषण कुमार सिंह (कार्यवाहक) का स्थान लिया; पूर्व DG (जेल), पूर्व CBI, DGP अरुणाचल प्रदेश
श्रीनिवासन के. स्वामी	अध्यक्ष (2025-26)	AAAI (एडवरटाइजिंग एजेंसिज़ एसोसिएशन ऑफ इंडिया)	चौथा कार्यकाल; AAAI की 80वीं वर्षगांठ; जयदीप गांधी उपाध्यक्ष
इंद्रनील भट्टाचार्य	पदेन सदस्य	RBI मौद्रिक नीति समिति (MPC)	कार्यकारी निदेशक, मौद्रिक नीति विभाग; राजीव रंजन का स्थान लिया
आनिश दयाल सिंह (IPS, 1988, मणिपुर)	उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA)	पीएमओ / भारत	पूर्व CRPF व ITBP प्रमुख; नक्सल विरोधी अभियानों व कल्याण पहलों के लिए प्रसिद्ध; NSA अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे
न्यायमूर्ति आलोक अराधे	न्यायाधीश (सिफारिश)	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	वर्तमान में बॉम्बे HC के मुख्य न्यायाधीश; करियर MP HC से शुरू; J&K व कर्नाटक HC में भी कार्य किया
न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली	न्यायाधीश (सिफारिश)	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	वर्तमान CJ, पटना HC; मूलतः गुजरात HC से; 2031 में CJI बनने की संभावना
राजीव रंजन	उपाध्यक्ष एवं मुख्य जोखिम अधिकारी	न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)	35+ वर्षों का RBI अनुभव; 5 साल का कार्यकाल (अगस्त 2025 से)
तेयमुर अब्बासगुलियेव	CEO	नायरा एनर्जी	SOCAR तुर्किये के CFO; अलेक्सांद्रो डेस डोरिडेस का स्थान लिया; बडीनार रिफाइनरी व 6,750+ पंपों का संचालन
अर्जुन चौधरी	एमडी एवं CEO	गृहम हाउसिंग फाइनेंस	पूर्व सिटीबैंक व एक्सिस बैंक; खुदरा ऋण व क्रेडिट कार्ड अनुभव; मनीष जायसवाल का स्थान (सलाहकार रहेंगे, दिस. 2025 तक)
गिरिश कौसगी	CEO (अपेक्षित)	IIFL होम फाइनेंस	पूर्व MD, PNB हाउसिंग फाइनेंस; मोनू रात्रा का स्थान लेंगे
एस. कृष्णन	गैर-कार्यकारी अध्यक्ष (मार्च 2028 तक)	जम्मू-कश्मीर बैंक	पूर्व MD & CEO, पंजाब एंड सिंध बैंक व तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक; 40+ वर्ष का अनुभव
दिनेश के. पटनायक	भारत के उच्चायुक्त	कनाडा	वरिष्ठ राजनयिक; वर्तमान में स्पेन में भारत के राजदूत; भारत-कनाडा संबंधों में सुधार का संकेत
क्रिस्टोफर कूटर	कनाडा के उच्चायुक्त	भारत	नए कनाडाई पीएम मार्क कार्नी द्वारा नियुक्त; संबंधों को रीसेट करने का प्रयास
राघव गुप्ता	शिक्षा प्रमुख (भारत एवं एपीएसी)	OpenAI	पूर्व MD, Coursera (APAC); AI शिक्षा पहल व इंडिया AI मिशन साझेदारी का नेतृत्व
उर्जित पटेल	कार्यकारी निदेशक (3 वर्ष)	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)	पूर्व RBI गवर्नर (2016-18); भारत व इसकी मतदाता-समूह का प्रतिनिधित्व करेंगे; 28 अगस्त 2025 से प्रभावी





नई नियुक्तियाँ: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जुलाई 2025

नियुक्तियाँ राष्ट्रीय

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	पद	संस्था / स्थान	प्रमुख विवरण
1	रवि अग्रवाल	अध्यक्ष	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)	जून 2026 तक पुनर्नियुक्त; 1988 बैच के IRS अधिकारी; कर नीति और प्रशासन में प्रमुख भूमिका
2	पराग जैन	प्रमुख	रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW)	ऑपरेशन सिंदूर में प्रमुख भूमिका; जून 2025 में रवि सिन्हा के सेवानिवृत्त होने के बाद नियुक्त
3	केशवन रामचंद्रन	कार्यकारी निदेशक (ED)	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	1 जुलाई 2025 से कार्यभार ग्रहण; नियामक विभाग में प्रुडेंशियल रेगुलेशन संभालते हैं
4	एयर मार्शल एस. शिवकुमार	प्रशासन प्रभारी वायु अधिकारी (AOA)	भारतीय वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली	35+ वर्षों का अनुभव; संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भी सेवा
5	सुनील कदम	कार्यकारी निदेशक (ED)	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI)	बाजार अखंडता और निवेशक सुरक्षा में अनुभव
6	अमिताभ कांत	गैर-कार्यकारी निदेशक	इंडिगो एयरलाइंस	नीति आयोग के पूर्व CEO; गवर्नेंस और नवाचार में माहिर
7	साहिल किनी	CEO	RBI इनोवेशन हब (RBIH), बेंगलुरु	सेतु के सह-संस्थापक; इंडिया स्टैक और UPI में अनुभव
8	सुकन्या सोनोवाल	राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत (2025-2027)	CYPAN	IIT गुवाहाटी की छात्रा; STEMvibe की सह-संस्थापक
9	संजोग गुप्ता	CEO	अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC)	2500+ उम्मीदवारों में चयनित; ओलंपिक्स 2028 और महिला क्रिकेट पर ध्यान
10	आदित्य मंगला	CEO - फूड ऑर्डरिंग डिवीजन	एटरनल (Zomato)	ग्राहक-केंद्रित नेतृत्व के लिए प्रशंसित
11	हरदीप सिंह ब्रार	अध्यक्ष एवं CEO	BMW इंडिया	30+ वर्षों का ऑटोमोबाइल अनुभव
12	सबीह खान	COO	एप्पल इंक.	आपूर्ति श्रृंखला विशेषज्ञ; 1995 से एप्पल में कार्यरत
13	प्रिया नायर	CEO एवं MD	हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL)	1995 से कंपनी में; रोहित जावा की उत्तराधिकारी
14	कुमार मंगलम बिडला	कार्यकारी समिति सदस्य	यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम	\$15B अमेरिकी निवेश के लिए सम्मानित
15	अभिजीत किशोर	अध्यक्ष (पुनर्नियुक्त)	COAI (बोडाफोन आइडिया)	5G नेतृत्व में प्रमुख भूमिका
16	राहुल वत्स	उपाध्यक्ष (पुनर्नियुक्त)	COAI (भारती एयरटेल)	डिजिटल और नियामक क्षेत्र में अनुभव
17	बबीता बी पी	डिप्टी CISO (GM - सुरक्षा)	भारतीय स्टेट बैंक (SBI)	साइबर सुरक्षा में अग्रणी महिला
18	डॉ. अभिजात शेट	अध्यक्ष	राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC)	13 जुलाई 2025 को नियुक्त; मेडिकल निरीक्षण घोटाले के बीच पदभार
19	सोनाली मिश्रा	महानिदेशक	रेलवे सुरक्षा बल (RPF)	पहली महिला DG; BSF व MP पुलिस में अनुभव
20	प्रो. अशीम कुमार घोष	राज्यपाल	हरियाणा	14 जुलाई 2025 को नियुक्त
21	पुसपति अशोक गजपति राजू	राज्यपाल	गोवा	प्रशासनिक सुधार के उद्देश्य से नियुक्त
22	कर्विंदर गुप्ता	उपराज्यपाल	लद्दाख	ब्रिगेडियर (से.नि.) बी.डी. मिश्रा के उत्तराधिकारी
23	आर. दोराईस्वामी	MD & CEO	भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)	28 अगस्त 2028 तक कार्यकाल; 38+ वर्षों का अनुभव
24	राघवेंद्र एस. भट	अंतरिम MD & CEO	कर्नाटक बैंक	1981 से सेवा में; 3 महीने के लिए अंतरिम प्रमुख
25	हेमंत रुपाणी	CEO	हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेस प्रा. लि. (HCCB)	8 सितम्बर 2025 से कार्यभार ग्रहण





क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	पद	संस्था / स्थान	प्रमुख विवरण
26	संजय कौल	MD & CEO	गिफ्ट सिटी, गांधीनगर	15 जुलाई 2025 को नियुक्त; वैश्विक वित्तीय केंद्र के विकास पर ध्यान
27	मनीष चोपड़ा	CEO	सब्यसाची कुल्लूर	लग्जरी फैशन ब्रांड का वैश्विक विस्तार लक्ष्य
28	अजय कुमार श्रीवास्तव	निदेशक (इंजीनियरिंग और R&D)	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)	37 वर्षों का विमानन डिज़ाइन अनुभव
29	नीतू चंद्रा	SVEEP आइकन	बिहार (भारत निर्वाचन आयोग)	आगामी विधानसभा चुनावों में मतदाता जागरूकता
30	क्रांति प्रकाश झा	SVEEP आइकन	बिहार (भारत निर्वाचन आयोग)	जागरूकता कार्यक्रमों में भागीदारी
31	डॉ. जे. रविशंकर	MD	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (BMRCL)	2001 बैच के IAS अधिकारी
32	दीपक बगला	मिशन निदेशक	अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग	निवेश इंडिया के पूर्व CEO
33	अजय सेठ	अध्यक्ष	बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)	पूर्व वित्त सचिव; आर्थिक नीतियों के विशेषज्ञ
34	प्रो. उमा कंजीलाल	कुलपति	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU)	पहली महिला VC; SWAYAM की पूर्व समन्वयक

नई नियुक्तियाँ: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जून 2025

नियुक्तियाँ राष्ट्रीय

व्यक्ति का नाम	पद पर नियुक्ति	मुख्य तथ्य
राजीव मेमानी	CII अध्यक्ष (2025-26)	EY इंडिया के चेयरमैन और CEO; सार्वजनिक-निजी सहयोग व नवाचार को बढ़ावा देंगे।
अशीष पांडे व कल्याण कुमार	यूनियन बैंक और सेंट्रल बैंक के MD & CEO	FSIB ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नियुक्तियों के लिए चयन किया।
एस. पद्मनाभन	चेयरमैन, टाटा केमिकल्स	IIM-बैंगलोर के पूर्व छात्र; स्थायी नवाचार और वैश्विक विस्तार पर ध्यान।
अश्वनी लोहानी	निदेशक, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय (PMML)	एयर इंडिया और रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख; 3 साल का कार्यकाल।
एस. महेन्द्र देव	अध्यक्ष, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM)	ग्रामीण विकास व कृषि के विशेषज्ञ; समावेशी विकास में योगदान।
रायन रोसलान्स्की	CEO, LinkedIn एवं MS Office AI प्रमुख	Microsoft 365 Copilot, Word, Teams जैसे प्रोडक्ट्स की निगरानी भी करेंगे।
टी. रबी शंकर	16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य	RBI डिप्टी गवर्नर; वित्तीय अनुशासन और डिजिटल नीति में विशेषज्ञ।
शैलेश सी. मेहता	अध्यक्ष, फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया	दीपक फर्टिलाइज़र्स के MD; स्थायी खेती और उर्वरक नवाचार में अग्रणी।
सत पाल भनू	अंतरिम CEO और MD, LIC	जून 8 से नियुक्त; 3 महीने तक पूर्ण अधिकारों के साथ।
कीर्ति गणोरकर	मैनेजिंग डायरेक्टर, सन फार्मास्युटिकल	1 सितम्बर से कार्यभार; 25+ वर्षों का अनुभव।
आर. दौरेस्वामी	CEO और MD, LIC (प्रस्तावित)	FSIB की अनुशंसा पर; अंतिम मंजूरी कैबिनेट समिति से लंबित।
नीना गुप्ता (अभियान में)	ब्रांड फेस, सिप्लाडाइन	“आपका फास्ट एंड एक्सपर्ट” अभियान में प्रमुख चेहरा।





व्यक्ति का नाम	पद पर नियुक्ति	मुख्य तथ्य
अमिताभ कांत	G20 शेरपा (पूर्व); वरिष्ठ सलाहकार, Fairfax	45 वर्षों की सेवा के बाद इस्तीफा; अब निजी क्षेत्र में भूमिका।
अरुण श्रीनिवास	भारत प्रमुख और MD, मेटा	1 जुलाई से कार्यभार; विज्ञापन और AI रणनीति में प्रमुख योगदान।
लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी	राष्ट्रपति की पहली महिला ADC	9 मई को नियुक्त; महिला सशक्तिकरण का प्रतीक।
अनुराधा ठाकुर	SEBI बोर्ड सदस्य	1 जुलाई से कार्यभार; भारत की पहली महिला आर्थिक मामलों की सचिव भी।
जी. संपत कुमार	MD, Nippon Koei India	कंपनी के पहले भारतीय प्रमुख; एशिया क्षेत्र में विस्तार की रणनीति।
प्रो. एम. सतीश कुमार	डीन, क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट – GIFT सिटी	UK-India शिक्षा सहयोग का नया चरण; 2026 से प्रवेश प्रक्रिया।
शिवासुब्रमण्यम रमन्	अध्यक्ष, PFRDA	5 साल का कार्यकाल; पूर्व SIDBI प्रमुख; नियामक व वित्तीय अनुभव।
जाओ जियायी (चीन)	अध्यक्ष, AIIB	अंतरराष्ट्रीय वित्त पृष्ठभूमि; AIIB की नई प्रमुख।
अनुज पांडे	CEO, UGR0 कैपिटल	जोखिम प्रबंधन और नेतृत्व निरंतरता पर फोकस।
अमिताभ कांत	वरिष्ठ सलाहकार, Fairfax Financial Holdings	वाणिज्यिक सोच और भारत में निवेश मार्गदर्शन।
प्रो. सुमन चक्रवर्ती	निदेशक, IIT खड़गपुर	19 जून से नियुक्त; कम लागत डायग्नोस्टिक तकनीक में विशेषज्ञ।

ब्रांड और अभियान राजदूत

व्यक्ति का नाम	ब्रांड / अभियान	मुख्य तथ्य
रोहित शर्मा	TCL इंडिया	दूसरी बार ब्रांड एंबेसडर नियुक्त; "मास्टर द मोमेंट" थीम के तहत तकनीक-आधारित अभियानों से ब्रांड को मजबूती।
एम. एस. धोनी	डेटॉल (Icy Cool रेंज)	28 मई को घोषित; साबुन, बॉडीवाश, हैंडवाश की नई रेंज के लिए ब्रांड एंबेसडर; गर्मी में ताजगी और सुरक्षा का संदेश।
कैटरीना कैफ	मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन एंबेसडर	Visit Maldives समर सेल कैपेन के साथ घोषित; भारत-मालदीव कूटनीतिक संबंधों की मजबूती और पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास।
अलियावती लोंगकुमेर	उत्तर कोरिया में भारत के राजदूत	4 वर्षों के बाद उच्चस्तरीय राजनयिक जुड़ाव की बहाली; दिसंबर 2024 में दूतावास पुनः खोला गया; क्षेत्रीय संतुलन व मानवीय सहयोग को रेखांकित करता है।

नई नियुक्तियाँ: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मई 2025

व्यक्ति का नाम	नियुक्ति पद	संगठन / स्थान	मुख्य विवरण
परमेश्वरन अय्यर	कार्यवाहक कार्यकारी निदेशक	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)	भारत ने परमेश्वरन अय्यर को के.वी. सुब्रमण्यम के स्थान पर IMF में अंतरिम कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है।
प्रकाश मगदुम	प्रबंध निदेशक	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC)	भारतीय सूचना सेवा (1999 बैच) के अधिकारी, जो फिल्म विरासत और भारतीय सिनेमा के प्रचार में प्रमुख भूमिका निभाएंगे।
संजय जोशी	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD)	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL)	FSIB ने उन्हें सेवानिवृत्त R.R. सिंह के स्थान पर CMD के रूप में अनुशंसित किया है।
अजय चावला	प्रबंध निदेशक	टाइटन कंपनी लिमिटेड	1 जनवरी 2026 से कार्यभार संभालेंगे, C.K. वेंकटरमण की सेवानिवृत्ति के बाद।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत	कार्यकारी अध्यक्ष	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)	सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश को 14 मई 2025 से नियुक्त किया गया, जो न्याय तक पहुंच को बेहतर बनाने में सहायक होंगे।
अजय कुमार	अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)	पूर्व रक्षा सचिव और डिजिटल इंडिया के प्रमुख अधिकारी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नियुक्त।





व्यक्ति का नाम	नियुक्ति पद	संगठन / स्थान	मुख्य विवरण
हरवंश चावला	अध्यक्ष	ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	व्यापार सहयोग, नीति सलाह और सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में रणनीतिक नियुक्ति।
पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़	विशिष्ट प्रोफेसर	एनएलयू दिल्ली	न्यायपालिका से शिक्षण क्षेत्र की ओर कदम, शैक्षणिक मार्गदर्शन में भूमिका।
अनुराग भूषण	राजदूत	स्वीडन	भारत और स्वीडन के बीच सहयोग को मजबूत करने हेतु प्रमुख कूटनीतिक नियुक्ति।
न्यायमूर्ति केम्पैया सोमशेखर	मुख्य न्यायाधीश	मणिपुर उच्च न्यायालय	सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त।
राम मोहन एम. के.	निदेशक	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA)	समुद्री निर्यात विशेषज्ञ, पूर्व में टोक्यो में रेजिडेंट डायरेक्टर रहे।
डॉ. समीर वी. कामत	अध्यक्ष	DRDO (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन)	डॉ. कामत को एक वर्ष का कार्यविस्तार मिला है, जो अब मई 2026 तक पद पर बने रहेंगे।
एन. वेणु	प्रबंध निदेशक	हिटाची इंडिया	2 जून 2025 से कार्यभार ग्रहण करेंगे, जबकि भरत कौशल को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

ब्रांड और अभियान राजदूत

व्यक्ति का नाम	ब्रांड / अभियान	मुख्य विवरण
तमन्ना भाटिया	कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड (KSDL)	KSDL ने तमन्ना भाटिया को अपना ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है ताकि कंपनी की पहचान को आधुनिक रूप देकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया जा सके। FY 2024-25 में ₹1,785.99 करोड़ का टर्नओवर रहा।
अनिल कुंबले	कर्नाटक वन विभाग	पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले को कर्नाटक वन विभाग का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है। वे बिना किसी मानदेय के इस भूमिका को निभा रहे हैं और वनों के संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा और हरित क्षेत्र निर्माण को बढ़ावा देंगे।
श्रद्धा कपूर	यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड	श्रद्धा कपूर को यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड ने अपने वैक्यूम क्लीनर उत्पादों की ब्रांड एंबेसडर बनाया है। यह साझेदारी देश में स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है।
शाहिद कपूर	वोग आईवियर	वोग आईवियर ने बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर को अपना ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है। वे तापसी पन्नू के साथ एक नए अभियान का हिस्सा हैं, जिसमें व्यक्तिगत शैली और स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है।
शुभमन गिल	ओकली	भारतीय टेस्ट टीम के युवा कप्तान शुभमन गिल को ओकली सनग्लास ब्रांड का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है। यह सहयोग "Artifacts from the Future" अभियान का हिस्सा है। उनकी स्टाइलिश छवि को ब्रांड ने प्रमुखता से अपनाया है।

नई नियुक्तियाँ: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अप्रैल 2025

नियुक्तियाँ राष्ट्रीय

व्यक्ति का नाम	पद	संस्था / स्थान	मुख्य बिंदु
डॉ. जय भट्टाचार्य	राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (NIH) के निदेशक	अमेरिका	• अमेरिकी सीनेट ने 25 मार्च 2025 को पुष्टि की; ट्रम्प द्वारा नामांकन। स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर, MD और अर्थशास्त्र में PhD। सार्वजनिक स्वास्थ्य और नीति में विशेषज्ञ।
निधि तिवारी	प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव	भारत सरकार	• आईएफएस अधिकारी, पहले पीएमओ में उप सचिव, विदेश मंत्रालय में भी सेवाएं दीं।
अंबुज चंदना	प्रबंध निदेशक और हेड, कंज्यूमर बैंकिंग	डीबीएस बैंक इंडिया	• कोटक महिंद्रा बैंक में 16+ वर्षों का अनुभव; खुदरा बैंकिंग और ऋण क्षेत्र में विशेषज्ञता।
सलीला पांडे	एमडी और सीईओ	एसबीआई काइर्स एंड पेमेंट सर्विसेज	• एसबीआई में 30 वर्षों का अनुभव; क्रेडिट सेवाओं और खुदरा बैंकिंग की विशेषज्ञ।





व्यक्ति का नाम	पद	संस्था / स्थान	मुख्य बिंदु
एन. चंद्रशेखरन	आईएमएफ सलाहकार परिषद सदस्य	टाटा संस	• उद्यमिता और विकास से संबंधित IMF सलाहकार परिषद में नियुक्त; वैश्विक व्यापार रणनीति में प्रमुख भूमिका।
स्वामीनाथन एस. अय्यर	पूर्णकालिक सदस्य (जीवन बीमा)	बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)	• 5 साल के लिए नियुक्त; बीमा क्षेत्र की नीति और निगरानी में विशेषज्ञता।
पूनम गुप्ता	डिप्टी गवर्नर	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• IMF, विश्व बैंक, NCAER में अनुभव; मौद्रिक नीति निर्माण में भूमिका।
एच. शंकर	प्रबंध निदेशक	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CPCL)	• जुलाई 2024 से अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे; परिष्करण परियोजनाओं में नेतृत्व किया।
सिवासुब्रमण्यम रामण	अध्यक्ष	पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)	• 5 वर्षों की नियुक्ति; राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना की निगरानी।
कमल हासन	अध्यक्ष	FICCI मीडिया और मनोरंजन समिति (दक्षिण)	• भारत के मीडिया क्षेत्र को \$100 बिलियन उद्योग में बदलने की दृष्टि।
सोहिनी राजोला	कार्यकारी निदेशक	NPCI	• भुगतान समाधान को बढ़ावा देने हेतु NPCI में नियुक्त।
मोहसिन नक़वी	अध्यक्ष	एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC)	• पीसीबी के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री; क्रिकेट कूटनीति में योगदान।
सीमा अग्रवाल	महानिदेशक, अग्रिम एवं बचाव सेवाएं	भारत सरकार	• पूर्व में नागरिक आपूर्ति की डीजी रही हैं; आठ अन्य आईपीएस अधिकारियों का तबादला भी हुआ।
बालाजी नुथलापाडी	कार्यकारी निदेशक – प्रौद्योगिकी एवं संचालन	इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक	• सिटी बैंक में वरिष्ठ पदों पर कार्यानुभव; आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त।
न्यायमूर्ति अरुण पाली	मुख्य न्यायाधीश	जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय	• सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर नियुक्ति; पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से स्थानांतरण।
सतीश चव्वा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)	ओमान इंडिया संयुक्त निवेश कोष (OIJIF)	• 20 वर्षों से अधिक का निजी इक्विटी और वित्तीय अनुभव।
विरल दावड़ा	उप मुख्य सूचना अधिकारी	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE)	• IT अवसंरचना को सशक्त बनाने हेतु नियुक्त; पूर्व CTO, NCDEX।
डॉ. मोहन राजन	अध्यक्ष और चिकित्सा निदेशक	राजन आई केयर हॉस्पिटल	• AIOS के उपाध्यक्ष नियुक्त; तमिलनाडु के पांचवें विशेषज्ञ ophthalmologist इस पद पर।
मीराबाई चानू	अध्यक्ष	IWLF एथलीट्स कमीशन	• अनुभवी खिलाड़ी नेतृत्व को बढ़ावा देने हेतु नियुक्त।
संतोष कुमार	उप मुख्य वित्तीय अधिकारी (Deputy CFO)	इंडसइंड बैंक	• माइक्रोफाइनेंस में बढ़ते NPA के मद्देनजर नियुक्ति।
टी. रबी शंकर	उप गवर्नर	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• एक वर्ष का पुनर्नियुक्ति कार्यकाल; आर्थिक स्थिरता और मौद्रिक नीति में भूमिका।
जज कावेरी बवेजा	रजिस्ट्रार (विजिलेंस)	दिल्ली उच्च न्यायालय	• प्रशासनिक फेरबदल के तहत नियुक्ति।
अजय भूषण प्रसाद पांडे	उपाध्यक्ष	एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक	• निवेश समाधान, सततता, और पोर्टफोलियो प्रबंधन विभाग की निगरानी।
जितेंद्र मिश्रा	अध्यक्ष	CIFEJ (बाल और युवा फिल्मों का अंतरराष्ट्रीय केंद्र)	• SIFFCY के निदेशक; 2025-2027 कार्यकाल के लिए निर्वाचित।





व्यक्ति का नाम	पद	संस्था / स्थान	मुख्य बिंदु
डॉ. मांगीलाल जाट	सचिव और महानिदेशक	DARE और ICAR	• 25 वर्षों का कृषि और जलवायु अनुकूल खेती में अनुभव।
स्टेसी सायर	उपाध्यक्ष और एमडी	बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी केंद्र	• 28 वर्षों का अनुभव; विमान कार्यक्रमों में नेतृत्व किया।
अनंत अंबानी	कार्यकारी निदेशक	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	• 1 मई 2025 से 5 वर्षों का कार्यकाल; हरित ऊर्जा परियोजनाओं में नेतृत्व।
डॉ. नीलम हुंगाना तिमिसिना	कार्यवाहक गवर्नर	नेपाल राष्ट्र बैंक	• 6 अप्रैल 2025 से कार्यभार ग्रहण; नेपाल के वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्ति।

ब्रांड और अभियान राजदूत

व्यक्ति का नाम	ब्रांड / अभियान	प्रमुख बिंदु
अनन्या पांडे	शनेल (Chanel)	• बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे को शनेल का पहली बार भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जो उनके और भारतीय फैशन उद्योग दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह उपलब्धि पेरिस में हुए शनेल स्प्रिंग/समर 2025 शो में उनकी उपस्थिति के बाद आई है।
कृति सेनन	ड्रीम टेक्नोलॉजी (Dreame Technology)	• ड्रीम टेक्नोलॉजी, एक प्रमुख चीनी स्मार्ट होम उपकरण ब्रांड, ने बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन को भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 2017 में स्थापित यह ब्रांड रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, कॉर्डलेस वैक्यूम और हेयर स्टाइलिंग टूल्स जैसे एआई-आधारित स्मार्ट उत्पादों के लिए जाना जाता है।

समझौता/समझौता ज्ञापन

समझौता/समझौता ज्ञापन: सितम्बर 2025

संगठन / देश / राज्य	एमओयू/ समझौता किसके साथ	क्षेत्र / उद्देश्य	मुख्य विवरण / महत्व
भारत	जापान	जलवायु साझेदारी - संयुक्त क्रेडिट मैकेनिज्म (JCM)	पेरिस समझौता अनुच्छेद 6.2 के तहत हस्ताक्षर; भारत-जापान के बीच कार्बन क्रेडिट व्यापार सक्षम करेगा। लगभग ₹10 ट्रिलियन (₹5.5 लाख करोड़) हरित निवेश को बढ़ावा; नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन, ऊर्जा दक्षता व कार्बन कैप्चर क्षेत्रों में। भारत की वैश्विक जलवायु कार्रवाई व नेट-ज़ीरो लक्ष्यों में भूमिका मजबूत।
भारत	यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA - स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिकटेस्टाइन)	मुक्त व्यापार समझौता (FTA)	1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी; भारत का EFTA देशों के साथ पहला FTA। इसमें कानूनी रूप से बाध्यकारी सतत विकास प्रावधान शामिल (भारत के लिए पहली बार)। द्विपक्षीय व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रोजगार सृजन व यूरोपीय बाजारों तक भारत की पहुँच में वृद्धि।
कोल इंडिया	NSTFDC (राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम)	जनजातीय शिक्षा एवं CSR सहयोग	एकलव्य विद्यालयों में जनजातीय छात्रों को सशक्त बनाने हेतु डिजिटल शिक्षा, करियर मेंटरशिप व सेनेटरी नैपकिन वैंडिंग मशीनें उपलब्ध कराना।
iDEX-DIO (डिफेंस इनोवेशन ऑर्गनाइजेशन)	EdCIL (इंडिया) लि.	रक्षा एवं एजु-टेक नवाचार	ASPIRE कार्यक्रम शुरू; 650+ स्टार्टअप्स को शामिल कर स्वदेशी नवाचार मॉडल से ₹1,652 करोड़ की प्रोक्योरमेंट ऑर्डर। रक्षा हेतु ड्यूल-यूज (दोहरी उपयोगी) समाधान विकसित करना।
SAI (भारतीय खेल प्राधिकरण)	IIT दिल्ली	खेल विज्ञान एवं नवाचार	खेल विज्ञान अनुसंधान, स्वदेशी उपकरण विकास और बायोमैकेनिक्स लैब हेतु समझौता। खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत को गति देने का लक्ष्य।





संगठन / देश / राज्य	एमओयू / समझौता किसके साथ	क्षेत्र / उद्देश्य	मुख्य विवरण / महत्व
TCIL (टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लि.)	पंजाब नेशनल बैंक (PNB)	डिजिटल बैंकिंग एवं आईटी परिवर्तन	3 सितम्बर 2025 को हस्ताक्षरित; आईटी अवसंरचना को उन्नत करने और डिजिटल बैंकिंग समाधान तेज़ करने के लिए साझेदारी।
भारत और आईएलओ	अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन	कौशल मान्यता	वैश्विक कौशल तुलना में सुधार लाने और भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए व्यवसायों का अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण विकसित करना।
आईआईटी कानपुर (भारत)	वियतनाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अनुसंधान	एआई अनुसंधान, नवाचार और शैक्षणिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए सहयोग।
भारतीय डाक	बीएसएनएल	दूरसंचार सेवाएं	भारतीय डाक देशभर में 1.65 लाख डाकघरों के माध्यम से बीएसएनएल सिम और रिचार्ज बेचेगा।
ऑयल इंडिया लिमिटेड	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और आरवीयूएनएल (राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड)	महत्वपूर्ण खनिज और नवीकरणीय ऊर्जा	राजस्थान में महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण और 1.2 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन।

समझौता/समझौता ज्ञापन: अगस्त 2025

साझेदारी / पहल	प्रमुख फोकस क्षेत्र	प्रभाव / परिणाम
बीएसएनएल (BSNL) व एनआरएल (NRL)	रिफाइनरी क्षेत्र में भारत का पहला 5G CNPN; इंडस्ट्री 4.0 तकनीकों का एकीकरण	परिचालन दक्षता में वृद्धि, साइबर सुरक्षा मज़बूत, नए रोजगार और नवाचार के अवसर
आयुष मंत्रालय व इशवेद-बायोप्लांट्स / AIHA-AIIMS	दुर्लभ औषधीय पौधों का संरक्षण (टिशू कल्चर द्वारा); राष्ट्रीय औषधीय पौधों उद्यान की स्थापना	जैव विविधता संरक्षण, जन-जागरूकता, पारंपरिक चिकित्सा व स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति
एसएपी (SAP) व गति शक्ति विश्वविद्यालय (GSV)	लॉजिस्टिक्स व परिवहन में डिजिटल स्किलिंग; पाठ्यक्रम विकास; शोध और रोजगार सृजन	रोजगार के अवसर, उद्योग-शैक्षणिक सहयोग, लॉजिस्टिक्स क्षमता में वृद्धि
भारत व फिलीपींस	रक्षा, डिजिटल तकनीक, अंतरिक्ष, समुद्री सहयोग, पर्यटन व सांस्कृतिक आदान-प्रदान में समझौते	द्विपक्षीय संबंध मज़बूत, सामरिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग
अटल इनोवेशन मिशन (AIM) व भाषिनी	नवाचार में भाषाई समावेशन; बहुभाषी उपकरणों का एकीकरण; स्टार्टअप सहयोग	जमीनी स्तर के नवोन्मेषकों को सशक्त करना, समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र, स्थानीय नवाचार को बढ़ावा
यूआईडीएआई (UIDAI) - भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI)	बायोमेट्रिक सुरक्षा, धोखाधड़ी/असामान्यता पहचान, एल्गोरिद्म सुधार	आधार सुरक्षा व विश्वसनीयता में सुधार
गिफ्ट सिटी (GIFT City) - गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय (GTU)	आईएफएससी शिक्षा, फिनटेक अनुसंधान, उत्कृष्टता केंद्र	कुशल कार्यबल, गुजरात की वैश्विक वित्तीय स्थिति मज़बूत
बीएसएनएल - वैश्विक टेक दिग्गज (Ericsson आदि)	5G, एआई प्रशिक्षण, दूरसंचार अनुसंधान व विकास, डिजिटल कौशल	भविष्य-तैयार कार्यबल, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा
उत्तरी फ्रंटियर रेलवे (NFR) - IIT गुवाहाटी	पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, सतत विकास	प्लास्टिक कचरे में कमी, हरित रेलवे संचालन
भारत - ज़ाम्बिया व्यापार समझौता	सहकारी व्यापार सहयोग, भारतीय मिशनों के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन	ज़ाम्बिया के साथ व्यापारिक संबंध मज़बूत, निर्यात संभावनाएँ बढ़ें
NCEL - सेनेगल व इंडोनेशिया एमओयू	सहकारी व्यापार का विस्तार, वैश्विक व्यापारिक गठबंधन निर्माण	भारतीय सहकारिताओं की वैश्विक पहुँच का विस्तार, अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति मज़बूत





साझेदारी / पहल	प्रमुख फोकस क्षेत्र	प्रभाव / परिणाम
UIDAI - स्टारलिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रा. लि.	आधार-आधारित प्रमाणीकरण से सैटेलाइट इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का पेपरलेस KYC	आसान ऑनबोर्डिंग, बेहतर अनुपालन, वैश्विक टेक साझेदारियों में आधार की क्षमता का प्रदर्शन
हरियाणा एवं राजस्थान - यमुना जल पाइपलाइन परियोजना (MoU)	हठनीकुंड से राजस्थान जिलों को 577 MCM पानी पहुँचाने हेतु भूमिगत पाइपलाइन की संयुक्त DPR	शुष्क जिलों (चूरू, सीकर, झुंझुनू) में जल उपलब्धता बढ़ाना, अंतर्राज्यीय जल सुरक्षा सहयोग को प्रोत्साहन
असम राइफल्स - IIIT मणिपुर (MoU)	रक्षा एवं सुरक्षा के लिए ड्रोन तकनीक; उन्नत ड्रोन प्रशिक्षण एवं रिक्रेशर कोर्स	निगरानी, टोही एवं लॉजिस्टिक्स को सुदृढ़ करना; रक्षा-अकादमिक सहयोग बढ़ाना; DGCA प्रमाणित प्रशिक्षण
RRU - SSB (अलवर) MoU	प्रशिक्षण, शैक्षणिक सहयोग, संयुक्त शोध एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रमाणित शिक्षा	फील्ड अनुभव व शोध का समन्वय, सुरक्षा बलों में पेशेवर क्षमता व नेतृत्व को मजबूती
भारत - WFP आशय पत्र	फोर्टिफाइड चावल आपूर्ति, मानवीय खाद्य सहायता, वैश्विक स्तर पर भूख से लड़ाई	संकटग्रस्त क्षेत्रों में विश्वसनीय खाद्य आपूर्ति, भारत की वैश्विक खाद्य सुरक्षा साझेदार छवि को मजबूत करना
भारत - भूटान MoU (कृषि)	कृषि व संबद्ध क्षेत्र, पशुधन स्वास्थ्य, शोध, फसलोत्तर प्रबंधन, मूल्य श्रृंखला विकास	खाद्य सुरक्षा में सुधार, सतत खेती को बढ़ावा, ग्रामीण समृद्धि एवं द्विपक्षीय सहयोग सुदृढ़ करना

समझौता/समझौता ज्ञापन: जुलाई 2025

क्र.सं.	स्तर	समझौता पक्ष	क्षेत्र / उद्देश्य
1	देश	भारत - श्रीलंका	स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र (SVCC) के सहयोग से जनरल सर जॉन कोटिलेवाला रक्षा विश्वविद्यालय (KDU) में हिंदी भाषा शिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ; सांस्कृतिक व शैक्षणिक संबंधों को बढ़ावा।
2	देश	भारत - सऊदी अरब	Maaden के साथ 5 वर्षों के लिए 31 लाख मीट्रिक टन DAP उर्वरक आपूर्ति का दीर्घकालिक समझौता; उर्वरक सुरक्षा को सुदृढ़ करना; स्वास्थ्य, औषधि, अनुसंधान और निवेश में सहयोग।
3	संगठन	DEPwD - श्री अरविंद सोसाइटी (SAS)	रूपांतरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोजेक्ट इंकलूजन का शुभारंभ; दिव्यांग बच्चों हेतु समावेशी शिक्षा के लिए ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण; दूरदराज क्षेत्रों तक पहुंच; RPwD अधिनियम 2016 के अनुरूप।
4	संगठन	NESTS - यूनिसेफ इंडिया, टाटा मोटर्स, Ex-Navodayan फाउंडेशन	1.3 लाख आदिवासी छात्रों के लिए TALASH कैरियर मार्गदर्शन, कौशल्या कौशल विकास, IIT-JEE/NEET कोचिंग; शिक्षा व रोजगार की तैयारी को सशक्त बनाना।
5	संगठन	प्रसार भारती - हैंडबॉल संघ भारत (HAI)	राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिताओं के निर्माण व प्रसारण हेतु तीन वर्षीय समझौता; DD Sports, Waves OTT आदि के माध्यम से खेल को बढ़ावा।
6	संगठन	NCDEX - भारतीय मौसम विभाग (IMD)	भारत के पहले मौसम आधारित डेरिवेटिव्स (वर्षा आधारित वायदा अनुबंध) की शुरुआत; किसानों और जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों को मौसमीय जोखिम से सुरक्षा; प्रशिक्षण व अनुसंधान शामिल।
7	संगठन	विमनानु लिमिटेड - CYGR	उन्नत ड्रोन निर्माण सहयोग; ISR, नैनो व फिक्स्ड-विंग UAVs का उत्पादन; रक्षा आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भर भारत को समर्थन।
8	संगठन	NIEPID - जय वकील फाउंडेशन	बौद्धिक विकलांग बच्चों के लिए DISHA अभियान पाठ्यक्रम; IEPs, बहु-संवेदी उपकरण, डिजिटल पोर्टल व शिक्षक प्रशिक्षण शामिल; SDGs और समावेशी शिक्षा के अनुरूप।
9	संगठन	ग्रामीण विकास मंत्रालय - LIC	बीमा सखी योजना; DAY-NRLM के तहत ग्रामीण महिलाओं को स्टाइपेंड आधारित LIC एजेंसी; महिला नेतृत्व वाले वित्तीय समावेशन व ग्रामीण आय सृजन को बढ़ावा।
10	संगठन / राज्य	पंचायतों के लिए PESA उत्कृष्टता केंद्र - पंचायती राज मंत्रालय, म.प्र. सरकार, IGNTU	जनजातीय क्षेत्रों में जमीनी शासन को सुदृढ़ करना; क्षमता निर्माण, अनुसंधान, सहभागी योजना, जनजातीय विरासत का संरक्षण; PESA अधिनियम व स्थानीय SDGs के अनुरूप।




समझौता/समझौता ज्ञापन: जून 2025

श्रेणी	संस्था	समझौता किसके साथ	क्षेत्र / उद्देश्य
देशों के बीच समझौते	भारत	साइप्रस	- NPCI और Eurobank Cyprus ने साइप्रस में UPI सेवाओं को शुरू करने के लिए समझौता किया। - प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान अंतिम रूप दिया गया। - पर्यटकों, व्यापारियों और निवेशकों के लिए सीमा-पार डिजिटल भुगतान सक्षम होगा। - साइप्रस (भारत का एक प्रमुख FDI स्रोत) ने NSE के साथ GIFT सिटी में फिनटेक सहयोग हेतु भी MoU पर हस्ताक्षर किए।
संगठनों के बीच समझौते	वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)	CSIR-CRRI और SPA-नई दिल्ली	10 जून 2025 को 9 NCR शहरों में शहरी सड़क पुनर्विकास के लिए त्रिपक्षीय MoU। - हरित रणनीतियाँ, स्मार्ट सड़क डिजाइन, और Web-GIS आधारित निगरानी प्रणाली लागू की जाएगी। - एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल (PMC) द्वारा समर्थन प्राप्त। - उद्देश्य: सड़क धूल नियंत्रण व वायु गुणवत्ता में सुधार।
	NPCI (राष्ट्रीय भुगतान निगम)	IDRBT (बैंकिंग तकनीकी अनुसंधान संस्थान)	- भारत के डिजिटल भुगतान क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने हेतु समझौता। - उन्नत प्रशिक्षण, भुगतान सुरक्षा प्रमाणन की शुरुआत, और IBCART 3.0 (सचेत) प्लेटफॉर्म की सुविधा। - उद्देश्य: डेटा गोपनीयता और ढांचागत मजबूती।
	शेल इंडिया एवं DGT (MSDE के अधीन प्रशिक्षण महानिदेशालय)	संयुक्त हरित कौशल एवं इलेक्ट्रिक वाहन (EV) प्रशिक्षण कार्यक्रम	- हरित अर्थव्यवस्था के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु रणनीतिक साझेदारी। - EV डायग्नोस्टिक्स, बैटरी सिस्टम, और प्रमाणन आधारित व्यावहारिक प्रशिक्षण। 5 राज्यों में कार्यान्वयन, 250+ प्रशिक्षकों और हजारों छात्रों को लाभ।
	मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड	इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक	- भारत में खुदरा वाहन वित्तपोषण को बढ़ावा देने हेतु समझौता। - नए, पुराने और वाणिज्यिक वाहनों के लिए सुलभ ऋण सुविधा। - अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन पर ध्यान।
	DPIIT (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग)	योरस्टोरी मीडिया	'भारत प्रोजेक्ट' के अंतर्गत जमीनी स्तर की उद्यमिता को बढ़ावा देना। - द्वितीय/तृतीय श्रेणी शहरों व ग्रामीण भारत के 10 लाख उद्यमियों को लक्षित। - AI टूल्स, स्टार्टअप लॉन्चपैड और स्थानीय कहानियों के माध्यम से समर्थन। - स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों के अनुरूप।




समझौता/समझौता ज्ञापन: मार्च 2025
देश के साथ समझौता ज्ञापन

देश / संस्था	जिसके साथ MoU	क्षेत्र / उद्देश्य
भारत	वियतनाम	बौद्ध सहयोग: भारत और वियतनाम ने <i>UN Day of Vesak 2025</i> के दौरान एक MoU पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता <i>International Buddhist Confederation (IBC)</i> और <i>Vietnam Buddhist Sangha (VBS)</i> के बीच हुआ, जिससे वियतनाम चैप्टर की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य बौद्ध धर्म के प्रचार, वैश्विक शांति और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।
भारत	चिली	व्यापार सहयोग: भारत और चिली ने <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)</i> के लिए ToR (Terms of Reference) पर हस्ताक्षर किए। यह 2006 के PTA (Preferential Trade Agreement) और 2016 के विस्तार पर आधारित है। समझौता डिजिटल सेवाओं, MSMEs, महत्वपूर्ण खनिजों और निवेश में सहयोग को बढ़ावा देगा। पहली वार्ता 26-30 मई 2025 को नई दिल्ली में हुई।
भारत	यूरोपीय संघ (EU)	प्रौद्योगिकी और पर्यावरण: <i>India-EU Trade and Technology Council (TTC)</i> के तहत <i>Marine Plastic Litter (MPL)</i> और <i>Waste to Green Hydrogen (W2GH)</i> पर संयुक्त अनुसंधान की शुरुआत हुई। ₹391 करोड़ (~€41 मिलियन) की संयुक्त निवेश राशि के साथ यह पहल स्वच्छ ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी, और समुद्री प्रदूषण नियंत्रण पर केंद्रित है।
IIT खड़गपुर (भारत)	IME, सिंगापुर (A*STAR के अंतर्गत)	सेमीकंडक्टर सहयोग: IIT खड़गपुर और सिंगापुर के Institute of Microelectronics (IME) ने सेमीकंडक्टर तकनीक पर वैश्विक सहयोग के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी अनुसंधान, नवाचार और उन्नत चिप निर्माण क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

राज्य के साथ समझौता ज्ञापन

राज्य	जिसके साथ MoU	क्षेत्र / उद्देश्य
मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना: इस परियोजना का उद्देश्य जल-संकटग्रस्त जिलों को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराना है। यह समझौता ताप्ती नदी के 31.13 TMC जल के उपयोग पर आधारित है। ₹19,244 करोड़ की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना 3.57 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करेगी और 90% तक केंद्रीय निधि प्राप्त होने की संभावना है। यह विश्व की सबसे बड़ी जल रिचार्ज योजनाओं में से एक मानी जा रही है और सहकारी संघवाद व जल प्रबंधन की दिशा में एक अहम कदम है।

संगठन के बीच समझौता ज्ञापन

संगठन	जिसके साथ MoU	क्षेत्र / उद्देश्य
इंडिया पेमेंट्स (IPPB)	पोस्ट बैंक आदित्य कैपिटल (ABCL)	बिडला लिमिटेड
		क्रेडिट पहुंच में सुधार: IPPB और ABCL ने भारत भर में ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए रणनीतिक साझेदारी की है। IPPB के डाक नेटवर्क और ABCL के डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों को व्यक्तिगत, व्यवसायिक और संपत्ति ऋणों तक सरल पहुंच प्राप्त होगी। यह पहल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है, डिजिटल इंडिया अभियान को समर्थन देती है, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता व डेटा एनालिटिक्स की मदद से वैयक्तिकृत वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। इस कदम से ग्रामीण जनसंख्या को लाभ मिलेगा, उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और शहरी-ग्रामीण ऋण अंतर को पाटने में मदद मिलेगी।

समझौता/समझौता ज्ञापन: अप्रैल 2025
देश के साथ समझौता ज्ञापन

देश	समझौता किसके साथ	क्षेत्र / उद्देश्य
भारत	रूस	भारत-रूस प्राथमिक निवेश परियोजनाओं पर कार्य समूह (IRWG-PIP) के 8वें सत्र में दोनों देशों ने 6 नई रणनीतिक परियोजनाओं पर सहमति जताई। यह बैठक नई दिल्ली में अमरदीप सिंह भाटिया (भारत) और व्लादिमीर इलिचेव (रूस) की सह-अध्यक्षता में हुई। सत्र का मुख्य फोकस व्यापार, प्रौद्योगिकीय सहयोग और आर्थिक विकास पर था। साथ ही, भारत-रूस निवेश मंच के दूसरे संस्करण में 80 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिससे संयुक्त परियोजनाओं में बढ़ती रुचि सामने आई।





राज्य के साथ समझौता ज्ञापन

राज्य	समझौता किसके साथ	क्षेत्र / उद्देश्य
केरल	आईआईटी बॉम्बे	केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) और आईआईटी बॉम्बे मिलकर व्हीकल-टू-ग्रिड (V2G) तकनीक को लागू करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू कर रहे हैं। यह तकनीक इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की बैटरियों को न केवल चार्ज करने बल्कि जरूरत पड़ने पर ग्रिड में बिजली वापस भेजने की सुविधा देती है। इस पहल का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण, ग्रिड की स्थिरता बढ़ाना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। परियोजना के तहत ईवी मालिकों को प्रीमियम टैरिफ जैसे वित्तीय प्रोत्साहन भी मिलेंगे, विशेष रूप से जब वे पीक आवर्स के दौरान ऊर्जा ग्रिड को उपलब्ध कराते हैं।

संगठन के बीच समझौता ज्ञापन

संगठन	समझौता किसके साथ	क्षेत्र / उद्देश्य
इंडिया पोस्ट	निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड	म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए डोर-टू-डोर KYC सत्यापन सेवा प्रदान करने के लिए समझौता किया गया है। इस पहल का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, वृद्ध नागरिकों, और चलने-फिरने में असमर्थ लोगों के लिए म्यूचुअल फंड निवेश को और अधिक सुलभ बनाना है। इंडिया पोस्ट का देशव्यापी नेटवर्क पहले ही UTI और SUUTI के लिए 5 लाख से अधिक KYC सत्यापन कर चुका है। यह भागीदारी जन निवेश पहल को भी समर्थन देती है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	स्विगी	नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल के माध्यम से गिग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने हेतु समझौता किया गया। इसका उद्देश्य अगले 2-3 वर्षों में 12 लाख नौकरी के अवसर पैदा करना है। इसमें रीयल-टाइम जॉब पोस्टिंग, समावेशी नियुक्ति (युवाओं, महिलाओं और फ्लेक्सिबल वर्क चाहने वालों के लिए) को बढ़ावा देना शामिल है। स्विगी गिग जॉब्स, डिलीवरी रोल्ल्स, और सपोर्ट रोल्ल्स पोस्ट करेगा, जो डिजिटल सशक्तिकरण और कर्मचारी कल्याण योजनाओं को भी सहयोग देगा।

बैंकिंग करंट अफेयर्स

बैंकिंग करंट अफेयर्स: सितम्बर 2025

बैंक

क्रम सं.	बैंक का नाम	उद्देश्य / पहल
1	सीएसबी बैंक (CSB Bank)	विदेशी पदार्पण: आरबीआई-अनुमोदित दुबई प्रतिनिधि कार्यालय (दुबई नियामक की स्वीकृति शेष); एनआरआई सेवाएँ और एनआरआई जमा बढ़ाना।
2	एसबीआई कार्ड x फ्लिपकार्ट	सह-ब्रांडेड 'फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड' लॉन्च; ऑनलाइन शॉपिंग पर विशेष कैशबैक।
3	बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB)	'बॉब डिजी उद्यम' लॉन्च: एमएसई के लिए ₹10-50 लाख तक जमानत-मुक्त डिजिटल वर्किंग कैपिटल ऋण (CC/OD, 12 माह अवधि; CGTMSE के अंतर्गत)।
4	कर्नाटक ग्रामीण बैंक (KGB)	11 विलयित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए सामान्य लोगो अपनाया; प्रतीकात्मकता: वित्त/विश्वास (गहरा नीला), जीवन/विकास (गहरा हरा)।
5	यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक x भारतपे	यूनिटी बैंक भारतपे क्रेडिट कार्ड (RuPay, UPI-लिंक योग्य; 12 माह तक ईएमआई) लॉन्च - व्यापारी भुगतान हेतु।
6	बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB)	रिलायंस कम्युनिकेशन्स/अनिल अंबानी ऋण खातों को धोखाधड़ी घोषित; ₹1,656 करोड़ की एक्सपोज़र।
7	इंडियन बैंक	कॉर्पोरेट साइट को indianbank.bank.in पर स्थानांतरित किया (RBI निर्देशानुसार साइबर सुरक्षा/एंटी-फ्राड हेतु)।
8	भारतीय स्टेट बैंक (SBI)	BRSR FY25: सर्वाधिक ग्राहक शिकायतें (6.87 लाख; 1.05 लाख लंबित); अधिकतर अनधिकृत ई-डेबिट पर।
9	पंजाब नेशनल बैंक (PNB)	राजस्थान सरकार के साथ ₹21,000 करोड़ का MoU (राइजिंग राजस्थान): सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु।
10	एसबीआई	'ट्रीम2डेमो' स्टार्टअप पिच फेस्ट आयोजित; उद्यमियों को निवेशकों से जोड़ना और स्टार्टअप वित्तपोषण प्रदर्शित करना।





क्रम सं.	बैंक का नाम	उद्देश्य / पहल
11	एक्सिस मैक्स लाइफ × IPPB	टियर-1 से परे किरायायती जीवन बीमा विस्तार हेतु साझेदारी; IPPB नेटवर्क और डाकघर एक्सेस पॉइंट्स का उपयोग।
12	आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक (APGB) × NABARD × AquaExchange	झींगा (श्रिम्प) फसल ऋण: ₹25 करोड़ प्रारंभिक; FY25 में ₹100 करोड़ और अगले FY में ₹250 करोड़ तक विस्तार की योजना।
13	सुर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक	FD-समर्थित सुरक्षित क्रेडिट कार्ड लॉन्च - RuPay Platinum (न्यूनतम FD ₹1,000) एवं RuPay Select (न्यूनतम FD ₹1,11,500); UPI-सक्षम।
14	एसबीआई	\$500 मिलियन जुटाए (5-वर्षीय सीनियर अनसिक्वर्ड नोट्स; कूपन 4.50%); SGX और NSE-IX (GIFT City) पर लिस्टिंग।
15	इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB)	8वीं वर्षगांठ: 12+ करोड़ ग्राहक; 1.64 लाख डाकघर व 1.9 लाख GDS/पोस्टमैन के माध्यम से अंतिम छोर सेवाएँ; नए डिजिटल उत्पाद लॉन्च।
16	यस बैंक	RBI ने आर. गांधी की चेयरमैन के रूप में पुनर्नियुक्ति को मई 2027 तक मंजूरी दी।
17	सीएसबी बैंक (प्रोफाइल)	स्थापना: 1920; मुख्यालय: त्रिशूर; एमडी एवं सीईओ: प्रलय मंडल।
18	पीएनबी (प्रोफाइल)	स्थापना: 1894; मुख्यालय: नई दिल्ली; एमडी एवं सीईओ: अशोक चंद्रा; टैगलाइन: "The Name You Can Bank Upon."
19	बैंक ऑफ बड़ौदा (प्रोफाइल)	स्थापना: 1908; मुख्यालय: वडोदरा; एमडी एवं सीईओ: देवदत्ता चंद; टैगलाइन: "India's International Bank."
20	एसबीआई (प्रोफाइल)	स्थापना: 1955; मुख्यालय: मुंबई; चेयरमैन: चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी।

आरबीआई समाचार

क्रम सं.	नाम	उद्देश्य / विवरण
1	आरबीआई बुलेटिन - प्राइवेट कैपेक्स आउटलुक	FY26 में निजी पूंजीगत व्यय (Capex) में 21.5% वृद्धि का अनुमान, ₹2.67 लाख करोड़ तक; कारण: ब्याज दर कटौती, अपस्फीति, तरलता, क्षमता उपयोग, ग्रीनफील्ड इंप्रा (मुख्यतः बिजली क्षेत्र)।
2	गवर्नर संजय मल्होत्रा का संबोधन ("संतुप्ति शिविर")	कहा भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर; GDP वृद्धि 7.8% (Q1 FY26); PMJDY खातों 55 करोड़; KYC प्रोत्साहन, म्यूल अकाउंट रोकथाम, UPI/डिजिटल साक्षरता पर जोर।
3	बंधन बैंक पर जुर्माना	नियामकीय/कानूनी चूक (कमीशन-आधारित वेतन, बैंकएंड डेटा परिवर्तन, कमज़ोर ऑडिट ट्रेल्स) पर ₹44.7 लाख का दंड।
4	FSDC उप-समिति बैठक (अध्यक्ष: RBI गवर्नर)	मैक्रो/वित्तीय स्थिरता, NSFI 2025-30 की समीक्षा; स्थिरता और विकास हेतु अंतर-नियामक समन्वय।
5	BSR-2 (जमा) - जून 2025	जमा में 11.3% वार्षिक वृद्धि; बड़े जमा 45.7%; परिवार 59.9%; वरिष्ठ नागरिक 20.4%; निजी बैंकों की वृद्धि पीएसबी से अधिक।
6	नरीमन पॉइंट भूमि खरीद	MMRCL से 4.16 एकड़ ज़मीन ₹3,472 करोड़ (+ ₹208.3 करोड़ स्टॉप झूटी) में खरीदी; स्वयं/वाणिज्यिक उपयोग हेतु फ्रीहोल्ड स्वामित्व।
7	भूपेन हजारीका स्मारक सिक्का	13 सितम्बर 2025 को जन्म शताब्दी पर सिक्का जारी; कार्यक्रम गुवाहाटी में, प्रधानमंत्री की उपस्थिति में।
8	यस बैंक नेतृत्व स्वीकृति	आर. गांधी को मई 2027 तक पुनः अध्यक्ष नियुक्त (नेतृत्व निरंतरता)।
9	मुद्रा शिक्षा पोर्टल	indiancurrency.rbi.org.in माइक्रोसाइट का शुभारंभ; इसमें 360° दृश्य, मल्टीमीडिया संसाधन और खेल शामिल, जनता को मुद्रा संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए।
10	विनियामक समीक्षा प्रकोष्ठ (RRC)	बैंकिंग विनियमों की समय-समय पर समीक्षा और संशोधन हेतु नया परामर्श समूह, बेहतर सुशासन के लिए।

नियामक प्राधिकरणों से संबंधित समसामयिक मामले

क्रम सं.	नाम	उद्देश्य / विवरण
1	IDRBT / .bank.in डोमेन	इंडियन बैंक ने अपनी वेबसाइट को .bank.in डोमेन पर स्थानांतरित किया (IDRBT रजिस्ट्रार के तहत) ताकि साइबर सुरक्षा व धोखाधड़ी-रोधी विश्वास मजबूत हो।
2	IRDAI विज्ञान 2047 (संदर्भ)	Axis Max Life × IPPB साझेदारी "2047 तक सभी के लिए बीमा" लक्ष्य से जुड़ी; ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा की पहुँच बढ़ाने पर केंद्रित।





क्रम सं.	नाम	उद्देश्य / विवरण
3	ADB-भारत सरकार (उत्तराखंड पर्यटन)	\$126.42 मिलियन ऋण तेहरी झील क्षेत्र में जलवायु-संवेदनशील पर्यटन, स्वच्छता, आपदा-तैयारी हेतु; 87,000 स्थानीय लोग और 27 लाख पर्यटक लाभान्वित होंगे।
4	विश्व बैंक SHORE (तमिलनाडु व कर्नाटक)	\$212.64 मिलियन IBRD ऋण तटीय मजबूती, प्लास्टिक कचरा कमी, और नए रोजगार सृजन के लिए।
5	ईपीएफओ (EPFO)	'पासबुक लाइट' ऐप लॉन्च किया गया, जिससे सदस्य अपने खाते तक तेज़ और सरल पहुंच प्राप्त कर सकेंगे।
6	यूपीआई (NPCI)	चुनिंदा व्यापारी श्रेणियों के लिए दैनिक P2M सीमा ₹10 लाख तक बढ़ाई गई (P2P सीमा ₹1 लाख ही रहेगी)।
7	फोनपे (PhonePe)	आरबीआई ने फोनपे को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में मंजूरी दी, जिससे एसएमई और अल्प-सेवित व्यवसायों तक पहुंच बढ़ेगी।

सेबी समाचार

क्रम सं.	घोषणा	मुख्य विवरण	प्रभावी तिथि
1	इंट्राडे डेरिवेटिव नियम कड़े (एक्सपायरी दिवस)	इंडेक्स ऑप्शंस की इंट्राडे नेट पोझिशन सीमा ₹1,500 करोड़ से बढ़ाकर ₹5,000 करोड़/इकाई की गई; FutEq पद्धति, रियल-टाइम निगरानी, 15 दिन में संयुक्त SOP।	सितम्बर 2025 (घोषित)
2	बंधन AMC - विशेष निवेश फंड	अरुधा SIF प्लेटफॉर्म की स्वीकृति (इक्विटी/डेट/हाइब्रिड; बिना हेज किए शॉर्ट डेरिवेटिव शामिल)।	सितम्बर 2025
3	IPO हेतु ESOP लचीलापन	प्रमोटर अब IPO से ≥1 वर्ष पहले दिए गए ESOP/SAR अपने पास रख सकते हैं (पहले वर्जित)।	सितम्बर 2025
4	PSU स्वैच्छिक डीलिलिस्टिंग ढांचा (≥90% सरकारी हिस्सेदारी)	पब्लिक नोट 2/3rd की शर्त ढीली; फिक्स्ड प्राइस डीलिलिस्टिंग ≥15% फ्लोर से ऊपर; नियमों में स्ट्राइक-ऑफ पर 7-वर्ष एस्करो में बकाया जमा।	सितम्बर 2025
5	AIFs में सह-निवेश विंडो (CIV योजनाएँ)	कैटेगरी I/II AIF अब मान्यताप्राप्त निवेशकों को CIV दे सकेंगे; कोई लीवरेज नहीं; निवेशक किसी इन्वेस्टमेंट में AIF योगदान का 3 गुना तक निवेश कर सकते हैं।	सितम्बर 2025
6	प्रवर्तन कार्रवाईयाँ (अप्रैल 2024-जून 2025)	886 इकाइयों पर धोखाधड़ी/अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए कार्यवाही।	अवधि अनुसार
7	SWAGAT-FI	लंबी अवधि के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के ऑनबोर्डिंग को आसान बनाने के लिए डिजिटल KYC आधारित पोर्टल लॉन्च किया गया।	सितम्बर 2025

बैंकिंग करंट अफेयर्स: अगस्त 2025

क्रम संख्या	बैंक का नाम	उद्देश्य / पहल
1	एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक	भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना जिसे आरबीआई से यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति मिली। यह उपलब्धि बैंक के मज़बूत बिज़नेस मॉडल, सुशासन और वित्तीय समावेशन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
2	बैंक ऑफ बड़ौदा	अपने bob इ पे (bob World) ऐप पर वैश्विक UPI सुविधा शुरू की। अब भारतीय और NRI ग्राहक 8 देशों (मॉरीशस, सिंगापुर, यूएई, अमेरिका, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, भूटान) में UPI से भुगतान कर सकेंगे। इसमें ₹1,00,000 प्रति लेनदेन सीमा और सिंगापुर से रीयल-टाइम प्रेषण जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।
3	आईसीआईसीआई बैंक	नए बचत खातों के लिए शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम औसत शेष राशि (MAB) ₹50,000 से घटाकर ₹15,000 कर दी। अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ₹25,000 से घटाकर ₹7,500 किया गया। ग्रामीण व अर्ध-शहरी मौजूदा ग्राहकों के लिए यह ₹5,000 ही रहेगा। यह कदम ग्राहक असंतोष के बाद उठाया गया।
4	आईसीआईसीआई बैंक	लगातार तीन वित्तीय वर्षों से निजी क्षेत्र के बड़े बैंकों में सबसे कम कर्मचारी त्याग दर (Attrition Rate) दर्ज की। FY23 में 30.9% से घटकर FY24 में 24.5% और FY25 में 18% हो गई। यह सफलता बेहतर वेतन संरचना और कार्य वातावरण का परिणाम है।
5	आईडीएफसी फर्स्ट बैंक	RemitFIRST2India प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह एक शून्य-शुल्क डिजिटल प्रेषण सेवा है, जिसके माध्यम से NRI सिंगापुर और हांगकांग से भारत में तेज़ और सुरक्षित धन प्रेषण कर सकते हैं। इसमें रीयल-टाइम ट्रैकिंग, प्रतिस्पर्धी फॉरेक्स दरें और पेपरलेस प्रक्रिया की सुविधा है।
6	एक्सिस बैंक	Lock FD फीचर लॉन्च किया। इससे ग्राहक अपनी फिक्स्ड डिपॉज़िट को ऑनलाइन चैनल से बंद नहीं कर पाएँगे, केवल शाखा जाकर पहचान सत्यापन के बाद ही बंद कर सकेंगे। यह सुविधा फिशिंग, मैलवेयर और हैकिंग जैसे डिजिटल धोखाधड़ी जोखिमों से बचाव प्रदान करती है।





क्रम संख्या	बैंक का नाम	उद्देश्य / पहल
7.	भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)	- भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) 15 अगस्त, 2025 से ₹25,000 से अधिक के आईएमपीएस ऑनलाइन हस्तांतरण पर मामूली शुल्क लगाना शुरू करेगा, जो राशि के आधार पर ₹2 से ₹10 प्लस जीएसटी तक होगा। - शाखा-आधारित आईएमपीएस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वेतन पैकेज खाताधारकों और चुनिंदा चालू खाता प्रकारों को छूट दी गई है। कॉर्पोरेट खाताधारकों पर 8 सितंबर, 2025 से संशोधित शुल्क लागू होंगे। - यह कदम एसबीआई द्वारा सेवा वितरण और लागत प्रबंधन के बीच संतुलन बनाने के प्रयास को दर्शाता है, जबकि प्रमुख ग्राहक वर्गों के लिए छूट बरकरार रखी गई है।
	भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)	79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, एसबीआई ने अग्रिमपथ योजना के अंतर्गत नामांकित अग्रिमपथों के लिए एक जमानत-मुक्त व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की, जिसमें शून्य प्रसंस्करण शुल्क और 30 सितंबर, 2025 तक वैध 10.50% की एक समान व्याज दर के साथ ₹4 लाख तक के ऋण की पेशकश की गई है। पुनर्भुगतान अवधि अग्रिमपथ सेवा अवधि के अनुरूप है। - इसके अतिरिक्त, एसबीआई ने ₹25,000 से अधिक के ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए आईएमपीएस शुल्क संशोधित किए हैं, जो अब ₹2 से ₹10 प्लस जीएसटी तक हैं, जो 15 अगस्त, 2025 से प्रभावी हैं।

आरबीआई समाचार

नियामक प्राधिकरणों से संबंधित समसामयिक मामले		
क्रम संख्या	नाम	उद्देश्य / पहल
1	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक का सरस्वत बैंक में विलय (4 अगस्त 2025 से प्रभावी)। सरस्वत बैंक सभी परिसंपत्तियों व देनदारियों को संभालेगा और ग्राहकों के हितों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह कदम सहकारी बैंकिंग ढाँचे को मजबूत करता है।
2	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	\$5 बिलियन डॉलर-रुपया स्वेप बिना रोलओवर के निपटाने का निर्णय लिया। यह RBI के रुपये की मजबूत तरलता (₹3.60 लाख करोड़+) पर विश्वास को दर्शाता है। इस कदम से तरलता स्थिर रहेगी और मनी मार्केट में बाधा नहीं आएगी।
3	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	RBI प्रोफेशनल फोरकास्टर सर्वे: 2025-26 में भारत के माल आयात 2.5% और निर्यात 1.2% बढ़ने का अनुमान। इससे व्यापार घाटा व चालू खाता घाटा (0.8% GDP) बढ़ सकता है। GDP वृद्धि दर 2025-26 में 6.4% और 2026-27 में 6.7% रहने की संभावना। CPI महंगाई 3.1% से बढ़कर 4.4% रहने का अनुमान।
4	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	विदेशी इकाइयों को स्पेशल रुपया बोखो अकाउंट (SRVA) में रखी अधिशेष राशि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों (ट्रेजरी बिल समेत) में निवेश की अनुमति दी। इससे अप्रयुक्त रुपये का सुरक्षित भारतीय ऋण साधनों में निवेश संभव होगा।
5	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	बैंकिंग सुविधा और वित्तीय समावेशन बढ़ाने हेतु तीन पहलें: (1) पंचायत स्तर पर डोरस्टेप re-KYC कैंप (जुलाई-सितंबर) जिसमें माइक्रो-इंश्योरेंस और पेंशन योजनाएँ भी उपलब्ध होंगी, (2) मृत ग्राहकों के दावों के लिए सरल प्रक्रिया, और (3) रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर उन्नत फीचर्स।
6.	आरबीआई तरलता प्रबंधन ढाँचा समीक्षा 2025	अल्पकालिक व्याज दरों पर नियंत्रण को मजबूत करना, बाजार स्थिरता सुनिश्चित करना, 14-दिवसीय परिवर्तनीय रेपो को बंद करना, डब्ल्यूएसीआर को परिचालन लक्ष्य के रूप में बनाए रखना, एसपीडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना तथा अधिशेष तरलता का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना।
7.	आरबीआई मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) - सितंबर 2025	मूल्य परिवर्तनों और मुद्रास्फीति अपेक्षाओं (3 महीने और 1 वर्ष) के बारे में घरेलू धारणाओं को समझना, तथा मौद्रिक नीति निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करना।

सेबी समाचार

क्रमांक	घोषणा	मुख्य विवरण	प्रभावी तिथि
1	रूपेश सतीश दलाल HUF पर ₹10 लाख का जुर्माना	HDFC मर्जर शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग; बेटे के संपर्क से Deloitte इनसाइडर से UPSI प्राप्त; 1-4 अप्रैल 2022 ट्रेड; PIT नियमों का उल्लंघन।	अप्रैल 2022 (मामला जाँच: नवंबर 2021-अप्रैल 2022, दंड 2025)
2	विशेष निवेश फंड (SIFs) में न्यूनतम निवेश अनिवार्य ₹10 लाख	AMC को दैनिक अनुपालन सुनिश्चित करना होगा; उल्लंघन पर यूनिट फ्रीज; 30 दिन में सुधार या ऑटो-रिडेम्पशन।	तत्काल (SEBI अधिसूचना, 2025)
3	NSE ने ₹40.35 करोड़ में मामला निपटारा	NDAL व थर्ड-पार्टी वेंडरों को संवेदनशील अप्रकाशित जानकारी साझा करने के आरोप (फरवरी 2021-मार्च 2022); बिना दोष स्वीकारे सुलह।	2025





क्रमांक	घोषणा	मुख्य विवरण	प्रभावी तिथि
4	MCXCCL को क्लीयरिंग कॉरपोरेशन की मान्यता नवीनीकृत	मान्यता 3 वर्ष के लिए वैध (31 जुलाई 2025 - 30 जुलाई 2028)।	31 जुलाई 2025
5	संबंधित पक्ष लेन-देन (RPTs) पर सीमा-आधारित विनियमन प्रस्तावित	टर्नओवर स्लैब पर आधारित थ्रेशोल्ड; नई सीमा ₹5,000 करोड़ तक; 60% कम लेन-देन पर शेयरधारक स्वीकृति आवश्यक।	टिप्पणियों हेतु खुला (25 अगस्त 2025 तक)
6	फ्रैक्शनल शेयर ट्रेडिंग की अनुमति (Innovation Sandbox)	बेंगलुरु स्टार्टअप Xaaults को मंजूरी; स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट व आंशिक शेयर टेस्टिंग; पूर्ण परीक्षण नियामक मंजूरी के बाद।	अगस्त 2025
7	द वेल्थ कंपनी (पेंटोमैथ ग्रुप) को म्यूचुअल फंड शुरू करने की मंजूरी	भारत का पहला फंड हाउस जिसकी संस्थापक महिला (मधु लूनावत); पंजीकरण प्रमाणपत्र मिला।	18 जुलाई 2025
8	विदेशी निवेशकों हेतु SWAGAT-FI पोर्टल प्रस्तावित	विश्वसनीय विदेशी निवेशकों के लिए 10 वर्ष की पंजीकरण वैधता; अनुपालन सरल।	प्रस्ताव (2025)
9	बड़े IPO ढांचे में सुधार का प्रस्ताव	खुदरा कोटा 25% तक घटाया; QIB आवंटन 60% तक बढ़ाया; एंकर निवेशकों में वीमा व पेंशन फंड शामिल।	प्रस्ताव (2025)
10	RPT शेयरधारक अनुमोदन के लिए उच्चतर सीमा प्रस्तावित	स्केल-आधारित मानक: टर्नओवर का 10% या ₹2,000-3,000 करोड़ तक की ऊँची सीमा; बड़ी कंपनियों को राहत।	प्रस्ताव (2025)
11	एल्गोरिथमिक व प्रॉपर्टायटरी ट्रेडिंग की परिभाषाएँ प्रस्तावित	स्टॉक ब्रोकर विनियमों में नई परिभाषाएँ; ब्रोकरों को NDS-OM पर व्यापक पहुँच पर विचार; Jane Street प्रतिबंध से जुड़ा कदम।	प्रस्ताव (जुलाई 2025)
12	न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (MPS) नियमों में ढील प्रस्तावित	पोस्ट-इश्यू मार्केट कैप बकेट्स पर आधारित समयसीमा; 25% MPS हेतु 10 वर्ष तक की मोहलत।	प्रस्ताव (2025)
13	886 संस्थाओं पर कार्रवाई	PFUTP विनियमों के तहत (अप्रैल 2024-जून 2025); वित्तीय रिपोर्ट में गलत बयान; US-स्थित Jane Street पर प्रतिबंध।	जून-जुलाई 2025
14	ब्लॉक डील फ्रेमवर्क सुधार का प्रस्ताव	न्यूनतम ऑर्डर साइज ₹25 करोड़; नॉन-F&O शेयरों के लिए 3% का व्यापक मूल्य बैंड; उसी दिन प्रकटीकरण अनिवार्य।	प्रस्ताव (2025)
15	पहली बार महिला MF निवेशकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रस्तावित	वित्तीय समावेशन हेतु; AMFI अभियानों 'इन्वेस्टमेंट का सही कदम' व 'भारत निवेश रेल यात्रा' से जुड़ा।	2025
16	IDBI बैंक में LIC का पुनर्वर्गीकरण मंजूर	LIC की वोटिंग शक्ति 10% तक सीमित (49.24% हिस्सेदारी होने पर भी); 2 वर्ष में 15% तक घटानी होगी; कोई विशेष अधिकार/बोर्ड नियंत्रण नहीं।	2025

बैंकिंग करंट अफेयर्स: जुलाई 2025

बैंक का नाम	उद्देश्य / पहल (हिंदी में विवरण)
कर्नाटक बैंक	कर्नाटक बैंक में नेतृत्व परिवर्तन हुआ क्योंकि एमडी व सीईओ और कार्यकारी निदेशक ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया। संचालन स्थिर बनाए रखने के लिए सीओओ की नियुक्ति की गई और निवेशकों को भरोसा दिलाया गया कि बैंक पूंजी से संपन्न है और परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्ध है। यह उत्तराधिकार योजना और सुशासन की महत्ता को दर्शाता है।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) - सौर ऊर्जा योजना	एसबीआई ने भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में योगदान देते हुए "सोलर रूफटॉप कार्यक्रम" शुरू किया, जिससे FY27 तक 40 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य है। यह भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य के अनुरूप है और बैंक की सामाजिक निवेश व हरित तकनीकी वित्त में प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) - वैश्विक व्यापार केंद्र	एसबीआई ने कोलकाता और हैदराबाद में दो ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर शुरू किए हैं, जो आयात-निर्यात सेवाओं को तेज और डिजिटल बनाने में सहायक होंगे। AI, ML और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का उपयोग कर व्यापार को सुरक्षित और कुशल बनाया जाएगा।
इंडियन बैंक व पंजाब नेशनल बैंक (PNB)	दोनों बैंकों ने क्रमशः 7 और 1 जुलाई 2025 से बचत खातों पर न्यूनतम बैलेंस जमाना हटा दिया। इंडियन बैंक ने एक-वर्षीय ऋण दर घटाकर 9% की, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में कदम है।
एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड	इस बैंक को RBI अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया, जिससे इसे आरबीआई सुविधाएं और क्लियरिंग हाउस सदस्यता मिलेगी। यह बैंक डिजिटल सेवाओं और निम्न-आय वर्ग के लिए सेवाएं प्रदान करता है।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) - QIP फंडिंग	एसबीआई ने ₹25,000 करोड़ का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) किया, जो 4.5 गुना ओवरसब्सक्राइब हुआ। इससे पूंजी अनुपात 11.50% हुआ और खुदरा, एमएसएमई व कॉर्पोरेट ऋण बढ़ाने की क्षमता बनी। यह बैंक और अर्थव्यवस्था में निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है।
फिनो पेमेंट्स बैंक	बैंक ने "GATI" नामक शून्य-बैलेंस डिजिटल बचत खाता लॉन्च किया, खासकर पश्चिम बंगाल में यूपीआई लेनदेन बढ़ाने के लिए। ग्राहक 40,301 मर्चेन्ट पॉइंट्स से तुरंत खाता खोल सकते हैं। यह पहल ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों, महिलाओं और युवाओं को लक्षित करती है।





बैंक का नाम	उद्देश्य / पहल (हिंदी में विवरण)
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) - वैश्विक उपभोक्ता सम्मान	ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा SBI को "विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक - 2025" घोषित किया गया। यह सम्मान बैंक की डिजिटल नवाचार, AI आधारित सेवाएं और बहुभाषीय वॉइस बैंकिंग के लिए मिला, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण ग्राहकों को लाभ हुआ।

आरबीआई समाचार

नियामक प्राधिकरणों से संबंधित समसामयिक मामले		
क्र.सं.	नाम	उद्देश्य
1	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) में धोखाधड़ी रोकने के लिए 1 जनवरी 2026 से नई सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। इसमें कड़े KYC नियम, एक ऑपरेटर-एक बैंक नीति, और लेनदेन की निगरानी शामिल है।
2	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	30 मई 2025 की सेक्टरल क्रेडिट रिपोर्ट के अनुसार, औद्योगिक ऋण, व्यक्तिगत ऋण और NBFC को दिए गए ऋण में गिरावट दर्ज हुई, जबकि मध्यम उद्यम और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वृद्धि हुई।
3	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	1 जनवरी 2026 से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) को दिए गए फ्लोटिंग रेट ऋणों पर प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं लगेगी, जिससे क्रेडिट सुलभ और सस्ता होगा।
4	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	RBI ने सभी वित्तीय संस्थाओं को टेलीकॉम विभाग द्वारा विकसित Financial Fraud Risk Indicator (FRI) प्रणाली अपनाने का निर्देश दिया है, जिससे साइबर धोखाधड़ी वाले मोबाइल नंबरों की पहचान हो सके।
5	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	30 जून 2025 से FRI प्रणाली को सभी बैंकों, NBFC और UPI प्लेटफॉर्म पर लागू किया गया है। यह वास्तविक समय में धोखाधड़ी का पता लगाकर डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करेगा।
6	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	1 जुलाई 2025 तक ₹2000 के नोटों में ₹6,099 करोड़ अभी भी चलन में हैं। RBI ने इनकी वापसी जारी रखी है, हालाँकि यह नोट अभी भी कानूनी रूप से वैध हैं।
7	e-Kuber प्रणाली	16 जुलाई 2025 से ₹75 करोड़ से ऊपर के सभी सरकारी भुगतान केवल e-Kuber प्रणाली के माध्यम से किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता और गति बढ़ेगी।
8	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	11 जुलाई 2025 को RBI ने ₹25,000 करोड़ की दो सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी की घोषणा की। इनमें से एक नई और एक पुनः जारी की गई है।
9	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	HDFC बैंक और श्रीराम फाइनेंस पर नियामकीय उल्लंघनों के लिए क्रमशः ₹4.88 लाख और ₹2.70 लाख का जुर्माना लगाया गया।
10	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	वित्तीय समावेशन सूचकांक (FY25) 64.2 से बढ़कर 67.0 हो गया है, जिससे डिजिटल वित्तीय सेवाओं और योजनाओं की सफलता झलकती है।
11	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	23 जुलाई 2025 को ₹50,000 करोड़ की VRR नीलामी आयोजित की गई, जिससे बाजार में तरलता की समस्या को सुलझाने में मदद मिली।
12	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	Warburg Pincus को IDFC फर्स्ट बैंक में ₹4,876 करोड़ का निवेश करने की अनुमति दी गई है, जिससे बैंक की पूंजी और विस्तार की क्षमता में वृद्धि होगी।

बैंकिंग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स

- भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वित्त वर्ष 26 में शेयरों के योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से लगभग ₹45,000 करोड़ जुटाएंगे, जिसकी शुरुआत एसबीआई से होगी। सरकार अक्टूबर 2025 तक आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने और कई अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शेयर बेचने की भी योजना बना रही है। ये कदम केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित सरकार की ₹47,000 करोड़ की विनिवेश योजना का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य बैंकों को मजबूत बनाना और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है।
- ताइवान के सबसे बड़े निजी बैंक, सीटीबीसी बैंक ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में एक आईएफएससी बैंकिंग इकाई (आईबीयू) स्थापित करने के लिए आवेदन किया है। यह आवेदन आईएफएससी के पास जमा किया गया है और इसमें ब्रिगेड टावर्स में 3,100 वर्ग फुट कार्यालय स्थान का उपयोग करने का प्रस्ताव है। बैंक पहले से ही नई दिल्ली में कार्यरत है और अब गिफ्ट सिटी के माध्यम से अपनी सेवाओं का विस्तार करने की योजना बना रहा है। ताइवान, यूएई और फ्रांस के अन्य बैंकों ने भी इसी तरह के कदम उठाए हैं। मार्च 2025 तक, गिफ्ट सिटी में 31 आईबीयू स्थापित किए जा चुके हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरी रुचि दिखा रहे हैं।
- एनपीसीआई इंटरनेशनल द्वारा 17 जुलाई, 2025 को विस्तारित यूपीआई-पेनाउ लिंकेज में अब 19 भारतीय बैंक शामिल हैं, जिसका उद्देश्य भारत और सिंगापुर के बीच वास्तविक समय में सीमा पार धन प्रेषण को बढ़ावा देना है। आरबीआई और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा समर्थित, यह पहल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और छात्रों के लिए, और वैश्विक डिजिटल भुगतान नवाचार में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करती है।
- अग्रणी फिनटेक स्टार्टअप, एक्ज़िमपे, ने आरबीआई का सैद्धांतिक रूप से पीए-सीबी लाइसेंस हासिल कर लिया है, जिससे वह ई-कॉमर्स, डिजिटल सेवाओं और बी2बी व्यापार के लिए सीमा-पार भुगतान की सुविधा प्रदान कर सकेगा। कंपनी की योजना वित्त वर्ष 26 तक 450 मिलियन डॉलर से अधिक के संसाधित लेनदेन और 3.5 मिलियन डॉलर की इक्विटी फंडिंग के साथ 10 गुना विस्तार करने की है। यह उपलब्धि एशियाई सीमा-पार भुगतान गलियारे में भारत की उपस्थिति को बढ़ाती है और एसएमई के लिए विनियमित फिनटेक समाधानों की भूमिका को मजबूत करती है।





- एचएसबीसी का एनजेडबीए से बाहर निकलना, प्रमुख अमेरिकी और कनाडाई ऋणदाताओं द्वारा स्थापित प्रवृत्ति का अनुसरण करते हुए, इस गठबंधन से बाहर निकलने वाला पहला ब्रिटिश बैंक बन गया है। इस निकासी ने जलवायु कार्यकर्ताओं और निवेशकों की व्यापक आलोचना को जन्म दिया है, जिससे एचएसबीसी की जलवायु प्राथमिकताओं पर संदेह पैदा हुआ है और बैंकिंग क्षेत्र के भीतर वैश्विक जलवायु समन्वय के लिए संभावित जोखिमों का संकेत मिला है। हालाँकि एचएसबीसी अपने नेट-ज़ीरो 2050 लक्ष्य की पुष्टि करता है, लेकिन इस कदम ने बैंकों द्वारा जलवायु जोखिमों, प्रकटीकरणों और क्षेत्र-व्यापी जवाबदेही से निपटने के तरीके में गहराते मतभेदों को उजागर किया है।
- केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) ने 31 मार्च, 2025 तक ₹1.62 ट्रिलियन बकाया वाले 1,629 इरादतन चूककर्ताओं की पहचान की है। सरकार ने NPA की वसूली के लिए कई कानूनी और प्रशासनिक उपाय लागू किए हैं, जिनमें SARFAESI, IBC के माध्यम से कार्रवाई और CIBIL व एक्सपेरियन जैसे क्रेडिट ब्यूरो के माध्यम से सार्वजनिक प्रकटीकरण शामिल है। यह मुद्दा बैंकिंग क्षेत्र की सेहत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, खासकर धीमी जमा वृद्धि और बढ़ते ऋण जोखिम को देखते हुए।

बैंकिंग करंट अफेयर्स: जून 2025

क्र.सं.	बैंक का नाम	उद्देश्य / पहल
1	केनरा बैंक	सभी बचत खातों (सैलरी और एनआरआई सहित) पर औसत मासिक शेष (AMB) अनिवार्यता समाप्त की; वित्तीय समावेशन की दिशा में कदम।
2	डॉयचे बैंक	स्टीफन शेफर को भारत स्थित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का सीईओ नियुक्त किया गया; तकनीकी नवाचार और भारत संचालन पर जोर।
3	एशियन डेवलपमेंट बैंक	भारत में ₹10 अरब की शहरी परिवर्तन योजना शुरू की; 100+ शहरों में मेट्रो, आरआरटीएस और सेवाओं का उन्नयन।
4	भारतीय स्टेट बैंक (SBI)	FY 2024-25 के लिए ₹8,076.84 करोड़ का डिविडेड सरकार को दिया; मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और राजस्व में योगदान।
5	फेडरल बैंक	स्केपिया के साथ मिलकर भारत का पहला वीज़ा + रूपे डुअल नेटवर्क क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया; UPI, विदेशी लेनदेन पर शून्य शुल्क।
6	एडीबी (ADB)	गुजरात स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए \$109.97 मिलियन ऋण मंजूर; तकनीकी शिक्षा और रोजगार उन्नयन की दिशा में प्रयास।
7	DFCC बैंक पीएलसी	NSE IX (GIFT सिटी) पर ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाला पहला विदेशी कॉर्पोरेट बना; सौर ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त देगा।
8	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस	मोहम्मद आरिफ खान को डिप्टी सीईओ नियुक्त किया गया; ग्राहक अनुभव और तकनीकी नवाचार पर केंद्रित दृष्टिकोण।
9	पंजाब नेशनल बैंक (PNB)	रक्षक प्लस योजना के तहत 26 शहीदों के परिवारों को ₹17.02 करोड़ वितरित; बीमा और सहायता प्रदान कर सैनिकों का सम्मान।

आरबीआई समाचार

विनियामक प्राधिकरणों से संबंधित करंट अफेयर्स

क्र.सं.	नाम	उद्देश्य / पहल
1	आरबीआई	नकदी संकट परीक्षण (Liquidity Stress Testing) रूपरेखा को मजबूत किया; NBFCs, सहकारी बैंकों, जलवायु जोखिमों को शामिल किया गया।
2	भारतीय रिज़र्व बैंक	FY26 में मुद्रास्फीति लक्ष्य ढांचे की समीक्षा करेगा; तरलता प्रबंधन पर पुनर्विचार करेगा; कोर मुद्रास्फीति पर जोर।
3	भारतीय रिज़र्व बैंक	PayPal और Worldline को क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में सैद्धांतिक मंजूरी दी; फ्रीलांसरों, MSMEs को लाभ।
4	भारतीय रिज़र्व बैंक	₹2000 नोटों की 98.26% वापसी पूरी; स्वच्छ नोट नीति के तहत निष्कासन की दिशा में अहम कदम।
5	भारतीय रिज़र्व बैंक	FY 2024-25 में ₹54.78 करोड़ के 353 दंड लगाए; सबसे अधिक दंड सहकारी बैंकों पर; साइबर सुरक्षा, KYC, फ्रॉड रिपोर्टिंग उल्लंघनों पर कार्रवाई।
6	भारतीय रिज़र्व बैंक	1 अप्रैल 2026 से प्रभावी नए सोना ऋण मानदंड; ₹2.5 लाख तक के ऋण के लिए LTV 85%; पारदर्शिता व उधारकर्ता सुरक्षा बढ़ेगी।
7	भारतीय रिज़र्व बैंक	हिंदी में अर्थव्यवस्था, बैंकिंग व वित्त विषयों पर मूल पुस्तक लेखन को प्रोत्साहन योजना शुरू; मान्यता और पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
8	भारतीय रिज़र्व बैंक	NBFCs को ₹5 लाख से कम ऋणों के लिए LTV 85% तक बढ़ाया गया; बुलेट पुनर्भुगतान ऋणों में चक्रवृद्धि व्याज शामिल किया जाएगा।





विनियामक प्राधिकरणों से संबंधित करेंट अफेयर्स

क्र.सं.	नाम	उद्देश्य / पहल
9	आरबीआई	• ₹30,000 करोड़ सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी; ₹5,000 करोड़ के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड शामिल; ई-क्यूबर मंच के माध्यम से।
10	भारतीय रिज़र्व बैंक	• परियोजना वित्त पर प्रावधान दर 5% से घटाकर 1% की गई; अचल संपत्ति और हाउसिंग ऋण को छूट; प्रभाव: ऋण सुलभता में वृद्धि।
11	भारतीय रिज़र्व बैंक	• FY 2025-26 से स्मॉल फाइनेंस बैंकों के PSL लक्ष्य 75% से घटाकर 60% किया गया; 40% अभी भी अनिवार्य उपक्षेत्रों में।
12	भारतीय रिज़र्व बैंक	• Q4 FY25 में ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स (HPI) में 3.1% वार्षिक वृद्धि दर्ज; कोलकाता में सर्वाधिक 8.8% बढ़ोतरी।
13	भारतीय रिज़र्व बैंक	• फिनो पेमेंट्स बैंक पर ₹29.6 लाख का जुर्माना; ग्राहकों के खातों में संतुलन सीमा उल्लंघन का मामला।
14	भारतीय रिज़र्व बैंक	• कॉल मनी मार्केट समय सीमा को 7 बजे तक बढ़ाया; अगस्त 1 से ट्राई-पार्टी और मार्केट रेपो 4 बजे तक खुले रहेंगे; संचालन में लचीलापन बढ़ेगा।

सेबी समाचार

क्र.सं.	घोषणा	मुख्य विवरण
1	SEBI ने अल्टो ट्रेडिंग उल्लंघनों के लिए सेटलमेंट योजना शुरू की	जून 16 से सितंबर 16, 2025 तक चालू योजना; ज़ेरोधा और 5Paisa जैसे 100+ ब्रोकर्स पर अनियमित अल्टो प्लेटफॉर्म से मिलकर गारंटीड रिटर्न देने का आरोप; कम लागत पर सेटलमेंट का अवसर।
2	सभी KYC एजेंसियों को मान्यता एजेंसी बनने का प्रस्ताव	वर्तमान में केवल CDSL और NSDL की सहायक एजेंसियाँ ही मान्यता एजेंसियाँ हैं; प्रस्ताव से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लागत घटेगी; निवेशकों की अस्थायी ऑनबोर्डिंग की अनुमति की सिफारिश भी शामिल।
3	निवेशकों को सलाहकारों को भुगतान के लिए CeFCoM प्लेटफॉर्म के उपयोग की सलाह	भुगतान पारदर्शिता व सुरक्षा बढ़ाने हेतु SEBI द्वारा प्रोत्साहन; ₹5 करोड़ से अधिक भुगतान पहले ही CeFCoM से हो चुके हैं; 1 अक्टूबर 2025 से SEBI Check टूल और प्रमाणित UPI हैंडल शुरू होंगे।
4	पंजीकृत बिचौलियों के लिए प्रमाणित UPI हैंडल अनिवार्य	1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी; "@valid" उपसर्ग अनिवार्य; जैसे abc.bkr@validhdfc; SEBI Check ऐप से UPI हैंडल की वैधता की पुष्टि संभव; पुराने UPI IDs दिसंबर 2026 से निष्क्रिय।
5	ESG ऋण प्रतिभूतियों के लिए संचालन दिशानिर्देश जारी	सामाजिक, स्थिरता और सतत विकास से जुड़े बॉन्ड्स के लिए दिशा-निर्देश; परियोजनाओं की पारदर्शिता, फंड वितरण, और तीसरे पक्ष की समीक्षा अनिवार्य; 5 जून 2025 से लागू।
6	निवेशकों की सुरक्षा हेतु 'SEBI Check' टूल शुरू	1 अक्टूबर 2025 से लागू; UPI हैंडल और बैंक खाते की वैधता की जांच के लिए टूल; QR कोड स्कैन या मैन्युअल एंट्री से जानकारी सत्यापित की जा सकेगी; केवल NPCI से अनुमोदित वैध भुगतान ID की अनुमति।
7	BSE लिमिटेड पर ₹25 लाख का जुर्माना	SEBI द्वारा कई नियामकीय उल्लंघनों पर दंड लगाया गया; BSE के सिस्टम में घोषणाओं की पूर्व-प्राप्ति और ब्रोकर्स की निगरानी में ढिलाई पाई गई; 45 दिनों में भुगतान का आदेश।

बैंकिंग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स

- निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) और सेबी ने 1 जून, 2025 को पुणे में पहला निवेशक शिविर शुरू किया, जिसका उद्देश्य निवेशकों को बिना दावे वाले लाभान्ध और शेयर वापस पाने, केवाईसी और नामांकन को अपडेट करने और आईईपीएफ दावा प्रक्रिया के बारे में जानने में मदद करना था। 450 से अधिक प्रतिभागियों को व्यक्तिगत सहायता से लाभ हुआ, जिसमें खोज सुविधा, फॉर्म भरने में सहायता और सामान्य त्रुटियों के बारे में जागरूकता शामिल है। निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए एक विशेष एनएसडीएल ब्रोशर भी जारी किया गया। यह पहल पारदर्शी, निवेशक-केंद्रित शासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके बाद शहर भर में और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- एसबीआई आर्थिक अनुसंधान रिपोर्ट में वित्त वर्ष 25 में घरेलू शुद्ध वित्तीय बचत में ₹22 लाख करोड़ की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जो जीएनडीआई का 6.5% है - जो आर्थिक मजबूती का संकेत है। इसमें आरबीआई के ₹2.69 लाख करोड़ के रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण और धोखाधड़ी की बढ़ती मात्रा जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत की वित्तीय प्रणाली की लचीलापन पर भी प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट मजबूत वित्तीय बुनियादी बातों और बचत, शासन और संस्थागत दक्षता में परिवर्तनकारी बदलावों की तस्वीर पेश करती है।
- RBI के आंकड़ों के अनुसार, मई 2025 में भारत में क्रेडिट कार्ड खर्च में साल-दर-साल 14.5% की वृद्धि हुई, जो ₹1.89 ट्रिलियन तक पहुँच गया। यह वृद्धि 760,000 नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से प्रेरित थी, जिसमें HDFC बैंक और SBI कार्ड्स सबसे आगे थे। प्रचलन में कार्डों की कुल संख्या बढ़कर 111.19 मिलियन हो गई, जो उपभोक्ताओं के बढ़ते विश्वास, डिजिटल भुगतान की ओर बढ़ते रुझान और खुदरा ऋण पैठ में वृद्धि को दर्शाता है। यह प्रवृत्ति देश की डिजिटल खपत अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में निजी बैंकों की भूमिका को पुष्ट करती है।





बैंकिंग करंट अफेयर्स: मई 2025

क्रम संख्या	बैंक का नाम	उद्देश्य / पहल का संक्षिप्त विवरण
1	भारतीय स्टेट बैंक (SBI)	FY25 की चौथी तिमाही में 10% मुनाफे में गिरावट; पूरे वर्ष का शुद्ध लाभ ₹70,901 करोड़; ₹25,000 करोड़ का इक्विटी जुटाने की योजना।
2	भारतीय स्टेट बैंक (SBI)	'Next LEAP' और 'SuPer SBI' जैसी पहल के तहत 2.3 लाख कर्मचारियों के कौशल उन्नयन का सबसे बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया।
3	कोटक महिंद्रा बैंक	कोटक सॉल्यूटिज क्रेडिट कार्ड लॉन्च — प्रीमियम, निमंत्रण-आधारित यात्रा कार्ड; ₹25,000 वार्षिक शुल्क, 10 एयरमाइल्स/₹100।
4	केनरा बैंक एवं यूनियन बैंक	'Canara TruEdge' और 'Union Wellness Deposit' जैसी विशेष जमा योजनाएं शुरू कीं; उच्च-मूल्य ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास।
5	केनरा बैंक	FY25 की चौथी तिमाही में 33.19% लाभ वृद्धि; सकल और शुद्ध NPA में गिरावट; ₹4 प्रति शेयर लाभांश की सिफारिश।
6	पंजाब नेशनल बैंक	ISARC में अपनी पूरी हिस्सेदारी ₹34.04 करोड़ में बेची; मुख्य बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति।
7	एयरटेल पेमेंट्स बैंक	RuPay-संचालित NCMC डेबिट व प्रीपेड कार्ड लॉन्च; "One Nation, One Card" मिशन को समर्थन।
8	भारतीय स्टेट बैंक (SBI)	LPAI के साथ MoU पर हस्ताक्षर; 26 जमीनी बंदरगाहों पर बैंकिंग सेवाओं को बेहतर करने की योजना।
9	इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB)	श्रमिकों की भलाई के लिए प्रतिबद्धता; मजदूर दिवस (1 मई) के अवसर पर विशेष पहल।
10	बैंक ऑफ इंडिया	Sa-Dhan के साथ समझौता ज्ञापन; सूक्ष्म और महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को वित्तीय सहायता।
11	कतार नेशनल बैंक (QNB)	GIFT सिटी में शाखा खोलने वाला MEA क्षेत्र का पहला बैंक; भारतीय कंपनियों को वैश्विक बैंकिंग सहायता प्रदान करेगा।
12	केनरा बैंक एवं यूनियन बैंक	धीमी जमा वृद्धि के बीच संसाधन जुटाने हेतु विशेष जमा योजनाएं शुरू कीं; FY25 में जमा वृद्धि घटकर 10.3%।
13	HDFC बैंक	नए Biz+ करेंट अकाउंट लॉन्च; व्यवसायों के लिए एकीकृत बैंकिंग सेवाएं।
14	एसबीएम बैंक इंडिया	ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंकाशोरेंस साझेदारी।
15	एक्सिस बैंक	फ्लिपकार्ट समूह के super.money UPI प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी; शून्य वार्षिक शुल्क वाला RuPay क्रेडिट कार्ड लॉन्च।
16	इंडसइंड बैंक	AIC STPINEXT के साथ समझौता; स्टार्टअप्स व MSMEs को बैंकिंग, वेतन और मार्गदर्शन सेवाएं।
17	केनरा बैंक	संस्थागत ग्राहकों के लिए "CANARA TruEdge" करेंट और सेविंग्स अकाउंट सूट लॉन्च; कोई न्यूनतम जमा आवश्यक नहीं।
18	इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक	आदित्य बिड़ला कैपिटल के साथ रणनीतिक साझेदारी; भारत के दूर-दराज क्षेत्रों में ऋण उत्पादों की पहुँच को बढ़ाना।

आरबीआई समाचार

आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2024-25: भारत के केंद्रीय बैंकिंग परिदृश्य का व्यापक अवलोकन

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने RBI अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। यह व्यापक दस्तावेज़ भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति, RBI के वित्तीय प्रदर्शन, बैंकिंग और डिजिटल भुगतान में प्रमुख रुझानों और आने वाले वर्ष के लिए इसकी नीति योजनाओं को रेखांकित करता है। यह आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने, डिजिटल परिवर्तन को प्रोत्साहित करने और तेजी से अस्थिर वैश्विक वातावरण में जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए केंद्रीय बैंक के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।

1. RBI का वित्तीय प्रदर्शन और बैलेंस शीट

- बैलेंस शीट: ₹76.25 लाख करोड़ (31 मार्च 2025 तक), पिछले वर्ष ₹70.47 लाख करोड़ → 8.21% वृद्धि।





- संपत्तियाँ:
 - सोने के भंडार में **52.09%** वृद्धि।
 - घरेलू निवेश में **14.32%** वृद्धि।
 - विदेशी निवेश में **1.70%** वृद्धि।
- देयताएँ: मुद्रा प्रवाह, पुनर्मूल्यांकन खाते, और बाज़ार संचालन में वृद्धि से बड़ोतरी।
- आय और व्यय:
 - कुल आय: **₹3.38** लाख करोड़ (**22.77%** वृद्धि)।
 - व्यय: **₹69,714** करोड़ (**7.76%** वृद्धि)।
 - सरप्लस ट्रांसफर केंद्र सरकार को: **₹2.69** लाख करोड़ (रिकॉर्ड स्तर)।
 - आपात स्थितियों के लिए **₹44,861** करोड़ का कंटीजेंसी फंड में योगदान।

2. मुद्रा प्रवाह और डिजिटल भुगतान की ओर झुकाव

- नकदी चलन:
 - मुद्रा-से-GDP अनुपात घटकर **11.2%**।
 - फिर भी मुद्रा प्रवाह **5.8%** बढ़ा — ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बनी रही।
 - **₹500** नोट सबसे अधिक प्रचलित।
- डिजिटल भुगतान:
 - खुदरा डिजिटल भुगतान में मूल्य में **17.9%** और वॉल्यूम में **35%** वृद्धि।
 - डिजिटल रुपया (CBDC) का मूल्य **334%** बढ़कर **₹1,016.5** करोड़ हुआ।

3. विदेशी निवेश और कॉरपोरेट बॉन्ड बाज़ार

- कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI): **₹1.21** लाख करोड़ (**11.4%** वृद्धि)।
- उपयोग की गई सीमा घटकर **15.8%** (**16.2%** से) — निवेश सीमा बढ़ने के कारण।

4. मुद्रा छपाई और नकली नोट

- **₹6,373** करोड़ खर्च किए गए नोट छपाई पर (**25%** की वृद्धि)।
- नकली नोटों में वृद्धि:
 - **₹500** नोट: **37.3%** वृद्धि।
 - **₹200** नोट: **13.9%** वृद्धि।
 - अन्य मूल्यवर्गों में गिरावट।

5. आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति पर दृष्टिकोण

- FY26 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि अनुमान: **6.5%**।
 - उपभोक्ता खर्च, सरकारी पूंजीगत व्यय और सेवा क्षेत्र से समर्थन।
- मुद्रास्फीति लक्ष्य: **4%**।
 - सामान्य मानसून, खाद्य आपूर्ति और वैश्विक तेल कीमतें महत्वपूर्ण।
 - जोखिम: जलवायु परिवर्तन, भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक व्यापार बाधाएँ।

6. साइबर सुरक्षा और डिजिटल बैंकिंग सुधार

- 'bank.in' डोमेन प्रस्तावित – प्रमाणित बैंकिंग वेबसाइट्स के लिए।
- UPI में नए नवाचार:
 - **UPI सर्कल**: भरोसेमंद लोगों को भुगतान की अनुमति।
 - छोटे वित्त बैंकों को **UPI** के माध्यम से प्री-अपूव्ड क्रेडिट लाइन की सुविधा।
 - अंतरराष्ट्रीय **UPI** कनेक्शन पर कार्य प्रगति पर।

7. स्वर्ण भंडार और विनिमय दर प्रबंधन

- स्वर्ण भंडार में **54.13** टन की वृद्धि।
- कुल मूल्य **₹4.32** लाख करोड़ (**57.12%** वृद्धि)।
- कारण: नई खरीद, वैश्विक सोने की कीमतों में वृद्धि, रुपए का अवमूल्यन।

SALE IS LIVE



Test Prime

**ALL EXAMS,
ONE SUBSCRIPTION.**











8. बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति और धोखाधड़ी

- धोखाधड़ी के मामले घटे, लेकिन कुल मूल्य ₹36,014 करोड़ (तीन गुना वृद्धि)।
 - पुराने मामलों की रिपोर्टिंग: ₹18,000 करोड़ से अधिक के 122 मामले।
- शहरी सहकारी बैंक (UCBs):
 - ऋण वृद्धि, पूंजी सुदृढ़ता और NPA में सुधार।
 - जोखिम आधारित पर्यवेक्षण और सुधारात्मक कार्रवाई ढाँचे का विस्तार।

9. घरेलू बचत और पूंजी बाज़ार गतिविधियाँ

- ग्रांस वित्तीय बचत: आय का 11.2% (पिछले वर्ष 10.7%)।
- नेट बचत: 5.1%।
- स्टॉक मार्केट:
 - QIPs और प्रेफरेंशियल शेयर: ₹2.2 लाख करोड़।
 - IPOs/FPOs: ₹2.1 लाख करोड़।

10. वैश्विक व्यापार में INR को बढ़ावा देना

- NRI और विदेशी नागरिक अब INR खाते विदेशों में रख सकते हैं।
- RBI ने स्थानीय मुद्रा समझौतों (LCS) पर हस्ताक्षर किए:
 - यूएई, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरीशस।
- FX-Retail प्लेटफॉर्म को NPCI के Bharat Connect से जोड़ने की योजना।

11. भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार दृष्टिकोण

- वैश्विक चुनौतियाँ: भू-राजनीतिक तनाव, संरक्षणवादी नीतियाँ।
- भारत की रणनीतियाँ:
 - 14 मुक्त व्यापार समझौते (FTAs), 6 वरीयता व्यापार समझौते (PTAs)।
 - अमेरिका, EU, ओमान, पेरू के साथ समझौते प्रक्रिया में।

त्वरित तथ्य: RBI एक दृष्टि में

- स्थापना: 1 अप्रैल 1935
- कानूनी प्राधिकरण: RBI अधिनियम, 1934
- गवर्नर (2025): संजय मल्होत्रा
- मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र

विनियामक प्राधिकरणों से संबंधित समसामयिक मामले

क्रमांक	नाम	उद्देश्य
1	RBI	• RBI ने SBI पर ₹1.72 करोड़ और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया। कारण: ऋण प्रतिबंधों, ई-धोखाधड़ी में ग्राहक उत्तरदायित्व और खाता खोलने के नियमों का उल्लंघन। यह कार्रवाई अनुपालन की कमी के कारण की गई, लेन-देन की वैधता पर सवाल नहीं।
2	RBI	• गवर्नर संजय मल्होत्रा ने FY26 के लिए सकारात्मक मुद्रास्फीति दृष्टिकोण व्यक्त किया। अप्रैल 2025 की मौद्रिक नीति बैठक में रेपो दर 6% कर दी गई और सहायक नीति रख अपनाया गया। उद्देश्य: आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना।
3	RBI	• डिजिटल लेंडिंग दिशा-निर्देश 2025 के तहत सभी विनियमित संस्थाओं को 13 मई से 15 जून 2025 तक CIMS पोर्टल पर अपने डिजिटल ऋण ऐप्स (DLA) रिपोर्ट करने होंगे। 1 जुलाई तक सार्वजनिक डायरेक्टरी जारी होगी। उद्देश्य: पारदर्शिता, उपभोक्ता संरक्षण, और अनुशासन।
4	RBI	• RBI जल्द ही ₹20 के नए नोट जारी करेगा, जिसमें गवर्नर संजय मल्होत्रा का हस्ताक्षर होगा। डिज़ाइन, रंग, और फीचर्स में कोई बदलाव नहीं होगा। पुराने नोट वैध रहेंगे।
5	RBI	• HCBL को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द। कारण: पूंजी और आय के मानकों को पूरा न करना। 98% जमाकर्ता DICGC के तहत ₹5 लाख तक बीमित। उद्देश्य: जमाकर्ता सुरक्षा और बैंकिंग अनुशासन।
6	RBI	• FY2024-25 में RBI ने ₹87.95 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचे रुपये की रक्षा के लिए \$398.71 अरब विदेशी मुद्रा बेची। कारण: वैश्विक अनिश्चितता, ट्रंप की वापसी की आशंका और व्यापार संरक्षणवाद। इस हस्तक्षेप से विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आई।





विनियामक प्राधिकरणों से संबंधित समसामयिक मामले

क्रमांक	नाम	उद्देश्य
7	RBI	● पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड (PRB) की स्थापना की गई। इसमें RBI अधिकारियों और सरकारी नामांकनों सहित 6 सदस्य शामिल हैं। उद्देश्य: भुगतान प्रणाली में सुरक्षा, नवाचार और सहयोग बढ़ाना।
8	RBI	● RBI ने FY2024-25 के लिए ₹2.68 लाख करोड़ का रिकॉर्ड अधिशेष सरकार को ट्रांसफर किया। यह निर्णय मजबूत वित्तीय स्थिति और CRB को 7.5% तक बढ़ाने के बाद लिया गया। इससे राजकोषीय घाटा घटेगा और सरकार को आर्थिक सहयोग मिलेगा।

सेबी समाचार

क्रमांक	घोषणा	मुख्य विवरण
1	खुदरा F&O ट्रेडर्स के लिए एप्टीक्यूड टेस्ट से इनकार	सेबी प्रमुख तुहिन कांता पांडे ने खुदरा निवेशकों के लिए F&O ट्रेडिंग से पहले एप्टीक्यूड टेस्ट की संभावना को खारिज किया। पर्याप्त मौजूदा जांच प्रणाली, व्यक्ति की वित्तीय स्वतंत्रता और जोखिम प्रबंधन उपायों को प्रमुख कारण बताया गया।
2	₹1 करोड़ न्यूनतम निवेश व डिमैट आवश्यक (SDIs)	सेबी ने सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रुमेंट्स (SDIs) के लिए ₹1 करोड़ का न्यूनतम निवेश अनिवार्य किया। यह नियम RBI-नियंत्रित और गैर-नियंत्रित संस्थाओं दोनों पर लागू होगा। सार्वजनिक प्रस्तावों के लिए समय सीमा और जोखिम प्रतिधारण की आवश्यकताएं भी जोड़ी गईं।
3	MII निदेशकों के लिए 'कूलिंग ऑफ पीरियड'	सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी जैसे बाजार अवसंरचना संस्थानों (MIIs) में निदेशकों के प्रतिस्पर्धी संस्थानों में नियुक्ति से पहले अनिवार्य 'कूलिंग ऑफ पीरियड' लागू किया। उद्देश्य: संस्थागत पारदर्शिता और अखंडता बढ़ाना।
4	MII के लिए आंतरिक ऑडिट मानकों को मजबूत किया	सेबी ने MIIs के लिए आंतरिक ऑडिट प्रणाली को मानकीकृत किया। MDs को ऑडिट समितियों का हिस्सा बनने से रोका गया। आंतरिक ऑडिटर को केवल ऑडिट समिति को रिपोर्ट देना होगा और वर्ष में दो बार महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी देनी होगी।
5	18 जून को सेबी बोर्ड बैठक	सेबी बोर्ड 18 जून को "Ease of Doing Business" पर आधारित नए सुधारों को मंजूरी देगा। QIP, REITs, InvITs, AIFs और FPI से जुड़ी नियमों में सरलीकरण और लचीलापन लाया जाएगा।
6	JioBlackRock को म्युचुअल फंड संचालन की अनुमति	सेबी ने Jio Financial Services और BlackRock की संयुक्त कंपनी JioBlackRock Asset Management को म्युचुअल फंड संचालन की मंजूरी दी। यह कदम भारत में खुदरा निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
7	संरचित उत्पादों व MLDs के लिए F&O सीमा में ढील की संभावना	सेबी संभावित रूप से संरचित उत्पादों और मार्केट-लिंक्ड डिबेंचर्स (MLDs) पर F&O स्थिति सीमाओं में छूट दे सकता है। उद्योग की मांग पर विचार करते हुए SEBI मौजूदा और प्रस्तावित सीमाओं को संशोधित कर सकता है, जबकि निगरानी को सख्त किया जाएगा।

बैंकिंग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक मामले

- RBI के आंकड़ों के अनुसार, FY25 में, HSBC और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे विदेशी बैंक नेट क्रेडिट कार्ड जोड़ने में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले के रूप में उभरे। HSBC ने 216,997 कार्ड जोड़े, जबकि Amex ने 107,086 जोड़े, जिससे पिछली गिरावट पलट गई और भारत के बढ़ते डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाया। समग्र बैंकिंग उद्योग ने 8 मिलियन से अधिक कार्ड जोड़े, जो उपभोक्ता ऋण मांग में वृद्धि और भारत में विदेशी खिलाड़ियों की खुदरा बैंकिंग महत्वाकांक्षाओं के पुनरुद्धार को रेखांकित करता है।
- मॉर्निंगस्टार डीबीआरएस ने 9 मई, 2025 को भारत की सॉवरैन क्रेडिट प्रोफाइल को उल्लेखनीय बढ़ावा दिया, जिसमें दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों रेटिंग को अपग्रेड किया गया। यह भारत के संरचनात्मक सुधारों, डिजिटल परिवर्तन और राजकोषीय समेकन के माध्यम से सफल नेविगेशन को दर्शाता है, जबकि यह सब उच्च विकास और व्यापक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखता है। रिपोर्ट यह भी सुझाव देती है कि आगे के सुधारों और कम कर्ज के साथ, भारत की रेटिंग और भी अधिक बढ़ सकती है।
- वित्त वर्ष 2025 में, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) ने ₹1.78 लाख करोड़ का रिकॉर्ड संचयी लाभ हासिल किया, जिसका मुख्य कारण भारतीय स्टेट बैंक (SBI) था, जिसने अकेले ही कुल लाभ में 40% से अधिक का योगदान दिया। वित्त वर्ष 2024 की तुलना में 26% की लाभ वृद्धि सरकार की 4R सुधार रणनीति की सफलता को रेखांकित करती है- NPA की पहचान, समाधान, पुनर्पूजीकरण और सुधार। वित्त वर्ष 18 में ₹85,390 करोड़ के नुकसान से लेकर वर्तमान ऐतिहासिक लाभ तक का यह वित्तीय बदलाव, पुनर्पूजीकरण, बैंक विलय और ऋण अनुशासन और प्रौद्योगिकी अपनाने पर जोर सहित नीतिगत परिवर्तनों के प्रभाव को उजागर करता है।





बैंकिंग करंट अफेयर्स: अप्रैल 2025

क्रम संख्या	बैंक का नाम	उद्देश्य / पहल का विवरण
1.	एक्सिस बैंक	जे.पी. मॉर्गन और उसकी ब्लॉकचेन यूनिट किनेक्सिस के साथ साझेदारी में, GIFT सिटी से भारत की पहली 24x7 यूएस डॉलर भुगतान सेवा वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए शुरू की। यह रीयल-टाइम डॉलर क्लियरिंग सुविधा तरलता प्रबंधन को बेहतर बनाती है, लागत कम करती है, और मध्य पूर्व देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देती है।
2.	बंधन बैंक	अप्रैल 2025 में "एलीट प्लस सेविंग्स अकाउंट" शुरू किया गया, जो उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों (HNIs) के लिए है। इसमें असीमित नकद जमा और विस्तारित बीमा कवरेज जैसी सुविधाएँ हैं।
3.	एसबीआई कार्ड	टाटा डिजिटल के साथ साझेदारी में "टाटा न्यू एसबीआई कार्ड" लॉन्च किया - दो संस्करण: टाटा न्यू प्लस और टाटा न्यू इनफिनिटी। दोनों कार्ड पर टाटा न्यू और सहयोगी ब्रांडों पर खर्च पर 10% तक इनाम (न्यूकॉइन्स), लाउज एक्सेस, सालाना शुल्क में छूट और बिल भुगतान पर कैशबैक जैसी सुविधाएँ हैं।
4.	भारतीय स्टेट बैंक (SBI)	15 अप्रैल 2025 से "अमृत वृष्टि एफडी योजना" फिर से शुरू की गई। वरिष्ठ नागरिकों को 7.55%, अति-वरिष्ठ नागरिकों को 7.65% और आम नागरिकों को 7.05% ब्याज दर मिलती है (444 दिनों की अवधि के लिए)। यह योजना बुजुर्गों के लिए सुरक्षित और उच्च-रिटर्न निवेश विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से है।
5.	पंजाब नेशनल बैंक (PNB)	12 अप्रैल 2025 को 131वें स्थापना दिवस पर 34 नए उत्पाद/सेवाएँ लॉन्च की गईं। इनमें महिलाओं, किसानों, एनआरआई और पेंशनरों के लिए 12 जमा योजनाएँ, 10 डिजिटल टूल (जैसे AI सहायक "पिहू", QR आधारित फीडबैक सिस्टम) और "साइबर रन" हाफ मैराथन जैसी पहलें शामिल हैं।
6.	भारतीय स्टेट बैंक (SBI)	शाखाओं पर प्रशिक्षित 'ग्राहक मित्रों' की नियुक्ति की गई, जो डिजिटल बैंकिंग और सेल्फ-सर्विस प्लेटफॉर्मों में ग्राहकों की सहायता करते हैं। उद्देश्य शाखाओं की भीड़ कम करना और वैकल्पिक बैंकिंग चैनलों को बढ़ावा देना है।

आरबीआई समाचार

विनियामक प्राधिकरणों से संबंधित करंट अफेयर्स		
क्रम संख्या	संस्था का नाम	उद्देश्य / पहल का विवरण
1.	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• वर्ष 2025 में RBI ने अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाई। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। प्रमुख मील के पत्थर: 1991 में आर्थिक उदारीकरण, और हाल की डिजिटल भुगतान व वित्तीय समावेशन में प्रगति।
2.	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• 2 अप्रैल 2025 को RBI ने बताया कि ₹2000 के 98.21% नोट बैंकिंग प्रणाली में लौटाए जा चुके हैं। यह नोट 2016 में विमोचन के बाद जारी हुए थे, और 2023 में RBI ने इन्हें चलन से हटाने की घोषणा की थी।
3.	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• 1 अप्रैल 2025 से, 500 शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को SAF से PCA फ्रेमवर्क में लाया जाएगा। यह कदम समय पर हस्तक्षेप और वित्तीय स्थिरता की बहाली के उद्देश्य से है।
4.	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• RBI ने सरकारी गारंटीशुदा सिक्क्योरिटी रिसीट्स (SRs) के लिए नई दिशा-निर्देश जारी किए, जिससे खराब ऋणों के समाधान और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। इसमें पूंजी उपचार और वेल्यूरेशन पद्धति में बदलाव शामिल हैं।
5.	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• 1 मई 2025 से एटीएम से मुफ्त सीमा से अधिक निकासी पर शुल्क ₹21 से बढ़ाकर ₹23 किया गया है। यह नियम नकद पुनर्चक्रण मशीनों पर भी लागू होगा (नकद जमा को छोड़कर)। उद्देश्य: एटीएम रखरखाव लागत की भरपाई।
6.	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) की सीमाएँ यथावत रहेंगी: केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों के लिए 6%, राज्य विकास ऋणों के लिए 2% और कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए 15%। उद्देश्य: स्थिर निवेश वातावरण बनाए रखना।
7.	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• NPCI को UPI P2M लेनदेन की सीमा बढ़ाने की अनुमति दी गई है (शिक्षा, स्वास्थ्य, क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसे क्षेत्रों में ₹2-5 लाख तक)। P2P सीमा ₹1 लाख यथावत है। यह कदम डिजिटल नवाचार को प्रोत्साहित करता है।
8.	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• 'RBI कहता है' अभियान के तहत RBI ने अपना ऑफिशियल WhatsApp चैनल लॉन्च किया है, जिससे वित्तीय साक्षरता, डिजिटल सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकथाम को बढ़ावा मिलेगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच सुनिश्चित करता है।
9.	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• अजन्ता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, औरंगाबाद का लाइसेंस 22 अप्रैल 2025 से रद्द किया गया, पूंजी की कमी और जमा धन की सुरक्षा में विफलता के कारण। 91.55% जमाकर्ताओं को DICGC योजना के तहत ₹5 लाख तक का बीमा मिलेगा।
10.	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• सभी बैंकों को 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी वेबसाइट का डोमेन '.bank.in' पर स्थानांतरित करना अनिवार्य किया गया है। उद्देश्य: साइबर सुरक्षा बढ़ाना और धोखाधड़ी को रोकना। IDRBT को एकमात्र रजिस्ट्रार बनाया गया है।
11.	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	• अब 10 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चे स्वतंत्र रूप से बचत खाता और सावधि जमा खाता खोल सकते हैं। यह वित्तीय साक्षरता को प्रारंभिक स्तर से प्रोत्साहित करने के लिए है। बैंकों को जोखिम नीति के आधार पर अनुमति देनी होगी।





सेबी समाचार

क्रम संख्या	घोषणा	मुख्य विवरण
1.	सेबी (SEBI)	ओवरनाइट और लिक्विड म्यूचुअल फंड योजनाओं में रिडेम्प्शन की कट-ऑफ टाइमिंग संशोधित की गई है, जो 1 जून 2025 से लागू होगी। यह Upstreaming Framework (दिसंबर 2023) के तहत लागू किया गया है ताकि निवेशकों के फंड की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ऑफलाइन मोड के लिए कट-ऑफ समय दोपहर 3:00 बजे है, जबकि ऑनलाइन मोड (केवल ओवरनाइट फंड्स) के लिए इसे शाम 7:00 बजे तक बढ़ाया गया है ताकि उसी दिन का NAV प्राप्त किया जा सके। यह कदम AMFI और सेबी की म्यूचुअल फंड सलाहकार समिति के समर्थन से उठाया गया है। इसका उद्देश्य कोलेटरल के बेहतर उपयोग और निवेशकों के फंड की सुरक्षा को मजबूत करना है।

अर्थव्यवस्था/व्यापार करंट अफेयर्स

अर्थव्यवस्था/व्यापार करंट अफेयर्स: सितम्बर 2025

अर्थव्यवस्था समाचार

- बीमा क्षेत्र सुधार: सरकार ने वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने, पूंजी पर्याप्तता को बढ़ावा देने और IRDAI की निगरानी में प्रवेश के लिए स्वचालित मार्ग (74% सीमा के स्थान पर) के माध्यम से बीमा में 100% एफडीआई का प्रस्ताव रखा है।
- निजी पूंजीगत व्यय परिदृश्य: आरबीआई के अगस्त 2025 के बुलेटिन के अनुसार, निजी कॉर्पोरेट पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 26 में 21.5% बढ़कर ₹2.67 लाख करोड़ हो जाएगा, जिसका नेतृत्व बुनियादी ढांचा और बिजली क्षेत्र करेंगे, और कम ब्याज दरों और घटती मुद्रास्फीति से सहायता मिलेगी।
- आरबीआई गवर्नर का बयान: आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, उन्होंने वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 7.8% जीडीपी वृद्धि और 55 करोड़ जन धन खातों का हवाला दिया।
- भारत का जीएसटी संग्रह: अगस्त 2025 में जीएसटी राजस्व ₹1.86 ट्रिलियन तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.5% अधिक है; जीएसटी परिषद सुधारों पर चर्चा करेगी।
- चालू खाता घाटा (सीएडी): भारत का सीएडी वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में घटकर 2.4 बिलियन डॉलर (जीडीपी का 0.2%) रह गया, जो वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में 0.9% था, जिसे उच्च सेवा प्रामियों और प्रेषणों में 18% की वृद्धि से सहायता मिली।
- जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान: मॉर्गन स्टेनली ने मजबूत Q1 विकास और जीएसटी कटौती का हवाला देते हुए भारत के वित्त वर्ष 26 के जीडीपी पूर्वानुमान को 6.7% (6.2% से) तक बढ़ा दिया।
- सेवा पीएमआई: भारत का सेवा पीएमआई अगस्त 2025 में 62.9 पर पहुँच गया, जो 15 वर्षों का उच्चतम स्तर है, हालाँकि इससे एक दशक में कीमतों में सबसे तेज़ वृद्धि हुई है।
- एफडीआई वृद्धि: वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में एफडीआई 15% बढ़कर 18.62 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, टैरिफ मुद्दों के बावजूद अमेरिकी निवेश तिगुना बढ़कर 5.61 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।
- आधार प्रमाणीकरण की उपलब्धि: यूआईडीआई ने अगस्त 2025 में 221 करोड़ लेनदेन दर्ज किए, जिनमें एआई-आधारित तकनीक का उपयोग करके 18.6 करोड़ चेहरे से प्रमाणीकरण शामिल हैं।
- यूपीआई लेनदेन सीमा में वृद्धि: एनपीसीआई ने पूंजी बाजार, बीमा और सरकारी क्षेत्रों में सत्यापित व्यापारियों के लिए यूपीआई सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख प्रति लेनदेन और ₹10 लाख प्रतिदिन कर दी (15 सितंबर से प्रभावी)।

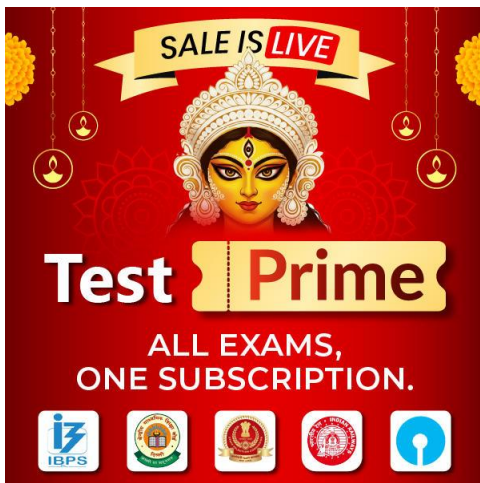
- जीडीपी में कृषि की भूमिका: प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने कहा कि कृषि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 15-20% का योगदान देती है, जो 60% कार्यबल का समर्थन करती है; राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य मिशन के शुभारंभ की घोषणा की।
- जीएसटी सुधार पर मूडीज: मूडीज ने चेतावनी दी है कि प्रस्तावित दो-स्लैब जीएसटी ढाँचे से सरकार को ₹48,000 करोड़ का राजस्व नुकसान हो सकता है, जबकि घरेलू खर्च में बढ़ोतरी होगी।
- खुदरा मुद्रास्फीति: अगस्त 2025 में बढ़कर 2.07% हो गई, जो अभी भी आरबीआई के लक्ष्य से कम है; खाद्य मुद्रास्फीति नकारात्मक रही।
- हर्षवर्धन चितले हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ नियुक्त: 5 जनवरी, 2026 को कार्यभार संभालेंगे; आईआईटी दिल्ली के स्वर्ण पदक विजेता, सिप्रिफाई, फिलिप्स और हनीवेल में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव।
- डेल की मुख्य वित्तीय अधिकारी यवोन मैकगिल का इस्तीफा: लगभग 30 वर्षों के बाद 9 सितंबर, 2025 को पद छोड़ेंगी; डेविड कैनेडी को अंतरिम मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया।
- इंटरनेट नेतृत्व में फेरबदल: सीईओ लिप-बू टैन की बदलाव रणनीति के बीच उत्पाद प्रमुख मिशेल जॉनसन होल्टहॉस 30 से अधिक वर्षों के बाद पद छोड़ेंगे।
- एनएचएआई के लिए बीमा जमानत बांड: ₹10,000 करोड़ का आंकड़ा पार किया; 12 बीमा कंपनियों ने ₹10,369 करोड़ मूल्य के 1,600 आईएसबी जारी किए, जो बैंक गारंटी के लिए लागत-प्रभावी विकल्प प्रदान करते हैं।
- आईईपीएफ स्थापना दिवस: निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण ने अपने 9वें स्थापना दिवस पर दावा न की गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें सेबी, आरबीआई, पीएफआरडीए और आईआरडीआई के अधिकारी शामिल हुए।
- वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% (प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़) अनुमानित - एसएंडपी।
- भारत की थोक मूल्य सूचकांक (WPI) मुद्रास्फीति पिछले वर्ष के -0.58% की तुलना में 0.52% (अगस्त 2025) पर सकारात्मक हो गई, जिसका प्रमुख कारण खाद्य एवं विनिर्माण क्षेत्र रहा।
- भारत का व्यापार घाटा जुलाई के 27.35 अरब डॉलर से घटकर 26.49 अरब डॉलर (अगस्त 2025) हो गया; निर्यात 35.1 अरब डॉलर और आयात 61.59 अरब डॉलर रहा।
- बेरोजगारी दर घटकर 5.1% (अगस्त 2025) हो गई; पुरुषों की 5.0%, महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है।





व्यापार समाचार

- टाटा-मर्क साझेदारी: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने गुजरात के धोलेरा में आगामी 91,000 करोड़ रुपये की फैब सुविधा का समर्थन करते हुए भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी लाने के लिए मर्क के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- डीपीआईआईटी-आईसीआईसीआई साझेदारी: डीपीआईआईटी ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक स्टार्टअप एंजेलमेंट प्रोग्राम शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को एक्सेलेरेटर और मेंटरशिप प्रदान करेगा।
- सिटीबैंक नियुक्ति: कौस्तुभ कुलकर्णी को सिटीबैंक में एशिया-प्रशांत निवेश बैंकिंग का सह-प्रमुख नियुक्त किया गया, जो क्षेत्रीय विस्तार को दर्शाता है।
- हर्षवर्धन चितले हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ नियुक्त: 5 जनवरी, 2026 को कार्यभार संभालेंगे; आईआईटी दिल्ली के स्वर्ण पदक विजेता, सिग्निफाई, फिलिप्स और हनीवेल में 30+ वर्षों का अनुभव।
- डेल की मुख्य वित्तीय अधिकारी यवोन मैकगिल का इस्तीफा: लगभग 30 वर्षों के बाद 9 सितंबर, 2025 को पद छोड़ेंगी; डेविड कैनेडी को अंतरिम मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया।
- इंटेल नेतृत्व में फेरबदल: सीईओ लिप-बू टैन की बदलाव रणनीति के बीच उत्पाद प्रमुख मिशेल जॉनसन होल्टहॉस 30+ वर्षों के बाद पद छोड़ेंगे।
- एनएचएआई के लिए बीमा जमानत बांड: ₹10,000 करोड़ का आंकड़ा पार किया; 12 बीमा कंपनियों ने ₹10,369 करोड़ मूल्य के 1,600 आईएसबी जारी किए, जो बैंक गारंटी के लिए लागत-प्रभावी विकल्प प्रदान करते हैं।
- आईपीएफए स्थापना दिवस: निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण ने अपने 9वें स्थापना दिवस पर दावा न की गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें सेबी, आरबीआई, पीएफआरडीए और आईआरडीएआई के अधिकारी शामिल हुए।
- कोटक811 बैंकिंग ऐप डाउनलोड (वर्ष 2025 की पहली छमाही) में 250% वार्षिक वृद्धि और 2.6 करोड़ उपयोगकर्ताओं के साथ विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा।



- एसबीआई ने यस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी जापान की एसएमबीसी को ₹8,889 करोड़ में बेची।
- वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% (प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़) अनुमानित - एसएंडपी।
- अपोलो टायर्स ने टीम इंडिया के प्रमुख प्रायोजक (121 द्विपक्षीय मैच + 21 आईसीसी मैच) के रूप में बीसीसीआई से ₹579 करोड़ का सौदा हासिल किया।
- मित्रा x सौरव गांगुली ने दुर्गा पूजा के मौसम के लिए 'सौरग्य' एथनिक वियर ब्रांड लॉन्च किया।
- जापान के आरएंडआई ने मज़बूत घरेलू माँग और राजकोपीय अनुशासन का हवाला देते हुए भारत की क्रेडिट रेटिंग को बीबीबी+ तक अपग्रेड किया।

अर्थव्यवस्था/व्यापार करंट अफेयर्स: अगस्त 2025

अगस्त 2025 तक जीडीपी और विकास दर

- जुलाई 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह ₹1.96 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जो साल-दर-साल 7.5% की वृद्धि दर्शाता है। हालाँकि, शुद्ध वृद्धि दर घटकर केवल 1.7% रह गई, जिसका मुख्य कारण रिफंड में 117% की तीव्र वृद्धि है, जिससे घरेलू खपत की गति को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का पूर्वानुमान बढ़ाकर 2025 और 2026 दोनों के लिए 6.4 प्रतिशत कर दिया है। यह संशोधित अनुमान एक बार फिर भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करता है। यह नया अनुमान IMF की अप्रैल 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट से बेहतर है, जिसमें भारत की 2025 के लिए 6.2 प्रतिशत और 2026 के लिए 6.3 प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया था।
- भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और निवेशक भावना के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, जैक मा की एंटफिन, जो एंट ग्रुप की चीनी सहयोगी है, ने पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस से पूरी तरह से बाहर निकलने का फैसला किया है। इस कदम से इस प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी से सभी चीनी स्वामित्व समाप्त हो गए हैं, जो कंपनी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और संभावित रूप से इसके निवेशक आधार का विस्तार करेगा। एंटफिन ने अपनी पूरी 5.84% हिस्सेदारी—जो 3.73 करोड़ शेयरों के बराबर है—लगभग ₹3,803 करोड़ के बड़े सौदे में बेच दी।
- टाटा मोटर्स ने 30 जुलाई 2025 को ऐलान किया कि उसकी कार्यकारी समिति ने इटली की इवेको ग्रुप NV की 100% हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। यह पूरी तरह नकद सौदा करीब 3.8 अरब यूरो (लगभग ₹34,600 करोड़) का है, जो सभी जरूरी मंजूरीयों पर निर्भर करेगा। खास बात यह है कि यह डील इवेको के डिफेंस बिजनेस को शामिल नहीं करती, जिसे वह पहले ही अलग बेचने की तैयारी में है।
- भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात उद्योग लगातार बढ़ रहा है और वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून 2025) में साल-दर-साल 47% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) के अनुसार, निर्यात वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के 8.43 अरब डॉलर से बढ़कर 12.4 अरब डॉलर हो गया। यह प्रदर्शन वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती स्थिति को पुष्ट करता है, जिसमें मोबाइल फोन निर्यात अग्रणी भूमिका निभा रहा है।





- आरबीआई के पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के 95वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 26 में भारत के व्यापार संतुलन पर फिर से दबाव पड़ सकता है। निष्कर्षों के अनुसार, इसी अवधि में व्यापारिक आयात में 2.5% की वृद्धि का अनुमान है, जबकि निर्यात में केवल 1.2% की वृद्धि की उम्मीद है। यह बेमेल दर्शाता है कि भारत का व्यापार असंतुलन बढ़ सकता है, जिससे चालू खाता घाटा (सीएडी) जीडीपी के 0.8% के बराबर हो सकता है – जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है।
- वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले के बाद अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार तनाव का हवाला देते हुए 2025 और 2026 के लिए भारत के विकास के अनुमान को कम कर दिया है। हालांकि टैरिफ का आर्थिक प्रभाव अभी भी सामने आ रहा है, लेकिन कंपनी ने चेतावनी दी है कि नीतिगत अनिश्चितता टैरिफ से भी ज़्यादा विकास पर असर डाल सकती है।
- कंसल्टिंग फर्म डेलॉयट इंडिया ने कहा कि मजबूत घरेलू बुनियाद और बढ़ते वैश्विक अवसरों के साथ चालू वित्त वर्ष (2025-26) में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.4 से 6.7 प्रतिशत रह सकती है। हालांकि, इसने यह भी कहा कि भारत को अपने व्यापार जोखिम पर नजर रखनी चाहिए और वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं से उत्पन्न नतीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। डेलॉयट इंडिया के अनुसार, रणनीतिक व्यापार बातचीत आय, रोजगार, मार्केट एक्सेस और घरेलू मांग को बढ़ाने वाले शक्तिशाली फैक्टर्स के रूप में काम करेंगी।
- वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने 1 अगस्त 2025 को जारी अपनी नवीनतम “इंडिया कॉर्पोरेट क्रेडिट ट्रेंड्स रिपोर्ट” में वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.3% कर दिया है, जो पहले 6.4% अनुमानित था। एजेंसी ने बताया कि जहां उच्च स्तर का बुनियादी ढांचा निवेश प्रमुख क्षेत्रों में मांग को बढ़ावा देता रहेगा, वहीं वैश्विक व्यापार से जुड़ी चुनौतियाँ और शुल्क (टैरिफ) संबंधी जोखिम भारत की विकास गति पर दबाव डाल सकते हैं।
- भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते जुलाई 2025 में नए शिखर पर पहुँच गए। भारत से अमेरिका को निर्यात 19.94% की बढ़त के साथ 8.01 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जबकि अमेरिका से आयात भी 13.78% बढ़कर 4.55 अरब डॉलर रहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष (2025-26) की अप्रैल-जुलाई अवधि में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है।
- केंद्र सरकार ने जीएसटी (GST) को और सरल बनाने के लिए दो स्लैब की नई प्रणाली (5% और 18%) का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही तंबाकू और पान मसाला जैसे चुनिंदा विलास/हानिकारक उत्पादों (sin goods) पर 40% का विशेष कर लगाया जाएगा। यह प्रस्ताव नेक्स्ट-जेनरेशन जीएसटी सुधारों का हिस्सा है, जिस पर सितंबर या अक्टूबर 2025 में जीएसटी परिषद विचार कर सकती है। यदि मंजूरी मिलती है, तो इसे वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही से लागू किया जा सकता है।
- भारत की खुदरा महंगाई जुलाई 2025 में घटकर 8 साल के निचले स्तर 1.55% पर आ गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य कीमतों में आई भारी गिरावट है। यह पहली बार है जब छह साल से अधिक समय में महंगाई भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 2% से 6% के सहनशीलता दायरे से नीचे गई है। इससे पहले, जून 2017 में महंगाई इससे कम दर्ज हुई थी।
- वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 3.95% की गिरावट दर्ज की गई है, जिसका मुख्य कारण करदाताओं को जारी किए गए रिफंड में उल्लेखनीय वृद्धि है। यह जानकारी सरकार द्वारा 12 अगस्त 2025 को जारी आँकड़ों में सामने आई।
- भारत ने 30 सितंबर तक 11% कॉटन आयात शुल्क को स्थगित कर दिया है, जिससे परिधान क्षेत्र को मदद मिलेगी और व्यापार तनाव तथा बढ़ती परिधान प्रतिस्पर्धा के बीच अमेरिका के प्रति सद्भावना का संकेत मिलेगा। एक महत्वपूर्ण नीतिगत कदम के तहत, भारत सरकार ने कॉटन पर 11% आयात शुल्क 30 सितंबर, 2025 तक स्थगित कर दिया है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब भारत के परिधान निर्यातक बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा और बढ़ती लागत का सामना कर रहे हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं।
- एक महत्वपूर्ण नीतिगत कदम के तहत, भारत सरकार ने कॉटन पर 11% आयात शुल्क 30 सितंबर, 2025 तक स्थगित कर दिया है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब भारत के परिधान निर्यातक बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा और बढ़ती लागत का सामना कर रहे हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस निलंबन से अमेरिकी कॉटन उत्पादकों को लाभ होने और देश के सबसे बड़े रोजगार सृजकों में से एक, भारत के कपड़ा और परिधान उद्योग को राहत मिलने की उम्मीद है।
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही (Q1) में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% की दर से बढ़ेगी, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 6.5% के अनुमान से अधिक है। हालांकि यह वृद्धि FY2025 की चौथी तिमाही (Q4) में दर्ज 7.4% की तुलना में कुछ कम है, लेकिन सेवाक्षेत्र की मजबूती और सरकारी पूंजीगत व्यय में तेज़ी के चलते यह दर काफी ठोस मानी जा रही है।
- भारत का थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई दर जुलाई 2025 में लगातार दूसरे महीने नकारात्मक रही, जो सालाना आधार पर -0.58% दर्ज की गई। यह थोक स्तर पर जारी डिफ्लेशन दर्शाता है कि खाद्य, ऊर्जा और धातु जैसे प्रमुख क्षेत्रों में इनपुट कीमतों में ठंडक का रुझान जारी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, खाद्य पदार्थों, खनिज तेलों, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बेसिक मेटल उत्पादों की कीमतों में गिरावट मुख्य कारण रही।
- भारत के माल व्यापार ने जुलाई 2025 में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जहाँ निर्यात 7.3% बढ़कर 37.24 अरब डॉलर पर पहुँच गया। इस वृद्धि को इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग वस्तुओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन ने सहारा दिया। हालांकि, आयात में तेज़ बढ़ोतरी के कारण व्यापार घाटा बढ़कर 27.35 अरब डॉलर पर पहुँच गया, जो पिछले आठ महीनों में सबसे अधिक है। यह आँकड़े वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अस्थायी डेटा में सामने आए।





- भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में तेज़ी दिखाई, जहाँ जीडीपी वृद्धि दर 7.8% दर्ज की गई। यह प्रदर्शन बाज़ार और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) दोनों के अनुमानों से बेहतर रहा और पिछली तिमाही (Q1 FY25) के 6.5% की तुलना में स्पष्ट रूप से तेज़ था। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच यह वृद्धि मज़बूत मैक्रोइकोनॉमिक बुनियादों को दर्शाती है।
- भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में जुलाई 2025 में साल-दर-साल आधार पर 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई। यह जून 2025 के 1.5% की तुलना में उल्लेखनीय सुधार है। इस वृद्धि का मुख्य कारण मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में 5.4% की तेज़ी रही, हालांकि खनन क्षेत्र में तेज़ गिरावट देखी गई। IIP विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के प्रदर्शन को मापने का एक प्रमुख संकेतक है, जो औद्योगिक स्वास्थ्य की झलक पेश करता है।
- भारत के कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) आयात में जुलाई 2025 में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के आँकड़ों के अनुसार, आयात माह-दर-माह (MoM) 8.7% घटकर 1.856 करोड़ मीट्रिक टन रह गया, जो फरवरी 2024 के बाद का सबसे निचला स्तर है। इस कमी के पीछे घरेलू ईंधन माँग में गिरावट, भू-राजनीतिक व्यापार तनाव और ख़ासकर रूसी तेल की ख़रीदारी से जुड़े नए आयात पैटर्न जिम्मेदार रहे।

ECONOMY NEWS

- जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड ने भारत में कोल्ड रोल्ड ग्रेन-ओरिएण्टेड (सीआरजीओ) विद्युत इस्पात उत्पादन का उल्लेखनीय विस्तार करने के लिए जापान की जेएफई स्टील कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी में ₹5,845 करोड़ के विशाल निवेश को मंजूरी दी है। इस विस्तार का उद्देश्य भारत की विद्युत इस्पात निर्माण क्षमताओं को मज़बूत करना, आयात पर निर्भरता कम करना और उच्च गुणवत्ता वाले विद्युत इस्पात की बढ़ती घरेलू माँग को पूरा करना है।
- भारत की डिजिटल गवर्नेंस को एक बड़ी मज़बूती देते हुए, आयकर विभाग ने LTIMindtree Ltd (लार्सन एंड टुब्रो की सहायक कंपनी) को PAN 2.0 परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए चुना है। यह परियोजना नवंबर 2024 में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) द्वारा मंजूरी दी गई थी। ₹811.5 करोड़ मूल्य की इस परियोजना का उद्देश्य पैन (PAN) और टैन (TAN) सेवाओं को आधुनिक बनाना और अधिक कुशल व पारदर्शी बनाना है। यह परियोजना अगले 18 महीनों के भीतर लागू होने की उम्मीद है।
- राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीईआर) ने भारत के व्यावसायिक विश्वास सूचकांक (बीसीआई) में तीव्र वृद्धि दर्ज की है, जो 2024-25 की अप्रैल-जून तिमाही में पिछली तिमाही के 139.3 से बढ़कर 149.4 हो गया। विश्वास में यह वृद्धि सभी प्रमुख आर्थिक संकेतकों में सकारात्मक उम्मीदों से प्रेरित है, जो आने वाले महीनों के लिए भारतीय व्यवसायों में प्रबल आशावाद का संकेत है।
- एसएंडपी ग्लोबल द्वारा जारी नवीनतम एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) के अनुसार, भारत का सेवा क्षेत्र जुलाई 2025 में 11 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया, जिसे मज़बूत अंतरराष्ट्रीय माँग और स्थिर घरेलू बिक्री से बल मिला। यह रिपोर्ट भारत के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में से एक में निरंतर विस्तार को रेखांकित करती है, जो मुद्रास्फीति के दबाव और धीमी भर्तियों के बावजूद मज़बूत गति का संकेत देती है।

- केंद्रीय जीएसटी के क्षेत्रीय अधिकारियों ने वित्त वर्ष 2024-25 तक पिछले पांच वर्षों में लगभग 7.08 लाख करोड़ रुपये की कर चोरी का पता लगाया है, इसमें लगभग 1.79 लाख करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की धोखाधड़ी भी शामिल है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में इससे जुड़े आंकड़े साझा किए। सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों के अनुसार अकेले वित्त वर्ष 2024-25 में, सीजीएसटी फ़ील्ड अधिकारियों की ओर से 2.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) चोरी का पता लगाया गया है।
- जुलाई महीने में भारत द्वारा आयात होने वाले पाम ऑयल में गिरावट आई है। वहीं सोयाबीन तेल का आयात पिछले तीन साल में उच्चतम स्तर पर है। पाम ऑयल तेल के आयात में गिरावट की वजह इंपोर्ट कॉन्टैक्ट का रद्द होना है। वहीं सोयाबीन तेल का आयात इसलिए बढ़ा है कि जून महीने में आयातित होने वाले तेल में देरी हुई, जो जुलाई में आयात किया है। भारत के आयात में गिरावट का असर इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों पर पड़ेगा, जो पाम ऑयल के प्रमुख उत्पादक देश हैं।
- जुलाई में भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता विश्वास में उल्लेखनीय सुधार देखा गया, जो अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। इस सकारात्मक बदलाव के पीछे मुख्य रूप से खुदरा महंगाई में गिरावट और अधिक अनुकूल ब्याज दरें हैं, जिनके चलते घर-परिवारों की धारणा बेहतर हुई है।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 1 अगस्त 2025 से यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) के निर्माण और अपडेट की प्रक्रिया के लिए फेस ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। इस नए नियम का उद्देश्य पहचान सत्यापन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सुरक्षित बनाना है। इसके तहत आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) का उपयोग किया जा रहा है, जिसे UMANG ऐप के माध्यम से लागू किया गया है।
- भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर चुका है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2 अगस्त को UPI ने पहली बार 707 मिलियन दैनिक लेनदेन का आंकड़ा पार कर लिया। यह रिकॉर्ड देश के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ी छलांग है, जिसका हाल के वर्षों में तेज़ी से विस्तार हुआ है।
- मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 56वीं बैठक 4-6 अगस्त, 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में डॉ. नागेश कुमार, श्री सौगत भट्टाचार्य, प्रो. राम सिंह, डॉ. पूनम गुप्ता और डॉ. राजीव रंजन भी उपस्थित थे।
- बीईएमएल लिमिटेड, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनी है, ने रेल और मेट्रो क्षेत्र में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय अनुबंध जीता है। यह परियोजना, जिसकी कीमत 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, मलेशिया से मिली है और इसमें देश की मास रैपिड ट्रांसपोर्ट (एमआरटी) प्रणाली के रेट्रोफिट और पुनः कंडीशनिंग का कार्य शामिल है।
- कर्नाटक में 2024-25 वित्त वर्ष के दौरान वस्तु एवं सेवा कर (GST) चोरी के मामलों में भारी उछाल दर्ज किया गया। केंद्रीय जीएसटी (CGST) विभाग ने ₹39,577 करोड़ की कर चोरी का पता लगाया, जो पिछले वर्ष की तुलना में पांच गुना से अधिक है। यह जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में लिखित जवाब में दी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्रीय अधिकारियों ने केवल UPI लेनदेन के आधार पर कोई नोटिस जारी नहीं किया है।





- भारत के निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था ने अगस्त 2025 में अब तक का सबसे तेज़ विस्तार दर्ज किया, जब एचएसबीसी फ्लैश इंडिया कॉम्पोज़िट पीएमआई आउटपुट इंडेक्स 61.1 (जुलाई) से उछलकर 65.2 तक पहुँच गया। एसएंडपी ग्लोबल के अनुसार, यह अब तक का सबसे ऊँचा स्तर है, जो मुख्यतः सेवाओं क्षेत्र की रिकॉर्ड वृद्धि और विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) में मज़बूत विस्तार से प्रेरित रहा।
- भारत के सार्वजनिक ऋण (Public Debt) पर व्याज़ भुगतान पिछले एक दशक में लगभग तीन गुना बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में व्याज़ भुगतान का अनुमान ₹12.76 लाख करोड़ तक पहुँचने का है। यह बढ़ोतरी भारत की बदलती ऋण संरचना और वित्तीय दबावों को उजागर करती है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी ताज़ा आँकड़ों के अनुसार, 15 अगस्त 2025 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) 1.48 अरब डॉलर बढ़कर 695.10 अरब डॉलर हो गया। वैश्विक बाज़ार की अस्थिरता के बीच यह वृद्धि मुख्यतः विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (Foreign Currency Assets) में बढ़ोतरी से प्रेरित रही है और यह रुपया स्थिर बनाए रखने में RBI की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है।
- सार्वजनिक ऋण बढ़ाए बिना बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण को बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, भारत सरकार ने टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टीओटी), बुनियादी ढाँचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) और प्रतिभूतिकरण जैसे तरीकों का उपयोग करके, वित्त वर्ष 25 तक संपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से ₹1,42,758 करोड़ जुटाए हैं। मौजूदा संपत्तियों का यह रणनीतिक मुद्रीकरण सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के विस्तार को सुनिश्चित करते हुए दीर्घकालिक निजी निवेश को सक्षम बनाता है।
- भारत का थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई दर जुलाई 2025 में लगातार दूसरे महीने नकारात्मक रही, जो सालाना आधार पर -0.58% दर्ज की गई। यह थोक स्तर पर जारी डिफ्लेशन दर्शाता है कि खाद्य, ऊर्जा और धातु जैसे प्रमुख क्षेत्रों में इनपुट कीमतों में ठंडक का रुझान जारी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, खाद्य पदार्थों, खनिज तेलों, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बेसिक मेटल उत्पादों की कीमतों में गिरावट मुख्य कारण रही।
- भारत के कोयला आयात में वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025) के दौरान 1.5% की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि में आयात बढ़कर 76.40 मिलियन टन (एमटी) हो गया, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 75.26 एमटी था। यह बढ़ोतरी सरकार द्वारा घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर ज़ोर देने के बावजूद हुई, जिसका मुख्य कारण मौसमी और आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियाँ रहीं, विशेषकर मानसून के महीनों में।
- भारत की घरेलू वित्तीय बचत को लेकर गोलडमैन सैक्स ने एक बड़ा अनुमान जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले दस वर्षों (2025-2035) में घरेलू वित्तीय बचत से 9.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि वित्तीय परिसंपत्तियों में प्रवाहित होगी। यह बदलाव भारत की अर्थव्यवस्था में भौतिक संपत्तियों (जैसे सोना और रियल एस्टेट) से वित्तीय साधनों की ओर झुकाव को दर्शाता है और वित्तीयकरण (financialization) एवं पूंजी बाज़ार की गहराई (capital market deepening) के एक अहम चरण को इंगित करता है।

BUSINESS NEWS

- अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को रेखांकित करते हुए, भारत की अग्रणी ऑटो कंपोनेंट निर्माता कंपनी टाटा ऑटोकॉम्प सिस्टम्स लिमिटेड ने स्लोवाकिया स्थित IAC ग्रुप के अधिग्रहण की योजना की घोषणा की है। यह अधिग्रहण इसकी ब्रिटिश सहायक कंपनी आर्टिफेक्स इंटीरियर सिस्टम्स लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा, जो यूरोप के ऑटोमोबाइल बाज़ार में टाटा ऑटोकॉम्प की उपस्थिति बढ़ाने की रणनीति का एक महत्वपूर्ण कदम है।
- टाटा मोटर्स ने 30 जुलाई 2025 को ऐलान किया कि उसकी कार्यकारी समिति ने इटली की इवेको ग्रुप NV की 100% हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। यह पूरी तरह नकद सौदा करीब 3.8 अरब यूरो (लगभग ₹34,600 करोड़) का है, जो सभी जरूरी मंजूरीयों पर निर्भर करेगा। खास बात यह है कि यह डील इवेको के डिफेंस बिजनेस को शामिल नहीं करती, जिसे वह पहले ही अलग बेचने की तैयारी में है।
- भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा नियमों के कई उल्लंघनों के लिए पॉलिसीबाज़ार इश्योरेंस ब्रोकर्स पर ₹5 करोड़ का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। इन उल्लंघनों में बीमा उत्पादों के भ्रामक प्रचार से लेकर प्रीमियम के भुगतान में देरी और आउटसोर्सिंग प्रथाओं में पारदर्शिता की कमी शामिल है। यह नियामक कार्रवाई बीमा मध्यस्थों के लिए उपभोक्ताओं का विश्वास और अनुपालन बनाए रखने की एक कड़ी चेतावनी है।
- जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड ने भारत में कोल्ड रोलड ग्रेन-ओरिएंटेड (सीआरजीओ) विद्युत इस्पात उत्पादन का उल्लेखनीय विस्तार करने के लिए जापान की जेएफई स्टील कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी में ₹5,845 करोड़ के विशाल निवेश को मंजूरी दी है। इस विस्तार का उद्देश्य भारत की विद्युत इस्पात निर्माण क्षमताओं को मज़बूत करना, आयात पर निर्भरता कम करना और उच्च गुणवत्ता वाले विद्युत इस्पात की बढ़ती घरेलू माँग को पूरा करना है।
- शेनझेन में 7-11 अगस्त 2025 को आयोजित 19वें चाइना ब्रांड फेस्टिवल में टॉपब्रांड यूनियन ने टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड्स सूची 2025 जारी की। “एआई एंड ग्लोबल एक्सपेंशन” थीम पर आधारित इस महोत्सव में दुनियाभर से 10,000 से अधिक प्रतिभागी—उद्यमी, नीति-निर्माता और ब्रांड लीडर्स—शामिल हुए।
- जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (JFSL) ने अपने जियोफाइनेंस ऐप में एक नया और शक्तिशाली फीचर लॉन्च किया है—टैक्स प्लानिंग और फाइलिंग मॉड्यूल, जिसे टैक्सबड्डी के सहयोग से विकसित किया गया है। 11 अगस्त 2025 को लॉन्च हुआ यह मॉड्यूल आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग की जटिलताओं को आसान, स्मार्ट, क़िफायती और हर भारतीय करदाता के लिए सुलभ बनाने का उद्देश्य रखता है।
- अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), जो विश्व बैंक समूह का सदस्य है, ने एच-ड्रीम फंड (एचडीएफसी कैपिटल डेवलपमेंट ऑफ़ रियल एस्टेट अफ़ोर्डेबल एंड मिड-इनकम फंड) में 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है। इस फंड का प्रबंधन एचडीएफसी समूह की रियल एस्टेट निवेश के लिए समर्पित प्राइवेट इक्विटी शाखा, एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजर्स, द्वारा किया जाएगा।





- बीईएमएल लिमिटेड, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनी है, ने रेल और मेट्रो क्षेत्र में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय अनुबंध जीता है। यह परियोजना, जिसकी कीमत 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, मलेशिया से मिली है और इसमें देश की मास रैपिड ट्रांसपोर्ट (एमआरटी) प्रणाली के रेट्रोफिट और पुनः कंडीशनिंग का कार्य शामिल है।
- भारत के बाहरी क्षेत्र की स्थिरता का मजबूत संकेत देते हुए, देश का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) 4.74 अरब डॉलर बढ़कर 8 अगस्त 2025 को समाप्त सप्ताह में 693.62 अरब डॉलर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, यह वृद्धि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार (SDRs) और अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में भारत की रिजर्व स्थिति में सकारात्मक बढ़ोतरी के कारण हुई।
- भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति तेल आयातक है, 2024-25 विपणन वर्ष में सोयाबीन तेल (सोयाऑयल) के आयात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने जा रहा है। पाम ऑयल की तुलना में प्रतिस्पर्धी कीमतों के कारण यह बदलाव होगा। डीलरों के अनुमान के अनुसार, इससे पाम ऑयल आयात पिछले पांच वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच जाएगा और वैश्विक वनस्पति तेल बाजार पर असर पड़ेगा।
- भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि के तहत फॉक्सकॉन की नई बेंगलुरु इकाई ने आधिकारिक रूप से काम शुरू कर दिया है। इस संयंत्र में अब आईफोन 17 का उत्पादन हो रहा है। कर्नाटक के देवनहल्ली स्थित यह यूनिट चीन से बाहर फॉक्सकॉन का दूसरा सबसे बड़ा कारखाना है, जो भारत की स्थिति को एप्पल की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में और मजबूत बनाता है।
- भारत के निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था ने अगस्त 2025 में अब तक का सबसे तेज़ विस्तार दर्ज किया, जब एचएसबीसी फ्लैश इंडिया कॉम्पोजिट पीएमआई आउटपुट इंडेक्स 61.1 (जुलाई) से उछलकर 65.2 तक पहुंच गया। एसएंडपी ग्लोबल के अनुसार, यह अब तक का सबसे ऊँचा स्तर है, जो मुख्यतः सेवाओं क्षेत्र की रिकॉर्ड वृद्धि और विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) में मजबूत विस्तार से प्रेरित रहा।
- भारत के सार्वजनिक ऋण (Public Debt) पर व्याज भुगतान पिछले एक दशक में लगभग तीन गुना बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में व्याज भुगतान का अनुमान ₹12.76 लाख करोड़ तक पहुँचने का है। यह बढ़ोतरी भारत की बदलती ऋण संरचना और वित्तीय दबावों को उजागर करती है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी ताज़ा आँकड़ों के अनुसार, 15 अगस्त 2025 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) 1.48 अरब डॉलर बढ़कर 695.10 अरब डॉलर हो गया। वैश्विक बाज़ार की अस्थिरता के बीच यह वृद्धि मुख्यतः विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (Foreign Currency Assets) में बढ़ोतरी से प्रेरित रही है और यह रुपया स्थिर बनाए रखने में RBI की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है।
- सार्वजनिक ऋण बढ़ाए बिना बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण को बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, भारत सरकार ने टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टीओटी), बुनियादी ढाँचा निवेश ट्रस्ट (इनवित) और प्रतिभूतिकरण जैसे तरीकों का उपयोग करके, वित्त वर्ष 25 तक संपत्ति

- मुद्रीकरण के माध्यम से ₹1,42,758 करोड़ जुटाए हैं। मौजूदा संपत्तियों का यह रणनीतिक मुद्रीकरण सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के विस्तार को सुनिश्चित करते हुए दीर्घकालिक निजी निवेश को सक्षम बनाता है।
- भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) वित्त वर्ष 2025 में 73 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो बड़े पैमाने पर इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश के कारण है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, यह आंकड़ा 2030 तक 3.5 गुना बढ़कर 257.9 अरब डॉलर होने का अनुमान है। यह 3.5 गुना वृद्धि भारत को एशिया के अग्रणी InvIT और REIT बाजारों में शामिल करेगी। इस उछाल के पीछे बढ़ता हुआ इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश और निवेशकों की सक्रिय भागीदारी मुख्य कारण हैं।
- रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने गुजरात के जामनगर और कच्छ को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के वैश्विक केंद्र बनाने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। कंपनी के 48वें वार्षिक आम बैठक (AGM) में रिलायंस न्यू एनर्जी के निदेशक अनंत अंबानी ने सौर ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज और हाइड्रोजन तकनीक में कंपनी के विशाल निवेश और अवसंरचना निर्माण का खाका प्रस्तुत किया। यह पहल भारत की स्थिति को वैश्विक ग्रीन एनर्जी इकोनॉमी में पुनर्परिभाषित करेगी।
- इन्फोसिस ने वैश्विक सीमा-पार भुगतान समाधानों को बेहतर बनाने के लिए मास्टरकार्ड के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। यह सहयोग मास्टरकार्ड मूव—धन हस्तांतरण क्षमताओं का एक पोर्टफोलियो—को एजवर्क सिस्टम्स के एक भाग, इन्फोसिस फिनेकल में एकीकृत करता है। इस एकीकरण का उद्देश्य दुनिया भर के वित्तीय संस्थानों को 200 से अधिक देशों तक पहुँच और 150 से अधिक मुद्राओं का समर्थन करते हुए तेज़, अधिक सुरक्षित और स्केलेबल सीमा-पार लेनदेन तक निर्बाध पहुँच प्रदान करना है।
- खनन मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) ने 30,000 करोड़ रुपये (लगभग 3.43 अरब डॉलर) के ऐतिहासिक निवेश की घोषणा की है। इस निवेश से ओडिशा में एक नया एल्यूमिनियम स्मेल्टर और एक कोयला-आधारित बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यह कदम भारत की औद्योगिक अवसंरचना विकास और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
- सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने भारत में अगले पाँच से छह वर्षों में 70,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। यह कदम विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाज़ार के प्रति कंपनी की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। यह घोषणा सुजुकी के अध्यक्ष तोशिहिरो सुजुकी ने गुजरात के हंसलपुर संयंत्र में मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई-विटारा (e-Vitara) के शुभारंभ अवसर पर की। यह भारत की हरित गतिशीलता (Green Mobility) की दिशा में एक अहम पड़ाव माना जा रहा है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, 22 अगस्त 2025 को समाप्त सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) में 4.38 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई और यह घटकर 690.72 अरब डॉलर पर पहुँच गया। यह गिरावट हाल ही में दर्ज उछाल के बाद आई है, जब सितंबर 2024 में भंडार अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर 704.88 अरब डॉलर पर पहुँचा था।





अर्थव्यवस्था/व्यापार करंट अफेयर्स: जुलाई 2025

अक्टूबर 2024 तक जीडीपी और विकास दर

- भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था, जिसे वर्ष 2017 में लागू किया गया था, ने राजस्व संग्रह के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में भारत का सकल GST संग्रह ₹22.08 लाख करोड़ तक पहुंच गया — जो अब तक का सर्वाधिक वार्षिक संग्रह है। यह उपलब्धि FY21 के ₹11.37 लाख करोड़ से दोगुनी वृद्धि को दर्शाती है।
- भारत का वाणिज्यिक वाहन (CV) क्षेत्र वित्त वर्ष 2025-26 में धीरे-धीरे पुनरुद्धार की ओर बढ़ रहा है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्र में इस साल थोक बिक्री में साल-दर-साल (Y-o-Y) 3-5% की वृद्धि की उम्मीद है। यह अनुमान पिछले वर्ष (FY25) में दर्ज की गई 1.2% गिरावट के बाद सामने आया है। इस सुधार का मुख्य कारण निर्माण एवं अवसंरचना गतिविधियों में तेजी और समग्र आर्थिक स्थिति में स्थिरता है। हालांकि, डीलरों के पास उच्च स्तर की इन्वेंट्री और कुछ CV वर्गों में कमजोर मांग अभी भी प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- कृषि और संबद्ध क्षेत्र से उत्पादन का सकल मूल्य (जीवीओ) वित्त वर्ष 2012 से वित्त वर्ष 2024 के दौरान स्थिर मूल्यों पर 54.6 प्रतिशत बढ़कर 29.49 लाख करोड़ रुपये हो गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने यह जानकारी दी। सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के तहत आने वाले एनएसओ ने 'कृषि व संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकीय रिपोर्ट (2011-12 से 2023-24)' का वार्षिक प्रकाशन जारी किया है।
- एसबीआई रिसर्च की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 297 अरब डॉलर का योगदान दिया, जो कि वैश्विक GDP वृद्धि का 6.7% है। इसमें से अकेले भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 44 अरब डॉलर यानी 1.1% वैश्विक वृद्धि में हिस्सेदारी निभाई। यह रिपोर्ट न केवल भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को दर्शाती है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि एसबीआई जैसी संस्थाएं भारत और वैश्विक दोनों स्तरों पर आर्थिक विकास को गति देने में अहम भूमिका निभा रही हैं।
- चालू वित्त वर्ष में 10 जुलाई तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 1.34 प्रतिशत घटकर लगभग 5.63 लाख करोड़ रुपये रह गया। शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों में इसकी पुष्टि हुई। इस दौरान शुद्ध कॉरपोरेट कर संग्रह 3.67 प्रतिशत घटकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपये रह गया, जो एक वर्ष पूर्व इसी अवधि में 2.07 लाख करोड़ रुपये था।
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के आंकड़ों के अनुसार, जून 2025 में फोनपे ने यूपीआई बाजार में अग्रणी स्थान हासिल किया, जिसने 8.54 अरब से अधिक लेनदेन संभाले और बाजार का 46.46% हिस्सा हासिल किया। इसके बाद गूगल पे (35.56%) और पेटीएम (6.90%) का स्थान रहा। हालांकि कुल यूपीआई लेनदेन थोड़ा घटकर 18.39 अरब रह गया, लेकिन नवी और सुपरमनी जैसे नए ऐप्स ने लगातार वृद्धि दर्ज की। राज्यों के अनुसार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ने यूपीआई लेनदेन में सबसे अधिक योगदान दिया।

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नवीनतम बुलेटिन के अनुसार मई 2025 में भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह में 98% की गिरावट दर्ज की गई, जो घटकर मात्र 35 मिलियन डॉलर रह गया। इस तीव्र गिरावट का मुख्य कारण विदेशी निवेशकों द्वारा भारी मात्रा में मुनाफ़ा निकालना (repatriation) और सकल FDI प्रवाह में कमी बताया गया है। हालांकि, इस गिरावट के बावजूद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 696.7 अरब डॉलर पर बना हुआ है, जो आयात कवर और ऋण स्थिरता के लिहाज से संतोषजनक स्थिति दर्शाता है।
- एशियाई विकास बैंक (ADB) ने अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी 2025 में 6.5% और 2026 में 6.7% की दर से वृद्धि करेगी, जिससे भारत की स्थिति दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में और मजबूत होती है। यह अनुमान मजबूत घरेलू मांग, सामान्य मानसून और संभावित मौद्रिक शिथिलता (monetary easing) पर आधारित है। इसके साथ ही, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी के चलते महंगाई दर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के लक्षित दायरे में रहने की संभावना है।
- इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (Ind-Ra), जो एक प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ने वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.3% कर दिया है। इससे पहले यह अनुमान इससे अधिक था। यह संशोधन वैश्विक अनिश्चितताओं, निवेश भावनाओं की कमजोरी और कुछ घरेलू सहायक कारकों जैसे कम मुद्रास्फीति और मौद्रिक सहजता के सम्मिलित प्रभाव को दर्शाता है। यह अपडेट उस समय आया है जब वैश्विक व्यापार मंदी और सतर्क निवेशक व्यवहार को लेकर व्यापक चिंताएँ बनी हुई हैं, जिससे भारत की समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण पर प्रभाव पड़ सकता है।
- भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सकल गैर-निष्पादित संपत्तियों (Gross NPAs) में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। मार्च 2021 में जहाँ यह अनुपात 9.11% था, वहीं मार्च 2025 तक घटकर मात्र 2.58% रह गया। इस बदलाव का श्रेय संस्थागत सुधारों, कड़े विनियामक ढाँचे और बेहतर ऋण अनुशासन को दिया जा रहा है।
- भारत के आठ प्रमुख बुनियादी ढाँचा उद्योगों ने जून 2025 में 1.7% की वृद्धि दर्ज की, जो मई के संशोधित 1.2% के आँकड़े की तुलना में मामूली वृद्धि है। जून 2024 की 5% वृद्धि दर से काफी कम होने के बावजूद, यह वृद्धि तीन महीने के उच्चतम स्तर को दर्शाती है, जो औद्योगिक उत्पादन में मिले-जुले रुझान को दर्शाती है।
- भारत सरकार ने 2047 तक पर्यटन क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान को 10% तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य भारत को \$32 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में बदलने की व्यापक योजना का हिस्सा है। सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक विविधता और आध्यात्मिक संपदा से समृद्ध भारत का पर्यटन क्षेत्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और वैश्विक प्रभाव का एक प्रमुख इंजन बन सकता है — बशर्ते ढाँचागत और रणनीतिक चुनौतियों का समाधान किया जाए।





- विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक और निर्यातक देशों में शामिल भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अपने चाय निर्यात में मामूली लेकिन सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत से चाय का निर्यात 2.85% बढ़ा है, जो वैश्विक स्तर पर चाय की स्थिर मांग और बेहतर बाजार मूल्य संकेतकों को दर्शाता है। निर्यात मूल्य में हुई वृद्धि प्रति किलोग्राम बेहतर मूल्य प्राप्ति को दर्शाती है, जो क्षेत्रीय असमानताओं के बावजूद भारत की चाय उद्योग के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

अर्थव्यवस्था समाचार

- भारत का सकल जीएसटी संग्रह वित्त वर्ष 2025 में रिकॉर्ड ₹22.08 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.4% की वृद्धि दर्शाता है और वित्त वर्ष 2021 में प्राप्त राजस्व से दोगुना है। औसत मासिक संग्रह में वृद्धि और करदाताओं का आधार 1.51 करोड़ से अधिक होने के साथ, जीएसटी प्रणाली ने राजकोषीय समेकन और कर पारदर्शिता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जीएसटी के आठ वर्षों का जश्न मनाते हुए, यह उपलब्धि भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को समर्थन देने वाले एक कुशल, एकीकृत कर ढाँचे के निर्माण में सफलता को दर्शाती है।
- जून 2025 के लिए भारत के राज्यवार जीएसटी संग्रह में महाराष्ट्र ₹30,553 करोड़ के साथ सबसे आगे रहा, उसके बाद कर्नाटक (₹13,409 करोड़) और गुजरात (₹11,404 करोड़) का स्थान रहा, जो मज़बूत औद्योगिक, वाणिज्यिक और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को दर्शाता है। तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों ने मज़बूत योगदान दिया, जबकि दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिशा ने पूर्व और उत्तर में राजस्व में बढ़त हासिल की। छोटे और पूर्वोत्तर राज्यों का संग्रह मामूली रहा, जो उनके विकासशील आर्थिक आधार को रेखांकित करता है, लेकिन रसद, पर्यटन और क्षेत्रीय उपभोग में रणनीतिक क्षमता को भी उजागर करता है।
- पिछले 11 वर्षों में, भारत का आयकर रिफंड 474% बढ़कर 2024-25 में ₹4.77 लाख करोड़ तक पहुँच गया है। यह मुख्य रूप से डिजिटल सुधारों के कारण है, जिससे रिफंड का समय 93 दिनों से घटकर 17 दिन रह गया है। ज़्यादा लोग रिटर्न दाखिल कर रहे हैं और कर संग्रह में रिफंड का हिस्सा भी बढ़ा है। सरकार की ऑनलाइन प्रणालियों और सुधारों ने एक तेज़ और अधिक पारदर्शी कर प्रणाली बनाने में मदद की है, जिससे करदाताओं का जीवन आसान हो गया है।
- वित्त वर्ष 2016 और वित्त वर्ष 2025 के बीच, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) ने RBI के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) में ₹12.08 लाख करोड़ बट्टे खाते में डाले, फिर भी DRT, SARFAESI और IBC के माध्यम से ऋण वसूली के प्रयास जारी रखे। जहाँ 10 सार्वजनिक बैंकों ने बट्टे खाते में डालने की राशि कम की, वहीं SBI और केनरा बैंक में वृद्धि देखी गई। मार्च 2025 तक, 1,629 विलफुल डिफॉल्टर्स पर ₹1.62 लाख करोड़ से अधिक बकाया था, और PMLA और FEOA के तहत ₹25,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति वसूल की गई। इसके अलावा, 48,570 कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है, क्योंकि सार्वजनिक बैंकों ने 96% कर्मचारियों को कवर किया है, जो परिसंपत्ति वसूली और मानव संसाधन प्रबंधन, दोनों में केंद्रित प्रयासों को दर्शाता है।

- एशियाई विकास बैंक (ADB) ने अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी 2025 में 6.5% और 2026 में 6.7% की दर से वृद्धि करेगी, जिससे भारत की स्थिति दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में और मजबूत होती है। यह अनुमान मजबूत घरेलू मांग, सामान्य मानसून और संभावित मौद्रिक शिथिलता (monetary easing) पर आधारित है। इसके साथ ही, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी के चलते महंगाई दर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के लक्षित दायरे में रहने की संभावना है।

व्यापार समाचार

- प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपने 25 वर्षों से चल रहे ऑपरेशन को 3 जुलाई 2025 को बंद कर दिया। यह कदम कंपनी की वैश्विक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वह अपने कर्मचारियों की संख्या घटा रही है और क्लाउड-आधारित सेवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। इस फैसले को कई विशेषज्ञ पाकिस्तान के व्यापारिक माहौल के लिए चिंताजनक संकेत मान रहे हैं।
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने जून 2025 में कुल 229.33 करोड़ आधार ऑथेंटिकेशन लेनदेन की सूचना दी, जो विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल पहचान सत्यापन के लिए आधार पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है। यह आंकड़ा जून 2024 में दर्ज किए गए लेनदेन की तुलना में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जो देश के डिजिटल परिवर्तन और आर्थिक गतिविधियों में आधार की बढ़ती भूमिका पर जोर देता है।
- भारत के इस्पात क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में अपने पहले अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया है। यह कंपनी की वैश्विक विस्तार योजना में एक रणनीतिक कदम है और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी इस्पात निर्माता के रूप में विकसित होने की इसकी महत्वाकांक्षा को पुष्ट करता है।
- भारत के रक्षा क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हुए रिलायंस डिफेंस (Reliance Defence)—जो रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी है—ने अमेरिका स्थित रक्षा ठेकेदार कोस्टल मैकेनिक्स इंक. (Coastal Mechanics Inc. - CMI) के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत महाराष्ट्र के नागपुर स्थित MIHAN (मल्टी-मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट) में एक अत्याधुनिक MRO (मैटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल) सुविधा की स्थापना की जाएगी। यह संयुक्त उपक्रम भारतीय सशस्त्र बलों और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए वायु और थल रक्षा प्लेटफार्मों के उन्नयन पर केंद्रित होगा, जो “आत्मनिर्भर भारत” अभियान के अनुरूप है।
- अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने बताया कि कंपनी ने 15,000 मेगावाट (मेगावाट) की परिचालन क्षमता को पार कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो कि अब 15,539.9 मेगावाट तक पहुंच गई है। यह उपलब्धि भारत में अब तक की सबसे तेज़ और बड़ी क्षमता वृद्धि को दर्शाती है। भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ने कहा कि परिचालन पोर्टफोलियो में 11,005.5 मेगावाट सोलर, 1,977.8 मेगावाट विंड और 2,556.6 मेगावाट विंड-सोलर हाइब्रिड क्षमता शामिल है।





- अडानी पावर लिमिटेड ने 4,000 करोड़ रुपये में दिवाला प्रक्रिया के जरिये 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण पूरा होने की मंगलवार को घोषणा की। अडानी पावर लिमिटेड (एपीएल) ने बयान में कहा कि 18 जून 2025 को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड (वीआईपीएल) के लिए उसकी समाधान योजना को मंजूरी दे दी है।
- अडानी पावर लिमिटेड ने 4,000 करोड़ रुपये में दिवाला प्रक्रिया के जरिये 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण पूरा होने की मंगलवार को घोषणा की। अडानी पावर लिमिटेड (एपीएल) ने बयान में कहा कि 18 जून 2025 को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड (वीआईपीएल) के लिए उसकी समाधान योजना को मंजूरी दे दी है।
- टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित मेकर मैक्सिटी मॉल में अपना पहला भारत शोरूम खोलकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह भव्य लॉन्च भारत के ऑटोमोबाइल और स्वच्छ गतिशीलता क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी क्षण का संकेत देता है, जिसमें कंपनी ने Model Y की दो वेरिएंट्स पेश की हैं — जिनकी शुरुआती कीमत ₹59.89 लाख से शुरू होती है।
- भारत के UPI इकोसिस्टम ने जून 2025 में ₹24.04 लाख करोड़ मूल्य के 18.40 अरब लेनदेन दर्ज किए, जो मासिक आधार पर मामूली गिरावट लेकिन मजबूत वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। विशेषज्ञ इस गिरावट का श्रेय मौसमी प्रभावों को देते हैं और मानते हैं कि UPI अब एक परिपक्व स्तर पर पहुँच रहा है, और IoT-आधारित भुगतान, एम्बेडेड क्रेडिट और B2B लेनदेन जैसे नवीन उपयोगों के माध्यम से अपने अगले विस्तार की तैयारी कर रहा है। औसतन 613 मिलियन दैनिक लेनदेन के साथ, UPI भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार बना हुआ है।
- भारत सरकार ने सॉवरेन वेल्थ फंड्स (SWF) और पेंशन फंड्स के लिए भारत में उनके निवेश पर कर छूट 31 मार्च, 2030 तक बढ़ा दी है। यह नीति लाभांश, व्याज और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को कवर करती है और इसका उद्देश्य दूरसंचार, लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक विदेशी निवेश आकर्षित करना है। यह नियम पहली बार 2020 में आयकर अधिनियम की धारा 10(23FE) के तहत लागू किया गया था, और नवीनतम विस्तार को राजस्व विभाग द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया था। NSDL के अनुसार, भारतीय कंपनियों में SWF द्वारा धारित संपत्ति में साल-दर-साल 60% की वृद्धि हुई है, जो अप्रैल 2024 तक ₹4.7 लाख करोड़ तक पहुँच गई है, जो निवेशकों के मजबूत विश्वास को दर्शाता है।
- जुलाई 2025 में, HSBC नेट-ज़ीरो बैंकिंग अलायंस (NZBA) से बाहर हो गया, जिससे इकोट्रिस्टी जैसे पर्यावरण-अनुकूल ग्राहकों की तीखी प्रतिक्रिया हुई, जिन्होंने बैंक की जलवायु विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। कार्बन क्षेत्रों के प्रति पूर्वाग्रह को लेकर आंतरिक चिंताओं से प्रेरित यह कदम, सतत वित्त के लिए बढ़ती वैश्विक अपेक्षाओं के बिल्कुल

विपरीत है। यह घटनाक्रम HSBC को नेट-ज़ीरो बैंकिंग के भविष्य, नैतिक निवेश और जलवायु कार्रवाई में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण बहस के केंद्र में ला खड़ा करता है।

- वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का चाय निर्यात 2.85% बढ़कर 257.88 मिलियन किलोग्राम हो गया, जिसमें उत्तर भारत में 8.15% की वृद्धि मुख्य रही। दक्षिण भारत में 4.92% की गिरावट देखी गई। औसत निर्यात मूल्य 12.65% बढ़कर 290.97 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, जिससे मूल्य प्राप्ति में वृद्धि हुई। कैलेंडर वर्ष 2024 में, कुल निर्यात 256.17 मिलियन किलोग्राम रहा, जो 10.57% की वृद्धि दर्शाता है।
- आरबीआई बुलेटिन के अनुसार, भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह मई 2025 में सालाना आधार पर 98% घटकर 35 मिलियन डॉलर रह गया, जो प्रत्यावर्तन में 24% की वृद्धि और सकल निवेश में 11% की गिरावट के कारण हुआ। सिंगापुर, मॉरीशस, यूएई और अमेरिका प्रमुख स्रोत थे, जहाँ विनिर्माण, वित्तीय और आईटी सेवाओं में निवेश हुआ। बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़कर 2.1 बिलियन डॉलर हो गया, जो मुख्यतः परिवहन और व्यावसायिक सेवाओं में था। इस गिरावट के बावजूद, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 696.7 बिलियन डॉलर रहा, जिसमें 11 महीनों का आयात और 95% बाह्य ऋण शामिल है।

अर्थव्यवस्था/व्यापार करंट अफेयर्स: जून 2025

अर्थव्यवस्था समाचार

- भारत के वित्त वर्ष 26 के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के पूर्वानुमानों में प्रमुख वैश्विक संस्थानों के अलग-अलग अनुमान देखने को मिले। OECD ने अमेरिकी टैरिफ, कमजोर मानसून और चल रहे वैश्विक व्यापार तनावों के जोखिम का हवाला देते हुए अपने अनुमान को घटाकर 6.3% कर दिया। इसके विपरीत, UBS ने अपने पूर्वानुमान को बढ़ाकर 6.4% कर दिया, जिसमें मजबूत निजी खपत, कर राहत और RBI द्वारा संभावित दर कटौती से समर्थन की उम्मीद थी। मतभेदों के बावजूद, दोनों संस्थान इस बात पर सहमत हुए कि सार्वजनिक निवेश और गिरती व्याज दरें आर्थिक गतिविधि को समर्थन देना जारी रखेंगी। हालाँकि, OECD ने वैश्विक आर्थिक विकास में व्यापक मंदी की चेतावनी दी, और इसे केवल 2.9% पर अनुमानित किया।
- इस बीच, नोमुरा ने जीएसटी संग्रह जैसे मजबूत हेडलाइन संकेतकों और ऑटो बिक्री और बैंक ऋण वृद्धि में कमजोर रुझानों के बीच बेमेल को देखते हुए भारत के जीडीपी पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.2% कर दिया। यह आरबीआई के 6.5% के अनुमान के विपरीत है, जो चल रही वैश्विक अस्थिरता के बीच सावधानी का संकेत देता है। रूढ़िवादी विकास दृष्टिकोण के बावजूद, नोमुरा ने अपने निफ्टी 50 लक्ष्य को 26,140 तक बढ़ा दिया, जो भारत के व्यापक आर्थिक लचीलेपन में विश्वास को दर्शाता है। ब्रोकरेज ने निर्यातकों की तुलना में घरेलू-उन्मुख क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का भी संकेत दिया। अलग से, बोफा सिक्योरिटीज ने भारतीय इक्विटी पर सकारात्मक दीर्घकालिक दृष्टिकोण दोहराया, इसका श्रेय निरंतर संरचनात्मक सुधारों और डिजिटलीकरण की प्रगति को दिया।





- विश्व बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 26 के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को 6.3% पर बनाए रखा, जिससे यह वैश्विक स्तर पर सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रही। जबकि दुनिया की लगभग 70% अर्थव्यवस्थाओं ने व्यापार संघर्षों, नीतिगत अस्पष्टता और सुस्त निवेश के कारण विकास में गिरावट देखी, भारत एक अपवाद बना रहा। रिपोर्ट ने भारत के मजबूत सेवा क्षेत्र, कम मुद्रास्फीति और RBI की मौद्रिक सहजता को विकास चालकों के रूप में श्रेय दिया। इसने देश के राजकोषीय अनुशासन की भी प्रशंसा की, जिसमें वित्त वर्ष 31 तक सार्वजनिक ऋण-से-जीडीपी अनुपात को 50% तक कम करने के मध्यम अवधि के लक्ष्य पर प्रकाश डाला गया।
- मई 2025 में भारत की बेरोज़गारी दर बढ़कर 5.6% हो गई, जिसका मुख्य कारण कटाई के बाद ग्रामीण कृषि रोजगार में मौसमी गिरावट है। डेटा से पता चला है कि युवा और महिलाएँ विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं, महिला श्रम बल भागीदारी घटकर 27.8% रह गई है। यह प्रवृत्ति पर्याप्त और समावेशी रोजगार सृजित करने में लगातार संरचनात्मक चुनौतियों को रेखांकित करती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में युवाओं की बेरोज़गारी बढ़ी है, जिससे केंद्रित रोजगार सृजन रणनीतियों की आवश्यकता पर ध्यान गया है।
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA ने भी कमजोर व्यापारिक निर्यात, व्यापार अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति में कमी को बाधाओं के रूप में उद्धृत करते हुए भारत की FY26 जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.2% लगाया है। हालांकि, इसने नोट किया कि मजबूत ग्रामीण मांग, पूंजीगत व्यय में अनुमानित 10.1% वृद्धि और घरेलू कर राहत प्रमुख समर्थन प्रदान कर सकती है। इसके अतिरिक्त, सेवाओं के निर्यात से माल निर्यात के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.4% पर अनुमानित है, जो सतर्क लेकिन स्थिर राजकोषीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। ICRA ने पुष्टि की कि बाहरी अस्थिरता के बावजूद भारत के व्यापक आर्थिक बुनियादी तत्व ठोस बने हुए हैं।
- मई 2025 में भारत के कोर सेक्टर की वृद्धि दर में भारी गिरावट आई और यह 0.7% पर आ गई, जो नौ महीने का सबसे निचला स्तर है। कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक और बिजली के उत्पादन में गिरावट के कारण यह गिरावट आई। यह लगातार दूसरा महीना था जब कोर सेक्टर में कमजोरी रही, जो औद्योगिक उत्पादन पर दबाव को दर्शाता है। हालांकि, सीमेंट (+9.2%) और स्टील (+6.7%) में मजबूती जारी रही। आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि गति बनाए रखने के लिए प्रमुख बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्रों में लक्षित नीति समर्थन की आवश्यकता है।
- भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 1.39% घटकर ₹4.59 लाख करोड़ रह गया, जिसका मुख्य कारण अग्रिम कर वृद्धि में कमी और कॉर्पोरेट कर प्राप्ति में कमी है। जबकि सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 4.86% की वृद्धि हुई, कर रिफंड में 58% की तीव्र वृद्धि ने शुद्ध संग्रह आधार को काफी कम कर दिया। कॉर्पोरेट अग्रिम कर में 5.86% की मामूली वृद्धि देखी गई, जबकि गैर-कॉर्पोरेट अग्रिम कर में 2.68% की गिरावट आई। ये घटनाक्रम शुरुआती राजकोषीय दबाव और कर अनुपालन और आर्थिक सुधार की गति की निगरानी के महत्व की ओर इशारा करते हैं।
- 24 जून, 2025 को, एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने वैश्विक अस्थिरता के बीच आर्थिक लचीलेपन का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 26 के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.5% कर दिया। वृद्धि के प्रमुख कारणों में सामान्य मानसून की उम्मीद शामिल थी, जो कृषि को समर्थन देगा, और कच्चे तेल की कीमतों में कमी, जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आयात लागत को कम करने में मदद करेगी। यह अपडेट भारत के नीतिगत ढांचे और बाहरी झटकों के बावजूद विकास को बनाए रखने की इसकी क्षमता में अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को दर्शाता है।
- वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में भारत ने 13.5 बिलियन डॉलर का चालू खाता अधिशेष दर्ज किया, जो पिछली तिमाही के घाटे से काफी बेहतर है। RBI के आंकड़ों के अनुसार, यह अधिशेष मजबूत सेवा निर्यात, विशेष रूप से IT और व्यावसायिक सेवाओं में, और विदेशों से प्रेषण में वृद्धि के कारण था। कम व्यापारिक व्यापार घाटा और शुद्ध प्राथमिक आय बहिर्वाह में गिरावट ने भी अधिशेष में योगदान दिया। FDI प्रवाह में कुछ कमी के बावजूद, यह सुधार बाहरी क्षेत्र की स्थिरता और समग्र आर्थिक बुनियादी बातों में वृद्धि को दर्शाता है।
- भारत की खुदरा मुद्रास्फीति मई 2025 में तेजी से घटकर 2.82% हो गई, जो फरवरी 2019 के बाद से इसका सबसे निचला स्तर है। यह गिरावट मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट के कारण हुई, जो घटकर 0.99% हो गई। अनुकूल आधार प्रभाव और आयात शुल्क में कटौती जैसे सरकारी उपायों से सब्जियों, दालों और मांस जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई। राज्यों में, केरल में सबसे अधिक मुद्रास्फीति दर्ज की गई, जबकि तेलंगाना में सबसे कम मुद्रास्फीति दर्ज की गई। भविष्य को देखते हुए, विश्लेषकों को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 26 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) औसतन 4% के आसपास रहेगा, हालांकि वे चेतावनी देते हैं कि मानसून का प्रदर्शन और भू-राजनीतिक घटनाक्रम मूल्य गतिशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। मौजूदा डेटा RBI की दरों में कटौती को आगे बढ़ाने की रणनीति का समर्थन करता है, लेकिन यह आगे की ढील के लिए सीमित गुंजाइश को भी इंगित करता है जब तक कि आर्थिक विकास काफी कमजोर न हो जाए।
- खुदरा मुद्रास्फीति के रुझान के अनुरूप, भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति (WPI) भी मई 2025 में 0.39% तक गिर गई, जो अप्रैल में 0.85% थी, जो खाद्य, ईंधन और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में गिरावट को दर्शाती है। गिरावट में एक प्रमुख योगदानकर्ता सब्जियों की कीमतों में भारी गिरावट थी, जो 21.62% तक गिर गई। WPI और CPI दोनों में यह एक साथ गिरावट मूल्य स्थिरता के लिए उत्साहजनक संकेत भेजती है, एक अधिक उदार मौद्रिक नीति रुख को मजबूत करती है और RBI को अधिक लचीलापन देती है, खासकर बाहरी अनिश्चितताओं के बीच।





- इसके अतिरिक्त, भारत अपने सीपीआई ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव की योजना बना रहा है, जिसमें आधार वर्ष को 2024 तक अपडेट करने और वर्तमान उपभोग पैटर्न को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए सीपीआई बास्केट का विस्तार करने का प्रस्ताव है। यह संशोधन घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2023-24 द्वारा सूचित किया जा रहा है, जिसने लगभग 407 उपभोग वस्तुओं के डेटा का विश्लेषण किया। मौजूदा 2012-आधारित सूचकांक की जगह, अपडेटेड CPI श्रृंखला 2026 की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसके अलावा, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 ने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण तंत्र में खाद्य कीमतों की भूमिका की समीक्षा की सिफारिश की है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि अस्थिर आपूर्ति-पक्ष व्यवहार के कारण खाद्य को बाहर रखा जा सकता है। यह आगे चलकर अधिक संरचनात्मक और लक्षित मुद्रास्फीति प्रबंधन की ओर बदलाव का संकेत देता है।

व्यापार समाचार

- भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक विकास में, वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के रूप में कार्य करने की अनुमति मिल गई है। इस लाइसेंस के साथ, फ्लिपकार्ट अब पारंपरिक ऋणदाताओं के साथ साझेदारी की बजाय सीधे अपने ग्राहकों और विक्रेताओं को ऋण प्रदान कर सकेगा। यह पहली बार है जब किसी भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी को ऐसा लाइसेंस मिला है, जिससे ऑनलाइन रिटेल में फिनटेक एकीकरण को नई दिशा मिलेगी।
- जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने वित्त वर्ष 2026 (FY26) के लिए भारत की GDP वृद्धि दर को घटाकर 6.2% कर दिया है, जो कि FY25 के 6.5% और FY24 के तेज़ 9.2% की वृद्धि दर से कम है। यह अनुमान 3 जून 2025 को जारी किया गया, जो यह संकेत देता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में धीमी गति देखी जा सकती है।
- भारत में फिनटेक और क्रेडिट इनोवेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, ट्रेवल-फोकस्ड फिनटेक प्लेटफॉर्म स्केपिया (Scapia) ने फेडरल बैंक के साथ मिलकर 'स्केपिया फेडरल RuPay क्रेडिट कार्ड' लॉन्च किया है। यह डुअल-नेटवर्क क्रेडिट कार्ड है जो Visa और RuPay दोनों नेटवर्क को एकीकृत करता है। कार्ड UPI, अंतरराष्ट्रीय उपयोग, और ऑनलाइन व ऑफलाइन भुगतान को सपोर्ट करता है—सभी खर्चों का एकीकृत क्रेडिट स्टेटमेंट के साथ। यह खासतौर पर मोबाइल-फर्स्ट ट्रेवलर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें शून्य फॉरेक्स मार्कअप, एयरपोर्ट सुविधाएं, और विशेष रिवाइंड्स शामिल हैं।
- भारत की स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रक्रिया को तेज़ करने की दिशा में एक बड़े कदम के तहत, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) ने ₹2,005.90 करोड़ का फंड Qualified Institutional Placement (QIP) के माध्यम से सफलतापूर्वक जुटाया है। इस पूंजी से एजेंसी की हरित ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और इसकी पूंजी पर्याप्तता तथा वित्तीय आधार को मज़बूती मिलेगी।
- थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड ने मुथूट फॉरेक्स (मुथूट ग्रुप का हिस्सा) के साथ साझेदारी की है ताकि उसके ट्रेवल और स्टूडेंट फॉरेक्स कार्ड्स को पूरे भारत में उपलब्ध कराया जा सके। मुथूट की 7,000 से अधिक शाखाओं (जिनमें से 43 विशेष फॉरेक्स शाखाएं हैं) के नेटवर्क के ज़रिए ये सेवाएं अब मेट्रो, मिनी-मेट्रो, टियर 2 से टियर 4 शहरों तक पहुंचेंगी।
- बजाज आलियांज द्वारा 20 जून 2025 को राज्यवार स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की शुरुआत भारत के स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नवाचार को दर्शाती है। भारत के विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य सेवा ढांचे, इलाज की लागत और रोगों के प्रकार में भारी भिन्नता है। ऐसे में यह पहल सस्ती और आवश्यकता-आधारित बीमा योजनाओं की मांग को पूरा करती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अभी तक बीमा नहीं मिला है क्योंकि प्रीमियम अधिक होता है।
- भारत में कर-संबंधी प्रक्रियाओं की दक्षता और सटीकता को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक नया डिजिटल समाधान पेश किया है, जो एक उन्नत API (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस) के माध्यम से PAN और बैंक खाते का वास्तविक समय (रियल-टाइम) सत्यापन सक्षम बनाता है। यह पहल करदाताओं और सरकारी विभागों दोनों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिससे आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर वित्तीय सत्यापन प्रक्रियाएं सरल और तेज़ हो सकें।
- भारत के विमानन निर्माण क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक प्रगति के तहत, रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर लिमिटेड (RAL) — जो कि रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की एक अनुषंगी कंपनी है — और फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी के तहत फाल्कन 2000 बिज़नेस जेट का निर्माण अब महाराष्ट्र के नागपुर में किया जाएगा। यह घोषणा 18 जून 2025 को पेरिस एयर शो में की गई और यह पहली बार है जब डसॉल्ट अपने किसी फाल्कन विमान का उत्पादन फ्रांस के बाहर कर रहा है। यह पहल 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' मिशनों के तहत भारत को उच्च गुणवत्ता वाले एयरोस्पेस विनिर्माण का नया केंद्र बनाएगी।
- भारत के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को एक बड़ा प्रोत्साहन देते हुए, एलन मस्क की स्टारलिन को देश में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए आधिकारिक लाइसेंस मिल गया है। यह घोषणा संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। यह निर्णय विशेष रूप से दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में भारत की डिजिटल खाई को पाटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे पहले मार्च 2025 में जियो प्लेटफॉर्म और भारती एयरटेल ने स्टारलिन सेवाओं की तैनाती के लिए स्पेसएक्स से साझेदारी की घोषणा की थी।
- अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, TVS मोटर कंपनी ने इंडोनेशिया में आधिकारिक रूप से अपना iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है। यह लॉन्च दक्षिण-पूर्व एशिया के तेजी से बढ़ते ईवी बाज़ार में कंपनी की एंट्री को दर्शाता है। बुकिंग अब आरंभिक कीमत IDR 29.9 लाख (लगभग ₹1.6 लाख) पर खुल चुकी है। TVS का लक्ष्य इंडोनेशियाई ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता, विश्वसनीय और किफायती ईवी समाधान प्रदान करना है।





- टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने काउंसिल ऑफ यूरोप डेवलपमेंट बैंक (CEB), जो पेरिस में स्थित है, के साथ साझेदारी की है ताकि बैंक के जटिल वित्तीय लेनदेन को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाया जा सके। इस सहयोग के तहत, TCS अपनी AI-संचालित समाधान प्रणाली 'TCS BaNCS™ for Reconciliations' को लागू करेगा, जो CEB की मिलान प्रक्रिया (reconciliation processes) को स्वचालित और आधुनिक बनाने में मदद करेगा।
- अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने बताया कि कंपनी ने 15,000 मेगावाट (मेगावाट) की परिचालन क्षमता को पार कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो कि अब 15,539.9 मेगावाट तक पहुंच गई है। यह उपलब्धि भारत में अब तक की सबसे तेज और बड़ी क्षमता वृद्धि को दर्शाती है। भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ने कहा कि परिचालन पोर्टफोलियो में 11,005.5 मेगावाट सोलर, 1,977.8 मेगावाट विंड और 2,556.6 मेगावाट विंड-सोलर हाइब्रिड क्षमता शामिल है।
- जियो ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लि. की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी जियो ब्लैकरॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड को ब्रोकरेज इकाई के रूप में परिचालन शुरू करने के लिए बाजार नियामक सेबी से मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि जियोब्लैकरॉक ब्रोकिंग का लक्ष्य निवेशकों के लिए सस्ती, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-संचालित निष्पादन क्षमताएं लाना है। यह कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (JFSL) और ब्लैकरॉक इंक के बीच 50:50 के संयुक्त उद्यम (जॉइंट वेंचर) JioBlackRock Investment Advisers Pvt. Ltd. की सहायक इकाई है।
- बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कंपनी द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों, विशेष रूप से आउटसोर्सिंग मानदंडों और पॉलिसीधारकों के KYC अनुपालन में चूक के चलते लगाया गया है।
- भारत के ईंधन खुदरा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, अदाणी टोटल गैस लिमिटेड (ATGL) और रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड (जियो-बीपी) ने एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां एक-दूसरे के ईंधन उत्पादों को चुनिंदा आउटलेट्स पर वितरित करेंगी। यह सहयोग निजी क्षेत्र के दो दिग्गजों के बीच हुआ है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के प्रभुत्व वाले बाजार में अपने पदचिह्न को मजबूत करना है।
- भारत के कृषि नवाचार को वैश्विक मंच पर ले जाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्था (IFFCO) ने ब्राज़ील में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय नैनो उर्वरक निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। यह रणनीतिक पहल ब्राज़ील की कंपनी NANO FERT के साथ साझेदारी में की गई है, जिसका उद्देश्य टिकाऊ और कुशल फसल पोषण समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करना है।
- ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की टॉप 100 कंपनियों का संयुक्त ब्रांड वैल्यू 236.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। यह रैंकिंग टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इन्फ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटैलिटी समेत विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख भारतीय ब्रांडों के ग्रोथ को दर्शा रही है। ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2025 के अनुसार, टाटा समूह ने \$30 अरब का आंकड़ा पार कर \$31.6 अरब की ब्रांड वैल्यू के साथ नया इतिहास रच दिया है।

- अदानी समूह ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जहां 23 जून 2025 को गुजरात के कच्छ में देश का पहला ऑफ-ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट चालू किया गया। यह अभिनव परियोजना भारत की स्वच्छ ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है और विकेंद्रित हाइड्रोजन उत्पादन की तकनीकी संभावनाओं को दर्शाती है।

अर्थव्यवस्था/व्यापार करंट अफेयर्स: मई 2025

अक्टूबर 2024 के अनुसार जीडीपी और विकास दर

- संयुक्त राष्ट्र ने भारत के 2025 के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के पूर्वानुमान को 2024 के 7.1% से घटाकर 6.3% कर दिया है, जबकि भारत को अभी भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना है। प्रमुख चालकों में मजबूत निजी खपत, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में वैश्विक बाधाओं जैसे व्यापार तनाव, टैरिफ वृद्धि और निवेश अनिश्चितता की भी चेतावनी दी गई है, जो समग्र वैश्विक विकास को प्रभावित करती है। भारत में मुद्रास्फीति आरबीआई की लक्ष्य सीमा के भीतर रहने का अनुमान है, जिससे मौद्रिक सहजता को बढ़ावा मिलेगा। वैश्विक जोखिमों के बावजूद, भारत के व्यापक आर्थिक बुनियादी तत्व मजबूत बने हुए हैं।
- मॉर्गन स्टेनली ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान वित्त वर्ष 26 के लिए 6.2% और वित्त वर्ष 27 के लिए 6.5% तक बढ़ा दिया है, जो मजबूत घरेलू मांग, शहरी और ग्रामीण खपत में वृद्धि और मजबूत सार्वजनिक पूंजीगत व्यय के कारण है। रिपोर्ट में व्यापक आर्थिक बुनियादी बातों की स्थिरता, आरबीआई द्वारा अपेक्षित नीतिगत ढील और भारत के बाहरी दृष्टिकोण पर कम हुए वैश्विक व्यापार तनाव के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है।
- फिच रेटिंग्स ने श्रम बल की अधिक भागीदारी और महामारी के कम होने का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 26 के लिए भारत के मध्यम अवधि के विकास पूर्वानुमान को बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। जबकि रिपोर्ट में श्रम उत्पादकता में कमी और कुल कारक उत्पादकता में गिरावट की चेतावनी दी गई है, भारत का दृष्टिकोण अन्य उभरते बाजारों, विशेष रूप से चीन के लिए घटते अनुमानों के विपरीत चमकता है। यह भारत की आर्थिक लचीलापन और विकास क्षमता की वैश्विक मान्यता का संकेत देता है।
- वैश्विक रेटिंग और एनालिटिक्स एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है, जिसे घरेलू खपत में सुधार, मुद्रास्फीति में कमी और अनुकूल मौद्रिक नीति से समर्थन मिलेगा।

अर्थव्यवस्था समाचार

- मॉर्गन स्टेनली ने भारत की दीर्घकालिक इक्विटी संभावनाओं पर अपने आशावादी दृष्टिकोण की पुष्टि की है, जिसमें ठोस मैक्रो फंडामेंटल, कम मुद्रास्फीति और घरेलू मांग को प्रमुख चालक बताया गया है। यह वित्तीय और औद्योगिक जैसे घरेलू क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है, जबकि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच धैर्यपूर्ण, दीर्घकालिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। ब्रोकरेज भारत को एक लचीला और अपेक्षाकृत अछूता बाजार मानता है, जो दुनिया भर में आर्थिक अस्थिरता का सामना करने में सक्षम है।





- मूडीज ने 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुमान को संशोधित कर 6.3% कर दिया है, जिसमें नीतिगत अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार में व्यवधान को प्राथमिक चुनौतियों के रूप में बताया गया है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, 2026 के लिए पूर्वानुमान 6.5% पर बना हुआ है, जो स्थिरता की उम्मीदों को दर्शाता है। एजेंसी ने यह भी कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने के लिए व्याज दरों को कम करना जारी रख सकता है। अमेरिका, चीन और वैश्विक बाजारों के लिए व्यापक दृष्टिकोण भी टैरिफ नीतियों, बाजार में उतार-चढ़ाव और निवेश जोखिमों के बीच धीमी गति को दर्शाता है।
- अप्रैल 2025 में हेडलाइन मुद्रास्फीति घटकर 3.16% रह गई, जो जुलाई 2019 के बाद सबसे कम है, जबकि खाद्य मुद्रास्फीति में भारी गिरावट आई और यह 1.78% पर आ गई, जिसका मुख्य कारण सब्जियों, फलों और अनाज की कीमतों में गिरावट है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कीमतों में नरमी देखी गई, जिससे व्यापक आर्थिक स्थिरता और उपभोक्ता राहत को समर्थन मिला।
- भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, अप्रैल 2025 में भारत का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) लगभग दोगुना होकर 6.8 बिलियन डॉलर हो गया, जो एक साल पहले 3.58 बिलियन डॉलर था। यह इकट्टी निवेश, ऋण और गारंटी में पर्याप्त वृद्धि के कारण हुआ। यह निवेश भावना में सुधार के बीच वैश्विक स्तर पर विस्तार करने के लिए भारतीय फर्मों के बीच बढ़ती इच्छा को दर्शाता है।
- राजकोषीय प्रबंधन के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि में, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 4.8% के अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जबकि कुल प्राप्तियाँ उम्मीदों से थोड़ी कम रहीं। यह अपडेट शुक्रवार को लेखा महानियंत्रक (सीजीए) द्वारा वर्ष के लिए अंतिम जीडीपी अनुमानों के साथ जारी किया गया।
- वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कोयला आयात 7.9% घटकर 243.62 मिलियन टन पर पहुंच गया, जिससे लगभग 7.93 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा की बचत हुई। वाणिज्यिक कोयला खनन और मिशन कोकिंग कोल जैसी सरकारी योजनाओं ने इस बदलाव का समर्थन किया, जबकि घरेलू कोयला उत्पादन में 5% की वृद्धि हुई। आयात में तेज गिरावट, विशेष रूप से बिजली क्षेत्र में, ऊर्जा सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और विकसित भारत विजन की दिशा में प्रगति को दर्शाती है।
- भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड एफडीआई प्रवाह हासिल किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% की वृद्धि दर्शाता है। सेवा क्षेत्र ने 40.77% की वृद्धि के साथ उछाल का नेतृत्व किया, इसके बाद विनिर्माण और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का स्थान रहा। महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली शीर्ष एफडीआई गंतव्य थे, जबकि सिंगापुर, मॉरीशस और अमेरिका प्रमुख निवेशक थे। उदार एफडीआई नीति सुधार, निवेशकों का बढ़ता विश्वास और विविध स्रोतों ने भारत को अपने विकसित भारत लक्ष्यों के अनुरूप वैश्विक निवेश हॉटस्पॉट के रूप में स्थापित किया है।

व्यापार समाचार

- भारत के व्यापार क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश का कुल निर्यात अब तक के सर्वोच्च स्तर यानी 824.9 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नवीनतम सेवाओं व्यापार रिपोर्ट में सामने आया है। यह निर्यात पिछले वर्ष के 778.1 अरब डॉलर की तुलना में 6.01% की मजबूत वृद्धि को दर्शाता है। इस उछाल में सेवाओं के निर्यात की विशेष भूमिका रही, जिसमें दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। यह भारत की आईटी, परामर्श, वित्त और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में बढ़ती दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को उजागर करता है।
- भारत के कोयला क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत मजबूती से की है, जिसमें अप्रैल 2025 में उत्पादन और आपूर्ति दोनों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। कोयला उत्पादन में निरंतर वृद्धि यह दर्शाती है कि ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास में कोयला अब भी रणनीतिक भूमिका निभा रहा है। आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू उपलब्धता बढ़ाने पर जोर देते हुए यह प्रदर्शन भारत की ऊर्जा प्रणाली और आत्मनिर्भरता लक्ष्यों के लिए अहम है।
- चीन की वित्तीय सेवा कंपनी एंट ग्रुप ने अपनी सहयोगी कंपनी Antfin (Netherlands) Holding BV के माध्यम से भारतीय फिनटेक कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (Paytm की मूल कंपनी) में अपनी 4% हिस्सेदारी बेचने की योजना की घोषणा की है। यह बिक्री भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर बल्क डील के माध्यम से की जाएगी। बिक्री की न्यूनतम कीमत ₹809.75 प्रति शेयर तय की गई है, जो कि एनएसई पर पेटीएम के पिछले बंद मूल्य ₹866.05 से लगभग 6.5% कम है।
- कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और वैश्विक व्यापारिक अनिश्चितताओं के बीच, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के दौरान भारत में मुद्रास्फीति (Inflation) लक्ष्य के अनुरूप रहने की उम्मीद है। उन्होंने 7 से 9 अप्रैल के बीच आयोजित मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee - MPC) की बैठक के दौरान यह बात कही। मल्होत्रा ने बताया कि वर्तमान में मुद्रास्फीति को कम करने वाली शक्तियाँ (Disinflationary forces), मुद्रास्फीति बढ़ाने वाले जोखिमों की तुलना में अधिक प्रभावी हैं, जिससे विकास को समर्थन देने के लिए मौद्रिक नीति में ढील (Monetary easing) की गुंजाइश बनती है।
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड (ABCL) के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य खासकर ग्रामीण और बैंकिंग सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में कर्ज उत्पादों की पहुंच को व्यापक बनाना है। इस पहल के तहत ABCL के विविध ऋण समाधान को IPPB के विशाल डाक नेटवर्क और डिजिटल अवसंरचना के साथ जोड़कर आम जनता को सहज क्रेडिट विकल्प प्रदान किए जाएंगे।
- फिच रेटिंग्स ने बेहतर श्रम बल भागीदारी और महामारी से हुए आर्थिक घावों में कमी को आधार मानकर भारत की मध्यावधि जीडीपी विकास दर अनुमान को वित्त वर्ष 2026 तक 6.4% कर दिया है। यह संशोधन ऐसे समय में हुआ है जब फिच ने अधिकांश अन्य उभरती बाजारों के विकास पूर्वानुमानों में कटौती की है, और चीन जैसे देश गहन संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यह उन्नत दृष्टिकोण भारत की लचीलापन और रोजगार तथा उत्पादकता में जारी संरचनात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है।





- मॉर्गन स्टेनली, एक प्रमुख वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म, ने मजबूत घरेलू मांग परिदृश्य और सुधरते व्यापक आर्थिक स्थिरता का हवाला देते हुए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के पूर्वानुमान को वित्त वर्ष 26 के लिए 6.2% और वित्त वर्ष 27 के लिए 6.5% तक मामूली रूप से उन्नत किया है। वृद्धि दर में यह वृद्धि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के आंतरिक विकास इंजनों में विश्वास को दर्शाती है।
- भारत के निर्यात क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2025 में मजबूत शुरुआत दर्ज की, अप्रैल में माल निर्यात में 9% की वृद्धि हुई, जिसका नेतृत्व इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान ने किया। यह उछाल मुख्य रूप से अमेरिका में टैरिफ अनिश्चितता के कारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वाशिंगटन को निर्यात में 27% की वृद्धि हुई। आयात में वृद्धि के बावजूद व्यापार घाटा बढ़ रहा है, रतन और आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स और वस्त्रों में ठोस प्रदर्शन के साथ-साथ सेवाओं के निर्यात में वृद्धि भारत की व्यापार रणनीति में लचीलापन और विविधीकरण का संकेत देती है।
- NSDL के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने इस सप्ताह भारतीय इक्विटी में ₹4,452 करोड़ डाले, जिससे मई में कुल निवेश ₹18,620 करोड़ हो गया। 2025 में पहले शुद्ध निकासी के बावजूद, यह उछाल घरेलू आर्थिक स्थिरता, वैश्विक अनिश्चितता में कमी और रक्षा, पूंजी बाजार और रियल एस्टेट में मजबूत क्षेत्रीय प्रदर्शन से प्रेरित निवेशकों के नए विश्वास को दर्शाता है। सेंसेक्स और निफ्टी में भी उछाल आया, जो सकारात्मक बाजार भावना को दर्शाता है।
- अप्रैल 2025 में भारत के कोर सेक्टर की वृद्धि दर में भारी गिरावट आई और यह 0.5% पर आ गई, जो पिछले आठ महीनों में सबसे कम प्रदर्शन है। रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक और कच्चे तेल जैसे प्रमुख क्षेत्रों में संकुचन देखा गया, जबकि केवल कोयला और प्राकृतिक गैस में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। कोर इंडस्ट्रीज का सूचकांक (ICI), जो IIP का 40.27% हिस्सा है, पिछले साल के उच्च आधार प्रभाव के बोझ तले संघर्ष कर रहा है। अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि अप्रैल का IIP 1% के आसपास रहेगा, जो औद्योगिक गतिविधि में व्यापक मंदी को दर्शाता है।
- दूरसंचार विभाग (DoT) ने UPI लेनदेन से जुड़ी साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI) लॉन्च किया है। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) में एकीकृत, FRI साइबर अपराध पोर्टल, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त इनपुट के आधार पर मोबाइल नंबरों को मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत करता है। फ़ोनपे, पेटीएम और गूगल पे जैसे प्रमुख UPI प्लेटफॉर्म पहले से ही वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए इन अलर्ट को शामिल कर रहे हैं, जिससे यह भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा उपाय बन गया है।
- मजबूत राजस्व वृद्धि, रणनीतिक लागत प्रबंधन और बुनियादी ढांचे और स्पेक्ट्रम में रिकॉर्ड-तोड़ निवेश की बदौलत बीएसएनएल ने वित्त वर्ष 2024-25 में लगातार तिमाही लाभ दर्ज करके वित्तीय बदलाव हासिल किया है। हालांकि उच्च मूल्यहास के कारण अल्पकालिक लाभ में उतार-चढ़ाव हो सकता है, लेकिन कंपनी के मूल तत्व ठोस हैं और आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत 4जी/5जी की तैनाती के लिए इसकी प्रतिबद्धता एक टिकाऊ और समावेशी दूरसंचार भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रही है। वार्षिक घाटे में 58% की कमी, परिसंपत्ति मुद्रीकरण में 77% की वृद्धि और EBITDA मार्जिन में 13-प्रतिशत-बिंदु वृद्धि जैसे प्रमुख मीट्रिक बीएसएनएल के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को चिह्नित करते हैं।

- अप्रैल 2025 में भारत की औद्योगिक गतिविधि वृद्धि आठ महीनों में सबसे कम हो गई, जो प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में मंदी का संकेत है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में केवल 2.7% की वृद्धि हुई, जबकि मार्च 2025 में वृद्धि दर 5.8% और अगस्त 2024 में 0.1% की गिरावट थी, जब पिछली बार वृद्धि इतनी सुस्त थी।
- भारत की विमानन विनिर्माण क्षमताएं और भी अधिक बढ़ने वाली हैं, क्योंकि टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएसएसएल) और यूरोपीय एयरोस्पेस डिगगज एयरबस ने देश की पहली निजी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन (एफएएल) स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है। इस रणनीतिक कदम से भारत वैश्विक एयरोस्पेस मानचित्र पर आ गया है, जिससे स्वदेशी रक्षा और विमानन विनिर्माण केंद्र बनने की इसकी महत्वाकांक्षा को बल मिला है।
- बेंगलुरु स्थित पालतू पशुओं के भोजन की कंपनी डूल्स आधिकारिक तौर पर यूनिकॉर्न (1 बिलियन डॉलर या उससे अधिक मूल्य का स्टार्टअप) बन गई है। ऐसा तब हुआ जब प्रसिद्ध स्विस् कंपनी नेस्ले ने डूल्स का एक छोटा हिस्सा खरीदा। इस सौदे के साथ, डूल्स 2025 में नेट्राडाइन, पोर्टर और जेएसडब्ल्यू वन प्लेटफॉर्म के बाद यूनिकॉर्न का दर्जा पाने वाला चौथा भारतीय स्टार्टअप बन गया है।

अर्थव्यवस्था/व्यापार करंट अफेयर्स: अप्रैल 2025

अप्रैल 2024 के अनुसार जीडीपी और विकास दर

- भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकारी और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) की सीमा में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। अपरिवर्तित सीमा – केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए 6%, राज्य ऋणों के लिए 2% और कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए 15% हैं।
- भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह मार्च 2025 में साल-दर-साल (YoY) 9.9% की मजबूत वृद्धि के साथ ₹1.96 लाख करोड़ तक पहुँच गया। यह वृद्धि मजबूत आर्थिक गतिविधियों और कर अनुपालन में सुधार को दर्शाती है।
- भारत के कोर सेक्टर की वृद्धि फरवरी 2025 में घटकर 2.9% रह गई, जो पिछले पांच महीनों में सबसे धीमी दर है। यह गिरावट फरवरी 2024 में दर्ज 7.1% की वृद्धि की तुलना में काफी कम है। आठ प्रमुख उद्योगों में से केवल तीन उद्योगों में मासिक उत्पादन में वृद्धि हुई, जबकि सिर्फ सीमेंट और उर्वरक ऐसे क्षेत्र थे, जिन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक उत्पादन दर्ज किया। कोर सेक्टर में यह मंदी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की वृद्धि को प्रभावित कर सकती है, जिसने जनवरी 2025 में 5% की वृद्धि दर्ज की थी।
- भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद लचीलेपन के साथ वृद्धि दर्ज कर रही है। एशियाई विकास आउटलुक (ADO) अप्रैल 2025 के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण घरेलू मांग में वृद्धि, ग्रामीण आय में सुधार, और मुद्रास्फीति में नरमी है। एशियाई विकास बैंक (ADB) का मानना है कि यह वृद्धि की गति वित्त वर्ष 2026 में भी बनी रहेगी, और GDP वृद्धि दर 6.8% रहने की संभावना है। इसका समर्थन अनुकूल राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों से होगा। हालाँकि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वैश्विक व्यापार चुनौतियों और नीतिगत अनिश्चितताओं का हवाला देते हुए अपना अनुमान थोड़ा घटाकर 6.5% कर दिया है।





- भारत की औद्योगिक गतिविधि फरवरी 2025 में स्पष्ट रूप से धीमी पड़ी, जहाँ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) केवल 2.9% की वृद्धि दर्ज कर पाया — जो कि पिछले छह महीनों में सबसे कम है। यह गिरावट मुख्यतः खनन, निर्माण और बिजली क्षेत्रों में सुस्त वृद्धि और पिछले वर्ष के उच्च आधार प्रभाव के कारण देखी गई। हालांकि अधिकांश उपयोग-आधारित वर्गों में उत्पादन कम हुआ, लेकिन पूंजीगत वस्तुएं एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहीं जहाँ उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नए वित्तीय वर्ष की पहली नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दरों में कटौती की घोषणा की है। 7 से 9 अप्रैल 2025 के बीच हुई 54वीं बैठक में समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 6% करने का निर्णय लिया, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। इसके साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) दर को 5.75% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) व बैंक दर को 6.25% कर दिया गया है।
- भारत में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीति मार्च 2025 में घटकर 2.05% रह गई, जो फरवरी 2025 में 2.38% थी। यह जानकारी 15 अप्रैल 2025 को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में दी गई। मुद्रास्फीति में यह गिरावट मुख्य रूप से सब्जियों की कीमतों में तीव्र गिरावट के कारण हुई, जिससे सब्जियों में 15.88% की ऋणात्मक मुद्रास्फीति (deflation) दर्ज की गई। हालांकि खाद्य वस्तुओं में कुल मिलाकर मुद्रास्फीति में कमी आई, लेकिन निर्मित उत्पादों की कीमतों में वृद्धि देखी गई। मार्च में निर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति 3.07% रही, जो फरवरी में 2.86% थी। आंकड़ों से स्पष्ट है कि मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति मिश्रित रही—एक ओर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई, वहीं ईंधन, बिजली और निर्मित वस्तुओं जैसे क्षेत्रों में दाम बढ़े।
- भारत के बैंकिंग क्षेत्र में वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में 12-13% की ऋण वृद्धि (क्रेडिट ग्रोथ) होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए अनुमानित 11-11.5% वृद्धि से थोड़ा अधिक है। क्रिसिल रेटिंग्स द्वारा साझा की गई इस सकारात्मक भविष्यवाणी के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि अनुकूल विनियामक उपाय, कर कटौती के कारण उपभोग में वृद्धि, और ब्याज दरों में नरमी।
- भारत की फार्मास्युटिकल उद्योग ने वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जहां दवा और फार्मा निर्यात पहली बार \$30 अरब के पार पहुंच गया है। मार्च 2025 में 31% की वार्षिक वृद्धि ने इस लक्ष्य को पार करने में अहम भूमिका निभाई, जिससे \$29.38 अरब के वार्षिक लक्ष्य को पीछे छोड़ दिया गया। यह उल्लेखनीय वृद्धि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और संभावित अमेरिकी टैरिफ जैसी चुनौतियों के बीच भी संभव हो पाई, जो सौभाग्यवश फार्मा निर्यात को प्रभावित नहीं कर सकीं। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहा, जबकि यूके, ब्राज़ील और फ्रांस जैसे अन्य प्रमुख बाजारों ने भी सीमित लेकिन स्थिर योगदान दिया।
- मार्च 2025 में भारत के कोर सेक्टर (मूलभूत क्षेत्र) के उत्पादन में वर्ष-दर-वर्ष 3.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसका प्रमुख कारण बढ़ते तापमान और समय से पहले शुरू हुई गर्मी की लहरों के कारण बिजली उत्पादन में इज़ाफा रहा। यह प्रदर्शन फरवरी 2025 की 3.4% वृद्धि की तुलना में थोड़ा बेहतर है, लेकिन मार्च 2024 में दर्ज की गई 6.3% की वृद्धि से कम है। देश की आठ प्रमुख आधारभूत उद्योगों — कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट

और बिजली — औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में 40.27% का योगदान करती हैं।

- घरेलू इस्पात उद्योग को संरक्षण देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने चुनिंदा श्रेणियों की इस्पात आयात पर 12% की अस्थायी सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की घोषणा की है। यह निर्णय 21 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गया है और इसका उद्देश्य विशेष रूप से चीन, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों से हो रहे कम लागत वाले इस्पात आयात में आई तेज़ बढ़ोतरी को रोकना है। इस कदम को उद्योग जगत की उन बढ़ती चिंताओं के जवाब के रूप में देखा जा रहा है, जिनमें अनुचित प्रतिस्पर्धा और बाज़ार के असंतुलन की बात उठाई जा रही थी। सरकार का यह फैसला घरेलू निर्माताओं को राहत देने और इस्पात क्षेत्र की स्थिरता बनाए रखने की दिशा में एक ठोस प्रयास माना जा रहा है।

अर्थव्यवस्था समाचार

- भारत के कोर सेक्टर की वृद्धि फरवरी 2025 में घटकर 2.9% रह गई, जो पिछले पांच महीनों में सबसे धीमी दर है। यह गिरावट फरवरी 2024 में दर्ज 7.1% की वृद्धि की तुलना में काफी कम है। आठ प्रमुख उद्योगों में से केवल तीन उद्योगों में मासिक उत्पादन में वृद्धि हुई, जबकि सिर्फ सीमेंट और उर्वरक ऐसे क्षेत्र थे, जिन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक उत्पादन दर्ज किया। कोर सेक्टर में यह मंदी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की वृद्धि को प्रभावित कर सकती है, जिसने जनवरी 2025 में 5% की वृद्धि दर्ज की थी।
- भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद लचीलेपन के साथ वृद्धि दर्ज कर रही है। एशियाई विकास आउटलुक (ADO) अप्रैल 2025 के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण घरेलू मांग में वृद्धि, ग्रामीण आय में सुधार, और मुद्रास्फीति में नरमी है। एशियाई विकास बैंक (ADB) का मानना है कि यह वृद्धि की गति वित्त वर्ष 2026 में भी बनी रहेगी, और GDP वृद्धि दर 6.8% रहने की संभावना है। इसका समर्थन अनुकूल राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों से होगा। हालाँकि, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वैश्विक व्यापार चुनौतियों और नीतिगत अनिश्चितताओं का हवाला देते हुए अपना अनुमान थोड़ा घटाकर 6.5% कर दिया है।

व्यापार समाचार

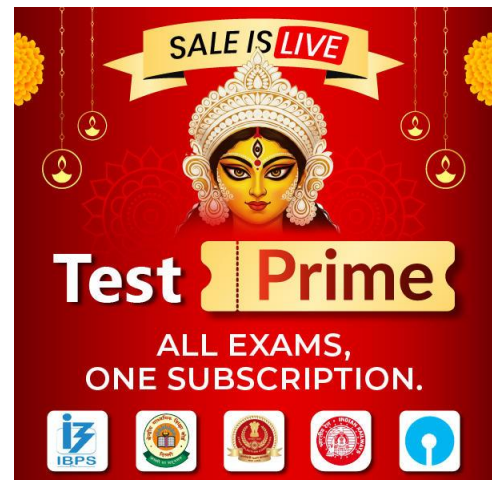
- टैरिफ एक ऐसा कर है जो सरकार दूसरे देशों से आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर लगाती है। जब ये उत्पाद अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हैं, तो उन्हें आयात करने वाले व्यवसाय को आयात करने वाले देश की सरकार को यह कर चुकाना पड़ता है।
- 5 अप्रैल, 2016 को शुरू की गई स्टैंड-अप इंडिया योजना ने हाशिए पर पड़े उद्यमियों को सशक्त बनाने के सात साल पूरे कर लिए हैं, जिसके तहत 61,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। आज्ञादी का अमृत महोत्सव के बैनर तले वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित इस पहल को अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।





- बेंगलुरु स्थित पेमेंट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी Juspay ने 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त किया है। कंपनी ने सीरीज़ D फंडिंग राउंड में \$60 मिलियन (लगभग ₹500 करोड़) जुटाए हैं। इस निवेश दौर का नेतृत्व Kedaara Capital ने किया, जिसमें मौजूदा निवेशकों SoftBank और Accel ने भी भाग लिया।
- दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजर कंपनी ब्लैकरॉक (BlackRock) ने भारत के अडानी ग्रुप (Adani Group) द्वारा जारी किए गए 750 मिलियन डॉलर के प्राइवेट बॉन्ड को सब्सक्राइब किया है। इस डील में कई प्रमुख अमेरिकी और यूरोपीय निवेशकों ने भी भाग लिया है, जो अडानी समूह में निवेशकों के विश्वास की सतर्क लेकिन उल्लेखनीय वापसी को दर्शाता है। यह पूंजी अडानी की सहायक कंपनी रिन्यू एक्सिम (Renew Exim) को प्रदान की जाएगी, जो आईटीडी सिमेंटेशन (ITD Cementation) के अधिग्रहण में उपयोग की जाएगी।
- फिनटेक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी Razorpay ने अपने Turbo UPI प्लगइन का अनावरण किया है, जिसे NPCI BHIM Services Limited (NBSL) और Axis Bank के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। इस समाधान में BHIM Vega प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है, जिससे लेन-देन के दौरान बाहरी रीडायरेक्शन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और उपयोगकर्ता सीधे ऐप के भीतर ही भुगतान पूरा कर सकते हैं। यह उन्नत UPI समाधान भुगतान विफलताओं को कम करने, लेन-देन की गति बढ़ाने, विश्वसनीयता में सुधार करने तथा एक सहज उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जो भारत में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित कर रहा है।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) ने एक महत्वपूर्ण नियामकीय कार्रवाई के तहत Gensol Engineering Ltd (GEL) और इसके प्रवर्तकों, अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी को प्रतिभूति बाजार में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। यह कार्रवाई कंपनी में गंभीर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चूक और फंड डायवर्जन (धन के ग़लत इस्तेमाल) के कारण की गई है। SEBI को जून 2024 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें शेयर की कीमतों में हेरफेर और कंपनी के धन का दुरुपयोग उजागर किया गया था। यह मामला नियामक संस्थाओं द्वारा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और निवेशकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के एक अहम उदाहरण के रूप में सामने आया है।
- एक रणनीतिक ब्रांडिंग पहल के तहत, मिल्कफेड पंजाब, जो भारत की सबसे बड़ी राज्य स्तरीय दुग्ध सहकारी संस्थाओं में से एक है, ने अपनी प्रमुख डेयरी ब्रांड वेरका (Verka) के लिए एक नया मास्कट 'वीरा' लॉन्च किया है। यह पहल वेरका की पहचान को देश और विदेशों में और अधिक मजबूत करने तथा बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है, जैसा कि वर्षों से अमूल गर्ल के माध्यम से अमूल ने किया है। वीरा, एक मुस्कुराता हुआ, हाथ जोड़े खड़ा नन्हा सिख बालक, पंजाब की गर्मजोशी, परंपरा और मेहमाननवाज़ी का प्रतीक है। यह शुभारंभ अमृतसर में ₹135 करोड़ की डेयरी विस्तार परियोजना की

- आधारशिला रखने के साथ हुआ, जो वेरका के संचालन के आधुनिकीकरण और इसके विस्तार के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- Zepto, जो भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते क्लिक-कॉमर्स स्टार्टअप्स में से एक है, ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने हाल ही में अपनी मूल कंपनी का नाम आधिकारिक रूप से बदल लिया है। अब इसे किरणाकार्ट टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड के बजाय Zepto प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा। यह बदलाव कंपनी की उपभोक्ता ब्रांड पहचान के अनुरूप किया गया है। यह नाम परिवर्तन हाल ही में मुंबई स्थित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ (RoC) द्वारा स्वीकृत किया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि कंपनी अब अपने ब्रांड की पहचान और हितधारकों की रणनीति को IPO से पहले और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर है।
- साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) भारत के खनन क्षेत्र में इतिहास रच रहा है, क्योंकि यह देश का पहला कोयला सार्वजनिक उपक्रम (PSU) बन गया है जो भूमिगत कोयला खनन के लिए पेस्ट फिल तकनीक को लागू कर रहा है। यह अत्याधुनिक पहल भारत के कोयला उद्योग में सतत और पर्यावरण-सम्मत खनन प्रथाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। इस नवाचारी तकनीक को अपनाने से सतही बाधाओं वाले क्षेत्रों में भी कोयले का सुरक्षित और कुशल दोहन संभव होगा, साथ ही इससे पर्यावरणीय प्रभाव को भी न्यूनतम किया जा सकेगा।
- भारत ने अपने आंतरिक जल परिवहन (IWT) क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान देश ने 145.5 मिलियन टन (MMT) कार्गो परिवहन दर्ज किया, जो वित्तीय वर्ष 2013-14 में मात्र 18.1 MMT था। इस उल्लेखनीय वृद्धि के पीछे व्यापक बुनियादी ढांचा विकास, नीति सुधारों और तकनीकी नवाचारों का योगदान है। भारत ने अपने राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 5 से बढ़ाकर 111 कर दी है और परिचालन लंबाई लगभग 4,900 किलोमीटर तक बढ़ा दी है, जो बहु-मॉडल लॉजिस्टिक्स और सतत विकास के प्रति देश की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।





रक्षा संबंधी करंट अफेयर्स

रक्षा संबंधी करंट अफेयर्स: सितम्बर 2025

अभ्यास

अभ्यास/कार्यक्रम का नाम	स्थल / भाग लेने वाले देश	मुख्य बिंदु
युद्ध कौशल 3.0	कामेंग क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश (भारत)	भारतीय सेना का व्यापक अभ्यास; ड्रोन, एआई-सक्षम रणनीति, सटीक हमले, स्वदेशी हथियार और नागरिक-रक्षा उद्योग समन्वय का प्रदर्शन; आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत।
युद्ध अभ्यास 2025	फोर्ट वेनराइट, अलास्का (भारत-अमेरिका संयुक्त अभ्यास)	21वाँ संस्करण (1-14 सितम्बर 2025); आर्कटिक युद्धकला, पारस्परिक सहयोग, बहु-क्षेत्रीय संचालन पर फोकस; भारतीय टुकड़ी मद्रास रेजीमेंट से।
मैत्री-XIV	मेघालय, भारत (भारत-थाईलैंड)	संयुक्त अभ्यास; 120 भारतीय सैनिक (मद्रास रेजीमेंट) और 53 रॉयल थाई आर्मी कर्मी; 14 सितम्बर 2025 तक आयोजन।
ज़ापाद अभ्यास 2025	मुलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड, रूस (बहुपक्षीय)	भारत ने 65-सदस्यीय दल भेजा (कुमाऊँ रेजीमेंट); 10-16 सितम्बर 2025; पारस्परिक सहयोग पर केंद्रित।
अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025	दिल्ली कैंट, भारत; 17 एनसीसी निदेशालय	12-दिवसीय शिविर; 1,547 कैडेट्स की भागीदारी; हथियार प्रशिक्षण व नक्शा-पढ़ाई शामिल; पंजाब और कर्नाटक को शीर्ष सम्मान।
सीजीजीएस 2025 (कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट)	भारत द्वारा मेज़बानी; वैश्विक सहभागिता	भारत ने समुद्री सुरक्षा का प्रदर्शन किया और 2027 में अगले शिखर सम्मेलन की मेज़बानी का प्रस्ताव दिया।

सौदे और समझौता ज्ञापन

संगठन	सहयोग संस्थाएँ	उद्देश्य / मुख्य बिंदु
DRDO	BHEL, JSPL, SAIL और अन्य	उन्नत सामग्री प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण ताकि आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाई जा सके।

सेना, नौसेना और वायु सेना समाचार

- भारतीय सेना ने एआई-सक्षम रणनीति और स्वदेशी हथियार प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास आयोजित किया।
- भारतीय सेना की टुकड़ी (मद्रास रेजीमेंट) अमेरिकी सेना के साथ अलास्का में युद्ध अभ्यास 2025 के लिए रवाना हुई।
- भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना ने मेघालय में मैत्री-XIV अभ्यास शुरू किया।
- एयर मार्शल संजीव घुराटिया, एवीएसएम, वीएसएम ने भारतीय वायुसेना मुख्यालय में एयर ऑफिसर-इन-चार्ज मेटेनेंस का पदभार ग्रहण किया; उनके पास संयुक्त राष्ट्र मिशन के अनुभव सहित 37 वर्षों का सेवा अनुभव है।
- डीआरडीओ ने उत्पादन के लिए उन्नत रक्षा सामग्री प्रौद्योगिकियों को स्थानांतरित करके भारतीय उद्योगों के साथ भागीदारी की।
- अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 का समापन: दिल्ली कैंट में 12 दिवसीय एनसीसी शिविर का समापन हुआ, जिसमें 17 निदेशालयों के 1,547 कैडेटों ने हथियार चलाने और मानचित्र पढ़ने की प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिसमें पंजाब और कर्नाटक निदेशालयों ने शीर्ष सम्मान प्राप्त किया।
- भारतीय नौसेना ने समुद्री अभियानों को बढ़ावा देने के लिए आईएनएस अरावली को एक प्रमुख संचार और एमडीए बेस के रूप में कमीशन किया।
- भारत ने सीजीजीएस 2025 में समुद्री सुरक्षा का प्रदर्शन किया और 2027 में अगले शिखर सम्मेलन की मेज़बानी का प्रस्ताव रखा।
- टीएसएल ने 145 मिलियन डॉलर के सौदे के तहत एक युद्धपोत पर पहला स्वदेशी एकीकृत लांज़ा-एन 3डी रडार स्थापित किया।

रक्षा संबंधी करंट अफेयर्स: अगस्त 2025

अभ्यास

अभ्यास / अभियान का नाम	स्थान / सहभागी देश	प्रमुख बिंदु
सिम्बेक्स 2025 (SIMBEX)	भारत - सिंगापुर (दक्षिण चीन सागर)	भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य नौसेना ने 28 जुलाई से 1 अगस्त तक संयुक्त अभ्यास किया। इसमें युद्धपोत, विमान और पेशेवर आदान-प्रदान शामिल रहे। यह 32वाँ संस्करण था जिसने समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत किया। साथ ही, दोनों देशों ने कूटनीतिक संबंधों के 60 वर्ष भी पूरे किए।
स्लिनैक्स-25 (SLINEX-25)	भारत - श्रीलंका (कोलंबो)	INS राणा और INS ज्योति श्रीलंका पहुँचे। भारत-श्रीलंका के बीच 12वाँ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ। उद्देश्य - इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना, समुद्री सहयोग और सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान।





अभ्यास / अभियान का नाम	स्थान / सहभागी देश	प्रमुख बिंदु
ऑपरेशन अलर्ट (Operation Alert)	राजस्थान सीमा (भारत)	सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने 11 से 17 अगस्त 2025 तक स्वतंत्रता दिवस पूर्व उच्च तीव्रता सुरक्षा अभियान चलाया। इसमें SOPs का अभ्यास, गश्त तेज़ करना, तकनीक आधारित निगरानी और 15 अगस्त को पूर्ण बल तैनाती शामिल रही।

टेस्टिंग

- डीआरडीओ ने 23 अगस्त 2025 को ओडिशा तट पर एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (आईएडीडब्ल्यूएस) का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। स्वदेशी क्यूआरएसएम, वीएसएचओआरएडीएस मिसाइलों और एक लेज़र-आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार (डीईडब्ल्यू) से युक्त इस बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली ने यूएवी और ड्रोन सहित कई हवाई लक्ष्यों को एक साथ नष्ट करके अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। एक केंद्रीकृत कमांड सेंटर द्वारा नियंत्रित, इस प्रणाली का प्रदर्शन वृत्तिहीन था।

सौदे और समझौता ज्ञापन

- भारत को स्पेन से अंतिम एयरबस C-295MW परिवहन विमान प्राप्त हुआ, जिससे 2021 के अनुबंध के तहत पहले 16 विमानों की आपूर्ति पूरी हो गई। 11 घंटे की उड़ान क्षमता के साथ 5-10 टन भार ले जाने में सक्षम यह विमान भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो बेड़े की जगह लेगा। शेष 40 विमानों का निर्माण भारत में बड़ोदरा स्थित टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा, जो सैन्य विमानों के लिए भारत की पहली निजी अंतिम असेंबली लाइन है। यह कार्यक्रम मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है और विमानन विनिर्माण में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने भारत की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए ₹67,000 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। भारतीय सेना के लिए, रात्रि गतिशीलता बढ़ाने हेतु वीएमपी के लिए थर्मल इमेजर-आधारित ड्राइवर नाइट साइट्स को मंजूरी दी गई है। भारतीय नौसेना कॉम्पैक्ट ऑटोनॉमस सरफेस क्राफ्ट, ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम खरीदेगी और बराक-1 मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड करेगी। भारतीय वायु सेना को माउंटेन रडार और सक्षम व स्पाइडर हथियार प्रणालियों का अपग्रेड मिलेगा।
- सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने स्वतंत्रता दिवस से पहले, 11 से 17 अगस्त, 2025 तक राजस्थान सीमा पर एक उच्च-तीव्रता वाला सुरक्षा अभियान, ऑपरेशन अलर्ट, शुरू किया है। यह अभियान सीमा सुरक्षा को मजबूत करने, मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पूर्वाभ्यास करने, और गहन गश्त, तकनीक-आधारित निगरानी और 15 अगस्त को पूरी ताकत से तैनाती के ज़रिए संभावित खतरों का मुकाबला करने पर केंद्रित है।
- भारत ने भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए 97 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों के लिए ₹62,000 करोड़ के सौदे को मंजूरी दे दी है, जिससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत स्वदेशी रक्षा निर्माण को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। 65% से ज़्यादा स्वदेशी कलपुर्जों वाले ये विमान पुराने पड़ चुके मिग-21 विमानों की जगह लेंगे, जिससे भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 1A बेड़े में विमानों की कुल संख्या बढ़कर 180 हो जाएगी। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा विकसित इस विमान में उन्नत एवियोनिक्स और रडार सिस्टम लगे हैं।
- भारत, पाँचवीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) के लिए उन्नत जेट इंजन के घरेलू निर्माण हेतु फ्रांस की सफ़्रान कंपनी के साथ साझेदारी कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा घोषित इस सहयोग का उद्देश्य वर्तमान वैश्विक मानकों से भी बेहतर, 110 किलो न्यूटन के शक्तिशाली थ्रस्ट वाला एक नया इंजन विकसित करना है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित और DRDO द्वारा समर्थित यह परियोजना एक दशक से चल रही है और भारत की रक्षा तकनीक को बढ़ावा देने और एयरोस्पेस निर्माण में आत्मनिर्भरता लाने की 15,000 करोड़ रुपये की योजना का एक हिस्सा है।
- भारत 'एक्सरसाइज़ ब्राइट स्टार 2025' (Exercise Bright Star 2025) में भाग लेने के लिए 700 से अधिक सैनिकों को तैनात करने जा रहा है। यह एक प्रमुख त्रि-सेवा (श्री-सर्विस) बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जो 28 अगस्त से 10 सितंबर तक मित्र में आयोजित होगा। यह कदम वैश्विक सैन्य सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- भारत के विशाल पूर्व सैनिक समुदाय के कल्याण को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ़ इंडिया (QCI) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य पूरे देश में 63 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएँ, पुनर्वास और अन्य कल्याणकारी सेवाएँ बेहतर ढंग से उपलब्ध कराना है।
- सैन्य वर्चस्व में वायु शक्ति हमेशा से निर्णायक रही है। अमेरिका ने जहाँ लंबी दूरी की हमलावर क्षमता दिखाने के लिए B-2 स्पिरिट और अब आने वाले B-21 रेडर जैसे स्टील्थ बॉम्बर विकसित किए हैं, वहीं चीन कथित तौर पर अपना छठी पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर बना रहा है, जिसे "व्हाइट एम्परर" कहा जा रहा है।
- भारत की समुद्री रक्षा क्षमता को नई शक्ति देने की दिशा में भारतीय नौसेना 26 अगस्त 2025 को विशाखापट्टनम नौसैनिक अड्डे पर प्रोजेक्ट-17A की दो उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट्स—आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि—को कमीशन करने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में होने वाला यह अनोखा डुअल कमीशनिंग पहली बार होगा जब अलग-अलग भारतीय शिपयार्ड्स में निर्मित दो बड़े सतही युद्धपोत एक साथ नौसेना में शामिल किए जाएंगे।

सेना, नौसेना और वायु सेना समाचार

- भारतीय नौसेना 26 अगस्त 2025 को विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में दो उन्नत प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट, उदयगिरि और हिमगिरि का जलावतरण करेगी। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) द्वारा निर्मित इन फ्रिगेट्स में डिज़ाइन, स्टील्थ, हथियारों और सेंसर में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जिनमें लगभग 75% स्वदेशी सामग्री है, जो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करता है। उल्लेखनीय है कि उदयगिरि नौसेना के युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किया गया 100वाँ जहाज है।





रक्षा संबंधी करंट अफेयर्स: जुलाई 2025

अभ्यास

अभ्यास का नाम	स्थान / भागीदार देश	प्रमुख बिंदु
जा माता	चेन्नई पोर्ट / जापान	जापानी तटरक्षक जहाज JCGS Itsukushima की यात्रा; संयुक्त प्रशिक्षण, समुद्री अभ्यास, और SAGAR व IIOOP पहल को समर्थन।
एक्सरसाइज टैलिस्मन सेबर 2025	ऑस्ट्रेलिया / 19 देश (भारत पहली बार)	भारत पहली बार भागीदार; 35,000+ सैनिक, लाइव फायरिंग, हवाई व नौसैनिक अभ्यास; हिंद-प्रशांत सहयोग को बढ़ावा।
प्रचंड शक्ति	मेरठ, उत्तर प्रदेश	भारतीय सेना द्वारा हाई-टेक डेमो; AI, ड्रोन, स्वायत्त प्रणाली व 'Year of Tech Absorption' पहल का प्रदर्शन।
पासेक्स (PASSEX)	मुंबई / भारत-ग्रीस	INS तरकश व HS Psara द्वारा अरब सागर में अभ्यास; सामरिक संचालन, हेलिकॉप्टर लैंडिंग व ब्रह्मोस-सज्जित युद्धपोत।
सिमवेक्स 2025	भारत-सिंगापुर	INS दिल्ली व सतपुड़ा की भागीदारी; द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास; एक्ट ईस्ट नीति व SAGAR को मजबूती।
बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025	जोधपुर / भारत-सिंगापुर	शहरी युद्ध, आतंकवाद विरोध, रीयल-टाइम सिमुलेशन; रणनीतिक सहयोग व क्षेत्रीय समन्वय पर बल।

परीक्षण

- भारत ने दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए पूरी तरह से स्वदेशी नौसैनिक हथियार, विस्तारित रेंज एंटी-सबमरीन रॉकेट (ERASR) के उपयोगकर्ता परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा और रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। 23 जून से 7 जुलाई, 2025 के बीच INS कवरत्ती से किए गए इन परीक्षणों में कई रेंजों में 17 रॉकेट लॉन्च शामिल थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय नौसेना और घरेलू रक्षा उद्योग की सराहना करते हुए कहा कि इससे नौसेना की मारक क्षमता बढ़ेगी।
- डीआरडीओ और भारतीय वायु सेना ने ओडिशा तट से सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान से अल्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (बीवीआरएएम) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) सीकर से लैस इस मिसाइल ने दोनों परीक्षणों में उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों पर सटीक निशाना साधा। यह सफलता भारत की रक्षा शक्ति को बढ़ाती है, 'मेक इन इंडिया' पहल का समर्थन करती है और विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करती है।
- लद्दाख में 15,000 फीट की ऊँचाई पर भारतीय सेना द्वारा आकाश प्राइम का सफल परीक्षण भारत की स्वदेशी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अपने उन्नत सीकर, उच्च-ऊँचाई संचालन क्षमता और ऑपरेशन सिंदूर में सिद्ध लड़ाकू भूमिका के साथ, आकाश प्राइम भारत की आत्मनिर्भरता और सीमा रक्षा तत्परता को मजबूत करता है। यह प्रणाली भविष्य में शामिल किए जाने के लिए तैयार है और आधुनिक हवाई खतरों से भारत के आकाश को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
- चांदीपुर रेंज में भारत द्वारा परमाणु क्षमता संपन्न पृथ्वी-II और अग्नि-I मिसाइलों के परीक्षण ने प्रमुख परिचालन मानकों की पुष्टि की और इसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया। डीआरडीओ द्वारा विकसित, दोनों मिसाइलें अपने विश्वसनीय, स्वदेशी डिज़ाइन और सिद्ध प्रभावशीलता के साथ भारत के परमाणु शस्त्रागार को बढ़ाती हैं, और सैन्य तैयारी और सामरिक सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखती हैं।
- भारत के डीआरडीओ ने कुरनूल में यूएवी-लॉन्चड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल (यूएलपीजीएम)-वी3 का सफल परीक्षण किया है, जिससे

ड्रोन-लॉन्चड प्रिसिजन स्ट्राइक क्षमताओं में एक बड़ी वृद्धि हुई है। 12.5 किलोग्राम की यह मिसाइल, दोहरे-श्रस्ट वाले सॉलिड मोटर द्वारा संचालित, दिन-रात लक्ष्यीकरण के लिए इन्फ्रारेड इमेजिंग का उपयोग करती है, दो-तरफ़ा डेटालिंक को सपोर्ट करती है, और कई वारहेड विकल्प प्रदान करती है। एमएसएमई, स्टार्टअप्स और अदानी व बीडीएल जैसी प्रमुख फर्मों के सहयोग से विकसित, यूएलपीजीएम कार्यक्रम के तीन प्रकार हैं, जिनमें वी3 (यूएलएम-ईआर) सबसे उन्नत है। यह उपलब्धि भारत की रक्षा तैयारियों को बढ़ाती है और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों के अनुरूप है।

सौदे और समझौता जापान

- जीई एफ404 इंजन से संचालित एलसीए तेजस एमके 1ए, भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। 2025 के अंत तक 12 जेट विमानों की आपूर्ति की जाएगी। एचएएल की योजना प्रति वर्ष 16 विमानों की है, बशर्ते इंजन समय पर वितरित किए जाएँ। इसमें एईएसए रडार, ईडब्ल्यू सूट और एस्ट्रा जैसी बीवीआर मिसाइलें शामिल हैं। ₹5,375 करोड़ का इंजन सौदा और आगामी ₹67,000 करोड़ का ऑर्डर इस स्वदेशी कार्यक्रम के रणनीतिक महत्व को दर्शाता है।

सेना, नौसेना और वायु सेना समाचार

- रियर एडमिरल वी. गणपति ने भारत के शीर्ष त्रि-सेवा प्रशिक्षण संस्थान, पुणे स्थित सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान (एमआईएलआईटी) के नए कमांडेंट का पदभार ग्रहण कर लिया है। सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण, एकीकरण की दिशा में बढ़ते प्रयासों और अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी शिक्षा की बढ़ती आवश्यकता के मद्देनजर उनकी नियुक्ति महत्वपूर्ण है।
- भारत का नवीनतम स्टील्थ फ्रिगेट, आईएनएस उदयगिरि, 1 जुलाई, 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। प्रोजेक्ट 17ए के तहत रिकॉर्ड 37 महीनों में निर्मित, यह युद्धपोत उन्नत स्टील्थ डिज़ाइन, स्वदेशी हथियार प्रणालियों और समुद्री अभियानों के लिए उपयुक्त बहु-मिशन क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। 200 से अधिक एमएसएमई के योगदान के साथ, यह समावेश भारत के रक्षा स्वदेशीकरण के प्रयासों और उसके नौसैनिक जहाज निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की बढ़ती ताकत को दर्शाता है।





- भारत ने रूस में अत्याधुनिक स्टीलथ ग्राइडेड मिसाइल फ्रिगेट, आईएनएस तमाल का जलावतरण किया है, जो भारतीय नौसेना के लिए विदेश में निर्मित अंतिम प्रमुख युद्धपोत है। प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत निर्मित, तमाल रक्षा स्वदेशीकरण की ओर बदलाव को रेखांकित करता है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल और HUMSA-NG सोनार जैसी प्रणालियों को एकीकृत किया गया है। यह पोत भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाता है और भारत-रूस रक्षा साझेदारी को मजबूत करता है, क्योंकि यह इस सहयोग के तहत निर्मित 51वाँ पोत है। पश्चिमी बेड़े को अब एक शक्तिशाली संपत्ति प्राप्त हुई है, जबकि भविष्य के युद्धपोतों का निर्माण घरेलू स्तर पर किया जाएगा, जिससे भारत अपने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के और करीब पहुँचेगा।
- मेरठ की सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया भारतीय नौसेना में लड़ाकू पायलट के रूप में प्रशिक्षित होने वाली पहली महिला बन गई हैं। उन्हें 3 जुलाई, 2025 को विशाखापत्तनम में एक समारोह में "विंग्स ऑफ़ गोल्ड" से सम्मानित किया गया। अब वह आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत जैसे विमानवाहक पोतों से मिग-29K और राफेल M जैसे लड़ाकू विमान उड़ाने का प्रशिक्षण लेंगी। यह उपलब्धि भारतीय नौसेना के लैंगिक समानता के प्रयासों और रक्षा एवं लड़ाकू विमानन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के उसके उद्देश्य को दर्शाती है।
- 9 जुलाई, 2025 को, भारतीय नौसेना को विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) से, अपना पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल (DSV), INS निस्तार प्राप्त हुआ। 75% स्वदेशी सामग्री के साथ, INS निस्तार 300 मीटर तक गहरे समुद्र में गोता लगा सकता है, DSRV का उपयोग करके फंसे हुए पनडुब्बी चालकों को बचा सकता है, और 1000 मीटर तक के अभियानों के लिए ROV ले जा सकता है। यह आधुनिक जहाज नौसेना के अंडरवाटर मिशन में सहायक है और आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लक्ष्यों को दर्शाता है।
- 18 जुलाई, 2025 को कमीशन किया गया INS निस्तार, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिज़ाइन और निर्मित भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है। यह गहरे समुद्र में गोताखोरी, 300 मीटर तक पनडुब्बी बचाव में सहायक है और DSRV के लिए एक मददरशिप के रूप में कार्य करता है। 80% स्वदेशी सामग्री, 120 से अधिक MSMEs की

- भागीदारी और उन्नत तकनीकों के साथ, यह भारत की पानी के नीचे की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करता है और आत्मनिर्भर भारत मिशन के अनुरूप है।
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन के बाद, भारत मैक्सार जैसी वैश्विक कंपनियों से उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह चित्र प्राप्त करके सैन्य निगरानी बढ़ा रहा है। एसबीएस-III कार्यक्रम का लक्ष्य 2029 तक 52 उपग्रहों को प्रक्षेपित करना है, जिनका संचालन रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जाएगा और जिसका बजट 3.2 बिलियन डॉलर है। यह कदम वास्तविक समय की निगरानी, बेहतर सीमा निगरानी और रणनीतिक तैयारी सुनिश्चित करता है, जबकि डेटा सुरक्षा और बाहरी निर्भरता जैसी चुनौतियाँ बनी रहती हैं।
- भारतीय वायु सेना सितंबर 2025 तक मिग-21 लड़ाकू विमानों को सेवानिवृत्त कर देगी, जिससे उनकी 60 साल की सेवा समाप्त हो जाएगी। 1963 में शामिल किए गए इन सोवियत निर्मित सुपरसोनिक विमानों ने 1971 और कारगिल सहित कई युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जेट इंजन की आपूर्ति में देरी जैसी चुनौतियों के बावजूद, स्वदेशी एलसीए तेजस मार्क 1ए के साथ इनकी जगह लेना आधुनिकीकरण की दिशा में एक कदम है। यह बदलाव आत्मनिर्भर भारत पहल का समर्थन करता है और भारतीय वायु सेना की वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करता है।
- भारतीय सेना को अमेरिका से अपने पहले अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर मिल गए हैं, जिनका उद्देश्य चुनौतीपूर्ण इलाकों में मारक क्षमता को बढ़ाना है। ये अत्याधुनिक हमलावर हेलीकॉप्टर उन्नत लक्ष्यीकरण प्रणाली, सटीक प्रहार क्षमता और रात्रिकालीन संचालन क्षमता से लैस हैं। यह कदम आर्मी एविएशन कोर की स्वायत्तता को बढ़ाता है, रक्षा आधुनिकीकरण को बढ़ावा देता है और सीमाओं पर भारत की सामरिक शक्ति को मजबूत करता है।
- गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) द्वारा निर्मित नियंत्रण पोत (पीसीवी) भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में तेल रिसाव की प्रतिक्रिया और समुद्री प्रदूषण नियंत्रण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए है। 4,170 टन विस्थापन और अत्याधुनिक प्रतिक्रिया उपकरणों के साथ, यह आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करता है, मारपोल के दायित्वों के अनुरूप है, और स्वदेशी जहाज निर्माण एवं तटीय पर्यावरण संरक्षण में एक मील का पत्थर है।

रक्षा संबंधी करंट अफेयर्स: जून 2025

अभ्यास

अभ्यास का नाम	स्थल / भागीदार देश	मुख्य बिंदु
एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ 2025	भारत - गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर, उत्तर प्रदेश भागीदार: भारत (IAF गरुड़ कमांडो), अमेरिका (USAF स्पेशल फोर्स)	- भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो और अमेरिकी वायुसेना के स्पेशल फोर्स के बीच पहला संयुक्त विशेष बल अभ्यास (26 मई - 10 जून, 2025)। - हवाई विशेष अभियान रणनीतियों का आदान-प्रदान और युद्ध तत्परता को बढ़ावा। - युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और कोप इंडिया से परे भारत-अमेरिका सैन्य संबंधों में नई परत।
एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025	मंगोलिया भागीदार: बहुराष्ट्रीय (भारत सहित)	- भारत ने 40-सदस्यीय दल भेजा, जिसमें महिला सैनिक भी शामिल हैं। - संयुक्त राष्ट्र-प्राधिकृत बहुराष्ट्रीय शांति मिशन अभ्यास (14-28 जून, 2025)।





अभ्यास का नाम	स्थल / भागीदार देश	मुख्य बिंदु
		- प्रशिक्षण में नागरिक निकासी, कॉर्डन और सर्च, काउंटर-IED और मेडिकल सहायता शामिल। - भारत की वैश्विक शांति और रक्षा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
साइबर सुरक्षा अभ्यास - साइबर सुरक्षा	भारत आयोजक: डिफेंस साइबर एजेंसी (इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ)	12-दिन का साइबर सुरक्षा अभ्यास; 100+ रक्षा कर्मियों की भागीदारी। - CISO सम्मेलन, खतरा सिमुलेशन और निर्णय निर्माण अभ्यास। - रक्षा क्षेत्र में साइबर लचीलापन और 'साइबर सुरक्षा-प्रथम' संस्कृति को बढ़ावा। - रक्षा मंत्रालय द्वारा इसे नियमित कार्यक्रम बनाया जाएगा।
एक्सरसाइज शक्ति 2025	फ्रांस - कैप लारजैक भागीदार: भारत, फ्रांस	- भारत-फ्रांस सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण। - उप-पारंपरिक युद्ध और आतंकवाद-रोधी संचालन पर केंद्रित। - जम्मू-कश्मीर राइफल्स की 90-सदस्यीय टुकड़ी ने फ्रांस की 13वीं फॉरेन लीजन हाफ-ब्रिगेड के साथ प्रशिक्षण लिया। - संयुक्त राष्ट्र चार्टर VII के तहत शहरी युद्ध स्थितियों का अभ्यास।

परीक्षण

- भारतीय सेना ने सोलर एयरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड (SDAL) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित VTOL ड्रोन रुद्रास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पोखरण रेंज में आयोजित परीक्षणों ने ड्रोन की सटीकता-निर्देशित एयरबस्ट हथियारों के साथ सीमा पार से गहरे हमले करने की क्षमता को प्रमाणित किया। 170 किलोमीटर की कुल रेंज, 1.5 घंटे की धीरज और वास्तविक समय के लाइव वीडियो रिले के साथ, रुद्रास्त्र भारत की स्टैंड-ऑफ स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाता है।
- भारत अपनी तोपखाना शक्ति को बढ़ाने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 300 किलोमीटर तक की रेंज वाली पिनाका रॉकेट प्रणाली के अगली पीढ़ी के बेरिएंट विकसित कर रहा है। DRDO द्वारा विकसित पिनाका-3 और पिनाका-4 सिस्टम सटीक हमले, तेजी से तैनाती और उच्च मात्रा में मारक क्षमता का समर्थन करेंगे। गाइडेड पिनाका के सफल परीक्षणों और 2030 तक 22 रेजिमेंटों को शामिल करने की सेना की योजना के साथ, ये विकास स्वदेशीकरण, आधुनिकीकरण और बढ़ी हुई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं।

डील और एमओयू

सेना, नौसेना और वायु सेना समाचार

- वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता और समुद्री उन्नति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, भारत गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) और नॉर्वे के कोंसबर्ग के बीच रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से अपना पहला स्वदेशी रूप से निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत (पीआरवी) बनाने के लिए तैयार है। यह सहयोग भारत की ध्रुवीय अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करने, इसकी 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग का विस्तार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- भारत अपनी सेना की तोपखाना प्रणालियों को और अधिक आधुनिक, शक्तिशाली और सटीक बनाने के लिए उन्हें उन्नत कर रहा है। कई वर्षों तक भारतीय सेना ने ब्रोफोर्स तोप का इस्तेमाल किया, जिसने कारगिल

युद्ध के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन अब भारत धनुष और ATAGS जैसी नई स्वदेशी तोपों का विकास और उपयोग कर रहा है।

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए, यूरोपीय संघ नौसेना बल (ईयूएनएवीएफओआर) के जहाज - ईएसपीएस रीना सोफिया (स्पेनिश नौसेना) और आईटीएस एंटोनियो मार्सेलिया (इटाली नौसेना) - ने 26 मई से 1 जून, 2025 तक मुंबई में अपना पहला बंदरगाह दौरा किया। यह ऐतिहासिक यात्रा भारत-यूरोपीय संघ की गहरी होती समुद्री साझेदारी को रेखांकित करती है और हाल ही में भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बीच उच्च स्तरीय चर्चा के बाद हुई है।
- भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय सेना ने "रुद्रास्त्र" (Rudrastra) नामक एक वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग (VTOL) मानव रहित हवाई वाहन (UAV) के सफल परीक्षण पूरे किए हैं। यह उन्नत ड्रोन गहराई तक स्ट्राइक मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसे Solar Aerospace and Defence Limited (SDAL) ने विकसित किया है। रुद्रास्त्र की सफलता भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम संकेत है।
- भारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने 12 जून, 2025 को नई दिल्ली में 137वीं अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति (OSCC) की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राष्ट्रीय रक्षा, ऊर्जा और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया। इस बैठक का उद्देश्य भारत के अपतटीय सुरक्षा बुनियादी ढांचे की तैयारियों का आकलन करना और उसे बढ़ाना था, जिसमें उभरते समुद्री और ऊर्जा संबंधी खतरों का जवाब देने के लिए संयुक्त एजेंसी समन्वय पर विशेष जोर दिया गया।
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 जून 2025 को दक्षिण ब्लॉक, नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) के 10 युवा कैडेट्स (5 लड़कियाँ और 5 लड़के) को सम्मानित किया, जिन्होंने विश्व की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। इन कैडेट्स की औसत आयु 19 वर्ष थी। इस अवसर पर उनके साहस, अनुशासन, और अदम्य उत्साह की सराहना की गई।





- भारतीय सेना के 40 सैनिकों का एक दल बुधवार को मंगोलिया पहुंचा। इनमें ज्यादातर सैनिक कुमाऊं रेजीमेंट की एक बटालियन से हैं। यह दल एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 'खान क्रेस्ट' में भाग लेगा। यह सैन्य अभ्यास 14 से 28 जून तक उलानबातर में आयोजित होगा। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी। यह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत शांति अभियानों के लिए भागीदार देशों की परस्पर संचालन क्षमता (interoperability) और संचालनिक तत्परता (operational readiness) बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है।
- भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को सेना उपप्रमुख (रणनीति) – Deputy Chief of Army Staff (Strategy) के पद पर नियुक्त किया गया है। यह पदभार उन्हें सेना की संचालन और खुफिया निदेशालयों की निगरानी का उत्तरदायित्व सौंपता है – जो भारतीय सेना की सबसे रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शाखाओं में से हैं।
- भारत के उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण रणनीतिक यात्रा के दौरान, थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में तैनात सैनिकों की संचालनिक तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ज्योतिरमठ में Ibex Tarana 88.4 FM नामक एक विशेष सामुदायिक रेडियो स्टेशन का भी उद्घाटन किया। यह पहल राष्ट्रीय सुरक्षा को सामुदायिक सशक्तिकरण से जोड़ने का एक अनूठा उदाहरण है।
- भारत अब अपनी तोपखाना क्षमताओं को एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी में है, क्योंकि जल्द ही पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के नए दीर्घ-मार्गी (लॉन्ग-रेंज) संस्करण शामिल किए जाएंगे, जो 300 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम होंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित यह प्रणाली सटीक हमलों, तेज़ तैनाती और अधिक मारक क्षमता को समर्थन देगी — जो भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
- भारत की तृतीय सुरक्षा क्षमताओं को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए, भारतीय नौसेना ने INS अर्नाला (INS Arnala) को विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में 18 जून 2025 को आधिकारिक रूप से कमीशन किया। यह पहला एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC) है और इसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की उपस्थिति में नौसेना में शामिल किया गया। 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित यह उन्नत पोत हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत के समुद्री हितों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण छलांग है।
- डिफेंस साइबर एजेंसी (Defence Cyber Agency) ने 16 जून 2025 को 'Cyber Suraksha' नामक एक बहु-चरणीय साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण अभ्यास की शुरुआत की। यह 12 दिवसीय कार्यक्रम (16 जून से 27 जून 2025 तक) रक्षा और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े 100 से अधिक प्रतिभागियों को वास्तविक साइबर खतरों का अनुकरण कर साइबर सुरक्षा, लचीलापन (resilience) और रणनीतिक निर्णय क्षमता का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA), रोमानिया के साथ साझेदारी में, ConvEx-3 नामक अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित कर रही है। 36 घंटे का यह अभ्यास रोमानिया की एकमात्र परमाणु ऊर्जा सुविधा, सेर्नबोडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक गंभीर परमाणु दुर्घटना का अनुकरण करता है। इसका उद्देश्य सरल लेकिन महत्वपूर्ण है – रेडियोलॉजिकल आपदा की स्थिति में वैश्विक आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं का आकलन करना।
- पेंटागन ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के क्रियान्वयन की घोषणा की, जो ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किया गया एक अत्यधिक गोपनीय सैन्य अभियान है। यह घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा दो सप्ताह की स्व-निर्धारित समय सीमा को समाप्त करने के कुछ ही दिनों बाद हुई, जो तेहरान के प्रति अमेरिकी रुख में एक नाटकीय बदलाव का संकेत है।

रक्षा संबंधी करंट अफेयर्स: मई 2025

अभ्यास

अभ्यास का नाम	स्थान / भागीदार देश	मुख्य बिंदु
HADR अभ्यास	भारत-मालदीव	INS शारदा की मालदीव यात्रा क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन और रक्षा कूटनीति में भारत की सक्रिय भूमिका को दर्शाती है। यह भारत की "महासागर (MAHASAGAR)" दृष्टि से मेल खाता है और खोज-बचाव, चिकित्सा सहायता एवं संयुक्त अभ्यासों के माध्यम से भारत-मालदीव संबंधों को मजबूत करता है।
IMDEX Asia 2025	सिंगापुर	INS किलटन की भागीदारी भारत की समुद्री कूटनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा में प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 70 से अधिक देशों की नौसेनाओं की उपस्थिति में यह मंच रणनीतिक संवाद, स्वदेशी क्षमताओं का प्रदर्शन और सहयोग को बढ़ावा देता है।
टेबलटॉप अभ्यास	क्वाड देश (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया)	होनोलूलू में आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य Indo-Pacific Logistics Network (IPLN) की शुरुआत है। इसका उद्देश्य नागरिक आपदा प्रतिक्रिया में साझा लॉजिस्टिक्स को सशक्त करना है। यह स्वतंत्र और मुक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति क्वाड की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
नोमैडिक एलिफेंट (NOMADIC ELEPHANT)	भारत-मंगोलिया	यह भारत-मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वाँ संस्करण है जो 31 मई से 13 जून 2025 तक उलानबातर, मंगोलिया में आयोजित हो रहा है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सामरिक और परिचालन तालमेल को बढ़ाना है।
ऑपरेशन अभ्यास	कर्नाटक राज्य अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएँ	बेंगलुरु में आयोजित यह माँक डिल नागरिक सुरक्षा के लिए की गई, जिसमें अग्निशमन, बचाव, और सार्वजनिक जागरूकता को शामिल किया गया। यह हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के संदर्भ में राष्ट्रीय आपातकालीन तैयारियों को परखने के लिए आयोजित किया गया था।
गोल्डन ड्रैगन-2025	चीन-कंबोडिया	कंबोडिया में आयोजित यह संयुक्त सैन्य अभ्यास आतंकवाद-रोधी, मानवीय सहायता और बहु-आयामी सैन्य अभियानों को कवर करता है। इसमें मानव रहित प्रणालियों का उपयोग और रणनीतिक सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने की झलक मिलती है।





टेस्टिंग

- डीआरडीओ ने एडीआरडीई, आगरा द्वारा विकसित अपने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण मध्य प्रदेश के श्योपुर से सफलतापूर्वक किया। एयरशिप ~17 किलोमीटर की स्ट्रेटोस्फेरिक ऊंचाई तक पहुंचा और 62 मिनट तक उड़ान भरी, जिसमें लिफाफा दबाव नियंत्रण और आपातकालीन अपस्फीति प्रणाली जैसी प्रमुख प्रणालियों का परीक्षण किया गया।

सौदा और समझौता ज्ञापन

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर कम विस्फोटकों के साथ लड़ाकू फायरिंग के माध्यम से मल्टी-इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन (MIGM) को सफलतापूर्वक प्रमाणित किया है। NSTL विशाखापत्तनम द्वारा अन्य DRDO प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और अपोलो माइक्रोसिस्टम्स द्वारा निर्मित, इस प्रणाली को आधुनिक स्टील्थ खतरों के खिलाफ भारत की अंडरसी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अपनी तत्परता की पुष्टि के साथ, MIGM भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार है, जो आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा।
- भारतीय नौसेना ने अर्नाला को शामिल किया है, जो पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW SWC) है, जिसे GRSE और L&T शिपयार्ड के बीच पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के माध्यम से विकसित किया गया है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ, यह 77 मीटर का युद्धपोत तटीय रक्षा को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन और माइन बिछाने के लिए। यह डिलीवरी आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करती है और भारत की समुद्री सुरक्षा वास्तुकला को मजबूत करती है।
- भारत का भार्गवस्त्र एक अभूतपूर्व स्वदेशी एंटी-ड्रोन सिस्टम है जो हार्ड-किल माइक्रो रॉकेट, सॉफ्ट-किल जैमिंग और उन्नत सेंसर के मिश्रण का उपयोग करके ड्रोन झुंडों के बढ़ते खतरे का प्रभावी ढंग से मुकाबला करता है। सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड (SDAL) द्वारा विकसित, यह विभिन्न इलाकों में काम कर सकता है और भारत के नेटवर्क-केंद्रित युद्ध बुनियादी ढांचे के साथ सहजता से एकीकृत होता है। यह नवाचार भारत की सीमाओं के पास उभरते हवाई खतरों और हाल ही में शत्रुतापूर्ण ड्रोन घुसपैठ के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने समुद्री जल विलवणीकरण के लिए एक उच्च दबाव वाली नैनोपोरस पॉलीमरिक झिल्ली को सफलतापूर्वक डिज़ाइन किया है, जो रक्षा और समुद्री प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के लिए भारत के अभियान में एक बड़ी सफलता है। DMSRDE द्वारा केवल आठ महीनों में विकसित की गई इस झिल्ली का भारतीय तटरक्षक बल (ICG) के एक अपतटीय गश्ती पोत (OPV) पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह नवाचार खारे पानी में क्लोराइड आयनों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करता है और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है। 500 घंटे के परीक्षण के बाद, इसे भविष्य में नागरिक तटीय उपयोग के लिए परिचालन रूप से तैनात करने की तैयारी है।
- भारतीय नौसेना, संस्कृति मंत्रालय और मेसर्स होदी इनोवेशन के सहयोग से, एक प्राचीन सिले हुए जहाज को शामिल कर रही है, जो अजंता गुफा चित्रों से प्रेरित 5वीं शताब्दी के जहाज की प्रतिकृति है। केरल के कारीगरों द्वारा पारंपरिक हाथ से सिलाई की तकनीक का उपयोग करके बनाया गया और आईआईटी मद्रास द्वारा तकनीकी रूप से समर्थित यह जहाज भारत की समुद्री विरासत और नौसैनिक शिल्प कौशल को दर्शाता है। गुजरात से ओमान तक की योजनाबद्ध यात्रा ऐतिहासिक व्यापार मार्गों को फिर से दर्शाएगी, जिससे एक समुद्री राष्ट्र के रूप में भारत की प्राचीन पहचान को बल मिलेगा।

सेना, नौसेना और वायु सेना समाचार

- भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) ने ऐतिहासिक दोहरे अभियान के तहत दुनिया के पांचवें सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मकालू पर चढ़ाई करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। जबकि माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई का प्रयास बर्फीले तूफान के कारण शिखर के पास ही रुक गया था, मकालू टीम ने 83% सफलता दर हासिल की। अनूप कुमार नेगी के नेतृत्व में पर्वतारोहियों ने 'स्वच्छ हिमालय - ग्लेशियर बचाओ' अभियान के तहत 150 किलोग्राम कचरा एकत्र करके पर्यावरणीय स्थिरता में भी योगदान दिया।
- भारत ने हॉकआई 360 उपग्रह-आधारित आरएफ निगरानी तकनीक के लिए अमेरिका के साथ 131 मिलियन डॉलर के समझौते को अंतिम रूप दिया है, जिससे समुद्री गतिविधि की निगरानी करने और अंधेरे जहाजों का पता लगाने की इसकी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह सौदा क्वाड लक्ष्यों का समर्थन करता है और भारत के तटीय सुरक्षा ढांचे को बढ़ावा देता है, खासकर इसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में। P-8I विमान और IFC-IOR जैसी मौजूदा प्रणालियों के साथ एकीकृत, यह तकनीक 24/7 वास्तविक समय, मौसम-प्रूफ निगरानी प्रदान करती है। यह विकास इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका-भारत रणनीतिक रक्षा सहयोग में एक नया अध्याय है।
- भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के ने नाविका सागर परिक्रमा II के तहत एक ऐतिहासिक परिक्रमा पूरी की है, जिसमें आठ महीनों में INS तारिणी पर 25,400 समुद्री मील की दूरी तय की गई। इस यात्रा ने नारी शक्ति का उदाहरण पेश किया, चक्रवाती समुद्रों को सहन किया और वैश्विक समुद्री कूटनीति को बढ़ावा दिया। उनका मिशन 29 मई, 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में मोरमुगाओ बंदरगाह पर समाप्त होगा, जो भारत की नौसेना और लिंग-समावेशी विरासत में एक गौरवपूर्ण क्षण है।
- हरित विमानन और स्वदेशी तकनीकी नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत ने इलेक्ट्रिक हंसा (ई-हंसा) का विकास शुरू किया है - यह अगली पीढ़ी का दो सीटों वाला इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान है। इस पहल का खुलासा केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने विज्ञान विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान किया।
- रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने तीन प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) - म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल), आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (एवीएनएल) और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल) को "मिनीरत्न" श्रेणी-I का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। यह मान्यता तीन वर्षों की छोटी अवधि के भीतर लाभ कमाने वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं में उनके तेजी से परिवर्तन को मान्यता देती है।





अभ्यास

अभ्यास का नाम	स्थान / भागीदार देश	मुख्य बिंदु
INIOCHOS-25	ग्रीस / 15 देश	भारतीय वायुसेना ने 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक एंड्राविडा एयर बेस, ग्रीस में बहुराष्ट्रीय अभ्यास INIOCHOS-25 में हिस्सा लिया। ► IAF ने Su-30 MKI, IL-78, और C-17 विमान तैनात किए। ► युद्ध कौशल, संयुक्त वायु अभियानों और सामरिक विशेषज्ञता को बढ़ाने पर जोर।
टाइगर ट्रायम्फ 2025	भारत (पूर्वी तट), अमेरिका	भारत-अमेरिका त्रि-सेवा HADR अभ्यास का चौथा संस्करण 1 से 13 अप्रैल 2025 तक। ► SOPs और संयुक्त समन्वय केंद्र (CCC) विकसित करना। ► विशाखापत्तनम में हार्बर चरण (1-7 अप्रैल) और काकीनाडा में समुद्री चरण (8-13 अप्रैल)।
इंद्रा 2025	भारत / रूस	भारतीय और रूसी नौसेनाओं के बीच 14वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक। ► समुद्री सुरक्षा खतरों का मुकाबला, संयुक्त संचालन की तैयारी और सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों का आदान-प्रदान।
दस्तलिक-VI (DUSTLIK-VI)	पुणे, भारत / उज्बेकिस्तान	भारत-उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास का 6वां संस्करण 16 से 28 अप्रैल 2025 तक। ► सामरिक समन्वय और सैन्य सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित।
आक्रामण (Aakraman)	भारत	भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित प्रमुख सैन्य अभ्यास, जिसमें राफेल और Su-30MKI लड़ाकू विमानों ने भाग लिया। ► पर्वतीय और स्थलीय लक्ष्यों पर हमलों का अभ्यास, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और लाइव फायरिंग शामिल। ► स-400, मेटियोर और रैम्पेज मिसाइलों का उपयोग।

सौदा और समझौता ज्ञापन

- वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपये (2.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर) पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.04% की वृद्धि दर्शाता है। रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) और निजी उद्योग द्वारा संचालित यह उछाल रक्षा विनिर्माण में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है। डीपीएसयू ने 42.85% की वृद्धि दर्ज की, जिसका योगदान 8,389 करोड़ रुपये रहा, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान 15,233 करोड़ रुपये रहा।
- भारत और फ्रांस 28 अप्रैल, 2025 को 26 राफेल-मरीन (राफेल-एम) जेट विमानों के लिए ₹63,000 करोड़ के जी-टू-जी सौदे को अंतिम रूप देने के लिए तैयार हैं - 22 सिंगल-सीटर और 4 ट्विन-सीटर ट्रेनर - भारत के नौसैनिक विमानन को बढ़ाने के लिए। इन जेट विमानों को INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा, जो स्वदेशी ट्विन इंजन डेक-बेस्ड फाइटर (TEDBF) तैयार होने तक क्षमता अंतर को पाटेंगे। डिलीवरी 3.5 साल में शुरू होगी, 6.5 साल में पूरी डिलीवरी होगी, जिससे भारत-फ्रांस के रणनीतिक रक्षा संबंध मजबूत होंगे।

सेना, नौसेना और वायु सेना समाचार

- भारतीय नौसेना की दो महिला अधिकारियों द्वारा संचालित नाविका सागर परिक्रमा-II (NSP-II) अभियान ने अपने वैश्विक परिक्रमा यात्रा के चौथे चरण को पूरा करते हुए केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश किया। INSV तारिणी को भारतीय वाणिज्य दूत रूबी जसप्रीत, दक्षिण अफ्रीकी नौसेना की रियर एडमिरल (JG) लिसा हेंड्रिक्स, और भारतीय रक्षा सलाहकार कैप्टन अतुल सपाहिया द्वारा बंदरगाह पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर दक्षिण अफ्रीकी नौसेना बैंड ने विशेष प्रस्तुति दी।
- भारतीय सेना ने DRDO और इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित MRSAM (मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल) के सफल परीक्षण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मिसाइल प्रणाली ने चार उड़ान परीक्षणों के दौरान उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक रोका और नष्ट कर दिया।
- भारत ने अपनी नौसैनिक विमानन शक्ति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फ्रांस के साथ ₹63,000 करोड़ (7 अरब डॉलर से अधिक) के अंतर-सरकारी समझौते को मंजूरी दी है, जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद की जाएगी। इस बहुप्रतीक्षित सौदे को कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति (CCS) द्वारा औपचारिक रूप से मंजूरी दी गई है। यह सौदा विशेष रूप से भारत के स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत से संचालन के लिए किया गया है और इससे नौसेना की वायु शक्ति को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा मिलेगा।
- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने 8 से 10 अप्रैल 2025 के बीच भारतीय वायु सेना के सुखोई-30 MKI विमान से लंबी दूरी की ग्लाइड बम 'गौरव' (Long-Range Glide Bomb - LRGB) के सफल परीक्षण किए। इन परीक्षणों में 'गौरव' बम ने लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्यों को अत्यंत सटीकता के साथ भेदा, जो भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और वायु से प्रक्षेपित हथियार प्रणालियों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्शाता है।
- भारतीय नौसेना ने 14 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली स्थित नौसेना भवन में अपने प्रतिष्ठित मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान संगोष्ठी - 'मेघायन-25' के तीसरे संस्करण का आयोजन किया। यह कार्यक्रम विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य समुद्री मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में जागरूकता और सहयोग को बढ़ावा देना था। संगोष्ठी का वर्चुअल उद्घाटन नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने किया। इस आयोजन में प्रमुख वैज्ञानिक एवं रक्षा संस्थानों की सक्रिय भागीदारी रही।





- भारत ने हाइपरसोनिक हथियारों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के अंतर्गत कार्यरत रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (DRDL) ने 25 अप्रैल 2025 को सक्रिय शीतलित स्क्यामजेट सबस्केल कम्बस्टर (Active Cooled Scramjet Subscale Combustor) का एक लंबी अवधि का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। यह परीक्षण हैदराबाद में हाल ही में स्थापित स्क्यामजेट कनेक्ट टेस्ट फैसिलिटी में आयोजित किया गया और यह 1,000 सेकंड से अधिक समय तक चला।
- भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस सुनयना गुरुवार, 17 अप्रैल 2025 को मोज़ाम्बिक के नाकाला बंदरगाह पर पहुँचा, जो इंडियन ओशन शिप (IOS) SAGAR मिशन के तहत उसकी चल रही तैनाती का हिस्सा है। यह पोर्ट कॉल भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में साझेदारी और स्थायित्व को बढ़ावा देने की भारत की रणनीतिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। आईएनएस सुनयना की यह यात्रा हाल ही में तंज़ानिया के डार-एस-सलाम में आयोजित भारत-अफ्रीका समुद्री साझेदारी अभ्यास "AIKEYME 25" के उद्घाटन सत्र में भाग लेने के बाद हो रही है, जो क्षेत्रीय समुद्री सहयोग को एक नई दिशा देने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।
- भारतीय वायुसेना (IAF) ने संयुक्त अरब अमीरात के अल धाफरा एयर बेस पर 'एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग-10' में भाग लेने के लिए अपना एक दल तैनात किया है। यह प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास 21 अप्रैल से 8 मई, 2025 तक आयोजित किया जाएगा। यह रणनीतिक सहभागिता भारत की वैश्विक साझेदारों के साथ सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अपनी संचालन क्षमताओं को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पुरस्कार और मान्यता

पुरस्कार और मान्यता: सितम्बर 2025

श्रेणी	पुरस्कार विजेता / नियुक्त व्यक्ति	क्षेत्र / श्रेणी	मुख्य विवरण
नियंत्रक महालेखापाल (CGA)	टी.सी.ए. कल्याणी (1991 बैच ICAS अधिकारी)	वित्त / प्रशासन	29वीं CGA के रूप में कार्यभार ग्रहण; 34 वर्षों का अनुभव; वित्तीय भूमिकाओं में महिला नेतृत्व का महत्वपूर्ण पड़ाव।
उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियुक्ति	अरुण कुमार व अन्य	न्यायपालिका	राष्ट्रपति द्वारा इलाहाबाद व केरल उच्च न्यायालय में नए न्यायाधीश नियुक्त; अतिरिक्त न्यायाधीशों का स्थायी रूप से पदोन्नयन शामिल।
NIRF रैंकिंग 2025	आईआईटी-मद्रास	शिक्षा / रैंकिंग	लगातार 7वें वर्ष शीर्ष स्थान; अन्य स्थानों पर IISc बेंगलुरु और IIT-मुंबई; कुल 17 श्रेणियाँ शामिल।
प्रो. वी.के. गोकक पुरस्कार	आनंद वी. पाटिल	साहित्य	बाल साहित्य पुरस्कार विजेता (केंद्रीय साहित्य अकादमी); 7 सितम्बर 2025 को बेंगलुरु में भारतीय विद्या भवन द्वारा सम्मानित।
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025	उत्कृष्ट शिक्षक	शिक्षा	5 सितम्बर 2025 (शिक्षक दिवस) पर प्रदान; थीम: "नई पीढ़ी के विद्यार्थियों को प्रेरित करना"; राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित।
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक - 82वाँ वेनिस फिल्म महोत्सव (ओरिज़ोंटी सेक्शन)	अनुपर्णा राय	सिनेमा / अंतरराष्ट्रीय फिल्म	Songs of Forgotten Trees फिल्म के लिए सम्मान।
कैमेल इंटरनेशनल अवार्ड (अरबियन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स)	यूनुस अहमद	व्यापार नेतृत्व	पलक्कड़ के NRI व्यवसायी; मिडिल ईस्ट डॉटस्पेस कोवर्किंग के कार्यकारी निदेशक; दुबई में सम्मानित।
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025	शहर: इंदौर, जबलपुर, आगरा, सूरत	पर्यावरण / वायु गुणवत्ता	राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यता; स्वच्छ वायु पहलों हेतु ₹1.55 लाख करोड़ जुटाए गए।
पी.वी. नरसिम्हा राव पुरस्कार (मरणोपरान्त)	डॉ. मनमोहन सिंह	राजनीति / आर्थिक सुधार	भारत के आर्थिक परिवर्तन में योगदान हेतु सम्मान; पत्नी गुरशरण कौर ने पुरस्कार ग्रहण किया।
इंस्पायर अवार्ड 2025 - इनोवेशन प्रतियोगिता	मुजफ्फरपुर (बिहार)	शिक्षा / छात्र नवाचार	7,403 छात्र प्रविष्टियों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान; बेंगलुरु व लखनऊ को पछाड़ा।
एएसएमई हॉल्ली मेडल 2025	बाबा कल्याणी (अध्यक्ष, भारत फोर्ज)	इंजीनियरिंग / विनिर्माण	उन्नत विनिर्माण एवं आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ता नवाचारों हेतु सम्मानित।
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 (प्रभावक श्रेणी)	बीईई (ऊर्जा दक्षता ब्यूरो) पहल	ऊर्जा दक्षता / डिजिटल सामग्री	ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने वाले इन्फ्लुएंसर्स हेतु नई श्रेणी प्रारंभ।
77वें प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स (2025)	सेथ रोगन, क्रिस्टिन मिलिओटी, जिन स्मार्ट व शो Severance, The Studio	टेलीविजन मनोरंजन	14 सितम्बर 2025 को आयोजित; उत्कृष्ट अभिनय और श्रृंखलाओं को सम्मानित।





श्रेणी	पुरस्कार विजेता / नियुक्त व्यक्ति	क्षेत्र / श्रेणी	मुख्य विवरण
भारत की आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि (2025)	नीरेज घायवान की Homebound	सिनेमा / सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर	भारत की ऑस्कर प्रविष्टि; मार्टिन स्कॉर्सेसी (कार्यकारी निर्माता) द्वारा समर्थित; वैश्विक स्तर पर प्रशंसा प्राप्त

पुरस्कार और मान्यता: अगस्त 2025

पुरस्कार का नाम	विजेता / सम्मानित	क्षेत्र	प्रमुख बिंदु
एम. एस. स्वामीनाथन ग्लोबल अवॉर्ड फॉर फूड एंड पीस	डॉ. एरेनारे	खाद्य सुरक्षा एवं शांति	पीएम मोदी द्वारा प्रारंभ; विकासशील देशों के वैज्ञानिकों को सम्मानित करने हेतु; नाइजीरिया में भूख से लड़ाई के लिए सम्मानित
इंक्वेटर इनिशिएटिव अवॉर्ड 2025	बीबी फ़ातिमा महिला स्वयं सहायता समूह, धारवाड़	जैव विविधता संरक्षण	103 देशों में से 10 वैश्विक विजेताओं में एकमात्र भारतीय समूह
वीरता एवं सेवा पदक 2025	1,090 पुलिस, अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा एवं कारागार कर्मी	जन सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा	233 वीरता पदक, 99 राष्ट्रपति पदक, 758 सराहनीय सेवा पदक; अधिकांश जम्मू-कश्मीर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों को
राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2025	15 सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी	लोक प्रशासन कथावाचन	8वाँ संस्करण; अनुभव पोर्टल के 10 वर्ष; उल्लेखनीय रूप से एक-तिहाई महिला प्रतिनिधित्व
इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025	नीरज घायवान (फ़िल्म होमबाउंड के लिए सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म एवं निर्देशक)	सिनेमा एवं फ़िल्म निर्देशन	फ़िल्म विस्थापन और भावनात्मक वापसी पर आधारित; मुख्य भूमिका में जान्हवी कपूर और अन्य कलाकार
मिस यूनिवर्स इंडिया 2025	मनिका विश्वकर्मा	सौंदर्य एवं तमाशा / मॉडलिंग	राजस्थान के गंगानगर की मॉडल; इससे पहले मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024; जयपुर में ताज पहनाया गया; थाईलैंड में 74वें मिस यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी; उर्वशी रौतेला और रिया सिंहा सहित 50 प्रतियोगियों द्वारा प्रशंसा की गई

पुरस्कार और मान्यता: जुलाई 2025

पुरस्कार का नाम	विजेता	क्षेत्र	मुख्य विवरण
फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर में सम्मान समारोह	राधानाथ स्वामी	आध्यात्मिक नेतृत्व	न्यूयॉर्क सिटी द्वारा सम्मानित; ISKCON नेता; सामुदायिक सेवा व अंतर-धार्मिक समरसता में योगदान
NASA-NSS स्पेस सेटलमेंट डिज़ाइन कॉन्टेस्ट 2025	एस.आर.एन. मेहता सीबीएसई स्कूल, कलबुर्गी	अंतरिक्ष विज्ञान / शिक्षा	"IRA" प्रोजेक्ट के लिए प्रथम पुरस्कार; ISDC-2025, ऑरलैंडो में प्रस्तुत
हॉलीवुड वॉक ऑफ़ फ़ेम (2026 वर्ग)	दीपिका पादुकोण	सिनेमा / वैश्विक मान्यता	वॉक ऑफ़ फ़ेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री; भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर बढ़ावा
तमिल विक्की सुरन पुरस्कार	वी. वेदाचलम	पुरातत्व / तमिल शिलालेख	कीलाडी खुदाई में योगदान; 25 पुस्तकें लिखीं; सार्वजनिक इतिहास में सक्रिय
मत्स्य पालन विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025	कासरगोड जिला	मत्स्य पालन / जलकृषि	केरल का सर्वश्रेष्ठ जिला; स्थायी जलकृषि में अग्रणी
चिंथा रवींद्रन पुरस्कार 2025	सरनकुमार लिम्बाले	साहित्य / दलित लेखन	दलित साहित्य व सामाजिक विचार के लिए; कोझिकोड में सम्मानित
IESA इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025	तेलंगाना राज्य	बैटरी निर्माण / हरित ऊर्जा	ईवी नीति व ऊर्जा भंडारण में नेतृत्व के लिए
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025	वर्षा देशपांडे	लैंगिक समानता / सामाजिक न्याय	बालिकाओं की रक्षा, कानूनी सुधार व दलित महिला सशक्तिकरण में कार्य
हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार 2080	कल्याण श्रेष्ठ	न्यायिक नेतृत्व	नेपाल में लोकतंत्र व न्याय क्षेत्र में नेतृत्व के लिए सम्मानित
पेन पिंटर पुरस्कार 2025	लैला अबूलेला	साहित्य	विश्वास, प्रवासन व मुस्लिम महिलाओं के जीवन पर लेखन के लिए





पुरस्कार का नाम	विजेता	क्षेत्र	मुख्य विवरण
कलिंग रत्न पुरस्कार 2024	धर्मेन्द्र प्रधान	जन सेवा / शिक्षा	राष्ट्रपति सुर्मू द्वारा ओडिशा में सम्मानित; शिक्षा व सांस्कृतिक एकता में योगदान
राष्ट्रीय जियोस्पेशियल प्रैक्टिशनर अवार्ड 2025	INCOIS	जियोस्पेशियल तकनीक	समुद्री GIS व आपदा पूर्वानुमान में नवाचार के लिए
राज्य कथकली पुरस्कार 2023	कुरुर वासुदेवन नामबूदिरि	प्रदर्शन कला (कथकली)	केरल सरकार द्वारा कथकली में योगदान के लिए सम्मानित
पलवूर अप्पु मारार वाद्य पुरस्कार 2023	शंकर वारियर	प्रदर्शन कला (चेंडा)	चेंडा वादन में उत्कृष्टता के लिए
पलवूर अप्पु मारार वाद्य पुरस्कार 2023	मट्टनूर शंकरनकुट्टी मारार	प्रदर्शन कला (महलम)	महलम वादन में उत्कृष्टता के लिए
केरलीय नृत्य-नाट्य पुरस्कार 2023	गिरीजादेवी	प्रदर्शन कला (कूडियाट्टम)	कूडियाट्टम नाटक में योगदान के लिए
WSIS प्राइजेज 2025 चैंपियन अवार्ड	मेरी पंचायत ऐप (MoPR & NIC)	ई-गवर्नेंस / तकनीक	2.65 लाख ग्राम पंचायतों में बहुभाषी उपयोगिता के लिए
बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 (FISM)	सुहानी शाह	जादू / प्रदर्शन कला	FISM में विजेता बनने वाली पहली भारतीय; जादू को मनोविज्ञान व कहानी से जोड़ती हैं
जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025	डॉ. वी. नारायणन (ISRO)	अंतरिक्ष विज्ञान	क्रायेोजेनिक प्रणोदन व रणनीतिक अभियानों में योगदान
पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड 2025	गीतांजलि श्री (अनुवाद: डेज़ी रॉकवेल)	साहित्य / अनुवाद	"Once Elephants Lived Here" के लिए; हिंदी साहित्य को वैश्विक मंच प्रदान किया

पुरस्कार और मान्यता: जून 2025

पुरस्कार का नाम	विजेता	प्रमुख तथ्य
ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड	कुमार मंगलम बिड़ला	USISPF द्वारा सम्मानित; अमेरिका में \$15 अरब निवेश और 5,400 नौकरियाँ सृजित कीं।
नाइटहुड (सर की उपाधि)	डेविड बेकहम	किंग चार्ल्स III के बर्थडे ऑनर्स में शामिल; यूनिसेफ और पर्यावरण कार्यों में योगदान के लिए।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 (स्वर्ण)	रोहिणी ग्राम पंचायत, धुले	100% आदिवासी गाँव; 956+ ऑनलाइन सेवाएं; व्हाट्सएप के माध्यम से प्रमाणपत्र वितरण।
पार्दो डी'ओनोर (Pardo d'Onore)	अलेक्जेंडर पेन (फिल्म निर्देशक)	लोकनों फिल्म फेस्टिवल 2025 का सर्वोच्च सम्मान; मानवतावादी सिनेमा के लिए प्रसिद्ध।
फूड प्लैनेट प्राइज 2025	नाइट्रो कैप्ट (NitroCapt)	हरित उर्वरक तकनीक; CO ₂ उत्सर्जन में 90% तक कमी की क्षमता।
स्कायट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवॉर्ड्स 2025	इंडिगो एयरलाइंस	बेस्ट लो-कॉस्ट एयरलाइन श्रेणी में तीसरा स्थान; 22.3 मिलियन यात्रियों की बोटींग पर आधारित।
पद्म भूषण 2025	श्री राम बहादुर राय	वरिष्ठ पत्रकार, IGNCA ट्रस्ट के अध्यक्ष; जेपी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी।
चैम्पियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025	द हिंदू	वीडियो स्टोरीटेलिंग, AI, पॉडकास्टिंग आदि में 10 पुरस्कार; डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्टता।
ज्यूरी पुरस्कार (Annecy एनीमेशन फेस्टिवल 2025)	देसी ऊन (Desi Oon)	भारतीय संस्कृति पर आधारित एनीमेशन फिल्म; MoMA संग्रह में शामिल, कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार।
डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25	इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB)	वित्त मंत्रालय द्वारा सम्मानित; डिजिटल बैंकिंग को ग्रामीण भारत तक पहुँचाया।
जेसीवी साहित्य पुरस्कार	(निरस्त कर दिया गया)	भारत का समृद्ध साहित्यिक पुरस्कार; 2018 से 7 संस्करण; अब बंद होने से साहित्यिक जगत में निराशा।





पुरस्कार और मान्यता: मई 2025

अन्य पुरस्कार

क्रम संख्या	पुरस्कार का नाम	विजेता
1	72वें मिस वर्ल्ड समारोह में मानवतावादी पुरस्कार	सोनू सूद
2	2025 यूनेस्को/गिलमोर् कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज	ला प्रेन्सा (निकारागुआ का सबसे पुराना समाचार पत्र)
3	वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन का ऑनर मेडल	भुवन ऋषु
4	2025 विश्व खाद्य पुरस्कार	मारियांगेला हंग्रिया
5	58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार	गुलज़ार (प्रसिद्ध कवि और गीतकार), रामभद्राचार्य (संस्कृत विद्वान और आध्यात्मिक गुरु)
6	अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025	वानु मुश्ताक
7	अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड (AMA)	भारतीय-अमेरिकी रैपर और गायिका राजा कुमारी
8	ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर (कनाडा इंडिया फाउंडेशन)	सद्गुरु (ईशा फाउंडेशन के संस्थापक)
9	मिस वर्ल्ड 2025 की टैलेंट फिनाले विजेता	मोनिका केज़िया सेम्बिरिंग

पुरस्कार और मान्यता: अप्रैल 2025

अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार

पुरस्कार का नाम	पुरस्कार विजेता	क्षेत्र	प्रमुख बिंदु
प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार	पुरातत्वविद माईना स्वामी	इतिहास और समाज सेवा	आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद माईना स्वामी को ऐतिहासिक शोध और सामाजिक सेवा में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू द्वारा तुमलापल्ली कलाक्षेत्रम, विजयवाड़ा में प्रदान किया गया। इसमें 'कलारत्न' उपाधि, 'हंसा' पदक, प्रशंसा प्रमाणपत्र और नकद पुरस्कार शामिल हैं।
गोल्ड मरकरी पुरस्कार (शांति और स्थायित्व के लिए)	दलाई लामा	शांति और पर्यावरण	गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल द्वारा 1 अप्रैल 2025 को दलाई लामा को धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान उनके अहिंसा, मानव गरिमा, धार्मिक संवाद और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जीवनभर के समर्पण को मान्यता देता है।
उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार	निखिल सिंघल	जनसंपर्क और रणनीतिक संचार	विगर मीडिया वर्ल्डवाइड के संस्थापक और नोएडा हाईराइज फेडरेशन के अध्यक्ष निखिल सिंघल को यह पुरस्कार 31 मार्च 2025 को लखनऊ के ताज होटल में तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित समारोह में दिया गया। उन्होंने अपनी टीम को समर्पण और उत्कृष्टता के लिए धन्यवाद दिया।
राष्ट्रीय युवा पुरस्कार	अकार्श श्रॉफ	सामाजिक सेवा और शिक्षा	युवास्पर्क के संस्थापक अकार्श श्रॉफ को आंगनवाड़ी डिजिटलीकरण और ग्रामीण शिक्षा नवाचार में उनके प्रभावशाली कार्य के लिए 3 अप्रैल 2025 को यह पुरस्कार संसद भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार 30 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को राष्ट्रीय विकास में योगदान के लिए दिया जाता है। इस वर्ष 22 युवाओं को सम्मानित किया गया।
फ्रेड डैरिंगटन पुरस्कार (कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए)	सुदर्शन पटनायक	रेत शिल्प और कला	सुदर्शन पटनायक ने अपनी भगवान गणेश की रेत कला के लिए यह पहला फ्रेड डैरिंगटन पुरस्कार जीता, जो "विश्व शांति" का संदेश देती है। 10 फीट ऊंची यह मूर्ति नवंबर 2025 तक वेमाउथ, डॉर्सेट के सैंडवर्ल्ड में प्रदर्शित की जा रही है। पुरस्कार में डैरिंगटन की कार्टून छवि वाला स्वर्ण पदक और पटनायक की मूर्ति की रेत से बना कांच का तरंग शामिल है।





पुरस्कार का नाम	पुरस्कार विजेता	क्षेत्र	प्रमुख बिंदु
'मास्टर ह्यूमर अवॉर्ड'	आमिर खान	हास्य और सिनेमा	चीन के मकाऊ में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कॉमेडी महोत्सव 2025 में बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को यह पुरस्कार 9-13 अप्रैल को प्रदान किया गया। चीन में उन्हें 'अंकल मी' के नाम से जाना जाता है। '3 इडियट्स', 'पीके', और 'दंगल' जैसी फिल्मों से उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक रही है, विशेष रूप से 'दंगल' ने ₹1000 करोड़ से अधिक की कमाई की।
वेरचोल दलित साहित्य पुरस्कार	पी. शिवकामी	साहित्य और सामाजिक चेतना	प्रसिद्ध लेखिका, पूर्व IAS अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता पी. शिवकामी को चेन्नई में नीलम सांस्कृतिक केंद्र द्वारा ₹1 लाख के पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने भाषण में दलित पहचान, प्रतिरोध की शक्ति, अंग्रेजी में लेखन के महत्व और साहित्य में दलित आवाजों की वृद्धि को रेखांकित किया।
'लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी' पुरस्कार	डॉ. डी. नागेश्वर रेड्डी	चिकित्सा (गैस्ट्रोएंटरोलॉजी)	हैदराबाद के AIG हॉस्पिटल्स के अध्यक्ष डॉ. डी. नागेश्वर रेड्डी को जापानी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी समुदाय द्वारा टोक्यो में SHOWA मेडिकल यूनिवर्सिटी में आयोजित 'टोक्यो लाइव ग्लोबल एंडोस्कोपी 2025' कार्यक्रम में यह सम्मान मिला।
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य (आधार बायोमेट्रिक अपडेट और सत्यापन)	मेघालय	शासन और पहचान प्रबंधन	भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार सत्यापन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेघालय को दो श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया। पुरस्कार नई दिल्ली में प्रस्तुत किए गए।
मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल	D. पांडा, राहुल कुमार पांडे (2023), राम रतन जाट, झूमर राम पूनिया, रणवीर सिंह जमवाल (2024)	सैन्य सेवा और साहसिक कार्य	यूनाइटेड सर्विस इंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया (USI) द्वारा आयोजित समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने यह मेडल उन सैन्य कर्मियों को प्रदान किया जिन्होंने सैन्य खोजबीन, अन्वेषण और साहसिक अभियानों में उत्कृष्ट योगदान दिया।
गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025	अच्युत सामंत	शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण	KIIT और KISS के संस्थापक अच्युत सामंत को यह पुरस्कार कोकराझार, असम में उनके शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण में योगदान के लिए प्रदान किया गया। पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिह्न और ₹1 लाख की राशि शामिल है, जिसे उन्होंने ट्रस्ट को वापस दान कर दिया।
ग्लोबल वैनगार्ड ऑनर	प्रियंका चोपड़ा	सिनेमा (बॉलीवुड-हॉलीवुड सेतु)	10 मई 2025 को लॉस एंजेलिस के म्यूजिक सेंटर में आयोजित गोल्ड हाउस गोल्ड गाला में प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड और हॉलीवुड के बीच 25 वर्षों के प्रभावशाली करियर के लिए पहला 'ग्लोबल वैनगार्ड ऑनर' दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (सार्वजनिक प्रशासन) 2024	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	नवाचार और पोषण प्रबंधन	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन को 'मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' के तहत टेक-आधारित पोषण प्रशासन में नवाचार के लिए यह पुरस्कार 21 अप्रैल 2025 को केंद्रीय सचिव श्री अनिल मलिक द्वारा प्राप्त किया गया।
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024	कुमार मंगलम बिड़ला	उद्योग और नेतृत्व	आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष और पद्म भूषण सम्मानित कुमार मंगलम बिड़ला को भारत की आर्थिक प्रगति में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए यह पुरस्कार 24 अप्रैल को मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिया गया।
'ऑर्ड्रे देज़ आर्ट ए लेत्र' (फ्रेंच कला और साहित्य सम्मान)	पायल कपाडिया	सिनेमा	मुंबई स्थित फिल्म निर्माता पायल कपाडिया को फ्रांस की सरकार द्वारा 'ऑफिसियर डान लोर्ड्रे देज़ आर्ट ए लेत्र' से सम्मानित किया गया। उनका फिल्म 'All We Imagine As Light' ने 77वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीता और गोल्डन ग्लोब में नामांकित हुई।
राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार	राजेश उन्नी	समुद्री क्षेत्र	सीनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को भारत के सर्वोच्च समुद्री सम्मान 'राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार' से 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस (मुंबई) पर सम्मानित किया गया।





शिखर सम्मेलन | कार्यक्रम | त्यौहार (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय)

शिखर सम्मेलन | कार्यक्रम | त्यौहार (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय): सितम्बर 2025

श्रेणी	आयोजन	स्थल	मुख्य बिंदु
शिखर सम्मेलन	भारत-चीन SCO बैठक	तियानजिन, चीन	पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी की 10 माह बाद मुलाकात; प्रत्यक्ष उड़ानों, सीमा व्यापार, कैलाश मानसरोवर यात्रा और पर्यटन वीजा की बहाली पर सहमति; आपसी विश्वास पुनर्निर्माण, आतंकवाद-विरोध, व्यापार और ग्लोबल साउथ पर सहयोग का संकल्प।
कार्यक्रम	सेमिकॉन इंडिया 2025	नई दिल्ली, भारत	पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन; भारत की सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं का प्रदर्शन; ₹1.5 लाख करोड़ मूल्य की 10 परियोजनाएँ; 48+ देशों की भागीदारी।

शिखर सम्मेलन | कार्यक्रम | त्यौहार (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय): अगस्त 2025

श्रेणी	कार्यक्रम / आयोजन	स्थान	प्रमुख बिंदु
शिखर सम्मेलन	बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025	थाईलैंड	पीएम मोदी ने सांस्कृतिक पहल 'सप्तसुर' की घोषणा की; बिम्स्टेक देशों के बीच कला और संस्कृति से क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा
कार्यक्रम	बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव - 'सप्तसुर'	भारत मंडपम, नई दिल्ली	आईसीसीआर द्वारा आयोजित; उद्घाटन ईएएम डॉ. एस. जयशंकर ने किया; 7 बिम्स्टेक देशों के कलाकार शामिल; सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूती
सम्मेलन	एम. एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	नई दिल्ली	पीएम मोदी ने उद्घाटन किया; थीम - "एवरग्रीन रेवोल्यूशन - द पाथ टू बायो-हैप्पीनेस"; कृषि एवं खाद्य सुरक्षा में डॉ. स्वामीनाथन के योगदान को सम्मान
कार्यशाला	डब्ल्यूएचओ-आईआरसीएच कार्यशाला: हर्बल मेडिसिन सुरक्षा एवं विनियमन	होटल फॉर्चून, गाज़ियाबाद	6-8 अगस्त 2025; आयुष मंत्रालय व WHO द्वारा आयोजित; अमेरिका, जापान, ब्राज़ील समेत 15+ देशों की भागीदारी; वैश्विक हर्बल दवा सुरक्षा पर फोकस
पहल	इंडो-बर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव (IBRRI) रणनीतिक योजना	रामसर COP15 (वैश्विक मंच)	कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम एवं IUCN द्वारा विकसित; 2030 तक आर्द्रभूमि संरक्षण, जैव विविधता व पारिस्थितिकी तंत्र की मजबूती का लक्ष्य
सेमिकॉन इंडिया 2025 (चौथा संस्करण)	यशोभूमि, नई दिल्ली 2 सितम्बर 2025	उद्घाटन: पीएम मोदी 350+ प्रदर्शक, 50+ वैश्विक CXOs, 33 देश आयोजन: SEMI एवं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (MeitY)	थीम: "नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावरहाउस का निर्माण" फोकस: फैब्स, पैकेजिंग, AI, स्मार्ट मैनुफैक्चरिंग, डिज़ाइन इनोवेशन
AIBD कार्यकारी बोर्ड (अध्यक्ष पद)	23वीं जनरल कॉन्फ्रेंस, फुकेत (थाईलैंड)	भारत पुनः अध्यक्ष चुना गया (2016 के बाद) AIBD की स्थापना 1977, यूनेस्को के तहत 92 सदस्य, 45 राष्ट्र	थीम: "जनता, शांति और समृद्धि हेतु मीडिया" भारत की एशिया-प्रशांत प्रसारण नेतृत्व व नीति-निर्माण में भूमिका को मजबूत किया
68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन (CPC-2025)	बारबाडोस 5-12 अक्टूबर 2025	भारतीय प्रतिनिधिमंडल: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश	चर्चा: लोकतंत्र, शासन में प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, वित्तीय पारदर्शिता, बहुपक्षवाद बिड़ला का संबोधन: "राष्ट्रमंडल: एक वैश्विक साझेदार" युवा सत्र: साइबर-बुलिंग एवं गैंग हिंसा
मिलमेडिकॉन-2025 (अंतरराष्ट्रीय सैन्य चिकित्सा सम्मेलन)	मानेकशां सेंटर, नई दिल्ली	उद्घाटन: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आयोजन: DGMS (आर्मी) भारतीय सेना के "सुधार वर्ष" का हिस्सा	फोकस: सैन्य चिकित्सा में नवाचार, चुनौतियाँ व सुधार थीम: ट्रॉमा केयर, स्वास्थ्य में AI, युद्धभूमि प्रतिक्रिया, महिला नेतृत्व विशेष: मिलिटरी नर्सिंग सर्विस की शताब्दी - "नारी शक्ति" का उत्सव




शिखर सम्मेलन | कार्यक्रम | त्यौहार (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय): जुलाई 2025

यहां आपकी तालिका को केवल मुख्य बिंदुओं के साथ और अनावश्यक पुनरावृत्ति के बिना सरलीकृत किया गया है:

श्रेणी	आयोजन	स्थान	मुख्य बिंदु
शिखर सम्मेलन	आसियान-भारत कूटनीति संवाद	चेन्नई	भारत द्वारा आयोजित पहला आसियान-भारत कूटनीति संवाद आसियान व तिमोर लेस्ते के 30+ प्रतिनिधि शामिल समुद्री सहयोग व सतत कूटनीति परियोजना को बढ़ावा सागरमाला, एकट ईस्ट नीति व विकसित भारत 2047 से जुड़ा भारत को क्षेत्रीय कूटनीति हब बनाने का लक्ष्य
शिखर सम्मेलन	17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन	रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील	पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र, IMF, विश्व बैंक, WTO में सुधार की मांग की अप्रैल 2025 के पहलगांम हमले का हवाला देते हुए आतंकवाद की निंदा पश्चिम एशिया और यूरोप में संवाद से शांति का समर्थन प्रस्ताव: ब्रिक्स साइंस रिपॉजिटरी, खनिज आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा, जिम्मेदार AI 'रियो घोषणा' में वैश्विक सुधार व तकनीक पर सहमति
शिखर सम्मेलन	11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन	नई दिल्ली	मक्का क्रांति योजना का शुभारंभ अनुसंधान, तकनीक और क्षेत्रीय कार्यक्रमों को बढ़ावा उत्तर प्रदेश में तेज मक्का विकास कार्यक्रम की सफलता मक्का: एथेनॉल, पशु चारा, जलवायु-उन्मुख खेती के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य: भारत को वैश्विक मक्का नेता बनाना
सम्मेलन	नगरीय स्थानीय निकायों का राष्ट्रीय सम्मेलन	मानेसर, गुरुग्राम	पहली ULB अध्यक्षों की बैठक प्रमुख विषय: लोकतांत्रिक शासन, समावेशी विकास, महिला सशक्तिकरण जमीनी संस्थानों को मज़बूती व सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा
सम्मेलन	पांडुलिपि धरोहर पर वैश्विक सम्मेलन	भारत मंडपम, नई दिल्ली	11-13 सितम्बर 2025 को पहली वैश्विक बैठक विषय: "भारत की ज्ञान विरासत की पुनर्प्राप्ति" 500+ प्रतिनिधि, दुर्लभ प्रदर्शनियाँ, डिजिटलीकरण व AI संग्रहण सत्र स्वामी विवेकानंद के 1893 भाषण की वर्षगांठ से जुड़ा आयोजन
सम्मेलन	व्यापार सुगमता सम्मेलन 2025	नई दिल्ली	विषय: "निरंतर व्यापार हेतु वैज्ञानिक उत्कृष्टता" परीक्षण अवसररचना सुधार पर फोकस 400+ व्यापार व उद्योग प्रतिनिधि लक्ष्य: व्यापार दक्षता, अनुपालन व आर्थिक वृद्धि में सुधार

शिखर सम्मेलन | कार्यक्रम | त्यौहार (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय): जून 2025

श्रेणी	कार्यक्रम	स्थान	प्रमुख बिंदु
इवेंट	इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) की पहली महासभा	नई दिल्ली	7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण हेतु वैश्विक गठबंधन; 9 देशों की भागीदारी; शासन ढांचे व नेतृत्व भूमिकाओं को अनुमोदन; 95 रेंज देशों को सहयोग व वित्तीय समर्थन।
सम्मेलन	राष्ट्रीय एग्री स्टैक सम्मेलन	नई दिल्ली	13 जून 2025 को आयोजन; ₹6,000 करोड़ की डिजिटल कृषि फंडिंग; DigiLocker-लिंकड प्रमाणपत्र, AI चैटबॉट, शिकायत निवारण प्रणाली लॉन्च; महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक ने नवाचार साझा किए।
सम्मेलन	बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025	बॉन, जर्मनी	16 जून 2025 से शुरू; UNFCCC के तकनीकी सत्र; COP शिखर सम्मेलन की तैयारी; अनुकूलन लक्ष्य, जलवायु वित्त, क्षति और तकनीकी हस्तांतरण पर चर्चा; 5,000+ प्रतिभागी।
सम्मेलन	इंडियन कंज़र्वेशन कॉन्फ्रेंस (ICCON) 2025	वाइल्डलाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून	25-27 जून 2025; भूपेंद्र यादव द्वारा उद्घाटन; 500+ प्रतिनिधि; TechBridge मंच द्वारा नवाचार; युवाओं की भागीदारी और समावेशिता को बढ़ावा।




शिखर सम्मेलन | कार्यक्रम | त्यौहार (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय): मई 2025

श्रेणी	घटना / सम्मेलन	स्थल	मुख्य बिंदु
सम्मेलन	द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025	-	पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन। पर्यटन, वस्त्र, कृषि-खाद्य प्रसंस्करण और ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश पर जोर। "एकट ईस्ट" नीति के अंतर्गत पूर्वोत्तर को समृद्धि का केंद्र बनाने की पहल।
सम्मेलन	9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक	ब्रासीलिया	भारत ने स्टार्टअप हब, MSME समर्थन और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा दिया। छह नए ब्रिक्स सदस्य शामिल हुए। सहयोग के सिद्धांत: सहयोग, समन्वय, समग्रता, सर्वसम्मति।
सम्मेलन	विश्व एयर ट्रांसपोर्ट समिट (WATS) 2025	नई दिल्ली	IATA द्वारा 1-3 जून 2025 को AGM और WATS का आयोजन। 42 वर्षों बाद भारत में यह आयोजन हो रहा है। वैश्विक विमानन जगत की उपस्थिति।
कार्यक्रम	Wings India 2026	हैदराबाद	28-31 जनवरी 2026 को प्रस्तावित। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में नवाचार, निवेश, कौशल विकास को बढ़ावा देने वाला मंच।
कार्यक्रम	78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा	-	आयुष्मान भारत, मातृ व बाल स्वास्थ्य में प्रगति, WHO द्वारा ट्रेकोमा-मुक्त प्रमाणन, और महामारी संधि की वकालत।
कार्यक्रम	67वीं गवर्निंग बॉडी बैठक (APO)	जकार्ता	भारत ने 2025-26 के लिए अध्यक्षता ग्रहण की। हरित उत्पादकता 2.0, डिजिटल परिवर्तन और नवाचार पर केंद्रित। NPC द्वारा MSME समर्थन।
कार्यक्रम	अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस सम्मेलन 2025	नई दिल्ली	भारतीय चाय के वैश्विक नेतृत्व को बढ़ावा। ब्रांडिंग, युवाओं की भागीदारी, जैविक नवाचार और निर्यात पर जोर।
कार्यक्रम	सी-ट्रेड मरीन लॉजिस्टिक्स मिडिल ईस्ट 2025	दुबई	इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग ने दमाम (सऊदी अरब) में कार्यालय खोला। समुद्री गलियारों में भारत की भूमिका मजबूत।
सम्मेलन	वर्ल्ड बैंक भूमि सम्मेलन 2025	-	भारत की SVAMITVA और ग्राम मंचित्र योजनाओं की सराहना। 2.44 करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित। भू-अधिकारों और जलवायु कार्रवाई पर जोर।
सम्मेलन	20वां UNFF सत्र	-	भारत की वन संरक्षण उपलब्धियाँ उजागर। बिग कैट एलायंस और पारिस्थितिक तंत्र मूल्यांकन पर चर्चा।
सम्मेलन	पश्चिमी क्षेत्रीय ऊर्जा सम्मेलन	-	स्मार्ट प्रीपेड मीटर, परमाणु ऊर्जा, हरित ऊर्जा जोन और वित्तीय स्थिरता पर चर्चा। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को समर्थन।
सम्मेलन	समावेशी भारत शिखर सम्मेलन 2025	-	विकलांगजनों के लिए डिजिटल पहुंच और समावेशी विकास। AI चैटबॉट और नई पाठ्यक्रम की शुरुआत।
सम्मेलन	मत्स्य सचिव सम्मेलन 2025	नई दिल्ली	पीएमएमएसवाई और अन्य योजनाओं की समीक्षा। ड्रोन से मछली परिवहन, बीमा, सैटेलाइट सुरक्षा और डिजिटल आउटरीच पर चर्चा।

शिखर सम्मेलन | कार्यक्रम | त्यौहार (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय): अप्रैल 2025

श्रेणी	कार्यक्रम	स्थल	मुख्य बिंदु
सम्मेलन	9वां ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट (GTS) 2025	नई दिल्ली	विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह सम्मेलन 10 से 12 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में होगा। थीम है - "संभावना"। यह उभरती तकनीकों के माध्यम से समावेशी विकास, डिजिटल शासन और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों की खोज करेगा। इसमें 40+ देशों से 150+ वक्ता शामिल होंगे।
सम्मेलन	IDF वर्ल्ड डायबिटीज कांग्रेस	बैंकॉक	WHO और इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन (IDF) द्वारा आयोजित यह हाइब्रिड साइड इवेंट "पुल बनाना: टीबी और मधुमेह को संबोधित करने की एकीकृत रणनीतियाँ" विषय पर आधारित था। इसमें 2023 में 1.25 मिलियन मौतों वाले 10.8 मिलियन टीबी मामलों और 2024 में 828 मिलियन वयस्कों में मधुमेह की स्थिति पर चर्चा हुई। टीबी और डायबिटीज की 15% सह-बीमारी दर उजागर की गई। WHO ने प्रारंभिक निदान, द्विदिश स्क्रीनिंग और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण हेतु नई गाइडलाइन लॉन्च की।
कार्यक्रम	11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक	ब्रासीलिया, ब्राज़ील	3 अप्रैल 2025 को आयोजित इस बैठक में भारत ने "बाकू से बेलेम रोडमैप" के अंतर्गत USD 1.3 ट्रिलियन जुटाने पर बल दिया। MoEFCC के अमनदीप गर्ग ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और सतत विकास, ऊर्जा सुरक्षा, तथा न्यायपूर्ण संक्रमण (Just Transition) पर जोर दिया। बैठक में जलवायु वित्त, ऊर्जा विविधीकरण, ग्रीन ग्रिड पहल, संसाधन दक्षता और परिपत्र अर्थव्यवस्था की बात की गई।





श्रेणी	कार्यक्रम	स्थल	मुख्य बिंदु
कार्यक्रम	ISAR - संयुक्त राष्ट्र अंतर-सरकारी विशेषज्ञ कार्य समूह	—	भारत को 2025-2027 की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय लेखांकन और रिपोर्टिंग मानकों पर संयुक्त राष्ट्र के ISAR कार्य समूह का सदस्य नियुक्त किया गया। यह भारत की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और कॉर्पोरेट प्रशासन में वैश्विक भूमिका को दर्शाता है। भारत वित्तीय व गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग, CSR, पर्यावरण और शासन जैसे क्षेत्रों में योगदान देगा।
कार्यक्रम	वैश्विक जलवायु कार्रवाई परिषद (Global Climate Action Council)	प्रस्तावित (COP30 से पहले)	ब्राज़ील ने COP30 (नवंबर 2025, बेलेम) से पहले UNFCCC के अंतर्गत एक "वैश्विक जलवायु कार्रवाई परिषद" के गठन का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य जलवायु वार्ताओं को सरल बनाना और निर्णय प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। यह प्रस्ताव मिश्रित अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं के बावजूद ब्राज़ील की अग्रणी भूमिका को दर्शाता है।
कार्यक्रम	बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति	नामसाई, अरुणाचल प्रदेश	संस्कृति मंत्रालय और अंतराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC) द्वारा 21-22 अप्रैल 2025 को आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में बुद्ध धर्म के पूर्वोत्तर भारत की कला, संस्कृति और इतिहास पर प्रभाव की चर्चा होगी। इसमें विशेष रूप से ताई खामती जनजाति द्वारा प्रचलित थेरवाद बौद्ध धर्म पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
सम्मेलन	राष्ट्रीय सम्मेलन 'पर्यावरण - 2025'	नई दिल्ली	29 मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया। पर्यावरण संरक्षण को दैनिक जिम्मेदारी बताया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा आयोजित सम्मेलन में पर्यावरणीय चुनौतियों, सर्वोत्तम प्रथाओं और नीति सहयोग पर चर्चा हुई।
सम्मेलन	सेना कमांडरों का सम्मेलन (ACC) 2025	नई दिल्ली	1-4 अप्रैल 2025 को आयोजित। राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य तैयारियों, तकनीकी समावेशन और सैनिक कल्याण पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS और नीति आयोग प्रमुख ने रक्षा रणनीति पर दृष्टिकोण साझा किया।
सम्मेलन	बड़े NBFCs के लिए सम्मेलन	चेन्नई	28 मार्च 2025 को RBI द्वारा आयोजित। विषय: "साझा दृष्टिकोण, साझा जिम्मेदारी: NBFCs को सुदृढ़ बनाना"। 200+ प्रतिभागी शामिल हुए। नियामकीय पर्यवेक्षण, जोखिम प्रबंधन, पारदर्शिता और निष्पक्ष उधारी पर चर्चा हुई।
सम्मेलन	6वां बिम्सटेक शिखर सम्मेलन	थाईलैंड	3 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया। उद्देश्य: व्यापार, संपर्क और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। क्षेत्रीय रणनीति और सांस्कृतिक संबंधों पर जोर। बैठक के बाद श्रीलंका दौरा।
सम्मेलन	जिटैक्स अफ्रीका 2025	माराकेच, मोरक्को	डिजिटल अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास पर वैश्विक संवाद का मंच। भारत के राज्यमंत्री जयंत चौधरी ने आधार, UPI, ONDC और स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया।

सूची/सूचकांक (रैंक और रिपोर्ट)

सूची/सूचकांक (रैंक और रिपोर्ट): सितम्बर 2025

क्रमांक	रिपोर्ट / रैंकिंग	प्रस्तुतकर्ता	मुख्य बिंदु / विशेषताएँ
1	वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2025	विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)	भारत 38वें स्थान पर (स्कोर ~40.5), 2020 में 48 से सुधार। - निम्न-मध्यम आय वर्ग व मध्य/दक्षिण एशिया में #1। - शीर्ष 10: स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, अमेरिका, कोरिया, सिंगापुर, ब्रिटेन, फ़िनलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, चीन। - भारत की मजबूती: ज्ञान व तकनीकी आउटपुट (#22), बाज़ार परिपक्वता (#38)। - कमजोर क्षेत्र: व्यापार परिपक्वता (#64), आधारभूत संरचना (#61), संस्थान (#58)। - 139 देशों, 80+ संकेतक, 7 स्तंभ शामिल।
2	ब्लूमबर्ग अरबपति सूचकांक (11 सितम्बर 2025)	ब्लूमबर्ग	लैरी एलिसन (Oracle सह-संस्थापक) ने अस्थायी रूप से एलन मस्क को पीछे छोड़ा। - एलिसन की संपत्ति \$383.2B (+\$89B एक दिन में, अब तक का सबसे बड़ा उछाल)। - मस्क ने फिर शीर्ष स्थान पाया: \$384B। - शीर्ष 10: मस्क, एलिसन, जुकरबर्ग, बेज़ोस, लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन, स्टीव बाल्मर, अर्नॉल्ड, जेनसन हुआंगा। - भारतीय: मुकेश अंबानी (#18, \$97.9B), गौतम अडानी (#21, \$80.9B)।





क्रमांक	रिपोर्ट / रैंकिंग	प्रस्तुतकर्ता	मुख्य बिंदु / विशेषताएँ
3	एनआईआरएफ रैंकिंग्स 2025 (10वाँ संस्करण)	शिक्षा मंत्रालय (भारत)	- जारी: 4 सितम्बर 2025। - समग्र शीर्ष 10: IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, AIIMS दिल्ली, JNU दिल्ली, BHU वाराणसी। - प्रमुख श्रेणियाँ: इंजीनियरिंग (IIT मद्रास #1), प्रबंधन (IIM अहमदाबाद #1), लॉ (NLSIU बेंगलुरु #1), मेडिकल (AIIMS दिल्ली #1), कृषि (IARI दिल्ली #1), विश्वविद्यालय (IISc #1), नवाचार (IIT मद्रास #1), ओपन विश्वविद्यालय (IGNOU #1) आदि। - शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने "विकसित भारत 2047" से जोड़ा; उद्यमिता को नया पैरामीटर बनाने का सुझाव।
4	वैश्विक शांति सूचकांक 2025 (GPI)	इंस्टीट्यूट फॉर इकॉनॉमिक्स एंड पीस (IEP)	- 19वाँ संस्करण; 163 देशों की सूची। - भारत 115वें स्थान पर (स्कोर 2.229), 2024 जैसा ही। - शीर्ष 10: आइसलैंड (#1), आयरलैंड, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, पुर्तगाल, डेनमार्क, स्लोवेनिया, फ़िनलैंड। - एशिया में शीर्ष: सिंगापुर, जापान, मलेशिया, भूटान आदि। - भारत की चुनौतियाँ: सीमा तनाव, शहरी सुरक्षा व आंतरिक सुरक्षा।
5	यूडीआईएसई+ रिपोर्ट 2024-25	शिक्षा मंत्रालय (भारत)	- 2018-19 से जारी; स्कूली शिक्षा पर आधारित। - शिक्षक: 1 करोड़ पार (+6.7% वृद्धि), PTR लक्ष्य (30:1) से बेहतर। - ड्रॉपआउट दर घटी: माध्यमिक स्तर 10.9% → 8.2%। - नामांकन: GER - माध्यमिक 68.5%, मध्य 90.3%। - स्कूल: एकल-शिक्षक स्कूल घटे 1.10 लाख → 1.04 लाख, शून्य-नामांकन स्कूल घटे। - आधारभूत संरचना: बिजली 93.6%, पानी 99.3%, इंटरनेट 63.5%, रैप/रेल 54.9%। - लैंगिक समानता: महिला शिक्षक 54.2%, छात्राओं का नामांकन 48.3%।

सूची/सूचकांक (रैंक और रिपोर्ट): अगस्त 2025

रिपोर्ट का नाम / रैंकिंग	प्रस्तुतकर्ता / स्रोत	मुख्य बिंदु
अनलॉकिंग अ \$200 बिलियन ऑपच्युनिटी: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया	नीति आयोग (जारीकर्ता: श्री राजीव गौबा) (4 अगस्त 2025)	भारत की ईवी बिक्री वृद्धि: 2016 में 50,000 → 2024 में 20.8 लाख 2030 तक 30% ईवी लक्ष्य क्रॉस-सेक्टर सहयोग व डेटा-आधारित नीतियों पर बल \$200 अरब अवसर को खोलने की रूपरेखा
भारत विश्व का 5वाँ सबसे बड़ा विमानन बाज़ार (2024)	अंतरराष्ट्रीय विमानन डेटा (2024 रिपोर्ट)	2024 में 241 मिलियन यात्रियों का आवागमन (11.1% वार्षिक वृद्धि) मुंबई-दिल्ली रूट विश्व में 7वाँ प्रीमियम यात्रा में 11.8% वृद्धि मुख्य विमान: बोइंग B737, एयरबस A320
हाउसिंग प्राइस इंडेक्स (HPI) – Q1 2025	Housing.com – ISB	मार्च 2025 तक HPI 132 (YoY +8 अंक) – 13 प्रमुख शहरों में सावधान खरीदार, आपूर्ति समायोजन, वैश्विक चुनौतियाँ सतत विकास हेतु मजबूत आधार
वन क्षेत्र अध्ययन (2015–2019)	IIT बॉम्बे	भारत में हर 1 वर्ग किमी नए वन पर 18 वर्ग किमी वन हानि सभी राज्यों में शुद्ध हानि 50% से अधिक नए वन खंडित व पारिस्थितिक रूप से कमजोर जैव विविधता हेतु सतत, जुड़े हुए वनों को प्राथमिकता की सिफारिश
रीथिंकिंग होमस्टेज़: नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज़	नीति आयोग + IAMAI	होमस्टे/बीएनबी के लिए रणनीतिक रोडमैप स्थानीय उद्यमिता व सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा लाइट-टच रेगुलेशन, सुरक्षा व स्थिरता डिजिटल एकीकरण व पब्लिक-प्राइवेट सहयोग पर बल
मुख्यमंत्रियों के आपराधिक रिकॉर्ड पर रिपोर्ट (2025)	ADR (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स)	40% मुख्यमंत्री आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं 30 में से 12 मुख्यमंत्रियों ने केस घोषित किए शीर्ष पर: तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी (89 मामले), तमिलनाडु CM एम.के. स्टालिन (47 मामले) 33% गंभीर आरोप: हत्या का प्रयास, रिश्वत, अपहरण




सूची/सूचकांक (रैंक और रिपोर्ट): जुलाई 2025

विषय / रिपोर्ट	प्रमुख आँकड़े और उपलब्धियाँ
हुरुन ग्लोबल यूनिफॉर्म इंडेक्स 2025: शीर्ष 10 देश	- अमेरिका - 758 यूनिफॉर्म (सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, बोस्टन, ऑस्टिन) - चीन - 343 (बीजिंग, शंघाई, शेनझेन, गुआंगझोउ) - भारत - 64 (बेंगलुरु, मुंबई, गुरुग्राम) - भारत तीसरे स्थान पर - प्रमुख स्टार्टअप: Zerodha, Dream11, Razorpay - अमेरिका और चीन के पास विश्व के 72% यूनिफॉर्म
भारत की पाँच वर्ष से कम आयु मृत्यु दर और टीकाकरण प्रगति	- UN IGME 2024: पाँच वर्ष से कम मृत्यु दर में 78% की गिरावट (वैश्विक औसत: 61%) - नवजात मृत्यु दर में 70% कमी - यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंच मुख्य कारण - जीरो-डोज बच्चों में उल्लेखनीय गिरावट
प्राजक्ता कोली TIME100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल	- प्राजक्ता (MostlySane) - एकमात्र भारतीय, 7M+ यूट्यूब सब्सक्राइबर्स - नेटफ्लिक्स, बॉलीवुड, उपन्यास लेखन, UN और WEF से सहयोग
फोर्ब्स: अफ्रीकी मूल के अमेरिकी अरबपति 2025	8 अफ्रीकी मूल के अरबपति - अमेरिका के 125 शीर्ष अप्रवासी अरबपतियों में - एलन मस्क (दुनिया के सबसे अमीर - \$393.1B) 14% अप्रवासी अरबपति, 18% संपत्ति पर नियंत्रण
भारत के सबसे प्रदूषित और स्वच्छतम शहर 2025	- CREA रिपोर्ट (जन-जून 2025): सबसे प्रदूषित - बर्नीहाट और दिल्ली (PM2.5 > 40) 293 में से 259 शहर सुरक्षित सीमा से ऊपर - सबसे स्वच्छ शहर - आइजोल (मिजोरम) - प्रदूषण नियंत्रण की तात्कालिक आवश्यकता
QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2026	- दिल्ली - दुनिया का सबसे किफायती छात्र शहर - रैंकिंग में सुधार: मुंबई (98), दिल्ली (104), बेंगलुरु (108), चेन्नई (128) - NEP 2020 के अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार क्षमता में मजबूती
हुरुन इंडिया अंडर-30 लिस्ट 2025	79 युवा उद्यमियों को मान्यता (जैसे Zepto के संस्थापक) \$5.2B+ की फंडिंग, 64,000+ नौकरियाँ सृजित - सॉफ्टवेयर, FMCG, फिनटेक में प्रथम पीढ़ी के संस्थापक प्रमुख
विश्व बैंक: भारत के शहरीकरण जोखिम 2025	2030 तक शहरी क्षेत्रों में 70% नए रोजगार - हीटवेव और बाढ़ से \$5B सालाना नुकसान की आशंका \$2.4T की आवश्यकता 2050 तक टिकाऊ अवसंरचना के लिए - उच्च जोखिम: दिल्ली, चेन्नई, सूरत, लखनऊ; सफल उदाहरण: अहमदाबाद, इंदौर, कोलकाता
CSMIA विश्व के शीर्ष 10 हवाई अड्डों में शामिल	- मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष 10 में - रीडर स्कोर: 84.23, 55M+ यात्री, 121 गंतव्य - सर्वश्रेष्ठ सिंगल-रनवे एयरपोर्ट; लगातार तीसरे साल सम्मानित
हेनली पासपोर्ट इंडेक्स भारत रैंकिंग 2025	- भारत की रैंकिंग 85वें से 77वें स्थान पर - सबसे बड़ा सुधार 59 देशों में वीजा-मुक्त/वीजा ऑन अराइवल सुविधा (मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका आदि) - मजबूत कूटनीति का संकेत
विश्व बैंक: भारत का गिनी इंडेक्स और गरीबी में प्रगति	- गिनी इंडेक्स: भारत चौथा सबसे समान देश (25.5); चीन (35.7), अमेरिका (41.8) से बेहतर - अत्यधिक गरीबी 2.3% (2011-12 में 16.2%) \$3/दिन की गरीबी - 5.3% 12 वर्षों में 171 मिलियन लोग गरीबी से बाहर - योजनाएँ: जन धन, आधार, DBT, आयुष्मान भारत, स्टैंड-अप इंडिया, PMGKAY
नीति आयोग SDG इंडेक्स - पूर्वोत्तर जिले 2023-24	121 जिलों में 85% ने SDG स्कोर में सुधार किया - सर्वश्रेष्ठ जिला: हनाहथिआल (मिजोरम) - स्कोर: 81.43 - सबसे कमजोर: लोंगडिंग (अरुणाचल) - स्कोर: 58.71 - मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा के सभी जिले "फ्रंट रनर" श्रेणी में - सबसे निरंतर प्रदर्शन: सिक्किम





सूची/सूचकांक (रैंक और रिपोर्ट): जून 2025

रैंकिंग

श्रेणी	विवरण
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (दिल्ली)	एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (ACI APAC & MID) द्वारा एशिया-प्रशांत और मध्य पूर्व के शीर्ष 10 हब एयरपोर्ट्स में स्थान; सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा; 153 गंतव्यों से जुड़ा।
मुंबई (डेटा सेंटर)	कुशमैन एंड वेकफील्ड 2025 रिपोर्ट के अनुसार निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता में विश्व में 6वां और एशिया-प्रशांत में 1वां स्थान; 335 मेगावाट क्षमता विकासाधीन।
भारत - ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025	विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा जारी रिपोर्ट में 148 देशों में से 131वां स्थान; लैंगिक समानता स्कोर 64.1%; महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में कमी के कारण गिरावट।
भारत - टीएचई इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2025	अमृता विश्व विद्यापीठम् (रैंक 41) और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (रैंक 48) भारत की 135 प्रविष्टियों में अग्रणी; जेएसएस अकादमी और शूलिनी यूनिवर्सिटी भी टॉप 100 में शामिल; UN SDGs प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग।
भारत - ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025	विश्व आर्थिक मंच के अनुसार भारत 71वें स्थान पर; पिछली रैंकिंग 63 थी; स्वच्छ ऊर्जा व दक्षता में सुधार, लेकिन ऊर्जा समानता और ग्रिड स्थिरता में कमी।
भारत - वैश्विक एसडीजी सूचकांक 2025	संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDGs) सूचकांक में भारत 99वें स्थान पर, स्कोर: 67; पहली बार शीर्ष 100 में स्थान; स्वास्थ्य, डिजिटल पहुंच और बुनियादी ढांचे में प्रगति।
भारत - विद्युत उत्पादन वृद्धि (IEA)	पिछले पांच वर्षों में वैश्विक विद्युत उत्पादन क्षमता में तीसरी सबसे अधिक वृद्धि; शहरीकरण, औद्योगिक विकास और सौर ऊर्जा के कारण वृद्धि।
भारत - 360 वन वेल्थ क्रिएटर्स लिस्ट 2025	40 वर्ष से कम आयु के युवा उद्यमियों को प्रमुखता; अंबानी भाई-बहन, निखिल कामत, भाविश अग्रवाल अग्रणी; कुल संपत्ति लगभग ₹100 लाख करोड़।
भारत - ट्राई टेलीकॉम रिपोर्ट (Q1 2025)	कुल 1.2 अरब ग्राहक; ₹98,250 करोड़ सकल राजस्व; उच्च औसत राजस्व प्रति उपयोगकर्ता (ARPU); डेटा उपयोग में तेज़ वृद्धि; 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) का उभार।

रिपोर्ट

रिपोर्ट का नाम	प्रस्तुतकर्ता	मुख्य बिंदु
34वीं सीपीग्राम्स रिपोर्ट (मई 2025)	लोक शिकायतों के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG)	कुल 78,123 शिकायतों का निपटारा; उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त व हल; 2 लाख शिकायतें लंबित; 'सेवोत्तम' के तहत 28,000+ अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
सिंप्री ईयरबुक 2025	स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI)	भारत परमाणु शस्त्रागार और डिलीवरी सिस्टम का विस्तार कर रहा है; वैश्विक परमाणु हथियारों की कुल संख्या 12,241; अमेरिका और रूस के पास 90% से अधिक हथियार; नई हथियार दौड़ की चेतावनी।
डब्ल्यूएमओ जलवायु रिपोर्ट 2024	विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)	एशिया में ग्लोबल औसत से दोगुनी तेजी से गर्मी बढ़ रही है; भारत में अत्यधिक गर्मी, हिमनद पिघलना और चक्रवात देखे गए; जलवायु अनुकूलन और समयपूर्व चेतावनी प्रणालियों पर बल।
इंडियाज़ डेटा इम्पैरेटिव - फ्यूचर फ्रंट रिपोर्ट	नीति आयोग	शासन में डेटा गुणवत्ता बेहद कमजोर पाई गई; सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए सटीकता, एकीकरण और मानकीकरण की सिफारिश।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025	यूएन एसडीजी नेटवर्क	भारत का स्थान: 99वां; केवल 17% वैश्विक एसडीजी लक्ष्य समय पर हैं; दक्षिण और पूर्वी एशिया में लक्ष्य प्राप्ति की सबसे तेज़ गति देखी गई।

सूची/सूचकांक (रैंक और रिपोर्ट): मई 2025

रैंकिंग

भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 पर बनी हुई है: एसआरएस 2021 रिपोर्ट

भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) वर्ष 2021 में 2.0 रही, जो कि 2020 के समान है। यह जानकारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) रिपोर्ट 2021 में दी गई है। यह रिपोर्ट देश की बदलती जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों जैसे कि प्रजनन दर, वृद्ध होती जनसंख्या और विवाह रूझानों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। रिपोर्ट के अनुसार, बिहार ने सबसे अधिक TFR 3.0 दर्ज की, जबकि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में सबसे कम TFR 1.4 दर्ज की गई।





क्यों चर्चा में है?

भारत की कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate - TFR) वर्ष 2021 में 2.0 रही, जो कि 2020 के समान है। यह जानकारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 7 मई 2025 को जारी की गई सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) रिपोर्ट 2021 में सामने आई है। यह रिपोर्ट जनसंख्या वृद्धि, वृद्धावस्था, और विवाह रुझानों जैसी प्रमुख जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों की जानकारी देती है — विशेष रूप से तब जब 2021 की जनगणना अब तक नहीं हुई है।

प्रमुख बिंदु: SRS 2021 रिपोर्ट के अनुसार

कुल प्रजनन दर (TFR)

- राष्ट्रीय औसत: 2.0 (2020 के समान)
- सबसे अधिक TFR: बिहार – 3.0
- सबसे कम TFR: दिल्ली व पश्चिम बंगाल – 1.4

TFR प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से कम:

- तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक आदि

TFR प्रतिस्थापन स्तर या अधिक:

- असम (2.1), गुजरात (2.0), हरियाणा (2.0)

आयु संरचना में बदलाव

- 0-14 वर्ष की आबादी में गिरावट:
- 1971 में 41.2% से घटकर 2021 में 24.8%
- 15-59 वर्ष (कार्यशील आयु वर्ग) में वृद्धि:
- 53.4% से बढ़कर 66.2%
- 60+ वर्ष की वृद्ध आबादी:
- 6% से बढ़कर 9%
- 65+ वर्ष: 5.3% से बढ़कर 5.9%

वृद्ध आबादी राज्यों में:

- सबसे अधिक वृद्धजन प्रतिशत:
 - केरल: 14.4%
 - तमिलनाडु: 12.9%
 - हिमाचल प्रदेश: 12.3%
- सबसे कम वृद्धजन प्रतिशत:
 - बिहार: 6.9%
 - असम: 7%
 - दिल्ली: 7.1%

विवाह प्रवृत्तियाँ

- महिलाओं की औसत विवाह आयु:
 - 1990 में 19.3 वर्ष से बढ़कर 2021 में 22.5 वर्ष

SRS सर्वेक्षण के बारे में

- कौन करता है: भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा संचालित
- जनगणना के बाद सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण
- कवरेज: 8,842 सैंपल इकाइयाँ
- नमूना जनसंख्या: लगभग 84 लाख लोग

निष्कर्ष:

SRS 2021 रिपोर्ट भारत की जनसांख्यिकीय संक्रमण (Demographic Transition) की दिशा को दर्शाती है, जिसमें प्रजनन दर में गिरावट, वृद्धावस्था में वृद्धि और विवाह आयु में बदलाव जैसे महत्वपूर्ण संकेत शामिल हैं। यह नीति निर्धारण और जनसंख्या से जुड़ी योजनाओं के लिए अहम दस्तावेज है।

रिपोर्ट

- मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) पर भारत की स्थिर प्रगति स्वास्थ्य और शिक्षा में उल्लेखनीय सुधार को दर्शाती है, जिसमें जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और स्कूल में उपस्थिति में वृद्धि शामिल है। हालांकि, आय और लिंग में असमानताएँ बनी हुई हैं, असमानता ने भारत के एचडीआई को 30% से अधिक कम कर दिया है। रिपोर्ट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भारत की बढ़ती क्षमता पर भी जोर दिया गया है, जिसके भविष्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। इन प्रगति के बावजूद, मानव विकास में वैश्विक प्रगति धीमी बनी हुई है, जो 2025 एचडीआई को उपलब्धियों और चल रही चुनौतियों दोनों के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में चिह्नित करती है।





- आईईए के ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 से पता चलता है कि ऊर्जा क्षेत्र से मीथेन उत्सर्जन उच्च और कम रिपोर्ट किया गया है, जिसमें परित्यक्त बुनियादी ढांचे और जीवाश्म ईंधन संचालन प्रदूषण का मुख्य कारण है। हालांकि तकनीकी समाधान और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञाएँ मौजूद हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन कमजोर है, और उपग्रह डेटा छिपे हुए उत्सर्जन को उजागर करना जारी रखता है। रिपोर्ट निगरानी बढ़ाने, नीतियों को लागू करने और रिसाव और भड़कने को कम करके ऊर्जा सुरक्षा लाभों को अनलॉक करने के लिए तत्काल कार्रवाई का आग्रह करती है।
- नीति आयोग की "मध्यम उद्यमों के लिए नीति तैयार करना" रिपोर्ट एमएसएमई क्षेत्र के एक बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त खंड की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एमएसएमई का केवल 0.3% प्रतिनिधित्व करने के बावजूद, मध्यम उद्यम निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे अपार संभावनाएं दिखती हैं। रिपोर्ट में वित्तीय सहायता, उद्योग 4.0, अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण अवसंरचना, कस्टम स्किलिंग और उनकी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल पर केंद्रित नीतिगत रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इन उपायों का उद्देश्य मध्यम उद्यमों को औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में स्थापित करना है, जो कि विकसित भारत @2047 विजन के साथ संरेखित है।

सूची/सूचकांक (रैंक और रिपोर्ट): अप्रैल 2025

रैंकिंग

- भारत ने वर्ष 2023 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में निजी निवेश के रूप में ₹11,943 करोड़ (अमेरिकी डॉलर 1.4 बिलियन) के साथ वैश्विक स्तर पर 10वां स्थान हासिल किया है, जो वैश्विक AI परिदृश्य में उसकी उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) द्वारा जारी 'फ्रंटियर तकनीकों के लिए तत्परता सूचकांक' में भारत ने 2022 में 48वें स्थान से सुधार करते हुए 2024 में 36वां स्थान प्राप्त किया। हालांकि, भारत को पवन ऊर्जा में जर्मनी, इलेक्ट्रिक वाहनों में जापान और 5जी तकनीक में दक्षिण कोरिया जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। भारत के पास 1.3 करोड़ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की मजबूत कार्यबल है और वह AI अनुसंधान और नैनो तकनीक में अग्रणी देशों में शामिल है। लेकिन इस नेतृत्व को बनाए रखने के लिए अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निरंतर निवेश और कार्यबल कौशल विकास आवश्यक है। अनुमान है कि AI का आर्थिक प्रभाव वर्ष 2033 तक ₹4,09,48,800 करोड़ (अमेरिकी डॉलर 4.8 ट्रिलियन) तक पहुंच सकता है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 7 अप्रैल 2025 को CERT-In, CSIRT-Fin और SISA के सहयोग से BFSI (बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा) क्षेत्र के लिए "डिजिटल ग्रेट रिपोर्ट 2024" जारी की। इस रिपोर्ट का शुभारंभ DFS, MeitY और SISA के शीर्ष अधिकारियों द्वारा किया गया। यह रिपोर्ट साइबर खतरों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है और साइबर सुरक्षा के लिए एक मजबूत रणनीति का खाका प्रदान करती है। रिपोर्ट में AI-आधारित साइबर हमलों, बढ़ते डिजिटल हमले के क्षेत्रों और अनुपालन से जुड़ी चुनौतियों को प्रमुख जोखिम के रूप में उजागर किया गया है। इसमें "लोग, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी" के स्तर पर समन्वित साइबर सुरक्षा रणनीति की सिफारिश की गई है, जिसका उद्देश्य संभावित खतरों का पूर्वानुमान लगाना, सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना और साझा खुफिया जानकारी के माध्यम से एक सुरक्षित डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है।
- Ookla के स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स (फरवरी 2025) के अनुसार, मुंबई ने भारतीय शहरों में सबसे धीमी फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड दर्ज की, जो वैश्विक स्तर पर 123वें स्थान पर रही, जहां डाउनलोड स्पीड 58.24 Mbps रही। वहीं, दिल्ली ने राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जो 89वें स्थान पर रही और डाउनलोड स्पीड 91.11 Mbps रही। इस असमानता के कारण भारत की वैश्विक ब्रॉडबैंड रैंकिंग 94 से गिरकर 95 हो गई। देश की औसत डाउनलोड स्पीड 61.66 Mbps, अपलोड स्पीड 57.89 Mbps और लेटेंसी 7 ms रही। मुंबई के खराब प्रदर्शन के पीछे घनी आबादी और भौगोलिक चुनौतियां प्रमुख कारण मानी गईं।
- दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डा एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) वर्ल्ड द्वारा 2024 में विश्व का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया, जहां 7.7 करोड़ यात्रियों की आवाजाही हुई। यह 2019 में 17वें स्थान से 2023 में 10वें और अब 2024 में 9वें स्थान तक पहुंचकर भारत की बढ़ती विमानन क्षमता, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और वैश्विक कनेक्टिविटी को दर्शाता है। GMR समूह के तहत दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) द्वारा संचालित IGI, शीर्ष 10 वैश्विक हवाई अड्डों में शामिल एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा है। इस सूची में शीर्ष पर अटलांटा और दुबई जैसे हवाई अड्डे हैं, जबकि 2024 में कुल 9.5 अरब यात्रियों ने हवाई यात्रा की।
- नीति आयोग की रिपोर्ट 'Unlocking \$25+ Billion Export Potential - India's Hand & Power Tools Sector' में भारत के हाथ और पावर टूल्स उद्योग के वैश्विक बाजार में अवसरों का विश्लेषण किया गया है, जिसका वर्तमान मूल्य \$100 अरब है और जो 2035 तक \$190 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास इस क्षेत्र में \$25 अरब के निर्यात और अगले दशक में 35 लाख नौकरियों के सृजन की अपार संभावनाएं हैं। हालांकि, उच्च कच्चे माल और लॉजिस्टिक्स लागत के कारण भारत को लागत संबंधी प्रतिस्पर्धा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
- 2025 की TIME 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनस जैसे वैश्विक हस्तियों को शामिल किया गया है, जिन्होंने राजनीति, नवाचार और सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। गौरतलब है कि इस वर्ष सूची में कोई भी भारतीय व्यक्तित्व शामिल नहीं है, जबकि 2024 में आलिया भट्ट और साक्षी मलिक को इस प्रतिष्ठित सूची में स्थान मिला था।





रिपोर्ट

रिपोर्ट का नाम	प्रस्तुतकर्ता	मुख्य बिंदु
यूनेस्को रिपोर्ट	यूनेस्को	‘न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ’ कार्यक्रम (27-28 मार्च 2025, फ्रांस) में स्कूल भोजन की गुणवत्ता पर चिंता जताई गई। ▶ 2024 में 47% प्राथमिक छात्र भोजन प्राप्त कर रहे थे। ▶ 27% भोजन में पोषण विशेषज्ञ की भूमिका नहीं थी। ▶ 187 में से केवल 93 देशों में स्कूल फूड कानून हैं। ▶ 65% देशों ने खाद्य मानक तय किए हैं।
2025 प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट	यूएनसीटीएडी	भारत ने फ्रंटियर तकनीकों को अपनाने में प्रगति की है, 2022 में 48वें स्थान से बढ़कर 2025 में 36वें स्थान पर पहुंचा। ▶ आईसीटी, अनुसंधान, औद्योगिक क्षमता और वित्त में सुधार। ▶ एआई और नैनो टेक्नोलॉजी में अग्रणी। ▶ विकासशील देशों के बीच भारत उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

पुस्तक और लेखक

पुस्तक और लेखक: सितम्बर 2025

पुस्तक का नाम	लेखक	मुख्य बिंदु
द चोल टाइगर्स : एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ	Amish Tripathi	Indic Chronicles श्रृंखला की दूसरी पुस्तक; लॉन्च हुई Crossword Kemps Corner में; सेलेब्स Ravi Dubey और Jimmy Shergill ने भी हिस्सा लिया।
डिफरेंट बट नो लेस	अनुपम खेर	चौथी पुस्तक; जून 2025 में रिलीज़ होगी; साहस और आत्म-विश्वास पर केंद्रित, उनके फिल्मी सफर से प्रेरित।
मदर मैरी कम्स टू मी	अरुंधति राय	2025 में रिलीज़ होने वाली संस्मरण; “The God of Small Things” के बाद उनका पब्लिशिंग में वापसी।

पुस्तक और लेखक: अगस्त 2025

पुस्तक का नाम	लेखक	मुख्य बिंदु
एम.एस. स्वामीनाथन: द मैं हू फेड इंडिया	प्रियंवदा जयकुमार	एम.एस. स्वामीनाथन की जीवनी, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उनके प्रारंभिक जीवन, विज्ञान को आईपीएस पर चुनने, भारत को खाद्यान्न आत्मनिर्भर बनाने में योगदान का विवरण। इतिहास, व्यक्तिगत प्रसंगों और वैज्ञानिक उपलब्धियों का मिश्रण।
ए ट्रीटाइज़ फॉर द रिमार्केबल रोहित	आर. कौशिक	रोहित शर्मा की जीवनगाथा – अंडर-17 क्रिकेट से लेकर भारत के सभी प्रारूपों के कप्तान बनने तक की यात्रा। झटके: 2010 टेस्ट डेब्यू छूटना, 2011 विश्व कप से बाहर रहना। उपलब्धियाँ: वनडे दोहरे शतक, 2019 में टेस्ट ओपनिंग सफलता, भारत को 2024 T20 वर्ल्ड कप व 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जिताना। सहकर्मियों व कोचों की आवाज़ों से सजी गर्मजोशी भरी कथा।
द कॉन्सियंस नेटवर्क	सुगाता श्रीनिवासराजू	आपातकाल (1975-77) के दौरान भारतीय प्रवासी प्रतिरोध की कहानी। अमेरिका में “इंडियंस फॉर डेमोक्रेसी (IFD)” समूह की भूमिका – शांतिपूर्ण विरोध, लॉबिंग व भारतीय लोकतंत्र के लिए वकालत। प्रवासी भारतीयों की देशभक्ति और नैतिक साहस का दस्तावेज़।

पुस्तक और लेखक: जुलाई 2025

पुस्तक का नाम	लेखक	मुख्य बिंदु
एक शेक्सपीयर प्रेमी की आत्मस्वीकृति (Confessions of a Shakespeare Addict)	वी.एस. (सेवानिवृत्त अधिकारी)	रवि 7 जुलाई 2025 को हैदराबाद में विमोचन। यह पुस्तक शेक्सपीयर के प्रति लेखक के प्रेम व साहित्यिक सफर को समर्पित है। अतिथि वक्ताओं ने लेखक की शेक्सपीयर पर गहरी समझ की सराहना की। उद्देश्य: शेक्सपीयर को आधुनिक पाठकों तक पहुँचाना।
दस पैसे का पोस्टकार्ड	एस. एन. (सेवानिवृत्त अधिकारी)	अहमद सैन्य 10 जुलाई 2025 को हैदराबाद में विमोचन। पोस्टकार्ड युग की भावनात्मक सुंदरता को उजागर करती है। अभिनेता विनय वर्मा द्वारा लॉन्च। जल्द ही नाटक के रूप में रूपांतरित होगी।





पुस्तक का नाम	लेखक	मुख्य बिंदु
छात्रों का सतत् स्वास्थ्य: उच्च शिक्षा में एक साझा जिम्मेदारी	(लेखक का नाम नहीं दिया गया)	26 जुलाई 2025 को देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विमोचन। उद्देश्य: उच्च शिक्षा में छात्रों की मानसिक व सामाजिक चुनौतियों के समाधान की आवश्यकता पर प्रकाश डालना।

पुस्तक और लेखक: जून 2025

पुस्तक का नाम	लेखक	मुख्य बिंदु
इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया	टी.सी.ए. श्रीनिवास राघवन	- इंदिरा गांधी के कार्यकाल (1975-77 की आपातकाल) का गहन विश्लेषण - लोकतंत्र, कार्यपालिका का वर्चस्व और नीति परिवर्तनों को रेखांकित करता है - आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ से पूर्व जारी
इंडिया: 5000 इयर्स ऑफ हिस्ट्री	ऑड्री ट्रशके	- भारत के 5000 वर्षों के इतिहास का समग्र विवरण - अभिलेखीय शोध, कथात्मक विश्लेषण और बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण का समावेश - सरलीकृत ऐतिहासिक दृष्टिकोण को चुनौती देता है
द स्टार्स लाइट द वे	सुचेता राज खन्ना	- शाज़मा की आध्यात्मिक और राजनीतिक यात्रा पर आधारित उपन्यास - पहचान, पूर्वजों की बुद्धि और आत्म-परिवर्तन की खोज - आस्था, साहस और आत्मिक जुड़ाव पर केंद्रित
इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स III: डिफरेंट स्टोक्स (1998-2014)	ए.के. भट्टाचार्य	- उदारीकरण के बाद चार वित्त मंत्रियों के निर्णयों का विश्लेषण - नीति परिवर्तनों और राजकोषीय सुधारों पर कथात्मक शैली - निष्पक्ष दृष्टिकोण; अर्थशास्त्रियों व UPSC छात्रों के लिए उपयुक्त
"वूमन! लाइफ! फ्रीडम!"	चवरा मकारेमी	- महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में 2022 के विद्रोह पर केंद्रित - मानवशास्त्र, व्यक्तिगत अनुभव और राजनीतिक प्रतिरोध का समावेश - ईरान की नारीवादी क्रांति और विरोध का इतिहास दर्शाता है
द इमरजेंसी डायरीज़	(लेखक उल्लेखित नहीं; अमित शाह द्वारा विमोचित)	- आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर प्रकाशित - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिगत गतिविधियों का दस्तावेजीकरण - व्यक्तिगत विवरण और अभिलेखों के माध्यम से लोकतांत्रिक संघर्ष को उजागर करता है
द वन: क्रिकेट, माय लाइफ एंड मोर	शिखर धवन	- शिखर धवन की आत्मकथा; क्रिकेट करियर और व्यक्तिगत संघर्षों का विवरण - टीममेट्स की प्रतिक्रियाएं और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान - हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा 26 जून 2025 को प्रकाशित

पुस्तक और लेखक: मई 2025

पुस्तक का नाम	लेखक	मुख्य बिंदु
PMO: प्रधानमंत्री कार्यालय - वर्षों की यात्रा	हिमांशु राय	15 अप्रैल 2025 को रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के विकास, ढांचे और महत्व की गहराई से चर्चा की गई है। यह पं. नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, सभी प्रधानमंत्रियों द्वारा PMO पर डाले गए प्रभाव को दर्शाती है।
जनता की कहानी - मेरी आत्मकथा	उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचित (लेखक: बंडारू दत्तात्रेय)	हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा, जिसे उपराष्ट्रपति ने जारी किया। यह पुस्तक उनके जीवन संघर्ष, सार्वजनिक सेवा और सामाजिक योगदान को प्रस्तुत करती है।





पुस्तक का नाम	लेखक	मुख्य बिंदु
ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स	नागालैंड सरकार	16 मई 2025 को जारी यह कॉफी टेबल बुक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत नागालैंड में हुए शहरी विकास और सस्ती आवास उपलब्धता की सफल कहानियाँ साझा करती है। यह पुस्तक समावेशी और टिकाऊ विकास के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
ओरिजिनल सिन	जेक टैपर और एलेक्स थॉम्पसन	यह पुस्तक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की मानसिक क्षमताओं में आई गिरावट की जाँच करती है और उनके निकटतम सहयोगियों द्वारा इस स्थिति को जनता से छिपाने के प्रयासों को उजागर करती है। इसमें मीडिया की निष्क्रियता और कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर भी प्रकाश डाला गया है।
एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी	पूजा पुजारा	चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा द्वारा लिखित यह संस्मरण एक क्रिकेटर के परिवार की चुनौतियों, मीडिया दबाव और व्यक्तिगत दृढ़ता की सच्ची झलक पेश करता है। यह वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2023 के बाद पुजारा के टीम से बाहर होने की घटना से प्रेरित है।

पुस्तक और लेखक: अप्रैल 2025

पुस्तक का नाम	लेखक / प्रकाशक	मुख्य बिंदु
द ग्रेट कन्सिलिएटर: लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया	संजीव चोपड़ा	• यह पुस्तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन और योगदान पर प्रकाश डालती है। इसमें BSF की स्थापना और "जय जवान, जय किसान" नारे की ऐतिहासिक भूमिका को रेखांकित किया गया है।
द इंडिया आई सॉ	एस. अम्बुजम्मल	• एस. अम्बुजम्मल की आत्मकथा 'नान कांडा भारतम' (अनुवाद: The India I Saw) में उनके संघर्षों और सामाजिक सुधार कार्यों का वर्णन है। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और गांधीवादी थीं, जिन्होंने महिला कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
केयरलेस पीपल	सारा विन-विलियम्स	• फेसबुक (अब मेटा) की पूर्व नीति निदेशक सारा विन द्वारा लिखित इस पुस्तक में कंपनी के अंदर चल रहे नैतिक पतन, नेतृत्व विफलताओं, और विवादास्पद वैश्विक हस्तक्षेप (जैसे 2016 अमेरिकी चुनाव, म्यांमार संकट) का खुलासा किया गया है।
आई एम सर्कुलर	MeitY व इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकोनॉमी (ICCE)	• यह कॉफी टेबल बुक भारत में परिपत्र अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 30 नवाचारों को प्रदर्शित करती है। इसमें ई-कचरा रीसाइक्लिंग, IoT-आधारित समाधान, और बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग जैसी पहल शामिल हैं। इसे 23 अप्रैल 2025 को लॉन्च किया गया।
संस्कृति का पाँचवाँ अध्याय	(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन)	• यह पुस्तक प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का संग्रह है जो भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और परंपरागत धरोहर पर केंद्रित है। 18 अप्रैल 2025 को IGNCA नई दिल्ली में इसका विमोचन हुआ, जिसमें कई प्रमुख संत और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

खेल करेंट अफेयर्स

खेल करेंट अफेयर्स: सितम्बर 2025

क्रिकेट

- 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप और 2026 टी20 विश्व कप से पहले महिला क्रिकेट के अनुभव को डिजिटल रूप से बेहतर बनाने के लिए आईसीसी-गूगल साझेदारी की घोषणा की गई।
- 2025 महिला विश्व कप विजेताओं के लिए रिकॉर्ड ₹40 करोड़ का पुरस्कार घोषित, 2022 से 239% की वृद्धि; टूर्नामेंट की सह-मेजबानी भारत और श्रीलंका द्वारा की जाएगी (30 सितंबर, 2025 से)।
- आईसीसी ने 30 सितंबर से गुवाहाटी में शुरू होने वाले महिला विश्व कप से पहले भारतीय सितारों को शामिल करते हुए "विल टू विन" अभियान शुरू किया।
- मिचेल स्टार्क ने भारत-श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप से छह महीने पहले, 65 मैच (79 विकेट) खेलने के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले लिया और अब वनडे और टेस्ट पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
- अमित मिश्रा ने संन्यास लिया: अनुभवी भारतीय लेग स्पिनर ने 22 टेस्ट, 36 वनडे, 3 आईपीएल हैट्रिक और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीत के एक हिस्से के साथ 25 साल के करियर का अंत किया।

बैडमिंटन और टेनिस

- सात्विक-चिराग ने मलेशिया के चिया-यिक को हराकर पेरिस में 2025 विश्व चैंपियनशिप में कम से कम कांस्य पदक पक्का किया, जो इस आयोजन में उनका दूसरा पदक था।
- नई दिल्ली अगस्त में 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा, यह आयोजन 17 साल बाद भारत में वापसी कर रहा है (पिछली बार 2009 में हैदराबाद में)।
- अल्काराज़ ने जैनिन सिनर को हराकर दूसरा यूएस ओपन खिताब जीता; यह उनका छठा ग्रैंड स्लैम है, और उन्होंने विश्व में नंबर 1 एटीपी रैंकिंग हासिल की।
- सबालेंका ने अमांडा अनिसिमोवा को हराकर यूएस ओपन का खिताब बरकरार रखा, सेरेना विलियम्स के बाद लगातार दो खिताब जीतने वाली पहली महिला।

तीरंदाजी और निशानेबाजी

- कपाउंड तीरंदाजी में ऐतिहासिक स्वर्ण: भारत की पुरुष टीम ने विश्व चैंपियनशिप में फ्रांस को 235-233 से हराकर इस स्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता।





- डोपिंग-रोधी सफलता: नाइपर, गुवाहाटी और एनडीटीएल ने मेथांडिएनोन दीर्घकालिक मेटाबोलाइट संदर्भ सामग्री विकसित की, जिससे वैश्विक डोपिंग-रोधी प्रयासों को बढ़ावा मिला।

एथलेटिक्स और फुटबॉल

- भारत ने राजगीर में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर अपना चौथा एशिया कप हॉकी खिताब जीता, 8 साल का सूखा खत्म किया और विश्व कप के लिए जगह पक्की की।
- भारत ने CAFA नेशंस कप में इतिहास रचा, ताजिकिस्तान में 1-1 से ड्रा के बाद ओमान को 3-2 (पेनल्टी शूटआउट) से हराकर कांस्य पदक जीता।
- 16 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा ने FIDE ग्रैंड स्विस् 2025 (समरकंद) में मौजूदा विश्व चैंपियन डी. गुकेश को हराकर क्लासिकल शतरंज में मौजूदा चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए।

अन्य खेल समाचार

- ऑस्कर पियास्त्री ने मैकलारेन के लिए ज़ेंडवूर्ट में डच जीपी 2025 जीता; टीम के साथी नॉरिस के रिटायर होने के बाद 34 अंकों की बढ़त बनाए रखी।
- वेरस्टैपेन ने इटैलियन जीपी 2025 (7 सितंबर) जीता, जो मई के बाद उनकी पहली जीत थी; क्वालीफाइंग के दौरान एफ1 इतिहास का सबसे तेज़ लैप लगाया।
- विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 नए शासी निकाय विश्व मुक्केबाजी के तहत लिवरपूल में शुरू हुई; भारत का प्रतिनिधित्व निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, सुमित कुंडु करेंगे।
- भारत 11-15 अक्टूबर, 2025 को भुवनेश्वर में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा।

खेल करंट अफेयर्स: अगस्त 2025

क्रिकेट

- एजबेस्टन में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) 2025 के फाइनल में, एबी डिविलियर्स ने सिर्फ 58 गेंदों पर शानदार शतक जड़कर दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस को पाकिस्तान चैंपियंस पर 9 विकेट से शानदार जीत दिलाई। शरजील खान के 76 रनों की बदौलत पाकिस्तान ने 195/5 का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया था। हालांकि, जेपी डुमिनी के समर्थन और डिविलियर्स के मास्टरक्लास ने लक्ष्य का आसानी से पीछा सुनिश्चित किया। चोट से जूझने के बावजूद, डिविलियर्स ने पाकिस्तान के जोशीले प्रदर्शन पर पानी फेर दिया और WCL के दूसरे संस्करण में दक्षिण अफ्रीका के लिए खिताब पक्का कर दिया।



- ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर 13,545 रनों के साथ विराट कोहली को पीछे छोड़कर टी20 क्रिकेट में पांचवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं वार्नर ने मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के खिलाफ 51 गेंदों में शानदार 71 रन बनाए, जिससे उनके टी20 आँकड़े 419 मैचों, 36.80 औसत, 140+ स्ट्राइक रेट, 8 शतक और 113 अर्द्धशतकों तक पहुँच गए। उनके इस प्रदर्शन के बावजूद, उनकी टीम 164 रनों के लक्ष्य का पीछा करने से चूक गई। द हंड्रेड में यह वार्नर का पहला सीज़न है, जहाँ उन्होंने पहले ही 3 मैचों में 75.00 की औसत से 150 रन बना लिए हैं।
- शुभमन गिल और सोफिया डंकले को जुलाई 2025 के लिए ICC प्लेयर्स ऑफ़ द मंथ चुना गया। गिल ने भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में अपनी पहली सीरीज़ में इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों में 567 रन बनाए, सोफिया डंकले ने भारत के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय और एकदिवसीय श्रृंखला में इंग्लैंड के लिए शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय में 144 और एकदिवसीय मैचों में 126 रन बनाए। उन्होंने लगातार मैच जिताऊ बल्लेबाजी प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्हें महीने की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला।
- आर अश्विन 2025 सीज़न के बाद आईपीएल से संन्यास ले लेंगे (221 मैच, 187 विकेट); विदेशी लीग खेलने के पत्र।
- डेविड वार्नर की उपलब्धि: द हंड्रेड 2025 में लंदन स्प्रिट के लिए खेलते हुए विराट कोहली को पछाड़कर 5वें सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले खिलाड़ी (13,545 रन) बन गए।
- आईसीसी प्लेयर्स ऑफ़ द मंथ (जुलाई 2025):
- पुरुष: शुभमन गिल - इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों में 567 रन (डेव्यू टेस्ट कप्तान के रूप में 269 रन सहित)।
- महिला: सोफिया डंकले - भारत के खिलाफ 144 टी20I + 126 वनडे रन।

तीरंदाजी और निशानेबाजी

- भारत ने अपनी पहली तीरंदाजी लीग शुरू की है, जिसका आयोजन अक्टूबर 2025 में दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा आयोजित इस लीग में छह फ्रैंचाइज़ी टीमें भाग लेंगी, जिनमें शीर्ष भारतीय और अंतराष्ट्रीय तीरंदाज शामिल होंगे। इसे विश्व तीरंदाजी, विश्व तीरंदाजी एशिया और खेल मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है। इस पेशेवर लीग से भारत में इस खेल में क्रांति आने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और वैश्विक ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद है।

एथलेटिक्स और फुटबॉल

- भारत की स्टार भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी ने पोलैंड में अंतराष्ट्रीय विस्लाव मनियाक मेमोरियल में 62.59 मीटर के सीज़न के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। 32 वर्षीय एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता ने शुरुआती बढ़त के साथ इस स्पर्धा में अपना दबदबा बनाया और अब इस सीज़न में दुनिया की शीर्ष 15 भाला फेंक खिलाड़ियों में शामिल हैं। उनका लक्ष्य टोक्यो में 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए 64 मीटर का क्वालीफिकेशन मार्क पार करना है।
- महिला फुटबॉल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी का उद्घाटन हैदराबाद के गाचीबोवली स्टेडियम परिसर में किया गया। एआईएफएफ, फीफा और तेलंगाना सरकार के बीच सहयोग से शुरू की गई यह पहल 30 लड़कियों और 30 लड़कों को आवासीय प्रशिक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण कार्यक्रमों के साथ सहायता प्रदान करेगी। यह अकादमी फीफा की प्रतिभा विकास योजना के तहत भारत के युवाओं को अंडर-17 फीफा विश्व कप जैसी वैश्विक प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।





- ब्रांड फाइनल फुटबॉल 50 रिपोर्ट में रियल मैड्रिड को 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है। इसकी ब्रांड वैल्यू €1.921 बिलियन और ब्रांड स्ट्रेंथ स्कोर लगभग 94.9 है। लगातार चौथे साल रैंकिंग में शीर्ष पर रहने वाली रियल मैड्रिड की सफलता का श्रेय उसके वैश्विक प्रशंसक आधार, रिकॉर्ड राजस्व और रणनीतिक प्रायोजन को जाता है, जिसमें उसका 15वां यूईएफए चैंपियंस लीग खिताब भी शामिल है। अन्य शीर्ष क्लबों में एफसी बार्सिलोना (€1.7 बिलियन), मैनचेस्टर सिटी (€1.4 बिलियन), लिवरपूल (€1.4 बिलियन) और पीएसजी (€1.4 बिलियन) शामिल हैं, जो यूरोप की शीर्ष फुटबॉल टीमों की व्यावसायिक शक्ति को दर्शाते हैं।
- भारत की मिनर्वा अकादमी एफसी ने अंडर-14 नॉर्वे कप 2025 जीतकर इतिहास रच दिया है। उसने फाइनल में नॉर्वेजियन टीम एसआईएफ को 14-1 से हराकर शानदार जीत हासिल की। चंडीगढ़ स्थित इस अकादमी ने न केवल ट्रांफी जीती, बल्कि आठ मैचों में 130 गोल करके सर्वकालिक टूर्नामेंट स्कोरिंग रिकॉर्ड भी बनाया—प्रति मैच 16.57 गोल का आश्चर्यजनक औसत।

अन्य खेल समाचार

- हंगेरियन ग्रां प्री 2025 में, लैंडो नॉरिस ने अपने साथी ऑस्कर पियास्त्री के साथ कड़े मुकाबले के बाद रोमांचक जीत हासिल की और केवल 0.698 सेकंड आगे रहे। यह नॉरिस की सीज़न की पाँचवीं जीत थी, जिससे पियास्त्री की चैंपियनशिप बढ़त केवल नौ अंकों की रह गई। जॉर्ज रसेल ने पोडियम स्थान हासिल किया, जबकि शुरुआती नेता चार्ल्स लेक्लर पेनल्टी के कारण चौथे स्थान पर खिसक गए। इस दौड़ में कई रणनीतिक आश्चर्य और कड़े मुकाबले देखने को मिले, जिससे यह सीज़न के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक बन गया।
- शतरंज में, मैग्नस कार्लसन ने रियाद में आयोजित शतरंज ईस्पोर्ट्स विश्व कप 2025 में अपना दबदबा बनाया और अलीरेज़ा फ़िरोज़ा को 4-2-1 के स्कोर से हराया। टीम लिक्विड का प्रतिनिधित्व करते हुए, कार्लसन ने पहला खिताब और \$250,000 का पुरस्कार जीता, जबकि टीम फाल्कन्स के लिए खेलते हुए फ़िरोज़ा ने \$190,000 जीते। यह आयोजन एक ऐतिहासिक कदम है क्योंकि शतरंज ईस्पोर्ट्स युग को अपना रहा है और पारंपरिक महारत को डिजिटल जुड़ाव के साथ जोड़ रहा है।
- भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने दिल्ली में अपनी विशेष आम बैठक के दौरान 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। भारत 31 अगस्त की समय सीमा से पहले अपना अंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। अगर यह प्रस्ताव सफल रहा, तो यह 20 साल पूरे हो जाएँगे जब भारत ने 2010 में नई दिल्ली में खेलों की मेजबानी की थी, जो देश का पहला और एकमात्र ऐसा आयोजन था।
- भारत की नम्रता बत्रा ने चीन के चेंगदू में होने वाले 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में पहुँचकर इतिहास रच दिया है। फिलीपींस की क्रिज़न फेथ कोलाडो को 2-0 से हराकर, उन्होंने वुशु में भारत का पहला विश्व खेल पदक पक्का कर लिया है, जिससे कम से कम रजत पदक पक्का हो गया है। अब मंगलवार को होने वाले फाइनल में नम्रता का सामना चीन की मंग्यू चैन से होगा और वे स्वर्ण पदक के लिए संघर्ष करेंगी। इसके अलावा, ऋषभ यादव ने पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में कांस्य पदक जीतकर खेलों में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक जीता।

- खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव (केआईडब्ल्यूएसएफ) के शुभंकर और लोगो का श्रीनगर में अनावरण किया गया। यह आयोजन खेलो इंडिया पहल के तहत पहली बार जल खेलों से पहले किया गया, जो 21-23 अगस्त, 2025 तक डल झील में आयोजित किया जाएगा। रंग-बिरंगे हिमालयन किंगफिशर, जो साहसिक कार्य, पर्यावरण-खेल और कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है, को आधिकारिक शुभंकर के रूप में पेश किया गया। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और साई के सहयोग से जम्मू-कश्मीर खेल परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में रोइंग, कैनोइंग और कयाकिंग जैसे पदक स्पर्धाओं के साथ-साथ शिकारा रेस और ट्रैगन बोट रेस जैसे डेमो इवेंट भी शामिल होंगे। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद है, जिससे डल झील भारत में जल खेलों का एक नया केंद्र बन जाएगी।
- भारत ने बैंकॉक में एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल 27 पदक हासिल किए, जिसमें रितिका ने महिलाओं के 80+ किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर एक मजबूत अंत किया। अंडर-19 टीम ने 14 पदक (3 स्वर्ण, 7 रजत, 4 कांस्य) जीते और कुल मिलाकर दूसरे स्थान पर रही, जबकि अंडर-22 टीम ने 13 पदक (1 स्वर्ण, 4 रजत, 8 कांस्य) अर्जित किए। यात्री पटेल, प्रिया, नीरज और इशान कटारिया जैसे खिलाड़ियों ने रजत पदक जीते, जिनमें से सभी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ये परिणाम शौकिया मुक्केबाजी में भारत की बढ़ती ताकत और उसकी युवा प्रतिभाओं की प्रबलता की पुष्टि करते हैं।

टेनिस

- इगा स्विएटेक ने जैस्मीन पाओलिनी (7-5, 6-4) को हराकर सिनसिनाटी ओपन 2025 जीता; अपने करियर का 24वां खिताब, विश्व में दूसरे स्थान पर वापसी।
- कार्लोस अल्काराज़ ने पुरुषों का सिनसिनाटी ओपन 2025 जीता, जो इस साल उनका छठा खिताब है, उन्होंने जैनिन सिनर (बीमार होने के कारण सेवानिवृत्त) को हराया; अब एटीपी रेस में ट्यूरीन की ओर से सबसे आगे हैं।

खेल करंट अफेयर्स: जुलाई 2025

क्रिकेट

- भारत ने 6 जुलाई, 2025 को एजबेस्टन में ऐतिहासिक टेस्ट जीत हासिल की, जिसमें उसने इंग्लैंड को रिकॉर्ड 336 रनों के अंतर से हराया, जो रनों के लिहाज से भारत की विदेश में सबसे बड़ी जीत थी। आकाश दीप ने 10 विकेट लिए, जो इंग्लैंड में किसी भारतीय द्वारा सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्रदर्शन था। एजबेस्टन में सात हार के बाद यह भारत की पहली टेस्ट जीत भी थी। इस मैच में कई रिकॉर्ड टूटे, जिसमें दोनों देशों के बीच किसी टेस्ट में सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड भी शामिल है। भारत ने अब श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली है, जो भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक गौरवपूर्ण क्षण है।
- आईपीएल का कुल मूल्य 2025 में बढ़कर 18.5 अरब डॉलर हो गया, जो एक शीर्ष खेल लीग के रूप में इसकी बढ़ती स्थिति को दर्शाता है। 2025 का खिताब जीतने के बाद, आरसीबी 26.9 करोड़ डॉलर के साथ सबसे मूल्यवान फ्रैंचाइज़ी बन गई। मुंबई इंडियंस और सीएसके ने भी दूसरा स्थान हासिल किया। प्रायोजन और दर्शकों की संख्या ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए—जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स ने ऐतिहासिक आंकड़े दर्ज किए। टाटा समूह ने अपने प्रायोजन सौदे को आगे बढ़ाया और पीबीकेएस ने ब्रांड वैल्यू में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की। लीग की सफलता दर्शाती है कि आईपीएल अब एक वैश्विक खेल व्यवसाय है, जो क्रिकेट, मनोरंजन और मीडिया को एक ऐसे तरीके से जोड़ता है जैसा कि कुछ ही अन्य आयोजन करते हैं।





- 10 जुलाई, 2025 को, क्रिकेट के घर कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड स्थित एमसीसी संग्रहालय में सचिन तेंदुलकर के चित्र का आधिकारिक अनावरण किया गया। यह चित्र स्टुअर्ट पियर्सन राइट ने बनाया था और तेंदुलकर ने भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट मैच की शुरुआत के लिए घंटी भी बजाई। उन्होंने इंग्लैंड में बिताए अपने शुरुआती दिनों की यादें साझा कीं और कहा कि यह चित्र उनके सफ़र का एक खास पल था। उन्होंने भारत के नए कप्तान शुभमन गिल की उनके शांत नेतृत्व और शानदार फ़ॉर्म के लिए भी प्रशंसा की।
- 11 जुलाई, 2025 को, इटली और नीदरलैंड दोनों ने यूरोप क्वालीफायर के अंतिम मैचों के बाद ICC पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में अपनी जगह पक्की कर ली। यह इटली का इस वैश्विक आयोजन में पहला प्रदर्शन होगा। नीदरलैंड से हारने के बावजूद, इटली ने बेहतर नेट रन रेट बनाए रखते हुए, अपने विरोधियों को 17वें ओवर तक रोककर क्वालीफिकेशन सुनिश्चित किया। नीदरलैंड ने रोलोफ वैन डेर मेरवे और माइकल लेविट के दमदार प्रदर्शन से 134/7 के लक्ष्य का पीछा किया। अब तक कुल 15 टीमें क्वालीफाई कर चुकी हैं, और आगामी क्वालीफायर के माध्यम से और टीमों की पुष्टि की जाएगी। विश्व कप 2026 में भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा।
- एमआई न्यू यॉर्क ने 14 जुलाई को डलास के ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम में वाशिंगटन फ्रीडम को 5 रनों से हराकर 2025 मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) का खिताब जीत लिया। सीज़न की खराब शुरुआत के बाद, एमआई न्यू यॉर्क ने क्विंटन डी कॉक, निकोलस पूरन, ट्रेट बोल्ट और रुशिल उगरकर जैसे खिलाड़ियों की मदद से ज़ोरदार वापसी की। डी कॉक ने 77 रन बनाए, जबकि उगरकर ने शानदार आखिरी ओवर फेंककर फ्रीडम को 181 के लक्ष्य तक पहुँचने से रोक दिया। यह एमआई न्यू यॉर्क का दूसरा एमएलसी खिताब है, जिसने तालिका में सबसे निचले स्थान से चैंपियन बनने तक के उनके सफर को वाकई प्रेरणादायक बना दिया है।
- अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने दक्षिण अफ्रीका के एडेन मार्करम और वेस्टइंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज को जून 2025 के प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया। मार्करम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ WTC फाइनल में 136 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली, जिससे दक्षिण अफ्रीका 1998 के बाद अपना पहला ICC खिताब जीतने में कामयाब रहा। मैथ्यूज ने वनडे में 104 रन और 4 विकेट लेकर प्रभावित किया, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20I श्रृंखला में 147 रन और 2 विकेट लिए। यह मैथ्यूज का चौथा ICC पुरस्कार है, जिससे वह मासिक रैंकिंग में दूसरी सबसे अधिक पुरस्कार पाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। दोनों खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन पर गर्व व्यक्त किया और भविष्य के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया।
- आंद्रे रसेल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इस तरह उनके 15 साल के करियर का अंत हो गया, जिसमें दो टी20 विश्व कप, 84 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच (1,078 रन और 61 विकेट) और एक मज़बूत वैश्विक फ्रैंचाइज़ी रिकॉर्ड शामिल है। उनका विदाई मैच 20 और 22 जुलाई, 2025 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जमैका में होगा। वह 2026 आईसीसी टी20 विश्व कप से पहले निकोलस पूरन के बाद संन्यास ले रहे हैं और अपने पीछे शक्ति, प्रदर्शन और गौरव की विरासत छोड़ रहे हैं।

बैडमिंटन और टेनिस

- जैनिन सिनर ने 13 जुलाई, 2025 को दो बार के गत विजेता कार्लोस अल्काराज़ को फाइनल में हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता। यह मैच 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 के स्कोर पर समाप्त हुआ। इस जीत

ने सिनर को अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब दिलाया और अल्काराज़ के 24 मैचों के विजय क्रम को रोक दिया। पुरुष टेनिस के शीर्ष सितारे, ये दोनों खिलाड़ी पिछले सात प्रमुख खिताब साझा कर चुके हैं, जो उनके बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता को दर्शाता है। सिनर की जीत भी फ्रेंच ओपन में अल्काराज़ से हारने के बाद आई, जिससे यह एक शानदार वापसी साबित हुई।

- इगा स्वियाटेक ने 12 जुलाई, 2025 को अमांडा अनिसिमोवा को मात्र 57 मिनट में 6-0, 6-0 के अभूतपूर्व स्कोर से हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता। यह जीत स्वियाटेक का छठा ग्रैंड स्लैम खिताब था और वह तीनों कोर्ट पर जीत हासिल करने वाली एकमात्र सक्रिय महिला खिलाड़ी बन गईं। अपना पहला बड़ा फाइनल खेल रही अनिसिमोवा, स्वियाटेक के स्तर की बराबरी नहीं कर सकीं। हाल के संघर्षों और एक संक्षिप्त डोपिंग प्रतिबंध के बावजूद, स्वियाटेक ने अपनी ताकत और दृढ़ संकल्प साबित किया। वेल्स की राजकुमारी केट ने फाइनल में भाग लिया, जिससे यह आयोजन और भी खास हो गया। यह जीत महिला टेनिस में एक बड़ी वापसी और ऐतिहासिक क्षण का प्रतीक है।
- जापान ओपन बैडमिंटन 2025, जो बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर का एक प्रमुख आयोजन है, में चीन के शी युकी ने पुरुष एकल का खिताब जीता, जबकि दक्षिण कोरिया की एन से-यंग ने महिला एकल में साल की अपनी छठी चैंपियनशिप जीती। चीन कुल तीन स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश बना, जबकि दक्षिण कोरिया और मलेशिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। इस टूर्नामेंट ने वैश्विक बैडमिंटन में एशियाई देशों के प्रभुत्व को और मजबूत किया, और सभी स्पर्धाओं में विश्व स्तरीय प्रतिभा और लचीलेपन का प्रदर्शन किया।
- भारत ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रच दिया जब तन्वी शर्मा और वेन्नाला कलागोटला एक ही संस्करण में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एकल जोड़ी बन गईं। जूनियर वर्ल्ड नंबर 1 तन्वी ने सीधे गेम्स में जीत के साथ अपना दबदबा दिखाया, जबकि वर्ल्ड नंबर 103 वेन्नाला ने कड़े मुकाबलों में दृढ़ता दिखाई। यह अभूतपूर्व उपलब्धि जूनियर महिला बैडमिंटन में भारत के बढ़ते कद को दर्शाती है और देश की खेल उपलब्धियों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

चेस

- भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने 4 जुलाई को क्रोएशिया के ज़ाग्रेब में सुपरयूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज़ 2025 में 14 अंक हासिल करते हुए रैपिड खिताब जीता। अब वह ग्रैंड शतरंज टूर में जान-क्रिज़स्टॉफ़ डूडा (11 अंक) और मैग्नस कार्लसन (10 अंक) से आगे हैं। ब्लिट्ज़ वर्ग 5 जुलाई से शुरू होगा और दोनों प्रारूपों के संयुक्त अंकों के आधार पर समग्र विजेता का फैसला किया जाएगा।
- मैग्नस कार्लसन ने 7 जुलाई को क्रोएशिया के ज़ाग्रेब में आयोजित सुपरयूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज़ 2025 शतरंज टूर्नामेंट में 22.5/36 अंक के साथ जीत हासिल की। उन्होंने एक राउंड पहले ही खिताब अपने नाम कर लिया। अमेरिका के वेस्ली सो 20/36 अंक के साथ दूसरे और भारत के डी. गुकेश 19.5/36 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इस ग्रैंड शतरंज टूर प्रतियोगिता में रैपिड और ब्लिट्ज़ प्रारूपों में खिलाड़ियों की परीक्षा ली गई। ब्लिट्ज़ में चुनौतियों के बावजूद, गुकेश ने शानदार प्रगति दिखाई। अगला आयोजन अगस्त 2025 में सेंट लुइस, मिसौरी में होगा। (





- चेन्नई के 23 वर्षीय हरिकृष्णन ए. रा., 11 जुलाई, 2025 को फ्रांस के ला प्लेग्रे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में अपना तीसरा ग्रैंडमास्टर नॉर्म हासिल करने के बाद भारत के 87वें ग्रैंडमास्टर बन गए। श्याम सुंदर के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित, हरिकृष्णन ने इससे पहले स्विट्जरलैंड (2023) और स्पेन (जून 2025) में ग्रैंडमास्टर नॉर्म हासिल किए थे। पी. इनियन के साथ ड्रॉ और जूल्स मौसार्ड पर जीत सहित उनके अंतिम प्रदर्शन ने उन्हें खिताब दिलाया। हरिकृष्णन, जिन्होंने हाल ही में एसआरएम से एम.कॉम की पढ़ाई पूरी की है, अमेरिका में एमबीए करने से पहले स्पेन और पुर्तगाल में प्रतिस्पर्धा करने की योजना बना रहे हैं। उनका अगला लक्ष्य 2600 की एलो रेटिंग हासिल करना है।
- FIDE विश्व कप 2025 भारत में 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक 206 खिलाड़ियों के साथ नॉकआउट प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए तीन क्वालीफिकेशन स्थान प्रदान करता है। हाल के अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भारत का शानदार प्रदर्शन और इसकी शतरंज संस्कृति इसे एक आदर्श मेज़बान बनाती है। क्वालीफिकेशन मार्गों में चैंपियन, रेटिंग, महाद्वीपीय आयोजन और नामांकन शामिल हैं। गुकेश, प्रज्ञानंदधा और एरिगोसी जैसे सितारों के साथ, भारत एक शतरंज महाशक्ति के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है।

ग्रैंड प्रिक्स

- लैंडो नॉरिस ने 6 जुलाई, 2025 को सिल्वरस्टोन में ब्रिटिश ग्रां प्री जीती, जो एक गीली और रोमांचक रेस थी। ऑस्कर पियास्त्री को 10 सेकंड की पेनल्टी मिलने के बाद उन्होंने बढ़त बना ली, जिससे नॉरिस को फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप में अंकों का अंतर कम करने में मदद मिली। 2008 के बाद से सिल्वरस्टोन में मैकलारेन की यह पहली जीत थी। निको हुलकेनबर्ग तीसरे स्थान पर रहे, और मैक्स वेरस्टेपेन एक चक्कर के बाद पाँचवें स्थान पर रहे। बारिश के कारण कई नए ड्राइवर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। नॉरिस ने अपने घरेलू दर्शकों के सामने इस जीत को एक सपना सच होने जैसा बताया।

एथलेटिक और फुटबॉल

- एफआईए अधिकारी आदिल सुमारिवाला ने 6 जुलाई, 2025 को बेंगलुरु में कहा कि भारत 2029 या 2031 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी के लिए रणनीतिक बोली लगाएगा। बोली प्रक्रिया इसी साल शुरू होगी और अंतिम निर्णय सितंबर 2026 में लिए जाएंगे। चूँकि टोक्यो (2025) और बीजिंग (2027) पहले से ही मेज़बानी कर रहे हैं, इसलिए 2031 में भारत के लिए बेहतर संभावनाएँ हो सकती हैं। भारत ने 2028 जूनियर विश्व चैंपियनशिप और भविष्य की एथलेटिक्स रिले स्पर्धाओं की मेज़बानी में भी रुचि दिखाई है। ये प्रयास 2036 में ओलंपिक खेलों को देश में लाने के भारत के लक्ष्य का हिस्सा हैं।
- ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में आयोजित कॉनकाकैफ़ गोल्ड कप 2025 के फ़ाइनल में मेक्सिको ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 2-1 से हरा दिया। अमेरिका के लिए क्रिस रिचर्ड्स ने शुरुआत में गोल किया, लेकिन मेक्सिको के लिए राउल जिमेनेज़ और एडसन अल्वारेज़ ने गोल करके जीत पक्की कर दी। इस जीत ने मेक्सिको को रिकॉर्ड 10वां गोल्ड कप खिताब दिलाया। इस मैच में नाटकीय पल, दमदार प्रदर्शन और भावुक श्रद्धांजलि देखने को मिली, जिसने इसे पूरे क्षेत्र के फुटबॉल प्रशंसकों के लिए एक यादगार फ़ाइनल बना दिया।
- नीरज चोपड़ा ने बेंगलुरु में 86.18 मीटर के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक के साथ

पहला नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 जीता। यह प्रतियोगिता विश्व एथलेटिक्स गोल्ड-स्तरीय श्रृंखला के तहत श्री कांतीरवा स्टेडियम में आयोजित की गई थी। केन्या के जूलियस येगो 84.51 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि श्रीलंका के रुमेश पथिरगे 84.34 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। नीरज ने आगामी वैश्विक प्रतियोगिताओं से पहले अपनी शीर्ष फॉर्म को बरकरार रखते हुए, तीसरे श्रो में दमदार प्रदर्शन से दर्शकों को प्रभावित किया। यह नया आयोजन अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स में भारत की बढ़ती उपस्थिति का भी प्रतीक है।

- भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में छह स्थान गिरकर 133वें स्थान पर आ गई है, जो दिसंबर 2016 के बाद से उसकी सबसे खराब रैंकिंग है। यह गिरावट जून 2025 में थाईलैंड और हांगकांग से मिली हार के बाद आई है, जिसके कारण कोच मनोलो मार्केज़ को भी पद छोड़ना पड़ा। उनके नेतृत्व में भारत ने आठ मैचों में सिर्फ़ एक जीत हासिल की। टीम संघर्ष कर रही है और 2027 एशियाई कप के लिए क्वालीफिकेशन खतरे में है, ऐसे में भारत के लिए वापसी का अगला मौका अक्टूबर में सिंगापुर के खिलाफ होगा।
- चेल्सी एफसी ने 13 जुलाई, 2025 को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में पीएसजी को 3-0 से हराकर फीफा क्लब विश्व कप 2025 जीत लिया। कोल पामर इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी रहे, जिन्होंने दो गोल किए और जोआओ पेड्रो को तीसरे गोल में असिस्ट किया। मैनेजर एंजो मारेस्का के नेतृत्व में चेल्सी की रणनीतिक रणनीति ने चैंपियंस लीग विजेता पीएसजी को पूरी तरह से मात दे दी। इस मैच में पीएसजी के जोआओ नेवेस को भी मैदान से बाहर भेज दिया गया, जिसने उनके खराब प्रदर्शन को और भी बदतर बना दिया। इस जीत के साथ, चेल्सी ने 40 मिलियन डॉलर का चैंपियन पुरस्कार अपने नाम किया और पामर को टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया।

अन्य खेल समाचार

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति (एनएसपी) 2025 को स्वीकृति दे दी है। देश के खेल परिदृश्य को नया आकार देने और खेलों के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक यह ऐतिहासिक पहल है। नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 का स्थान लेगी और देश को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और वर्ष 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए एक दूरदर्शी और कार्यनीतिक रोडमैप तैयार करेगी। एनएसपी 2025 को केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ), खिलाड़ियों, खेल विशेषज्ञों और सार्वजनिक हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किया गया है।
- भारत और श्रीलंका द्वारा सह-आयोजित आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए इटली और नीदरलैंड्स ने यूरोप क्वालिफायर्स के अंतिम दिन अपने स्थान पक्के किए। जहां नीदरलैंड्स ने अपना मुकाबला जीतकर क्वालिफाई किया, वहीं नेट रन रेट के आधार पर इटली ने पहली बार इस टूर्नामेंट में जगह बनाई।
- चेन्नई के 23 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्णन ए. रा. ने 11 जुलाई 2025 को फ्रांस में आयोजित ला प्लेग्रे इंटरनेशनल चैस फेस्टिवल में अपना अंतिम ग्रैंडमास्टर (GM) नॉर्म पूरा कर भारत के 87वें ग्रैंडमास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया। यह उपलब्धि उन्होंने इंटरनेशनल मास्टर (IM) बनने के सात साल बाद हासिल की।





- भारत 2027 में शूटिंग विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, इसकी घोषणा 10 जुलाई 2025 को नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) ने की। यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ (ISSF) द्वारा लिया गया। ये आयोजन भारत को वैश्विक निशानेबाजी प्रतियोगिताओं का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं।
- लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम स्थित एमसीसी म्यूज़ियम में 10 जुलाई 2025 को सचिन तेंदुलकर का चित्र (पोर्ट्रेट) अनावरण किया गया। यह चित्र प्रसिद्ध ब्रिटिश कलाकार स्टुअर्ट पियर्सन राइट द्वारा बनाया गया है। यह कार्यक्रम भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच से पहले आयोजित किया गया, और यह पल क्रिकेट के इस महान खिलाड़ी के लिए बेहद भावुक क्षण था। यह सम्मान तेंदुलकर के लिए विशेष है, क्योंकि इंग्लैंड में खेले गए उनके कई मुकाबले उनकी यादों में बसे हुए हैं।
- भारत ने जर्मनी के राइन-रुहर में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जहां तैराक श्रीहरि नटराज और बी. बेनेडिक्शन रोहित ने अपने-अपने स्पर्धाओं में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। इन उपलब्धियों ने अंतरराष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिताओं में भारत की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाया और देश की खेल उत्कृष्टता को नई ऊंचाई दी।
- बिहार की रग्बी टीम ने देहरादून में आयोजित 10वीं जूनियर नेशनल रग्बी 7s चैंपियनशिप 2025 में अंडर-18 बाँयज़ खिताब जीतकर एक रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन ओडिशा को 17-15 से हराया। यह जीत न केवल जूनियर रग्बी में बिहार की बढ़ती श्रेष्ठता को दर्शाती है, बल्कि इस सप्ताह की शुरुआत में अंडर-18 गर्ल्स खिताब जीतने के बाद राज्य के लिए एक ऐतिहासिक 'डबल' भी पूरा करती है।
- अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित मेटलाइफ स्टेडियम में खेले गए फाइनल में चेल्सी एफसी ने पेरिस सेंट-जर्मेन (PSG) को 3-0 से हराकर फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। इस ऐतिहासिक जीत में 22 वर्षीय युवा मिडफील्डर कोल पामर ने दो गोल दागे और तीसरे गोल में असिस्ट कर शानदार प्रदर्शन किया। यह चेल्सी का दूसरा क्लब वर्ल्ड कप खिताब है।
- पोलैंड की इगा स्विगटेक ने 12 जुलाई 2025 को अपने करियर का पहला विंबलडन खिताब जीत लिया। उन्होंने फाइनल में अमेरिका की अमांडा अनीसिमोवा को सिर्फ 57 मिनट में 6-0, 6-0 से हरा दिया। यह मुकाबला टेनिस इतिहास के सबसे एकतरफा महिला फाइनल्स में से एक बन गया। "डबल बैगेल" स्कोरलाइन (दोनों सेट में 6-0) के साथ यह जीत इतिहास में दर्ज हो गई और इगा स्विगटेक के करियर में एक और ग्रैंड स्लैम खिताब जुड़ गया।
- विश्व नंबर एक जानिक सिनर ने ऑल इंग्लैंड क्लब पर इतिहास रचते हुए पहली बार विंबलडन ट्रॉफी अपने नाम की। सिनर ने ग्रासकोर्ट पर लगातार दो वर्ष से खिताब जीतने वाले स्पेन के कार्लोस अल्कराज को तीन घंटे चले फाइनल मुकाबले में 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर खिताब जीता। सिनर विंबलडन खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बने। इसके साथ ही सिनर ने पिछले महीने फ्रेंच ओपन के फाइनल में अल्कराज से मिली हार का भी हिसाब चुकता कर लिया। यह सिनर के करियर का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है।

- भारत ने जर्मनी के राइन-रुहर में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में गर्व का क्षण दर्ज किया, जब तीरंदाज परनीत कौर और कुशल दलाल ने कंपाउंड मिक्सड टीम आर्चरी इवेंट में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। यह उपलब्धि न केवल भारत की खेल जगत में बढ़ती सफलता को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि विश्व स्तर पर भारतीय विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी अब गैर-पारंपरिक ओलंपिक खेलों, जैसे कंपाउंड आर्चरी, में भी अपना परचम लहरा रहे हैं।
- IBSF वर्ल्ड 6-रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में एक चौकाने वाले मुकाबले में वेल्स के 16 वर्षीय क्यू खिलाड़ी रिले पॉवेल ने भारत के दिग्गज स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी को हराकर खिताब जीत लिया। बहरीन की राजधानी मनामा में खेले गए इस रोमांचक फाइनल में पॉवेल ने आडवाणी को 5-4 से मात दी, जिससे आडवाणी अपने 40वें जन्मदिन पर रिकॉर्ड 29वां विश्व खिताब जीतने से चूक गए। यह जीत पॉवेल के करियर का एक अहम मोड़ साबित हुई है और यह स्नूकर खेल में उभरती युवा प्रतिभाओं के वैश्विक उदय को दर्शाती है।
- भारत की प्रमुख मोटरस्पोर्ट्स प्रतियोगिता — MRF MMSC FMSCI इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2025 — का पहला चरण कोयंबटूर के करी मोटर स्पीडवे में संपन्न हुआ, जिसमें MRF F2000, फॉर्मूला 1600 और ट्यूरिंग कार्स जैसी प्रमुख श्रेणियों में उभरती हुई युवा प्रतिभाओं ने दमदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में किशोर रेसर्स के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, जो भारतीय मोटरस्पोर्ट्स के उज्ज्वल भविष्य की ओर संकेत करती है।

खेल करेंट अफेयर्स: जून 2025

क्रिकेट

- ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे से संन्यास लिया
ग्लेन मैक्सवेल 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वनडे इंटरनेशनल से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने फिटनेस संबंधी समस्याओं और युवा खिलाड़ियों के लिए जगह बनाने की आवश्यकता का हवाला दिया। वह टी20 खेलना जारी रखेंगे।
- हेनरिक क्लासेन ने संन्यास की घोषणा की
दक्षिण अफ्रीकी विकेटकीपर-बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, उन्होंने 3000 से ज्यादा सफ़ेद गेंद के रन के साथ अपने सात साल के करियर का अंत किया।
- आरसीबी ने अपना पहला आईपीएल खिताब जीता
राॅयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने आईपीएल 2025 के फ़ाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर कई सालों के नज़दीकी मुकाबले के बाद अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी हासिल की।
- भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ का नाम बदला गया
भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज़ को अब एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी कहा जाएगा, जो पटौदी और डी मेलो ट्रॉफियों की जगह लेगी।
- एमएस धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया
एमएस धोनी 2025 में शामिल होने वाले सात नए खिलाड़ियों में से एक हैं, जो मैथ्यू हेडन, डैनियल विटोरी, हाशिम अमला, ग्रीम स्मिथ, सना मीर और सारा टेलर जैसे दिग्गजों में शामिल हैं।





- निकोलस पूरन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया 29 साल की उम्र में, पूरन ने 106 T20I और 61 ODI के साथ संन्यास लिया, जो वेस्टइंडीज के सबसे ज्यादा T20I खिलाड़ी रहे।
- MCC ने बाउंड्री कैच पर नियम 19.5.2 को अपडेट किया "बन्नी हॉप" कैच अब गैरकानूनी है। फ़ील्डर वैध कैच को पूरा करने के लिए अंदर उतरने से पहले बाउंड्री के बाहर से सिर्फ़ एक बार हवा में छू सकते हैं।
- चार दिवसीय टेस्ट शुरू किए जाएंगे 2027-29 विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप चक्र से शुरू होकर, छोटे देश चार दिवसीय टेस्ट खेलेंगे, जबकि भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पाँच दिवसीय मैच खेलेंगे।
- महिला वनडे विश्व कप 2025 का कार्यक्रम घोषित यह आयोजन 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में होगा। राजनीतिक तनाव के कारण पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में होंगे।
- जसप्रीत बुमराह ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की हेडिंग्ले में पांच विकेट लेने के बाद वे SENA देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बन गए।
- ऋषभ पंत ने हेडिंग्ले में दो शतक बनाए पंत ने दोनों पारियों में शतक बनाए, 252 रन बनाए और टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बन गए।
- रिकू सिंह बनेंगी शिक्षा अधिकारी रिकू सिंह को राज्य खेल नीति के तहत उत्तर प्रदेश में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। क्रिकेट प्रतिबद्धताओं के कारण उनकी शादी फरवरी 2026 तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
- टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक की शुरुआत की गई 2025-27 WTC चक्र में ओवरों के बीच एक नया 60 सेकंड का टाइमर लगाया गया है। तीन उल्लंघनों के परिणामस्वरूप पांच रन का जुर्माना लगेगा। लार और छोटे रन के नियमों को भी अद्यतन किया गया है।

बैडमिंटन और टेनिस

- कार्लोस अल्काराज़ ने फ्रेंच ओपन 2025 जीता अल्काराज़ ने पांच घंटे के रोमांचक मुकाबले में जैनिक् सिनर को हराया, अपना दूसरा फ्रेंच ओपन खिताब और पांचवां ग्रैंड स्लैम जीता।
- इंडोनेशिया ओपन 2025 की मुख्य बातें एंडर्स एंटोनसेन और एन से-यंग ने एकल खिताब जीते। फ्रांस ने अपना पहला सुपर 1000 मिश्रित युगल खिताब जीता।
- विंबलडन 2025 की पुरस्कार राशि में वृद्धि कुल पुरस्कार राशि अब 53.5 मिलियन पाउंड है। एकल चैंपियन को 3 मिलियन पाउंड मिलेंगे।
- टेलर फ्रिट्ज़ ने स्टार्टगार्ट ओपन 2025 जीता फ्रिट्ज़ ने ज़ेबरेव को सीधे सेटों में हराया, अपने करियर का नौवां खिताब हासिल किया और दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी बन गए।

शतरंज

- डी गुकेश ने मैग्स कार्लसन को हराया गुकेश ने नॉर्वे शतरंज 2025 में क्लासिकल गेम में कार्लसन को हराया, यह विश्व चैंपियन पर उनकी पहली जीत थी।
- मैग्स कार्लसन ने नॉर्वे शतरंज 2025 जीता कार्लसन ने 16 अंकों के साथ अपना सातवां खिताब हासिल किया, उन्होंने फैबियानो कारुआना और गुकेश को मामूली अंतर से हराया।

- अरविंद चिदंबरम ने आर्मेनिया में जीत हासिल की उन्होंने प्रज्ञानंद को टाईब्रेक में हराकर छठा स्टेपन अवजान मेमोरियल खिताब जीता।
- प्रज्ञानंद ने उज्ज्वल कप मास्टर्स जीता यह इस साल का उनका तीसरा क्लासिकल खिताब है। अब वे लाइव रेटिंग में दुनिया के चौथे नंबर पर हैं।

हॉकी

- भारत ने महिला एशिया कप 2025 अभियान की शुरुआत की भारत 5 सितंबर को हांगजो में थाईलैंड से भिड़ेगा, जिसका लक्ष्य खिताब जीतना और 2026 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करना है।
- हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 चेन्नई में आयोजित किया गया इसमें पुरुष और महिला आयु वर्ग के दिग्गज खिलाड़ी भाग लेंगे, सक्रिय उम्र बढ़ने को बढ़ावा देंगे और हॉकी के दिग्गजों का जश्न मनाएं।

एथलेटिक्स और फुटबॉल

- पुर्तगाल ने यूईएफए नेशंस लीग 2025 जीता पुर्तगाल ने 2-2 से ड्रा के बाद पेनल्टी पर स्पेन को हराया, जिससे वह दो बार खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई।
- क्रिस्टियानो रोनाल्डो ईस्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के राजदूत बने रोनाल्डो को रियाद में 2025 संस्करण के लिए वैश्विक राजदूत नामित किया गया है और वह फ़ैटल फ़्यूरी में एक खेलने योग्य चरित्र के रूप में दिखाई देते हैं।
- फ़ीफ़ा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का विस्तार अब संयुक्त राज्य अमेरिका में 32 टीमों का आयोजन, जिसमें खिलाड़ियों की थकान और शेड्यूलिंग को लेकर चिंताएँ जताई गई हैं।
- ऑस्कर पियास्ट्री ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता मैकलारेन ड्राइवर ने पोल से फ़िनिश तक बढ़त बनाते हुए सीज़न की अपनी पाँचवीं जीत दर्ज की।
- आर्मंड डुप्लांटिस ने फिर से पोल वॉल्ट का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा स्टॉकहोम डायमंड लीग में 6.28 मीटर की दूरी तय की, जिससे एक नया व्यक्तिगत और वैश्विक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन स्थापित हुआ।
- नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग जीती 88.16 मीटर के श्रो के साथ, नीरज शीर्ष फ़ॉर्म में लौटे और आगामी चैंपियनशिप के लिए गति बनाई।
- कार्लोस अल्काराज़ ने फिर से क्वींस क्लब का खिताब जीता अल्काराज़ ने तीन सेटों में जिरी लेहेका को हराया और अपने ग्रास-कोर्ट जीत के सिलसिले को 18 मैचों तक बढ़ाया।
- ओक्लाहोमा सिटी थंडर ने एनबीए फ़ाइनल 2025 जीता थंडर ने गेम 7 में इंडियाना पेसर्स को हराया, जिसमें शाई गिलगियस-अलेक्जेंडर को फ़ाइनल एमवीपी चुना गया।
- भारत 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा यह आयोजन 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। शुभंकर 'विराज' लचीलेपन का प्रतीक है।
- ललित उपाध्याय ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया ओलंपियन ने 179 से अधिक कैप और भारत की हॉकी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान के साथ अपने करियर का अंत किया।





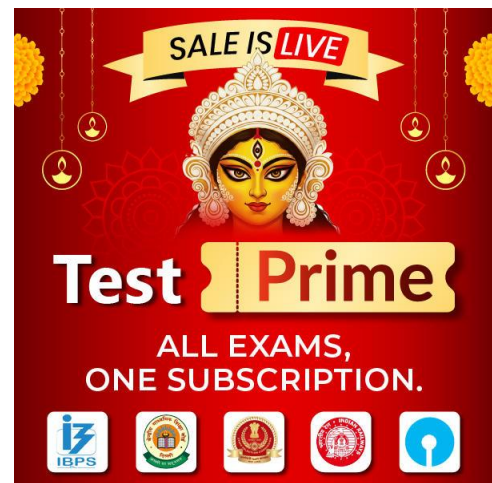
- नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक जीता चेक गणराज्य में 85.29 मीटर का श्रो हासिल किया, जो सीज़न का उनका पाँचवाँ प्रदर्शन था।
- भारत 2029 विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबानी करेगा। गुजरात अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में इस कार्यक्रम की मेजबानी करेगा, जिसमें 70 से अधिक देश भाग लेंगे।

खेल करेंट अफेयर्स: मई 2025

क्रिकेट

- आईपीएल 2025 में पर्पल कैप की जंग काफी रोमांचक रही है, जिसमें गेंदबाज दबाव में आकर मैच जीतने वाली प्रदर्शन दे रहे हैं। इस समय जोश हेजलवुड (RCB) 18 विकेट्स के साथ सबसे आगे हैं, उनका औसत 17 है और उन्होंने 36 ओवर में गेंदबाजी की है। प्रसिध कृष्णा (GT) और नूर अहमद (CSK) उनके बाद हैं, जो अपनी इकॉनमी और स्ट्राइक रेट के साथ प्रभावी प्रदर्शन कर रहे हैं। अनुभवी गेंदबाजों जैसे ट्रेट बाउल्ट, हर्षल पटेल और कुलदीप यादव भी लगातार शीर्ष विकेट-टेकर्स में शामिल रहे हैं। इस सीज़न में गेंदबाजों ने आक्रामक बल्लेबाजों को चुनौती दी है, और पर्पल कैप की जंग को रोमांचक और प्रतिस्पर्धी बनाया है।
- IPL 2025 में ऑरेंज कैप की दौड़ बेहद रोमांचक रही है, जिसमें कुछ शानदार बैटिंग प्रदर्शन देखने को मिले हैं। सूची में सबसे ऊपर विराट कोहली (RCB) हैं, जिन्होंने 10 पारियों में 443 रन बनाकर 63 की शानदार औसत बनाए रखी है। उनके बाद सूर्यकुमार यादव (MI) और साई सुदर्शन (GT) 427 और 417 रन बनाकर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने अपनी निरंतरता और विस्फोटक स्ट्राइक रेट से फैंस को मंत्रमुग्ध कर दिया है। पीछे से, निकोलस पूरन, मिशेल मार्श और केएल राहुल जैसे पावर हिटर्स ने प्रतियोगिता को और भी कड़ा कर दिया है। यह सूची अनुभव और उभरते हुए टैलेंट का बेहतरीन मिश्रण है, जिससे 2025 सीज़न अब तक का सबसे रोमांचक ऑरेंज कैप की लड़ाई बन गया है।
- भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, रोहित शर्मा — जो भारत के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक और वर्तमान टेस्ट कप्तान हैं — ने आधिकारिक रूप से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। यह निर्णय उन्होंने बहुप्रतीक्षित भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला से ठीक पहले लिया, जिससे उनके लंबे और उतार-चढ़ाव भरे टेस्ट करियर का अंत हो गया। रोहित ने 2013 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था और अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो संघर्ष, पुनर्निर्माण और नेतृत्व से भरी रही है। हालांकि उन्होंने IPL 2025 के दौरान टीम की कप्तानी जारी रखने की इच्छा जताई थी, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) में बदलते समीकरणों के कारण उनके टेस्ट करियर का समापन अपेक्षा से पहले और कुछ हद तक अप्रत्याशित रूप से हो गया।
- भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद आईपीएल 2025 को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है। बीसीसीआई द्वारा यह निर्णय फ्रैंचाइजी और हितधारकों द्वारा व्यक्त की गई सुरक्षा चिंताओं के कारण लिया गया था, खासकर 8 मई को धर्मशाला मैच रद्द होने के बाद। बोर्ड ने देश की रक्षा तत्परता को स्वीकार करते हुए, हितधारकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का विकल्प चुना और फिर से शुरू करने से पहले पुनर्मूल्यांकन का इंतजार कर रहा है। यह आयोजन खेल कार्यक्रमों पर अंतरराष्ट्रीय संघर्ष के प्रभाव को रेखांकित करता है, जिसमें बीसीसीआई की संकट प्रतिक्रिया के केंद्र में रसद और खिलाड़ी कल्याण है।

- मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने 16 मई, 2025 को मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का अनावरण किया, जिसमें टेस्ट और टी20 क्रिकेट से हाल ही में संन्यास लेने वाले भारतीय क्रिकेट के दिग्गज को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में अजीत वाडेकर और शरद पवार के नाम पर स्टैंड का उद्घाटन भी हुआ, जो भारतीय क्रिकेट और क्रिकेट प्रशासन में उनके अमूल्य योगदान को याद करते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल 2023-25 के विजेताओं के लिए रिकॉर्ड 3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹30 करोड़) की पुरस्कार राशि की घोषणा की है। यह ऐतिहासिक मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 11 जून 2025 से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। यह पुरस्कार राशि अब तक की सबसे बड़ी है और पिछले संस्करणों में दी गई राशि से दोगुनी से भी अधिक है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ICC टेस्ट क्रिकेट के गौरव को आधुनिक युग में और ऊंचा उठाने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है।
- बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। यह सम्मान उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला में उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए दिया गया। यह मिराज का पहला अवसर है जब उन्होंने यह पुरस्कार जीता है, और वह यह सम्मान पाने वाले केवल तीसरे बांग्लादेशी क्रिकेटर बने हैं। उनसे पहले मुशफिकुर रहीम और शाकिब अल हसन को यह उपलब्धि मिली थी।
- धर्मशाला में 8 मई 2025 को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच चल रहे मैच के दौरान सुरक्षा कारणों से IPL 2025 को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था। अब, BCCI ने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श के बाद टूर्नामेंट के पुनः आरंभ की घोषणा की है।
- इंग्लैंड के प्रमुख बल्लेबाज जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बनकर क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि 22 मई, 2025 को ट्रेट ब्रिज में जिम्बाब्वे के खिलाफ इंग्लैंड के एकमात्र टेस्ट के दौरान हासिल हुई। रूट की 34 रनों की पारी ने उन्हें दिग्गज जैक कैलिस से आगे कर दिया, जो उनके शानदार करियर का एक और यादगार अध्याय है।





बैडमिंटन और टेनिस

- चीन ने ज़ियामेन, चीन में आयोजित फ़ाइनल में दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराकर सुदीरमन कप 2025 जीतकर विश्व बैडमिंटन में अपना वर्चस्व बढ़ाया। एन सेयंग के शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन के बावजूद, जिन्होंने लगातार 25 जीत के साथ अपना बेहतरीन सीज़न बरकरार रखा, चीनी टीम के चौतरफा दबदबे ने विश्व मिश्रित टीम चैंपियनशिप में अपना 14वां खिताब सुरक्षित कर लिया।
- कार्लोस अलकराज (Carlos Alcaraz) ने जानिक सिनर को हराकर पहली बार इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया। रविवार को खेले गए फ़ाइनल मुकाबले में अलकराज ने विश्व नंबर एक सिनर को सीधे सेटों में 7-6 (5), 6-1 से मात देकर इस महीने होने वाले फ्रेंच ओपन के लिए दावा ठोक दिया है। पिछले वर्ष की शुरुआत से अब तक अलकराज ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने सिनर को एक से अधिक बार हराया है और वह लगातार चार मुकाबलों में सिनर पर जीत दर्ज कर चुके हैं।

शतरंज

- चेन्नई के 19 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी श्रीहरि एलआर, यूई के अल-एन में एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप में अपना तीसरा नॉर्म हासिल करने के बाद आधिकारिक तौर पर भारत के 86वें ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। शतरंज थुलिर अकादमी में जीएम श्यामसुंदर द्वारा प्रशिक्षित, श्रीहरि ने लगातार विकास दिखाया है, शीर्ष-रेटेड खिलाड़ियों को हराया है और भारत की शतरंज प्रतिभा पाइपलाइन की ताकत दिखाई है। उनकी यह उपलब्धि भारत के पिछले जीएम खिताब के लगभग एक साल बाद आई है और वैश्विक शतरंज में देश की तेजी से प्रगति को दर्शाती है।

तीरंदाजी और निशानेबाजी

- 17 वर्षीय भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, उन्होंने यूरोपीय चैंपियन और ओलंपियन अन्ना डुल्स को हराया। कम वजन से लेकर विश्व कप विजेता बनने तक का उनका सफर तकनीकी सुधार, पारिवारिक समर्थन और विशेषज्ञ कोचिंग द्वारा चिह्नित है। एशियाई चैंपियनशिप और जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पहले के पदकों के साथ, यह जीत अंतरराष्ट्रीय शूटिंग में भारत के भविष्य को मजबूत करती है और उसके ओलंपिक सपनों को प्रेरित कर सकती है।

एथलेटिक और फुटबॉल

- फीफा ने आधिकारिक तौर पर कांगो गणराज्य के फुटबॉल महासंघ (FECOFOOT) पर लगाया गया निलंबन हटा लिया है, जिससे तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के आरोपों के कारण तीन महीने से चल रहा गतिरोध समाप्त हो गया है। FECOFOOT और कांगो के खेल मंत्रालय के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के कारण लगाए गए इस प्रतिबंध ने राष्ट्रीय फुटबॉल संचालन को बाधित कर दिया था और महासंघ के मुख्यालय सहित प्रमुख खेल सुविधाओं को बंद कर दिया था।
- दीपिका कुमारी ने शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में लिम सिहयोन से सेमीफाइनल में हार का सामना करते हुए कांस्य पदक हासिल किया। कांग चाए यंग के खिलाफ कांस्य पदक के प्लेऑफ में उनकी जीत ने रिकर्व और कंपाउंड तीरंदाजी दोनों स्पर्धाओं में मजबूत प्रदर्शन के साथ भारत

की पदक संख्या में वृद्धि में योगदान दिया। इस वैश्विक आयोजन में भारत की सफलता तीरंदाजी में देश के बढ़ते कद को दर्शाती है।

- तीरंदाजी विश्व कप 2025 - शंघाई में भारत ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। दीपिका कुमारी ने रिकर्व में कांस्य पदक के साथ अपना 18वां व्यक्तिगत पोडियम बनाया, जबकि अंडर 21 विश्व चैंपियन पार्थ सालुंखे ने अपना पहला सीनियर पदक जीता। भारत ने कंपाउंड स्पर्धाओं में अपना दबदबा कायम रखा, व्यक्तिगत, टीम और मिश्रित श्रेणियों में पदक जीते, जिससे तीरंदाजी में उसका वैश्विक कद मजबूत हुआ।
- भारत के ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 2025 दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला फेंकर 90 मीटर की बाधा को पार करके अपने करियर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय और तीसरे एशियाई बन गए, और वैश्विक एथलीटों के एक विशिष्ट समूह में शामिल हो गए। अपने ऐतिहासिक प्रयास के बावजूद, चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे, क्योंकि जर्मनी के जूलियन वेबर ने अंतिम दौर में 91.06 मीटर का विश्व-अग्रणी श्रो बनाया। चोपड़ा ने संतुष्टि और आशा व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य की प्रतियोगिताओं में वे 90 मीटर से अधिक श्रो हासिल करना चाहते हैं।
- भारत ने शंघाई में आयोजित आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 पदक जीते, जिनमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य शामिल हैं। स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर वापसी करते हुए अपना 18वां वर्ल्ड कप पदक जीता, जबकि युवा प्रतिभा पार्थ सालुंखे ने सीनियर स्तर पर पहला कांस्य पदक जीतकर भारत की बढ़ती ताकत और गहराई को प्रदर्शित किया।
- पूर्व स्पेन और लिवरपूल के गोलकीपर पेपे रीना ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि वे 2024-25 सत्र के अंत में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। वर्तमान में इटली की सीरी ए क्लब कोमो के लिए खेल रहे 42 वर्षीय रीना, अपने शानदार करियर का समापन करेंगे, जो दो दशकों से अधिक समय तक चला और जिसमें उन्होंने यूरोप के शीर्ष क्लबों के लिए 1,000 से अधिक प्रतिस्पर्धी मैच खेले। अपनी स्थिरता और नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध रीना अपना अंतिम मैच इंटर मिलान के खिलाफ खेलेंगे।
- भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट शिवपाल सिंह, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, दूसरी बार डोप टेस्ट में असफल पाए गए हैं। इस साल की शुरुआत में NIS पटियाला में प्रशिक्षण के दौरान लिए गए आउट-ऑफ-कॉम्पटीशन यूरिन सैंपल में प्रतिबंधित पदार्थ मिला। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) ने उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, और यदि आरोप साबित होते हैं, तो उन्हें अधिकतम 8 साल का प्रतिबंध झेलना पड़ सकता है, जिससे उनका करियर समाप्त हो सकता है।
- भारत ने अपनी धैर्य और साहस का परिचय देते हुए सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप का खिताब सफलतापूर्वक बचा लिया। 18 मई को खेले गए हुए फ़ाइनल में भारत ने बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया, जबकि मैच का समय समाप्त होने पर स्कोर 1-1 था। दर्शकों के समर्थन से भारत ने दूसरे मिनट में कप्तान सिगमयूम शामी के गोल से बढ़त बनाई। लेकिन बांग्लादेश ने 61वें मिनट में मोहम्मद जाय के गोल से बराबरी कर ली। भारत ने पेनल्टी शूटआउट की शुरुआत अच्छी नहीं की, जब रोहन सिंह का कमजोर प्रयास बांग्लादेश के गोलकीपर ने रोक लिया। यह भारत का दूसरा SAFF U-19 खिताब है—पहला खिताब भारत ने 2023 में जीता था।





अन्य खेल समाचार

- बिहार में आयोजित खेले इंडिया यूथ गेम्स 2025 राज्य के खेल परिदृश्य के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण है। सेपकटकरा और ईस्पोर्ट्स जैसे नए खेलों सहित 27 विषयों में 6,000 से अधिक एथलीटों की भागीदारी के साथ, यह आयोजन भविष्य की वैश्विक प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस कार्यक्रम ने बिहार के खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, जिसमें 38 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
- मिस एस्टोनिया, एलीज़ रैंडमा ने हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया, और शीर्ष 40 क्वार्टर फाइनलिस्ट में फास्ट-ट्रेक स्थान हासिल किया। इस कार्यक्रम में 108 प्रतियोगियों ने बैडमिंटन और स्प्रिंग जैसे विविध खेलों में प्रतिस्पर्धा की, और मल्लखंब, योग और स्केटिंग का सांस्कृतिक प्रदर्शन किया। जुपली कृष्ण राव और राजीव शुक्ला जैसे गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। यह ऐतिहासिक जीत एस्टोनिया के 25 साल बाद मिस वर्ल्ड की सुर्खियों में फिर से प्रवेश को दर्शाती है।
- भारत के ओलंपियन भाला फेंक खिलाड़ी शिवपाल सिंह दूसरे डोप टेस्ट में विफल हो गए हैं, जिसके बाद राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी (NADA) ने उन्हें अस्थायी निलंबन के तहत रखा है। इस साल की शुरुआत में प्रतियोगिता से इतर परीक्षण के दौरान लिए गए उनके मूत्र के नमूने में प्रतिबंधित पदार्थ के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया था। WADA और NADA के नियमों के तहत दोबारा अपराध करने पर उन पर आठ साल का प्रतिबंध लग सकता है, जिससे उनका खेल करियर खत्म होने का खतरा है। शिवपाल पर पहले 2021 में सकारात्मक परीक्षण के बाद एक साल का प्रतिबंध लगाया गया था और उन्होंने 2023 में सफल वापसी की थी।
- भारत सरकार ने आठ पूर्वोत्तर राज्यों में खेलो इंडिया नॉर्थईस्ट गेम्स के वार्षिक रोटेशन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय खेल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना और युवा प्रतिभाओं की खोज करना है। जमीनी स्तर पर विकास, नई प्रतिभा खोज तकनीकों और ASMITA लीग जैसे समर्पित कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण निवेश के साथ, यह पहल पूर्वोत्तर को भारत के खेल भविष्य में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है। यह घोषणा वैश्विक खेल मंच पर भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती है, जिसमें 2030 राष्ट्रमंडल खेलों और 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोलियाँ शामिल हैं।
- कुश मैनी ने फ़ॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 24 मई, 2025 को मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट रेस में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। डैम्स लुकास ऑयल के लिए ड्राइविंग करते हुए, पोल से पोडियम तक मैनी की संयमित ड्राइव राष्ट्रीय गौरव का क्षण था, जिसे गौतम सिंघानिया जैसे भारतीय मोटरस्पोर्ट संरक्षकों की उपस्थिति ने और बढ़ा दिया। इस जीत से भारतीय मोटरस्पोर्ट आकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ की उम्मीद है।
- भारत के महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में पुरुषों की भाला फेंक F42 श्रेणी में विश्व रिकॉर्ड बनाकर देश को गौरवान्वित किया। 27 वर्षीय एथलीट ने अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प को साबित करते हुए रिकॉर्ड तोड़ श्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता।

- अहमदाबाद 1 से 10 अप्रैल तक 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इस बड़े खेल आयोजन की पुष्टि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने की है। यह अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा निर्धारित नए भार वर्गों का पालन करने वाली पहली एशियाई चैंपियनशिप होगी। यह आयोजन पहले गांधीनगर में आयोजित होने वाला था, लेकिन बाद में इसे अहमदाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया।

खेल करेंट अफेयर्स: अप्रैल 2025

क्रिकेट

- अनुभवी भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बार फिर अपनी शानदार प्रतिभा का परिचय देते हुए टी20 क्रिकेट में 13,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2025 के मुकाबले में हासिल की गई यह उपलब्धि कोहली को दुनिया भर में शीर्ष पांच टी20 रन बनाने वाले खिलाड़ियों में शामिल करती है।
- क्रिकेट आधिकारिक तौर पर लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों में ऐतिहासिक वापसी कर रहा है, जैसा कि 9 अप्रैल, 2025 को अंतराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) द्वारा पुष्टि की गई है। इस खेल में पुरुषों और महिलाओं के T20 टूर्नामेंट के लिए छह-छह टीमें होंगी, जिसमें प्रत्येक लिंग के लिए कुल 90 एथलीट कोटा होगा। यह 128 वर्षों के बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी को दर्शाता है, इससे पहले यह केवल 1900 पेरिस खेलों में ही शामिल हुआ था।
- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने आईपीएल 2025 सीजन में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। कोहली आईपीएल इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने मिलाकर 1000 बाउंड्रीज़ (चौके + छक्के) का आंकड़ा पार किया। यह कीर्तिमान बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में RCB बनाम दिल्ली कैपिटल्स (DC) मुकाबले के दौरान दर्ज किया गया।
- भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को मार्च 2025 के लिए ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। यह सम्मान उन्हें ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया, जिसमें उन्होंने भारत को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई। अय्यर ने पूरे टूर्नामेंट में कुल 243 रन बनाए। उन्होंने इस खिताब की दौड़ में न्यूजीलैंड के जैकब डफी और राचिन रविंद्र को पीछे छोड़ा। इस तरह भारत के लिए यह लगातार दूसरा महीना रहा जब किसी भारतीय खिलाड़ी ने यह सम्मान जीता—फरवरी 2025 में यह पुरस्कार शुभमन गिल को मिला था। श्रेयस अय्यर के दबाव भरे मुकाबलों में लगातार अच्छे प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम में एक मजबूत और विश्वसनीय खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है।
- अंतराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने विस्थापित अफगान महिला क्रिकेटर्स के अधिकारों और आकांक्षाओं की रक्षा करने और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कार्यबल का गठन करने की घोषणा की है। यह पहल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI), इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB), और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के साथ साझेदारी में की गई है। इसका उद्देश्य इन खिलाड़ियों को आर्थिक और विकासात्मक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे विस्थापन और राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद अपने क्रिकेट सफर को जारी रख सकें।





- विराट कोहली, जो आधुनिक क्रिकेट के दिग्गजों में गिने जाते हैं, ने IPL 2025 के दौरान टी20 क्रिकेट में अपना 100वां अर्धशतक बनाकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। यह यादगार पारी मैच 28 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सर्वाधिक मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में खेरी गई, जहां कोहली ने 45 गेंदों पर नाबाद 62 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। यह पारी IPL में उनका 66वां 50+ स्कोर भी था, जिससे वह डेविड वॉर्नर के साथ संयुक्त रूप से सर्वाधिक 50+ स्कोर वाले खिलाड़ी बन गए। यह उपलब्धि कोहली की लगातार प्रदर्शन करने की क्षमता और टी20 फॉर्मेट में उनकी लंबी उम्र और क्लास को दर्शाती है।
- मुंबई इंडियंस (MI) के ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा ने टी20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे कर लिए हैं। वह यह मुकाम हासिल करने वाले विराट कोहली के बाद दूसरे भारतीय क्रिकेटर बने हैं। यह उपलब्धि रोहित ने आईपीएल 2025 के मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेले गए मैच के दौरान हासिल की। रोहित अब उन चुनिंदा खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने टी20 क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 12,000 से अधिक रन बनाए हैं — वह ऐसा करने वाले दुनिया के आठवें बल्लेबाज हैं। रोहित की निरंतरता और नेतृत्व ने उन्हें MI के लिए एक अहम खिलाड़ी बना दिया है, और उनके योगदान ने वर्षों से टीम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- विराट कोहली ने आईपीएल इतिहास में एक और शानदार कीर्तिमान स्थापित करते हुए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वॉर्नर को पीछे छोड़ सबसे ज्यादा फिफ्टी-प्लस स्कोर (50 से अधिक रन की पारियाँ) बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यह उपलब्धि कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूर (RCB) की पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ मुल्लापुर में खेले गए रोमांचक मुकाबले में हासिल की। कोहली ने 54 गेंदों में नाबाद 73 रन की जिम्मेदार पारी खेली, जिससे RCB ने 158 रनों का लक्ष्य 7 विकेट से हासिल कर लिया। यह विराट कोहली का आईपीएल में 67वां फिफ्टी-प्लस स्कोर है, जो उनकी निरंतरता और टी20 क्रिकेट में अद्वितीय कौशल का प्रमाण है। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन ने कोहली को लीग के सबसे प्रभावशाली और भरोसेमंद खिलाड़ियों में और भी मजबूत स्थान दिलाया है।

बैडमिंटन और टेनिस

- बॉम्बे जिमखाना, मुंबई (24-28 मार्च, 2025) में आयोजित इंडियन ओपन 2025 पीएसए कॉपर इवेंट में अनाहत सिंह ने अपना 11वां पीएसए खिताब जीता, जिससे भारत की शीर्ष रैंक वाली महिला स्कैश खिलाड़ी के रूप में उनकी स्थिति फिर से पुख्ता हुई, जबकि करीम एल टॉर्की (मिस्र, विश्व नंबर 64) ने पुरुष एकल फाइनल में अभय सिंह (भारत) के खिलाफ जीत हासिल की। 53,500 डॉलर की पुरस्कार राशि के साथ, यह 2018 के बाद से भारत का सबसे अधिक रेटिंग वाला पीएसए इवेंट था और देश में आयोजित पहला पीएसए कॉपर इवेंट था।
- विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी आर्यना सर्बालेंका ने फाइनल में जेसिका पेगुला को 7-5, 6-2 से हराकर मियामी ओपन का अपना पहला खिताब जीता, इस तरह उन्होंने टूर्नामेंट में कोई भी सेट गंवाए बिना खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही उन्होंने 19वां WTA खिताब अपने नाम कर लिया, जिसमें 8 WTA 1000 खिताब और 3 ग्रैंड स्लैम खिताब शामिल हैं। सर्बालेंका का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने पहले सेट में पेगुला की सर्विस को लव के लिए तोड़ा और दूसरे सेट में आक्रामक शॉट-मेकिंग का प्रदर्शन किया।

हॉकी

- भारतीय महिला हॉकी की दिग्गज खिलाड़ी बंदना कटारिया ने 15 साल के शानदार करियर के बाद 2 अप्रैल, 2024 को अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की। 32 वर्षीय स्ट्राइकर, जिन्होंने 320 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और 158 गोल किए हैं, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं। कटारिया ने इंस्टाग्राम पर अपनी भावनात्मक विदाई साझा की, जिसमें उन्होंने अपने करियर के "चरम" पर कदम पीछे खींचने के अपने फैसले पर जोर दिया, उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खेल को छोड़ने का फैसला किया।

रेसिंग

- फ्रांसेस्को बैगनिया ने अमेरिका के ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की, जब मार्क मार्केज़ सर्किट ऑफ़ द अमेरिकाज़ (COTA) में नौवें लैप पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। डुकाटी ने पोडियम पर अपना दबदबा बनाया, एलेक्स मार्केज़ दूसरे और फैबियो डि जियानान्टोनियो तीसरे स्थान पर रहे, जिससे डुकाटी की लगातार 20वीं ग्रैंड प्रिक्स जीत दर्ज हुई, जो होंडा के रिकॉर्ड (22) से सिर्फ दो जीत पीछे है।
- मैक्स वस्टेंपेन ने जापानी ग्रैंड प्रिक्स में 2025 फॉर्मूला 1 सीज़न की अपनी पहली रेस जीती, जिससे उनकी लगातार चौथी जीत सुनिश्चित हुई। मैकलारेन के लैंडो नॉरिस और ऑस्कर पियास्त्री के साथ एक करीबी मुकाबले के बाद, वस्टेंपेन ने रणनीतिक पिट स्टॉप और टायर विकल्पों की मदद से बढ़त बनाए रखी। पोल पोजिशन के लिए क्वालीफाइंग में उन्होंने नॉरिस को सिर्फ 0.012 सेकंड से पीछे छोड़ा। यह रेस रेड बुल के लिए भी महत्वपूर्ण थी, जो होंडा पावर के साथ उनकी आखिरी रेस थी। वस्टेंपेन ने स्टैंडिंग में अपनी बढ़त को बढ़ाया, अब नॉरिस से सिर्फ एक अंक आगे हैं। अन्य उल्लेखनीय फिनिश में चार्ल्स लेक्लर (फेरारी) चौथे और जॉर्ज रसेल (मर्सिडीज) पांचवें स्थान पर रहे।

एथलेटिक और फुटबॉल

- भारत ने ब्राजील के फोर्ज़ डू इगुआकु में 2025 विश्व मुक्केबाजी कप में ऐतिहासिक शुरुआत की, हितेश गुलिया स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए। उनकी जीत तब हुई जब उनके प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड के ओडेल कामारा चोट के कारण प्रतियोगिता से हट गए। अभिनाश जामवाल ने 65 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता, जबकि जदुमणि सिंह मंडेंगबाम, मनीष राठौर, सचिन और विशाल ने कांस्य पदक जीते। भारत ने कुल छह पदक जीते, जो विश्व मुक्केबाजी कप में अपनी पहली भागीदारी में एक मजबूत प्रदर्शन था, जिसने 2028 ओलंपिक से पहले एक महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया।
- भारत ने अम्मान में 2025 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में प्रीस्टाइल और ग्रीको-रोमन कुश्ती में दमदार प्रदर्शन करते हुए 10 पदक जीते। मनीषा भानवाला (62 किग्रा) ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि दीपक पुनिया (92 किग्रा), उदित (61 किग्रा) और रीतिका हुड्डा (76 किग्रा) ने रजत पदक जीता। अंतिम पंगल (53 किग्रा) और दिनेश (125 किग्रा) सहित छह पहलवानों ने कांस्य पदक जीता। 30 सदस्यीय दल में मानसी लाठेर और मुकुल दहिया जैसी शीर्ष प्रतिभाएँ शामिल थीं, जिन्होंने महाद्वीपीय कुश्ती में भारत के प्रभुत्व को मजबूत किया।





OTHER SPORTS NEWS

- मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, ने आधिकारिक तौर पर एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। वे श्रीलंका के शम्मी सिल्वा का स्थान लेंगे और महाद्वीप की क्रिकेट संस्था का नेतृत्व करने पर गर्व व्यक्त किया।
- कारगिल विजय दिवस 2025 समारोह के हिस्से के रूप में भारतीय सेना द्वारा जुबर स्टेडियम में बटालिक क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना, खेलों को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं को जोड़ना था। यह स्थानीय शिल्प कौशल को बढ़ावा देने का भी एक प्रयास था।
- नई दिल्ली में आयोजित अदित्य बिड़ला मेमोरियल पोलो कप 2025 का समापन एक रोमांचक फाइनल मुकाबले के साथ हुआ, जिसमें राजनिगंधा अचीवर्स ने जिंदल पैथर को हराकर खिताब अपने नाम किया। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट स्वर्णीय श्री अदित्य विक्रम बिड़ला के पोलो खेल के प्रति प्रेम को समर्पित है और इसमें दुनिया के कुछ बेहतरीन पोलो खिलाड़ियों ने भाग लिया।
- भारत की मुक्केबाजी टीम ने ब्राजील के फॉज़ डू इगुआसू में आयोजित 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में अपने पहले ही प्रयास में शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में हितेश गुलिया ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। वे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले और अब तक के एकमात्र भारतीय मुक्केबाज बने। उनका यह ऐतिहासिक जीत तब और खास बन गई जब फाइनल में उनके प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड के ओडेल कैमारा चोट के चलते मुकाबले में नहीं उतर पाए। हितेश की इस उपलब्धि के अलावा, अभिनाश जम्वाल ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया, जबकि चार अन्य भारतीय मुक्केबाजों ने विभिन्न भार वर्गों में कांस्य पदक अपने नाम किए।
- मैक्स वेरस्टैपेन ने 2025 जापानी ग्रैंड प्रिक्स में मैकलारेन के ड्राइवर लैंडो नोरिस और ऑस्कर पियास्ती को पछाड़कर लगातार चौथी जीत दर्ज की। वेरस्टैपेन की पोल पोजीशन और रेस में लगातार बेहतर प्रदर्शन ने उन्हें स्टैंडिंग में अपनी बढ़त को और मजबूत करने में मदद की, अब वे नोरिस से सिर्फ एक अंक पीछे हैं।
- संयुक्त राष्ट्र (यूनाइटेड किंगडम) 2035 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए एकमात्र "वैध" बोलीदाता बनकर उभरा है। इस बात की पुष्टि फीफा अध्यक्ष जियानी इनफैंटिनो ने की है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड द्वारा संयुक्त रूप से यह बोली प्रस्तुत की गई है, जिससे यह तय माना जा रहा है कि यह टूर्नामेंट एक बार फिर यूरोप में लौटेगा—2023 संस्करण के बाद पहली बार। यह ऐतिहासिक अवसर 2022 में आयोजित UEFA महिला यूरो जैसे सफल आयोजनों की सफलता के बाद आया है और यह क्षेत्र में महिला फुटबॉल के बढ़ते प्रभाव और लोकप्रियता को भी दर्शाता है।
- उत्तर प्रदेश के 22 वर्षीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने पेरू के लीमा में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप (अप्रैल 2025) में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारतीय निशानेबाजी टीम में शानदार वापसी की। ओलंपिक चैंपियनों से सजी इस फाइनल में उन्होंने कड़ी टक्कर और कम स्कोर वाले मुकाबले में धैर्य और साहस का परिचय दिया। यह उनका दो वर्षों में पहला व्यक्तिगत वर्ल्ड कप पदक है, जो

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी जबरदस्त वापसी को दर्शाता है।

- खेलो इंडिया यूथ गेम्स (KIYG) 2025 पहली बार बिहार में आयोजित होने जा रहे हैं, जो राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह प्रतिष्ठित आयोजन 4 मई से 15 मई 2025 तक होगा और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना में किया जाएगा। यह कार्यक्रम न केवल राज्य में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि बिहार के खेल बुनियादी ढांचे को भी मजबूती प्रदान करेगा और उभरते हुए खिलाड़ियों को एक राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराएगा।
- कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन में 13 अप्रैल 2025 को मोहन बागान सुपर जायंट ने बेंगलुरु एफसी को 2-1 से हराकर इंडियन सुपर लीग (ISL) 2024-25 का खिताब अपने नाम किया। यह जीत कई मायनों में ऐतिहासिक रही – पहली बार किसी टीम ने घरेलू मैदान पर ISL फाइनल जीता, और मोहन बागान पहली टीम बनी जिसने लीग शील्ड और ISL ट्रॉफी दोनों एक ही सीजन में अपने नाम की।
- भारत ने अंतरराष्ट्रीय शूटिंग सत्र की शानदार शुरुआत करते हुए 2025 के पहले ISSF विश्व कप (राइफल, पिस्टल और शॉटगन वर्गों के लिए) में कुल दूसरा स्थान हासिल किया। यह टूर्नामेंट आगामी पेरिस ओलंपिक से पहले आयोजित किया गया, जिसमें भारत की युवा और अनुभवी प्रतिभा का बेहतरीन संगम देखने को मिला। हालांकि अंतिम स्पर्धा में भारत मामूली अंतर से पदक से चूक गया, फिर भी भारतीय दल ने कुल 8 पदक जीतकर अपनी क्षमता, निरंतरता और उज्ज्वल भविष्य की मजबूत झलक पेश की। यह प्रदर्शन आने वाले ओलंपिक के लिए भारत की तैयारियों और उम्मीदों को और मजबूत करता है।
- मैकलारेन के ऑस्कर पियास्ती ने बहरीन इंटरनेशनल सर्किट पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 2025 फॉर्मूला 1 सीजन की अपनी दूसरी जीत हासिल की। पियास्ती, जिन्होंने पोल पोजीशन से शुरुआत की, ने रेस में सेफ्टी कार के हस्तक्षेप के बावजूद दबदबा बनाए रखा, जो उनके और टीममेट लैंडो नॉरिस के साथ खिताबी संघर्ष को मजबूत करता है। इस जीत के साथ, वह 2025 सीजन के पहले रिपीट विजेता बने और मैकलारेन के लिए उनके बहरेनी मालिकों के होम ट्रैक पर पहली जीत दर्ज की।
- भारत की रिकर्व पुरुष तीरंदाजी टीम, जिसमें धीरज बोम्मादेवर, अतानु दास, और तरुणदीप राय शामिल थे, ने अपनी 2025 सीजन की शुरुआत ऑबर्नडेल, फ्लोरिडा में आयोजित विश्व कप स्टेज 1 में रजत पदक के साथ की। हालांकि, वे दुनिया की नंबर दो टीम थे, भारतीय त्रयी फाइनल में चीन से 1-5 से हार गई, जो इस टूर्नामेंट में तीसरे नंबर पर थी। भारतीय टीम ने इससे पहले सेमीफाइनल में स्पेन (8वीं सीड) को हराया था।
- दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, जो 3 से 5 मई तक रांची, झारखंड में आयोजित होने वाली थी, को सात महीनों में दूसरी बार स्थगित कर दिया गया है। पहले यह प्रतियोगिता अक्टूबर 2024 में प्रस्तावित थी, लेकिन इस बार की देरी का कारण पाकिस्तानी खिलाड़ियों के वीजा क्लियरेंस से जुड़ी समस्याएं बताई जा रही हैं। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में दक्षिण एशिया के शीर्ष एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद थी, जिनमें पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अर्शद नदीम और श्रीलंका के प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं। अब इस आयोजन के लिए नई संभावित तारीख जून 2025 के दूसरे या तीसरे सप्ताह की तय की गई है, जो वीजा मुद्दों के समाधान पर निर्भर करेगी।





साइंस एंड टेक्नोलॉजी

साइंस एंड टेक्नोलॉजी: सितम्बर 2025

उपग्रह / अंतरिक्ष प्रक्षेपण

- रमन अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रतुश कॉस्मिक डॉन मिशन के लिए विकसित किया गया एक छोटा कंप्यूटर, जो चंद्रमा के दूरस्थ भाग पर प्रारंभिक ब्रह्मांड से 21-सेमी हाइड्रोजन संकेतों का पता लगाएगा।
- आईआईटी जोधपुर एआई नवाचार: सांस्कृतिक विरासत और पाठ पहचान के लिए विज्ञान, भाषा और शिक्षण समूह के अंतर्गत 13 भारतीय भाषाओं के लिए एआई उपकरण विकसित कर रहा है।
- तमिलनाडु में इसरो का नया अंतरिक्ष बंदरगाह दिसंबर 2026 तक चालू हो जाएगा, जो छोटे उपग्रह प्रक्षेपणों में सहायता करेगा।
- भारत ने मंगल मिशन और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की भविष्य की योजनाओं के साथ, नौ अंतरिक्ष विश्व रिकॉर्ड बनाए।
- इसरो ने एचएएल को एसएसएलवी तकनीक हस्तांतरित की: 100वां तकनीकी-हस्तांतरण सौदा, जिससे 24 महीनों में स्वतंत्र एसएसएलवी उत्पादन संभव हो सकेगा।
- नासा के पर्सिवियरेंस रोवर ने कार्बनिक कार्बन और खनिज भंडारों के माध्यम से मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के सबसे मजबूत संकेत पाए हैं।

राष्ट्रीय

- दुबई में वैश्विक डाक कांग्रेस का नेतृत्व भारत ने किया: ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसका मुख्य उद्देश्य धन प्रेषण के लिए यूपीआई-यूपीयू एकीकरण पर केंद्रित था।
- दिल्ली का एम्स, दा विंची रोबोटिक सर्जरी प्लेटफॉर्म पर डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया।
- राष्ट्रीय वन शहीद दिवस (11 सितंबर) खेजरली नरसंहार के बलिदानों की स्मृति में "शहीदों का स्मरण, वनों की रक्षा" थीम के साथ मनाया गया।
- स्वामी विवेकानंद के 1893 के शिकागो भाषण में सार्वभौमिक भाईचारे और सद्भाव पर दिए गए भाषण के सम्मान में दिग्विजय दिवस मनाया गया।
- दुर्लभ ड्रैगनफ्लाई की पुनः खोज: क्रोकोथेमिस एरिथ्रिया, जो आमतौर पर यूरोप और हिमालय में देखी जाती है, पश्चिमी घाट (केरल और तमिलनाडु) में 550 मीटर से ऊपर पाई गई; संभवतः हिमयुग की अवशेष प्रजाति, जो जैव विविधता की समृद्धि और शोला-घासभूमि पारिस्थितिकी तंत्र की नाजूकता को उजागर करती है।

अंतरराष्ट्रीय

- 7-8 सितंबर को 82 मिनट का दुर्लभ पूर्ण चंद्रग्रहण (ब्लड मून) एशिया, अफ्रीका और यूरोप में दिखाई देगा।
- रूस का कोलन कैंसर वैक्सीन: परीक्षणों में 80% ट्यूमर में कमी और बेहतर जीवन दर दिखाई दी।
- रूस का एंटेरोमिक्स mRNA कैंसर वैक्सीन: 48 रोगियों पर किए गए शुरुआती परीक्षणों में ट्यूमर सिकुड़ने और बिना किसी बड़े दुष्प्रभाव के 100% प्रभावकारिता दिखाई दी।
- विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस (13 सितंबर) "प्राथमिक चिकित्सा और जलवायु परिवर्तन" थीम के साथ मनाया गया, जिसमें आपातकालीन तैयारियों पर प्रकाश डाला गया।

- देशभक्त दिवस (अमेरिका, 11 सितंबर) 2001 के आतंकवादी हमले के पीड़ितों की याद में मनाया गया, जिसमें प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं को सम्मानित किया गया।

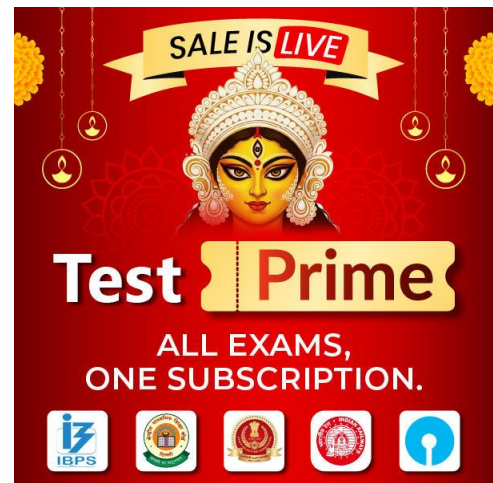
साइंस एंड टेक्नोलॉजी: अगस्त 2025

उपग्रह प्रक्षेपण

- इसरो 2025 के अंत में श्रीहरिकोटा से एलवीएम3 के जरिए एसटीडी स्पेसमोबाइल (अमेरिका) द्वारा विकसित 6,500 किलोग्राम वजन की ब्लूबर्ड संचार उपग्रह को प्रक्षेपित करने की तैयारी कर रहा है। यह मिशन निसार के सफल प्रक्षेपण के बाद है और भारत-अमेरिका के बीच बढ़ते अंतरिक्ष सहयोग को दर्शाता है। यह भारत के व्यापक अंतरिक्ष लक्ष्यों, जिनमें गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम और 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य शामिल है, के अनुरूप भी है।
- मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए पैराशूट-आधारित मंदन प्रणाली। भारतीय वायु सेना, डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के सहयोग से हासिल की गई यह उपलब्धि, मानव-रेटेड लॉन्च व्हीकल (एचएलवीएम3) और कू मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और कू एस्केप सिस्टम (सीईएस) जैसी अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियों के पूरा होने के बाद हासिल की गई है। यह मिशन भारत के व्यापक अंतरिक्ष दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर उतरना है।

राष्ट्रीय

- इसरो ने अपने गगनयान कार्यक्रम के तहत लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर 10 दिवसीय उच्च-ऊंचाई वाला अंतरिक्ष सिमुलेशन आयोजित किया। प्रोटोप्लेनेट द्वारा नवनिर्मित HOPE (ग्रहों की खोज के लिए हिमालयन आउटपोस्ट) सुविधा में आयोजित इस अध्ययन में अलगाव, ठंड के तनाव और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया गया। 135 आवेदकों में से दो प्रतिभागियों, राहुल मोगालापल्ली और यमन अकोट का चयन किया गया, जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों की दिनचर्या का अनुकरण किया।





- कृषि लचीलापन बढ़ाने के लिए, ICRISAT ने ICAR के सहयोग से और मानसून मिशन III के तहत, महाराष्ट्र में एक AI-संचालित जलवायु परामर्श सेवा शुरू की। AI-सक्षम व्हाट्सएप बॉट का उपयोग करते हुए, यह सेवा छोटे किसानों को स्थानीय मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करती है, और इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की योजना है।
- IndiaAI और नेशनल कैंसर ग्रिड (NCG) ने CATCH अनुदान कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें ₹50 लाख तक के पायलट अनुदान और ₹1 करोड़ तक के स्केल-अप फंडिंग की पेशकश की गई है। यह कार्यक्रम 2 सितंबर, 2025 तक खुला रहेगा और कैंसर की जांच, निदान और उपचार में एआई-संचालित समाधानों का समर्थन करता है, तथा जिम्मेदार एआई विकास और नैदानिक सत्यापन को प्रोत्साहित करता है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अंतर्गत भारत जेन एआई, जून 2026 तक आठवीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं का समर्थन करेगा। यह पहल, राष्ट्रीय अंतःविषय साइबर-भौतिक प्रणालियों मिशन का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य डिजिटल समावेशिता सुनिश्चित करना और पूरे भारत में बहुभाषी एआई पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है।
- डॉ. जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद स्थित एनआईएवी में भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, जो पशु चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग है। उन्होंने अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ₹19.98 करोड़ की लागत से नए बुनियादी ढांचे की आधारशिला भी रखी। ₹1.85 करोड़ की लागत से निर्मित यह प्रयोगशाला पशुओं के लिए पुनर्योजी चिकित्सा और कोशिकीय उपचारों पर केंद्रित होगी। उन्होंने रोगाणुरोधी प्रतिरोध का मुकाबला करने और 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए पाँच नवीन पशु चिकित्सा निदान उपकरण भी लॉन्च किए। प्रधानमंत्री मोदी की बायोई3 नीति की प्रशंसा करते हुए, मंत्री ने जैव प्रौद्योगिकी-संचालित विकास में भारत के नेतृत्व पर जोर दिया, जिसका लक्ष्य पशुपालन और कृषि में एक सदावहार क्रांति लाना है।
- न्यूजीलैंड का दुर्लभ ब्लू पिंकगिल मशरूम, तेलंगाना के कागजनगर जंगल में खोजा गया, जो दुर्लभ एजलीन वर्णकों के कारण अपने आकर्षक आसमानी नीले रंग को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त, पूर्वी घाट (कवल टाइगर रिजर्व) में पहली बार देखा गया शटलकॉक मशरूम, इस क्षेत्र की समृद्ध कवक विविधता और अद्वितीय पारिस्थितिक स्थितियों को दर्शाता है।
- इसरो ने अरुणाचल प्रदेश के शि-योमी जिले के मेचुका सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। शिक्षा मंत्री पासंग दोरजी सोना द्वारा उद्घाटन की गई इस प्रयोगशाला का उद्देश्य, इसरो और मुस्कान फाउंडेशन के सहयोग से, छात्रों में व्यावहारिक शिक्षा के माध्यम से अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि जगाना है। मंत्री के पिता के नाम पर "पासंग वांगचुक सोना इसरो अंतरिक्ष प्रयोगशाला" नाम दिया गया यह कार्यक्रम, जीवन को बदलने की शिक्षा की शक्ति में उनके विश्वास का सम्मान करता है।
- इसरो - गगनयान अपडेट: दिसंबर 2025 में पहली मानवयुक्त मिशन परीक्षण उड़ान; 80% परीक्षण पूरे। इसरो ने GLEX-2025 प्रणोदन प्रणाली और 6,500 किलोग्राम वजनी अमेरिकी संचार उपग्रह प्रक्षेपण सहित 196 उपलब्धियाँ हासिल कीं।

- भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्र मिशन: भारत का लक्ष्य 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक मानवयुक्त चंद्र मिशन स्थापित करना है। मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन की सराहना की।
- भारत वैश्विक एआई दौड़ में अग्रणी बन गया है, और ओपनएआई ने मात्र ₹399/माह पर चैटजीपीटी गो लॉन्च करके और नई दिल्ली में अपने पहले भारतीय कार्यालय की घोषणा करके इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत एआई मिशन के अनुरूप यह कदम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्लेक्सिटी और xAI के साथ प्रतिस्पर्धा को और तेज़ करता है, जिससे तेज़ी से बढ़ते बाज़ार में मूल्य युद्ध छिड़ गया है। ओपनएआई का स्थानीयकरण—यूपीआई एकीकरण, भारतीय भाषाएँ और शिक्षा उपकरण—भारत के विशाल छात्र आधार और डेवलपर पारिस्थितिकी तंत्र की ज़रूरतों को पूरा करता है। यह उद्घाल उपयोगकर्ताओं को किफायती एआई पहुँच प्रदान करता है, साथ ही यह भारतीय स्टार्टअप्स के लिए चुनौतियाँ भी पैदा करता है, जिससे उन्हें पूँजी-भारी परिदृश्य में सहयोग करने या अनुकूलन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

अंतरराष्ट्रीय

- भारत ने ब्रिटेन के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर बेंगलुरु की एक 38 वर्षीय महिला में दुनिया के सबसे दुर्लभ रक्त समूह - CRIB की पहचान की है। क्रोमर रक्त समूह प्रणाली का हिस्सा होने के कारण, इस रक्त में एक सामान्य प्रतिजन का अभाव होता है, जिससे रक्त आधान बेहद मुश्किल हो जाता है। यह खोज वैश्विक स्तर पर गहन देखभाल, प्रसवपूर्व निदान और दुर्लभ रक्तदान प्रणालियों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है।
- अंतर्निहित भूख से निपटने के लिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (CIP) के सहयोग से लौह-समृद्ध जैव-सशक्त आलू की खेती शुरू कर रहा है। यह पहल विटामिन A से भरपूर शकरकंदों के लिए प्रयासों का पूरक है, जो ICAR के 61 फसलों को कवर करने वाले जैव-सशक्तीकरण कार्यक्रम का हिस्सा हैं। यह पोषण सुरक्षा को मज़बूत करता है और जलवायु-अनुकूल कृषि में भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित करता है।
- स्पेसएक्स ने टेक्सास के स्टारवेस से अपना दसवाँ सफल स्टारशिप परीक्षण प्रक्षेपण पूरा किया, जिससे दुनिया के पहले पूर्णतः पुनः प्रयोज्य रॉकेट की दिशा में प्रगति का प्रदर्शन हुआ। सुपर हेवी बूस्टर ने मेक्सिको की खाड़ी में नियंत्रित स्पलैशडाउन हासिल किया, जबकि स्टारशिप के ऊपरी चरण ने अंतरिक्ष में पुनः प्रज्वलन किया और हिंद महासागर में सॉफ्ट-लैंडिंग की। उल्लेखनीय रूप से, इसने स्टारलैंक सिमुलेटर का उपयोग करके पेलोड परिनियोजन का भी प्रदर्शन किया, जिससे सभी प्रमुख उद्देश्य पूरे हुए और 2027 में नासा के आर्टेमिस III जैसे भविष्य के मिशनों में सहायता मिली।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एआई गवर्नेंस पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दो प्रमुख पहलों — एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल और एआई गवर्नेंस पर वैश्विक संवाद — की शुरुआत की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस कदम की सराहना करते हुए इसे एआई के लाभों और जोखिमों के संतुलन की दिशा में एक "महत्वपूर्ण कदम" बताया है। वैज्ञानिक पैनल नीति निर्धारण के लिए स्वतंत्र आकलन प्रस्तुत करेगा, जबकि संवाद वैश्विक हितधारकों के लिए एक समावेशी मंच के रूप में कार्य करेगा। ये प्रयास भविष्य के समझौते (2024) के अंतर्गत वैश्विक डिजिटल समझौते का समर्थन करते हैं।





- नैनो बनाना, गूगल के नए AI-संचालित फोटो-एडिटिंग टूल का कोड नाम है, जिसे आधिकारिक तौर पर जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज के रूप में लॉन्च किया गया है और इसे गूगल डीपमाइंड द्वारा विकसित किया गया है। यह उपयोगकर्ताओं को कई तस्वीरों को मिलाने, पात्रों की एकरूपता बनाए रखने और प्राकृतिक भाषा संकेतों का उपयोग करके हेयरस्टाइल बदलने, वेशभूषा जोड़ने या पृष्ठभूमि बदलने जैसे रचनात्मक संपादन करने की सुविधा देता है। इसका एक प्रमुख फीचर, "डिज़ाइन मिक्सिंग", उपयोगकर्ताओं को अनोखे प्रभाव के लिए एक तस्वीर से दूसरी तस्वीर में बनावट या शैलियों को स्थानांतरित करने की सुविधा देता है।

साइंस एंड टेक्नोलॉजी: जुलाई 2025

उपग्रह प्रक्षेपण

- हैदराबाद की कंपनी आनंत टेक्नोलॉजीज़ को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। यह प्रोजेक्ट IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र) द्वारा स्वीकृत किया गया है और इसके 2028 में शुरू होने की उम्मीद है। यह सेवा पूरी तरह से भारत में बने उपग्रहों के जरिए संचालित की जाएगी। यह कदम अंतरिक्ष-आधारित इंटरनेट सेवाओं में Starlink, OneWeb और Amazon Kuiper जैसे वैश्विक खिलाड़ियों को टक्कर देने की दिशा में भारत का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
- इसरो ने तीन जुलाई को महेंद्रगिरी स्थित अपने प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम (एसएमपीएस) के दो सफल परीक्षण किए। ये छोटे अवधि के परीक्षण क्रमशः 30 सेकंड और 100 सेकंड तक चले। इसरो ने कहा कि इनका उद्देश्य परीक्षण आलेख के कान्फिगरेशन को प्रमाणित करना था। परीक्षण के दौरान प्रोपल्शन सिस्टम का समग्र प्रदर्शन पूर्व-टेस्ट पूर्वानुमानों के अनुसार सामान्य था। 100 सेकंड के परीक्षण के दौरान, विभिन्न मोड में सभी रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम (आरसीएस) थ्रस्टर्स का समवर्ती संचालन और सभी लिक्विड अपोजी मोटर (एलएएम) इंजनों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया।
- भारत ने अपनी रणनीतिक रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए 17 जुलाई 2025 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से परमाणु क्षमता से युक्त पृथ्वी-2 और अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण सामरिक बल कमान (Strategic Forces Command) के तहत किए गए, जिनमें सभी परिचालन मानकों की सफलतापूर्वक पुष्टि हुई और देश की स्वदेशी मिसाइल क्षमताओं को मजबूती मिली।
- भारतीय वायुसेना के अधिकारी और अंतरिक्ष यात्री गुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए। वे Axiom-4 मिशन का हिस्सा थे, जो अमेरिका की निजी अंतरिक्ष कंपनी Axiom Space द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष मिशन था। शुक्ला और उनके तीन सह-यात्रियों ने 18 दिन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर बिताए और इस दौरान पृथ्वी की 288 बार परिक्रमा की। उन्होंने कई वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिनका उद्देश्य भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं को सक्षम बनाना और पृथ्वी पर जीवन को बेहतर बनाना था।
- इज़रायल ने 13 जुलाई 2025 को अमेरिका के केप केनेवरल से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से अपने अब तक के सबसे उन्नत संचार उपग्रह Dror-1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इस उपग्रह का निर्माण इज़रायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ (IAI) द्वारा किया गया है और यह अगले 15 वर्षों तक देश की संचार आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह लॉन्च इज़रायल की अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय संचार प्रणाली में अंतरिक्ष-आधारित संरचनाओं की भूमिका तेजी से बढ़ रही है।
- नासा ने पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सौर तूफानों और अंतरिक्ष मौसम से ग्रह की रक्षा कैसे करता है, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए TRACERS मिशन (टेंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनामिक्स रीकॉनिसेंस सैटेलाइट्स) लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य चुंबकीय पुनर्संयोजन का अध्ययन करना है—एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय कवच के साथ क्रिया करता है, जिससे ऊर्जा विस्फोट होता है जो उपग्रहों, पावर ग्रिड और संचार को प्रभावित कर सकता है।
- भारत 30 जुलाई 2025 को NASA-ISRO सिंथेटिक अपचर रडार (NISAR) उपग्रह का प्रक्षेपण करने जा रहा है। यह ISRO और NASA के बीच पहला संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, जिसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC-SHAR) से GSLV-F16 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। उपग्रह को 743 किमी की ऊंचाई पर 98.4° झुकाव वाले सन-सिंक्रोनस कक्षा (SSO) में स्थापित किया जाएगा, जिससे पृथ्वी की सतह का हर मौसम और प्रकाश परिस्थितियों में लगातार अवलोकन संभव होगा।

राष्ट्रीय

- हार्ड-एंड एआई चिप्स में वैश्विक अग्रणी एनवीडिया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनकर इतिहास रचने के लिए तैयार है। गुरुवार को इसका बाजार पूंजीकरण 3.92 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो 26 दिसंबर, 2024 को स्थापित एप्पल के 3.915 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड को पार कर गया। यह न केवल एनवीडिया के लिए, बल्कि पूरी तकनीक और वित्तीय दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है।
- लद्दाख ने विज्ञान आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। हाल ही में लेह में आयोजित पहले "एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल" का सफल समापन हुआ। यह दो दिवसीय आयोजन लद्दाख पर्यटन विभाग और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA), बंगलुरु के सहयोग से किया गया, जिसका उद्देश्य लद्दाख को खगोल पर्यटन (Astro Tourism) के प्रमुख गंतव्यों में शामिल करना है।
- स्विट्जरलैंड ने नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए पहली बार मलेरिया के उपचार की दवा 'Coartem' को मंजूरी दे दी है। यह दवा नोवार्टिस द्वारा विकसित की गई है। यह दवा उन नवजात शिशुओं के लिए बनाई गई है जिनका वजन 2 से 5 किलोग्राम के बीच है। यह कदम बेहद अहम है, क्योंकि मलेरिया खासकर अफ्रीका में बच्चों की मौत का एक बड़ा कारण है। यह मलेरिया से होने वाली मौतों को रोकने में अहम भूमिका निभाएगी, विशेषकर अफ्रीका में जहां वर्ष 2023 में मलेरिया से 5 लाख से अधिक मौतें हुईं, जिनमें अधिकांश बच्चे शामिल थे।





- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने वेबएक्स स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्लेटफॉर्म के माध्यम से “कला सेतु – भारत के लिए रियल-टाइम लैंग्वेज टेक” चैलेंज लॉन्च किया है। यह राष्ट्रव्यापी पहल देश के अग्रणी एआई स्टार्ट-अप को कई भारतीय भाषाओं के सहयोग के साथ पाठ्य इनपुट से ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक कंटेंट के स्वचालित सृजन के लिए स्वदेशी, स्केलेबल समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है।
- आंध्र प्रदेश सरकार ने डेंगू और मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए, खासकर बरसात के मौसम में, एक नई परियोजना शुरू की है। स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम (SMoSS) नामक यह परियोजना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करती है। यह सबसे पहले छह बड़े शहरों में शुरू होगी। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर साल हज़ारों लोग इन बीमारियों से बीमार पड़ते हैं।
- असम के बक्सा ज़िले में गार्सिनिया कुसुमे नामक एक नई वृक्ष प्रजाति की खोज की गई है। गार्सिनिया वंश का यह वृक्ष वरिष्ठ वनस्पतिशास्त्री जतिंद्र शर्मा द्वारा खोजा गया था और इसका नाम उनकी दिवंगत माँ कुसुम देवी की स्मृति में रखा गया है। यह खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की वनस्पति विविधता में वृद्धि करती है और असम की समृद्ध वनस्पति विरासत को उजागर करती है। [Click here to read article](#)
- एचसीएलटेक की सॉफ्टवेयर इकाई HCLSoftware ने Domino 14.5 लॉन्च किया है—एक उन्नत प्लेटफॉर्म जो सरकारों और विनियमित संगठनों के लिए डेटा संप्रभुता (Data Sovereignty) और डेटा गोपनीयता (Data Privacy) को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस नवीनतम संस्करण की प्रमुख विशेषता है Domino IQ, एक सॉवरेन एआई (Sovereign AI) समाधान, जिसे विशेष रूप से राष्ट्रीय और कॉर्पोरेट स्तर की संवेदनशील जानकारी को विदेशी हस्तक्षेप और पहुँच से सुरक्षित रखने के लिए विकसित किया गया है। यह प्लेटफॉर्म उन संस्थाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो डेटा पर पूर्ण नियंत्रण और सुरक्षा चाहते हैं।
- केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 6 जुलाई 2025 को नई दिल्ली स्थित CSIR-IGIB (इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी) में राष्ट्रीय बायोबैंक का उद्घाटन किया। यह नई सुविधा भारत भर के लोगों से स्वास्थ्य और आनुवंशिक (जेनेटिक) डेटा एकत्र करने में मदद करेगी। इसका उद्देश्य बीमारियों की समय रहते पहचान करना और भविष्य में प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत उपचार योजना (पर्सनलाइज़्ड ट्रीटमेंट) को संभव बनाना है।
- लाइकेन (lichen) एक सहजीवी जीव होते हैं, जो कवक (fungi) और प्रकाश संश्लेषण करने वाले भागीदारों—आमतौर पर हरित शैवाल या सायनोबैक्टीरिया—के सहयोग से बनते हैं। ये जीव पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि मृदा निर्माण, वायु प्रदूषण की निगरानी, और खाद्य श्रृंखला को बनाए रखना। Allographa वंश, जो Graphidaceae कुल से संबंधित है, मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जिनमें पश्चिमी घाट भी शामिल हैं—जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और विश्व के जैव विविधता के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है।
- भारतीय प्रबंध संस्थान कोझिकोड (IIMK) ने प्रबंधन शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने और ज्ञान के प्रसार को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक अग्रणी पहल की शुरुआत की है, जिसका नाम है “ज्ञानोदय – शिक्षण नवाचार और प्रकाशन केंद्र”। यह केंद्र शिक्षण के पारंपरिक ढांचे से आगे बढ़कर प्रबंधन शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की दिशा में कार्य कर रहा है।

- गूगल ने भारतीय छात्रों को एक शानदार मौका दिया है। अब 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के छात्रों को Google Gemini AI Pro प्लान का एक साल का सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलेगा। यह ऑफर खास तौर पर छात्रों को नई डिजिटल तकनीकों से जोड़ने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का अनुभव देने के लिए लाया गया है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को उन्नत AI टूल्स प्रदान करना है जिससे वे अपनी शैक्षणिक दक्षता, रचनात्मकता और शोध क्षमताओं को बेहतर बना सकें।
- न्यूयॉर्क में दुर्लभ भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक वस्तुओं की एक नीलामी में पृथ्वी पर अब तक पाया गया मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में बिक गया। उल्कापिंड की नीलामी का यह एक नया रिकार्ड बनाया है। एनडब्ल्यूए 16788 नामक इस पत्थर की नीलामी में ऑनलाइन और फोन बोलीदाताओं के बीच 15 मिनट तक बोली लगाने की होड़ मची रही। 54 पाउंड (24.5 किलोग्राम) के इस पत्थर की खोज नवंबर 2023 में नाइजर के सहारा रेगिस्तान में एक उल्कापिंड खोजने वाले ने की थी।
- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने जनस्वास्थ्य नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन ‘AdFalcivax’ के व्यवसायीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। इस वैक्सीन का उद्देश्य मानवों में सबसे घातक मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम फेल्लिपेरम से लड़ना है। ICMR ने तकनीक हस्तांतरण और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए दवा कंपनियों और विनिर्माताओं से साझेदारी हेतु “रुचि की अभिव्यक्ति” (Expression of Interest – EoI) आमंत्रित की है।

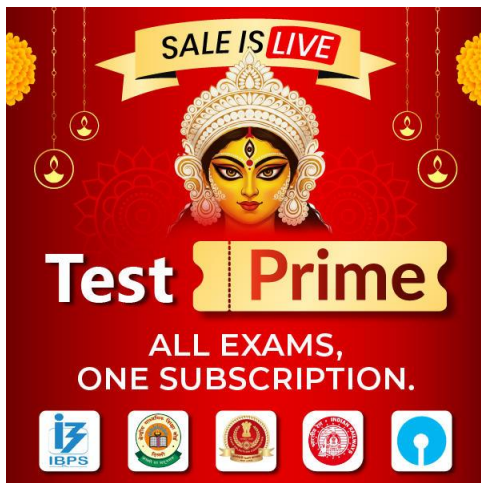
अंतरराष्ट्रीय

- एनवीडिया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, जिसका बाजार पूंजीकरण 3.92 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गया है, जिसने एप्पल के पिछले रिकार्ड को पीछे छोड़ दिया है। एआई बूम से प्रेरित होकर, एआई चिप तकनीक में एनवीडिया के प्रभुत्व ने जबरदस्त वृद्धि को गति दी है, अप्रैल से इसके शेयर में 68% की वृद्धि हुई है। इसका मूल्य अब कनाडा, मेक्सिको और यहाँ तक कि ब्रिटेन के पूरे शेयर बाजारों से भी अधिक है, जो एनवीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भविष्य में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।
- एचसीएलटेक की सॉफ्टवेयर शाखा, एचसीएलसॉफ्टवेयर ने डोमिनो 14.5 लॉन्च किया है, जो सरकारों और विनियमित संगठनों के लिए डेटा संप्रभुता और बेहतर गोपनीयता पर केंद्रित एक उन्नत प्लेटफॉर्म है। इसकी प्रमुख विशेषता, डोमिनो आईक्यू, एक संप्रभु एआई समाधान है जिसे संवेदनशील राष्ट्रीय और उद्यम डेटा को विदेशी निगरानी से सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कार्यकारी उपाध्यक्ष रिचर्ड जेफ्ट्स ने स्थानीय डिजिटल नियंत्रण के महत्व पर जोर दिया, खासकर ऐसे समय में जब देश डेटा सुरक्षा ढाँचों को कड़ा कर रहे हैं।
- स्विट्ज़रलैंड के स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्विस्मेडिक ने नोवार्टिस द्वारा निर्मित शिशुओं के लिए मलेरिया की दवा को अपनी पहली मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी 9 जुलाई, 2025 को मिली है और 2 से 5 किलोग्राम वज़न वाले शिशुओं पर लागू होगी। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मलेरिया हज़ारों बच्चों की जान लेता है, खासकर अफ्रीका में, जहाँ 2023 में दुनिया भर में मलेरिया से होने वाली 95% मौतें हुईं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नई दवा सुरक्षित और प्रभावी है, और इसे मलेरिया प्रभावित देशों में गैर-लाभकारी आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। यह कदम दुनिया की सबसे घातक बीमारियों में से एक के खिलाफ लड़ाई में सबसे कम उम्र के बच्चों की जान बचाने में मदद कर सकता है।





- तस्मानिया विश्वविद्यालय के एडवर्ड डोडरिज सहित वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में पाया गया है कि अंटार्कटिका में गर्मियों में समुद्री बर्फ का स्तर रिकॉर्ड निम्न स्तर पर है। शोध दल ने इसके प्रभावों का अध्ययन करने के लिए उपग्रह डेटा, रोबोटिक महासागर सेंसर और कंप्यूटर मॉडल का उपयोग किया। उनके निष्कर्ष समुद्र के बढ़ते तापमान, समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों को हो रहे नुकसान और बढ़ते वैश्विक जोखिमों को दर्शाते हैं। यह चिंताजनक प्रवृत्ति 2016 में शुरू हुई और जारी है। वैज्ञानिक ग्रह को दीर्घकालिक नुकसान से बचाने के लिए जलवायु कार्रवाई में तेज़ी लाने का आह्वान करते हैं।
- बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चीनी वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे हल्के माइंड-कंट्रोलर के निर्माण की घोषणा की है, जिसका वजन सिर्फ 74 मिलीग्राम है। इस उपकरण का इस्तेमाल मधुमक्खियों को नियंत्रित करने और उन्हें साइबॉर्ग में बदलने के लिए किया जाता है, जो सैन्य अभियानों, शहरी युद्ध, नशीली दवाओं की खोज और आपदा बचाव के दौरान आदेशों का पालन कर सकते हैं। यह नियंत्रक मधुमक्खियों के मस्तिष्क में डाली गई तीन छोटी सुइयों के माध्यम से संकेत भेजता है, जिससे उनके उड़ान पथ का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन होता है। टीम का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर झाओ जीलियांग ने कहा कि कीट साइबॉर्ग मशीनों की तुलना में बेहतर गति, चुपके और धीरज प्रदान करते हैं। हालाँकि बैटरी लाइफ़ एक समस्या बनी हुई है, टीम भविष्य में इसे बेहतर बनाने की योजना बना रही है।
- इज़राइल ने 13 जुलाई, 2025 को केप कैनावेरल से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके अपने ड्रॉन-1 संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) द्वारा निर्मित, ड्रॉन-1 का वजन 4.5 टन है और यह बड़े एंटेना और सौर पैनलों से सुसज्जित है। यह 15 वर्षों तक इज़राइल की संचार आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह प्रक्षेपण इज़राइल के अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को मजबूत करने, तकनीकी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने और उन्नत उपग्रह प्रणालियों का उपयोग करके सुरक्षित संचार नेटवर्क का विस्तार करने के प्रयासों को दर्शाता है।
- गूगल पात्र भारतीय छात्रों को 15 सितंबर, 2025 तक मुफ्त जेमिनी एआई प्रो एक्सेस प्रदान कर रहा है। इसमें जेमिनी 2.5 प्रो, डीप रिसर्च, जेमिनी फॉर वर्कस्पेस और 2TB क्लाउड स्टोरेज जैसे टूल शामिल हैं। यह ऑफ़र परीक्षा की तैयारी, रचनात्मकता और डिजिटल सशक्तिकरण में मदद करता है। छात्र आईडी के साथ आवेदन करने और एक साल मुफ्त पाने के लिए gemini.google/students पर जाएँ।



साइंस एंड टेक्नोलॉजी: जून 2025

सैटेलाइट लॉन्च

- भारत जीआरएसई और नॉर्वे के कॉग्सबर्ग के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता जापान के माध्यम से अपने पहले ध्रुवीय अनुसंधान पोत (पीआरवी) के निर्माण की शुरुआत कर रहा है। एनसीपीओआर द्वारा उपयोग किया जाने वाला यह पोत ध्रुवीय अनुसंधान में भारत की भूमिका को बढ़ाएगा और इसके मेक इन इंडिया कौशल को दर्शाएगा। नॉर्वे में नॉर-शिपिंग 2025 कार्यक्रम में भाग लेने वाले केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने भारत के महासागर विज्ञान को भी बढ़ावा दिया, टिकाऊ समुद्री निवेश को प्रोत्साहित किया और जहाज निर्माण और हरित रसद में अवसरों पर प्रकाश डाला। यह विकास भारत के समुद्री परिवर्तन और वैश्विक सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- भारतीय वायु सेना के अधिकारी शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले 634वें अंतरिक्ष यात्री बन गए, जो भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। एक्सिओम-4 मिशन के तहत, उन्होंने 26 जून, 2025 को यूएसए, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ आईएसएस में सफलतापूर्वक डॉक किया। 14 दिवसीय मिशन वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानव अंतरिक्ष उड़ान में भारत के बढ़ते योगदान को प्रदर्शित करने पर केंद्रित होगा।

राष्ट्रीय

- आगामी ऐक्सिओम मिशन-4 (Axiom-4) केवल एक और अंतरिक्ष उड़ान नहीं है—यह भारत सहित कई देशों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि का प्रतीक है। इस मिशन में भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ल की भागीदारी भारत के अंतरिक्ष युग में एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। यह मिशन न केवल अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक है, बल्कि वैज्ञानिक नवाचार और मानव अंतरिक्ष उड़ान में व्यावसायिक प्रगति का भी प्रतिनिधित्व करता है।
- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने इसरो (ISRO) से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SSLV) के निर्माण और व्यवसायीकरण (commercialisation) के लिए ₹511 करोड़ का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (ToT) समझौता हासिल किया है। इस घोषणा को IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र) ने सफल निविदा प्रक्रिया के बाद सार्वजनिक किया। यह भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में वाणिज्यिक विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- भारत में कैंसर उपचार अनुसंधान को एक नई दिशा देते हुए, भारतीय वैज्ञानिकों ने गोल्ड नैनो-कप्स के संश्लेषण (synthesis) की एक सरल और नवीन तकनीक विकसित की है, जो फोटोथर्मल थेरेपी (PTT) में अत्यधिक प्रभावशाली साबित हो सकती है। ये विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए PEGylated सेमी-शेल्स गर्मी के माध्यम से कैंसर ट्यूमर को लक्षित कर नष्ट करने में सक्षम हैं, जिससे यह पारंपरिक उपचारों की तुलना में कम दर्दनाक और अधिक प्रभावी विकल्प बनता है। यह नवाचार INST मोहाली, IIT बॉम्बे और ACTREC - टाटा मेमोरियल सेंटर के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है और इसका मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में सर्वाइवल रेट बढ़ाने की दिशा में बड़ा योगदान हो सकता है।





- भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की विशेषता वाले एक्सिओम मिशन 4 (एक्स-4) को एक्सिओम स्पेस द्वारा घोषित 22 जून, 2025 तक पुनर्निर्धारित किया गया है। यह समायोजन नासा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के रूसी खंड में चल रहे रखरखाव के मूल्यांकन के बाद किया गया है। यह मिशन, जिसमें भारत, पोलैंड, हंगरी और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं, ISS के लिए चौथा निजी चालक दल मिशन है और वाणिज्यिक मानव अंतरिक्ष उड़ान में भारत के लिए एक बड़ा कदम है।
- केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने 14 जून, 2025 को चेन्नई में गरुड एयरोस्पेस की कृषि-ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही, मंत्री ने 300 उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) का भी अनावरण किया और डीजीसीए द्वारा अनुमोदित ट्रेन द ट्रेनर (टीटीटी) कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई, जिससे भारत ड्रोन नवाचार, आत्मनिर्भरता और कौशल विकास के मामले में सबसे आगे खड़ा हो गया। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन हब में बदलने के सपने को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- भारत में क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल के तहत, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की स्थापना जनवरी 2026 तक की जाएगी। इसकी घोषणा आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग (ITE&C) के सचिव कटमनेनी भास्कर ने 25 जून 2025 को विजयवाड़ा में आयोजित एक उच्चस्तरीय कार्यशाला के दौरान की।
- पश्चिम गोदावरी (आंध्र प्रदेश) के पालकोल्लु की रहने वाली डांगेटी जाह्नवी ने भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कर लिया है। वे नासा के प्रतिष्ठित "इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम" को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। यह उपलब्धि भारत की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अभियानों में भागीदारी और एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी में बढ़ती क्षमताओं का प्रतीक है।
- गूगल ने भारत में अपने क्रांतिकारी AI मोड की आधिकारिक शुरुआत कर दी है, जो सर्च टेक्नोलॉजी के विकास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। यह नवाचार पारंपरिक कीवर्ड-आधारित खोज के ढांचे से आगे बढ़कर उपयोगकर्ताओं को अधिक स्वाभाविक, संवादात्मक और जटिल जानकारी खोजने की सुविधा प्रदान करता है।
- भारत की क्वांटम क्रांति अमरावती क्वांटम वैली की घोषणा के साथ आकार ले रही है, जो देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग हब है, जिसे जनवरी 2026 तक लॉन्च किया जाना है। आंध्र प्रदेश के ITE&C विभाग की अगुवाई में, इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा, लॉजिस्टिक्स, एग्री-टेक और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। IBM, LTIMindtree और TCS जैसी प्रमुख कंपनियों के सहयोग से और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के साथ जुड़कर, यह परियोजना राष्ट्रीय उत्पादकता और भविष्य के लिए तैयार कौशल को बढ़ावा देने के लिए क्वांटम AI, सुरक्षित संचार (QNu प्रोजेक्ट) और उन्नत कंप्यूटिंग को एकीकृत करेगी।

INTERNATIONAL

- व्हाट्सएप, टेलीग्राम और वीचैट जैसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को टक्कर देने के लिए एक रणनीतिक कदम उठाते हुए, एलन मस्क के एक्स (पूर्व में ट्विटर) ने एक नई मैसेजिंग सेवा, एक्सचैट लॉन्च की है। सुरक्षा

और क्रॉस-प्लेटफॉर्म कार्यक्षमता पर जोर देने के साथ डिज़ाइन किया गया, एक्सचैट का लक्ष्य मैसेजिंग, फ़ाइल शेयरिंग और वीडियो/ऑडियो कॉलिंग को मिलाकर एक ऑल-इन-वन सुपर ऐप के लिए मस्क के विज़न का एक प्रमुख घटक बनना है।

- चीन ने पृथ्वी के निकट स्थित धुद्रग्रह (Asteroid), 2016HO3 से नमूने एकत्र करने और बाद में मुख्य-बेल्ट धूमकेतु का पता लगाने के लिए तियानवेन-2 अंतरग्रहीय मिशन लॉन्च किया है। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन (CNSA) के नेतृत्व में यह महत्वपूर्ण अंतरिक्ष प्रयास, चीन के महत्वाकांक्षी ब्रह्मांडीय एजेंडे में एक साहसिक कदम है, जिसका उद्देश्य सौर मंडल की उत्पत्ति और ग्रहों के विकास के बारे में मानवता की समझ को गहरा करना है।
- एक ऐतिहासिक उपलब्धि में, जापानी ऑटोमोबाइल दिग्गज होंडा (Honda) ने अपनी पहली पुनः प्रयोज्य (Reusable) रॉकेट का सफल लॉन्च और लैंडिंग परीक्षण 17 जून 2025 को किया। यह परीक्षण जापान के होक्काइडो प्रांत के टाइकी टाउन स्थित होंडा के लॉन्च केंद्र (जिसे "स्पेस टाउन" भी कहा जाता है) पर हुआ। यह परीक्षण होंडा की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आधिकारिक एंट्री को चिह्नित करता है और यह कंपनी को SpaceX और Blue Origin जैसी कंपनियों के साथ उसी लीग में ला खड़ा करता है।
- चीन के युन्नान प्रांत में वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों की किडनी में दो नए हेनिपा वायरस की पहचान की है, जो इंसानों में जानलेवा निपाह और हेंड्रा वायरस जैसे लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं। ये वायरस मस्तिष्क में सूजन (एन्सेफलाइटिस) और गंभीर श्वसन संक्रमण का कारण बन सकते हैं। चूंकि ये वायरस किडनी में पाए गए हैं - जो मूत्र उत्पादन का अंग है - विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि चमगादड़ों के मूत्र से दूषित फल या पानी के माध्यम से ये इंसानों तक पहुंच सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां चमगादड़ इंसानों के निवास के पास रहते हैं।

साइंस एंड टेक्नोलॉजी: मई 2025

उपग्रह प्रक्षेपण

- अमेज़न ने अपने महत्वाकांक्षी \$10 बिलियन के प्रोजेक्ट क्यूपर की शुरुआत करते हुए 27 सैटेलाइट्स के पहले बैच को लॉन्च कर दिया है। इस परियोजना का उद्देश्य विश्वभर में, खासकर दूरदराज़ और ग्रामीण क्षेत्रों में, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। यह लॉन्च अमेज़न की ओर से स्पेसएक्स के स्टारलिनक को चुनौती देने की दिशा में पहला कदम है, जिसके अब तक 8,000 से अधिक सैटेलाइट्स कक्षा में हैं और जिसके दुनियाभर में लाखों उपयोगकर्ता हैं।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 24 अप्रैल, 2025 को तमिलनाडु के महेन्द्रगिरी स्थित ISRO प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स (IPRC) में अपने सेमीक्रायोजेनिक इंजन का शॉर्ट-ड्यूरेशन हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने अपने प्रोपल्शन प्रौद्योगिकी में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जब उसने महेन्द्रगिरी, तमिलनाडु स्थित ISRO प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स (IPRC) में अपने सेमीक्रायोजेनिक इंजन का शॉर्ट-ड्यूरेशन हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक किया। यह परीक्षण 24 अप्रैल, 2025 को किया गया और मार्च 2025 में सफल पहले हॉट टेस्ट के बाद यह दूसरा मील का पत्थर है। नवीनतम इग्निशन टेस्ट इंजन प्रणालियों और अनुक्रमों को सत्यापित करता है, जो भविष्य में होने वाले लॉन्च वाहन अभियानों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।





- भारत और जापान का चंद्रयान-5 (जिसे LUPEX भी कहा जाता है) मिशन डिजाइन चरण में आगे बढ़ रहा है, जिसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और पानी-बर्फ का पता लगाना है। जापान के H3 रॉकेट पर 2027-28 में लॉन्च होने वाला 6.5 टन का लैंडर और 350 किलोग्राम का रोवर सात उपकरणों (ISRO, JAXA, ESA और NASA से) से लैस होकर इन-सीटू वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। यह परियोजना वैश्विक सहयोग का एक मजबूत प्रतीक है और भारत के सफल चंद्रयान-3 मिशन के बाद शुरू की गई है।

राष्ट्रीय

- भारत का महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान अब अपने अंतिम विकास चरण में पहुँच गया है, और इसका पहला मानवयुक्त अभियान 2027 की शुरुआत में प्रक्षेपित किया जाएगा। यह मिशन भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतीक है, जो उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। साथ ही, यह भारत को एक वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में और अधिक सशक्त बनाता है।
- भारत 2026 में निर्धारित अपने पहले मानवयुक्त गहरे महासागर मिशन, 'समुद्रयान' के प्रक्षेपण के साथ समुद्री अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाने के लिए तैयार है। स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी वाहन, मत्स्य 6000 का उपयोग करते हुए, इस मिशन का उद्देश्य 6,000 मीटर तक की समुद्री गहराई का अन्वेषण करना है, जिससे समुद्री जैव विविधता और संसाधन क्षमता के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिल सके।
- भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई BioE3 (Biotechnology for Economy, Environment & Employment) नीति के तहत एक ऐतिहासिक पहल की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि भारत पहली बार अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर जैविक प्रयोग करेगा, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में मानव जीवन की स्थायित्व का अध्ययन करना है। यह प्रयोग AXIOM-4 मिशन के तहत किया जाएगा, जिसमें भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी चालक दल के सदस्य होंगे।
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 (11 मई) के अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), भारत सरकार ने सीमेंट क्षेत्र के लिए देश का पहला कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन (CCU) टेस्टबेड क्लस्टर लॉन्च किया। यह पहल Public-Private Partnership (PPP) मॉडल पर आधारित है और नेट जीरो 2070 लक्ष्य की दिशा में भारत का एक बड़ा कदम है।
- भारत की अंतरिक्ष निगरानी क्षमताओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने एक रणनीतिक साझेदारी की है। इस समझौते को औपचारिक रूप से एक समझौता ज्ञापन (MoU) के माध्यम से अंतिम रूप दिया गया, जिसे आर्यभट्ट प्रेक्षणीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान (ARIES), नैनीताल और इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (IRDE), देहरादून के बीच हस्ताक्षरित किया गया।

- एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि में, मुख्यतः चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज़ के शोधकर्ताओं ने एशियाई खेती योग्य धान (Oryza sativa L.) का पहला पैनजीनोम (Pangenome) तैयार किया है। 144 प्रकार की धान की किस्मों—जंगली और खेती योग्य—के जीनोम को अनुक्रमित (sequence) करके, इस शोध ने एक व्यापक आनुवंशिक मानचित्र प्रदान किया है, जो धान की नस्लों को जलवायु-संवेदनशील, अधिक उपज देने वाली और रोग प्रतिरोधी बनाने में क्रांतिकारी भूमिका निभा सकता है। यह खोज वैश्विक खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित फसलों की विफलता से लड़ने में एक मील का पत्थर है।
- बेंगलुरु स्थित एआई स्टार्टअप Sarvam AI ने अपना नवीनतम टेक्स्ट-टू-स्पीच (TTS) मॉडल 'Bulbul-v2' लॉन्च किया है, जिसे विशेष रूप से भारत की विविध भाषाई पहचान को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। यह मॉडल 11 भारतीय भाषाओं में प्राकृतिक, मानवीय जैसी आवाज़ें और प्रामाणिक क्षेत्रीय उच्चारण प्रदान करता है, जिससे यह बिज़नेस, ब्रांड और डेवलपर्स के लिए एक प्रभावशाली उपकरण बनता है जो भारतीय दर्शकों के लिए अनुकूल आवाज़ों की तलाश में हैं।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने मिशन LiFE (Lifestyle for Environment) के अंतर्गत शुरू की गई नागरिक-केंद्रित पहल 'Ideas4LiFE' के तहत 21 विजेता विचारों की घोषणा की है। यह घोषणा 22 मई 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा की गई। इस पहल का उद्देश्य समुदाय-आधारित समाधान को प्रोत्साहित करना और संसाधनों के "सोच-समझकर और उद्देश्यपूर्ण उपयोग" की प्रधानमंत्री की सोच को साकार करना है।
- अरुणाचल प्रदेश के लेपराडा जिले में यूथालिया मलक्काना (Euthalia malaccana) की पुष्टि के साथ भारत के तितली परिवार में एक उल्लेखनीय नया सदस्य जुड़ गया है। पहले इसे एक उप-प्रजाति या दक्षिण-पूर्व एशिया तक सीमित माना जाता था, लेकिन भारत में इस तितली प्रजाति की निश्चित उपस्थिति इंडो-ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में यूथालिया मलक्काना की ज्ञात सीमा का विस्तार करती है। व्यापक फील्डवर्क और फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण के माध्यम से सत्यापित यह खोज पूर्वोत्तर क्षेत्र के जैव विविधता रिकॉर्ड को समृद्ध करती है और वन्यजीव अनुसंधान में नागरिक विज्ञान के महत्व को उजागर करती है।
- जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेज़ी से उद्योगों, अर्थव्यवस्थाओं और वैश्विक शक्ति संतुलनों को पुनर्परिभाषित कर रहा है, वैसे-वैसे Google और Baidu के बीच प्रतिस्पर्धा अमेरिका और चीन के बीच एक बड़े तकनीकी दौड़ का प्रतीक बन गई है। ये दोनों टेक दिग्गज न केवल अपने-अपने क्षेत्रों में सर्च इंजन के नेता हैं, बल्कि AI क्रांति में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जहाँ वे अत्याधुनिक AI तकनीकों के अनुसंधान, विकास और कार्यान्वयन में भारी निवेश कर रहे हैं।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को 18 मई 2025 को एक झटका लगा जब उसका भरोसेमंद रॉकेट पीएसएलवी-सी61 मिशन असफल हो गया। इस मिशन का उद्देश्य उन्नत पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट ईओएस-09 को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करना था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण सैटेलाइट अपनी तय कक्षा में नहीं पहुँच सका। प्रारंभिक विश्लेषण के अनुसार, इसके तीसरे चरण के प्रणोदन प्रणाली में फ्लेक्स नोजल की खराबी का संदेह है।





- OpenAI ने Codex नामक एक शक्तिशाली नया क्लाउड-आधारित AI कोडिंग एजेंट लॉन्च किया है, जो एक साथ कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कार्यों को स्वतः और समानांतर रूप से संभालने में सक्षम है। यह टूल नए फीचर्स लिखने, टेस्ट चलाने, बग्स ठीक करने और पुल रिक्वेस्ट तैयार करने जैसे कार्य कर सकता है। Codex, डेवलपर के कोडबेस को संदर्भ के रूप में लेकर एक सुरक्षित सैंडबॉक्स वातावरण में काम करता है, जिससे डेवलपर की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।
- एक बड़ी सफलता में, GRAIL (ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी) मिशन के डेटा पर आधारित एक नए नासा अध्ययन ने आखिरकार दशकों पुराने रहस्य को सुलझा दिया है कि चंद्रमा का निकटवर्ती भाग उसके दूरवर्ती भाग से नाटकीय रूप से अलग क्यों दिखता है। निष्कर्ष चंद्रमा की आंतरिक संरचना, ज्वालामुखी इतिहास और तापीय विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।
- जब वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों की तुलना होती है, तो ISRO (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) और NASA (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) को अक्सर आमने-सामने रखा जाता है। हालांकि दोनों एजेंसियां वैज्ञानिक उत्कृष्टता और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उनके बजट, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं में बड़ा अंतर है।

INTERNATIONAL

- वैज्ञानिकों ने उन्नत हार्डफाई अनुक्रमण का उपयोग करके 144 किस्मों का विश्लेषण करके एशियाई चावल का पहला पैनजीनोम बनाया है। यह नया जीनोम मानचित्र एक व्यापक आनुवंशिक आधार प्रदान करता है, जिससे शोधकर्ताओं को सूखा प्रतिरोध, रोग सहिष्णुता और जलवायु लचीलापन जैसे गुणों के साथ बेहतर चावल की किस्मों को डिजाइन करने में मदद मिलती है। अध्ययन में Or-IIIa जंगली चावल में चावल की विकासवादी जड़ों पर प्रकाश डाला गया है, जो विशेष रूप से भारत जैसे कमजोर क्षेत्रों में फसल अनुकूलन, पैदावार और खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए मार्ग प्रदान करता है।
- फेसएज, 58,000 से ज्यादा पोर्ट्रेट पर प्रशिक्षित एक नया AI टूल है, जो सेल्फी का उपयोग करके किसी व्यक्ति की जैविक आयु का अनुमान लगाता है। इसने कैंसर से बचने की भविष्यवाणियों को बेहतर बनाने और शारीरिक कमजोरी की पहचान करके डॉक्टरों को उपचार की तीव्रता के बारे में मार्गदर्शन करने की क्षमता दिखाई है। दलैंसेट डिजिटल हेल्थ में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि कैंसर के मरीज अपनी वास्तविक उम्र से जैविक रूप से ज्यादा उम्र के दिखाई देते हैं, जो सीधे तौर पर खराब परिणामों से जुड़ा है। व्यक्तिगत देखभाल का वादा करते हुए, एल्गोरिदम संभावित पूर्वाग्रह, दुरुपयोग और किसी की जैविक उम्र जानने के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में नैतिक प्रश्न भी उठाता है।
- असम में एआई एंकर अंकिता की शुरुआत डिजिटल गवर्नेंस और मीडिया में एआई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा अनावरण किए जाने पर, अंकिता ने असमिया में कैबिनेट की मुख्य बातें प्रस्तुत कीं, जिसमें डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलना और चाय बागान श्रमिकों के लिए समय अनुदान शामिल है। यह पहल तकनीकी नवाचार को प्रदर्शित करती है, लेकिन यह पारंपरिक मीडिया भूमिकाओं में रोजगार विस्थापन के बारे में चिंता भी जगाती है।

- 22 मई, 2025 को, MoEFCC ने अपने 'आइडियाज़4लाइफ' पहल के तहत 21 विजेता विचारों की घोषणा की, जो मिशन लाइफ के तहत विकसित एक नागरिक-संचालित कार्यक्रम है। यूनिसेफ युवाह के साथ साझेदारी में, मंत्रालय ने ऊर्जा, जल संरक्षण, प्लास्टिक में कमी और स्वस्थ जीवन शैली सहित सात स्थिरता विषयों पर केंद्रित विचारों का चयन किया। इस पहल में 1384 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं और सतत जीवन और जलवायु कार्रवाई के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप अभिनव, व्यवहार्य और स्केलेबल समाधानों की पहचान करने के लिए एक कठोर तीन-चरणीय चयन प्रक्रिया के माध्यम से इसका मूल्यांकन किया गया।
- प्रोजेक्ट स्टारलाइन का नवीनतम विकास, Google Beam, AI-संचालित 3D वीडियो और लाइट-फील्ड डिस्प्ले का उपयोग करके दूरस्थ संचार में क्रांति लाने के लिए तैयार है। यह एक यथार्थवादी, आयामी वीडियो अनुभव प्रदान करता है जो उपयोगकर्ताओं को भावनाओं और अभिव्यक्तियों को पढ़ने में सक्षम बनाता है जैसे कि वे व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हों। बिल्ट-इन स्पीच ट्रांसलेशन और ज़ूम, एचपी और डेलोइट जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी के साथ, Google Beam से दुनिया भर में उद्यम संचार और क्रॉस-सांस्कृतिक सहयोग को नया रूप देने की उम्मीद है।
- भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट और योटा डेटा सर्विसेज ने देश भर में एआई अपनाने का समर्थन करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। यह सहयोग माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की एआई सेवाओं को योटा के शक्ति क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करेगा, जिसका उद्देश्य घरेलू एआई क्षमताओं और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

साइंस एंड टेक्नोलॉजी: अप्रैल 2025

राष्ट्रीय

- बहुप्रतीक्षित NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) उपग्रह मिशन, जो भारत की इसरो और अमेरिका की नासा के बीच एक अनोखी सहयोगात्मक परियोजना है, अब जून 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद है। यह उपलब्धि कई बार की देरी के बाद सामने आई है, विशेष रूप से असेंबली और परीक्षण चरणों के दौरान। इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को आगामी अंतरिक्ष अभियानों की जानकारी दी, जिसमें NISAR और मई महीने में प्रस्तावित अन्य प्रमुख मिशन शामिल हैं।
- सी-डॉट ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एसटीएल) के साथ मिलकर 4-कोर मल्टी-कोर फाइबर (एमसीएफ) पर भारत के पहले क्यूकेडी ट्रांसमिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह क्वांटम-सुरक्षित संचार नेटवर्क की दिशा में देश की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मल्टी-कोर फाइबर (एमसीएफ) तकनीक एक ही फाइबर के भीतर कई कोर में डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम करके शक्तिशाली समाधान प्रदान करती है। इससे भौतिक स्थान और बुनियादी ढांचे की लागत में काफी बचत होती है। क्यूकेडी के लिए आमतौर पर क्वांटम चैनल के लिए एक समर्पित डार्क फाइबर की आवश्यकता होती है।





- आंध्र प्रदेश के अमरावती में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव शुरू करके भारत अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण छलांग लगा रहा है। रीयल-टाइम गवर्नेंस सोसाइटी (RTGS) की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में IBM, TCS और L&T जैसी अग्रणी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने इस प्रगतिशील परियोजना के रोडमैप को आकार देने के लिए भाग लिया। यह प्रस्तावित सुविधा क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान, नवाचार और पारिस्थितिकी तंत्र विकास के लिए एक विश्वस्तरीय केंद्र बनने का लक्ष्य रखती है, जो उन्नत संगणन तकनीकों में भारत की वैश्विक नेतृत्व की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
- बढ़ते साइबर अपराधों के खतरे के बीच, आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन ने 1 अप्रैल 2025 को साइबर कमांडोज के पहले बैच का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। इस विशेष पहल का उद्देश्य पूरे भारत में कानून प्रवर्तन अधिकारियों को उन्नत साइबर सुरक्षा तकनीकों से लैस करना है, ताकि वे तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल खतरों से प्रभावी रूप से निपट सकें।
- मेटा (Meta), जिसके सीईओ मार्क ज़ुकरबर्ग हैं, ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए एलएलएएमए-4 (Llama-4) नामक अगली पीढ़ी के बड़े भाषा मॉडल सूट को लॉन्च किया है। यह घोषणा 6 अप्रैल 2025 को की गई। इस सूट में तीन शक्तिशाली एआई मॉडल शामिल हैं – स्काउट (Scout), मैवरिक (Maverick), और बेहेमोथ (Behemoth) – जिन्हें मल्टीमॉडल क्षमताओं और तार्किक सोच के विभिन्न स्तरों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है।
- भारत का पहला “एजेंटिक एआई हैकाथॉन”, जिसे Techvantage.ai ने CrewAI के सहयोग से आयोजित किया, देश के एआई क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। यह आयोजन “एजेंटिक एआई वीक” के दौरान हुआ और इसमें देशभर से 1,500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जो स्वायत्त एआई प्रणालियों के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाता है। ये एआई एजेंट जटिल व्यावसायिक चुनौतियों को हल करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, और यह हैकाथॉन इस तेजी से उभरते क्षेत्र में नवाचार का एक मंच बना। यह एक महीने तक चलने वाली पहल थी, जिसमें कई शहरों में गतिविधियाँ हुईं और इसका भव्य समापन केरल के टेक्नोपार्क में हुआ।
- भारत ने अपने पहले स्वदेशी रूप से विकसित उपग्रह “आर्यभट” की स्वर्ण जयंती मनाई, जिसे 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री आर्यभट के नाम पर रखे गए इस उपग्रह ने भारत की वैज्ञानिक यात्रा में ऐतिहासिक छलांग का प्रतीक बनते हुए, इसरो (ISRO) को एक वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में उभरने की राह दिखाई। शीत युद्ध काल के दौरान तकनीकी संसाधनों और अवसंरचनात्मक सीमाओं के बावजूद, आर्यभट की सफलता ने भारत के भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की नींव रखी और आज भी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है।

अंतरराष्ट्रीय

- बांग्लादेश ने 8 अप्रैल 2025 को आर्टेमिस समझौते (Artemis Accords) पर हस्ताक्षर कर अंतरिक्ष अन्वेषण में अपनी प्रतिबद्धता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकट किया। इस ऐतिहासिक कदम के साथ बांग्लादेश इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया। यह कार्यक्रम ढाका में आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा सचिव अशरफ

उद्दीन ने बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व किया। वहीं, NASA की कार्यवाहक प्रशासक जेनेट पेट्रो ने बांग्लादेश के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे अंतरिक्ष सहयोग के नए युग की शुरुआत बताया।

- डालस स्थित बायोटेक कंपनी कोलॉसल बायोसाइंसेज़ ने पहली बार एक विलुप्त प्रजाति को फिर से जीवित करने में सफलता प्राप्त की है — डायर वुल्फ (Dire Wolf), जो लगभग 12,500 साल पहले विलुप्त हो गई थी। आधुनिक डीएनए तकनीक और CRISPR जैसी जीन-संपादन तकनीकों का उपयोग करते हुए, कंपनी ने तीन डायर वुल्फ पिल्लों को जन्म दिया है। यह उपलब्धि “डी-एक्सटिंक्शन” (विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करने) के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। कोलॉसल बायोसाइंसेज़ का उद्देश्य केवल विलुप्त जीवों को लौटाना नहीं है, बल्कि जैव-विविधता के संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन को बहाल करने में भी योगदान देना है।
- सी-डॉट ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एसटीएल) के साथ मिलकर 4-कोर मल्टी-कोर फाइबर (एमसीएफ) पर भारत के पहले क्यूकेडी ट्रांसमिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह क्वांटम-सुरक्षित संचार नेटवर्क की दिशा में देश की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मल्टी-कोर फाइबर (एमसीएफ) तकनीक एक ही फाइबर के भीतर कई कोर में डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम करके शक्तिशाली समाधान प्रदान करती है। इससे भौतिक स्थान और बुनियादी ढांचे की लागत में काफी बचत होती है। क्यूकेडी के लिए आमतौर पर क्वांटम चैनल के लिए एक समर्पित डार्क फाइबर की आवश्यकता होती है।
- ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट ने 14 अप्रैल 2025 को एक ऐतिहासिक सबऑर्बिटल अंतरिक्ष उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसमें केवल महिलाएं सवार थीं — यह 1963 के बाद पहली बार हुआ जब वलेन्टीना तेरेश्कोवा ने पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में उड़ान भरी थी। यह प्रक्षेपण टेक्सास के वैन हॉर्न से हुआ और इसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी छह प्रमुख महिलाओं ने हिस्सा लिया। लगभग 10 मिनट की यह उड़ान व्यावसायिक अंतरिक्ष यात्रा, एयरोस्पेस में लैंगिक प्रतिनिधित्व और पाँप कल्चर के माध्यम से वैज्ञानिक जागरूकता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई।
- बहुप्रतीक्षित NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) उपग्रह मिशन, जो भारत की इसरो और अमेरिका की नासा के बीच एक अनोखी सहयोगात्मक परियोजना है, अब जून 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद है। यह उपलब्धि कई बार की देरी के बाद सामने आई है, विशेष रूप से असेंबली और परीक्षण चरणों के दौरान। इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को आगामी अंतरिक्ष अभियानों की जानकारी दी, जिसमें NISAR और मई महीने में प्रस्तावित अन्य प्रमुख मिशन शामिल हैं।
- नासा (NASA) क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पाथफाइंडर (Quantum Gravity Gradiometer Pathfinder – QGGPF) के विकास का नेतृत्व कर रहा है। यह एक कॉम्पैक्ट और अत्यधिक संवेदनशील क्वांटम सेंसर है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को अभूतपूर्व सटीकता के साथ मानचित्रित करने का वादा करता है। यह नई तकनीक पृथ्वी की सतह और उपसतह को समझने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है, जिससे जलवायु विज्ञान, संसाधन खोज, नेविगेशन और ग्रहों के अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में नए आयाम खुलेंगे।





योजनाएं/ऐप्स/पोर्टल

राष्ट्रीय योजनाएँ/ऐप्स: अगस्त 2025

केंद्रीय सरकार की योजनाएँ

पहल / योजना का नाम	मंत्रालय	वर्ष	उद्देश्य / मुख्य बिंदु
प्रधानमंत्री इंटरनेट योजना (PMIS)	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	2023	युवाओं को जिलों की विभिन्न कंपनियों में इंटरनेट अवसर प्रदान करना; रोजगार योग्यता और समावेशिता बढ़ाना। दूसरे चरण में महिला भागीदारी 31% से बढ़कर 41% हुई।
मिशन पोषण 2.0	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2021	पोषण अभियान और आईसीडीएस को मिलाकर गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के पोषण में सुधार। 300 दिन तक "टेक-होम राशन (THR)" उपलब्ध।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2017	गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को मातृत्व लाभ प्रदान करना, ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम हो। जुलाई 2025 तक 4.05 करोड़ से अधिक लाभार्थी।
मेरीट योजना (MERITE Scheme)	शिक्षा मंत्रालय	2025	तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और रोजगार योग्यता में सुधार; शोध, नवाचार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के लक्ष्यों को बढ़ावा।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	2025	वर्ष 2027 तक 3.5 करोड़ नौकरियाँ सृजित करना; प्रथम बार नियुक्त कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन।
पीएम ई-ड्राइव योजना	भारी उद्योग मंत्रालय	2028 तक बढ़ाई गई	इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, चार्जिंग अवसंरचना का समर्थन, और बाजार परिपक्व होने पर सब्सिडी घटाना।
स्टैंड-अप इंडिया योजना	वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग)	2016	एससी/एसटी व महिला उद्यमियों को ग्रीनफील्ड उद्यमों (व्यापार, विनिर्माण, सेवा व संबद्ध कृषि क्षेत्रों) हेतु ऋण प्रदान करना
संशोधित व्याज अनुदान योजना (MISS)	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	चालू	लघु अवधि फसल ऋण पर व्याज अनुदान; 2024-25 में ₹17,811.72 करोड़ वितरित
फोर्टिफाइड राइस योजना (2028 तक विस्तार)	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	2021 (PM POSHAN के तहत देशव्यापी लागू)	कुपोषण व एनीमिया से लड़ना; विद्यालय भोजन में फोर्टिफाइड चावल, डबल फोर्टिफाइड नमक व फोर्टिफाइड खाद्य तेल उपलब्ध; एनडीडीवी के "गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम" से सहयोग
SASCI – राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता (पर्यटन परियोजनाएँ)	पर्यटन मंत्रालय	2025	₹3,295.76 करोड़ से 40 परियोजनाएँ स्वीकृत; 100% केंद्रीय वित्त पोषण; कम प्रसिद्ध स्थलों का विकास, उत्तरदायी पर्यटन, स्थिरता व स्थानीय विकास पर जोर
पीयर-टू-पीयर (P2P) लेंडिंग विनियम	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	2017	RBI विनियमित डिजिटल लेंडिंग प्रणाली; निष्पक्ष व्यवहार, पारदर्शिता और उधारकर्ता संरक्षण सुनिश्चित करना
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi)	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)	2020 (2030 तक विस्तार)	31 मार्च 2030 तक पुनर्गठन व विस्तार; ₹7,332 करोड़ व्यय; ऋण सीमा ₹15k, ₹25k, ₹50k; UPI-लिंकड रूपे क्रेडिट कार्ड, कैशबैक प्रोत्साहन; शहरी व उपनगरीय क्षेत्रों में विस्तार; 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लक्षित
प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY)	वित्त मंत्रालय	2014	11वीं वर्षगांठ (28 अगस्त 2025); विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना; 56.2 करोड़ खाते, ₹2.68 लाख करोड़ जमा, 56% खाते महिलाओं के नाम, 38.7 करोड़ रूपे कार्ड जारी; DBT, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मज़बूती और वित्तीय बहिष्करण में कमी

राज्य सरकार की योजनाएँ

पहल / योजना का नाम	राज्य	वर्ष	उद्देश्य / मुख्य बिंदु
मुख्यमंत्री निजुत मोड़ना 2.0	असम	2025	सरकारी/सहायता प्राप्त संस्थानों में एच.एस. (हायर सेकेंडरी) से लेकर पीजी स्तर तक की छात्राओं को मासिक वित्तीय सहायता। उद्देश्य: स्कूल-छोड़ दर (Dropout Rate) कम करना और महिला शिक्षा को सशक्त बनाना। अनुमानित लाभार्थी: 4 लाख+ छात्राएँ।





पहल / योजना का नाम	राज्य	वर्ष	उद्देश्य / मुख्य बिंदु
श्रमश्री योजना	पश्चिम बंगाल सरकार (श्रम विभाग)	2025	राज्य में वापस लौटने वाले बंगाली प्रवासी श्रमिकों का पुनर्वास; 1 वर्ष (या रोजगार मिलने तक) के लिए 5,000 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा, साथ ही कौशल प्रशिक्षण, जॉब कार्ड और स्वरोजगार के लिए ऋण भी प्रदान किया जाएगा।

राष्ट्रीय योजनाएँ/ऐप्स: जुलाई 2025

केंद्र सरकार की योजनाएँ

पहल का नाम	मंत्रालय	वर्ष	उद्देश्य (विस्तृत विवरण)
SPREE 2025	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (ESIC)	2025	नियोक्ताओं और कर्मचारियों को ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करता है, बिना निरीक्षण के डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से। पिछली अवधि के जुर्माने का डर हटाकर असंगठित श्रमिकों को ईएसआई लाभों से जोड़ने का प्रयास।
एमनेस्टी योजना - 2025	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (ESIC)	2025	ईएसआईसी अनुपालन से संबंधित लंबित कानूनी विवादों को हल करने हेतु। स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना, मुकदमों में कमी लाना और सामाजिक सुरक्षा प्रवर्तन में सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना।
ईएसआईसी के साथ आयुष एकीकरण	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (ESIC)	2025	आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी जैसी आयुष प्रणालियों को ईएसआईसी अस्पतालों में सम्मिलित कर समग्र स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना। धर्मार्थ अस्पतालों के साथ साझेदारी।
लघु बचत ब्याज नीति	वित्त मंत्रालय	2025	पीपीएफ, एनएससी, सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं में ब्याज दर स्थिर रखकर सार्वजनिक विश्वास बनाए रखना और आर्थिक अनिश्चितता के बीच घरेलू बचत को समर्थन देना।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	कृषि मंत्रालय	—	10 वर्षों की समीक्षा में गैर-ऋणी किसानों को शामिल करने में प्रगति दिखी है। आगे की सिफारिशें: केन्द्रीय हिस्सेदारी में वृद्धि, राष्ट्रीय मॉडल, तृतीय पक्ष मूल्यांकन।
पीएम ई-ड्राइव पहल	—	—	पहली इलेक्ट्रिक ट्रक योजना, प्रत्येक वाहन पर ₹9.6 लाख तक की प्रोत्साहन राशि। N2/N3 श्रेणी के 5,600 ट्रकों को लक्ष्य बनाना। पुराने डीजल ट्रकों की स्कैपिंग अनिवार्य। आत्मनिर्भर भारत और नेट-ज़ीरो लक्ष्यों में सहायक।
रोजगार-लिंक प्रोत्साहन योजना	—	2025	₹1 लाख करोड़ की योजना, 3.5 करोड़ नौकरियाँ (1.92 करोड़ प्रथम बार काम करने वाले)। प्रति कर्मचारी ₹3,000/माह और नए कर्मचारियों को ₹15,000 तक वेतन सहायता।
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY)	—	2025	₹24,000 करोड़/वर्ष की 6 वर्षीय योजना, 100 पिछड़े जिलों में कृषि उन्नयन। 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं का समन्वय। 1.7 करोड़ किसानों को लाभ।
अदिति योजना (ADEETIE)	ऊर्जा मंत्रालय (BEE)	—	₹1,000 करोड़ की योजना, एमएसएमई उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार। 60 क्लस्टर, 14 सेक्टर, 30-50% तक ऊर्जा बचत का लक्ष्य। ब्याज सबवेंशन और तकनीकी ऑडिट।
वीसीएफ निपटान योजना 2025	सेबी (SEBI)	2025	वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए एआईएफ रूपांतरण के दौरान हुई उल्लंघनों का समाधान। 21 जुलाई 2025 से 19 जनवरी 2026 तक लागू। स्वैच्छिक अनुपालन और निवेशक संरक्षण को बढ़ावा।
नई रोजगार योजना	—	2025	पहली बार निजी क्षेत्र में कार्यरत युवाओं को ₹15,000 प्रोत्साहन राशि। पूर्वी राज्यों (जैसे बिहार) में रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान। ₹1 लाख करोड़ का बजट।
बीमा सखी योजना	एलआईसी (LIC)	2024	ग्रामीण महिलाओं को महिला करियर एजेंट के रूप में सशक्त बनाना। पहले 3 वर्षों के लिए ₹7,000-₹5,000 की वजीफा और कमीशन। 2 लाख से अधिक पंजीकरण, ₹520 करोड़ का बजट (2025-26)।
पालना योजना	—	2022	कार्यरत माताओं के लिए डे-केयर/क्रेच सुविधा, 6 माह-6 वर्ष तक के बच्चों हेतु। आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़ाव, पोषण और स्वास्थ्य निगरानी। 17,000 केंद्रों का लक्ष्य, 14,599 स्वीकृत।
स्किल इंडिया मिशन	—	2015-2025	6 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। पीएमकेवीवाई 4.0, पीएम-नैप्स और जेएसएस का एकीकरण। एआई, रोबोटिक्स और हरित ऊर्जा पर विशेष ध्यान। 1.63 करोड़ (पीएमकेवीवाई), 26 लाख (जेएसएस), 43.47 लाख (प्रशिक्षु)।





राज्य सरकार की योजनाएँ

पहल का नाम	राज्य / सरकार	उद्देश्य (विस्तृत विवरण)
पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी-मुक्त गांव योजना	राजस्थान सरकार	4 जुलाई 2025 को शुरू की गई योजना, जो बीपीएल परिवारों को 5,000 गांवों में सहायता देती है। ₹1 लाख तक का रोजगार/व्यवसाय सहायता और स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को ₹15,000 की सहायता। गरीबी से बाहर निकलने वाले परिवारों को ₹21,000 का पुरस्कार और आत्मनिर्भर परिवार कार्ड दिए जाते हैं। गांव-स्तरीय योजनाएं परिवारों को कौशल व रोजगार कार्यक्रमों से जोड़ती हैं।
मुख्यमंत्री सेहत योजना	पंजाब सरकार	8 जुलाई 2025 को शुरू की गई योजना, जो राज्य के हर परिवार को ₹10 लाख तक वार्षिक निःशुल्क और नकदरहित इलाज प्रदान करती है। लगभग 65 लाख परिवारों को कवर करती है, जिनमें किसान, मजदूर, पेंशनभोगी, व्यापारी और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड से सरकारी और निजी अस्पतालों में 2,000+ बीमारियों का इलाज संभव। आयुष्मान भारत लाभार्थियों को ₹5 लाख अतिरिक्त टॉप-अप।
गज मित्र योजना	असम कैबिनेट	11 जुलाई 2025 को मंजूरी मिली योजना जो 80 हाथी-संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में लागू की जाएगी। इसमें हाथी-अनुकूल वनस्पति का रोपण, त्वरित प्रतिक्रिया दल, और सामुदायिक जागरूकता शामिल हैं। मानव और हाथियों की मौत को रोकने का उद्देश्य, जो अक्सर अवैध बाड़बंदी और अतिक्रमण से होती है।
डिजी-लक्ष्मी योजना	आंध्र प्रदेश सरकार	30 जून 2025 को शुरू की गई योजना, जो शहरी गरीब महिलाओं को उद्यमिता में सशक्त बनाती है। शहरी निकायों में 9,034 कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) स्थापित किए गए हैं, जिन्हें SHG महिलाएं चलाती हैं और लगभग 250 सार्वजनिक सेवाएं देती हैं। प्रशिक्षण और ₹2-2.5 लाख का ऋण प्रदान कर "एक परिवार, एक उद्यमी" मिशन को समर्थन।
प्रेरणा आसनी योजना	असम कैबिनेट	कक्षा 10 के छात्रों को ₹300 मासिक सहायता प्रदान करती है, जिससे शिक्षा को प्रोत्साहन मिले। यह ग्रामीण आय, पारंपरिक कामगारों और शिक्षा के समर्थन हेतु व्यापक कल्याण उपायों का हिस्सा है।
ग्रामीण कर्मियों के लिए मासिक वेतन वृद्धि	असम कैबिनेट	गांव प्रधानों का वेतन ₹9,000 से बढ़ाकर ₹14,000 किया गया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ₹8,000 और सहायकों को ₹4,000। यह जमीनी स्तर के कार्यबल के योगदान को मान्यता देने और सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम है।
साधु भत्ता योजना	असम कैबिनेट	सत्रों (Satras) में रहने वाले साधुओं को ₹1,500 मासिक भत्ता प्रदान करती है, जिससे सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाओं को समर्थन मिलता है।
कांसे के कारीगरों के लिए जीएसटी रिफंड योजना	असम कैबिनेट	पारंपरिक कारीगरी को बढ़ावा देने और ग्रामीण शिल्प को समर्थन देने हेतु कांस्य (bell metal) कारीगरों को जीएसटी रिफंड प्रदान करती है।
रवींद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय	असम कैबिनेट	रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रवींद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय किया गया, ताकि सांस्कृतिक विरासत को सम्मान मिल सके।

राष्ट्रीय योजनाएँ/ऐप्स: जून 2025

केंद्रीय सरकार की योजनाएं

पहल का नाम	उद्देश्य
एमजीएनआरईजीएस	- केंद्र ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के लिए MGNREGS व्यय को 60% पर सीमित कर दिया है, जिससे यह योजना पहली बार MEP/QEP ढांचे के अंतर्गत आ गई है। यह कदम ₹21,000 करोड़ की लंबित देनदारियों के बीच उठाया गया है, और इससे योजना की रोजगार सृजन क्षमता प्रभावित हो सकती है। 86,000 करोड़ रुपये के वार्षिक आवंटन और 198.86 करोड़ व्यक्ति दिवस के महत्वाकांक्षी श्रम लक्ष्य के साथ, यह निर्णय मांग-संचालित एमजीएनआरईजीएस के वित्तीय प्रबंधन में एक प्रमुख नीतिगत बदलाव को दर्शाता है। हालांकि इसका उद्देश्य राजकोषीय नियंत्रण है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित रोजगार की कमी के बारे में चिंता बनी हुई है।
जयहिंद योजना	- दिल्ली विश्वविद्यालय ने बुनियादी कंप्यूटर प्रशिक्षण और सीयूईटी तैयारी सहायता प्रदान करके दूरदराज के क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति (एसटी) छात्रों को सशक्त बनाने के लिए जयहिंद योजना शुरू की है। - यह कार्यक्रम स्कूली छात्रों (कक्षा 9-12) को लक्षित करता है और डिजिटल पहुंच की कमी और ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियाओं से अपरिचितता जैसी चुनौतियों का समाधान करता है। - मणिपुर के उखरुल से 25 छात्रों के पहले बैच के साथ, यह पहल डीयू द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है और इसे उच्च शिक्षा में जनजातीय भागीदारी का समर्थन करने के लिए एक वार्षिक कौशल निर्माण कार्यक्रम के रूप में देखा गया है।





पहल का नाम	उद्देश्य
भारतीय रेल	- भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों को बिना किसी बीमा प्रीमियम के ₹1 करोड़ दुर्घटना मुआवज़ा देने की पेशकश करते हुए एक नई कल्याणकारी पहल शुरू की है। - इस योजना के तहत, कर्मचारियों को केवल एसबीआई जैसे किसी एक भागीदार बैंक के साथ वेतन पैकेज खाता बनाए रखने की आवश्यकता है। - इस नीति के तहत लोको पायलट सुशील लाल के परिवार को पहला लाभ मिलने के बाद इस कदम का प्रचार किया गया। - वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, इस योजना को रेलवे यूनियनों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कर्मचारी इस जीवन रक्षक कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए जाएं।
नव्या योजना	- लैंगिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, सरकार ने विकसित भारत@2047 विजन के तहत किशोरियों के लिए एक पायलट कौशल पहल, नव्या शुरू की है। 19 राज्यों के 27 जिलों में शुरू की गई नव्या, न्यूनतम कक्षा 10 की शिक्षा के साथ 16-18 वर्ष की आयु की लड़कियों को गैर-पारंपरिक नौकरी भूमिकाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी। - यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय के बीच पीएमकेवीवाई जैसे ढांचे का उपयोग करते हुए एक सहयोगात्मक प्रयास को दर्शाता है।
SIGHT योजना	- SECI ने भारत के उर्वरक क्षेत्र, जो जीवाश्म-आधारित हाइड्रोजन का एक प्रमुख उपभोक्ता है, को डीकार्बोनाइज करने के लिए SIGHT योजना के तहत 724,000 टन/वर्ष के लिए एक ऐतिहासिक ग्रीन अमोनिया निविदा जारी की है। ₹1,533.4 करोड़ के प्रोत्साहन, दीर्घकालिक अनुबंधों और भुगतान सुरक्षा तंत्र द्वारा समर्थित, यह पहल बाजार में विश्वास और पर्यावरणीय लाभ दोनों प्रदान करती है। - पारंपरिक अमोनिया को ग्रीन हाइड्रोजन-व्युत्पन्न अमोनिया से बदलकर, परियोजना जलवायु लक्ष्यों, आयात निर्भरता और औद्योगिक स्थिरता को संबोधित करती है।
शीर्ष राष्ट्रीय खिलाड़ी वजीफा योजना (टीएनपीएसएस)	- अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (AICF) द्वारा 25 जून, 2025 को शुरू की गई शीर्ष राष्ट्रीय खिलाड़ी वजीफा योजना (TNPSS) भारत में जमीनी स्तर पर शतरंज के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। - अंडर-7 से अंडर-19 श्रेणियों में 78 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों के लिए प्रति तिमाही ₹60,000 से ₹1.5 लाख तक की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के साथ, इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, प्रतिभा को पहचानना और खिलाड़ी विकास में वित्तीय बाधाओं को दूर करना है। - यह पहल लैंगिक समानता और युवा खेलों में निरंतर निवेश को बढ़ावा देते हुए, वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनने की भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षा को रेखांकित करती है।
एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस)	31 मार्च, 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए केंद्रीय सरकार के एनपीएस सेवानिवृत्त (≥10 वर्ष की सेवा) के लिए 30 जून, 2025 तक आवेदन करें - एकमुश्त राशि: सेवा के 6 महीनों के लिए अंतिम मूल + डीए का 1/10वां हिस्सा - टॉप-अप पेंशन: यूपीएस और एनपीएस वार्षिकी के बीच का अंतर - ब्याज: पीपीएफ दर पर बकाया - शुरू: जनवरी 2025, पिछले 12 महीने के मूल वेतन का 50% औसत सुनिश्चित करता है
एसपीएमईपीसीआई (ईवी विनिर्माण योजना)	- EV CBU's पर 15% सीमा शुल्क ≥\$35,000 (CIF) 5 वर्षों के लिए वैध - आयात कोटा: रोलओवर के साथ 8,000 EV/वर्ष - ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड निवेश पात्र - लक्ष्य: घरेलू EV उद्योग, स्वच्छ गतिशीलता को बढ़ावा देना - मंत्री: एच.डी. कुमारस्वामी - टेस्ला: शुरुआत में रुचि है, विनिर्माण में नहीं
कृषि निवेश पोर्टल	14 केंद्रीय और 9 राज्य विभागों में कृषि-योजनाओं को एकीकृत करता है - कवर: 17 प्रमुख योजनाएँ (एआईएफ, एएचआईडीएफ, पीएम-कुसुम, आदि) - केंद्रीकृत पोर्टल: ट्रैकिंग, आवेदन, योजना जानकारी - फोकस: पीपीपी, क्रेडिट-लिंकड, वीसी, स्टार्टअप - लक्ष्य: निजी कृषि-निवेश को बढ़ावा देना, इन्फ्रा और मूल्य श्रृंखलाओं में सुधार करना - वित्त वर्ष 25 आवंटन: ₹1.31 लाख करोड़





पहल का नाम	उद्देश्य
पीएम-वाणी टैरिफ सुधार	- ट्राई ने पीएम-वाणी के तहत पीडीओ के लिए टैरिफ की सीमा तय की - पीएम-वाणी की योजनाएं पहले एफटीटीएच से 2 गुना महंगी थीं - उदाहरण: • 100 एमबीपीएस: ₹1,532.82 (पीएम-वाणी) बनाम ₹706.82 (एफटीटीएच) - ड्राफ्ट ऑर्डर: 70वां संशोधन (अगस्त 2024) - डीओटी संशोधन (सितंबर 2024): आईएसपी के साथ वाणिज्यिक अनुबंधों की कोई आवश्यकता नहीं - उद्देश्य: किफायती, समावेशी सार्वजनिक वाई-फाई
सीईजीएसएससी - एससी क्रेडिट गारंटी योजना	- लॉन्च: 6 मई, 2015 - एजेंसी: IFCI लिमिटेड - SC-स्वामित्व वाली फर्मों/व्यक्तियों के लिए जिनके पास $\geq 51\%$ स्वामित्व है - गारंटी कवर: ₹0.15 - ₹5 करोड़ - अवधि: 7 वर्ष तक - विशेष बैंक सेल और SLBC द्वारा निगरानी

राज्य सरकार की योजनाएँ

राजीव गांधी वन संवर्धन योजना	- हिमाचल प्रदेश ने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से हरियाली बढ़ाने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है। - मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू द्वारा शुरू की गई इस योजना में महिला मंडल, युवक मंडल और एसएचजी को बंजर भूमि पर वन बहाली में शामिल किया गया है। इसके पूरक के रूप में ग्रीन एडॉप्शन स्कीम है, जो बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के लिए अंबुजा, अदानी और अल्ट्राटेक जैसी कॉर्पोरेट कंपनियों को लाती है। - इसके अतिरिक्त, वन विभाग में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए वन मित्रों को शामिल किया गया और इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण और टिकाऊ वन प्रबंधन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया।
पंजाब उद्योग क्रांति	10 जून, 2025 को शुरू की गई पंजाब उद्योग क्रांति भारत में औद्योगिक शासन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। - फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल, 45 दिनों में स्वीकृतियां और रंग-कोडित स्टाम्प पेपर सहित अपने 12 साहसिक सुधारों के साथ, पंजाब का लक्ष्य नौकरशाही की लालफीताशाही को खत्म करना और व्यापार के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देना है। - मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप नेता अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को औद्योगिक नीति सुधार में राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया है, जिससे यह निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन के लिए एक संभावित चुंबक बन गया है।
कर्नाटक सरकार	- युवा निधि योजना के तहत, कर्नाटक सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से यादगीर जिले में 39,132 बेरोजगार युवाओं को ₹11.70 लाख वितरित किए हैं। - स्नातकों को पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद छह महीने की छूट अवधि के बाद दो साल तक ₹3,000/माह और डिप्लोमा धारकों को ₹1,500/माह मिलते हैं। - लाभार्थियों को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सेवा सिंधु पोर्टल पर मासिक रूप से नौकरी की स्थिति की रिपोर्ट करनी चाहिए। - यह पहल युवा सशक्तिकरण, कल्याण और समावेशी शासन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
विद्या शक्ति	25 जून, 2025 को, आंध्र प्रदेश ने 'विद्या शक्ति' नामक एक सुधारात्मक शिक्षण पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में स्कूल के बाद के सत्रों के माध्यम से धीमी गति से सीखने वालों का समर्थन करना है। 4,424 स्कूलों और 576 केजीवीवी में लागू किया गया, तकनीक-सक्षम कार्यक्रम सीखने के अंतराल को पाटने, ड्रॉपआउट को कम करने और नामांकन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिसमें आईआईटी-मद्रास प्रवर्तक द्वारा समर्थित शिक्षक प्रशिक्षण शामिल है। - शिक्षा नेताओं द्वारा समर्थित, 'विद्या शक्ति' राज्य में समावेशी, डिजिटल रूप से संचालित शिक्षा सुधार के लिए एक प्रमुख कदम का संकेत देती है।
उत्तर प्रदेश में अग्निपथ योजना के तहत पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस पद आरक्षित	- सैन्य प्रशिक्षित युवाओं के सम्मान और पुनर्वास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने सीधी पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% श्रेष्ठिज आरक्षण को मंजूरी दे दी है। - घोषणा की गई कि नीति 2026 से लागू की जाएगी, जो अग्निपथ योजना से पहले अग्निवीर बैच की वापसी के साथ संरेखित होगी।





राष्ट्रीय योजनाएँ/ऐप्स: मई 2025

केंद्रीय सरकार की योजनाएँ

पहल का नाम	मंत्रालय	वर्ष	उद्देश्य
राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) उन्नयन योजना	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	2025	1000 आईटीआई का आधुनिकीकरण करना, 20 लाख युवाओं को उद्योग-उन्मुख पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करना; Viksit Bharat 2047 लक्ष्य के अनुरूप कौशल पारिस्थितिकी तैयार करना।
स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS)	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	विस्तार: 2025	स्टार्टअप्स को वित्तीय पहुंच और नवाचार में सहायता; शुरुआती चरण की कंपनियों को गारंटी कवर और शुल्क में छूट के माध्यम से प्रोत्साहित करना।
इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विनिर्माण योजना (ECMS)	इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय	1 मई 2025	पीसीबी, कैमरा मॉड्यूल, लिथियम आयन सेल जैसी उप-इकाइयों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन; इलेक्ट्रॉनिक आयात पर निर्भरता को कम करना।
विकसित कृषि संकल्प अभियान (VKSA)	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	2025	विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से भारतीय कृषि में बदलाव लाना; इसका शुभारंभ पुरी (ओडिशा) और भुवनेश्वर के ICAR-CIFA केंद्र से हुआ।
जन सुरक्षा योजनाएं	वित्त मंत्रालय	9 मई 2015	असंगठित क्षेत्र के गरीब और वंचित वर्गों को सस्ती बीमा और पेंशन लाभ प्रदान करना; तीन योजनाएं: PMJJBY, PMSBY, और APY; अब तक 82 करोड़ लाभार्थी।

राज्य सरकार की योजनाएँ

योजना का नाम	राज्य	प्रारंभ वर्ष	उद्देश्य
ज्योति योजना (Jyothi Scheme)	केरल	मई 2025	प्रवासी बच्चों को आंगनवाड़ी और सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाना; स्वास्थ्य, कल्याण और सामाजिक सहायता प्रदान करना; सांस्कृतिक समावेशन को बढ़ावा देना।
पंडित लाखमी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना	हरियाणा	2025	60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ कलाकारों को ₹10,000 या ₹7,000 मासिक मानधन देना; पारंपरिक कला को संरक्षित करना और सांस्कृतिक योगदान को सम्मान देना।
गुजरात कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	गुजरात	2025	AIS अधिकारियों, राज्य कर्मियों और पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करना; स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को मजबूत करना और आर्थिक बोझ को कम करना।

राष्ट्रीय योजनाएँ/ऐप्स: अप्रैल 2025

केंद्र सरकार की योजना

पहल का नाम	उद्देश्य
मल्टीमॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने का कार्यक्रम (SMILE)	भारत के लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना, लागत को कम करना और दक्षता में वृद्धि करना। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) और पीएम गतिशक्ति का समर्थन करता है तथा मल्टीमॉडल परिवहन, वेयरहाउसिंग मानकीकरण और डिजिटल व्यापार लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देता है।
"एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)" नीति	43 मौजूदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 28 में समेकित कर परिचालन दक्षता बढ़ाना और आपसी प्रतिस्पर्धा को कम करना। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह और सेवा वितरण को बेहतर बनाना है। इस नीति से लागत में कटौती और बैंकिंग ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)	5 अप्रैल 2025 को दिल्ली ने इस योजना को लागू किया, जिससे यह 35वां राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बना। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)	8 अप्रैल 2025 को इस योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह योजना बिना गारंटी के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण प्रदान कर 'वित्त पोषण का लोकतंत्रीकरण' करती है और ग्रामीण भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देती है। अब तक 52 करोड़ ऋण ₹32.61 लाख करोड़ की राशि में स्वीकृत हुए हैं।
सागरमाला कार्यक्रम	मार्च 2015 में शुरू की गई यह योजना भारत के समुद्री क्षेत्र को परिवर्तित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। यह बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, संपर्क बढ़ाना, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, और तटीय तथा अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से लॉजिस्टिक्स लागत को कम कर व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार करना चाहती है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGS)	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के तहत मजदूरी दरों में 2.33% से 7.48% तक की वृद्धि की गई है। यह पहली बार है जब किसी राज्य में मजदूरी ₹400 प्रति दिन तक पहुंची है, जिसमें हरियाणा को सबसे अधिक बढ़ोतरी मिली है।





राज्य सरकार की योजना

पहल का नाम	उद्देश्य
स्वर्ण आंध्र - 2047 विजन	• "शून्य गरीबी - P4 नीति" की शुरुआत उगादी (30 मार्च 2025) को की जाएगी, जिसका उद्देश्य 2047 तक गरीबी को पूरी तरह समाप्त करना है। यह सार्वजनिक-निजी-जन सहभागिता (P4 मॉडल) पर आधारित है और आवास, स्वच्छता, जलापूर्ति, एलपीजी, विश्वसनीय बिजली, हाई-स्पीड इंटरनेट और उद्यमिता पर केंद्रित है।
मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (असम)	• 1 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा शुरू की गई यह योजना महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करती है। पहले वर्ष ₹10,000 की सहायता, दूसरे वर्ष ₹25,000, और तीसरे वर्ष ₹50,000 दी जाएगी। इसका लक्ष्य 30 लाख महिलाओं को सशक्त बनाना है।
स्टैंड-अप इंडिया योजना	• 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई इस योजना ने अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को नए व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। अब तक ₹61,000 करोड़ से अधिक के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिससे आर्थिक समावेशन और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला है।
उत्तर प्रदेश: 'शून्य गरीबी मिशन'	• मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 अप्रैल 2025 को डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर इस मिशन की घोषणा की। इसका उद्देश्य वंचित वर्गों (जैसे मुसहर, थारू, कोल आदि) को सभी सरकारी लाभ प्रदान कर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है।
पिंक ई-रिक्शा पहल (महाराष्ट्र)	• डिप्टी सीएम अजित पवार द्वारा शुरू की गई यह योजना 20-50 वर्ष की महिलाओं (विशेष रूप से विधवा, तलाकशुदा, निम्न-आय वर्ग) को 10,000 इलेक्ट्रिक रिक्शा वितरित करती है। इसमें ₹1 लाख की सब्सिडी और कम ब्याज पर बैंक ऋण उपलब्ध है।
यशस्विनी स्वास्थ्य बीमा योजना (कर्नाटक)	• ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने हेतु इस योजना में जटिल उपचारों के लिए 50% और सामान्य प्रक्रियाओं के लिए 15%-25% दर वृद्धि प्रस्तावित है। 69 नई प्रक्रियाएं जोड़ी जाएंगी और 6 पुरानी हटेंगी। कुल अनुमानित लागत ₹127.5 करोड़ है, जिसमें ₹40 करोड़ अतिरिक्त बजट प्रस्तावित है।

महत्वपूर्ण दिवस

महत्वपूर्ण दिवस: सितम्बर 2025

महत्वपूर्ण दिवस एवं उत्सव (सितंबर 2025)

दिनांक	दिवस / उत्सव	थीम / विवरण
1-7 सितम्बर	राष्ट्रीय पोषण सप्ताह (भारत)	थीम: "बेहतर जीवन के लिए सही भोजन"; संतुलित आहार, सावधान खाने की आदतें और कुपोषण पर ध्यान।
2 सितम्बर	विश्व नारियल दिवस	एशियन पैसिफिक नारियल कम्युनिटी की स्थापना का उत्सव; भारत दुनिया का 3रा सबसे बड़ा नारियल उत्पादक।
3 सितम्बर	स्काईस्क्रेपर डे	लुई एच. सुलिवन की जयंती, "स्काईस्क्रेपर के पिता" एवं फॉर्म फॉलोज़ फंक्शन सिद्धांत को सम्मान।
5 सितम्बर	शिक्षक दिवस (भारत)	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के 2रे राष्ट्रपति, दार्शनिक और शिक्षाविद को सम्मान।
7 सितम्बर	ब्राज़ील स्वतंत्रता दिवस	पुर्तगाल से स्वतंत्रता की 203वीं वर्षगांठ।
7 सितम्बर	दादा-दादी दिवस (यूएस, कनाडा, भारत)	दादा-दादी के प्रेम, ज्ञान और योगदान का उत्सव।
8 सितम्बर	अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस	थीम: "डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा"; डिजिटल विभाजन को पाटने पर ध्यान।
8 सितम्बर	विश्व फिजियोथेरेपी दिवस	थीम: "स्वस्थ उम्र बढ़ना"; बुजुर्गों में कमजोरी रोकने पर जोर।
10 सितम्बर	विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस	थीम: "आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलना"; भारत में Tele-MANAS और DMHP पहल।
11 सितम्बर	राष्ट्रीय वन शहीद दिवस (भारत)	थीम: "शहीदों को याद करना, जंगलों की रक्षा करना"; जैसे खेजरली हत्याकांड की स्मृति।
11 सितम्बर	पैट्रियट डे (यूएसए)	9/11 आतंकवादी हमले के शिकार और प्रथम प्रतिक्रिया देने वालों को सम्मान।
11 सितम्बर	दिविजय दिवस (भारत)	स्वामी विवेकानंद का 1893 शिकागो भाषण, सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा।
13 सितम्बर	विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस	थीम: "प्राथमिक चिकित्सा और जलवायु परिवर्तन"; आपातकालीन तैयारी और जलवायु आपदा प्रतिक्रिया।
15 सितम्बर	इंजीनियर्स डे (भारत)	थीम: "डीप टेक और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता: भारत की टेकडे को आगे बढ़ाना"; सर एम. विश्वेश्वरैया को सम्मानित।
15 सितम्बर	अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस	थीम: "लिंग समानता प्राप्त करना, कदम दर कदम"; समावेशी लोकतांत्रिक शासन पर ध्यान।





दिनांक	दिवस / उत्सव	थीम / विवरण
16 सितम्बर	विश्व ओजोन दिवस	थीम: "विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक"; वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की 40वीं वर्षगांठ।
17 सितम्बर	विश्व रोगी सुरक्षा दिवस	थीम: "हर नवजात और बच्चे के लिए सुरक्षित देखभाल"; बाल स्वास्थ्य और चिकित्सकीय त्रुटियों को कम करना।
17 सितम्बर	विश्वकर्मा पूजा	दिव्य इंजीनियर विश्वकर्मा का सम्मान; कारीगर और श्रमिक अपने औजार और शिल्प कौशल की पूजा करते हैं।
18 सितम्बर	विश्व बांस दिवस	थीम: "अगली पीढ़ी का बांस"; डिज़ाइन, नवाचार और स्थिरता को उजागर करना।
18 सितम्बर	अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस	वैश्विक लिंग वेतन अंतर को संबोधित करने और वेतन समानता को बढ़ावा देना।
19 सितम्बर	अंतर्राष्ट्रीय पैरेंट जैसा बोलो दिवस	दुनिया भर में मज़ेदार और खेल-खिलौने वाले तरीके से समुद्री डाकू बोलचाल की परंपरा का जश्न।
20 सितम्बर	अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस	हिमालयी संकटग्रस्त रेड पांडा (10,000 से भी कम बचे हैं) के संरक्षण पर ध्यान।

महत्वपूर्ण दिवस: अगस्त 2025

तिथि	दिवस / आयोजन	विषय / विवरण
1 अगस्त 2025	विश्व स्तनपान सप्ताह (1-7 अगस्त)	विषय: "स्तनपान को प्राथमिकता दें: सतत सहयोग प्रणाली बनाएं"; दीर्घकालिक सहयोग, सार्वजनिक स्वीकृति और नीतिगत समर्थन पर बल।
1 अगस्त 2025	राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस	बॉबी मैथ्यूज़ और जोश मैडिगन (2015) की उपलब्धि का स्मरण; शारीरिक-मानसिक फिटनेस और पर्वतों के पर्यावरणीय महत्व को बढ़ावा।
1 अगस्त 2025	विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस	जागरूकता, रोकथाम और प्रारंभिक पहचान पर जोर; धूम्रपान, प्रदूषण और अनुवांशिक कारणों से जुड़े जोखिमों की जानकारी।
1 अगस्त 2025	वर्ल्ड वाइड वेब दिवस	विषय: "भविष्य को सशक्त बनाना: समावेशी, सुरक्षित और खुला वेब"; डिजिटल समावेशन, नैतिक एआई और सार्वभौमिक पहुँच पर बल।
3 अगस्त 2025	क्लोव्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस	दुर्लभ रोग CLOVES सिंड्रोम के प्रति जागरूकता; शीघ्र पहचान, उपचार और सामुदायिक सहयोग को प्रोत्साहन।
6 अगस्त 2025	हिरोशिमा दिवस	1945 की परमाणु बमबारी की स्मृति; शांति, अहिंसा और परमाणु निरस्त्रीकरण का संदेश; 'हिबाकुशा' (बचे हुए लोग) का सम्मान।
7 अगस्त 2025	राष्ट्रीय हथकरघा दिवस	विषय: "हथकरघा – सशक्त महिलाएँ, सशक्त राष्ट्र"; भारतीय बुनकरों का उत्सव और 1905 के स्वदेशी आंदोलन की स्मृति; 2015 में आरंभ।
9 अगस्त 2025	विश्व संस्कृत दिवस	प्राचीन संस्कृत भाषा का उत्सव; संरक्षण और युवाओं में शिक्षा को बढ़ावा।
9 अगस्त 2025	नागासाकी दिवस	परमाणु बमबारी की 80वीं वर्षगांठ; शांति, निरस्त्रीकरण और वैश्विक स्मरण का संदेश।
10 अगस्त 2025	विश्व सिंह दिवस	सिंह संरक्षण, आवास हानि और शिकार से जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश।
12 अगस्त 2025	अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस	विषय: "स्थानीय युवा कार्रवाई – एसडीजी और उससे आगे"; युवाओं की भागीदारी पर जोर।
12 अगस्त 2025	विश्व हाथी दिवस	विषय: "दुनिया को हाथियों की मदद के लिए एकजुट करना"; संरक्षण प्रयासों पर बल।
15 अगस्त 2025	स्वतंत्रता दिवस (भारत)	79वाँ उत्सव; स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति और 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की दृष्टि।
19 अगस्त	विश्व मानवीय दिवस	विषय: "वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना"; मानवीय कार्यकर्ताओं और वैश्विक सहायता प्रयासों को सम्मानित करता है।
19 अगस्त	विश्व फोटोग्राफी दिवस	विषय: "माय फ़ेवरेट फ़ोटो"; फोटोग्राफी की कला, इतिहास और प्रभाव का उत्सव; विश्व फोटोग्राफी सप्ताह (12-26 अगस्त) का हिस्सा।
20 अगस्त	विश्व मच्छर दिवस	1897 में सर रोनाल्ड रॉस की खोज (मलेरिया का कारण मादा एनोफिलीज़ मच्छर) की याद; मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ज़िका आदि पर जागरूकता।
21 अगस्त	विश्व उद्यमी दिवस	170+ देशों में मनाया जाता है; नवाचार, रोजगार सृजन और उद्यमियों की दृढ़ता को सम्मान।
21 अगस्त	विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस	विषय: "समावेशी भविष्य के लिए वरिष्ठों की आवाज़ को सशक्त बनाना"; बुजुर्गों की गरिमा, सम्मान और समावेशन को बढ़ावा।
21 अगस्त	आतंकवाद पीड़ितों की स्मृति और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस	विषय: "आशा से एकजुट: आतंकवाद पीड़ितों के लिए सामूहिक कार्रवाई"; एकजुटता और मानवाधिकारों को बढ़ावा।





तिथि	दिवस / आयोजन	विषय / विवरण
22 अगस्त	मद्रास दिवस	1639 में मद्रास (चेन्नई) की स्थापना की स्मृति; विरासत, संस्कृति और नागरिक गौरव का उत्सव।
22 अगस्त	धर्म या आस्था आधारित हिंसा के पीड़ितों की स्मृति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस	UNGA प्रस्ताव A/RES/73/296; धर्म या आस्था के कारण हिंसा झेलने वाले पीड़ितों को सम्मान; धर्म की स्वतंत्रता व शांतिपूर्ण सभा को बढ़ावा।
23 अगस्त	राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस (भारत)	चंद्रयान-3 (2023) की सफल सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति; विषय: "आर्यभट्ट से गगनयान: प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएँ"; भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों व भविष्य मिशनों पर प्रकाश।
26 अगस्त	महिला समानता दिवस	19वाँ संशोधन (1920) से अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार; 1848 के सेनेका फॉल्स सम्मेलन से जुड़ा; 1973 से मान्यता; लैंगिक समानता के संघर्ष को सम्मान।
23 सितम्बर	आयुर्वेद दिवस	धनतेरस से निश्चित तिथि पर स्थानांतरित; विषय: "लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद"; आयुष मंत्रालय द्वारा वैश्विक जागरूकता हेतु।
29-31 अगस्त	राष्ट्रीय खेल दिवस (भारत)	फ्रिट इंडिया मिशन के तहत 3-दिवसीय अभियान; मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि; विषय: "एक घंटा, खेल के मैदान में"; "शांतिपूर्ण व समावेशी समाज हेतु खेल" पर भी प्रकाश।
26 अगस्त	अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस	2004 में कोलीन पेज द्वारा स्थापित; कुत्तों के कल्याण, गोद लेने, और सेवा/सुरक्षा/भावनात्मक सहयोग में योगदान पर जागरूकता; 2013 में न्यूयॉर्क में आधिकारिक मान्यता।
29 अगस्त	परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस	2009 में UN द्वारा स्थापित; कज़ाख़स्तान के सेमीपलाटिंस्क परीक्षण स्थल (1991) के बंद होने की याद; परमाणु परीक्षणों के दुष्प्रभाव व निरस्त्रीकरण पर जागरूकता।
30 अगस्त	जबरन शायब कर दिए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस	मानवाधिकार उल्लंघन को उजागर करने हेतु; सत्य, न्याय और दण्ड से मुक्ति का अंत करने की मांग।
30 अगस्त	राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस (भारत)	पहली बार 2001 में (2000 नीति पैकेज के बाद); आर्थिक विकास, उद्यमिता, ग्रामीण उत्थान और सांस्कृतिक विरासत में SSI के योगदान को सम्मान।

महत्वपूर्ण दिवस: जुलाई 2025

दिनांक	दिवस / अवलोकन का नाम	विषय / विवरण
1 जुलाई 2025	राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस	विषय: "मास्क के पीछे: कौन करता है चिकित्सकों का उपचार?" — डॉक्टरों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक भलाई पर केंद्रित; उनके निःस्वार्थ योगदान का सम्मान।
1 जुलाई 2025	राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस	ICAI की 76वीं वर्षगांठ; लेखा, कराधान और राष्ट्र निर्माण में CAs की भूमिका को मान्यता।
1 जुलाई 2025	जीएसटी दिवस	2017 में लागू GST की वर्षगांठ; अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार और एकरूपता का उत्सव।
1 जुलाई 2025	SBI स्थापना दिवस	भारतीय स्टेट बैंक की 70वीं वर्षगांठ; ₹61 ट्रिलियन की परिसंपत्ति और डिजिटल नेतृत्व को सम्मान।
2 जुलाई 2025	विश्व खेल पत्रकार दिवस	विषय: "न्यायपूर्ण खेल का समर्थन: ईमानदारी और प्रभाव के साथ रिपोर्टिंग" — खेल पत्रकारों की भूमिका का सम्मान।
4 जुलाई 2025	स्वामी विवेकानंद पुण्यतिथि	1902 में निधन; वेदांत, राष्ट्रवाद और सेवा के उनके संदेशों की स्मृति।
5 जुलाई 2025	अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस (CoopsDay)	विषय: "समावेशी और टिकाऊ समाधानों की दिशा में सहकारिता" — सतत विकास लक्ष्यों में सहकारी संस्थाओं की भूमिका।
6 जुलाई 2025	विश्व ग्रामीण विकास दिवस	पहला आयोजन; ग्रामीण समुदायों, महिलाओं, युवाओं और किसानों को सशक्त करने पर ध्यान।
7 जुलाई 2025	विश्व जैव-उत्पाद दिवस	नवीकरणीय स्रोतों से टिकाऊ जैव-उत्पादों को बढ़ावा; भारत की बायो-इंडस्ट्री में भूमिका।
7 जुलाई	विश्व स्वाहिली भाषा दिवस	स्वाहिली को अफ्रीकी एकता की भाषा के रूप में सम्मान; सांस्कृतिक गौरव को प्रोत्साहन।
11 जुलाई 2025	विश्व जनसंख्या दिवस	विषय: "युवा सशक्तिकरण और समानता के साथ वांछित परिवार निर्माण" — प्रजनन अधिकारों और लैंगिक समानता पर ध्यान।
11 जुलाई 2025	विश्व घोड़ा दिवस	पहला आयोजन; कृषि, संस्कृति और चिकित्सा में घोड़ों की भूमिका; कल्याण और संरक्षण पर जोर।
15 जुलाई 2025	विश्व युवा कौशल दिवस	विषय: "कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कौशल द्वारा युवा सशक्तिकरण" — TVET और रोज़गार अवसरों पर फोकस।
15 जुलाई 2025	विश्व सर्प दिवस	सर्प संरक्षण के लिए जागरूकता; सर्प-थीम वाले पोस्टकार्ड और जैव विविधता शिक्षा।





दिनांक	दिवस / अवलोकन का नाम	विषय / विवरण
16 जुलाई 2025	AI प्रशंसा दिवस (भारत)	डिजिटल इंडिया, AI फॉर ऑल, स्किल इंडिया AI पोर्टल जैसी पहलों को उजागर करना।
17 जुलाई 2025	अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस	ICC की स्थापना का स्मरण; मानवाधिकार और न्याय के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता।
18 जुलाई 2025	नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस	विषय: "अब भी हमारे हाथों में है—गरीबी और असमानता से लड़ना" — 67 मिनट की सेवा को प्रेरणा।
20 जुलाई 2025	विश्व शतरंज दिवस	FIDE की स्थापना का स्मरण; बौद्धिक विकास और वैश्विक एकता में शतरंज की भूमिका।
20 जुलाई 2025	अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस	अपोलो 11 लैंडिंग की स्मृति; शांतिपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा।
22 जुलाई 2025	विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस	विषय: "हर उम्र के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य" — जीवनशैली, निद्रा, आहार और मानसिक व्यस्तता पर बल।
22 जुलाई 2025	नाबार्ड स्थापना दिवस (44वां)	ग्रामीण विकास में नाबार्ड की भूमिका; ऋण, डिजिटलीकरण और जलवायु-स्थायित्व पर ध्यान।
22 जुलाई 2025	राष्ट्रीय ध्वज दिवस	तिरंगे की 78वीं वर्षगांठ; देशभक्ति और झंडा संहिता के पालन को प्रोत्साहन।
23 जुलाई 2025	राष्ट्रीय प्रसारण दिवस	भारत में रेडियो इतिहास का स्मरण; स्वतंत्रता संग्राम और आपदा संचार में आकाशवाणी की भूमिका।
24 जुलाई 2025	आयकर दिवस	1860 में आयकर की शुरुआत की स्मृति; कर प्रणाली के आधुनिकीकरण और स्वैच्छिक अनुपालन पर जोर।
25 जुलाई 2025	अफ्रीकी मूल की महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस	नस्लवाद और लिंगभेद से लड़ने की पहल; शिक्षा और नेतृत्व में भागीदारी पर बल।
25 जुलाई 2025	विश्व डूबने की रोकथाम दिवस	डूबने से बचाव हेतु जागरूकता; तैराकी शिक्षा और प्रशिक्षण पर बल।
25 जुलाई 2025	न्यायिक कल्याण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस	न्यायिक स्वास्थ्य और न्याय की गुणवत्ता के बीच संबंध; मानसिक कल्याण पर जागरूकता।
26 जुलाई 2025	विश्व मैन्ग्रोव दिवस	मैन्ग्रोव वनों के संरक्षण और जलवायु स्थिरता में उनकी भूमिका पर जोर।

महत्वपूर्ण दिवस: जून 2025

तिथि	दिवस / अवसर	विवरण
1 जून	अभिभावकों का वैश्विक दिवस	बच्चों की भलाई और विकास में माता-पिता की भूमिका को मान्यता देने के लिए। 2025 में सकारात्मक पालन-पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, और समावेशी देखभाल पर जोर।
1 जून	विश्व दुग्ध दिवस	थीम: "लेट्स सेलिब्रेट द पॉवर ऑफ डेयरी"; पोषण, आजीविका और सतत विकास में दूध की भूमिका पर जोर।
2 जून	तेलंगाना स्थापना दिवस	2014 में भारत का 29वां राज्य बना। क्षेत्रीय असंतुलन और सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष का प्रतीक।
4 जून	आक्रोश के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस	सशस्त्र संघर्षों में बच्चों पर अत्याचार को उजागर करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना।
5 जून	विश्व पर्यावरण दिवस	थीम: "बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन"; प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने की वैश्विक पहल।
5 जून	IUU मत्स्य शिकार विरोध दिवस	अवैध और अनियंत्रित मत्स्य पालन पर रोक लगाने हेतु।
7 जून	विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस	थीम: "फूड सेफ्टी: साइंस इन एक्शन"; खाद्य प्रदूषण रोकने के लिए विज्ञान और नवाचार का प्रयोग।
8 जून	विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस	ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता और शीघ्र निदान के लिए।
9 जून	विश्व प्रत्यायन दिवस	थीम: "SMEs को सशक्त बनाना"; गुणवत्ता मानकों और डिजिटल पारदर्शिता को बढ़ावा।
10 जून	सभ्यताओं के बीच संवाद हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस	संस्कृति, संवाद और वैश्विक शांति को बढ़ावा देना।
11 जून	खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस	थीम: "चुने खेल - हर दिन"; बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए खेल के महत्व पर जोर।
12 जून	बाल श्रम विरोधी विश्व दिवस	थीम: "प्रगति स्पष्ट है, लेकिन और प्रयास आवश्यक हैं"; बाल श्रम के उन्मूलन की आवश्यकता।
12 जून	विश्व किडनी कैंसर दिवस	थीम: "किडनी स्वास्थ्य को समझना"; जागरूकता और शीघ्र जांच के लिए प्रेरणा।
13 जून	अल्बिनिज़्म जागरूकता दिवस	रंगद्रव्य की कमी से पीड़ितों के अधिकार और सुरक्षा की मांग।
14 जून	विश्व रक्तदाता दिवस	थीम: "रक्त दें, आशा दें"; सुरक्षित रक्तदान के लिए जागरूकता।
15 जून	वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस	बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ वैश्विक अभियान।





तिथि	दिवस / अवसर	विवरण
16 जून	घरेलू कामगार दिवस	सम्मानजनक कार्य, वेतन और अधिकार की मांग।
16 जून	पारिवारिक प्रेषण अंतर्राष्ट्रीय दिवस	थीम: "विकास के लिए प्रेषण"; प्रवासी श्रमिकों की भूमिका को मान्यता।
17 जून	मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस	थीम: "भूमि बहाल करें, अवसर खोलें"; भूमि पुनर्स्थापन पर बल।
18 जून	हेट स्पीच विरोध दिवस	ऑनलाइन घृणा और कट्टरता के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान।
19 जून	संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन दिवस	थीम: "चक्र तोड़ें, घाव भरें"; पीड़ितों को न्याय और सहायता।
20 जून	विश्व शरणार्थी दिवस	थीम: "शरणार्थियों के साथ एकजुटता"; मानवता और अवसर की समानता का संदेश।
23 जून	संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस	लोक सेवकों की भूमिका और नवाचार को मान्यता।
23 जून	अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस	थीम: "लेट्स मूव?"; सक्रिय जीवनशैली को प्रेरणा।
23 जून	अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस	थीम: "कानूनी अधिकारों और समावेशी विकास द्वारा विधवाओं को सशक्त बनाना"।
24 जून	राजनयिक महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस	थीम: "नेतृत्व में रुकावटों को समाप्त करना"; नीति-निर्माण में लैंगिक समानता।
25 जून	नाविक दिवस	थीम: "मेरा उत्पीड़न-मुक्त पोत"; समुद्री कार्यस्थलों में गरिमा और सुरक्षा।
27 जून	डेफ्लाइंडनेस अंतर्राष्ट्रीय दिवस	हेलन केलर की स्मृति में; दृष्टि और श्रवण बाधित लोगों के अधिकारों को पहचान।
29 जून	उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस	जैव विविधता, संस्कृति और विकास चुनौतियों पर ध्यान।
29 जून	राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस	प्रो. पी.सी. महालनोबिस की स्मृति में; नीति निर्माण में आंकड़ों की भूमिका को मान्यता।

महत्वपूर्ण दिवस: मई 2025

तिथि	दिन / अवसर	विषय / विवरण
5 मई	विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस	पुर्तगाली भाषा और संस्कृति का उत्सव; 2009 में आरंभ, 2019 से UNESCO द्वारा मान्यता प्राप्त।
6 मई	विश्व अस्थमा दिवस 2025	विषय: "इनहेलड उपचार सभी के लिए सुलभ बनाना" - अस्थमा के प्रति जागरूकता।
6 मई	अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस	शरीर-सकारात्मकता और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला दिवस; आहार संस्कृति के दुष्प्रभावों पर ध्यान केंद्रित।
7 मई	विश्व एथलेटिक्स दिवस 2025	युवाओं के बीच फिटनेस, खेल भावना और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।
7 मई	सीमा सड़क संगठन (BRO) दिवस	भारत की सीमा सुरक्षा और विकास में 64 वर्षों का योगदान; 55,000+ किमी सड़कें निर्मित।
8 मई	विश्व थैलेसीमिया दिवस 2025	विषय: "थैलेसीमिया के लिए एकजुट: समुदायों का मिलन, मरीजों को प्राथमिकता"।
8 मई	विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025	विषय: "मानवता को जीवित रखना" - रेड क्रॉस की मानव सेवा को समर्पित।
10 मई	विश्व प्रवासी पक्षी दिवस	विषय: "पक्षी-अनुकूल शहर और समुदाय बनाना" - शहरीकरण से पक्षियों की सुरक्षा।
11 मई	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025	विषय: "नवाचार से सतत भविष्य को सशक्त बनाना"; पोखरण परीक्षण, HANSA-3 और त्रिशूल परीक्षण की वर्षगांठ।
12 मई	अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025	विषय: "हमारी नर्सें हमारा भविष्य। नर्सों की देखभाल से अर्थव्यवस्था सशक्त"।
12-18 मई	8वां वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह	पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित बुनियादी ढांचे और गति नियंत्रण पर जोर।
12 मई	पौधों के स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस	खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता और सतत कृषि में पौधों के महत्व को रेखांकित करता है।
15 मई	अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस	परिवारों की भूमिका और सामाजिक स्थिरता को महत्व देना।
16 मई	राष्ट्रीय डेंगू दिवस	डेंगू के खिलाफ जागरूकता, रोकथाम और समय पर उपचार पर जोर।
16 मई	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस	विषय: "प्रकाश, नवाचार, समाज" - प्रकाश तकनीकों और नवाचार की सराहना।
16 मई	शांतिपूर्वक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस	विविधता में एकता और वैश्विक सह-अस्तित्व को प्रोत्साहन देना।
17 मई	विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2025	विषय: "सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार" - डिजिटल समावेशन और तकनीकी समानता।





तिथि	दिन / अवसर	विषय / विवरण
18 मई	अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस	विषय: "तेज़ी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य" - संग्रहालयों का नवाचार और समावेश।
19 मई	विश्व फेयर प्ले दिवस	2025 में पहली बार मनाया गया; खेलों में निष्पक्षता, ईमानदारी और सम्मान को बढ़ावा देना।
20 मई	विश्व मधुमक्खी दिवस 2025	विषय: "प्रकृति से प्रेरणा लें - हमें पोषित करें"; परागणकर्ता संरक्षण पर बल।
20 मई	विश्व मापन दिवस 2025	भारत में कानूनी मापन में सुधार; "वन नेशन, वन टाइम" और eMaap पोर्टल की शुरुआत।
21 मई	अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2025	विषय: "बेहतर जीवन के लिए चाय"; सतत कृषि और महिला सशक्तिकरण में चाय का योगदान।
21 मई	राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस	पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि; आतंकवाद के खिलाफ शांति और एकता का संदेश।
21 मई	सांस्कृतिक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस	अंतरसंस्कृतिक संवाद और सतत विकास के लिए विविधता का सम्मान।
22 मई	जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025	विषय: "प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास"; वैश्विक जैव विविधता ढांचे के अनुरूप।
23 मई	प्रसूति फिस्टुला समाप्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस	विषय: "उसका स्वास्थ्य, उसका अधिकार" - महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा।
23 मई	विश्व कछुआ दिवस	कछुओं और कछुए की प्रजातियों के संरक्षण के लिए वैश्विक जागरूकता।
25 मई	विश्व फुटबॉल दिवस	1924 पेरिस ओलंपिक में फुटबॉल की शताब्दी के अवसर पर 2024 में घोषित; शांति और विकास में खेल की भूमिका को रेखांकित करता है।
25 मई	विश्व थायरॉइड दिवस 2025	भारत में थायरॉइड समस्याओं की बढ़ती दर पर जागरूकता; आयोडीनयुक्त नमक और शीघ्र जांच पर जोर।
25-31 मई	गैर-स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकता सप्ताह	17 शेष क्षेत्रों के लिए आत्मनिर्णय के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र का विशेष सप्ताह।
28 मई	विश्व भूख दिवस 2025	स्थानीय नेतृत्व वाले समाधान जैसे शिक्षा, जलवायु-लचीली कृषि और लैंगिक सशक्तिकरण पर ध्यान।
29 मई	संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस	विषय: "शांति की भविष्यवाणी"; evolving सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप शांति अभियानों में नवाचार।
29 मई	अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस	1953 में एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे द्वारा माउंट एवरेस्ट की पहली सफल चढ़ाई की स्मृति।
30 मई	आलू का अंतर्राष्ट्रीय दिवस	विषय: "इतिहास को आकार देना, भविष्य को पोषण देना"; आलू के पोषण और सतत कृषि में योगदान को उजागर करता है।
30 मई	हिंदी पत्रकारिता दिवस	हिंदी भाषा में पत्रकारिता के 200 वर्षों का उत्सव; लोकतंत्र और जन-जागरूकता में हिंदी मीडिया की भूमिका को सम्मान।
31 मई	विश्व तंबाकू निषेध दिवस	विषय: "चमकदार उत्पाद, अंधे इरादे - आकर्षण का पर्दाफाश"; तंबाकू के दुष्प्रभावों के विरुद्ध जागरूकता।
31 मई	अहिल्याबाई होल्कर जयंती	2025 में उनकी 300वीं जयंती; एक न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और समाजसेवी शासिका के रूप में उनकी स्मृति।

महत्वपूर्ण दिवस: अप्रैल 2025

दिनांक	दिवस/अवसर	विषय/विवरण
1 अप्रैल	उत्कल दिवस (ओडिशा दिवस)	• 1936 में ओडिशा का गठन, भारत का पहला भाषाई राज्य; कालिंग युद्ध और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान।
2 अप्रैल	विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस	• विषय: "न्यूरोडायवर्सिटी और सतत विकास लक्ष्य (SDGs) को बढ़ावा देना"।
4 अप्रैल	अंतर्राष्ट्रीय बारूदी सुरंग जागरूकता दिवस	• विषय: "सुरक्षित भविष्य यहीं से शुरू होता है" — युद्ध क्षेत्रों में बारूदी सुरंगों से निपटने पर ध्यान।
5 अप्रैल	समता दिवस	• बाबू जगजीवन राम की जयंती; सामाजिक न्याय और समानता के लिए समर्पित।
5 अप्रैल	राष्ट्रीय समुद्री दिवस	• 1919 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की पहली समुद्री यात्रा की स्मृति में।





दिनांक	दिवस/अवसर	विषय/विवरण
6 अप्रैल	स्वामीनारायण जयंती	• भगवान स्वामीनारायण की जयंती; चैत शुक्ल नवमी को राम नवमी के साथ मनाई जाती है।
6 अप्रैल	खेल के माध्यम से विकास व शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस	• विषय: "खेल से सामाजिक समावेश की ओर"।
7 अप्रैल	विश्व स्वास्थ्य दिवस	• विषय: "स्वस्थ प्रारंभ, आशापूर्ण भविष्य" — मातृ और नवजात स्वास्थ्य पर केंद्रित।
7 अप्रैल	1994 तुत्सी नरसंहार की अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस	• रवांडा में हुए नरसंहार की स्मृति में; शांति व शिक्षा के महत्व पर बल।
10 अप्रैल	महावीर जयंती	• भगवान महावीर की 2623वीं जयंती; अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह का संदेश।
10 अप्रैल	विश्व होम्योपैथी दिवस	• डॉ. हैनिमन की जयंती; "समान समान को ठीक करता है" सिद्धांत को बढ़ावा।
13 अप्रैल	सियाचिन दिवस	• ऑपरेशन मेघदूत (1984) की स्मृति में; दुनिया के सबसे ऊँचे युद्धक्षेत्र की सुरक्षा।
14 अप्रैल	अंबेडकर जयंती	• डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती; संविधान निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रणेता।
14 अप्रैल	विश्व शगास रोग दिवस	• लैटिन अमेरिका में प्रचलित एक मौन परजीवी रोग के प्रति जागरूकता।
15 अप्रैल	हिमाचल दिवस	• 1948 में प्रांत के रूप में गठन; 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा।
15 अप्रैल	विश्व कला दिवस	• लिओनार्डो दा विंची की जयंती पर; विषय: "एकता और उपचार हेतु कला"।
18 अप्रैल	विश्व धरोहर दिवस	• विषय: "आपदाओं और संघर्षों से विरासत को खतरा" — संरक्षण पर जागरूकता।
19 अप्रैल	विश्व यकृत दिवस	• विषय: "भोजन ही दवा है" — यकृत स्वास्थ्य में पोषण की भूमिका।
21 अप्रैल	राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस	• सरदार पटेल द्वारा 1947 में 'भारत की स्टील फ्रेम' कहे गए IAS अधिकारियों की स्मृति में।
21 अप्रैल	विश्व रचनात्मकता व नवाचार दिवस	• नवाचार और समस्या समाधान की वैश्विक भूमिका को उजागर करता है।
22 अप्रैल	पृथ्वी दिवस	• विषय: "हमारी शक्ति, हमारा ग्रह" — पर्यावरणीय जिम्मेदारी और नवीकरणीय ऊर्जा पर बल।
23 अप्रैल	विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस	• विषय: "एसडीजी प्राप्त करने में साहित्य की भूमिका" — साहित्य व लेखकों का सम्मान।
24 अप्रैल	राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस	• 73वें संविधान संशोधन की वर्षगांठ; ग्राम स्वराज व डिजिटल पंचायतों का उत्सव।
24-30 अप्रैल	विश्व टीकाकरण सप्ताह	• विषय: "सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है" — जीवन रक्षक टीकों के प्रति जागरूकता।
25 अप्रैल	विश्व मलेरिया दिवस	• विषय: "मलेरिया समाप्त करें: पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनःजागरण"।
25 अप्रैल	अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस	• 1945 में UN चार्टर ड्राफ्ट करने वाले प्रतिनिधियों की भूमिका को सम्मान।

निधन (राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय)

निधन (राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय): सितम्बर 2025

- फैशन आइकन का निधन: दिग्गज इतालवी फैशन डिजाइनर जियोर्जियो अरमानी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिन्हें आधुनिक इतालवी लालित्य के साथ 2.3 बिलियन यूरो का फैशन साम्राज्य बनाने के लिए विश्व स्तर पर "री जियोर्जियो" के रूप में जाना जाता था।
- भरतनाट्यम की दिग्गज हस्ती का निधन: कलाक्षेत्र की संस्थापक गुरु और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता शारदा हॉफमैन का 14 सितंबर को कैलिफ़ोर्निया में 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- दिग्गज अभिनेता-निर्देशक रॉबर्ट रेडफोर्ड का 89 वर्ष की आयु में निधन, सिनेमा और सामाजिक कार्यकर्ताओं में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है।
- मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री डी.डी. लपांग का निधन: 1992-2008 के बीच चार बार मुख्यमंत्री रहे सम्मानित राजनीतिक नेता का शिलांग में 91 वर्ष की आयु में निधन, आम सहमति बनाने के लिए याद किए जाते हैं।
- बॉक्सिंग के दिग्गज रिकी हैटन का निधन: ब्रिटिश विश्व चैंपियन मुक्केबाज "द हिटमैन" का 46 वर्ष की आयु में निधन, 48 मुकाबलों में 45 जीत की विरासत के साथ, मानसिक स्वास्थ्य वकालत के लिए याद किए जाते हैं।
- असमिया संगीत के दिग्गज जुबीन गर्ग का 52 वर्ष की आयु में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन, "या अली" जैसी हिट फिल्मों और उनकी विशाल सांस्कृतिक विरासत के लिए याद किया जाता है।





निधन (राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय): अगस्त 2025

राष्ट्रीय

क्रम संख्या	नाम	क्षेत्र	जन्म स्थान	प्रमुख तथ्य
1	शिवू सोरेन	राजनीति (जनजातीय नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा संस्थापक)	नेमरा, झारखंड	4 अगस्त 2025 को 81 वर्ष की आयु में निधन; "दिशोम गुरु" के नाम से प्रसिद्ध; झारखंड राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका; तीन बार मुख्यमंत्री रहे।
2	सत्य पाल मलिक	राजनीति (पूर्व राज्यपाल)	हिसावड़ा, उत्तर प्रदेश	5 अगस्त 2025 को 79 वर्ष की आयु में निधन; अनुच्छेद 370 हटाए जाने के समय जम्मू-कश्मीर के अंतिम राज्यपाल; गोवा, मेघालय और बिहार के राज्यपाल भी रहे।
3	ला गणेशन	राजनीति	तमिलनाडु, भारत	नागालैंड और मणिपुर के पूर्व राज्यपाल; राज्यसभा सांसद रहे; तमिल संस्कृति के संवाहक और प्रोत्साहक।
4	जसविंदर भल्ला (65)	पंजाबी हास्य अभिनेता और अभिनेता	लुधियाना, पंजाब	पंजाबी सिनेमा के सांस्कृतिक प्रतीक; कैरी ऑन जट्टा, गड्डी चलदी है छल्ला मारके के लिए प्रसिद्ध; बुद्धि और सामाजिक व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं।
5	अच्युत पोतदार (91)	हिंदी और मराठी अभिनेता	जबलपुर, मध्य प्रदेश	125+ फिल्मों (3 इंडियट्स, तेज़ाब, रंगीला) में अभिनय किया; अपनी प्रसिद्ध पंक्ति "कहना क्या चाहते हो?" के लिए जाने जाते हैं; मराठी रंगमंच से सिनेमा की ओर संक्रमण।

अंतरराष्ट्रीय

क्रम संख्या	नाम	क्षेत्र	जन्म स्थान	प्रमुख तथ्य
1	हीरोमासा उराकावा	मुक्केबाजी	जापान	नॉकआउट के बाद मस्तिष्क चोटों से निधन; वर्ष 2025 में तीसरे बॉक्सर जिनकी मृत्यु हुई।
2	डॉ. बीसी पेस	खेल चिकित्सा / हॉकी	भारत	ओलंपिक हॉकी पदक विजेता, प्रसिद्ध खेल चिकित्सक; टेनिस खिलाड़ी लिण्डर पेस के पिता।
3	बॉब सिम्पसन (89)	क्रिकेटर और कोच	सिडनी, ऑस्ट्रेलिया	62 टेस्ट मैच खेले (1957-1978); 4,869 रन बनाए, 10 शतक; एशेज और विश्व कप विजेता कप्तान; ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल।
4	न्यायाधीश फ्रैंक कैप्रियो (88)	न्यायाधीश और टीवी व्यक्तित्व	प्रोविडेंस, रोड आइलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका	"विश्व के सबसे अच्छे न्यायाधीश" के रूप में विख्यात; कॉर्ट इन प्रोविडेंस के स्टार; लगभग 40 वर्षों तक न्यायालय में सेवा की; अपने दयालु निर्णयों के लिए सोशल मीडिया सनसनी।

निधन (राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय): जुलाई 2025

राष्ट्रीय

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	क्षेत्र	जन्म स्थान	मुख्य तथ्य
1	डॉ. बी.वी. पट्टाभिराम	सम्मोहन विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक, प्रेरक वक्ता	भारत	75 वर्ष की आयु में हैदराबाद में हृदयगति रुकने से निधन; सम्मोहन और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी; वैश्विक कार्यशालाएं संचालित कीं; भारत का पहला जादू स्कूल स्थापित किया; मानद डॉक्टरेट प्राप्त।
2	पीटर रुफाई	फुटबॉल (गोलकीपर)	नाइजीरिया	"डोडो मायाना" के नाम से प्रसिद्ध; AFCON 1994 विजेता; 1994 और 1998 फीफा वर्ल्ड कप खेले; 65 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भागीदारी; 4 जुलाई 2025 को 61 वर्ष की आयु में निधन।
3	वत्सला	वन्यजीवन (हाथी संरक्षण)	निलांबूर वन, केरल	एशिया की सबसे उम्रदराज जीवित हथिनी (100+); 1993 में पन्ना टाइगर रिजर्व स्थानांतरित; बाघ ट्रेकिंग और गश्ती में मदद की; 2003 में सेवा निवृत्त; 8 जुलाई 2025 को निधन।
4	चारुपारा रवि	राजनीति (समाजवादी नेता)	केरल	RJD राज्य उपाध्यक्ष; 1977 में जनता पार्टी आंदोलन से जुड़े; 1980, 1996, 2011 में चुनाव लड़े; 8 जुलाई 2025 को 77 वर्ष की आयु में निधन।
5	बिस्मिल्ला जान शिनवारी	क्रिकेट अंपायरिंग	नंगरहार प्रांत, अफगानिस्तान	ICC पैनल अंपायर; 34 ODI, 26 T20I में अंपायरिंग; 7 जुलाई 2025 को 41 वर्ष की आयु में सर्जरी के दौरान निधन।





क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	क्षेत्र	जन्म स्थान	मुख्य तथ्य
6	एन. तिप्पण्णा	कानून एवं राजनीति	तुरुवनूर, कर्नाटक	कर्नाटक विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष; JD(S) राज्य प्रमुख; शिक्षा और समाज सेवा में अग्रणी; 11 जुलाई 2025 को 97 वर्ष की आयु में निधन।
7	कोटा श्रीनिवास राव	तेलुगु सिनेमा अभिनेता, पूर्व विधायक	आंध्र प्रदेश, भारत	40+ वर्षों का सिने करियर; विविध भूमिकाओं में अभिनय; कई पुरस्कारों से सम्मानित; तेलुगु फिल्म व राजनीति को बड़ा नुकसान।
8	बी. सरोजा देवी	भारतीय सिनेमा अभिनेत्री	बेंगलुरु, कर्नाटक, भारत	190+ फिल्मों में अभिनय (तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी); पद्म भूषण सम्मानित; सुंदरता, प्रतिभा और गरिमा की मिसाल।
9	मुहम्मद बुहारी	राजनेता, नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति	दाउरा, कत्सिना राज्य, नाइजीरिया	सैनिक से लोकतांत्रिक राष्ट्रपति (2015-2023); सुरक्षा और भ्रष्टाचार विरोध पर केंद्रित शासन।
10	फौजा सिंह	मैराथन धावक	व्यास पिंड, पंजाब, भारत	दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक; 89 वर्ष की उम्र में दौड़ शुरू की; कई अंतरराष्ट्रीय मैराथन पूरी कीं।
11	एंड्रिया गिब्सन	कवि, सामाजिक कार्यकर्ता	कैलाइस, मेन, अमेरिका	समलैंगिक कवि; कोलोराडो की पूर्व पोएट लॉरिट; लिंग पहचान, प्रेम और कैंसर से संघर्ष पर लेखन।
12	फेलिक्स बॉमगार्टनर	चरम खेल, स्काइडाइवर	साल्ज़बर्ग, ऑस्ट्रिया	फ्री फॉल में ध्वनि की गति पार करने वाले पहले व्यक्ति (2012); एयरोस्पेस व एडवेंचर स्पोर्ट्स में प्रेरणा स्रोत।

अंतरराष्ट्रीय

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	क्षेत्र	जन्म स्थान	मुख्य तथ्य
1	जूलियन मैकमोहन	अभिनेता	ऑस्ट्रेलिया	56 वर्ष की आयु में फ्लोरिडा में कैंसर से निधन; <i>Fantastic Four</i> , <i>Nip/Tuck</i> , <i>Charmed</i> जैसी फिल्मों और सीरीज में अभिनय; ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री बिली मैकमोहन के पुत्र; अंतिम बार नेटफ्लिक्स की <i>The Residence</i> में नजर आए।
2	एलन बर्गमैन	ऑस्कर विजेता गीतकार	ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, अमेरिका	3 ऑस्कर पुरस्कार, 16 नामांकन; मैरिलिन बर्गमैन, बारबरा स्ट्राइज़ेंड और मिशेल लीग्रांड के साथ सहयोग; <i>The Way We Were</i> और <i>Nice 'n' Easy</i> जैसे क्लासिक्स के रचयिता; हॉलीवुड के संगीत इतिहास को गहराई से प्रभावित किया।
3	बी.एस. अच्युतानंदन	राजनीतिज्ञ (पूर्व केरल मुख्यमंत्री, CPI(M) नेता)	आलप्पुझा, केरल, भारत	नारियल उद्योग के श्रमिक से मुख्यमंत्री तक का सफर; भूमि सुधार, किसानों के अधिकार और भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों के पुरोधा; 1964 में CPI(M) गठन में प्रमुख भूमिका; उनकी वक्तृत्व कला, सादगी और नैतिक नेतृत्व के लिए विख्यात।
4	हल्क होगन	पेशेवर पहलवान, मनोरंजनकर्ता	ऑगस्टा, जॉर्जिया, अमेरिका	WWE के दिग्गज; दो बार हॉल ऑफ फेम में शामिल; 1980 के दशक में पेशेवर कुश्ती का चेहरा बने; 8 <i>WrestleMania</i> इवेंट में मुख्य भूमिका; "Hulkamania" नारों के लिए प्रसिद्ध; अभिनेता और पॉप संस्कृति में भी लोकप्रिय चेहरा।

निधन (राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय): जून 2025

राष्ट्रीय

क्रम संख्या	नाम	क्षेत्र	जन्म स्थान	प्रमुख तथ्य
1	विक्रम सुगुमरन	तमिल फिल्म निर्देशक	—	47 वर्ष की आयु में मदुरै से चेन्नई यात्रा के दौरान हृदयगति रुकने से निधन - मधु यानै कूट्टम, रावण कूट्टम, आडुकलम जैसी फिल्मों से जुड़े - बालू महेंद्र के शिष्य, ग्रामीण यथार्थवादी सिनेमा के लिए प्रसिद्ध
2	दाजी पांशिकर	मराठी विद्वान व साहित्यकार	—	92 वर्ष की आयु में ठाणे में निधन - महाभारत, भावार्थ रामायण, एकनाथी भागवत पर गहन शोध - महाराष्ट्र रंगमंच में योगदान; CM देवेंद्र फडणवीस द्वारा श्रद्धांजलि
3	विजय रूपाणी	राजनीतिज्ञ (पूर्व CM, गुजरात)	—	- एयर इंडिया 171 दुर्घटना में निधन 2016-2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री, भाजपा उपाध्यक्ष - आपातकाल के दौरान सेवा व सरल राजनीतिक छवि के लिए प्रसिद्ध





क्रम संख्या	नाम	क्षेत्र	जन्म स्थान	प्रमुख तथ्य
4	उस्ताद गुलाम नबी शाह	कश्मीरी लोक संगीतकार	डांगीवाचा, रफियाबाद	11 जून 2025 को निधन 30+ वर्षों तक J&K सूचना विभाग में कार्यरत - सरंगी, बज्जा नगमा, ग्लास डांस में निपुण; शेर-ए-कश्मीर अवॉर्ड से सम्मानित
5	बिल एटकिन्सन	सॉफ्टवेयर अग्रदूत	—	5 जून 2025 को 74 वर्ष की आयु में निधन - QuickDraw के निर्माता; Apple Lisa और Macintosh में अहम भूमिका - GUI के pull-down menu जैसे तत्वों के जनक
6	नेल्लै सु. मुथु	पूर्व ISRO वैज्ञानिक व तमिल लेखक	तिरुनेलवेली	16 जून 2025 को तिरुवनंतपुरम में निधन (आयु 74) - डॉ. कलाम के साथ कार्य; 170+ पुस्तकें लिखीं, जैसे विनवेली 2057 - सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में सेवा
7	मारुति चित्तमपल्ली	पर्यावरणविद्, पद्मश्री	—	- सोलापुर में 93 वर्ष की आयु में निधन 36 वर्षों तक वन विभाग में कार्य - पक्षीकोश, पशुकोश, मत्स्यकोश जैसे ग्रंथों के लेखक; 'अरण्य ऋषि' के रूप में प्रसिद्ध
8	दिलीप दोषी	क्रिकेटर	—	- लंदन में 77 वर्ष की आयु में निधन 114 टेस्ट विकेट; पारंपरिक स्पिन गेंदबाजी के लिए प्रसिद्ध 1981 मेलबर्न टेस्ट में टूटे पैर के साथ खेले; Spin Punch आत्मकथा के लेखक
9	शेफाली जरीवाला	अभिनेत्री, नृत्यांगना	—	- मुंबई में 42 वर्ष की आयु में अचानक निधन - कांटा लगा गाने और बिग बॉस 13 में प्रसिद्धि - कारण जांच के अधीन; कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम

अंतरराष्ट्रीय

क्रम संख्या	नाम	क्षेत्र	जन्म स्थान	प्रमुख तथ्य
1	एतियेन-एमिल बॉल्यू (Étienne-Émile Baulieu)	फ्रांसीसी जैव रसायनविद्	फ्रांस	98 वर्ष की आयु में निधन - RU-486 (माइफेप्रिस्टोन) के आविष्कारक - सुरक्षित गर्भपात चिकित्सा में क्रांति - DHEA और प्रोजेस्टीरोन पर विशेष अनुसंधान - प्रजनन अधिकारों और वृद्धावस्था अनुसंधान के प्रबल पक्षधर - वैज्ञानिक दूरदृष्टि और मानवतावादी के रूप में प्रसिद्ध

निधन (राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय): मई 2025

राष्ट्रीय

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	क्षेत्र	जन्म स्थान	मुख्य तथ्य
1	के. वी. राबिया	साक्षरता कार्यकर्ता	केरल	पद्म श्री से सम्मानित के. वी. राबिया ने पोलियो, कैंसर और रीढ़ की चोटों के बावजूद केरल साक्षरता मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने समाज के वंचित वर्गों को शिक्षा दिलाने में जीवन समर्पित किया।
2	डॉ. सुब्बण्णा अय्यप्पन	वैज्ञानिक	(कर्नाटक अनुमानित)	भारत की 'नीली क्रांति' के जनक माने जाने वाले डॉ. अय्यप्पन का शव कावेरी नदी में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। उन्होंने जलीय कृषि और ग्रामीण आजीविका में क्रांतिकारी योगदान दिया था।
3	डॉ. जयंत विष्णु नारळीकर	खगोल भौतिकशास्त्री व विज्ञान संप्रेषक	पुणे, महाराष्ट्र	पद्म विभूषण से सम्मानित डॉ. नारळीकर IUCAA पुणे के संस्थापक थे। उन्होंने TIFR में खगोल भौतिकी को विकसित किया और विज्ञान संप्रेषण में अग्रणी भूमिका निभाई।
4	डॉ. एम. आर. श्रीनिवासन	परमाणु ऊर्जा वैज्ञानिक	तमिलनाडु (अनुमानित)	भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और एनपीसीआईएल के संस्थापक अध्यक्ष। उन्होंने 'अप्सरा' जैसे परमाणु रिएक्टर और 18 परमाणु संयंत्रों के विकास में योगदान दिया।





क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	क्षेत्र	जन्म स्थान	मुख्य तथ्य
5	डॉ. सरोज घोष	विज्ञान संग्रहालय आंदोलन के प्रवर्तक	कोलकाता (अनुमानित)	नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स (NCSM) के प्रथम महानिदेशक, जिन्होंने देशभर में विज्ञान केंद्रों का विकेंद्रीकृत नेटवर्क स्थापित किया और संसद संग्रहालय व राष्ट्रपति भवन संग्रहालय के निर्माण में भी योगदान दिया।
6	सुखदेव सिंह ढींडसा	राजनीतिज्ञ, शिअद नेता व पूर्व सांसद	संगरूर, पंजाब	वरिष्ठ अकाली दल नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री। 89 वर्ष की आयु में मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में निधन। पंजाब की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान।
7	राजेश	अनुभवी तमिल अभिनेता	चेन्नई, तमिलनाडु	तमिल फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध अभिनेता। 75 वर्ष की आयु में 29 मई 2025 को दिल का दौरा पड़ने से निधन। कई दशकों तक अभिनय क्षेत्र में सक्रिय रहे।

अंतरराष्ट्रीय

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	क्षेत्र	जन्म स्थान	मुख्य तथ्य
1	लुइस गाल्वान	फुटबॉल	अर्जेंटीना	अर्जेंटीना के 1978 विश्व कप विजेता डिफेंडर लुइस गाल्वान का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्लब एटलेटिको टालेरस से लंबे जुड़ाव और मजबूत रक्षात्मक खेल के लिए प्रसिद्ध रहे। उनकी भूमिका 1978 की विवादास्पद विश्व कप जीत में ऐतिहासिक रही।
2	होसे मुजिका	पूर्व राष्ट्रपति (उरुग्वे)	उरुग्वे	"दुनिया के सबसे गरीब राष्ट्रपति" कहे जाने वाले होसे मुजिका का 2025 में कैंसर से निधन हो गया। उन्होंने टुपामारोस गुरिल्ला से राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया। उनके कार्यकाल में गर्भपात, समलैंगिक विवाह और गांजा को वैध किया गया। उन्होंने सादगी से जीवन जिया और वेतन का अधिकांश हिस्सा दान करते थे।

निधन (राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय): अप्रैल 2025

राष्ट्रीय

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	क्षेत्र	जन्म स्थान	मुख्य तथ्य
1	मनोज कुमार	बॉलीवुड अभिनेता	पाकिस्तान (जन्म: हरिकृष्ण गिरि गोस्वामी)	• 87 वर्ष की आयु में निधन। "हरियाली और रास्ता", "वो कौन थी?", "पत्थर के सनम" जैसी फिल्मों से प्रसिद्ध। देशभक्ति फिल्मों के लिए विशेष रूप से पहचाने जाते हैं। विभाजन के बाद दिल्ली में बसे।
2	रविकुमार	मलयालम व तमिल फिल्म अभिनेता	चेन्नई	• 71 वर्ष की आयु में 4 अप्रैल 2025 को निधन। "उल्लास यात्रा" (1975), "अवरगल" (1977) जैसी फिल्मों में रोमांटिक भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध। फिल्मी परिवार से संबंध—माता भारती, पिता के.एम.के. मेनन।
3	पद्मश्री राम सहाय पांडे	राय लोकनृत्य के कलाकार	सागर, मध्य प्रदेश	• 92 वर्ष की आयु में निधन। गरीबी और सामाजिक प्रतिबंधों के बावजूद राय नृत्य को लोकप्रिय सांस्कृतिक पहचान में बदलने का कार्य किया। इस लोकनृत्य को नवजीवन देने के लिए सराहे गए।
4	दादी रतन मोहिनी	आध्यात्मिक नेत्री (ब्रह्मा कुमारी)	हैदराबाद, सिंध (अब पाकिस्तान)	• 100 वर्ष की आयु में 8 अप्रैल 2025 को निधन। ब्रह्मा कुमारीज की प्रमुख प्रशासक (2021 से)। विश्व शांति सम्मेलन 1954 में प्रतिनिधित्व किया। विश्वभर में शांति और मूल्यों का प्रचार-प्रसार किया।
5	कुमुदिनी लाखिया	कथक नृत्यांगना	भारत	• (1930-2024) में निधन। कथक को कथा और साहित्य पर निर्भरता से बाहर निकालकर आधुनिक विषयों और समूह-नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया। राम गोपाल के साथ यूरोप दौरे से वैश्विक दृष्टिकोण मिला।
6	डॉ. के. कस्तूरीरंगन	वैज्ञानिक, पूर्व ISRO अध्यक्ष	भारत	• 84 वर्ष की आयु में 25 अप्रैल 2025 को निधन। PSLV, GSLV, IRS-1A और भास्कर-1 व II मिशन में अग्रणी भूमिका। 1994-2003 तक ISRO प्रमुख रहे। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में चार दशकों तक अमूल्य योगदान।
7	एम. जी. एस. नारायणन	इतिहासकार	पोननी, केरल	• 92 वर्ष की आयु में निधन। केरल और दक्षिण भारत के प्राचीन व मध्यकालीन इतिहास के विशेषज्ञ। ICHR के सदस्य सचिव और अध्यक्ष रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट में अकादमिक उत्कृष्टता के लिए सराहे गए।





अंतरराष्ट्रीय

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	क्षेत्र	जन्म स्थान	मुख्य तथ्य
1	रिचर्ड चेम्बरलिन	अमेरिकी अभिनेता	बेवर्ली हिल्स, कैलिफ़ोर्निया	"मिनीसिरिज़ के राजा" के रूप में प्रसिद्ध। 90 वर्ष की आयु में 30 मार्च 2024 को हवाई के वाइमनालो में निधन। 'Dr. Kildare' (1961-66) में डॉ. जेम्स की भूमिका से लोकप्रियता। युद्ध सेवा के बाद अभिनय को अपनाया। 1963-65 तक 'Most Popular Male Star' का खिताब जीता।
2	बेल किल्मर	अमेरिकी अभिनेता	लॉस एंजेलिस, कैलिफ़ोर्निया	65 वर्ष की आयु में न्यूमोनिया से निधन। 'Top Gun', 'Batman Forever', 'The Doors' जैसी फिल्मों में यादगार भूमिकाएं। जूलियार्ड ड्रामा डिवीजन में सबसे कम उम्र में प्रवेश। 'Top Secret!' (1984) से हॉलीवुड में शुरुआत की। वर्षों तक गले के कैंसर से जूझा।
3	जीन मार्श	ब्रिटिश अभिनेत्री व पटकथाकार	लंदन, यूनाइटेड किंगडम	90 वर्ष की आयु में 13 अप्रैल 2025 को डिमेंशिया से निधन। 'Upstairs, Downstairs' की सह-निर्माता व अभिनेत्री। Emmy पुरस्कार विजेता भूमिका 'Mrs. Rose Buck' से प्रसिद्ध। ब्रिटिश टेलीविजन में गहरी छाप छोड़ी।
4	पोप फ्रांसिस	कैथोलिक धर्मगुरु (पोप)	व्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना	88 वर्ष की आयु में डबल न्यूमोनिया से निधन। 2013 में पहले लैटिन अमेरिकी, जेसुइट व गैर-यूरोपीय पोप बने। समलैंगिक अधिकारों, जलवायु संरक्षण, प्रवासियों और सामाजिक न्याय पर प्रगतिशील विचार। वेटिकन सुधारों और अंतर-धार्मिक संवाद के पक्षधर।
5	मारियो वर्गास योसा	पेरुवियन लेखक व पत्रकार	अरेक्किपा, पेरू	89 वर्ष की आयु में 14 अप्रैल 2025 को निधन। 2010 में साहित्य के नोबेल विजेता। 'The Time of the Hero', 'The Green House' सहित 30+ पुस्तकों के लेखक। सत्ता और व्यक्ति के संघर्ष की विषयवस्तु पर केंद्रित लेखन। राजनीति और साहित्य दोनों में वैश्विक प्रभावशाली व्यक्तित्व।

विविध करेंट अफेयर्स | वन-लाइनर्स

विविध करेंट अफेयर्स | वन-लाइनर्स: सितम्बर 2025

- दुर्लभ ड्रेगनफ्लाई की पुनः खोज: क्रोकोथेमिस एरिथ्रिया, जो आमतौर पर यूरोप और हिमालय में देखी जाती है, पश्चिमी घाट (केरल और तमिलनाडु) में 550 मीटर से ऊपर पाई गई; संभवतः हिमयुग की अवशेष प्रजाति, जो जैव विविधता की समृद्धि और शोला-घासभूमि पारिस्थितिकी तंत्र की नाजुकता को उजागर करती है।

विविध करेंट अफेयर्स | वन-लाइनर्स: अगस्त 2025

- प्रतिष्ठित फिल्म शोले के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, महाराष्ट्र डाक मंडल ने स्वतंत्रता दिवस 2025 पर विशेष चित्र पोस्टकार्ड, एक प्रस्तुति पैक और एक विशेष गोल्डन कैंसिलेशन जारी किया। इन स्मारक वस्तुओं का अनावरण मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अमिताभ सिंह ने किया और निर्देशक रमेश सिप्पी को भेंट किया। इस कार्यक्रम में फिल्म और डाक से जुड़े गणमान्य लोगों ने भाग लिया और डाक टिकट संग्रहकर्ताओं और सिनेमा प्रेमियों ने फिल्म के स्थायी सांस्कृतिक प्रभाव को प्रदर्शित किया। भारतीय डाक ने इससे पहले शतरंज चैंपियन डी. गुकेश और भारत की 2025 क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी जीत जैसे खेल दिग्गजों को भी इसी तरह के विशेष कैंसिलेशन के साथ सम्मानित किया है।
- एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें "भारत को भोजन देने वाले व्यक्ति" के रूप में जाना जाता है, ने भारत की हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने नॉर्मन बोरलॉग के बीजों से बनी बौनी गेहूँ की किस्मों को अपनाकर देश को पीएल 480 आयातों के अंतर्गत खाद्यान्न पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया। नौकरशाही की देरी और राजनीतिक विरोध के बावजूद, प्रधानमंत्रियों शास्त्री और इंदिरा गांधी के सशक्त नेतृत्व ने उनके प्रयासों को बल दिया, जिसके परिणामस्वरूप

1968 तक गेहूँ उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उनकी विरासत वैज्ञानिक नवाचार, राजनीतिक इच्छाशक्ति और संस्थागत समर्थन के महत्वपूर्ण महत्व को उजागर करती है। आज, जलवायु परिवर्तन, अनुसंधान एवं विकास के लिए कम धन और संस्थागत स्वायत्तता का अभाव जैसी चुनौतियाँ प्रगति के लिए खतरा हैं, जो भारत के कृषि भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल देती हैं।

विविध करेंट अफेयर्स | वन-लाइनर्स: जुलाई 2025

- पुडुचेरी ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में एक अग्रणी कदम उठाया है, क्योंकि यह भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसने TB स्क्रीनिंग को परिवार गोद लेने के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एकीकृत किया है। यह अभिनव दृष्टिकोण मेडिकल कॉलेजों, छात्रों और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के बीच सहयोग के माध्यम से चलाया जा रहा है।
- पुरातत्व और आनुवंशिकी में एक ऐतिहासिक उपलब्धि में, शोधकर्ताओं ने प्राचीन मिश्र के पहले पूर्ण जीनोम को सफलतापूर्वक अनुक्रमित किया है। यह खोज न केवल प्राचीन मानव आबादी की हमारी समझ में नए द्वार खोलती है, बल्कि पार-सांस्कृतिक अंतर्क्रियाओं पर भी प्रकाश डालती है।
- प्रसिद्ध निवेशक और अरबपति परोपकारी वॉरेन बफेट, जो बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन और सीईओ हैं, ने 27 जून 2025 को कंपनी के स्टॉक्स के रूप में पाँच परोपकारी संस्थाओं को 6 अरब डॉलर का बड़ा दान देने की घोषणा की। यह उनका अब तक का सबसे बड़ा परोपकारी कदमों में से एक है, जिससे 2006 से अब तक उनके कुल दान की राशि लगभग 60 अरब डॉलर तक पहुँच गई है।

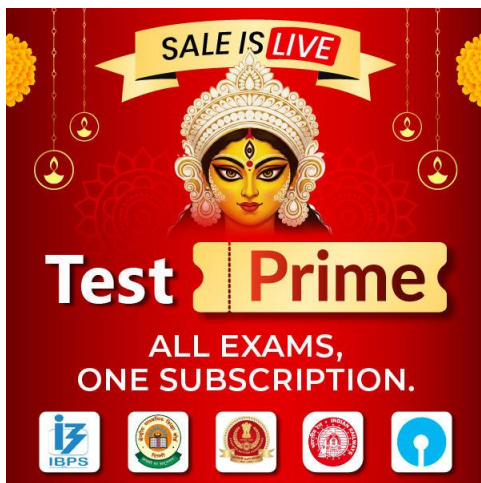




- Alphabet Inc. के CEO सुंदर पिचाई अब आधिकारिक रूप से अरबपति क्लब में शामिल हो गए हैं, क्योंकि उनकी कुल संपत्ति \$1.1 बिलियन (लगभग ₹9,100 करोड़) के पार पहुंच गई है। यह उपलब्धि मुख्य रूप से Alphabet के शेयर मूल्य में तेज़ वृद्धि और कंपनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में गहरे निवेश के कारण हासिल हुई है। सुंदर पिचाई की यह यात्रा तमिलनाडु की साधारण पृष्ठभूमि से शुरू होकर वैश्विक तकनीकी नेतृत्व तक की अद्भुत कहानी है, जो न केवल मेहनत और दूरदर्शिता का प्रतीक है, बल्कि दुनिया भर के युवाओं के लिए प्रेरणा भी है।

विविध करेंट अफेयर्स | वन-लाइनर्स: जून 2025

- एलन मस्क के एक्स ने XChat को पेश किया है, जो एक सुरक्षित, क्रॉस-प्लेटफॉर्म मैसेजिंग ऐप है जो वर्तमान में भुगतान करने वाले ग्राहकों के लिए बीटा में है। बिटकॉइन जैसे एन्क्रिप्शन, गायब होने वाले संदेश और ऑडियो/वीडियो कॉलिंग से लैस, यह ऐप व्हाट्सएप, टेलीग्राम और वीचैट जैसे प्रतिद्वंद्वी प्लेटफॉर्मों को टक्कर देने के लिए मस्क के प्रयास को दर्शाता है। यह भविष्य में ग्रीक एआई जैसे संभावित रूप से एआई-संचालित टूल सहित एकीकृत सेवाओं के साथ एक्स को एक सुपर ऐप में बदलने के उनके व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन और सीईओ, प्रसिद्ध निवेशक और अरबपति परोपकारी वॉरेन बफेट ने पांच धर्मार्थ संस्थाओं को कंपनी के स्टॉक में 6 बिलियन डॉलर का बड़ा दान देने की घोषणा की है। 27 जून, 2025 को प्रकट की गई उदारता के नवीनतम कार्य से 2006 से अब तक उनके द्वारा किए गए कुल दान की राशि लगभग 60 बिलियन डॉलर हो गई है। इस दान का बड़ा हिस्सा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ-साथ बफेट के परिवार से निकटता से जुड़े फाउंडेशनों को लाभ पहुंचाएगा।
- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्वीडन में स्टॉकहोम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को संबोधित करते हुए भारत की मतदाता सूची प्रणाली की पारदर्शिता और कठोरता पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे भारत ने 1960 से यह सुनिश्चित किया है कि मतदाता सूची हर साल सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाए, जिससे दावे, आपत्तियां और अपील की जा सकें - यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में विश्वास और अखंडता को मजबूत करती है।



विविध करेंट अफेयर्स | वन-लाइनर्स: मई 2025

- डाक विभाग जल्द ही प्रसिद्ध तबला वादक पंडित चतुर लाल की जन्मशती के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी करेगा। यह विशेष श्रद्धांजलि भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके अद्वितीय योगदान को सम्मानित करती है, विशेष रूप से तबले को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने और प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ उनके उल्लेखनीय सहयोग के लिए।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अंडमान सागर के ऊपर एक ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण (cyclonic circulation) की पहचान की है, जो 16 से 22 मई के बीच एक निम्न-दाब क्षेत्र (low-pressure system) में विकसित हो सकता है। यदि तीव्रता बढ़ती है, तो यह 23 से 28 मई के बीच एक चक्रवातीय तूफान (cyclonic storm) का रूप ले सकता है, जिसे चक्रवात शक्ति नाम दिया जाएगा (यह नाम श्रीलंका द्वारा प्रस्तावित किया गया है)।
- महाराणा प्रताप जयंती 2025 भारत के सबसे प्रतिष्ठित योद्धा राजाओं में से एक - मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह की 485वीं जयंती है। अपनी अदम्य भावना, प्रचंड देशभक्ति और मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ महान प्रतिरोध के लिए जाने जाने वाले इस दिन का राजस्थान और भारत के विभिन्न हिस्सों में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है।
- हैदराबाद के 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय पादकांति ने इतिहास रच दिया है। वह अब प्रसिद्ध 7 शिखरों की चुनौती को पूरा करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने सातों महाद्वीपों में से प्रत्येक पर सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई की - जो दुनिया भर के पर्वतारोहियों के लिए एक बड़ा सपना है।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने जलवायु परिवर्तन के बारे में गंभीर चेतावनी दी है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, 70% संभावना है कि वर्ष 2025 और 2029 के बीच वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाएगा।
- कश्मीर ने फलों के परिवहन में एक बड़ा कदम उठाया है। पहली बार घाटी से ताजी चेरी को कटरा (जम्मू) से मुंबई तक ट्रेन से भेजा जाएगा। इस नई सेवा से उन छोटे किसानों को मदद मिलेगी जो पहले हवाई जहाज से अपने फल नहीं भेज पाते थे।

विविध करेंट अफेयर्स | वन-लाइनर्स: अप्रैल 2025

- बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर की एक महत्वपूर्ण कंपनी HIL लिमिटेड और सीके बिरला ग्रुप का हिस्सा, ने रीब्रांडिंग की है और अब इसे BirlaNu लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। यह बदलाव निर्माण उद्योग के लिए गुणवत्ता, नवाचार और स्थायी उत्पाद बनाने के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- कुंभकोणम पान पत्ता (थंजावुर) और थोवलई फूलों की माला (कन्याकुमारी) को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया गया है। इस मान्यता के साथ, तमिलनाडु के कुल जीआई उत्पादों की संख्या 62 हो गई है। चार महीने की समीक्षा प्रक्रिया के बाद, 30 नवंबर 2024 को सरकारी गजट में इन उत्पादों की आधिकारिक जीआई स्थिति प्रकाशित की गई।





- अहमदाबाद के जमालपुर क्षेत्र में कारीगरों द्वारा सदियों से संजोई गई पारंपरिक सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कला को आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया गया है। यह अनूठी हस्तनिर्मित वस्त्र कला गुजरात की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित किया गया है।
- मिन्न के रेड सी में 27 मार्च 2025 को हर्गदा तट के पास पर्यटकों के लिए उपयोग की जाने वाली सिनाबाद पनडुब्बी डूब गई। इस दुर्घटना में छह विदेशी पर्यटकों की मृत्यु हो गई, जिनमें सभी रूसी नागरिक थे। यह पनडुब्बी 45 विदेशी पर्यटकों और पांच मिन्नी क्रू सदस्यों के साथ नियमित यात्रा पर थी जब यह हादसा हुआ।
- पश्चिम बंगाल ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राज्य के सात पारंपरिक उत्पादों को हाल ही में भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त हुआ है, जिनमें प्रसिद्ध नोलें गुडर संदेश और बारुईपुर अमरूद शामिल हैं। इस मान्यता से इन पारंपरिक वस्तुओं को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी, जिससे राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और इसकी सांस्कृतिक पहचान और सशक्त होगी।
- यशराज फिल्मस के बैनर तले बनी शाहरुख खान और काजोल की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के नाम एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। डीडीएलजे अब लीसेस्टर स्क्वायर लंदन

में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन जाएगी, जिससे जुड़ा स्टैच्यू यहां लगेगा। शाहरुख और काजोल का फिल्म के एक सीन का स्टैच्यू 'सीन्स इन द स्क्वायर' में लगेगा। इसकी घोषणा हार्ट ऑफ लंदन बिजनेस अलायंस ने की। लीसेस्टर स्क्वायर में 'सीन्स इन द स्क्वायर' मूवी ट्रेल में अब डीडीएलजे के रूप में एक नई प्रतिमा लगेगी। यह हिंदी सिनेमा की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म के 30 साल पूरे होने के जश्न की शुरुआत होगी।

- केंद्र सरकार ने मेघालय के दो पारंपरिक वस्त्र उत्पादों – रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को आधिकारिक तौर पर भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्रदान किए हैं। यह मान्यता न केवल क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देती है बल्कि इसके स्वदेशी शिल्प को कानूनी संरक्षण और बेहतर बाज़ारीकरण भी प्रदान करती है।
- हाल ही में बनारस शहनाई को भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया जाना भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को एक ऐतिहासिक मान्यता है। पूरी दुनिया में उस्ताद बिस्मिल्ला खान के माध्यम से प्रसिद्ध हुई शहनाई केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक संगीत का प्रतीक है। वाराणसी (काशी) के पारंपरिक कारीगरों के लिए यह GI टैग केवल एक आधिकारिक प्रमाणपत्र नहीं है, बल्कि उनकी पीढ़ियों से चली आ रही विरासत, निष्ठा और शिल्प कौशल को मिला एक भावनात्मक और सांस्कृतिक सम्मान है।

स्थैतिक टेकअवे करेंट अफेयर्स

स्थैतिक टेकअवे करेंट अफेयर्स: सितम्बर 2025

संक्षिप्त नाम / संगठन	श्रेणी	मुख्यालय / राजधानी	स्थापना / गठन वर्ष	प्रमुख कार्य / भूमिका	वर्तमान प्रमुख (2025)
EPFO	सांविधिक निकाय	नई दिल्ली	1952 (EPF अधिनियम)	भारतीय श्रमिकों के लिए भविष्य निधि, पेंशन और बीमा प्रबंधन	केंद्रीय PF कमिश्नर: नीलम शामी राव
IRDAI	नियामक (बीमा)	हैदराबाद, तेलंगाना	1999 (IRDA अधिनियम)	बीमा उद्योग का नियमन और पॉलिसीधारकों का संरक्षण	चेयरपर्सन: अजय सेठ (1 सितम्बर 2025 से)
MNRE	मंत्रालय	नई दिल्ली	1992	नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन, बायोमास) परियोजनाओं के लिए nodal मंत्रालय	मंत्री: प्रल्हाद जोशी
SEBI	नियामक	मुंबई	1988 (सांविधिक 1992)	शेयर बाजार का नियमन, निवेशकों का संरक्षण	चेयरपर्सन: तुहिन कांता पांडे
WPI	मुद्रास्फीति सूचकांक	-	1942	थोक स्तर पर मुद्रास्फीति मापन, आधार वर्ष: 2011-12	आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा संकलित
UPI	डिजिटल भुगतान प्रणाली	मुंबई	2016 (NPCI)	रीयल-टाइम मनी ट्रांसफर सक्षम करना	NPCI CEO: दिनीप अस्वे (RBI निगरानी)
ISRO	अंतरिक्ष एजेंसी	बेंगलुरु	1969	राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी - उपग्रह प्रक्षेपण एवं अंतरिक्ष अन्वेषण	अध्यक्ष: डॉ. वी. नारायणन
NITI Aayog	नीति सलाहकार	नई दिल्ली	2015	नीति निर्माण एवं रणनीति निकाय	चेयरपर्सन: PM नरेंद्र मोदी; CEO: B.V.R. सुब्रह्मण्यम
FSSAI	नियामक (खाद्य सुरक्षा)	नई दिल्ली	2008	खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण	चेयरपर्सन: पुण्य सलीला श्रीवास्तव; CEO: राजित पुनहानी





संक्षिप्त नाम / संगठन	श्रेणी	मुख्यालय / राजधानी	स्थापना / गठन वर्ष	प्रमुख कार्य / भूमिका	वर्तमान प्रमुख (2025)
DRDO	अनुसंधान एवं विकास एजेंसी	नई दिल्ली	1958	रक्षा R&D संगठन	अध्यक्ष: डॉ. समीर बी. कमत
RBI	केंद्रीय बैंक	मुंबई	1935	मौद्रिक नीति, बैंकिंग और मुद्रा का नियमन	गवर्नर: संजय मल्होत्रा (दिसम्बर 2024 से)
HAL	PSU (एयरोस्पेस)	बेंगलुरु	1940	विमान और एयरोस्पेस निर्माण	चेयरमैन & MD: डॉ. डी.के. सुनील
CPRI	अनुसंधान संस्थान	बेंगलुरु	1960	पावर R&D और परीक्षण	DG (अतिरिक्त प्रभार): आसित सिंह
भारतीय सेना	सशस्त्र बल	नई दिल्ली	1895 (आधुनिक)	भूमि रक्षा	COAS: जनरल उपेंद्र द्विवेदी
भारतीय नौसेना	सशस्त्र बल	नई दिल्ली	1612 (विरासत)	समुद्री रक्षा	CNS: एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी
NCC	युवा संगठन	नई दिल्ली	1948	युवा कैडेट प्रशिक्षण	DG: लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीरपाल सिंह
CSIR-NIScPR	अनुसंधान संस्थान	नई दिल्ली	2021 (मर्जर)	नीति और विज्ञान संचार अनुसंधान	निदेशक: डॉ. गीता वाणी रायसम
AIIMS दिल्ली	चिकित्सा संस्थान	नई दिल्ली	1956	प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल	निदेशक: डॉ. एम. श्रीनिवास
अटल इनोवेशन मिशन	इनोवेशन मिशन (NITI)	नई दिल्ली	2016	स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा	मिशन डायरेक्टर: दीपक बागला
IIM अहमदाबाद	प्रबंधन संस्थान	अहमदाबाद, गुजरात	1961	प्रमुख बिजनेस स्कूल	निदेशक: प्रो. भरत भास्कर; BoG चेयरपर्सन: पंकज आर. पटेल
रमन रिसर्च इंस्टिट्यूट	अनुसंधान संस्थान	बेंगलुरु	1948	मूलभूत अनुसंधान (कॉस्मिक, खगोल विज्ञान, भौतिकी)	निदेशक: प्रो. तरुण सौरदीप
IEPFA	सरकारी प्राधिकरण (MCA)	नई दिल्ली	2016	निवेशक शिक्षा और संरक्षण	CEO: अनीता शाह अकेला
NSE	स्टॉक एक्सचेंज	मुंबई	1992	प्रतिभूति और डेरिवेटिव्स मार्केट	चेयरपर्सन: श्रीनिवास इन्जेती; MD & CEO: आशीषकुमार चौहान
SBI	सार्वजनिक क्षेत्र बैंक	मुंबई	1955	भारत का सबसे बड़ा PSB	चेयरमैन: चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी
पंजाब नेशनल बैंक	सार्वजनिक क्षेत्र बैंक	नई दिल्ली	1894	भारत के सबसे पुराने PSB में से एक	MD & CEO: अशोक चंद्र
यस बैंक	निजी बैंक	मुंबई	2004	निजी क्षेत्र बैंक	चेयरमैन: आर. गांधी; MD & CEO: प्रशांत कुमार
NHPC लिमिटेड	PSU (पावर)	फरीदाबाद, हरियाणा	1975	हाइड्रोपावर परियोजनाएँ	चेयरमैन & MD: भूपेंद्र गुप्ता
TCIL	PSU (टेलिकॉम)	नई दिल्ली	1978	टेलिकॉम कंसल्टेंसी और इन्फ्रास्ट्रक्चर	CMD: संजीव कुमार
हीरो मोटोकॉर्प	ऑटो (टू-व्हीलर्स)	नई दिल्ली	1984	सबसे बड़ा टू-व्हीलर निर्माता	एक्जिटिंग CEO: विक्रम कासबेखर; CEO-डिज़िग्रेट: हर्षवर्धन चितले (जनवरी 2026 से)
कॉयर बोर्ड	सांविधिक निकाय (MSME)	कोच्चि, केरल	1953	कॉयर उद्योग को बढ़ावा	चेयरमैन (अतिरिक्त प्रभार): विपुल गोयल
ओडिशा	राज्य	भुवनेश्वर	-	खनिज और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध	CM: मोहन चरन माजी; गवर्नर: डॉ. हरि बाबू कांभम्पाटी
छत्तीसगढ़	राज्य	रायपुर	-	"भारत का चावल का कटोरा"	CM: विष्णु देव साई; गवर्नर: रमन डेका





संक्षिप्त नाम / संगठन	श्रेणी	मुख्यालय / राजधानी	स्थापना / गठन वर्ष	प्रमुख कार्य / भूमिका	वर्तमान प्रमुख (2025)
मेघालय	राज्य	शिलांग	-	वर्षा और जीवित जड़ पुलों के लिए प्रसिद्ध	CM: कानराड के. संध्या; गवर्नर: C H विजयशंकर
महाराष्ट्र	राज्य	मुंबई	-	भारत की वित्तीय राजधानी	CM: देवेंद्र फडणवीस; गवर्नर: C.P. राधाकृष्णन
बिहार	राज्य	पटना	-	कृषि और धरोहर	CM: नीतीश कुमार; गवर्नर: अरिफ मोहम्मद खान
असम	राज्य	दिसपुर	-	चाय, तेल और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध	CM: हेमन्ता बिस्वा शर्मा; गवर्नर: लक्ष्मण प्रसाद आचार्य
तमिलनाडु	राज्य	चेन्नई	-	उद्योग और ड्रविड संस्कृति के लिए प्रसिद्ध	CM: M.K. स्टालिन; गवर्नर: R.N. रवी

अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और वैश्विक कंपनियों की जानकारी

संगठन / कंपनी	श्रेणी	मुख्यालय	स्थापना	प्रमुख कार्य / भूमिका	वर्तमान प्रमुख (2025)
UNESCO	यूएन एजेंसी	पेरिस, फ्रांस	1945	शिक्षा, संस्कृति, विश्व धरोहर	DG: ऑड्रे अजुले
FIDE	खेल संगठन (शतरंज)	लॉज़ान, स्विट्ज़रलैंड	1924	वैश्विक शतरंज का संचालन	अध्यक्ष: आर्काडी ड्वोर्कोविच
ICC	खेल संगठन (क्रिकेट)	दुबई, UAE	1909 (1989 में नाम बदला)	वैश्विक क्रिकेट का संचालन	चेयरमैन: जय शाह; CEO: संजोग गुप्ता
Oracle	टेक कंपनी	ऑस्टिन, टेक्सास, USA	1977	सॉफ्टवेयर, क्लाउड	CEO: सफ़रा कैटज़; कार्यकारी अध्यक्ष: लैरी एलिसन
Tesla	ईवी कंपनी	ऑस्टिन, टेक्सास, USA	2003	इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा भंडारण	CEO: एलोन मस्क
Meta (Facebook)	टेक कंपनी	मेनलो पार्क, USA	2004	सोशल मीडिया और टेक	CEO: मार्क जुकरबर्ग
Amazon	टेक एवं रिटेल	सिएटल & आर्लिंगटन, USA	1994	ई-कॉमर्स & क्लाउड	CEO: एंडी जेसी
Alphabet (Google)	टेक होलिंग	माउंटेन व्यू, USA	2015 (Google 1998)	सर्च, विज्ञापन, क्लाउड	CEO: सुंदर पिचाई
Microsoft	टेक कंपनी	रेडमंड, USA	1975	सॉफ्टवेयर, क्लाउड	CEO & चेयरमैन: सत्या नडेला
LVMH	समूह कंपनी	पेरिस, फ्रांस	1987	लक्ज़री वस्त्र	CEO & चेयरमैन: बर्नार्ड अर्नॉल्ट
NVIDIA	सेमीकंडक्टर	सांता क्लारा, USA	1993	AI चिप्स और GPU	CEO: जेनसन हुआंग
Intel	सेमीकंडक्टर	सांता क्लारा, USA	1968	प्रोसेसर, AI	CEO: लिप-बू तान (मार्च 2025 से)
Dell Technologies	टेक कंपनी	राउंड रॉक, USA	1984	कंप्यूटर और सेवाएँ	CEO: माइकल डेल
Honeywell	इंडस्ट्रियल टेक	शार्लोट, USA	1906	औद्योगिक और एयरोस्पेस	CEO: विमल कपूर
Philips	कंज्यूमर & हेल्थकेयर	एम्स्टर्डम, नीदरलैंड	1891	हेल्थकेयर उपकरण	CEO: रॉय जैकॉब्स
Signify	लाइटिंग कंपनी	आइंडहोवन, नीदरलैंड	2016 (स्पिनऑफ)	स्मार्ट लाइटिंग	CEO: एरिक रोंडोलाट
Reliance Industries	समूह कंपनी	मुंबई, भारत	1973	ऊर्जा, रिटेल, टेलीकॉम	चेयरमैन: मुकेश अंबानी
Adani Group	समूह कंपनी	अहमदाबाद, भारत	1988	ऊर्जा, इंफ्रा, लॉजिस्टिक्स	चेयरमैन: गौतम अडानी





संगठन / कंपनी	श्रेणी	मुख्यालय	स्थापना	प्रमुख कार्य / भूमिका	वर्तमान प्रमुख (2025)
नेपाल	राष्ट्र	काठमांडू	-	दक्षिण एशियाई देश	पीएम: सुशीला कार्की; राष्ट्रपति: राम चंद्र पौडेल
सिंगापुर	राष्ट्र (लायन सिटी)	सिंगापुर	-	एशियाई वित्तीय हब	पीएम: लॉरेस वोंग; राष्ट्रपति: थरमन शंमुगरत्नम
थाईलैंड	राष्ट्र	बैंकॉक	-	दक्षिण पूर्व एशियाई देश	पीएम: अनुतिन चार्नविराकुल; राजा: रामा X
Tata Electronics	सहायक कंपनी (Tata Group)	भारत	-	इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर	Tata Sons चेयरमैन: एन. चंद्रशेखरन

स्थैतिक टेकअवे करेंट अफेयर्स: अगस्त 2025

क्रमांक	स्थैतिक नाम	विवरण
1	इसरो (ISRO)	अध्यक्ष - वी. नारायणन
2	नासा (NASA)	प्रमुख - सीन डफी
3	फीफा (FIFA)	अध्यक्ष - जियानी इन्फेंटिनो
4	बिम्स्टेक (BIMSTEC)	मुख्यालय - ढाका, बांग्लादेश
5	एयरबस इंडिया	सीईओ - जर्गेन वेस्टरमियर
6	इंडसइंड बैंक	सीईओ - राजीव आनंद
7	जगुआर लैंड रोवर	सीईओ - पी. बी. बालाजी
8	एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक	सीईओ - संजय अग्रवाल
9	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	गवर्नर - संजय मल्होत्रा
10	गोल्डमैन सैक्स	अध्यक्ष - डेविड सोलोमन
11	टाटा मोटर्स	सीईओ - ग्युन्टर बुशेक
12	पेटीएम	सीईओ - विजय शेखर शर्मा
13	डेलॉइट इंडिया	सीईओ - रोमन शेटी
14	जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	सीईओ - जयंता आचार्य
15	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस	सीईओ - गिरीश कौसगी
16	बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB)	प्रबंध निदेशक - देवदत्ता चौद
17	जियो फाइनेंशियल सर्विस	सीईओ - हितेश सेठिया
18	आईसीआईसीआई बैंक	प्रबंध निदेशक - संदीप बख्शी
19	आईडीएफसी बैंक	प्रबंध निदेशक - वी. वैद्यनाथन
20	एक्सिस बैंक	प्रबंध निदेशक - अमिताभ चौधरी
21	माइक्रोसॉफ्ट	सीईओ - सत्य नडेला
22	एनवीडिया (NVIDIA)	सीईओ - जेनसन हुआंग
23	एप्पल	सीईओ - टिम कुक
24	अल्फाबेट (गूगल)	सीईओ - सुंदर पिचाई
25	अमेज़न	सीईओ - एंडी जेसी
26	रूस	राष्ट्रपति - व्लादिमीर पुतिन; राजधानी - मॉस्को
27	अमेरिका (USA)	राष्ट्रपति - डोनाल्ड ट्रंप; राजधानी - वॉशिंगटन डी.सी.
28	चीन	राष्ट्रपति - शी जिनपिंग; राजधानी - बीजिंग
29	अज़रबैजान	राष्ट्रपति - इल्हाम अलीयेव; राजधानी - बाकू
30	आर्मेनिया	राष्ट्रपति - वाहगन खाचातुरयान; राजधानी - येरेवन





क्रमांक	स्थैतिक नाम	विवरण
31	कंबोडिया	प्रधानमंत्री - हुन मानेट; राजधानी - प्नॉम पेन्ह
32	थाईलैंड	प्रधानमंत्री - पैटोंगटार्न शिनवात्रा; राजधानी - बैंकॉक
33	मेक्सिको	राष्ट्रपति - क्लॉडिया शीनबाम; राजधानी - मेक्सिको सिटी
34	मोल्दोवा	राष्ट्रपति - माया सैंडू; राजधानी - चिसीनाउ
35	ज़ाम्बिया	राष्ट्रपति - हाकाइंडे हिचिलेमा; राजधानी - लुसाका
36	ऑस्ट्रेलिया	प्रधानमंत्री - एंथनी अल्बानीज़; राजधानी - कैनबरा
37	सिंगापुर	प्रधानमंत्री - लॉरेंस वोंग; राजधानी - सिंगापुर सिटी
38	केन्या	राष्ट्रपति - विलियम रूटो; राजधानी - नैरोबी
39	असम	राज्यपाल - लक्ष्मण प्रसाद आचार्य; मुख्यमंत्री - हेमंता सरमा
40	पंजाब	राज्यपाल - गुलाब चंद कटारिया; मुख्यमंत्री - भगवंत मान
41	दिल्ली	उप-राज्यपाल - विनय सक्सेना; मुख्यमंत्री - अरविंद केजरीवाल
42	गुजरात	राज्यपाल - आचार्य देवव्रत; मुख्यमंत्री - भूपेंद्र पटेल
43	सिक्किम	राज्यपाल - ओमप्रकाश माथुर; मुख्यमंत्री - प्रेम (पेम) तमांग
44	छत्तीसगढ़	राज्यपाल - खंभापति; मुख्यमंत्री - विष्णु देव साई
45	जम्मू और कश्मीर	उप-राज्यपाल - मनोज सिन्हा; मुख्यमंत्री - उमर अब्दुल्ला
46	मध्य प्रदेश	राज्यपाल - मंगुभाई पटेल; मुख्यमंत्री - मोहन यादव
47	आंध्र प्रदेश	राज्यपाल - अब्दुल नज़ीर; मुख्यमंत्री - चंद्रबाबू नायडू
48	तमिलनाडु	राज्यपाल - आर. एन. रवि; मुख्यमंत्री - एम. के. स्टालिन
49	महाराष्ट्र	राज्यपाल - राधाकृष्णन; मुख्यमंत्री - देवेंद्र फडणवीस
50	ज़ाम्बिया	राष्ट्रपति - हाकाइन्डे हिचिलेमा
51	ऑस्ट्रेलिया	प्रधानमंत्री - एंथनी अल्बानीज़
52	सिंगापुर	प्रधानमंत्री - लॉरेंस वोंग (2024-)
53	केन्या	राष्ट्रपति - विलियम रूटो
54	असम	मुख्यमंत्री - हिमंत बिस्वा सरमा; राज्यपाल - गुलाब चंद कटारिया
55	पंजाब	मुख्यमंत्री - भगवंत मान; राज्यपाल - बनवारीलाल पुरोहित
56	दिल्ली (केंद्र शासित प्रदेश)	मुख्यमंत्री - अरविंद केजरीवाल; उप-राज्यपाल - विनय सक्सेना
57	ओडिशा	मुख्यमंत्री - मोहन चरण मजिही (2024-); राज्यपाल - रघुबर दास
58	बिहार	मुख्यमंत्री - नीतीश कुमार; राज्यपाल - राजेन्द्र अर्लेकर
59	केरल	मुख्यमंत्री - पिनराई विजयन; राज्यपाल - आरिफ मोहम्मद खान
60	गुजरात	मुख्यमंत्री - भूपेन्द्र पटेल; राज्यपाल - आचार्य देवव्रत
61	आंध्र प्रदेश	मुख्यमंत्री - एन. चंद्रबाबू नायडू (2024-); राज्यपाल - एस. अब्दुल नज़ीर
62	सिक्किम	मुख्यमंत्री - प्रेम सिंह तमांग (गोलाय); राज्यपाल - लक्ष्मण प्रसाद आचार्य
63	छत्तीसगढ़	मुख्यमंत्री - विष्णु देव साय (2023-); राज्यपाल - बिस्वभूषण हरिचंदन
64	जम्मू व कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश)	उप-राज्यपाल - मनोज सिन्हा (कोई मुख्यमंत्री नहीं)
65	मध्य प्रदेश	मुख्यमंत्री - मोहन यादव (2023-); राज्यपाल - मंगुभाई पटेल
66	तमिलनाडु	मुख्यमंत्री - एम. के. स्टालिन; राज्यपाल - आर. एन. रवि
67	महाराष्ट्र	मुख्यमंत्री - एकनाथ शिंदे; उपमुख्यमंत्री - देवेंद्र फडणवीस; राज्यपाल - रमेश बैस
68	पश्चिम बंगाल	मुख्यमंत्री - ममता बनर्जी; राज्यपाल - सी. वी. आनंद बोस




स्थैतिक टेकअवे करेंट अफेयर्स: जुलाई 2025

क्र.सं.	स्थैतिक नाम	विवरण (हिंदी में)
1	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	गवर्नर - संजय मल्होत्रा
2	भारतीय स्टेट बैंक (SBI)	चेयरमैन/MD - चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी
3	इंडियन बैंक	MD - बिनोद कुमार
4	पंजाब नेशनल बैंक (PNB)	MD - अशोक चंद्रा
5	कर्नाटक बैंक	MD - श्रीकृष्णन शर्मा
6	अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	CEO - अमित सिंह
7	अडानी पावर	CEO - शेरसिंह ख्यालिया
8	स्लाइस (SLICE)	CEO - रंजन बजाज
9	फोनपे (PhonePe)	CEO - समीर निगम
10	अक्को (ACKO)	CEO - वरुण दूआ
11	एक्सिम पे (Exim Pay)	CEO - अर्जुन ज़ाज़रिया
12	फिनो पेमेंट्स बैंक	CEO - ऋषि गुप्ता
13	इंडिगो एयरलाइंस	CEO - पियेटर एल्बर्स
14	हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL)	CEO - प्रिया नायर
15	एनवीडिया (NVIDIA)	CEO - हुआंग जेनसिन
16	एप्पल (Apple)	CEO - टिम कुक
17	टेस्ला (Tesla)	CEO - एलन मस्क
18	HSBC इंडिया बैंक	CEO - हितेन्द्र डेव
19	बिड़ला समूह	चेयरमैन - कुमार मंगलम बिड़ला
20	रिलायंस जिओ	चेयरमैन - आकाश अंबानी
21	सेल (SAIL)	CEO - अमरेंद्र प्रकाश
22	एशियाई विकास बैंक (ADB)	मुख्यालय - मनीला, फिलीपींस
23	इसरो (ISRO)	अध्यक्ष - वी. नारायणन
24	नासा (NASA)	प्रमुख - सीन डफी
25	अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC)	चेयरमैन - जय शाह
26	भारत	PM - नरेंद्र मोदी; राजधानी - नई दिल्ली
27	जापान	PM - शिगेरू इशिबा; राजधानी - टोक्यो
28	अमेरिका	राष्ट्रपति - डोनाल्ड ट्रंप; राजधानी - वॉशिंगटन D.C.
29	ऑस्ट्रेलिया	PM - एंथनी अल्बनीस; राजधानी - कैनबरा
30	यूएई	राष्ट्रपति - मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान; राजधानी - अबू धाबी
31	फ्रांस	राष्ट्रपति - इमैनुएल मैक्रों; राजधानी - पेरिस
32	यूक्रेन	राष्ट्रपति - वोलोडिमिर जेलेंस्की; राजधानी - कीव
33	सऊदी अरब	राष्ट्रपति - मोहम्मद बिन सलमान; राजधानी - जेद्दा
34	रूस	राष्ट्रपति - व्लादिमीर पुतिन; राजधानी - मास्को
35	सुरिनाम	राष्ट्रपति - जेनिफर साइमन; राजधानी - पारामारिबो
36	कोलंबिया	राष्ट्रपति - गुस्तावो पेद्रो; राजधानी - बोगोटा
37	बुल्गारिया	राष्ट्रपति - रूमेन रादेव; राजधानी - सोफिया
38	मालदीव	राष्ट्रपति - मोहम्मद मुइजु; राजधानी - माले
39	चीन	राष्ट्रपति - शी जिनपिंग; राजधानी - बीजिंग
40	श्रीलंका	राष्ट्रपति - अनुर कुमार डिसानायके; राजधानी - कोलंबो





क्र.सं.	स्थैतिक नाम	विवरण (हिंदी में)
41	ओडिशा	CM - मोहन माझी; राज्यपाल - खंभापति; राजधानी - भुवनेश्वर
42	गुजरात	CM - भूपेंद्र पटेल; राज्यपाल - आचार्य देवव्रत; राजधानी - गांधीनगर
43	उत्तर प्रदेश	CM - योगी आदित्यनाथ; राज्यपाल - आनंदीबेन पटेल; राजधानी - लखनऊ
44	कर्नाटक	CM - सिद्धारमैया; राज्यपाल - थावरचंद गहलोत; राजधानी - बेंगलुरु
45	जम्मू और कश्मीर	CM - उमर अब्दुल्ला; उपराज्यपाल - मनोज सिन्हा; राजधानी - जम्मू
46	बिहार	CM - नीतीश कुमार; राज्यपाल - आरिफ खान; राजधानी - पटना
47	तमिलनाडु	CM - एम.के. स्टालिन; राज्यपाल - आर.एन. रवि; राजधानी - चेन्नई
48	सिक्किम	CM - प्रेम सिंह तमांग; राज्यपाल - ओमप्रकाश माथुर; राजधानी - गंगटोक
49	मध्य प्रदेश	CM - मोहन यादव; राज्यपाल - मंगुभाई पटेल; राजधानी - भोपाल
50	गोवा	CM - प्रमोद सावंत; राज्यपाल - पुसापति अशोक राजू; राजधानी - पणजी
51	हिमाचल प्रदेश	CM - सुखविंदर सिंह सुक्खू; राज्यपाल - शिव प्रताप शुक्ल; राजधानी - शिमला
52	महाराष्ट्र	CM - देवेंद्र फडणवीस; राज्यपाल - राधाकृष्णन; राजधानी - मुंबई
53	आंध्र प्रदेश	CM - चंद्रबाबू नायडू; राज्यपाल - अब्दुल नज़ीर; राजधानी - अमरावती
54	केरल	CM - पिनराई विजयन; राज्यपाल - अर्लेकर राजेन्द्र; राजधानी - तिरुवनंतपुरम
55	दिल्ली	CM - रेखा गुप्ता; उपराज्यपाल - विनय सक्सेना; राजधानी - नई दिल्ली
56	उत्तराखंड	CM - पुष्कर सिंह धामी; राज्यपाल - गुरमीत सिंह; राजधानी - देहरादून
57	झारखंड	CM - हेमंत सोरेन; राज्यपाल - संतोष गंगवार; राजधानी - रांची

स्थैतिक टेकअवे करेंट अफेयर्स: जून 2025

संगठन

स्थैतिक नाम	स्थैतिक विवरण
एसबीआई	एमडी - चल्ला श्रीनिवासलु शेटी
आरबीआई	राज्यपाल- संजय मल्होत्रा
फेडरल बैंक	एमडी - केवीएस मणियन
मुथूट ग्रुप	एमडी - जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट
एशियाई विकास बैंक	मुख्यालय - मनीला
सन फार्मा	एमडी - कीर्ति गणोरकर
थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड	एमडी - महेश अय्यर
एसबीआई	एमडी - चल्ला श्रीनिवासलु शेटी
आरबीआई	राज्यपाल- संजय मल्होत्रा
फेडरल बैंक	एमडी - केवीएस मणियन
मुथूट ग्रुप	एमडी - जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट
नासा	प्रमुख - जेनेट पेट्रो
इसरो	अध्यक्ष - वी नारायणन
होंडा स्पेस	सीईओ - तोशिरिरो मिबे
आईसीसी	अध्यक्ष - जय शाह
फीफा	राष्ट्रपति - जियोवानी इन्फैंटिनो
इंडिगो एयरलाइंस	सीईओ - पीटर एल्बर्स
एयर इंडिया	सीईओ - कैम्पबेल विल्सन
निप्पॉन कोड इंडिया	सीईओ - संपत कुमार
मेटा इंडिया	सीईओ - संध्या देवनाथन





स्थैतिक नाम	स्थैतिक विवरण
पीएनबी	एमडी - अशोक चंद्रा
एसबीआई	एमडी - चल्ला श्रीनिवासलु शेटी
आरबीआई	राज्यपाल - संजय मल्होत्रा
गूगल	सीईओ - सुंदर पिचाई
इंडिगो एयरलाइंस	सीईओ - पीटर एल्बर्स
एयर इंडिया	सीईओ - कैम्पबेल विल्सन
निप्पॉन कोई इंडिया	सीईओ - संपत कुमार
ICC (अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद)	अध्यक्ष - जय शाह
फीफा	अध्यक्ष - जियाननी इन्फेंटिनो (संशोधित)
SIDBI	अध्यक्ष - मनोज मिश्र

देश

देश	नेतृत्व और पूंजी
जर्मनी	चांसलर - फ्रेडरिक मर्ज़ राजधानी - म्यूनिख
पुर्तगाल	पीएम - लुइस मोटेनेग्रो राजधानी - लिस्बन
दक्षिण कोरिया	राष्ट्रपति - ली जे म्युंग राजधानी - सियोल
पोलैंड	राष्ट्रपति - आंद्रेज डूडा राजधानी - वारसा
निकारागुआ	राष्ट्रपति - जोस डैनियल ओर्टेगा राजधानी - मानागुआ
बांग्लादेश	राजधानी - ढाका
कनाडा	राष्ट्रपति - मार्क कार्नी राजधानी - ओटावा
इजराइल	प्रधानमंत्री - बेजामिन नेतन्याहू राजधानी - यरुशलम
श्रीलंका	अध्यक्ष - अनुरा कुमारा दिसानायके राजधानी - कोलंबो
अमेरिका	राष्ट्रपति - डोनाल्ड ट्रम्प राजधानी - वाशिंगटन डी.सी.
ईरान	राजधानी - तेहरान
इटली	पीएम - जॉर्जिया मेलोनी राजधानी - रोम
साइप्रस	राष्ट्रपति - निकोस क्रिसोडौलिडेस राजधानी - निकोसिया
यूके	पीएम - कीर स्टार्मर राजधानी - लंदन
रूस	राष्ट्रपति - व्लादिमीर पुतिन राजधानी - मास्को
क्रोएशिया	पीएम - आंद्रेज प्लेंकोविक राजधानी - ज़गरेब
रोमानिया	राष्ट्रपति - इली बोवोजान राजधानी - बुखारेस्ट
यूक्रेन	राष्ट्रपति - ज़ेलेन्स्की राजधानी - कीव





भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मुख्यमंत्री / राज्यपाल / राजधानी
कर्नाटक	सीएम - सिद्धारमैया राज्यपाल - थावर चंद गेहलोत
केरल	सीएम- पिनारई विजयन गवर्नर - आर आर्लेकर
उत्तर प्रदेश	सीएम - योगी आदित्यनाथ राज्यपाल - आनंदीबेन पटेल
जम्मू और कश्मीर	मुख्यमंत्री - उमर अब्दुल्ला उपराज्यपाल-मनोज सिन्हा
पंजाब	सीएम - भगवत मान राज्यपाल - गुलाब चंद कटारिया राजधानी - चंडीगढ़
गुजरात	सीएम-भूपेंद्र पटेल राज्यपाल - आचार्य देवव्रत राजधानी - गांधीनगर
महाराष्ट्र	मुख्यमंत्री - देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल - राधाकृष्णन राजधानी - मुंबई
बिहार	मुख्यमंत्री - नीतीश कुमार राज्यपाल - आरिफ खान राजधानी - पटना
यूपी	सीएम - योगी आदित्यनाथ राज्यपाल - आनंदीबेन पटेल
कर्नाटक	सीएम - सिद्धारमैया राज्यपाल - थावर चंद गेहलोत
आंध्र प्रदेश	सीएम - चंद्रबाबू नायडू राज्यपाल - अब्दुल नजीर
पश्चिम बंगाल	मुख्यमंत्री - ममता बनर्जी राज्यपाल - सी वी आनंद बोस
दिल्ली	सीएम - रेखा गुप्ता एल. गवर्नर - वी.के.सक्सेना
ओडिशा	सीएम - मोहन माझी राज्यपाल - हरि बाबू कंभमपति राजधानी-भुवनेश्वर
एमपी	सीएम - मोहन यादव राज्यपाल - मंगुभाई पटेल राजधानी - भोपाल
असम	मुख्यमंत्री - हिमंत बिस्वा सरमा; राज्यपाल - लक्ष्मण प्रसाद आचार्य; राजधानी - दिसपुर





स्थैतिक टेकअवे करेंट अफेयर्स: मई 2025

क्रमांक	स्थैतिक नाम	स्थैतिक विवरण
संगठन		
1	एसबीआई	अध्यक्ष - चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी
2	आरबीआई	राज्यपाल - संजय मल्होत्रा
3	सेबी	अध्यक्ष - तुहिन कांता पांडे
4	बाँव	एमडी - देवदत्त चंद
5	पीएनबी -	एमडी - अशोक चंद्रा
6	यस बैंक	एमडी - प्रशांत कुमार
7	स्टारलैंक	सीईओ - सिरिल आनंद
देश		
8	यूएसए	राजधानी - वाशिंगटन डी.सी. राष्ट्रपति - डोनाल्ड ट्रम्प मुद्रा - USD
9	अंगोला	राजधानी - लुआंडा राष्ट्रपति - जोआओ लौरेंको मुद्रा - क्वानज़ा
10	रूस	राजधानी - मास्को राष्ट्रपति - व्लादिमीर पुतिन मुद्रा - रूबल
11	वियतनाम	राजधानी - हनोई राष्ट्रपति - लुओंग कुओंग मुद्रा - डॉंग
12	फ्रांस	राजधानी - पेरिस राष्ट्रपति - इमैनुएल मैक्रों मुद्रा - यूरो
भारतीय राज्य		
13	कर्नाटक	राज्यपाल - थावर चंद गेहलोत सीएम - सिद्धारमैया राजधानी - बेंगलुरु
14	महाराष्ट्र	राज्यपाल - सी. पी. राधाकृष्णन मुख्यमंत्री - देवेंद्र फडणवीस राजधानी - मुंबई
15	उत्तर प्रदेश	राज्यपाल - आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री - योगी आदित्यनाथ राजधानी - लखनऊ
16	मध्य प्रदेश	राज्यपाल - मंगुभाई पटेल सीएम - मोहन यादव राजधानी - भोपाल
17	गुजरात	राज्यपाल - आचार्य देवव्रत सीएम - भूपेंद्र पटेल राजधानी - गांधीनगर
18	पंजाब	राज्यपाल - गुलाब चंद कटारिया सीएम - भगवत मान राजधानी - चंडीगढ़
19	जम्मू और कश्मीर	उपराज्यपाल - मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री - उमर अब्दुल्ला राजधानी - श्री नगर





क्रमांक	स्थैतिक नाम	स्थैतिक विवरण
1	एसबीआई	अध्यक्ष - चल्ला श्रीनिवासलु शेटी
2	आरबीआई	राज्यपाल - संजय मल्होत्रा
3	सेबी	अध्यक्ष - तुहिन कांता पांडे
4	बॉव	एमडी - देवदत्त चंद
5	पीएनबी -	एमडी - अशोक चंद्रा
6	यस बैंक	एमडी - प्रशांत कुमार
7	स्टारलिनक	सीईओ - सिरिल आनंद
देश		
8	यूएसए	राजधानी - वाशिंगटन डी.सी. राष्ट्रपति - डोनाल्ड ट्रम्प मुद्रा - USD
9	अंगोला	राजधानी - लुआंडा राष्ट्रपति - जोआओ लौरेंको मुद्रा - क्वानज़ा
10	रूस	राजधानी - मास्को राष्ट्रपति - व्लादिमीर पुतिन मुद्रा - रूबल
11	वियतनाम	राजधानी - हनोई राष्ट्रपति - लुओंग कुओंग मुद्रा - डॉंग
12	फ्रांस	राजधानी - पेरिस राष्ट्रपति - इमैनुएल मैक्रों मुद्रा - यूरो
भारतीय राज्य		
13	कर्नाटक	राज्यपाल - थावर चंद गेहलोत सीएम- सिद्धारमैया राजधानी - बेंगलुरु
14	महाराष्ट्र	राज्यपाल - सी. पी. राधाकृष्णन मुख्यमंत्री - देवेन्द्र फडणवीस राजधानी - मुंबई
15	उत्तर प्रदेश	राज्यपाल - आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री - योगी आदित्यनाथ राजधानी - लखनऊ
16	मध्य प्रदेश	राज्यपाल - मंगुभाई पटेल सीएम - मोहन यादव राजधानी - भोपाल
17	गुजरात	राज्यपाल - आचार्य देवव्रत सीएम-भूपेंद्र पटेल राजधानी - गांधीनगर
18	पंजाब	राज्यपाल - गुलाब चंद कटारिया सीएम - भगवत मान राजधानी - चंडीगढ़
19	जम्मू और कश्मीर	उपराज्यपाल-मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री - उमर अब्दुल्ला राजधानी - श्री नगर





क्रमांक	स्थैतिक नाम	स्थैतिक विवरण
1	त्रिपुरा	राज्यपाल - एन. रेड्डी मुख्यमंत्री - माणिक साहा राजधानी - अगरतला
2	मिजोरम	राज्यपाल - वी के सिंह सीएम - लालदुहोमा राजधानी - आइजोल
3	उत्तर प्रदेश	राज्यपाल - आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री - योगी आदित्यनाथ राजधानी - लखनऊ
4	तमिलनाडु	राज्यपाल - आर एन रवि मुख्यमंत्री - एम के स्टालिन राजधानी - चेन्नई
5	गुजरात	राज्यपाल - आचार्य देवव्रत सीएम - भूपेंद्र पटेल राजधानी - गांधीनगर
6	राजस्थान	राज्यपाल - हरिभाऊ बागडे सीएम - भजन लाल राजधानी - जयपुर
7	असम	राज्यपाल - लक्ष्मण आचार्य सीएम - हिमंत बिस्वा सरमा राजधानी - दिसपुर
8	यूएसए	राष्ट्रपति - डोनाल्ड ट्रम्प राजधानी - वाशिंगटन डी. सी
9	चीन	राष्ट्रपति - शी जिनपिंग राजधानी - बीजिंग
10	इंडोनेशिया	राष्ट्रपति - प्रबोवो सुबिआंतो राजधानी - जकार्ता
11	कंबोडिया	राष्ट्रपति - हेंग समरीन राजधानी - नोम पेन्ह
12	डब्ल्यूएचओ	मुख्यालय - जिनेवा
13	इसरो	अध्यक्ष - वी नारायणन
14	भारतीय रिजर्व बैंक	राज्यपाल - संजय मल्होत्रा
15	एसबीआई	अध्यक्ष - चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी
	पीएनबी	एमडी - अशोक चंद्रा

स्थैतिक टेकअवे करेंट अफेयर्स: अप्रैल 2025

क्रमांक	स्थैतिक नाम	स्थैतिक विवरण
संगठन		
1	एशियाई विकास बैंक	राष्ट्रपति - मासातो कांडा मुख्यालय - मांडलुयॉन्ग, मनीला, फिलीपींस
2	आरबीआई	राज्यपाल - संजय मल्होत्रा मुख्यालय - मुंबई
3	एसबीआई	अध्यक्ष - चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी मुख्यालय - मुंबई
4	एसबीआई कार्ड और भुगतान सेवाएँ	एमडी और सीईओ - सलिला पांडे
5	डीबीएस बैंक इंडिया	एमडी और सीईओ - रजत वर्मा





क्रमांक	स्थैतिक नाम	स्थैतिक विवरण
6	टाटा संस	अध्यक्ष - नटराजन चन्द्रशेखरन
7	एक्सिस बैंक	एमडी और सीईओ - अमिताभ चौधरी
8	फिक्की	अध्यक्ष - हर्ष वर्धन अग्रवाल
9	आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड	सीईओ - विशाखा मुले
10	रेनॉल्ट ग्रुप	सीईओ - वेंकटराम मामिलापल्ले
11	निसान इंडिया	सीईओ-सौरभ वत्स
12	स्पेस एक्स	सीईओ - एलोन मस्क
13	माइक्रोसॉफ्ट	सीईओ - सत्या नडेला
14	एशियाई क्रिकेट परिषद	अध्यक्ष - मोहसिन नकवी मुख्यालय - दुबई
देश		
15	यूएसए	राष्ट्रपति - डोनाल्ड ट्रम्प मुद्रा - अमेरिकी डॉलर राजधानी - वाशिंगटन डी.सी.
16	ब्राजील	राष्ट्रपति - लूला दा सिल्वा मुद्रा - ब्राज़ीलियन रियल राजधानी - ब्राज़ीलिया
17	म्यांमार	राष्ट्रपति - मिन आंग हलाइंग (कार्यवाहक) मुद्रा - क्यात राजधानी - नेपीडॉ
18	सिंगापुर	प्रधानमंत्री - लॉरेंस वोंग मुद्रा - सिंगापुर डॉलर राजधानी - सिंगापुर
19	थाईलैंड	राष्ट्रपति - पैटोंगटार्न शिनावात्रा मुद्रा - थाई बात राजधानी - बैंकॉक
20	जापान	पीएम - इशिबा शिगेरु मुद्रा - यान राजधानी-टोक्यो
21	रूस	राष्ट्रपति - व्लादिमीर पुतिन मुद्रा - रूसी रूबल राजधानी - मास्को
राज्य		
22	असम	राज्यपाल- लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सीएम-हेमंत बिस्वा सरमा राजधानी - दिसपुर
23	पंजाब	राज्यपाल- गुलाब चंद सीएम - भगवंत मान राजधानी - चंडीगढ़
24	छत्तीसगढ़	राज्यपाल- रामेन डेका सीएम-विष्णुदेव साय राजधानी - रायपुर
25	पश्चिम बंगाल	राज्यपाल- सी. वी. आनंद बोस मुख्यमंत्री - ममता बनर्जी राजधानी - कोलकाता





क्रमांक	स्थैतिक नाम	स्थैतिक विवरण
26	महाराष्ट्र	राज्यपाल- सी. पी. राधाकृष्णन मुख्यमंत्री - देवेन्द्र फडणवीस राजधानी - मुंबई
27	तेलंगाना	राज्यपाल- जिष्णु देव वर्मा सीएम - रेवंत रेड्डी राजधानी - हैदराबाद
28	आंध्र प्रदेश	राज्यपाल- एस. अब्दुल नज़ीर सीएम - चंद्रबाबू नायडू राजधानी - अमरावती
29	ओडिशा	राज्यपाल- हरि बाबू कंभरपति सीएम - मोहन चरण माझी राजधानी-भुवनेश्वर

क्रमांक	नाम	विवरण
संगठन		
1	यूनेस्को	मुख्यालय - पेरिस, फ्रांस
2	सेबी	अध्यक्ष - तुहिन कांता पांडे प्रधान कार्यालय - मुंबई
3	स्विगी	संस्थापक - श्रीहर्ष मेजेस्टी, नंदन रेड्डी, राहुल जैमिनी
4	ब्लू ओरिजिन	सीईओ - डेव लिम्प
5	अडानी लिमिटेड	अध्यक्ष - गौतम अडानी
6	डब्ल्यूएचओ	महानिदेशक - टेड्रोस एडनोम गेब्रेयसस
7	भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार	अजय कुमार सूद
8	इंडसइंड बैंक	एमडी - सुमंत कथपालिया मुख्य कार्यालय - मुंबई
देश		
9	संयुक्त राज्य अमेरिका	राष्ट्रपति - डोनाल्ड ट्रम्प राजधानी - वाशिंगटन डी.सी. मुद्रा - USD
10	चीन	राष्ट्रपति - शी जिनपिंग राजधानी - बीजिंग मुद्रा - युआन
11	गैबॉन	राष्ट्रपति - ब्राइस ओलिगुई नगोमा राजधानी - लिब्रेविल मुद्रा - सीएफए फ्रैंक
12	इक्वाडोर	राष्ट्रपति - डेनियल नोबोआ राजधानी - क्विटो मुद्रा: अमरीकी डॉलर
13	तंजानिया	राष्ट्रपति - सामिया सुलुह राजधानी - डोडोमा
14	यूएई	राष्ट्रपति - शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान राजधानी - अबू धाबी मुद्रा - यूएई दिरहम





क्रमांक	नाम	विवरण
भारतीय राज्य		
15	केरल	गवर्नर - आर्लेकर सीएम- पिनाराई विजयन राजधानी - तिरुवनंतपुरम
16	तमिलनाडु	राज्यपाल - आर. एन. रवि मुख्यमंत्री - एम. के. स्टालिन राजधानी - चेन्नई
17	मेघालय	राज्यपाल - सी. विजयशंकर मुख्यमंत्री - कॉनराड सैग्मा राजधानी - शिलांग
18	अरुणाचल प्रदेश	राज्यपाल - कैवल्य परनायक सीएम- पेमा खांडू राजधानी - ईटानगर
19	तेलंगाना	राज्यपाल - जिष्णु देव वर्मा सीएम - रेवंत रेड्डी राजधानी - हैदराबाद
20	गुजरात	राज्यपाल - आचार्य देवव्रत सीएम-भूपेंद्र पटेल राजधानी - गांधीनगर
21	मध्य प्रदेश	राज्यपाल - मंगुभाई पटेल सीएम - मोहन यादव राजधानी - भोपाल
22	पश्चिम बंगाल	राज्यपाल - सी. वी. आनंद बोस मुख्यमंत्री - ममता बनर्जी राजधानी - कोलकाता

क्रमांक	स्थैतिक नाम	स्थैतिक विवरण
संगठन		
1	इसरो	अध्यक्ष - वी नारायणन
2	आरबीआई	राज्यपाल - संजय मल्होत्रा
3	सेबी	अध्यक्ष - तुहिन कांता पांडे
4	एसबीआई	अध्यक्ष - चल्ला श्रीनिवासलु शेटी
5	पीएनबी (पंजाब नेशनल बैंक)	एमडी/सीईओ - अशोक चंद्रा
6	यूनेस्को	मुख्यालय - पेरिस
7	आईएमएफ	राष्ट्रपति - क्रिस्टालिना जॉर्जिवा
8	विश्व बैंक	अध्यक्ष - अजय बंगा
9	बोइंग	सीईओ - केली ऑर्टबर्ग
10	एयर इंडिया	सीईओ - कैम्पबेल विल्सन
11	रिलायंस इंडस्ट्रीज	अध्यक्ष - मुकेश अंबानी
देश		
12	यूएसए	राष्ट्रपति - डोनाल्ड ट्रम्प राजधानी - वाशिंगटन डी.सी. मुद्रा - USD
13	चीन	राष्ट्रपति - शी जिनपिंग राजधानी - बीजिंग





क्रमांक	स्थैतिक नाम	स्थैतिक विवरण
		मुद्रा - युआन
14	कजाकिस्तान	राष्ट्रपति - कसम टोकयेव राजधानी - तेंगे मुद्रा - अस्ताना
15	सऊदी अरब	राष्ट्रपति - मोहम्मद बिन सलमान राजधानी - रियाद मुद्रा - सऊदी रियाल
16	दक्षिण अफ्रीका	राष्ट्रपति - सिरिल रामफोसा
17	केन्या	राष्ट्रपति - विलियम रूटो राजधानी - नैरोबी मुद्रा - शिलिंग
18	रूस	राष्ट्रपति - व्लादिमीर पुतिन राजधानी - मास्को मुद्रा - रूबल
19	फ्रांस	राष्ट्रपति - इमैनुएल मैक्रों राजधानी - पेरिस मुद्रा - यूरो
भारतीय राज्य		
20	आंध्र प्रदेश	राज्यपाल - एस अब्दुल नज़ीर सीएम - चंद्रबाबू नायडू राजधानी - अमरावती
21	तेलंगाना	राज्यपाल - जिष्णु देव वर्मा सीएम - रेवंत रेड्डी राजधानी - हैदराबाद
22	बिहार	राज्यपाल - आरिफ खान मुख्यमंत्री - नीतीश कुमार राजधानी - पटना
23	महाराष्ट्र	राज्यपाल - सी. पी. राधाकृष्णन मुख्यमंत्री - देवेन्द्र फडणवीस राजधानी - मुंबई
24	ओडिशा	राज्यपाल - हरि बाबू कंभमपति सीएम - मोहन चरण माझी राजधानी - भुवनेश्वर
25	कर्नाटक	राज्यपाल - थावर चंद गेहलोत सीएम - सिद्धारमैया राजधानी - बेंगलुरु

